राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10]   तेरहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का उन्नीसवां दिवस   [संख्या : 9

सोमवार,

11 मार्च, 2013

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाबचन्द कटारिया।

प्रदेश की निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन इकाइयां

164. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक राज्य में विद्युत उत्पादन की किन-किन नवीन इकाइयों से कितना विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? उक्त नवीन इकाइयों का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक किन नवीन विद्युत इकाइयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है? उक्त इकाइयों का निर्माण पूर्ण कर विद्युत उत्पादन कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा तथा उक्त इकाइयों से राज्य को कितनी विद्युत उत्पादन प्राप्त होगी?

(3) उक्त नवीन इकाइयों के निर्माण कार्य हेतु कितना बजट प्रावधान प्रति वर्ष रखा गया है तथा अब तक कितनी राशि इस हेतु व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): (1) राज्य में दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 में नवीन विद्युत उत्पादन इकाइयों से विद्युत उत्पादन एवं उनके निर्माण कार्य का विवरण प्रपत्र-अ पर उपलब्ध है।

(2) राज्य में दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक राज्य की नवीन विद्युत उत्पादन इकाइयों के निर्माण, उनसे उत्पादन प्रारम्भ की तिथि, उनसे राज्य को मिलने वाली विद्युत का विवरण प्रपत्र-ब पर उपलब्ध है।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

(3) राज्य में दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक राज्य की नवीन विद्युत उत्पादन इकाइयों के निर्माण कार्य हेतु प्रति वर्ष किये गये बजट प्रावधन एवं व्यय का विवरण प्रपत्र-ब पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जो आपने प्रपत्र दिया है उससे क्या यह स्पष्ट होता है कि 2006 में जब हमारी गवर्नमेंट थी तब हमने 1070 मेगावाट की स्वीकृति दी और वर्ष 2008 और 2010 तक उसका कार्य पूर्ण किया? क्या यह भी सच है कि 2007 में हमने 540 मेगावाट की स्वीकृति दी और वह आपने 2009 और 2011 के बीच में पूरी की? क्या यह भी सच है कि 2005 में हमने ढाई सौ मेगावाट की स्वीकृति दी और वह 2011 में तैयार हुई? क्या यह भी सच है कि जुलाई, 2008 अर्थात हमारा ही है, 1200 मेगावाट की स्वीकृति दी, अभी आप जैसा इस प्रश्न के जवाब में दे रहे हैं कि 30.03.2013 को सम्भावना है? क्या यह भी सच है कि दिसम्बर, 2008, हमने 8 दिसम्बर को सरकार छोड़ी थी और आपने ग्रहण की थी, 500 मेगावाट, तो 3560 मेगावाट की स्वीकृति जो हमने हमारी गवर्नमेंट के समय जारी की थी, उसकी ही उपलब्धि आपको हुई है, एक? क्या यह सच है कि आपकी सरकार आने के बाद 2008-09 से लेकर अब तक केवल जुलाई, 2009 में 160 मेगावाट, नवम्बर, 2012 जो अभी-अभी गया है, 150 मेगावाट, यह सब मिलाकर 310 मेगावाट की ही स्वीकृति दी गयी, जो भी अभी प्रोसेस में है, फाइनल होकर एक भी नहीं आई? क्या यह भी सच है कि जनवरी, 2010 में आप 1200 मेगावाट जो दिखा रहे हो, यह निजी क्षेत्र की है, सरकार का इसमें कुछ भी लेना-देना नहीं है? क्या यह भी सच है, आपके इस चार्ट के अनुसार, आर.ए.पी.पी.-7 और आर.ए.पी.पी.-8, यह 700-700 मेगावाट की जो योजना है, इसमें से राज्य सरकार का हिस्सा मात्र 700 मेगावाट है और इसकी भी जो हमको पूर्ति मिलेगी वह 2017 में मिलेगी? आपके दिये हुए चार्ट से क्या यह प्रमाणित है कि हमारी सरकार के समय जो हमने आनगोइंग योजनाएं चालू कर रखी थीं, उनका विद्युत उत्पादन इन वर्षों में हुआ है? जब से आप शासन में आये, तब से लेकर, कौनसा प्लाण्ट आपने स्वीकृत किया और उसकी उपलब्धि आपको आई है, यह बता दें?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत उत्पादन एक सतत् प्रक्रिया है और कोई भी प्लाण्ट, अगर सब-क्रिटिकल है, ढाई

(डा. जितेन्द्र सिंह)

सौ मेगावाट का है, इसको करीब दो वर्ष का समय लगता है और सुपर-क्रिटिकल को चार वर्ष का टेन्टेटिव समय लगता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा लीडर आफ अपोजीशन ने कहा है, किस वक्त में कितना-कितना कार्य हुआ, यह मैं आपको बताने के लिये आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। 2003 से 2008 जब प्रतिपक्ष की सरकार थी, उस समय फर्म एनर्जी जिसमें थर्मल और गैस से आधारित जनरेशन होता है, वह मात्र 455 मेगावाट हुआ था। वे प्लाण्ट गिरल-1 और धौलपुर 110x3 मेगावाट लगे हैं गैस आपरेटेड, मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत द्वारा उनका भूमि पूजन 2003 के माह 07-08 में किया गया। मैं आनरेबल लीडर आफ अपोजीशन से कहना चाहूंगा, मैं आपको कम्पेयर टेबल दे रहा हूं 1998 से 2003 की हमारा जनरेशन, फर्म जनरेशन गैस एण्ड थर्मल, it was 1270 megawatt. 2003 से नवम्बर, 2008 में जो जनरेशन था, It was 455 megawatt only. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने कहा है, अभी जो हमारा जनरेशन हुआ है 2008 से जनवरी, 2013 तक, यह 170 मेगावाट है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप अब अपना कहें। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): Just a minute, Sir, I am explaining you. आप सीनियर लीडर हैं। मैं एक-एक प्लाण्ट के बारे में बता रहा हूं अभी जो आपने कहा, कि हमारे वक्त 1070 मेगावाट जनरेशन हुआ। उसमें छबड़ा 1 -2, इसका आर्डर आफ-कोर्स आपने दिया था, बी.टी.जी. का, बायलर, टर्बाइन एण्ड जनरेटर। लेकिन आपने जो अपने प्रश्न में पूछा है, मैं एक्जेक्टली बताऊं, विद्युत इकाइयों का निर्माण, उनसे प्रारम्भ करने की तिथि। आपने पूछा है प्रारम्भ करने की तिथि, तो प्रारम्भ करने की तिथि, We haven't hidden out anything. हमने आपसे कुछ नहीं छिपाया। रामगढ़ हमारा, जुलाई, 2009 के अन्दर उसमें कार्यादेश प्राप्त हुआ, 2010 के अन्दर हमने उसको प्रारम्भ किया। छबड़ा जिसके लिये आपने कहा है एक और दो, एक और दो के अन्दर जब आपकी सरकार थी, आपने सिर्फ बी.टी.जी. आर्डर दिया। जब तक बी.ओ.पी. आर्डर फाइनलाइज नहीं होता है तब तक you can't expect कि आप क्लीयरेंस करके जनरेशन स्टार्ट कर सकें। उसका प्रारम्भ तभी हुआ, बी.टी.जी आर्डर, बी.ओ.पी. आर्डर, 29.12.08 में जब हमारी सरकार आई माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत की। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोयले की भी व्यवस्था नहीं थी। वह आफ-कोर्स परसा ईस्ट एण्ड कांटे बेसिन जो कोल माइन है, वह

(डा. जितेन्द्र सिंह)

आपके टाइम में ली गई थी, लेकिन उसका एन्वायर्नमेंटल क्लीयरेंस नहीं था। आपने अखबारों में निरन्तर पढ़ा होगा, एन्वायर्नमेंटल क्लीयरेंस हमारे आने के बाद हुआ। Same happened with Kali-Sind. जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं 600 मेगावाट के, इसका ई.पी.सी. का काण्ट्रेक्ट, 2000 फरवरी में, इसकी एन्वायर्नमेंटल क्लीयरेंस मिली। तो सवाल यह नहीं है कि We have clarified it. हमने कहीं अपना वह लेने की कोशिश नहीं की है। We have mentioned it कि काली-सिंध, जुलाई 2008 में कार्यादेश दिया हमने। We haven't hidden anything, Sir. और नम्बर-2 का हमने उसमें दिया था, जुलाई, 08 We gave. आपने इसका आदेश दिया था, इसको सैंक्शन किया था। हमने कतई नहीं छिपाया। लेकिन जैसा कि आपने प्रश्न में पूछा है कार्य प्रारम्भ करने की तिथि, काली सिंध की कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 26.02.2009 थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, सवाल इस बात का नहीं है कि किसको क्रेडिट दी जाए या किसको नहीं दी जाए। मैं माननीय लीडर आफ अपोजीशन को बताना चाहूंगा कि आपका जिस समय जनरेशन हुआ, टोटल उसको अगर हम एस्टीमेट करें तो हमारी जब 2008 में सरकार आई तो generation was 6540 megawatt. आज जनवरी-फरवरी, 2013 में generation is 11168 megawatt । तो 4628 मेगावाट जनरेशन हुआ है, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह तो हमारा है, क्या थपथपा रहे हो?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): उसके अन्दर इश्यू है थपथपाने का क्योंकि इतना बड़ा जनरेशन और जो आगे आने वाले साल भर का वक्त है ... (व्यवधान) उससे 3000 मेगावाट आएगा जो आजादी के बाद आज तक नहीं आया।

श्री करणसिंह (छबड़ा): आपके खुद का क्या है? खुद का क्या है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उस समय तो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, वह तो जब होगी तब देख लेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब देने दीजिए और प्रश्न पूछने दीजिए। अंकित नहीं होगा। फालतू की पंचायती मत कीजिए, बैठिए। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है और आपने भी जो जवाब दिया उसी के अनुरूप

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिया। पर मैं जो चीज प्रस्तुत कर रहा हूं, आपके जवाब में आपने जो चार्ट बताए हैं, उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कोई नया नहीं जोड़ रहा। ये इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि यह गिरल लिग्नाइट थर्मल स्टेशन 125 मेगावाट, दिसम्बर, 2006 में स्वीकृत हो गया था, काम चालू हो गया था। आपने लिखा विद्युत उत्पादन इकाई के निर्माण प्रारम्भ होने की तिथि। इसी तरह से जून, 2006, 250 मेगावाट, फिर 165 मेगावाट। यह सारा मैंने जोड़ा है, यह सारा मिलाकर 1070 मेगावाट की 2006 में हमारी सरकार के समय स्वीकृति दी गयी। 2007 में हमने 540 मेगावाट की दी और उसके बाद 2005 में हमने 250 वह दी थी और बाकी जो जुलाई की आपने बताई है, यह हमने दी। जो पहले आप राज करके गये थे उस समय का भी आपने इसमें आंकड़ा दिया है। उसमें दो इकइयां, एक तो आर.ए.पी.पी. इकाई नम्बर-5, 220 मेगावाट, इसमें राज्य का हिस्सा कितना है? केवल 48 मेगावाट। कितना? केवल 48 मेगावाट। फिर आर.ए.पी.पी.-6, इसमें भी जो 220 मेगावाट की दी, उसमें भी आपका हिस्सा 48 मेगावाट। इन दोनों को जोड़ लीजिए। ये जो आप उस समय दे गए थे, वे हमारे टाइम पर कम्प्लीट हुए।

मेरा प्रश्न यह है, जो चार्ट आपने दिया है उस चार्ट में आप तो यह बता दें कि आपकी सरकार आयी दिसम्बर एण्ड में, 2008 से लेकर आज अपन मार्च, 2013 में खड़े हैं, आपने अपनी कौनसी इकाई की स्वीकृति दी और उसके आधार पर आपने बिजली पैदा कर दी? क्या जैसा आप कह रहे हो, चार साल का 48 परसेंट बजट बिजली पर खर्च करने के बाद भी बिजली आपके द्वारा एक यूनिट पैदा नहीं हुई, यह सच है क्या? आपके इस चार्ट से सच है क्या? वास्तव में आप इस आंकड़े को जो गिना रहे हो, अपनी कमजोरी को छुपा कर आप अपने आपको तो भले ही खुश कर लेंगे। लेकिन यह जो आपने दिया है दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक 1696 मेगावाट पवन ऊर्जा, इसमें आपकी गांठ का क्या लगा? पवन ऊर्जा में आपकी गांठ का क्या लगा? प्राइवेट आदमी आया, वह पैदा कर रहा है। आपने क्या कमाल कर दिया? जो पैसा हमने दिया आपको बजट में, उसकी उपलब्धि क्या है? उसके द्वारा कौनसी नई यूनिट आपने लगाई जिससे राजस्थान की जनता को बिजली प्राप्त हुई हो?

आपने सरासर राजस्थान की जनता को अंधेरे में रखा है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बिजली है। मेरा आप पर चार्ज है, इस बात का चार्ज है कि राज

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

में आने से लेकर मार्च, 2013 तक एक यूनिट बिजली भी आप पैदा नहीं कर पाये। क्या यह सच है? इसको मैं जानना चाहता हूं। आपके इसी से मैंने यह प्रमाणित कर दिया। 2009 का है, 160 मेगावाट रामगढ़ गैस तापीय परियोजना है, इसमें 110 मेगावाट गैस टर्बाइन, यह आपने पैदा किया और उसके बाद 50 मेगावाट स्टीम टबाईन, यह भी रामगढ़ में है, ये दोनों मिला दो तो 160 मेगावाट होती है जिसको आपने 2009 में शुरू किया। इसमें से एक तो अभी 15 मार्च, 2013 तक सम्भावित मान रहे हो कि मार्च, 2013 तक इसकी उपलब्धि होगी। और एक मान रहे हो, 31.7.2013 में मिलेगी। तो आपकी यह भी नहीं है। अभी तो जुलाई आएगी तब होगी। आज की तारीख में यह जो आपका 110 मेगावाट है, इसमें भी कुछ नहीं है।

सच में राजस्थान की जनता को आप भ्रमित कर रहे हैं। आपके आंकड़े इस बात को साबित कर रहे हैं कि जितनी मेगावाट बिजली पैदा हुई, जो हम शुरूआत बिजली की करके गए थे आप वही मात्र उत्पादन में लेकर आये। कोई कमाल नहीं किया गया है, इस बात को मान लो।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता, प्रतिपक्ष बहुत ही तजुर्बेदार और एक्सपीरिएंसड हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में रहे हैं, सवाल इस बात का है कि...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मंत्रीजी, विस्तार से जानकारी दो आधा-पौन घंटे पूरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम समझ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ताकि नरेगा बच जाए। आगे नरेगा आ रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): किस तरह से षडयंत्र की बू आ रही है। (व्यवधान) भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): चार-चार कलक्टर सस्पैंड होंगे, चार-चार। (व्यवधान) चार-चार कलक्टर सस्पैंड होंगे। उनको बचाने के लिए लम्बा करो, लम्बा करो। यह कोई तरीका हुआ? बेकार की बात है। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): गांवों में ढाणियों के कनेक्शन तो बंद कर दिये आपने। (व्यवधान) रघुजी, गांवों में आजाद भारत में पहली दफे बंद किये हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): आनरेबल सर, माननीय लीडर आफ अपोजिशन ने पूछा है कि आपकी सरकार ने क्या किया, ये सब हमारे वक्त के स्वीकृत किये हुए थे। आनरेबल सर, यह एक सतत प्रक्रिया है कि किस समय में क्या कारखाने शुरू हुए। हमने हमारी रिप्लाई में कोई हाइड नहीं किया कि हम छुपाकर कोई बहबूदी बताने की चेष्टा कर रहे हैं। आनरेबल सर, जस्ट ए मिनट। हमने स्पष्ट लिखा है कि गिरल लिग्नाइट 2006 में स्टार्ट हुआ But it was completed on 26.12.2008। आपका सूरतगढ़ सुपर थर्मल-6 स्टार्ट हुआ जून, 2006 में but it was….just a minute Sir. ... (व्यवधान) सर, मैं नहीं कह रहा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमने जो शुरू किये उनको आप बंद कर सकते थे क्या? मैंने प्रश्न पूछा है, आपकी सरकार के आने के बाद जिसको आपने स्वीकृत करके चालू किया हो और उससे एक यूनिट बिजली मिल गई हो, उसका आप नाम बता दो कि वह कौनसी जगह है जहां से आपको एक यूनिट बिजली मिली हो। यह क्या बात है?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 13 कारखाने शुरू हुए वे भी तो हमारे ही वक्त में कम्प्लीट हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिजली हमने दी आपको। (व्यवधान) पूरे राजस्थान स्टेट को हमने दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई कारखाने बीच में ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): भले ही आप मेजें थपथपा लो।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसी सरकार का क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है। Our first priority was कि पूर्व में जो हमारे स्थापित प्लांट्स हैं, हमारी जिम्मेदारी थी कि पहले उनको पूर्ण करें। किसी की भी सरकार हो...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आपने एक यूनिट भी पैदा किया है क्या? एक यूनिट भी किया हो तो बता दो। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): ... (व्यवधान) इतनी सारी यूनिट को एक यूनिट बोल रहे हो। (व्यवधान) यह बैठे हुए हैं हमारे सीकर के कॉमरेड, यह खड़े हो जाते, सड़कें रोक लेते। चार साल में एक बार भी सड़क रुकी हो तो बताइये बिजली को लेकर। वह कदापि नहीं हुआ, सरकार ने दी है। (व्यवधान) मैं कोई जोर से नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हम तो समझने के लिए समझना चाहते थे। (व्यवधान) हमें तो आप यह समझा दो कि कोई ऐसा यूनिट जो आपने आकर शुरू किया हो और उससे बिजली पैदा कर दी हो, उसका नाम बता दो। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा में 13 बार धरने हुए। 13 बार धरने हुए। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): दिसम्बर तक भी बिजली कटौती हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले आप मूल प्रश्नकर्ता का उत्तर दें।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय लीडर आफ अपोजिशन ने पूछा है कि आपके वक्त में कौन से प्लांट प्रारम्भ हुए। आपने पूछा है कि नवीन विद्युत इकाइयों का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया। तो ये प्रारम्भ किये गये, मैं बोल रहा हूं। 'प्रारम्भ' वर्ड, नम्बर-2 में आप देख लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बिजली पैदा की क्या?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): नम्बर-1, रामगढ़ गैस तापीय परियोजना, 110 मेगावाट, गैस टर्बाइन यह 15.03.2013 तक शुरू हो जाएगा। 50 मेगावाट स्टीम टर्बाइन, यह 31.07.2013 तक शुरू हो जाएगा। छबड़ा-3, यह मैंने लिखा है स्पष्ट कि दिसम्बर, 2008 में बी.ओ.पी. हुआ था और 29 दिसम्बर को उसके आदेश दिये गये। यह 30.3.2013 तक कम्प्लीट होगा। छबड़ा-4, इसका प्लांट का आर्डर 2008 में दिया गया था, यह 31.7.2013 से शुरू होगा। कालीसिंध 600 मेगावाट, जुलाई में आपके वक्त में इसके आर्डर दिये। लेकिन आपने पूछा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि, इसकी कार्य प्रारम्भ करने की तिथि थी 26.2.2009 । एन्वायर्नमेंट क्लीयरेंस के बगैर आप चालू नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना एन्वायर्नमेंट क्लीयरेंस के कोई भी प्लांट चालू नहीं हो सकता। आपने शुरू कर दिया लेकिन हमने 26.2.2009 को एन्वायर्नमेंट क्लीयरेंस दिया। 26.3.2013 तक कालीसिंध-1, 600 मेगावाट और कालीसिंध-2 600 मेगावाट 31.7.2013 तक शुरू हो जाएगा। रामगढ़ 110 और 50 के दो हैं, वे क्रमश: अक्टूबर, 2014 में और मार्च, 2015 में होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और बताना चाहूंगा, आपने स्वीकृत

(डा. जितेन्द्र सिंह)

कर दिये लेकिन जो परसा ईस्ट एण्ड कांटे बेसिन की कोल माइन थी उस पर एंवायर्नमेंट क्लीयरेंस आपने नहीं लिया, वे रुक गये सारे के सारे। एन्वायर्नमेंट क्लीयरेंस हमारी सरकार ने किया है तब जाकर ये वर्किंग आर्डर में आये सारे के सारे। सवाल इस बात का नहीं है। स्वीकृत आप चाहे एक दर्जन कर दें और उसके बाद उनका शुभारम्भ कर दें जब तक कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। आनरेबल अशोक गहलोतजी की सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इम्प्लीमेंट किया है।

आगे आने वाले एक वर्ष के अन्दर, मैं आपको बताना चाहूंगा, 1860 मेगावाट हमारा काली सिंध वन एण्ड टू से आएगा, छबड़ा से आएगा। I am not talking about the private sector. हमें बिजली मिलनी चाहिये। कवई का प्लांट तैयार पड़ा है, एनी टाइम सुपर क्रिटिकल, उसमें 1260 मेगावाट अगस्त, 2013 में मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, राजवैस्ट आप बता रहे हैं, जो प्राइवेट सैक्टर का है, लिग्नाइट आपरेटेड है 3, 4 एण्ड 5, वन टू थ्री फोर आज साथ चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने राजवैस्ट को आपके टाइम में स्वीकृत कर दिया था, लिग्नाइट माइन्स का क्या हुआ? उन बेचारों की रुकी रहीं सारी की सारी। किसानों को मुआवजे नहीं दिये गये। 900 करोड़ रुपये के मुआवजे माननीय अशोकजी गहलोत ने उनको दिलवाये। बिजली कहीं से मिले, प्राइवेट और सरकार का मतलब नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इतना बेइज्जत और क्यों हो रहे हो? कमाल कर रहे हो। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): बिजली मिल रही है, बिजली बिलकुल मिल रही है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): चार-चार घंटे औद्योगिक और घरेलू बंद है।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा रिन्युअल एनर्जी के बारे में, आपने पूछा विंड के बारे में आपने क्या किया।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): आपने ढाणियों के कनेक्शन क्यों बंद कर दिये? अध्यक्ष महोदय, एक भी ढाणी में बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब देने दीजिये।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): पहले आपके लीडर आफ अपोजिशन

(डा. जितेन्द्र सिंह)

की रिप्लाई तो देने दीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, विंड का मेरे पास रिकार्ड है, विंड के अन्दर 543 मेगावाट आपके वक्त में...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मंत्री महोदय, इस रिकार्ड को तो घर पर पढ़ते रहना, यहां इस बात का जवाब दो।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): हमारे वक्त में 1728 मेगावाट विंड का जनरेशन हो गया। सोलर का आपके जीरो जनरेशन था और हमारे टाइम में जवाहर लाल सोलर मिशन में राजस्थान नम्बर वन है इंडिया के अन्दर और वन थाउजेण्ड मेगावाट....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपका क्या लगा इसमें?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): दिसम्बर, 2013 तक पैदा करेंगे और रिकार्ड जनरेशन करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 दिसम्बर, 2005 को इन्होंने लड्डू बांटे थे 3 लाख 78 हजार रुपये के। लेकिन डैम से पानी लाने की व्यवस्था इन्होंने नहीं की। लड्डू बांटकर भूमि पूजन करके छोड़कर चले गये।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, प्रपत्र 'अ' के अन्दर आपने 1070 मेगावाट के विद्युत संयंत्र जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में लगे, उनमें उत्पादन कब कब प्रारम्भ किया, उसकी तिथि दी है, क्या यह सही है कि इन पांचों विद्युत संयंत्रों में जो 1070 मेगावाट के थे, जनवरी, 2008 में टर्बाइन इनका खड़ा हो गया और मार्च, 2008 से मई, 2008 के बीच में हाइड्रो टैस्ट हो गया? क्या यह भी सही है कि आपके विद्युत उत्पादन निगम ने 26 दिसम्बर, 2008 को जब तत्कालीन केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जयराम रमेश आये, तब यह स्वीकार किया कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पिछली सरकार के समय के जो संयंत्र हैं, इन पर लगभग काम पूरा हो गया है, हम इनमें मार्च, 2009 को विद्युत उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे? यह दो वर्ष विलम्ब से क्यों हुआ?

नम्बर दो, आपने परिपत्र ब में जिस 1860 मेगावाट का जिक्र किया है, जिसमें राजवैस्ट भी है, जिसमें काली सिंध भी है, जिसमें छबड़ा की यूनिट तीन और चार हैं और रामगढ़ की 160 हैं, क्या यह सही है कि 2011-12 में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपने उनसे यह कहलवाया कि उन सभी 1860 मेगावाट के विद्युत संयंत्रों का उत्पादन मार्च, 2012 में प्रारम्भ कर देंगे एवं इसका वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे? आपने वाणिज्यिक उत्पादन क्यों नहीं प्रारम्भ किया? क्या यह भी सही है कि आपने अब तक जिन 7,750 विद्युत संयंत्रों की अलग-अलग समय पर थोथी घोषणाएं की हैं, उनमें से एक भी संयंत्र पर, जो प्रतिपक्ष के नेता ने आरोप लगाये, आरोप आप पर है कि आपने जिन संयंत्रों की घोषणा की, उनमें एक संयंत्र ने एक मेगावाट विद्युत अगर उत्पादन किया हो तो बता दें। क्या यह भी सही है कि आपने महंगी बिजली खरीदी?

श्री अध्यक्ष: आप कितने प्रश्न पूछ रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने विद्युत संयंत्रों का निर्माण कार्य इसलिये धीमा किया कि आपको महंगी बिजली खरीदकर चांदी कूटने का षड्यन्त्र करना था। लोगों के धन का अपव्यय करना था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने कितने प्रश्न पूछे, आपको याद है क्या? याद है आपको?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, दो पूछे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्डा। मंत्रीजी, फूलचन्द भिण्डा पूछ लें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, परिपत्र क्रमांक अ पर 11 यूनिट ऐसी हैं जो हमारे कार्यकाल में स्वीकृत हुई और हमने ही प्रारम्भ कीं। 11 यूनिट हैं इस परिपत्र में। उसके बाद में जो राजवैस्ट की बात कही गयी है, इन्होंने कहा, पर्यावरण की अनुमति हमने ली। सरकार इनकी थी, रुकाने के लिये कोशिश की, फिर भी 2007 में हमने कार्य प्रारम्भ कर दिया। उस समय हमारी सरकार थी, कार्य प्रारम्भ हो चुका था। इन्होंने खूब रुकावट डाली। केन्द्र सरकार को कानाफूसी करके इन्होंने खूब रुकावट डाली,

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

फिर भी हमने कार्य प्रारम्भ किया। 11 के 11 प्रारम्भ किये। पहला भाषण जब मैंने पहली विधान सभा में दिया तब कहा था पांच महीने में वे हो जाएंगे। 2013 में पांच महीने हो रहे हैं क्या? यह भी इन्होंने उस समय असत्य बोला।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनलाल गुप्ता। (व्यवधान) यह सही नहीं है इस प्रकार से। आप विराज जाएं। अंकित नहीं हो रहा है। मैंने मोहनलाल गुप्ता को अलाउ किया है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय बड़ी डींग हांक रहे हैं कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया। मैं एक ही क्वेश्चन कर जवाब चाहता हूं कि किसानों को 8 घंटे बिजली आप दे रहे हैं क्या? किसानों को कितने बिजली कनेक्शन एडिशनल दिये और उनको क्यों रोक रखा है? इतनी डींग हांकने का मतलब यही है कि आपने बहुत कनेक्शन दिये हैं और 8 घंटे से ज्यादा बिजली सप्लाई कर रहे हैं किसानों को। यह बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने सारे प्रश्नों की बौछार हो गयी। मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब दे दिया। फिर भी, हमारे माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि आपकी सरकार ने बिजली कितनों को दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर, ...(व्यवधान) सर, पहले टोटल तो बता लेने दो आप। पूरे राजस्थान में इन चार वर्षों में..... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, यह तो मंत्री महोदय टाइम पास कर रहे हैं। रघुजी कहकर गये हैं कि तुम टाइम पास ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आप तो सवाल पूछ रहे हो, कोई सवाल पूछोगे तो जवाब देंगे। हमारे विद्वान मंत्रीजी एक-एक चीज का पूरा खुलासा करके आपको जवाब दे रहे हैं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): किसानों को कितने घंटे बिजली दे रहे हो?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार ने कितने कनेक्शन दिये। माननीय

(डा. जितेन्द्र सिंह)

अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पेयर करता हूं टेबिल के अनुसार। चार साल के अन्दर 2 लाख 50 हजार एग्रीकल्चर के कनेक्शन दिये गये। माननीय प्रतिपक्ष की सरकार में मात्र 71 थे। आगे आने वाले एक वर्ष में 75 हजार एग्रीकल्चर कनेक्शन दिये जाएंगे जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा की है। और डोमेस्टिक कनेक्शन बीपीएल को साढ़े 16 लाख, जो इतिहास है आज, It will be a record generation, Sir. साढ़े 16 लाख कनेक्शन दिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): विराजो, विराजो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह आसन का काम आप क्यों कर रहे हो? विस्तार से जवाब दे रहे हैं मंत्री महोदय। आपका माइक ऊपर करो आप।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): आप पूछिये सवाल।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आगे चलो, नहीं पूछेंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): कब तक बचोगे?

जोधपुर जिले में उचित मूल्य की आबंटित दुकानें

165. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा)**:** क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में रिक्त एवं अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन कर दिया गया है? यदि हां, तो कब एवं कहां-कहां पर? इस हेतु आबंटन प्रक्रिया के क्या मानदण्ड तय किये गये?

(2) क्या उक्त आबंटन प्रक्रिया में किसी प्रकार का आरक्षण दिया गया? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर आरक्षण दिया गया एवं उसके क्या मानदण्ड थे? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त दुकान आबंटियों को आबंटन पत्र जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो क्यों?

(4) क्या गत वर्ष रिक्तियों के विपरीत आवेदकों (आरक्षित वर्ग) से आवेदन पत्र मांगे गये थे? यदि हां, तो इस हेतु जनवरी, 2013 तक कितनी कितनी उचित मूल्य की दुकानों हेतु आवेदकों का चयन कर आबंटन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री परसादीलाल): (1) जी हां। जोधपुर जिले में रिक्त एवं अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानों की चयन प्रक्रिया माह जून-जुलाई, 2011 में पूर्ण की गयी थी। जोधपुर शहर एवं ग्रामीण

(श्री परसादीलाल)

की चयन सूची के आधार पर जारी किये गये आबंटन/प्राधिकार पत्र की सूची परिशिष्ट-1 पर एवं आबंटन प्रक्रिया के मानदण्ड सम्बन्धी आदेश दिनांक 27.02.2009 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के मानदण्ड सम्बन्धी आदेश दिनांक 6.10.2009, 10.11.2009, 30.4.2010 एवं 8.12.2010 की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। आदेश की अनुपालना में किस-किस स्थान पर आरक्षण दिया गया, की सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्ष 2011 में चयन समिति द्वारा चयनित एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार स्वीकृत अभ्यर्थियों को वर्ष 2012 में (दिनांक 27.4.2012 से पूर्व) प्राधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं।

(4) जी नहीं। वर्ष 2012 में शेष रही रिक्त/अतिरिक्त उचित मूल्य दुकानों के आबंटन हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.4.2012 जिसके द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आबंटन में आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को अधिक्रमित कर दिया गया है, आदेश की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, मेरे इस सवाल के लगते ही और आज आपका जवाब था, रात को आपने राजस्थान के दलितों पर इतना कुठाराघात किया है कि आपने इस आरक्षण व्यवस्था को खतम कर दिया। आपने 06.10.2009 को इस आरक्षण व्यवस्था को चालू किया, किन कारणों से आज आपने इस आरक्षण की व्यवस्था को खतम कर दिया? आप खुद आरक्षित वर्ग से आते हैं, यदि इस तरह से आप आरक्षण व्यवस्था को खतम करने पर उतारू होंगे तो यह ठीक नहीं है।

आज के दैनिक भास्कर में खुला समाचार लिखा है कि 'राशन के दुकानदारों के लिए एससी और एसटी का आरक्षण खतम'। क्या यह सही है कि इस आरक्षण व्यवस्था को खतम करके दलितों पर कुठाराघात कर रहे हैं? मेरा एक ही सवाल है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा, आरक्षण की व्यवस्था पहले नहीं थी। बीच में इसको चालू किया गया। पीयूसीएल बनाम यूनियन आफ इण्डिया में न्यायाधिपति भागवत समिति की

(श्री परसादीलाल)

सिफारिशों के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उचित मूल्य की दुकानों का कम्प्यूटराइजेशन करने के सम्बन्ध में पारित आदेश, भारत सरकार के निर्देश एवं उचित मूल्य की दुकानों में महिला समूह व सहकारी समितियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन हेतु विभाग द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को निरस्त करके माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश थे, भागवत समिति की जो सिफारिशें थीं, उसी के अनुरूप राज्य सरकार को नई डीलरशिप अपाइन्ट करने के निर्देश दिये गये थे। भारत सरकार के निर्देश आये थे। फिर भी हमने जो परिपत्र जारी किया, आप उसको ध्यान से पढ़ें, टीएसपी एरिया में टीएसपी के लिए 50 परसेंट का आरक्षण रखा है। एससी वालों का भी रखा है। सहरिया क्षेत्र में सहरियाओं के लिए हमने 50 परसेंट दुकानें आरक्षित रखी हैं। भारत सरकार इसके लिए अण्डरटेकिंग दे चुकी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आरक्षण व्यवस्था को कहीं भी, कोई कानून में नहीं है, कोई रूल्स में नहीं है। यह एक व्यवस्था लागू की गई थी भारत सरकार के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, भागवत समिति की रिपोर्ट के बाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भागवत समिति की रिपोर्ट को सभी राज्य सरकारों को लागू करवाने के लिए भारत सरकार से अण्डरटेकिंग ले ली कि आप यह प्रायोरिटी रखेंगे आरक्षण में, डीलर आपाइन्टमेंट में। पहली ग्राम सेवा सहकारी समितियां, दूसरी ग्राम पंचायतें, तीसरी एसएजी ग्रुप, इनके अलावा किसी को कोई डीलरशिप नहीं दी जाएगी। क्या सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश नहीं मानेगी? आप दलितों के बारे में कह रहे हैं, माननीय सदस्य, सुप्रीम कोर्ट इसकी मानिटरिंग कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश होंगे उनकी सरकार अक्षरश: पालना करेगी।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, पीयूसीएल बनाम वाधवा के आदेश 27.04.2012 को हो गये थे, उसके बाद किन कारणों से विज्ञप्ति जारी करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को नहीं लिया गया? पांच-पांच, छह-छह दुकानों का कोटा उनका आरक्षण व्यवस्था के पहले निर्धारित था। उनसे मंथली लेने के लिए, मैं खुला कह रहा हूं। विज्ञप्ति जारी करके डर दिखा कर एक साल से इस व्यवस्था को बन्द करके पांच-पांच, छह-छह दुकानों की जगह एक दुकान आबंटित कर दी है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को कोई कन्फ्यूजन हो रहा है। मैंने आपको कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, भारत सरकार से अण्डरटेकिंग लिया है और सभी राज्य सरकारों ने अण्डरटेकिंग दिया है जिसके परिप्रेक्ष्य में हमने अभी एक आर्डर निकाला है। अण्डरटेकिंग भारत सरकार दे चुकी। हमारी जो डीलरशिप की व्यवस्था है प्राइवेट की, भारत सरकार ने इसको पूरे देश में समाप्त करने के लिए कहा है। प्राइवेट डीलरशिप किसी को भी नहीं दी जाएगी। जो हमारी सहकारी संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, महिला स्वयं सहायता समूह हैं, इन तीन कैटेगरी के अलावा कहीं भी किसी को डीलरशिप नहीं देंगे। इसलिए इसमें किसी का लेना-देना क्या है? स्पष्ट आदेश जारी कर दिया, ज्योंही भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला। इसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें इसकी शत-प्रतिशत पालना करें। उसके परिप्रेक्ष्य में एक आर्डर सरकार ने निकाल भी दिया है 06.03.2013 को। अब जो भी कोई डीलरशिप लेगा, आबंटन के लिए न तो सलाहकार समिति की जरूरत है, न विज्ञप्ति जारी करने की जरूरत है। जहां भी दुकानें रिक्त होंगी, वहां पर ग्राम पंचायतें डीलरशिप ले लें, ग्राम सेवा सहकारी समितियां ले लें, महिला स्वयं सहायता समूह ले लें। न किसी नेता की सिफारिश है, न किसी सलाहकारी समिति की सिफारिश है। हमारी सरकार बिलकुल ट्रांसपेरेंसी से कर रही है। इसमें कौनसी घूस की बात हो गई? आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई घूस नहीं है। जिसको भी जरूरत हो, इनमें से कोई भी एप्लीकेशन लगाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपने डीलरशिप की पूरी व्यवस्था खतम तो कर दी न? (व्यवधान) ठीक है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह निर्देश मिला है। ज्योंही सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलेगा, जिस दिन भी मिलेगा, हम उसी दिन प्राइवेट डीलरशिप को समाप्त कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: और कोई पूरक प्रश्न नहीं है?

एक माननीय सदस्य: आज तो बड़ा संतुष्टिपूर्वक दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं तो पूरी छूट दे रहा हूं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): प्रश्न ही नहीं हैं इनके पास।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): प्रश्न संख्या 166.

श्री अध्यक्ष: नाम तो पुकारने दो। नाम तो पुकारूं।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): सुओ मोटो जान लिया कि आप यही पुकारेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रभुलाल सैनी।

'मनरेगा' योजनान्तर्गत अनियमितता के दर्ज प्रकरणों की जांच

166. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) एवं **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:-

(1) नरेगा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 2009 से दिसम्बर, 2012 तक कितने प्रकरण गबन तथा अनियमितता के पाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 5 जिला कलक्टरों के विरुद्ध भी उक्त अवधि के दौरान अनियमितताओं/राशि का दुरुपयोग के मामले प्रकाश में आये थे? यदि हां, तो उक्त प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई? जांच रिपोर्ट मय अभिशंसा तथा आरोप की प्रति मय जांच परिणाम की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई तथा कितने कर्मचारी/अधिकारियों के विरुद्ध जांच विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री (श्री महेन्द्र जीत सिंह): (1) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रदेश में 2009 से दिसम्बर, 2012 तक गबन/अनियमितता के 695 प्रकरण पाये गये।

(2) जी हां। प्रकरण में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर जांच करायी गयी। जांच रिपोर्ट मय अभिशंसा एवं जांच परिणाम की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) उक्त अवधि के दौरान प्रदेश में कुल 559 एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं एवं 349 कर्मचारी/अधिकारियों के विरुद्ध जांच विचाराधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने खण्ड 1 में कहा कि 695 ऐसे प्रकरण हैं जो कि अनियमितता और गबन के हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इनमें से कितने प्रकरण जन

(श्री प्रभुलाल सैनी)

प्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ हैं? ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें प्रोसीजरल कमी दिखाकर आपने उनको चेतावनी देकर छोड़ा है? और कितने मुकदमों में एफआईआर दर्ज हुई? मंत्री महोदय, साथ ही मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि वित्त विभाग के आदेश 06.12.1997 क्या हैं? उसके बारे में आप सदन को जानकारी देंगे।

खण्ड 2 के सम्बन्ध में मेरा आपसे प्रश्न यह है कि तत्कालीन पंचायती राज मंत्रीजी द्वारा मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र लिखा गया 12.12.2010 को, जिसमें उच्च स्तरीय अधिकारियों के द्वारा की गई जांच के बारे में असहमति प्रकट करते हुए उन्होंने कहा था कि यह प्रकरण रोंगफुल इंटेंशनल मेंसरिया से इंगित है। इसके बाद आपके द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? इसके बारे में भी आप सदन को बताने की कृपा करें।

इसके अलावा पांच कलक्टर्स जो जिला कोआर्डिनेटर नरेगा हैं, उनके बारे में आपने जांच करवायी है। माननीय मंत्री के द्वारा एक पत्र लिखा गया था, ट्री गार्ड खरीदने पर झालावाड़ जिले में गम्भीर अनियमितता हुई थी, उसके जांच परिणाम क्या रहे? यह भी जानकारी सदन को आप देने का कष्ट करें।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किन-किन अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है या जांच प्रक्रियाधीन है, के बारे में पूछा है। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि कुल इसमें 687 व्यक्ति सम्मिलित हैं जिनमें से 18 कार्यक्रम अधिकारी, 115 ग्राम सचिव, 18 ग्राम रोजगार सहायक, 34 तकनीकी कार्मिक, 49 मेट और 132 सरपंच इस तरह से अलग-अलग व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हैं।

दूसरा प्रश्न पांच आईएएस अधिकारियों के सम्बन्ध में पूछा गया है, मैं कहना चाहूंगा कि विधान सभा के आठवें सत्र में प्रश्न संख्या 435 माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया द्वारा पूछा गया था जिसका उत्तर सदन में मैंने स्वयं दिया और सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी इसका जवाब दिया है इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं, इस प्रश्न का उत्तर और कोई शेष रहता नहीं है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच रिपोर्ट के अनुसार जिन जिला कलक्टर्स द्वारा इसमें अनियमितताएं बरती गयी हैं उसमें डूंगरपुर में 85 लाख 1640 रुपये, करौली में 51 लाख रुपये प्लांटेशन

(श्री प्रभुलाल सैनी)

खरीद के बारे में, दौसा में 198 कम्प्यूटर के लिए 91 लाख 1334, शिशु पालना 32 लाख 36688, शिशु पालना 21 लाख 57 हजार 7, यानी कुल 1 करोड़ 45 लाख रुपये, टोंक में कम्प्यूटर खरीद के लिए 1 करोड़ 41 लाख रुपये और हनुमानगढ़ में 72 लाख 21667 की वित्तीय अनियमितताएं बतायी गयी हैं।

माननीय मंत्रीजी ने जो पत्र लिखा उसके बारे में आपने नहीं बताया, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने अपनी नोटशीट में लिखा है मुख्य मंत्रीजी को, जिला कलक्टर डूंगरपुर, टोंक, हनुमानगढ़ एवं दौसा कम्प्यूटर खरीद तथा जिला कलक्टर झालावाड़ द्वारा ट्री-गार्ड की खरीद के सम्बन्ध में स्पष्ट अनियमितताएं पायी गयी हैं। योजनाओं से सम्बन्धित इन अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति की रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरकर्ता सहमत नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिन कलक्टर्स द्वारा कम्प्यूटर खरीद की गयी है उनके द्वारा डी.ओ.आई.टी. द्वारा जारी निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। जानबूझकर सीधे कम्पनी से क्रय नहीं कर के वितरक से क्रय किया गया जो इनके रांगफुल इन्टेंशन और मेंसरिया को इंगित करता है। इसी प्रकार ट्री-गार्ड खरीद की अनियमितता पायी गयी है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इनके उपरोक्त कृत्यों को ignorance and inexperienced समझ कर नैग्लिजेंस मान लेना उचित नहीं है। हमें यदि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है, नरेगा के भ्रष्टाचार को रोकना है तो यह आवश्यक है कि इन कलक्टर्स के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। यह आपका पत्र है 22.12.2010 का।

मंत्री महोदय, मैं आपसे इस पत्र के माध्यम से यह जानकारी चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस पर क्या कार्यवाही की? इस पर जब कार्यवाही हुई तो आपने जिन पांच कलक्टर्स की बात की है, झालवाड़ कलक्टर के बारे में आपने कहीं भी इसमें अंकित नहीं किया। कम्प्यूटर खरीद में इनको खरीद करना चाहिए था, डी.जी.एस. एण्ड डी. यानी डाइरेक्ट्रेट जनरल आफ सप्लायर्स एण्ड द डिस्पोजल से, जो इसका मुख्य काम है। A Central Purchase and the Quality Assurance Organisation of the Govt. of India or the State Government. मेरा आपसे यह कहना कि इन्होंने डी.जी.एस. एण्ड डी. के माध्यम से नहीं खरीदे, सम्बन्धित एजेंट से नहीं खरीदकर तीसरी फर्म से खरीदे। क्या जी.एफ. एण्ड ए.आर. नियमों की परिधि में ये आते हैं या नहीं आते हैं? आप इसका जवाब दें।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर मेरा यही बात कहना है। माननीय सदस्य जो बात पूछ रहे हैं यह बात तो पहले हम कह चुके हैं, रिकार्ड में भी आ चुका है। उच्च स्तर पर चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में और अतिरिक्त सैक्रेटरी वित्त और प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज की सदस्यता में एक तीन अधिकारियों की सर्वोच्च कमेटी के द्वारा जांच हुई है। उस जांच के बाद में जो जांच रिपोर्ट आयी है उस जांच रिपोर्ट के आधार पर उन तमाम अधिकारियों को डी.ओ.पी. सैक्रेटरी ने हिदायत दी है और यह कहा है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करें। यह बात क्योंकि सदन में पहले हो चुकी है, इसलिए जहां तक माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, मुझे आगे बोलने की इसमें आवश्यकता नहीं है।

जहां तक वो झालावाड़ के बारे में पूछ रहे हैं, झालावाड़ कलक्टर के बारे में जांच हुई है लेकिन झालावाड़ कलक्टर को बिलकुल उन्होंने दोषी नहीं माना है। यह रिकार्ड भी पूर्व में आ चुका है।

इसलिए मैं सदन से यही बात कहूंगा कि सर्वोच्च स्तरीय कमेटी की जांच रिपोर्ट और सदन के नेता मुख्य मंत्रीजी के बाद में कोई चीज बाकी नहीं रहती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिए, जवाब आने दीजिए। मैं अलाउ नहीं करूंगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा, इस तरह है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मेरा ही विधान सभा में प्रश्न था और उस पर उस समय के जो मंत्री थे उन्होंने अपनी रिकमन्डेशन में लिखा है कि इन सारे अधिकारियों ने इसमें बदनीयती से अपने निर्णय लिये इसलिए इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

विषय जब यहां हाउस में आया तो मुख्य मंत्रीजी ने एक कमेटी की घोषणा की और उस कमेटी के द्वारा जांच हुई। इसमें जो कमेटी ने रिकमन्डेशन की है - ''The Committee while absolving the Collectors, has recommended that the Administrative Department conduct follow up enquiry to fix responsibility of other officials involved for various acts of omission and commission.'' मतलब कमेटी यह रिकमण्ड करती है कि इसमें अनियमितता हुई है, इस अनियमितता में जो और भी अधिकारी इसके लिए दोषी पाये जाते हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही करो। उसी के तहत आपने जो कार्यवाही की है, इसमें आप बता रहे हो कि 349 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हुई है। मैं इसमें से जानना चाहता हूं कि जिस कमेटी ने अपनी रिकमन्डेशन की'

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

''Computers were purchased under NREGS in the districts of Dungarpur, Tonk, Hanumangarh and Dausa in which irregularities were allegedly committed...'' कमेटी की रिपोर्ट ही पढ़ रहा हूं, ''These irregularities commonly covered purchase of computers from firms not authorized by DGS&D i.e. from local firms, (though at DGS&D rates), which is violative of the GF&AR as well as extant instructions of Finance Department. Since almost all purchases of computers under NREGSs around that time occurred under the similar circumstances.....'' यह जो परचेज कमेटी का हैड है नरेगा का यह कौन है? अगर नरेगा का परचेज हैड कलक्टर है तो नीचे के अधिकारियों को आप कैसे दोषी मान सकते हो और कलक्टर को कैसे छोड़ सकते हो?

यह बदनीयती से की हुई जांच है। अपने सेम कैडर के अधिकारियों को बचाने के लिए इस प्रकार का निर्णय लेकर नीचे के गरीब लोगों को, जिनका कोई दोष नहीं, उनको तो मारने का काम कर रहे हो और जो लोग इसके मूल दोषी हैं, जिन्होंने इसमें हेराफेरी का है, नहीं जानता क्या कलक्टर, नरेगा के नियम नहीं पढ़ता है क्या? अगर नरेगा के नियम कलक्टर पढ़ता है और उसके बाद इल्लीगल परचेज करता है, बिना आथोराइज डीलर से करता है तो इसमें मुख्य रूप से दोषी कलक्टर है।

मैंने उस दिन कहा था, हम लोगों की निगाह में बड़े आदमी को बचाने का स्वभाव बन गया। छोटे-छोटे को मार कर टांग दो और कह दो कि हमने बहुत न्याय कर दिया। यह न्याय गलत होगा। अगर कलक्टर दोषी नहीं तो इनमें से एक भी व्यक्ति को दोषी नहीं मान सकता। कौन समझेगा इस बात को? आप बताइये, कौन है हैड परचेज कमेटी का और किसके दस्तखत से यह परचेज हुआ? उसका दोष क्यों नहीं है? यह समझ आना चाहिए। कोई रिपोर्ट बनाओ, कमेटी बनाओ। मैं तो समझना चाहता हूं, जब कभी भी मंत्री दस्तखत कर देता है न, तो चीफ सैक्रेटरी उसके ऊपर का अधिकारी नहीं होता है। यह अगर जाएगा तो आपका निर्णय कैबिनेट में जाएगा, मुख्य मंत्रीजी के पास जाएगा। वहां से जब फाइल ओके होगी तब इस फाइल को ओके माना जाएगा। बाकी तो मिनिस्टर का आर्डर आज भी स्टैंड करता है, वो वेकेट नहीं हो सकता।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, इस मामले में पहले बहस हो चुकी। सदन के नेता ने जो जवाब दिये हैं 01 मार्च, 2012 को, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ईर्रेगुलरिटी अलग बात होती है, करप्शन अलग बात

(डा. रघु शर्मा)

होती है। (व्यवधान) यह बात पहले उठायी जा चुकी है सदन के अन्दर, जवाब सदन के नेता द्वारा दिया जा चुका है। (व्यवधान) कोई करप्शन नहीं हुआ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कमेटी बना देने से ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): कोई करप्शन नहीं हुआ ...(व्यवधान) इर्रेगुलरिटी अलग बात है ...(व्यवधान) यह जवाब है सदन के नेता महोदय का इसी सदन के अन्दर। (व्यवधान) इसके बारे में आप बता दीजिए, क्या जवाब है ...(व्यवधान) कोई करप्शन नहीं हुआ, कोई स्कैण्डल नहीं हुआ, यह सदन के नेता ने कहा है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इस पर प्रोसीजर को पूरा करना पड़ेगा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह जवाब है सदन के नेता का इस हाउस के अन्दर ...(व्यवधान) इसके बारे में आप बता दीजिए ...(व्यवधान) कोई करप्शन नहीं हुआ, कोई स्कैण्डल नहीं हुआ ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जो हुआ है ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इर्रेगुलरिटी हो सकती है? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप चोरों को बचाना चाहते हो क्या? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह जवाब की कापी है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मंत्री को बोलने दो। (व्यवधान) चोरी हुई है चोरी। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सदन के नेता का जवाब देख लीजिए। (व्यवधान) आप इस हाउस की प्रोसीडिंग्स देख लें। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ का सदन कूप में आगमन)

आपको वैल में आने की अनुमति है क्या? आप कितनी बार बिना अनुमति के खड़े होते हैं। मैं भी सरकारी मुख्य सचेतक हूं, मेरा भी अधिकार है। मैं भी बात कह सकता हूं यहां पर, आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है मेरे को, माननीय तारानगर से आने वाले सदस्य।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): +++ को बचाना चाहते हो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: संसदीय मंत्रीजी कुछ बोल रहे हैं, इसका ध्यान रखें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): कलक्टर और ...(व्यवधान) +++ को बचाना चाहते हो।

श्री अध्यक्ष: संसदीय मंत्री बोल रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप +++ हो और +++ को बचाना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सुन लो न, क्या दिक्कत है!

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, न तो सदन का कोई नियम और न कोई परम्परा इस बात की इजाजत देती है कि एक ही प्रश्न को बार-बार उठाया जाए। सदन के नेता इस बाबत काफी विस्तार से जवाब दे चुके हैं। अब उसी इश्यू को बार-बार उठाकर परम्पराएं तोड़ने का काम किया जा रहा है। (व्यवधान) मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि इस तरीके की बात को ...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ...(व्यवधान) सुरेश कलमाड़ी तो सेण्टर ने माफ कर दिया और यहां कलक्टर माफ कर दिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कोई परम्परा नहीं तोड़ रहा हूं मैं। ...(व्यवधान) मैं लीगल सवाल-जवाब कर रहा हूं आपके सामने। (व्यवधान) अगर कोई मंत्री ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे ही निवेदन कर सकता हूं। अगर कोई मंत्री अपनी किसी प्रकार की फाइल पर रिकमण्डेशन कर दे, उसके ऊपर कोई जांच कमेटी चीफ सैक्रेटरी या किसी की बैठे? वे सब उसके लोअर हैं। मान लो, उन्होंने जांच कर भी ली तो इस जांच रिपोर्ट का या इसको कोई एण्डोर्स करेगा तो या तो कैबिनेट करेगी या मुख्य मंत्री ही करेगा। तो यह इनका आर्डर फाइनल आर्डर नहीं हो सकता क्योंकि हाउस में कमेटी के गठन की घोषणा स्वयं मुख्य मंत्री ....

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जो नेता ने कह दिया वह तो फाइनल है। आपको सारा जवाब दे चुके पहले ...(व्यवधान) गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आया है ...(व्यवधान) पूरा जवाब है ...(व्यवधान) सदन के नेता ने कहा, कोई करप्शन नहीं ...(व्यवधान) कोई स्कैण्डल नहीं, कोई इर्रेगुलरिटी नहीं।

(डा. रघु शर्मा)

इर्रेगुलरिटी की जांच हो गयी ...(व्यवधान) चीफ सैक्रेटरी के लेवल पर इर्रेगुलरिटी की जांच हो गयी। (व्यवधान) अब क्या चाहते हैं आप लोग? (व्यवधान) हर साल यह सवाल उठाएंगे और हर साल सरकार जवाब देगी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह जानना चाहता हूं कि ...(व्यवधान) यह सहमति राजस्थान के मुख्य मंत्री ने दी है क्या? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप सदन के नेता का जवाब सुनो। आप पढ़ लो इसको अच्छी तरह से। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): पढ़ ली। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): जिस बात पर पहले निस्तारण हो चुका है उसको बार-बार लाकर समय खराब न करें। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा हाथ के इशारे से अंकित नहीं करने के निर्देश)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आगमन)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

(माकपा के माननीय सदस्य श्री पेमाराम द्वारा बहिर्गमन)

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जांच कहां से करेंगे? इस प्रकरण में जांच की गुंजाइश नहीं है। केवल मुख्य मंत्री या कैबिनेट ही इस जांच रिपोर्ट को ओ के कर सकते हैं। यदि मुख्य मंत्री ने इस जांच रिपोर्ट को ओ के कर दिया तो वो हाउस में रख दो, +++ और अगर उन्होंने नहीं की तो अधिकारियों की रिपोर्ट मंत्री की रिपोर्ट से ऊपर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष:, मंत्रीजी कह रहे हैं, मैंने जवाब दे दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हाउस में कमेटी बनी थी। हाउस में यह विषय उठा था और हाउस में ही कमेटी बनी थी। इस कमेटी का निस्तारण दो ही रास्ते से हो सकता है। (व्यवधान) अब आप चले जाओ। एक सैकिण्ड, आप चले जाओ। आ जाओ, आ जाओ।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है। समाप्त हो गया समय...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह इस स्तर पर नहीं हो सकता है। हाउस में जो कमेटी का गठन हुआ, या तो स्पीकर के दस्तखत से यह फाइल निपट सकती है, या कैबिनेट और मुख्य मंत्री के दस्तखत से फाइल निपट सकती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें, आसन पांवों पर है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बाकी इस फाइल का निस्तारण हो नहीं सकता। इस तरह कलक्टर को बचाने का जो षडयंत्र सरकार ने किया, मैं और मेरा दल आज भी विरोध करते हैं, कल भी करेंगे और बाद में भी करेंगे। बहिर्गमन करते हैं इस बात पर। यह क्या बात है ?

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

1. डा. जसवन्त सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में मोढण से नानगवास, गिगलाना, रायसराणा, विधाना जाट, हरियाणा बार्डर तक सड़क के बिलकुल टूटी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री रविन्द्र सिंह बोहरा एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर मिलने में काफी देर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्रीमती अनिता भदेल एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तोपदड़ा (अजमेर) में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत एस सी/एस टी के छात्रावास के लिये बजट आबंटन में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्रीमती संजना आगरी एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से तहसील रायपुर स्थित झिलमिल बांध से बिरांटियाकलां के काश्तकारों को सिंचाई के लिये पानी दिये जाने के सम्बन्ध में।
5. श्री कानसिंह कोटड़ी एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सामुदायिक चिकित्सालय व प्राथमिक चिकित्सालयों का विद्युत सम्बन्ध विच्छेद बजट अभाव में होने की कार्यवाही को रोकने के सम्बन्ध में।
6. श्री कालीचरण सराफ एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
7. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से केकड़ी तहसील में एक मार्बल खान को बचाने के लिये सावर कस्बे से चितीवास गांव तक की निर्माणाधीन सड़क के मार्ग को बदलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
8. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से जिला पाली के सटडाट संयड बांध के कैचमेंट क्षेत्र में अवैध निर्माण होने से काश्तकारों में व्याप्त भारी रोष के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

9. डा. फूलचन्द भिण्डा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन, छठे वेतनमान का 40 प्रतिशत एरियर न देने, सिफारिश अनुरूप वेतनमान नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के लागू होने के उपरान्त भी राज्य में बालकों को गैर सरकारी विद्यालयों में प्रवेश नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। बाहर जाना है तो बाहर जाएं।

11. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में विगत 6 दिन से अराजकता तथा कानूनविहीन वातावरण बना होने के सम्बन्ध में।

12. श्री ओटाराम देवासी, सदस्य की ओर से सिरोही जिले को नर्मदा सिंचाई परियोजना से जोड़ने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

13. श्री हरिसिंह रावत एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम की ग्राम पंचायत कालागुमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन आदि की राशि का पोस्टमैन द्वारा 5-6 माह से भुगतान नहीं कर खुर्द-बुर्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

14. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में आधार कार्ड बनाने में हो रही अव्यवस्था से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

15. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, सीकर द्वारा किसानों के हितों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

16. श्री राधेश्याम गंगानगर एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से श्रीगंगानगर में मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा करने के उपरान्त

(श्री अध्यक्ष)

भी कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री हरिसिंह रावत, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्री पेमाराम एवं श्री राधेश्याम गंगानगर को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) डा. जसवन्त सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में जैनपूरबास पहाड़ी होते हुए बानसूर जाने वाली सड़क के टूटे होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री अनिल जैन, सदस्य की ओर से बकानी उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के कस्बा गोविन्दगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में कतिपय संकाय और खोलने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चाकसू की सभी पंचायतों सहित चाकसू नगर में बसों का सुचारु संचालन करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री ग्यारसाराम कोली, सदस्य की ओर से तहसील रूपवास के ग्राम खेरिया बिल्लोच से उत्तर प्रदेश सीमा एवं नयागांव से उत्तर प्रदेश सीमा तक रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती संजना आगरी, सदस्य की ओर से राजकीय चिकित्सालय सोजत सिटी, रायपुर व गांवों के पी एच सी व सी एच सी केन्द्रों पर चिकित्सकों की नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर में सड़कों की बदहाल स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा, सदस्य की ओर से नागौर शहर में

(श्री अध्यक्ष)

विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा मीटर जांच के नाम पर मनमानी करने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती अनीता सिंह, सदस्य की ओर से कस्बा नगर के वार्ड नं. 1, 2, 3, 4 एवं 5 की पेयजल की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

यह कहां सीखा है आपने ?

(10) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर के राजकीय महिला चिकित्सालय (जनाना अस्पताल) में प्रसूताओं को कलेवा योजना का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से पुलिस थाना काछोला के अव्यावहारिक क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करवाने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

यह पूर्व मंत्री भी हैं। आप तो बहिष्कार कर गये थे। (व्यवधान) पर आसन पांवों पर होता है तो अन्दर आते हैं? फिर बैठ गये, फिर खड़े हो गये, फिर बैठ गये। यह सिस्टम आप ही बिगाड़ रहे हो...(व्यवधान) हे प्रभु, इन्हें सद्‌बुद्धि दो..(व्यवधान) आप भी उसी संज्ञा में हो, आसन पांवों पर हो और खड़े होकर मांग रहे हो। आसन पांवों पर हो तब भी? नहीं, मैं बीच में आपको बोलने दूं आसन पांवों पर हो तो? ये भी सैकिण्ड टर्म हैं।

(12) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से तहसील राजसमन्द के राजस्व ग्राम धोइन्दा के खसरा नं. 3616, 3539 व 3539/1 से 3539/12 की भूमि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा अवाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री हरिसिंह रावत। (व्यवधान) आसन पांवों पर है। माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। सुनाई नहीं दिया आपको? मंत्री भी रहे हो आप, नियमों की जानकारी नहीं है? बड़े वरिष्ठ भी हो। हरिसिंह रावत। (अनुपस्थित) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। (अनुपस्थित) श्री पेमाराम।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, आज केकड़ी में लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं...

श्री अध्यक्ष: अलाउ नहीं। अंकित नहीं। अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम। अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, सीकर द्वारा किसानों के हित विरुद्ध कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक ऐसे विषय पर सरकार का और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...

(12.07 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, सीकर द्वारा काश्तकारों के हितों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। क्योंकि सहकारिता की डिमाण्ड मुखबन्द में है इसलिये मैं इस विषय को आपकी आज्ञा से यहां ला रहा हूं। मैं सरकार और मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हमारे सीकर जिले में सहकारिता एक सबके लिये और सब एक के लिये है। अभी सरकार ने बजट में भी घोषणा की है कि एक लाख रुपये तक हम लिमिट बढ़ाएंगे। किसान को फसली ऋण देंगे, किसान के लिये बढ़िया काम करेंगे। मगर सीकर जिले में सहकारी बैंक जो कार्यवाही कर रहा है वह न केवल सरकार के नियमों के विरुद्ध है, अपितु सीकर जिले के किसानों के भी घोर विरोध में है। ऐसे तुगलकी आदेश रहे हैं जैसे एक ताजा उदाहरण मेरे निर्वाचन क्षेत्र का गूठ़डा तकेलान गांव है जो आज तक सीकर बैंक से संचालित था, उसे 40 किलोमीटर दूर दांतारामगढ़ ले जाने का उन्होंने निर्णय किया है। लोगों ने तब राय दी और सुझाव दिया तो बैंक के प्रशासक मंडल और संचालक मंडल ने इस चीज को नहीं मानने का काम किया।

(श्री पेमाराम)

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, तरह-तरह के घोटाले, तरह-तरह की अनियमितताएं। सूचना के अधिकार में जब हमने इनकी कार्यवाही निकलवाकर देखा तो इनके पास दो गाड़ियां थीं, एक गाड़ी फिर ले आये। दो गाड़ियां होने के बावजूद बोलेरो गाड़ी, बड़ा अफसोस होगा। गाड़ी निकलती है इनकी 16.10.2009 को शाम के 4.30 बजे, कम्पनी से नयी गाड़ी। और, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सूचना के अधिकार में लाग बुक मांगी है, लाग बुक भर रहे हैं सुबह 8 बजे से। जब कम्पनी से सूचना के अधिकार में मांगा तो कम्पनी कह रही है कि कम्पनी के शो-रूम से गाड़ी साढ़े 4 बजे बाहर निकली है। मैं नहीं समझ पाया कि इनके पास पहले कहां से गाड़ी आ गयी। उपाध्यक्ष महोदय, सीकर के डीटीओ आफिस से जब सूचना ली गयी तो डीटीओ इस गाड़ी आरजे-23 यूए 2941 को रजिस्ट्रेशन नम्बर देता है 17.11.2009 को और ये लाग बुक भरकर के सरकारी पैसे को विद्ड्रा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब इसकी शिकायत की गयी, मंत्रीजी से की गयी, जांच हुई तो सीकर के अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने जांच में दोषी पाया। धारा 30 के तहत 18 जून, 2012 को जांच रिपोर्ट भेज दी। संचालक मंडल तुगलकी फैसले लेकर सहकारिता के नियमों के विरुद्ध जो कर रहा है, संयुक्त रजिस्ट्रार, बैंकिंग को धारा 30 के तहत कार्यवाही करने के लिए रिपोर्ट भेजी गयी। आज तक उस रिपोर्ट पर कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं समझ पाया कि इसको अधिकारी दबा रहे हैं या इसमें कोई राजनीतिक दबाव है। हमारे सीकर जिले में इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, एक तरफ इनका ड्राइवर संविदा पर इनका कर्मचारी है, वह इनसे तनख्वाह ले रहा है और दूसरी तरफ उसी ड्राइवर को सहकारी समिति के फंड से भुगतान दें, दोहरा। संचालक मंडल जनता की सेवा करने के लिए, बैंक का संचालन करने के लिए बना है, लेकिन ये अपना दायित्व भूलकर सरकारी धन को हड़पने का काम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सीकर के सहकारी बैंक में सीकर के किसानों की हिस्सा राशि जमा है, उस पैसे का भारी दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार के स्तर पर उस पर रोक नहीं किया जाना दुर्भाग्य की बात है। ये सारे कागज मैंने सूचना के अधिकार में मंगा रखे हैं, इसमें भारी अनियमितता, भारी घोटाला है। नियमानुसार उच्च अधिकारियों के पास कार्यवाही करने के लिए शिकायत

(श्री पेमाराम)

भेज दी गयी, लेकिन जून, 2012 से लेकर अभी मार्च चल रहा है, उच्चाधिकारी उस पर कार्यवाही नहीं करें, उसको दबाकर बैठे हैं। यदि उस पर कार्यवाही करें तो सीकर का संचालक मंडल भंग हो जाएगा। अगर वह भंग हो जाता है तो कम से कम जनता के पैसे का दुरुपयोग तो नहीं करेंगे, घोटाला तो नहीं करेंगे। कोई राजनीतिक कारण है या प्रभाव है, क्यों कोई कार्यवाही नहीं हो रही है? वे सीकर के किसानों के पैसों का घोटाला कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को ऋण उपलब्ध कराना चाहिए, किसानों को सुविधा दी जानी चाहिए। उसके बजाय वे तुगलकी आदेश निकालकर इस गांव को उस बैंक से जोड़ देते हैं और दूसरे गांव को दूसरी बैंक से जोड़ देते हैं। जो सुविधाजनक है वह काम तो वे कर नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करो। काफी समय हो गया आपको।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, समाप्त तो कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: 2 मिनट की जगह 10 मिनट हो गये आपको। देख लो।

श्री पेमाराम (धोद): एक मिनट में समाप्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का और मंत्रीजी का आपके मार्फत ध्यानाकर्षित करते हुए चाहूंगा कि जांच हो गयी उसमें दोषी पाये गये, मंत्रीजी यह तो बताएं कि वह उन दोषियों को बचाने का काम करेंगे या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे? आप सीकर के किसानों का जो शेयर है उस बैंक में, उसको बचाने का काम करें। वर्ना वे तो घोटाला करके उस बैंक के पैसों को हड़पने का काम कर रहे हैं- चाहे ड्राइवर के नाम पर हड़पें, चाहे गाड़ी की झूठी लाग बुक भरकर पैसों को हड़पने का काम करें, चाहे नियम विरुद्ध काम करके किसानों के हितों पर कुठाराघात करें। मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी उनको रोकने का काम करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यहां बैठे हैं और संचालक मंडल जो ऐसे कुकृत्य कर रहा है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: राधेश्यामजी गंगानगर। केवल राधेश्यामजी गंगानगर... (व्यवधान)

(माननीय उपाध्यक्ष द्वारा हाथ के इशारे से अंकित करने से मना किया गया)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये, माननीय राधेश्यामजी। (व्यवधान) केवल माननीय राधेश्यामजी गंगानगर। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आपका अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) माननीय राधेश्यामजी, आप बोलिये, केवल आपका अंकित हो रहा है ... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से और सरकार से जानना चाहता हूं कि विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 50 के तहत ...(व्यवधान)...

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्रीगंगानगर में मेडिकल कालेज की घोषणा

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट घोषणा में मेडिकल कालेज गंगानगर में खोलने की बात कही है। उन्होंने 300 बैड के हास्पिटल जितने भी राजस्थान में हैं, उनमें मेडिकल कालेज खोलने की बात कही है जिसमें एल्फाबेटिकली गंगानगर का नाम 15वें नम्बर पर है।

उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर के मेडिकल कालेज की घोषणा आलरैडी सरकार कर चुकी है। वहां भूख हड़ताल हुई थी, वहां बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। आंदोलन 6 महीने तक चलता रहा, उसके बाद भूख हड़ताल हुई। उस भूख हड़ताल को बंद करवाने के लिए कलक्टर वहां गये। उन्होंने लिखित में पत्र दिया कि सरकार ने गंगानगर का मेडिकल कालेज मंजूर कर दिया है, 30 मार्च-राजस्थान दिवस पर इसका शिलान्यास होगा। लेकिन इस बजट के अन्दर उसका कोई उल्लेख नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार यह भी बताए, मंत्री महोदय यह भी बताने का कष्ट करें कि क्या 100 करोड़ रुपया किसी दानदाता ने सरकार को कभी दिया है? उसने यह भी आश्वासन दिया है कि मैं 400-500 करोड़ भी लगाने

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

के लिए तैयार हूं। वहां जमीन उपलब्ध है, साढ़े 350 बैड का हास्पिटल है। आप घोषणा कर रहे हो जयपुर में। जयपुर मेडिकल कालेज जहां पहले है, वहां खोलेंगे। जमीन वहां है नहीं, वहां 98 करोड़ रुपया भी दे रहे हो। लेकिन गंगानगर में किसी सुविधा का आपने जिक्र तक नहीं किया। दूसरी तरफ आप तारीख दे रहे हो। एक तरफ लड्डू बंट रहे हैं, पटाखे छूट रहे हैं। जुलूस निकाल रहे हैं हमारे भाई। कांग्रेस के विधायक वहां के और वहां के एम.पी. कांग्रेस पार्टी के वहां स्टेटमेंट दे रहे हैं। विज्ञापन छप रहे हैं लाख-लाख रुपये के। यह बताने का कष्ट करें कि क्या वह मेडिकल कालेज गुम हो गया। यह कहा था कि मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलेंगे। मेडिकल कालेज भी खोलेंगे, यूनिवर्सिटी भी खोलेंगे। बाद में यह कह दिया गया, राजस्थान के जो पार्टी के विधायक हैं कांग्रेस के और सांसद हैं, उन्होंने लिखकर दे दिया कि मेडिकल कालेज की गंगानगर में कोई जरूरत नहीं है। वह हाउस में मौजूद हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जानकारी चाहिए। यह जानकारी हाउस दे, सरकार दे कि क्या मेडिकल कालेज गंगानगर में खोलने का इरादा है अथवा नहीं है? क्या दानदाता ने 100 करोड़ रुपया दिया कि नहीं दिया? क्या एमओयू हो चुका? (व्यवधान) वहां अखबारों में आ गया कि एमओयू हो गया। मेडिकल कालेज की घोषणा हो गयी, पैसे आ गये।

श्री उपाध्यक्ष: बैठें, माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मैं ऐसे बैठने वाला नहीं हूं। मेरी बात का जवाब नहीं आया। वहां भूख हड़ताल हुई है। 4-6 महीने तक वहां लाखों की तादाद में लोग धरने पर बैठे हैं। जुलूस, जलसे हुए हैं। यह गंगानगर की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है, कुठाराघात है। इस धोखे पर या तो मुझे सरकार से जवाब दिलवाएं अन्यथा मैं आपके सामने धरने पर बैठूंगा।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): यह तो चाहते ही नहीं हैं। सरकार कालेज दे रही है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी बात समाप्त करिये। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मुझे जवाब दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष: आप बात तो समाप्त करोगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब इतनी बड़ी बात हो गयी उसके बाद बजट घोषणा में केवल जयपुर का नाम है कि मेडिकल कालेज दे दिया। इतने पैसे अलाट हो गये फाइनेंस में। जमीन लेने के लिए पैसा दे दिया। जहां जमीन है और मेडिकल कालेज के लिए सारी बातें पूरी करता है, उस जगह पर नहीं। इतना बड़ा धोखा!

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): इसका सरकार जवाब दे।

श्री उपाध्यक्ष: रिपीटीशन नहीं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सरकार जवाब दे मेरी बातों का।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी बोल रहे हैं। जवाब दे रहे हैं। आप विराजें। चिकित्सा राज्य मंत्रीजी।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आने वाले वरिष्ठ सदस्य काफी चिंता जाहिर कर रहे हैं। यह जो धोखे का आरोप लगा रहे हैं, इस तरह की जो बात कर रहे हैं यह बात अच्छी नहीं है। इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि सरकार निश्चित रूप से वहां पर मेडिकल कालेज खोलना चाहती है। आपने जो बात कही कि वहां के विधायकों और सांसद ने लिखकर दिया कि वहां कालेज की जरूरत नहीं है, यह बिलकुल मिथ्या आरोप है। इस बात का मैं खण्डन करता हूं। क्योंकि मुख्य मंत्रीजी ने या हमारे मंत्रालय ने कभी भी लिखकर नहीं दिया। अलबत्ता सारे के सारे विधायकों ने एक आवाज उठाकर ...(व्यवधान) मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये। आप नहीं सुनना चाहते क्या? आप सुनिये।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): मैं बता रहा हूं आपको। मैं समाचारपत्रों में नहीं जाना चाह रहा, कि उनकी सोच क्या थी लिखने के पीछे। जब भी मिले हैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से या आदरणीय दुरु मियां साहब से, तब एक ही बात इन्होंने उठाई है कि वहां पर सरकारी मेडिकल कालेज खोलना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार 15.2.2013 को जिन भामाशाह की आप बात कर रहे हैं, माननीय अग्रवाल साहब, उनके साथ बैठकर हमारी अधिकारियों की मीटिंग हुई और मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं पैसा सरकार को नहीं दूंगा, मैं वहां की आधारभूत संरचना

(डा. राजकुमार शर्मा)

है उसको बनाकर दूंगा। उन्होंने कभी भी चार सौ-पांच सौ, आप तो हो सकता है कि एक हजार करोड़ भी बता देंगे, अब हजार करोड़ के कितने शून्य लगते हैं, मुझे भी नहीं पता। आप लोग सिर्फ यह कहकर कि कोई दे रहा है, उनके साथ, बीडी अग्रवाल के साथ ...(व्यवधान) मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): मेरी बात सुनिये। मैं बता रहा हूं, आप जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपकी बात सुनूंगा, मेरी थोड़ी अर्ज सुन लीजिये ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो जाए। आपके सामने यहीं जब मीटिंग हुई थी...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बात नहीं सुनना चाहते। आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी व्यक्तिगत तरीके से रखिये। सदन में वही बात रखिये जो सत्य कथन हो।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि सरकार मेरी बात, मान लो आपको..

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, ऐसे नहीं। यह बहस नहीं है, व्यक्ति यहां पर कुछ नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह प्रार्थना है, मेरा मतलब तो मेडिकल कालेज से है...

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब चाहते हो? आप विराजिये। ऐसे नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सरकार कह दे कि हम इसमें खोल रहे हैं और 30 मार्च को हम इसका शिलान्यास कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब चाहते हो? आप विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ऐसे कैसे बैठ जाऊंगा?

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय सदस्य...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): वह जवाब दे रहे हैं, आप कह रहे हो बैठ जाओ, कैसे बैठ जाऊं?

श्री पेमाराम (धोद): मेरे वाला भी जवाब दे रहे हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव लगा हुआ था, दो मिनट का आप मौका दे दें। दो मिनट का ही।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय चन्द्रकान्ताजी, आप सुनिये। मैं चेयर पर नहीं था, माननीय अध्यक्षजी से ...(व्यवधान) आप विराजिये। आप सिस्टम को तो समझिये। आप बाहर थीं सदन में विराजमान नहीं थीं, अध्यक्षजी ने आपकी अनुपस्थिति दर्ज करा दी है। मेरे निर्णय को जब अध्यक्षजी नहीं बदल रहे हैं तो आप इसके लिए उनके वेश्म में जाकर मिल लीजिये। उन्होंने खुद आपकी अनुपस्थिति दर्ज की है। इसलिए इस प्रकरण को आगे नहीं उठाएं।

माननीय डाक्टर जसवन्त सिंह यादव। (व्यवधान) अब अंकित नहीं होगा।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) आप सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान) डाक्टर जसवन्त यादव। और किसी का नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल माननीय जसवन्त सिंह यादव। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, आप अलग से मिल लीजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर जसवन्त सिंह यादव।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैं सदन में माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रीजी जब जवाब दें, वह अपना स्पष्टीकरण दें, आसन को कोई भी एतराज नहीं है ...(व्यवधान) आप बात सुनिये। यह सदन के प्रोसीजर की बात है। मंत्रीजी जवाब दे रहे थे इस प्रकरण में, केवल दो मिनट में आपको अपनी बात कहनी थी, मंत्रीजी का जवाब आवश्यक नहीं था। चूंकि हित की बात है, स्टेट के डवलपमेंट की बात है तो मंत्रीजी जवाब दे रहे थे। मंत्रीजी पहली बात

(श्री उपाध्यक्ष)

इजाजत लिये बिना जब खड़े हुए, मैंने कहा कि बोलिये आप, अब उसके बाद में तीन-चार दफा आपने विघ्न डाला। आप खुद नहीं चाहते कि मंत्रीजी सरकार का जवाब दें। इसलिए कृपा करें। आप एक तो राधेश्यामजी और जो मंत्रीजी आपके पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, उनसे ज्यादा वरिष्ठ हो, आपको सदन के कायदे-कानून, नियम कंठस्थ हैं, इरादतन जैसे आदत होती है, सदन में इसके बाद भी आप बोल रहे हैं, जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। इसलिए कृपा करके मंत्रीजी चाहें तो दे दें। (व्यवधान) आप सुनिये। मंत्रीजी चाहें तो जवाब दे दें बाकी इस पर कोई एक्सप्लेनेशन, कोई जवाब नहीं होगा।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर में सरकारी मेडिकल कालेज खोलने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था हमारे प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा की अध्यक्षता में। 15.2.2013 को यह निर्णय लिया गया। उसमें जो हमारे दानदाता हैं, पर उन दानदाता के साथ विचार-विमर्श हुआ और एक एमओयू साइन करने की बात पर डिसीजन हुआ कि एमओयू साइन किया जाए। एमओयू साइन करने के पश्चात् उसको माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास भेजा जाएगा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करूंगा, पैसा सरकार को नहीं दूंगा। यह जो बात हुई वहां पर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो एम सी आई की गाइडलाइन के अनुसार जो चीजें जो आवश्यक हैं सरकारी मेडिकल कालेज के लिये, वहां पर वह बना दें, हमें आपत्ति नहीं है। जब एमओयू साइन हो जाएगा दानदाता के साथ तो राज्य सरकार निश्चित रूप से चाहती है कि वहां पर सरकारी मेडिकल कालेज खुले।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का मैं एक बार फिर खण्डन करना चाहता हूं। वहां के एमपी और सारे कांग्रेस के विधायक साहिबान, सबने पुरजोर शब्दों में माननीय मुख्य मंत्रीजी से अपील की है कि गंगानगर के अन्दर सरकारी मेडिकल कालेज खुलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डाक्टर जसवन्त सिंह यादव। (व्यवधान) आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? सिम्पल।

सूचना

विश्वविद्यालय/ कालेज शिक्षकों का विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षक हजारों की तादाद में पूरे प्रदेश से विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। वे अपनी मांगों के लिये कई बार सरकार से मिल चुके परन्तु सरकार ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस उपेक्षापूर्ण रवैये के खिलाफ आज हजारों शिक्षक यहां पर आये हैं विधान सभा के सामने। उनकी यह समस्या है कि कई वर्षों से चाहे कालेजों के हों या यूनिवर्सिटीज के...

श्री उपाध्यक्ष: आप संक्षेप में कहें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं दो मिनट में कह दूंगा। इनमें कई सालों से पद रिक्त पड़े हैं पर उसके बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। उसी प्रकार से नए यूजीसी वेतनमानों के बारे में आदेश जारी करते समय 60 प्रतिशत एरियर का भी भुगतान कर दिया, 2009-10 में और 2010-11 में बाकी 40 प्रतिशत एरियर का भुगतान करना था। तीन साल बीत गये, अभी तक उनको कोई भुगतान नहीं किया।

इसी प्रकार से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में जितने भी राज्य हैं, चाहे वह मध्यप्रदेश हो, चाहे उत्तरप्रदेश हो, बिहार हो, हर राज्य ने यूजीसी के निर्देशानुसार कालेज शिक्षकों के लैक्चरर के स्थान पर एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर, ये पदनाम कर दिये, परन्तु हमारे राजस्थान में उनके पदनाम परिवर्तित नहीं किये गये। इसी प्रकार से बार-बार मांग करते हुए भी कई राज्यों में रिटायरमेंट की एज 60 साल से 65 साल हो गई परन्तु यहां पर रिटायरमेंट की एज भी नहीं बढ़ाई जा रही है। इस प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनकी कई मांगें हैं, मैं उनको विस्तार से नहीं बताऊंगा, केवल पाइन्टेड बताऊंगा- महाविद्यालय शिक्षा में स्थायी निदेशक व अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति की जाए। लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों को परीवीक्षा काल में नियुक्ति की तिथि से स्थायी सेवा के सम्पूर्ण लाभ दिये जाएं।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर पर वैसे ही आप पर्ची देने के बाद ही बोलने की

(श्री रतन देसाई उर्फ देवासी)

इजाजत देते हैं। आपका तो भाषण ही हो गया। इतना कोई सीरियस पाइण्ट भी नहीं था।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): चयनित वेतनमान पात्रता सेवा में पूर्व में अन्यत्र की गई सेवा का भी समावेश किया जाए। आरईएस में आये शिक्षकों की यूजीसी वेतनमानों के एरियर की राशि का भुगतान एवं अन्य समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। इस प्रकार से उनकी 16-17 मांगें हैं। मेरा यह कहना है कि सरकार संवेदनशील होने का सबूत दे और शिक्षक जो आये हैं, उनके प्रतिनिधिमण्डल को बुलाकर बात करे और उनकी समस्याओं का समाधान करे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। डाक्टर जसवन्त सिंह यादव।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उनसे वार्ता तो करें। उनके प्रतिनिधिमण्डल को बुलाकर उच्च शिक्षा मंत्रीजी बात तो करें। आज वे सड़क पर खड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष: यह 131 नहीं है। (व्यवधान) अब कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) डाक्टर जसवन्त सिंह यादव।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बहरोड़ में जैनपुरबास पहाड़ी-बानसूर की क्षतिग्रस्त सड़क

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र बहरोड में जैनपुरबास पहाड़ी होते हुए बानसूर जाने वाली सड़क बिलकुल टूटी हुई है। यह सड़क क्षेत्र की मुख्य सड़क है जो तहसील मुख्यालय व जिला मुख्यालय को जोड़ती है, जिस पर वाहन तो क्या पैदल व्यक्ति भी नहीं चल सकता। इससे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कई वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं व कई जीवन लीलाएं समाप्त हो चुकी हैं। वाहन आते हैं तो धूल उड़ती है, इससे आम आदमी को परेशानी होती है और अस्थमा जैसे असाध्य रोग होने

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

का डर रहता है जिससे जनता में भारी आक्रोश है। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त गम्भीर समस्या का समाधान करावें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अनिल जैन।

बकानी उप तहसील का तहसील में क्रमोन्नयन

श्री अनिल जैन (खानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत बकानी उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने के विषय पर विशेष उल्लेख का प्रस्ताव।

महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 में विशेष उल्लेख के जरिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि खानपुर विधान सभा क्षेत्र में स्टेट समय में स्थापित बकानी उप तहसील राजस्थान की सबसे बड़ी उप तहसील है। इस उप तहसील में 25 ग्राम पंचायत, 175 ग्राम, 4 गिरदावर वृत्त एवं 29 पटवार मण्डल स्थापित हैं। बकानी उप तहसील मुख्यालय अपने तहसील मुख्यालय झालरापाटन से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र की जनता लम्बे समय से तहसील मुख्यालय के काफी दूर होने से पीड़ित व परेशान चली आ रही है तथा लम्बे समय से अपने उप तहसील मुख्यालय को तहसील मुख्यालय में बदलने के लिए आवाज उठा रही है, आंदोलन कर रही है। मेरे द्वारा इस बाबत विधान सभा में प्रश्न उठाया गया था किन्तु सरकार द्वारा 1992 में मजीठिया कमेटी के मानदंडों का हवाला देते हुए वर्तमान में बकानी को तहसील मुख्यालय में बदलने का विचार नहीं होने से अवगत कराया गया। मजीठिया कमेटी की राय अनुसार नवीन तहसील मुख्यालय हेतु कम से कम 40 पटवार मण्डल एवं इसी अनुपात में भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त होना आवश्यक होना चाहिए। सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में झालावाड़ जिले में ही एक उप तहसील मुख्यालय को तहसील में क्रमोन्नत किया गया है जिसके अन्तर्गत मात्र 14 पटवार मण्डल, 14 पंचायतें, 2 भू-अभिलेख निरीक्षण वृत्त एवं 99 ग्राम ही स्थित हैं। अब सरकार अपने फैसले को सही साबित करने के लिए निकट की तहसीलों के ग्राम तोड़-मरोड़ कर मापदंडों को पूरा करने पर आमादा हो रही है। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि झालावाड़ जिले में मात्र 14 पटवार मण्डल वाली उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया गया जब कि स्टेट समय की प्रदेश की सबसे बड़ी उप तहसील बकानी को तहसील में क्रमोन्नत नहीं किया

(श्री अनिल जैन)

गया? बकानी क्षेत्र की तहसील होने की पात्रता नवीन तहसील असनावर से कई गुना ज्यादा थी। सरकार द्वारा की गई इस प्रकार की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। ईमानदारी का दम भरने वाली इस सरकार में कतई ईमानदारी प्रकट नहीं होती है। वर्षों से क्षेत्रवासी बकानी उप तहसील को तहसील बनाने हेतु लगातार मांग कर रही है। अब क्षेत्र की जनता में आक्रोश पैदा हो गया है और वह आंदोलित हो रहे हैं। यह आवश्यक हो गया है कि क्षेत्र विशेष बकानी की भौगोलिक स्थिति, आम जनता की सुविधा एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उप तहसील बकानी को नवीन तहसील में क्रमोन्नत किया जाए।

मैं उक्त विषय पर प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख कर रहा हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा।

रामगढ़ के राजकीय महाविद्यालय, गोविन्दगढ़ में संकायों में बढ़ोत्तरी

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम, 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय, विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के कस्बा गोविन्दगढ़, जिला अलवर में पिछले 15 वर्ष से राजकीय महाविद्यालय कार्यरत है। सौभाग्य की बात है कि यह राजकीय महाविद्यालय महामहिम स्व. श्री भैंरोसिंह शेखावत ने विशेष रूप से प्रारम्भ किया था। किन्तु अत्यन्त पीड़ा का विषय है कि पिछले 15 वर्ष से इस राजकीय महाविद्यालय में मात्र 4 विषय हैं जो अध्यापन हेतु कार्यरत रहे हैं। यहां 760 विद्यार्थी हैं। यह इस क्षेत्र का एक मात्र महाविद्यालय है। इसमें कामां विधान सभा क्षेत्र व नगर (भरतपुर) विधान सभा क्षेत्र के भी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। उक्त महाविद्यालय में निम्न विषय खोलने का कष्ट करें:- 1. इतिहास, 2. भूगोल, 3. अंग्रेजी लिटरेचर, 4 ड्राइंग-पेंटिंग, 5. होम साइंस। उक्त विषयों के खुलने से यहां पढ़ने वाली 400 छात्राओं को भी काफी लाभ मिलेगा। वैसे भी सरकार महिला शिक्षा को बढ़ोतरी हेतु बहुत प्रचार करती है। इस महाविद्यालय में उक्त विषयों को अगले नये सत्र से शीघ्र खोलने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीया श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा।

चाकसू में बस सेवा का सुचारू संचालन

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि परिवहन मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय सार्वजनिक परिवहन सुविधा से जोड़ा जाएगा, परन्तु इस पर पिछले 4 वर्ष में भी अमल नहीं हुआ। मंत्रीजी को कई बार इस समस्या के बारे में सूचित किया गया लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। चाकसू विधान सभा क्षेत्र में 4 साल पहले प्रत्येक पंचायत में बस सुविधा उपलब्ध थी किन्तु आज ग्रामीण जनता इतनी परेशान है कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।

हजारों की संख्या में ग्रामीण जनता तथा छात्र-छात्राओं का जयपुर में पढ़ने तथा अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए आना जाना-लगा रहता है। किन्तु बसों की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरन अवैध रूप से चलने वाली जीपों व अन्य निजी वाहनों के माध्यम से आना पड़ता है। इन वाहनों के ओवरलोड सवारियां लेने की होड़ के कारण भयंकर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीणों व छात्र-छात्राओं के एक्सीडेंट हो चुके हैं। उक्त बातों को ध्यान में रखकर बसों का संचालन पंचायत तक करने का आदेश दिया जाए।

जयपुर से टोंक जाने वाली बसें भी चाकसू बस स्टैण्ड पर नहीं रुकतीं। और तो और, पूर्व में टिकिट विंडो चालू थी, परन्तु वर्तमान में बंद पड़ी है। जनता को परेशानी होती है कि हम जाएं तो किस साधन से जाएं। शिवदासपुरा, शीतला, चाकसू बस स्टैण्ड पर सभी आने-जाने वाली बसों का ठहराव हो। चाकसू से कोटखावदा, गरूड़वासी, ठिकरिया मीणान, ठिकरिया गुजरान, छांदेल पंचायतों तक संचालन हो। उक्त सभी ग्राम बड़ी पंचायतों में आते हैं तथा इनकी आबादी भी काफी संख्या में है।

इसी प्रकार फागी की 14 पंचायतें जो कि चाकसू विधान सभा क्षेत्र में आती हैं, वहां पर भी बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। चांदमाकलां, बीची से सेदरिया, पीपला से बोकड़ावास इत्यादि सभी पंचायतों में 4 साल पहले बसों का सुचारु रूप से संचालन हो रहा था, परन्तु वर्तमान में उक्त पंचायतों में बसों का संचालन ठप हो गया है जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मेरी सरकार से मांग है कि चाकसू विधान सभा क्षेत्र के

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

अन्तर्गत आने वाली सभी पंचायतों सहित चाकसू नगर में बसों का सुचारु रूप से संचालन कराया जाए, उनका ठहराव कराएं तथा अवैध रूप से चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ग्यारसाराम कोली- (अनुपस्थित)

माननीय श्रीमती संजना आगरी।

सोजत में चिकित्सा केन्द्रों पर चिकित्सकों की नियुक्तियां

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम, 295 के तहत विशेष उल्लेख में आपको बताना चाहूंगी।

महोदय, सोजत सिटी राजकीय चिकित्सालय सोजत तहसील के साथ मारवाड़, जैतारण व रायपुर क्षेत्र का सबसे बड़ा चिकित्सालय है जिसमें चिकित्सकों के कुल 40-50 पद खाली हैं। मैंने पिछले 4 वर्षों में राजस्थान के इस गरिमामय सदन में चिकित्सा मंत्रीजी को बार-बार अवगत कराया कि उक्त चिकित्सालय में मात्र 15-16 डाक्टर कार्यरत हैं। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर की कमी है, उनको परिवार नियोजन कैम्पों में भेज दिया जाता है। एनेस्थीसिया जैसे मूलभूत पद की हमेशा जरूरत रहती है, एक्सीडेंट व प्रसव के समय पीडित महिला को जब सिजेरियन की जरूरत होती है, डाक्टर के नहीं रहने से पीड़ित महिलाओं को सोजत से 50-150 किलोमीटर दूर पाली या जोधपुर रैफर कर दिया जाता है। जिन्दी भगवान भरोसे छोड़ दी जाती है। एक्सीडेंट कैजुअल्टी में कई लोग इधर-उधर भटकते रास्ते में ही काल का ग्रास बन जाते हैं।

मंत्रीजी ने हमेशा आश्वासन दिया कि हमारे पास डाक्टरों की व्यवस्था होते ही सोजत चिकित्सालय में डाक्टरों का पदस्थापन कर दिया जाएगा। हमारा दुर्भाग्य यह रहा कि मंत्रीजी के 4 वर्षों के आश्वासन के बाद आज सोजत चिकित्सालय में 19 डाक्टर, थे 50 प्रतिशत नियुक्ति थी, आज वह भी घट कर मात्र 7-8 डाक्टर कार्यरत हैं। चिकित्सालयों में जो सीटी स्कैन मशीन है वह ताले में पड़ी है। हमेशा 40-50 मरीज स्कैन के आते हैं, उन्हें दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं।

मंत्रीजी ने गत बजट सत्र में 19 डाक्टरों का स्थानान्तरण कर सोजत विधान सभा क्षेत्र में पदस्थापन हेतु भेजा लेकिन आज तक एक भी डाक्टर ने जोइन नहीं किया। आज सीएचसी चिकित्सालयों के ये हालात हैं तो गांवों-

(श्रीमती संजना आगरी)

ढाणियों के पीएचसी की तो हम बात भी नहीं कर सकते। सरकार नि:शुल्क दवा की बातें करती है, 5-7 दवा से ज्यादा मेडिसिन का नाम ही नहीं ले सकते। बड़ी एजेंसीज व कम्पनियों को ठेके देकर घोटालों व फर्जीवाड़े को बढ़ावा देना है। आज स्वाइन फ्लू जैसी गम्भीर बीमारी से हजारों लोगों की मौत हो रही है। मेरे सोजत विधान सभा क्षेत्र में माली समाज के 23 वर्ष के लड़के की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। 4-5 मरीज जोधपुर रैफर किये गये। चिकित्सा विभाग की नींद तक नहीं खुली। ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

मंत्रीजी से निवेदन है कि चिकित्सा विभाग को अतिशीघ्र निर्देश दें कि सोजत विधान सभा क्षेत्र के गांव-ढाणियों में चिकित्सकों की टीम भिजवा कर सर्वे करावें ताकि टेमीफ्लू व स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों पर रोकथाम लग सके और यह बीमारी अन्य लोगों व बच्चों में न फैल सके।

मैं मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि लोक हित की महती आवश्यकताओं को देखते हुए राजकीय चिकित्सालय, सोजत सिटी, रायपुर व गांवों के पीएचसी व सीएचसी केन्द्रों पर अतिशीघ्र चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए ताकि आम जन को परेशानियों का सामना न करना पड़े।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास।

जोधपुर में बदहाल सड़कें

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के तहत जोधपुर में सड़कों की बदहाल स्थिति की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। मेरा अनुरोध है कि जोधपुर में सड़कों को विभिन्न विकास कार्यों यथा पेयजल, सीवरेज, टेलीफोन और भूमिगत केबलिंग आदि कार्यों के लिए खोद कर लम्बे समय तक खुदा हुआ छोड़ देना एक प्रचलन बन गया है। इस कारण लम्बे समय तक ये सड़कें खुदी ही पड़ी रहती हैं और इन पर आवागमन लगभग असम्भव हो जाता है, दुर्घटनाएं होती हैं। इन खुदी सड़कों पर चलते वाहनों से उड़ने वाली धूल से वाहन चालकों को डस्ट एलर्जी और दमा तक होने का खतरा बना रहता है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड की मुख्य सड़क डेढ़ वर्ष से ज्यादा समय से खुदी पड़ी है। मुख्य चौपासनी रोड की यही हालत है और यही हालात कमोबेश पूरे शहर के हैं।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

इन मुख्य सड़कों से आम निवासियों के घरों को जोड़ने वाली सैक्टर सड़कों का तो कई क्षेत्रों में अस्तित्व ही नहीं बचा है। यहां बजट का अभाव बताकर सड़क निर्माण ही नहीं किया जा रहा है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, पूर्वी-पश्चिमी पाल रोड योजना, कमला नेहरू नगर, भूण्टिया, सूरसागर क्षेत्र में सैक्टर सड़कों के ऐसे ही बदतर हालात हैं।

जोधपुर में सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम का विकास नहीं होने से जो थोड़ी बहुत सड़कें बनाई भी जाती हैं, वे हर हल्की बौछार या बारिश के बाद ही बिखर जाती हैं जिसके बाद हर साल करोड़ों रुपये व्यय कर मरम्मत का कार्य किया जाता है। ये करोड़ों रुपये उन सड़कों पर व्यय किये जाते हैं जो कि पहले से ही गारंटी पीरियड में होती हैं।

अत: मेरा निवेदन है कि जोधपुर में यह जांच कराई जाए कि गत चार वर्षों में कितनी सड़कें किस-किस विभाग ने किस-किस कार्य के लिए कब-कब खोदीं और कब उनका पुनर्निर्माण करवाया गया। क्या सड़क खोदने के लिए विभागीय समन्वय समिति से अनुमति प्राप्त की गई थी? कितनी सड़कें गारंटी पीरियड की होने के बावजूद अलग कार्यादेश अन्तर्गत पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत की गई? गत चार वर्षों में कितनी सड़कों के बारिश से क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत, पैचवर्क अथवा पुनर्निर्माण किया गया और इस पर कितनी राशि व्यय की गई? क्या बारिश से सड़कें टूटने का समाधान खोजा गया?

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जोधपुर की सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए अविलम्ब उक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत सभी जिम्मेदार विभागों की समन्वय समिति बनाकर ठोस कार्यवाही आरम्भ करें और लम्बे समय तक सड़क खोद कर सुध नहीं लेने वाले संवेदकों, अभियंताओं, अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें। मेरी यह भी मांग है कि सूरसागर विधान सभा क्षेत्र की सैक्टर सड़कों के निर्माण के लिए अलग से राशि स्वीकृत की जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा।

(अनुपस्थित)

माननीय श्रीमती अनीता सिंह।

नगर के कतिपय वार्डों में पेयजल समस्या

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नगर के कस्बा नगर के वार्ड नं. 1,

(श्रीमती अनीता सिंह)

2, 3, 4 व 5 में पेयजल की समस्या की ओर आपका ध्यानाकर्षण करना चाहती हूं। इनमें पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पाइप लाइन डालने हेतु करीब 4 वर्ष पूर्व स्वीकृति जारी की गई थी लेकिन विभाग की लापरवाही एवं लेट-लतीफी के कारण आज तक इन वार्डों में पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है और न ही इस ओर कोई ध्यान दिया जा रहा है। एक प्राणी को रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए, ही लेकिन उसके जीवन के लिए पानी भी अत्यावश्यक है। परन्तु प्रशासन व विभाग की अनदेखी के कारण वार्डवासियों को प्यासा मारने की पूर्ण कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो सरकार यह कह रही है कि सभी को पेयजल और वह भी शुद्ध उपलब्ध कराएंगे और दूसरी ओर विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है।

अत: यह देखने की बात है कि सरकार योजनाओं की स्वीकृति जारी करती है और उनके क्रियान्वयन में बरसों लग जाते हैं। कस्बा नगर में चार वर्ष पूर्व स्वीकृति जारी होने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं होने की जांच करवाई जाए और इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर के राजकीय महिला चिकित्सालय में कलेवा योजना के लाभ से वंचित प्रसूताएं

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत अजमेर के राजकीय महिला चिकित्सालय (जनाना अस्पताल) में प्रसूताओं को कलेवा योजना का लाभ नहीं मिलने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। अजमेर स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय जिसे जनाना अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है, इस अस्पताल में अजमेर शहर के अतिरिक्त आस-पास के गांवों सहित सम्पूर्ण सम्भाग से बड़ी संख्या में महिलाएं प्रसव एवं अन्य इलाज के लिए आती हैं।

लगभग तीन वर्ष पूर्व महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रसूताओं व नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'कलेवा योजना' प्रारम्भ की गई थी, परन्तु गत दिनों मुझे यह जानकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजना अजमेर के 'जनाना अस्पताल' में आज तक प्रारम्भ ही नहीं हुई है। महिला एवं

(श्री वासुदेव देवनानी)

बाल विकास विभाग की अनदेखी एवं लापरवाही के कारण इतने बड़े महिला अस्पताल में तीन वर्ष की अवधि में लगभग 32 हजार प्रसूताओं को पौष्टिक कलेवा नहीं मिल सका। इस सम्बन्ध में विभाग के स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही तो साफ-साफ दिखाई दे रही है परन्तु इतनी भारी अनियमितता का पता विभाग के उच्चाधिकारियों को नहीं लग पाना भी विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिह्न उत्पन्न करता है।

गत दिनों उक्त अस्पताल में कलेवा योजना प्रारम्भ नहीं किये जाने के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में भी बड़ी खबरें छपी थीं परन्तु उसके बाद भी अभी तक विभाग नहीं चेता। आज भी वहां पर प्रसूताओं को कलेवा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। आम जनता एवं सरकार की जानकारी में आने के बाद भी विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया जाना अत्यन्त विचारणीय है।

अत: मेरा आग्रह है कि सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाकर इस महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें और अस्पताल में भर्ती होने वाली प्रसूताओं को योजनानुसार पौष्टिक कलेवा उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री शिवजीराम मीणा।

जहाजपुर की पंचायत समिति कोटड़ी के कुछ गांवों का पुलिस क्षेत्राधिकार

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा अत्यन्त लोक महत्व का विषय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की कोटड़ी पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायतें कोठाज एवं कांटी के सभी गांव तथा ग्राम पंचायत छापरेल के दो गांव मोडियाखेड़ा व बेलवा को वर्तमान में पुलिस थाना काछोला के क्षेत्राधिकार में किया गया है जो कि वृत्ताधिकारी माण्डलगढ़ के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित है। जबकि शेष पंचायतों के लिए पुलिस थाना कोटड़ी होकर वृत्ताधिकारी शाहपुरा के क्षेत्राधिकार में है।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त गांवों को पुलिस

(श्री शिवजीराम मीणा)

थाना क्षेत्र काछोला में सम्मिलित करना भौगोलिक दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र से निकलने वाली बनास नदी के एक तरफ उक्त गांव बसे हुए हैं एवं नदी के दूसरी तरफ काफी दूर पुलिस थाना काछोला स्थित है तथा इन गांवों के आसपास बनास नदी पर पुलिया भी नहीं बनी हुई है। इस प्रकार उक्त पंचायतों की आम जनता को साधारण पुलिस सहायता के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है तथा वर्षा ऋतु में तो आपातकालीन पुलिस सहायता के लिए कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं जो कि सभी के लिए एक विचारणीय बिन्दु है।

अत: मेरा सरकार से विनम्र शब्दों में आग्रह है कि मेरे क्षेत्र की तहसील कोटड़ी के अव्यावहारिक रूप से पुलिस थाना काछोला में सम्मिलित ग्राम पंचायत कोठाज एवं कांटी तथा छापडेल पंचायत के ग्राम मोडियाखेड़ा व बेलवा के पुलिस क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करवाकर पुलिस थाना कोटड़ी में सम्मिलित कराने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती किरण माहेश्वरी।

राजसमन्द तहसील के ग्राम धोइन्दा की राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि का प्रकरण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान आवासन मण्डल, उपखण्ड राजसमन्द के अन्तर्गत राजस्व ग्राम धोइन्दा तहसील राजसमन्द की खसरा संख्या 3616, 3539 व 3539/1 से 3539/12 तक भूमि किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा सन 1975 में जे.के. इण्डस्ट्रीज लि. टायर प्लांट कांकरोली को पूर्व में अवाप्त की गयी भूमि के एवज में कृषकों को आबंटित की गई थी।

राजस्व ग्राम धोइन्दा तहसील राजसमन्द के किसानों द्वारा खसरा संख्या 3616, 3539, 3539/1 से 3539/12 भूमि किसानों को भरण-पोषण हेतु दी गई थी। इस बंजर ऊबड़-खाबड़ भूमि को किसानों द्वारा ट्रैक्टरों, जे.सी.बी. द्वारा समतल किया गया तथा कंकड़-पत्थर निकालकर देसी खाद डालकर उसमें कुए, बोरिंग, पम्प सैट आदि लगवाकर पैदावार लायक बनाने में काफी श्रम एवं अत्यधिक आर्थिक नुकसान का सामना करके अपने परिवार का भरण-पोषण करने लगे। कुछ किसानों ने अपनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति के कारण रुपयों

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

की आवश्यकता होने पर इस भूमि को बेच दिया जिससे कुछ खरीददारों ने इस भूमि पर प्लाट काट दिये। खरीददारों ने भू-उपयोग परिवर्तन एवं नामांतरण हेतु आवेदन किया लेकिन उनकी फाइलें तत्कालीन अभियन्ता श्री एस. भाटी द्वारा लिखे पत्र से रुक गयीं और आज भी रुकी हुई हैं।

उक्त खसरा नम्बरों की भूमि किसानों को वर्ष 1974-75 में (जे.के. टायर इण्डस्ट्रीज स्थापित करने के बदलने में दी गई थी) आबंटित की गई थी लेकिन वर्तमान में इस भूमि को राजस्थान आवासन मण्डल अपनी ही भूमि मानकर किसानों को आये दिन नोटिस जारी करता है जिससे किसानों को राजसमन्द, उदयपुर एवं जयपुर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे किसानों को काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा उनके परिवारों का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है। अत: उक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार से मांग करती हूं कि इसकी आवश्यक जांच करवाकर सरकार द्वारा किसानों को वर्ष 1974-75 में दी गई उक्त खसरा नम्बरों की जमीन राजस्थान आवासन मण्डल पुन: अवाप्ति की कार्यवाही कर रहा है, इस कार्यवाही को निरस्त कराकर किसानों के साथ हो रहे घोर अन्याय में सहायता प्रदान करें ताकि ये अपने परिवारों का भरण-पोषण कर सकें। इसके अतिरिक्त इन किसानों के पास आय का कोई स्रोत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: खातेदारी टीनेंट है क्या यह?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हां।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष: अभी इसके बाद। आपका आएगा। अभी 10 मिनट तो रुकिये आप। सिस्टम से चलिये। माननीय श्री शंकरसिंहजी रावत।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

ब्यावर में स्वाइन फ्लू का उपचार

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में स्वाइन फ्लू की बीमारी बहुत भयंकर रूप से चारों तरफ एरिया में फैल रही है। वहां पर काफी लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। चार लोगों की मौत

(श्री शंकर सिंह)

हो चुकी है और अभी भी भंवरसिंह नाम का एक व्यक्ति अमरपुर का है, उसका इलाज ब्यावर में नहीं हुआ। न तो वहां दवाइयां मिल रही हैं, न ही वहां पर दवाइयों की पूरी उपलब्धता है। इसलिए उसका इलाज अजमेर के प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। वहां उसके पैसे लग रहे हैं। सरकार एक ओर तो इस बजट में इतनी वाहवाही लूट रही है और कह रही है कि हम पूरी दवाइयां फ्री दे रहे हैं, इलाज भी फ्री करवा रहे हैं, तो ऐसे गरीब लोग प्राइवेट अस्पतालों में क्यों अपना धन खर्च कर रहे हैं? उनको शौक नहीं है। मेरा सरकार से आपके माध्यम से आग्रह है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए डाक्टर्स की कमी पूर्ति हो। दवाइयों के लिए मैं उनको व्यक्तिगत बता रहा हूं, ऐसे लोगों का इलाज होना चाहिए और सरकार की तरफ से इलाज होना चाहिए। ब्यावर अमृतपुर अस्पताल, राजस्थान का 'अ' श्रेणी का अस्पताल रहा है लेकिन यह सरकार आने के बाद में 20-20 डाक्टर्स की कमी है और नर्सिंग स्टाफ की भी भारी मात्रा में कमी है। वहां अभी पूरी नहीं हो रही है चाहे सीएचसी जवाजा हो, पीएचसी किशनपुरा हो, पीएचसी टाडगढ़ हो, पीएचसी बड़ाखेड़ा हो, पीएचसी राजावास हो, सब जगह पर डाक्टर्स की बिलकुल नहीं के बराबर सुविधा है। यह डाक्टर्स की कमी कब पूरी होगी, ऐसा मैं सरकार से जवाब चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है, ऐसे भयंकर बीमारियों के ग्रस्त मरीज प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। वे प्राइवेट में नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसी बीमारी जहां पर भी फैल रही है। वहां पर सरकार की तरफ से इलाज करवाने के लिए मेरा आग्रह है। माननीय मंत्री महोदय से भी आपके माध्यम से निवेदन है कि इसमें आप संतोषप्रद जवाब दें। जनहित का मैटर है। बीमारी जिसके लग जाती है, वह पेशेंट कहलाता है, जाति नहीं होती है उसकी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डाक्टर दिगम्बर सिंहजी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से एक...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, आप ही का मुद्दा है यह। एक साथ हो जाएगा।

सूचना

जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में संविदाकर्मियों की हड़ताल

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन। सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज में संविदाकर्मी पिछले छह दिन से हड़ताल पर हैं और इसके कारण मरीजों को जो परेशानी हो रही है, पेशेंट या उसके घरवाले ही जानते हैं। मरीज एसएमएस अस्पताल को छोड़कर प्राइवेट अस्पताल की तरफ मजबूरी में पलायन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स नहीं हैं। पिछले चार साल से लगातार उन ठेकाकर्मियों का शोषण करने के बाद उनको एक साल के बाद दूसरा, दूसरे साल के बाद तीसरा, हर साल एश्योरेंस देते हैं कि हम आपको नियमित करेंगे हम आपको नियमित करेंगे। इसी तरह से इन्होंने...

श्री उपाध्यक्ष: शार्ट में। इन्फार्मेशन का मतलब है बिलकुल शार्ट में। हां, पिन-पाइंट।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इसी तरह से सरकार ने, खुद माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एनआरएचएम के तहत जो काम करने वाले संविदाकर्मी हैं, चाहे वह नर्सिंग स्टाफ हों, चाहे वह पैरामेडिकल स्टाफ हों, सबके लिए घोषणा की थी कि हम आपको नियमित करेंगे। उसके बावजूद भी उनका आज तक नियमितीकरण नहीं हुआ। 5-5, 6-6 घंटे लगातार मरीज लाइन में खड़ा है केवल पर्ची कटवाने के लिए। पर्ची कटवाने की जहां व्यवस्था नहीं है, उस अस्पताल के अन्दर इलाज की क्या व्यवस्था होगी? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार को डाइरेक्ट करें कि जल्दी से उन संविदाकर्मियों से वार्ता करे। इस हड़ताल को खतम करो।

श्री उपाध्यक्ष: विराजो, आप। माननीय श्री केसारामजी चौधरी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, आप बोलोगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी के ऊपर मंत्री महोदय कुछ बोल देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: मैं मंत्रीजी को रोक भी नहीं सकता और ऐसे पाइंट पर अनुरोध भी नहीं कर सकता। माननीय श्री केसाराम चौधरी।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: तो फिर दोनों का ही जवाब एक साथ दे दें।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

ब्यावर में स्वाइन फ्लू का उपचार

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): हां, मैं दे देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय विधायक ने जो चिंता जताई है, सरकार ने पहले से ही स्पष्ट कर रखा है। स्वाइन फ्लू के जो भी रोगी हैं, जो आइडेंटिफाइड हैं, उनका इलाज बिलकुल मुफ्त कर रहे हैं। आप किसी निजी अस्पताल की बात कर रहे हैं कि इन्होंने अपने किसी रोगी को निजी अस्पताल में भर्ती कर रखा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर में हमने लेटेस्ट टैक्नोलोजी की काफी जांचों की मशीन लगा रखी है, वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कृपया वह अपने पेशेंट को हमारे सरकारी अस्पताल में लेकर आ जाएं, सरकार उनका पूरा नि:शुल्क इलाज करेगी, यह मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

सूचना

जयपुर के सफाई मानसिंह चिकित्सालय में संविदाकर्मियों की हड़ताल

दूसरा, सवाई मानसिंह अस्पताल सहित तीन-चार अन्य अस्पतालों के अन्दर जो संविदाकर्मी हड़ताल पर हैं, माननीय दिगम्बर सिंहजी खुद चिकित्सा मंत्री रहे हैं, कभी भी सरकार ने यह नहीं कहा कि जो वहां पर संविदाकर्मी लगे हुए हैं, उनको नियमित करेंगे। आप एनआरएचएम वालों की बात कर रहे हैं तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक बात कही थी। एनआरएचएम सिर्फ राजस्थान का ही प्रोजैक्ट नहीं है, यह पूरे हिन्दुस्तान का प्रोजैक्ट है। पहले और एकमात्र मुख्य मंत्री राजस्थान के हैं जिन्होंने गवर्नमेंट आफ इण्डिया को लिखा कि इनकी सेवाओं को देखते हुए इनको स्थाई करने के प्रयास करने चाहिए। जब उस दिशा में गवर्नमेंट आफ इण्डिया से कोई जवाब नहीं आया तो हम लोगों ने यह तय किया कि इनको बोनस अंक देकर हम लोग नियमित करें। हमने 31,292 पोस्ट क्रीएट कर दी हैं, उनकी आन लाइन फार्म भरने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है और अगले दो-तीन महीनों के अन्दर इस प्रक्रिया को पूरा करके इन 31,292 पोस्टों पर नियमित नियुक्ति कर देंगे।

जहां तक इनसे वार्ता की बात है, चार दौर की वार्ता उनसे हो चुकी

(डा. राजकुमार शर्मा)

है। वे लोग नियमित करने की मांग कर रहे हैं। सरकार का उनसे सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं था, वे एक एनजीओ के माध्यम से हैं, ठेके के माध्यम से हैं। इसलिए हम लोग कैसे सीधे उनको रैगुलर कर दें? उनसे बात के चार दौर समाप्त हो चुके हैं। एक बार लास्ट दौर में उन्होंने कह दिया था कि हम लोग आपकी बात से सहमत हैं और हड़ताल आज वापस लेंगे। उसके बाद में वहां पर जाकर वापस मुकर गये। अब कौन उनके पीछे है, कौन व्यवस्था बिगाड़ना चाहता है? उपाध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस बात का भी आप पता करवाएं कि वे हमारे से हां करके जाते हैं और बीच में पता नहीं उनको कौन मिल जाता है और वहां जाकर ना कर देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री केसाराम चौधरी। माननीय श्री केसाराम चौधरी केवल।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): **×××**

श्री उपाध्यक्ष: नो क्वेश्चन। केसारामजी चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): हां, मैं बोल रहा हूं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): **×××**

श्री उपाध्यक्ष: केसारामजी चौधरी केवल। (व्यवधान) नो क्वेश्चन।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): **×××**

श्री उपाध्यक्ष: केसारामजी, बोलिये आप। आप बोलिये, आपका ही अंकित हो रहा है, उनका नहीं हो रहा है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ये बोल रहे हैं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं। इनका अंकित नहीं हो रहा है। यह तो सरकार की मर्जी है कि वह बीच में बोल रही है। तो हम बीच में क्यों रोकें?

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

मारवाड़ जंक्शन के धारिया बांध का जीर्णोद्धार

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कल्याणकारी सरकार, किसानों की हितैषी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष: उत्तेजनाजनक बात नहीं आनी चाहिये। बहुत ही शांति।

(13.00 बजे)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अच्छी ही बात कह रहा हूं, अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार की सराहना कर रहा हूं, दूसरी बात मैं कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में धारिया बांध 1996 में स्वीकृत हुआ था। आरआईडीएफ-तृतीय में यह बांध स्वीकृत हुआ और 571 लाख 34 हजार रुपये की स्वीकृति जारी हुई थी 1996 में। जब यह स्वीकृति हुई थी तो इस क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर दौड़ी थी और किसानों ने अपेक्षा की थी कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र में बांध बनने से हमारे कुओं का जलस्तर बढ़ेगा। 136 हैक्टेयर कमांड क्षेत्र व 214 हैक्टेयर भराव क्षमता, कुल मिलाकर 1351 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था। इस निर्माण कार्य का वर्ष 1997 में एक कम्पनी गंगोत्री एन्टरप्राइजेज लिमिटेड, लखनऊ को टेण्डर दिया गया, 72 लाख 88 हजार 665 रुपये में ठेका दिया गया। काम अधूरा छोड़ कर भाग गई। फिर दूसरी कम्पनी आई, 6.3.1999 को मैसर्स गुरदेव सिंह सिंधी एण्ड कम्पनी, कोटा को टेण्डर दिया गया। उसको एक करोड़ पच्चीस लाख अठहत्तर हजार सात सौ इक्यावन का ठेका देकर काम शुरू किया, 6.3.1999 में कार्य शुरू कर दिया। उसके बाद उसी कम्पनी को फिर ठेका दिया गया वर्ष 2001 में और एक करोड़ चौबीस लाख बयालीस हजार नौ सौ सतरह रुपये खर्च करने के लिए उसको दिये गये। इतने रुपये खर्च होने के बाद वह बांध 2002 में पूर्ण हो गया, नहरें भी पक्की बन गई। नहरें पक्की बनने के बाद पांच-छह साल बारिश नहीं हुई, लेकिन जैसे ही 2006-07 में पहली बारिश हुई, वह बांध छत्तीस जगह से फूट कर बिलकुल तितर-बितर होकर बिखर गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस बांध के लिए मैंने 26.8.2009 को तृतीय सत्र के अन्दर पूछा था और उसमें इन्होंने बताया था कि संसाधनों की उपलब्धता होने पर बांध का पुन: निर्माण किया जाएगा। फिर 2011 में मैंने प्रश्न पूछा तो इन्होंने कहां, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जाएगा और अब भी ये बार-बार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की बात कर रहे हैं। यह सरकार अब जाने को तैयार हो गई है, क्या जाते-जाते यह सरकार इस बांध को पूरा करने का विचार रखती है या नहीं? इस बांध से इतने लोगों को फायदा होने वाला था उसकी जगह उनकी जमीनों में चौकड़ियां डाल कर जमीन को खराब करके रख दिया। वर्षों से बारह और छह, अठारह साल हो गये, अठारह साल से अभी तक वह फूटा हुआ बांध पड़ा है। मैं मांग करता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि

(श्री केसाराम चौधरी)

इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृति जारी करें और इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करें ताकि अगले साल किसानों को राहत मिल सके। यह किसानों की हितैषी और कल्याणकारी सरकार कहलाती है, मगर चार साल में वित्तीय संसाधन ही उपलब्ध नहीं हुए। इस सरकार के खजाने में पैसों की न मालूम कहां कमी है, बार-बार पूछने पर यही जवाब दिया जा रहा है कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर इसको पूर्ण किया जाएगा। मैं इस तरह से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आप इसी वित्तीय वर्ष में इसकी स्वीकृति जारी करें ताकि किसानों को राहत मिल सके और किसानों को फायदा हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री रामहेत सिंहजी।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): धन्यवाद, सर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, रामहेतसिंहजी। मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): एक साथ दे देना जवाब।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी कोई जवाब देना चाहते हैं, रामहेत सिंहजी, एक मिनट।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जाते-जाते की यह सरकार की बात कर रहे हैं, यह सरकार तो वापस आ रही है। इनकी सरकार जाते-जाते भी नहीं कर पायी। (व्यवधान) इनकी सरकार जाते-जाते भी नहीं कर पायी, हमारी सरकार तो वापस आ रही है। वापस आने वाली सरकार में इस 6.3 को मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट भाषण पेश किया है उसमें इसके पुनरुद्धार के लिए, मरम्मत के लिए 21 करोड़ रुपये की घोषणा कर दी गई है। माननीय सदस्य को ध्यान में नहीं है इसलिए आपकी जानकारी में ले आता हूं। और....

श्री उपाध्यक्ष: पढ़ नहीं पाये होंगे। यह क्या है इसमें, बजट भाषण में?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): 21 करोड़ रुपये से इसका पुनरुद्धार, मरम्मत कर दी जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक, साहब, धन्यवाद। (व्यवधान) जब बजट भाषण में है तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। माननीय रामहेत सिंहजी। (व्यवधान) नो डिस्कशन। बैठिये। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): धन्यवाद दे दो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप तो यह कह दें कि यह सैंक्शन हो गया.... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सैंक्शन है आपका....

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सैंक्शन हो गया? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय रामहेत सिंहजी।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 11 जनवरी, 2003 को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्रीमती कमलाजी द्वारा हरसोली तहसील कार्यालय का उद्‌घाटन कर दिया गया। उसके बाद....

श्री उपाध्यक्ष: यह तो पहले आ गया यहां सदन में, दोबारा चर्चा नहीं हो सकती।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): मेरी पर्ची है, मेरी पर्ची।

श्री उपाध्यक्ष: दोबारा चर्चा नहीं हो सकती। माननीय श्री ओटाराम देवासी।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): आप सुनिये तो सही। सुनो तो सही। मैं इस बात को नहीं कह रहा, आप सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष: बिलकुल नहीं, कतई नहीं। यह सैक्रेटेरिएट ने नहीं देखा होगा। यह पहले चर्चा हो चुकी।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): आप सुनोगे, मेरी पर्ची निकली है। मेरा अधिकार है, मुझे बोलने का अवसर दोगे आप। मैंने पर्ची में लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष: आपको एक मिनट से, एक मिनट, एक सैकण्ड नहीं... (व्यवधान) आप सुनिये, बात सुनिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पर्ची निकली है, पर्ची।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): स्पीकर साहब ने तो दो मिनट के लिए अलाउ किया है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बात सुनिये। आप उसी तरह रखें। एक मिनट विराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पर्ची निकली है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): पर्ची निकली है।

श्री उपाध्यक्ष: मेरी बात सुनिये पहले। एक मिनट विराजें। (व्यवधान) एक मिनट विराजिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): +++ (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पर्ची निकली है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपको मौका दे रहा हूं, बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): +++ स्पीकर ने अलाउ कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष: देखिये, मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप बैठें। (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उप तहसील के, हरसौली के बारे में पर्ची निकली है।

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये। अब आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ऐसे नहीं बात करेंगे, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये, आप विराजिये। मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे। माननीय सदस्य, यह सदन में साफ है रूल्स-प्रोसीजर में कि जिस बात की एक दफा चर्चा हो गई, दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब यह पर्ची आई, पर्ची तो सैक्रेटेरिएट देखता नहीं है। वह ले ली, इसका मतलब यह नहीं है। यदि आपसे किसी ने अनुरोध किया है तो राइट नहीं समझें। राइट आपका रूल्स एण्ड प्रोसीजर में...(व्यवधान) आप सुनिये, बात तो सुनिये न आप। नहीं, वह दिला देंगे लेकिन आप एक मिनट में अपनी कोई बात फिर भी कहना चाहें, इसको प्रोसीजरली नहीं माना जाएगा क्योंकि आप, आपका तर्क, आपके मन में कोई....

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): यह मेरे लिए ही लागू है क्या? मैं मेरे क्षेत्र की बात नहीं रख सकता? सदन में असत्य बोला जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: एक दफा, नहीं, आप....

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): गलत चिट्ठी भेजी जा रही है मंत्री द्वारा।

श्री उपाध्यक्ष: झूठ शब्द तो वैसे भी असत्य उसमें है। आप बताइये, लेकिन एक बात बार-बार सदन में नहीं उठ सकती। इसलिए नहीं उठ सकती कि नई बात फिर कैसे रखेंगे? आप अपनी बात कह दें संक्षेप में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य खोज करके, अन्वेषण करके नये तथ्य लेकर आये हैं, इनका अधिकार है। उपाध्यक्ष महोदय, आप ही संरक्षण नहीं देंगे तो कौन संरक्षण देगा? नहीं, अब...

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, वह दे दिया, लेकिन यह उसको राइट नहीं मानें। यह राइट नहीं समझें, बोलने का मौका दे रहा हूं अब।

हरसौली को उप तहसील का दर्जा दिये जाने की घोषणा

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों बजट में और मेरे सवाल के जवाब में माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर द्वारा उप तहसील हरसौली को उप तहसील होना नहीं बताया गया, उसके कारण जनता आक्रोशित है। एक पत्र माननीय मंत्रीजी का और मिला जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। प्रिय श्री खेरियाजी, विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास जिला अलवर के हरसौली को उप तहसील बनाने के सम्बन्ध में आपका पत्र मुझे मिला। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु मैं प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान को निर्देशित करता हूं। यह 28 तारीख का पत्र मिला जो वहां पर पढ़कर सुनाया गया। इसी तरह से संसदीय कार्य मंत्री, कार्यालय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, स्वतंत्र प्रभार, रक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें यह कहा गया- श्री जितेन्द्र सिंहजी के अतिरिक्त निजी सचिव श्री रमेश भारद्वाज ने यह भी बताया है कि माननीय रक्षा राज्य मंत्रीजी ने हरसौली में तहसील की स्वीकृति के लिए श्री अशोक गहलोतजी से व्यक्तिगत अनुरोध किया है। श्री सिंह के अनुरोध पर श्री गहलोत द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया है कि शीघ्र ही हरसौली में तहसील की घोषणा की जाएगी। इसी आधार पर 8 तारीख के अख़बार में एक विज्ञापन छपा है जिसमें लिखा है, माननीय श्री अशोक गहलोतजी व केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह का हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, उन्होंने हमको ठोस आश्वासन दिया है कि हरसौली उप तहसील बनाने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इसी बजट में उप तहसील बनाने की घोषणा कर दी जाएगी। यह विज्ञापन छपा है। सात तारीख से जब से माननीय मंत्रीजी ने मेरे सवाल के जवाब में हरसौली को उप तहसील नहीं माना और बजट आने के बाद तीन दिन से बाजार बंद हैं, धरना दिया जा रहा है। आज पूरे बाजार में वहां चक्का जाम है। अभी आधा घंटे पहले मेरे पास फोन आया था कि हरसौली के परगना में जो चालीस गांव पड़ते हैं, कल एक भी परिवार में खाना नहीं बनेगा, सुबह नाश्ता नहीं बनेगा। कोई बच्चा स्कूल जाएगा वह भी भूखा जाएगा, कोई सौ साल का बुजुर्ग है वह भी अन्न का त्याग करेगा, ऐसी हालत बनी है।

माननीय रक्षा राज्य मंत्री परचों के द्वारा वहां कह रहे हैं, मैं मंत्रीजी से सारी बात स्पष्ट करना चाहता हूं, उप तहसील बनाने का आपने आश्वासन दिया है क्या? क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा हरसौली को उप तहसील बनाने का आश्वासन दिया गया है? क्या रक्षा राज्य मंत्री द्वारा आग्रह किया गया कि

(श्री रामहेत सिंह)

हरसौली को तहसील बनाएंगे, इस तरह का प्रेस नोट छपा है? मंत्री महोदय सदन में हैं, इस बात को स्पष्ट करें। सरकार की मंशा साफ है, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, तहसील या उप तहसील जो भी बनाना चाहते हैं सदन को बता दें। अलवर जिलाधीश महोदय को निर्देशित करें कि वे आंदोलित जनता के बीच में जाकर सरकार जो कर रही है उसकी घोषणा करा दें ताकि बहुत बड़ा जन आंदोलन जो हरसौली परगना पर होने वाला है, उसको टाला जा सके और सरकार ने जो गलती की है उसको ठीक किया जा सके। इतना ही निवेदन है, मंत्रीजी सदन में हैं, मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी सारी बात को स्पष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ओटारामजी देवासी।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): मंत्रीजी, खड़े हो रहे थे पहले जवाब देने के लिए इसका, स्पष्ट करा दें।

श्री उपाध्यक्ष: आसन रोकेगा नहीं, नहीं दें तो खतम करो।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): तो मना करवा दें कि नहीं देंगे। यह गुमराह करने वाले पत्र क्यों भेज रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओटाराम देवासी।

सिरोही को नर्मदा नहर से जल वितरण की योजना

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सिरोही विधान सभा क्षेत्र में 90 प्रतिशत फ्लोराइडयुक्त पानी है जिसके लोगों के अन्दर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं- जोड़े के दर्द, कमर से झुकने की स्थिति। सिरोही जिले के लोग फ्लोराइडयुक्त पानी पीने को मजबूर हैं। सिरोही में पेयजल की भारी समस्या व निरन्तर गिरते भू-जल को ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती सरकार ने 2008 में सिरोही को नर्बदा नहर से जोड़ने की योजना बनाई थी जिसे वर्तमान सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है। सिरोही की आम जनता को पीने का मीठा पानी मिलने वाला था, 2008 से लेकर आज 2013 आ गया है, परन्तु नर्बदा का वह प्रोजैक्ट आज दिन तक लागू नहीं हुआ। मुख्य मंत्रीजी का जो बजट भाषण था उसमें आपने नर्बदा प्रोजैक्ट की घोषणा की, वह जालौर और पाली के लिए की है। मुझे यही विश्वास था कि सरकार सिरोही का भी ध्यान रखेगी परन्तु सिरोही ज़िले को बिलकुल ही इग्नोर किया गया। मैंने तो देखा है, सिरोही ज़िले में राज्य सरकार न तो डाक्टर लगा सकती और न बिजली का कनेक्शन दे सकती। एक विधि

(श्री ओटाराम देवासी)

महाविद्यालय था उसकी भी मान्यता रद्द कर दी। अब पानी भी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। तो यह सिरोही के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमें तो पूरा विश्वास है कि सिरोही जिला राजस्थान के अन्दर है, परन्तु जिस तरह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हम तो देख रहे हैं कि सिरोही जिला राजस्थान के बाहर है, गुजरात के अन्दर है। 2008 में प्रोजैक्ट बना था नर्बदा का पानी सिरोही ज़िले को देने के लिए। शिवगंज के 53, सिरोही के 77, रेवदर के 103 और पिण्डवाड़ा के 23 गांवों को नर्बदा की पेयजल की योजना बनाई थी। 2008 में 258 गांवों का प्रोजैक्ट बना था, करीब 41 हजार 890 करोड़ का प्रोजैक्ट था, वह सरकार ने कौन से बस्ते में डाल दिया जो आज दिन तक सिरोही ज़िले को पानी नहीं मिल रहा है? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पांच साल के कार्यकाल में एक तो उपलब्धि बता दे कि हमने सिरोही के लिए यह किया है। पांच साल पूरे होने वाले हैं, पांच साल के अन्दर आपने सिरोही ज़िले के लिए एक भी ऐसा काम नहीं किया है जो सिरोही के लिए कांग्रेस पार्टी के नाम से हो सके। मैं देख रहा हूं कि जवांई का प्रोजैक्ट है उससे पाली और जैतारण तक पानी पहुंच रहा है। जबकि जंवाई बांध थोड़ा बहुत सिरोही की धरती पर भी बना हुआ है। शिवगंज को जवांई का पानी दिया जा रहा है, क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि वह आने वाले समय में पंचायत समिति शिवगंज को भी पेयजल के लिए या सिंचाई के लिए पानी दे सके? नर्बदा का जो प्रोजैक्ट है उसका भी सरकार जवाब दे। पाली और जालौर में आपने 323 करोड़ रुपए की परियोजना लागू की है। दूसरी आपने एक 150 करोड़ की योजना बनाई, पाली के लिए जवांई बांध की 309 करोड़ की परियोजना बनाई। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सिरोही के लिए जो भी प्रोजैक्ट बनाया हो वह सदन में रखें। यही मेरी भावना है, मंत्रीजी इस पर जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री मोहनलालजी गुप्ता। पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन का मतलब है शार्ट में।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): मंत्री विराजे हैं, नर्बदा का पानी..

श्री उपाध्यक्ष: जवाब दें, मना नहीं मंत्रीजी को। माननीय मोहनलालजी।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): मंत्रीजी, जवाब दें। सिरोही का पानी है और सिरोही के लिए हम मांग कर रहे हैं।

श्री जगसीराम (रेवदर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सिरोही की मांग है और यह लम्बे समय से मांग कर रहे हैं। इनके चार साल पूरे हो गए हैं, आज तक इनका कोई समाधान नहीं हुआ है। मंत्रीजी विराजमान हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मोहनलालजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्रीजी जवाब दें या नहीं दें लेकिन वह सुनें तो सही। माननीय सदस्य अपनी बात कर रहे थे, इतनी गम्भीर समस्या है।

श्री जगसीराम (रेवदर): इसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कम से कम मंत्रीजी यह बताएं तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्रीजी यहां बातों में मस्त हो रहे हैं। इन्होंने तो यहीं दरबार खोल रखा है अपना। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए यहीं दरबार चला रखा है।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): जवाब तो दो कि देंगे या नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मोहनलालजी। केवल मोहनलालजी का अंकित होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मोहनलालजी गुप्ता।

श्री जगसीराम (रेवदर): ×××

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें। मंत्रीजी बोल रहे हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने चिंता प्रकट की है। सिरोही का उनका प्रोजैक्ट जो नर्बदा नहर से जुड़ना था, वह 2008 में बना। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि सिरोही ज़िले में 2001 के सेंसेक्स के अनुसार कुल 455 राजस्व गांव हैं। सभी विभिन्न पेयजल योजनाओं से जुडे हैं। दो शहर माउंट आबू और शिवगंज सरफेस स्रोतों से जुडे हुए हैं, शेष पूरा जिला ग्राउंड वाटर से जुड़ा हुआ है। कुल 455 गांवों में 85 गांव क्षेत्रीय पेयजल योजना, 12 गांव स्वजलधारा योजना, 41 गांव पाइप योजना, 24 गांव पम्प एंड टैंक योजना, 70 गांव जनता जल योजना और 223 गांव हैंडपम्प योजना से

(डा. जितेन्द्र सिंह)

जुड़े हैं। इनमें भू-जल की गुणवत्ता और उपलब्धता अच्छी है। जिन गांवों में फ्लोराइड की मात्रा नोर्म्स से अधिक है उनमें डि-फ्लोराइडेशन संयंत्र लगे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि फ्लोराइड जिन-जिन गांवों में है, कृपया उसकी आप मुझे लिस्ट उपलब्ध करा दें,

एक डिफ्लोराइडेशन की कास्ट 80 हजार रुपये आती है, जितने आप देंगे सब मैं स्वीकृत कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आपका जवाब आ गया, इन्होंने कह दिया। आप बता दीजिये इनको। यहां सदन में नहीं।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): आपने जो कहा है नर्बदा नदी से सिरोही को जोड़ा जाए, मैं एक्सपीडाइट कराता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: यह एश्योरेंस है गवर्नमेंट का। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। विराजिये। मंत्रीजी ने एश्योर कर दिया, ठीक है। माननीय श्री मोहन लालजी गुप्ता।

सूचना

जयपुर में उपजाऊ भूमि की अवाप्ति के विरोध में किसानों का धरना

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के बाहर हजारों किसान जे.डी.ए. की मनमानी के खिलाफ धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों किसानों की उपजाऊ भूमि को जे.डी.ए. अवाप्त कर रहा है और वह अवाप्त कर रहा है कालोनी बसाने के लिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उन किसानों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। जे.डी.ए. ने जो आज तक कालोनियां बसाई हैं उन कालोनियों में भी लोगबाग नहीं जा रहे हैं, वो जमीनें खाली पड़ी हुई हैं। वहां लोगबाग बस नहीं रहे हैं उसके बावजूद भी कालोनी बसाने के लिए नींदड़ गांव के किसानों की उपजाऊ जमीनों को वो ले रही है। उपजाऊ जमीन है, वहां पर सब्जी अच्छी होती है वहां पर फसल अच्छी होती है और वह उन फसलों को खतम करके, सब्जियों को खतम करके जमीन ले रही है। सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जे.डी.ए. इस प्रकार की अन्यायपूर्ण कार्यवाही उनके साथ न करे और उनकी जमीन को अवाप्ति से मुक्त करे।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री फूलचन्दजी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): सरकार जवाब देगी, साहब। सरकार उनकी समस्या का समाधान तो करे। उपाध्यक्ष महोदय, बाहर हजारों किसान खड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष: सरकार की नालेज में आ गया। फूलचन्दजी, आप बोलिये। केवल फूलचन्दजी का। फूलचन्दजी, आप बोलिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षकों का विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उपाध्यक्षजी, आज राजस्थान के सम्पूर्ण उच्च शिक्षा के अधिकारी सड़कों पर हैं और उसका कारण है कि सरकार उदासीनता बरत रही है। 1300 रिटें हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ मंजूर हो चुकीं, चार एस.एल.पी. सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकीं, सरकार सुनती नहीं है। मंत्रीजी से कल मैंने आग्रह किया था कि कल शिक्षक आएंगे आप उनकी बात सुनें, लेकिन आज वो भी नदारद हैं। इस कारण से आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से। उच्च शिक्षा एक ऐसा विभाग है जहां सुखाड़ियाजी ने, राणावत आयोग ने पूरे इंडिया में प्राध्यापकों को गजेटेड आफिसर बनाया था। आज बदतर स्थिति है, सारे राज्यों में उच्च शिक्षा का अलग सिस्टम हो गया...

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ...और राजस्थान पिछड़ता जा रहा है। उच्च सेवा वर्ग भी नहीं है, कालेजिएट ब्रांच शिक्षा विभाग इस प्रकार की स्थिति है। 399 करोड़ रुपये का बिल यू.जी.सी. में पड़ा है लेकिन उसको सरकार ला नहीं पा रही है, इस कारण से शिक्षकों का चालीस प्रतिशत एरियर भुगतान नहीं हो रहा है। आर.ए.एस. को लगा दिया गया उच्च शिक्षा में, इससे तौहीन हो रही है उच्च शिक्षा की।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज शिक्षक आये हैं उनको...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आप समाप्त करें। विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): इसलिए आपका प्रोटेक्शन चाहते हैं, सरकार को आप निर्देशित करें कि निश्चित तौर पर शिक्षकों को सुना जाए और उनका समाधान किया जाए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री महेन्द्र जीत सिंह जी मालवीय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे। श्री महेन्द्र जीत सिंह जी मालवीय।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या : एफ4(6)पीईएसए-रूल/लीगल/पीआर/2010/249 दिनांक 27.2.2013 जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए ग्रामों को मान्यता प्रदान की गई है : एवं
2. अधिसचूना संख्या : एफ4(6)पीईएसए-रूल/लीगल/पीआर/2010/250 दिनांक 27.2.2013 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (मोडिफिकेशन आफ प्रोविजन्स फार देयर एप्लीकेशन टू शिड्यूल्ड एरियाज) नियम, 2011 में संशोधन किया गया है।

प्रतिवेदन एवं लेखे

आउटपुट बजट वर्ष 2011-12 व आउटकम बजट वर्ष 2012-13

श्री उपाध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री आउटपुट बजट वर्ष 2011-12 एवं आउटकम बजट वर्ष 2012-13 सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आउटपुट बजट वर्ष 2011-12 एवं आउटकम बजट वर्ष 2012-13 सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2008-09 के लेखों की अंकेक्षण प्रतिवेदन व टिप्पणी

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2008-09 के लेखों की आडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय डा. जितेन्द्र सिंह। अनुपस्थित।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है!

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, हैं कहां तो? आपने पुकारा है।

श्री उपाध्यक्ष: धारीवाल जी रख रहे हैं। माननीय धारीवाल जी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, पहले आपसे अनुमति ली है क्या इन्होंने? पहले आपको सूचित किया है, उपाध्यक्ष महोदय, या पहले आपसे अनुमति ली है? नियम और प्रक्रियाओं को कुछ तो देखो। नहीं, वैसे तो आसन सर्वोपरि है पर आप देखिये, मंत्री महोदय सदन के प्रति कितने गम्भीर हैं। टहलते-टहलते बाहर चले गये।

श्री उपाध्यक्ष: समय का ध्यान रखें मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104 (4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2008-09 के लेखों की आडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिका

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

सूरसागर के राजकीय अस्पतालों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का प्रारम्भ

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के राजकीय अस्पतालों में मातृ

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं आरम्भ करने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती कमला कस्वां, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

सादुलपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों को सुधारने बाबत् एक याचिका उपस्थापित करती हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013- श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013- श्री बृजकिशोर शर्मा, प्रभारी मंत्री राजस्थान विद्यालय (फीस के

(श्री उपाध्यक्ष)

संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-14 । सामान्य वाद-विवाद। माननीय श्री राजपाल सिंह जी शेखावत।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने राजपाल जी का नाम पुकारा है। आप नियम से आइये। इस बात को दुबारा रख दीजिये आप, कोई दिक्कत नहीं है। श्री राजपाल सिंह जी। आप तो नियम जानती हैं, माननीय सदस्या।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं नियमानुसार ही बोल रही हूं, साहब, कोई नयी परम्परा तो शुरू कर नहीं रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राजपाल सिंह जी शेखावत।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार का यह पांचवां और आखिरी बजट है। मैं सोचता था, बजट में मुख्य मंत्री पिछले पांच साल में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जाने की कोशिश की है, उसकी चर्चा करेंगे। पांच साल में किस तरह का

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

फिस्कल कंसोलिडेशन का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है, उसका विश्लेषण करेंगे और आने वाले टाइम राजस्थान को किस जगह पहुंचाना चाहते हैं, उसका विजन देंगे। लेकिन यह दुर्भाग्य से बजट नहीं है। इसमें न राजस्थान की आर्थिक स्थिति के बारे में कोई चर्चा थी, न राजस्थान के फिस्कल स्टेट के डाइरेक्शन के बारे में कोई बात है, न इसमें कोई चिन्ता है राजस्थान की आर्थिक हालत के लिए, राजस्थान के राजस्थानी की आर्थिक स्थिति के लिए। यह महज एक डरे हुए, घबराये हुए, सहमे हुए, हताश, असफल, अपराधबोध से ग्रस्त ऐसे मुख्य मंत्री, ऐसे वित्त मंत्री का चुनावी घोषणा पत्र था जो हथियार डाल चुका है और जो सौदे पर उतरा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री 2008 में ऐसे वक्त में आये थे जब 11वीं पंचवर्षीय योजना आधी से ज्यादा बची हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना उन्हीं के काल में शुरू होने वाली थी। प्रदेश 8 प्रतिशत औसत विकास दर से आगे बढ रहा था। राजकोषीय घाटा प्रदेश की जी एस डी पी का केवल 1.75 प्रतिशत था, रेवेन्यू सरप्लस था और राजस्थान का आम आदमी केवल 3369 रुपये टैक्स दे रहा था। राजस्थान तेजी से विकसित होने वाले राज्यों की कतार में खड़ा था और एक ऐसा प्लेटफार्म बन गया था जिस प्लेटफार्म के जरिए हम हाई ट्रेजेक्टरी ग्रोथ के राज्यों में जा सकते थे। लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने वह मौका खो दिया। मुख्यमंत्री जी के हाथ में विकास का तीर जो हमने सौंपा था, वह उन्होंने छोड़ दिया। पिछली सरकार का नाम था काम करने वाली सरकार और गये पांच साल में राजस्थान की जनता को सरकार मिली है बात करने वाली सरकार। यह जो ट्रांसफार्मेशन हुआ है गये चार-पांच साल में राजस्थान की कल्चर में, राजस्थान की पोलिटिक्स में, राजस्थान की इकोनोमी पर जिसका इम्पैक्ट आया है वह था वर्किंग गवर्नमेंट टू वोकल गवर्नमेंट। यह वोकल गवर्नमेंट है। इन्होंने 111 पन्नों का बजट भाषण दिया उपाध्यक्ष महोदय, 111 पन्नों के बजट भाषण में राजस्थान की फिस्कल स्टेट के बारे में 15 लाइनें नहीं बोल पाये। पूरे 111 पन्नों के भाषण में 15 लाइनें ऐसी नहीं थीं जिन लाइनों के जरिए कोई राजस्थान की आर्थिक स्थिति के बारे में अंदाजा लगा सके, राजस्थान की गरीब जनता की आर्थिक स्थिति के बारे में कोई अंदाजा लगा सके। आने वाले समय में राजस्थान विकास की किस प्रकार की गति पैदा करेगा उस गति के बारे में कोई इन्फरेंस निकाला जा सके।

इसमें मुख्य मंत्रीजी की गलती नहीं है, मुख्य मंत्रीजी के पास कहने

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

को कुछ था भी नहीं। मुख्य मंत्रीजी अगर इस बारे में बात करते तो उन्हें बताना पड़ता, 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो हमारी आब्जेक्टिविटी थी towards faster and more inclusive growth, हम चाहते थे 9 परसेंट की वृद्धि। 9 परसेंट की ग्रोथ और ग्रोथ भी कैसी? इनक्लूजिव ग्रोथ। यानि जो 8 परसेंट की एवरेज कम्पाउंडेड ग्रोथ वसुंधरा जी छोड़ कर गई थीं उस 8 परसेंट की कम्पाउंडेड ग्रोथ को 9 परसेंट की कम्पाउंडेड ग्रोथ में तब्दील करने का 11वीं पंचवर्षीय योजना का आब्जेक्ट था वह ग्रोथ भी इनक्लूजिव, समाज के सभी तबकों को साथ लेकर। पूरे राजस्थान के आम-अवाम को साथ लेकर विकास की तरफ बढ़ने की जो बात की थी उस टार्गेट के बारे में लोग चर्चा करते, उन्हें यह बताना पड़ता कि उस टार्गेट का क्या हुआ। उन्हें यह भी बताना पड़ता कि हम प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत पर ले जाना चाहते हैं जिसमें आज भी 11-12 हजार रुपये का गैप है, उसका क्या हुआ। न हम यह टार्गेट पूरा कर पाए, न हम 9 परसेंट की इकोनोमी ग्रोथ का टार्गेट पूरा कर पाए। इसके बजाय हमने किया क्या, 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमने टार्गेट घटा लिये। टार्गेट तो पूरे कर नहीं पाये? 12वीं पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रियल सैक्टर की ग्रोथ को हमने कम कर लिया, एग्रीकल्चर सैक्टर की ग्रोथ को हमने कम मान लिया।

एक बात मुख्य मंत्रीजी ने बड़े जोर से कही, 10-15 लाइनों में एक ही बात कहते रहे वो कि सरप्लस बजट है, रेवेन्यू सरप्लस। उपाध्यक्ष महोदय, बजट सरप्लस का तो कोई मतलब नहीं होता। कर्ज लेकर अगर बजट का सरप्लस पैदा किया जाए तो जितना सरप्लस उन्होंने छोड़ा था, 2-3 हजार करोड़ रुपए का कर्ज और लेते, बजट सरप्लस और बढ़ जाता। इसलिए बजट सरप्लस तो मिसनोमर है। लेकिन जिस रेवेन्यू अकाउंट के सरप्लस की वह बात कर रहे हैं, वह राजस्थान 2007-08 में ही आ गया था, 2006-07 में ही आ गया था। बड़ी बड़ी बात कही कि हम रेवेन्यू सरप्लस में आये। उन्होंने अपने बजट में क्या कहा? कुशल वित्तीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप हम वित्तीय मानकों में सुधार ला सके। और 2011-12, बजट पेश कर रहे हैं 2013-14 का, हवाला दे रहे हैं 2011-12 का, 2011-12 का राजस्व अधिशेष 3357 करोड़ रहा है। फिर उसके बाद में 2011-12 का यह अधिशेष 2013-14 आते-आते एक तिहाई कैसे रह गया? जिस 2011-12 के अधिशेष की घोषणा आप 2013-14 के बजट भाषण में छाती ठोक कर कह रहे हो। आपको राजस्थान की जनता को यह भी बताना था कि जो अधिशेष 2011-12 में 3357 करोड़ का था वह घटते-

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

घटते 2013-14 में एक तिहाई कैसे रह गया। यह अधिशेष जिसके लिए आप छाती ठोक रहे हो, वह भी आपके भरोसे नहीं आया था। आ भी नहीं सकता क्योंकि जिस वित्त मंत्री की खुद की राजस्व प्राप्तियां, आन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, उसकी वृद्धि दर 12, 13, 14 पांच साल चली हो और जिसका रेवेन्यू एक्सपेंडीचर 26 परसेंट की दर से बढ़ा हो, मेरा खर्चा तो बढ़ रहा हो 26 परसेंट की दर से और मेरी आय बढ़ रही हो 12 परसेंट, 14 परसेंट, मेरी औकात वाली आय, मेरी आय जो मैं जनरेट करता हूं, जिसको जनरेट करने की मेरी पोटेंसी है वह बढ़ रही है 13 परसेंट, 14 परसेंट, 12 परसेंट, तो अपने आप ही राजस्व सरप्लस नहीं आ सकता। लेकिन राजस्व सरप्लस फिर भी आया। यह फिर भी कैसे आया? क्योंकि यह सरप्लस मुख्य मंत्रीजी का सरप्लस नहीं था, यह सरप्लस राजस्थान के फाइनेंस मिनिस्टर का सरप्लस नहीं था। यह पैरासाइट सरप्लस था। यह राजस्थान के +++ का पैरासाइट सरप्लस था जो अपने बूते पर खड़ा नहीं हुआ। यह सरप्लस आया इसलिए, 13वें वित्त आयोग ने अपने अंशदान में ढाई गुणा वृद्धि नहीं की होती, ग्रांट-इन-एड में दो गुणा वृद्धि नहीं की होती और राजस्थान की जनता की किस्मत से राजस्थान में पैट्रोलियम पैदा नहीं हुआ होता तो मैं इतना बताना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा राजस्व घाटा अगर दर्ज होता तो वह अशोक गहलोत के राज में दर्ज होता। आल टाइम, न भूतो न भविष्यति- न कभी भूत में हुआ, न कभी भविष्य में होगा। अगर यह पैट्रोलियम नहीं मिलता, 13वां वित्त आयोग ढाई गुणा पैसा ज्यादा नहीं देता, ग्रांट-इन-एड में दो गुणा पैसा नहीं मिलता तो राजस्थान की हालत आज सबसे बड़े रिकार्ड रेवेन्यू डेफिसिट की हुआ करती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, वसुंधरा जी के पांच साल में हमको दिल्ली से पैसा मिला था। सेंट्रल ट्रांसफर्स थे हमारे, हमको मिले पूरे पांच साल में 54582 करोड़- ग्रांट-इन-एड भी शामिल कर लो, हमारे सेंट्रल टैक्स के शेयर भी शामिल कर लो। और इन फाइनेंस मिनिस्टर साहब को दो साल में कितने मिले? हमसे दो हजार करोड़ से ज्यादा 56595 करोड़ तो इनको दो साल में ही मिल गये। जिसको दो साल में 56595 करोड़ रुपए मिल जाएं, वह आज राजस्व अधिशेष की बात करे। राजस्व अधिशेष की थोथी बातें बंद करें और राजस्थान की जनता को यह बताएं कि पांच साल में, 112640 करोड़ रुपए के सेंट्रल ट्रांसफर्स के बावजूद और 15615 करोड़ की पैट्रोलियम आय के बावजूद और राजस्थान की जनता पर 2051 से लेकर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

4620 रुपए तक का टैक्स लादने के बावजूद राजस्व अधिशेष लगातार कम क्यों हो रहा है। यह राजकोषीय घाटा लगातार क्यों बढ़ रहा है? इतना ज्यादा, 112640 करोड़ रुपया। साढ़े पन्द्रह हजार करोड़ से ऊपर पैट्रोलियम से और जनता पर टैक्स हो जाए दो गुणा, उसके बावजूद राजस्व अधिशेष घट रहा है, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। 2007-08 में वसुंधरा जी के राज में फिस्कल डेफिसिट जी एस डी पी का था केवल 1.75 परसेंट। किसी 13वें वित्त आयोग के कहने से नहीं किया था हमने, किसी 12वें वित्त आयोग के दवाब से नहीं किया था हमने। यह हमारी फिस्कल पोटेंसी से किया था। फिस्कल पोटेंसी से हमारा फिस्कल डेफिसिट था 1.75 परसेंट जी एस डी पी का। आज क्या है? आज 2.48 है। 2.48 फिस्कल डेफिसिट हो गया, लगातार बढ़ता हुआ। 2011 में फिस्कल डेफिसिट 3625 करोड़ था वह 2012-13 में 208 परसेंट बढा। एक साल में फिस्कल डेफिसिट बढ़ा 208 परसेंट और वह हो गया 11203 करोड़ रुपया। 2011-12 के फिस्कल डेफिसिट का मुकाबला मैं इस साल के फिस्कल डेफिसिट से करूं तो 2011-12 के मुकाबले 2013-14 में फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया 270 परसेंट से ज्यादा। जिसका फिस्कल डेफिसिट तीन साल में 270 परसेंट बढ़ जाए, जिसका राजकोषीय घाटा 1.75 से 2.4 पर आ जाए, जिसका रेवेन्यू सरप्लस पैरासाइट सरप्लस हो, उसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? यह भी इसलिए किया कि एफ आर बी एम से डर रहे हैं। एफ आर बी एम ने कहा कि 3 परसेंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो क्या करें? आप दिल्ली नहीं गये क्या? राजस्थान पावर सैक्टर रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान दिल्ली के सामने पेश नहीं किया क्या आपने? रिस्ट्रक्चरिंग प्लान में आपकी सहमति नहीं है क्या? रिस्ट्रक्चरिंग प्लान कह क्या रहा है? रिक्स्ट्रक्चरिंग प्लान कह रहा है, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, दिसम्बर, 2011 तक जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनीज हैं जिनके ऊपर कर्जा था 39 हजार करोड़ रुपए का, उस 39 हजार करोड़ रुपए के आधे कर्जे को आने वाले पांच साल में सरकार के कर्जे के रूप में आप वहन कर लेंगे। आज साल शुरू हो गया, 19500 करोड़ का मतलब हुआ 3900 करोड़ रुपया प्रति वर्ष। इस साल के 13 हजार करोड़ के कर्जे में आपने बजट में यह दिखाया नहीं, यह 3900 करोड़ का वादा जो दिल्ली करके आये हो और जो कल पूरा करना पड़ेगा आपको, इसको आपने बजट में दिखाया नहीं। बजट से छुपाया। एफ आर बी एम से डर गये, 13वें वित्त आयोग से डर गये। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आज छुपा लेंगे, कल चुनाव में मालूम

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

पड़ेगा, आर ई में आएगा, एक्चुअल में आएगा। और जब यह आर ई और एक्चुअल में आएगा तो फिस्कल डेफिसिट 13 हजार करोड़ का नहीं रहेगा, यह फिस्कल डेफिसिट 17 हजार करोड़ से ऊपर जाएगा और एफ आर बी एम की धज्जियां उड़ाने वाले मुख्य मंत्री के रूप में आपको याद किया जाएगा।

मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपको ईमानदारी के साथ राजस्थान की जनता के सामने यह स्वीकार करना चाहिए था कि आप फिस्कल कंट्रोल खो चुके हो। 3 परसेंट से ज्यादा आपका फिस्कल डेफिसिट होने वाला है जब आप रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के पैसे को समाहित करेंगे। रेवेन्यू सरप्लस आपके भरोसे नहीं है। आपको कहना चाहिए, आपको साफ तौर से राजस्थान की जनता को बताना चाहिए कि आप फिस्कल कंट्रोल खो चुके हैं, आपकी फिस्कल क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। बैंकों ने आपको पैसा देने से मना कर दिया है। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी की डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनीज को तो बैंकों ने बहुत पहले हाथ खडे कर दिये एक तरीका निकाला कि कम्पनी ले आये। हमको तो कर्जा चाहिए, कर्जे के बिना हमारा काम नहीं चलता। बैंक हमको कर्जा देता नहीं। बैंक हमको कर्जा देना नहीं, क्या किया इन्होंने? एक नई कम्पनी बना ली, राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड। काम क्या है उसका? कोई काम नहीं। अपना काम कर्जा लेना। आपको क्यों कोई कर्जा दे देगा? डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनीज के पास कोई सामान नहीं, इस कम्पनी के पास सामान नहीं। इस कम्पनी के सामान के लिए आपने किया क्या? आपने कहा कि जहां-जहां सरकारी जमीन अलाट होगी वहां 10 प्रतिशत की जमीन फोकट में इस कम्पनी को चली जाएगी। पूरे राजस्थान में जहां-जहां जमीन का अलाटमेंट होगा उसका 10 प्रतिशत इस कम्पनी को चला जाएगा और वो दस प्रतिशत जमीन को ही ये मोरगेज करेंगे। इसको ऐसे क्यों बताएंगे? मोरेगेज करेंगे, वो कर्जा लेंगे और कर्जा लेकर कम्पनियां चलाएंगे। ऐसी हालत को राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की जनता ने कभी नहीं देखा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप राजस्थान को तबाह कर रहे हैं। अभी क्रेडिबिलिटी खतम हो चुकी है। आप राजस्थान को तबाह कर रहे हैं। वसुन्धरा जी के राज की 8 परसेंट की जी एस डी पी की रेट से घटकर आप 5.3 पर तो आ गये। आपने खुद के डाक्यूमेंट में मान लिया, यह डाक्यूमेंट आपका है, पेश किया है मुख्य मंत्रीजी ने। इन्होंने खुद मान लिया कि अगले साल कोई ग्रोथ-व्रोथ नहीं होने वाली है। अब के साल हो गई 5.3, कैसे मिला-मिलूकर कर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

लिया, अगले साल कोई ग्रोथ नहीं है। यह जो बजट इन्होंने पेश किया है, it will generate low growth in Rajasthan यह खुद कह रहा है एफ आर बी एम एक्ट के अन्दर वर्ष 12-13 में। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी एस डी पी की ग्रोथ रेट कैसे निकाली जाती है। इस तरह से है कि जो नोमीनल ग्रोथ रेट है, प्रचलित मूल्यों पर जो जी एस डी पी है उसमें इन्फ्लेशन को घटाने के बाद जी एस डी पी आती है। जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें नोमीनल ग्रोथ रेट को माइनस कर दो तो मोटे तौर पर, I am talking about thumb rule, जी एस डी पी आ जाएगी। आपने क्या कहा? इस साल आपकी 14 परसेंट है, तभी तो 5 पाइंट आया आपका ग्रोथ रेट। इन्फ्लेशन घट गया, 5.3 परसेंट आ गया। आपने कहा, अगली साल क्या होगा। वर्ष 12-13 में सकल घरेलू उत्पाद चालू कीमतों पर 14.73 परसेंट यानि 5.3 परसेंट की ग्रोथ जीएसडीपी की। वर्ष 13-14 में क्या होगी? 10 परसेंट अनुमानित। यानि जहां पर इनफ्लेशन चल रहा हो 9.6 परसेंट, 9.6 परसेंट के इनफ्लेशन पर ग्रोथ अगर नोमीनल 10 परसेंट आती है तो जीएसडीपी की असल ग्रोथ होगी पाइंट चार परसेंट। इनका दावा भी पूरा कर लें तो इनका वादा है अगली साल राजस्थान में केवल 5.4 परसेंट ग्रोथ देने का। जो सरकार अपने पूरे बजट में पाइंट चार परसेंट ग्रोथ का दावा करती है, उससे आप किसी भी प्रकार से ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी दयनीय हालत पांच साल में हुई क्यों? हम तो बहुत अच्छा राज छोड़कर गये थे। रेवेन्यू सरप्लस था, फिस्कल डेफिसिट 1.75 पर था, 8 परसेंट की ग्रोथ रेट थी, यह हालत पांच साल में बिगड़ क्यों गयी? क्योंकि इकोनोमी की ग्रोथ के लिए सिर्फ बातें नहीं चाहिए थीं। विधान सभा में और प्रेस के सामने बड़ी-बड़ी बातें करने से इकोनोमी में बूस्ट पैदा नहीं होता। घोषणाएं करने से इकोनोमी में बूस्ट पैदा नहीं होता, ओछेपन के आरोप लगाने से इकोनोमिक बूस्ट पैदा नहीं होता। इकोनोमिक बूस्ट पैदा होता है कैपिटल से। अगर इकोनोमिकल ग्रोथ आपको लानी है तो कैपिटल की ग्रोथ लानी पड़ेगी कैपिटल की ग्रोथ से आपके यहां इकोनोमिकल बूस्ट मिलेगा। आपको खर्चा चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडीचर। आपके बजट में कैपिटल एक्सपेंडीचर कितना है? इकोनोमी में थ्रस्ट पैदा करने के लिए कैपिटल आउट-ले कितना है? आप अर्थव्यवस्था को कैपिटल एक्सपेंडीचर प्रोवाइड करा पाये न कैपीटल आउट-ले पर ले पाये। आपका कुल खर्चा लगातार बढ़ रहा है। आपका कुल खर्चा भी बढ़ रहा है, आपका राजस्व खर्चा भी बढ़ रहा है। कैपीटल

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

एक्सपेंडीचर बढ़ने के बाद लगातार घट रहा है। 2013-14 में राजस्व व्यय बढ़ा है 12.53 परसेंट की दर से। राजस्थान सरकार का 2013-14 में जो रेवेन्यू एक्सपेंडीचर है, वह बढ़ेगा इनके खुद के बजट के हिसाब से 12.53 प्रतिशत की दर से। पर कैपिटल एक्सपेंडीचर बढ़ेगा नहीं, घटेगा। माइनस पाइंट 66 परसेंट की दर से। जिस इकोनोमी का कैपिटल एक्सपेंडीचर नेगेटिव हो और जिसका रेवेन्यू एक्सपेंडीचर वैरी पाजीटिव हो टू द एक्सटेंट आफ 13 परसेंट, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? इन माननीय मुख्य मंत्रीजी के, वित्त मंत्रीजी के काल में गये पांच साल के कैपिटल एक्सपेंडीचर की तीन बार नेगेटिव ग्रोथ रह गई है। जिसकी पांच साल में तीन बार कैपिटल एक्सपेंडीचर की ग्रोथ रेट नेगेटिव रही हो, उसके बारे में खुदा खैर ही करे। उसके बारे में क्या बात करनी है। कैपिटल आउट-ले, कैपीटल एक्सपेंडीचर का और भी कलेजा है जो असल थ्रस्ट पैदा करता है जी डी पी में, जो जी डी पी को बढ़ाता है, जो राजस्थान की इकोनोमी के अन्दर कर्ज चुकाने की ताकत पैदा करता है, जो रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कैपिटल फार्मेशन करता है। हमारे शासन काल में पूरे पांच साल में कैपिटल आउट-ले था टोटल बजटरी वोल्यूम का 14.60 परसेंट, पूरे पांच साल में। यानि 100 रुपये हम जो इकोनोमी में पम्प कर रहे थे उसका 15 परसेंट सीधा राजस्थान की जी डी पी को बढ़ाने, कैपिटल फार्मेशन करने, एम्प्लायमेंट जनरेट करने, असेट्स जनरेट करने के लिए खर्च कर रहे थे। आपके जमाने में आकर रह गया 12.3 परसेंट। इतनी जेनरस दिल्ली की हैल्प के बावजूद, इतनी जेनरस ग्रांट-इन-एड के बावजूद, राजस्थान की जनता पर दुगने से ज्यादा टैक्स डालने के बावजूद आपका कैपिटल आउट-ले रह गया 12.3 परसेंट। आप कैपिटल एक्सपेंडीचर नहीं बढ़ा पाये, कैपीटल आउट-ले नहीं बढ़ा पाये। एक चीज बढ़ा पाये आप, कर्जा। मुझे किसी ने पूछा कि यह सरकार पांच किस पर टिकी रही। मैंने कहा, तीन 'क' पर टिकी रही। पहला कृपा पर टिकी रही, दिल्ली की कृपा पर, दिल्ली की थर्टीन्थ फाइनेंस कमीशन की कृपा पर, ग्रांट-इन-एड की कृपा पर या राजस्थान की जनता की किस्मत के भरोसे जो पैट्रोलियम का पैसा है उसके भरोसे या कर्ज के भरोसे। पूरे पांच साल में इन तीन 'क' पर मुख्य मंत्रीजी ने अपनी अर्थव्यवस्था चलाई हो, कृपा पर चलाई हो, किस्मत पर चलाई हो, कर्जे पर चलाई हो, उसके बारे में क्या कह सकते हैं।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कर्जे के लिए हमने कई नये -नये तरीके ईजाद किए हैं। मैंने आपको कहा कि राजस्थान स्टेट पावर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

फाइनेंशियल कारपोरेशन बनाया है हमने। एक नया ट्रेंड हमने शुरू किया है पांच साल में। राजस्थान की जनता को धोखे में रखकर कर्जा लगाया है। पहले हम प्लान साइज बढ़ाते थे, हमने भी प्लान साइज बढ़ाया। हम प्लान साइज बढ़ाते, कर्जा बढ़ता था। लोग कहते थे, कर्जा बढ़ रहा है। सरकार का बढ़ रहा है, भई। प्लान की साइज बढ़ रही है, विकास करना चाहते हैं इसलिए कर्जा बढ़ रहा है। आपने क्या करना शुरू किया? आपका कर्जा बचत में नहीं दिखता। कम दिखता है, असल कर्जा आपका ज्यादा होता है। आपकी जो प्लान फन्डिंग है, प्लान फन्डिंग की जो बोरोइंग है उस बोरोइंग को आप बजट में रिफ्लैक्ट नहीं करते और कहते हैं कि यह गारंटी लोन है, हमारा लोन नहीं है। यह गांरटी लोन है। भाई साहब, अगर आपका लोन नहीं माना जाएगा तो कर्जे वाली कम्पनियों को बैंक लोन देना क्यों बंद किया? आपने गये पांच साल के अन्दर प्लान फन्डिंग के नाम पर बजट से बाहर, बजट से ज्यादा बोरोइंग की है। आपने पूरे पांच साल के अन्दर बजट बोरोइंग की है 43 हजार 238 करोड़ रुपये की, नैट बोरोइंग। बजट बोरोइंग आपने की है 43 हजार 238 करोड़ की और एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग, आउटसाइड बजट बोरोइंग, वो बोरोइंग की है आपने 53 हजार करोड़ से ऊपर। इस प्रकार से आपने अकेले इस साल में पूरे 25 हजार से ज्यादा का कर्जा लिया है और बजट बोरोइंग 43 हजार 238 करोड़ रुपये करने के बाद में राजस्थान का खुद का खर्चा हो गया है 1 लाख 31 हजार 480 करोड़। आउट साइड बजट बोरोइंग आपने शुरू की है वह की है 81 हजार 936 करोड़ रुपये।

श्री उपाध्यक्ष: करीब 20 मिनट हो गये आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बोलने दीजिए, साहब।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): आपने जो नये कर्जे का तरीका निकाला है, कर्जे के तरीके को छुपाकर निकाला है जो डिसीटफुल डैट है, धोखे से ले रहे हो आप, राजस्थान की जनता की आंखों में धूल झोंककर आप कर्जा ले रहे हो, उस कर्जे की चर्चा करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी बोरोइंग पांच साल में हुई है। इस प्रकार राजस्थान की जनता पर 31 मार्च, 2014 तक कर्जा होगा 2 लाख 13 हजार 416 करोड़ रुपये, यानि आज की जो जी डी पी चल रही है अभी, उसका 50 परसेंट और आपकी रेवेन्यू रिसीट का 276 परसेंट। आपकी रेवेन्यू रिसीट का 276 परसेंट कर्जा आपने राजस्थान की

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जनता पर डाल दिया, आपकी सरकार ही वेंटिलेटर पर नहीं है, सर। आपने खुद पांच वेंटिलेटर पर रहते-रहते राजस्थान की अर्थव्यवस्था को ही वेंटिलेटर पर डाल दिया है। आज आप फिस्कल डेस्ट्रक्शन के किनारे पर हैं, राजस्थान राजकोष विनाश के कगार पर है। आज राजस्थान का आम आदमी पिस रहा है। 2007-08 में राजस्थान का प्रति व्यक्ति टैक्स चुका रहा था 3 हजार 369, आज राजस्थान का आदमी टैक्स चुका रहा है सात हजार तीन सौ तैयासी रुपये एक साल में। यानि पांच साल में दुगने से ज्यादा टैक्स आपने जनता से लिया है। गांव डूब रहा है, किसान डूब रहा है, जी एस डी पी के अन्दर एग्रीकल्चर का हिस्सा घट रहा है। घटते-घटते 70 परसेंट लोग रह गये एग्रीकल्चर पर। जी एस डी पी में हमारा हिस्सा 19 परसेंट हिस्सा हमारा आ रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर पर जो लोग टिके हुए हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय कान्स्टेंट प्राइस पर पिछले तीन साल से लगातार गिर रही है- 2010-11 के अन्दर थी 14790 रुपये, 2011-12 के अन्दर घटकर आई 14554 रुपये और 2012-13 में घटकर रह गई 13957 रुपये। अगर आपने यह टैक्स लगा दिया सात हजार तीन सौ तियासी रुपये का, इसको मैं माइनस कर दूं, नैट इनकम निकालना चाहता हूं, तो राजस्थान के किसान केवल 88 रुपये रोज पर जिन्दा हैं। 88 रुपये रोज पर जिन्दा हैं। यह अलग बात है कि आप कहें कि 26 रुपये, 32 रुपये कमाने वाला भी अमीर है। वह गरीबी की रेखा में नहीं है, वह अमीर है। लेकिन अब मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के आदमी की आमदनी लगातार घट रही है। उनके लिये राजस्थान के मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री बनकर नहीं आये, एक काल बनकर आये। गांव के गरीब और किसान के लिये काल बनकर आये हैं।

अब चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली से लेकर जयपुर तक एक ही नाम सुन रहा है- फ्लैगशिप, फ्लैगशिप। आपको पता है आपके फ्लैगशिप में फ्लैग कौन से कलर का है? लाल रंग का, खतरे का। शिप डूबने वाला है खुद, डुबोने वाला भी है। आप क्या सोचते हैं कि राजस्थन की जनता और हिन्दुस्तान की जनता खुद्दार नहीं है? आजादी के 65 साल बाद अगर हिन्दुस्तान की जनता के लिये फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया जाए, हिन्दुस्तान की आजादी के 65 साल बाद अगर हिन्दुस्तान की जनता के लिये साड़ी बांटी जाए, कम्बल बांटा जाए तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। हिन्दुस्तान में 65 साल राज किसने किया? लगातार राज करने वाले लोग, उन्होंने जी.डी.पी. को 3.5

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

प्रतिशत पर रखा। 1947 में हम आजाद हुए, इससे दो साल पहले जापान नाम का छोटा-सा देश नेस्तनाबूद हो गया था। आज जापान कहां, हम कहां! हमसे एक साल बाद चीन में आजादी आई। आज चीन कहां, हम कहां हैं! हमारे बाद इजराइल पैदा हुआ, आज हम कहां हैं, वह कहां है! कोरिया कहां है! हम कहां हैं! अगर हमारी जी.डी.पी. की ग्रोथ रेट 6 प्रतिशत होती, अगर हम यह चेन्ड इकोनोमी नहीं लाये होते, अगर हम बैरिकेडेड इकोनोमी नहीं लाये होते, अगर हमने कैपिटल को खुला छोड़ा होता, टैक्नोलोजी को खुला छोड़ा होता, अगर आपने ट्रेड को खुला छोड़ा होता तो राजस्थान के अन्दर और हिन्दुस्तान के अन्दर ग्रोथ रेट 8 से 9 प्रतिशत आती। और 8 से 9 प्रतिशत ग्रोथ रेट आती तो जिस पर-कैपिटा इनकम की मैं बात कर रहा हूं वह पर-कैपिटा इनकम 10 गुने से ज्यादा होती। राजस्थान क्या हिन्दुस्तान के आदमी को कटोरा लेकर, भीख मांगकर सरकार से कम्बल मांगने की जरूरत नहीं होती। राजस्थान की जनता, यहां राणा पैदा हुए, यहां सांगा पैदा हुए हैं, यहां सूरजमल पैदा हुए हैं, यहां वोटों का सौदा नहीं हो सकता, यहां स्वाभिमान का सौदा नहीं हो सकता। आज आप पूरे बाजार में जाकर कह रहे हैं एक रुपया किलो चावल, एक रुपया किलो गेहूं ले लो। पांच रुपये किलो आटा ले लो, साड़ी ले लो, कम्बल ले लो, पर हमको वोट दे दो। किसलिये वोट दे दो? जिसकी चर्चा मैं आधे घण्टे से कर रहा हूं- राजस्थान को डुबोने के लिये, राजस्थान के गरीब को मारने के लिये, राजस्थान के गांव को पीछे किनारे पहुंचाने के लिये, राजस्थान के युवा को सड़कों पर घुमाने के लिये? कोई इन वोटों का सौदा करने वाला नहीं है। यह आपका फ्लैगशिप जो रैड रंग का फ्लैग लेकर चला है, यह आपको डुबोएगा। निश्चित रूप से डुबोएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप इतने ही बड़े आदमी थे, नरेगा लेकर आये, दिल्ली से फलाना-फलाना लेकर आये, वह आपकी स्पेशल कैटेगरी का क्या हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं? राजस्थान को स्पेशल कैटेगरी की लगातार बात कर रहे थे- राजस्थान इतना बड़ा है, इतना डैजर्ट है, इतना बार्डर है, सर्विसेज को पहुंचाने की कास्ट बहुत ऊंची है। उन्होंने आपको धक्का देकर निकाल दिया तो आप कहने लगे कि नहीं, नहीं, हमको पैकेज दे दो। पानी का 55 हजार करोड़ का पैकेज दे दो। वह पैकेज कहां गया 55 हजार करोड़ का? आप कह रहे थे, कड़ी से कड़ी मिला दो। हमने तो कड़ी से कड़ी मिला दीं। लेकिन राजस्थान की कड़ियां आपने तोड़ दीं। राजस्थान की जनता

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

की कड़ी आपने तोड़ दी। उसके लिये राजस्थान की जनता आपको कतई माफ नहीं करेगी, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

बड़े जोर-शोर से बातें चल रही थीं रिफाइनरी, रिफाइनरी। रिफाइनरी ला रहे हैं, हम ला रहे हैं, हम लाएंगे। हम भी लाना चाहते थे। हमारे टाइम ही बातें शुरू हुई थीं। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को पूछना चाहूंगा, मैंने अर्थशास्त्र के जितने जानकार हैं उनसे बात करने की कोशिश की। रिफाइनरी की दुनिया में जितने एक्सपर्ट्स माने जाते हैं उनसे मैंने बात करने की कोशिश की। मैंने उनसे पूछा, हमें एक इकोनोमिक्स समझ में नहीं आ रही है। मुख्य मंत्रीजी को ज्यादा आती है इकोनोमिक्स। 37 हजार करोड़ रुपये की राजस्थान में रिफाइनरी लगेगी। 37 हजार करोड़ की रिफाइनरी लगेगी यानी कैपिटल इन्वैस्टमेंट होगा 37 हजार करोड़ का। 37 हजार करोड़ की दुकान लगेगी और दुकान को चलाने में जो घाटा होगा, वह होगा 57 हजार करोड़ का। 37 हजार करोड़ का कैपिटल इन्वैस्टमेंट, 53 हजार करोड़ का उसमें घाटा। यानी उसमें वाएबिलिटी गैप हम देने वाले हैं 15 साल तक लगातार पौने चार हजार करोड़ रुपये हर साल। ऐसी रिफाइनरी राजस्थान के इतिहास में कहां है? पहली बार तो रिफाइनरी आ रही है। राजस्थान 15वां स्टेट है। 24वीं, 25वीं, 26वीं रिफाइनरी हिन्दुस्तान में लग रही है। मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, जब मुख्य मंत्रीजी इस पर जवाब दें, हमारा ज्ञानवर्द्धन करें कि लास्ट हिन्दुस्तान में लगी हुई कौनसी रिफाइनरी ऐसी है जिसका वायबिलिटी गैप इतना ह्यूज है? जिसके कैपिटल इन्वैस्टमेंट और वाएबिलिटी गैप के बीच में यह रेशो है? यही बात थी, ओ.एन.जी.सी. लगातार इस तरह की मांग कर रही थी। अगर इस मांग को स्वीकार कर लेते तो रिफाइनरी बहुत पहले लग चुकी होती, हुजूर। आज काम हो रहा होता। जमीन देंगे, पानी देंगे, इन्फ्रास्ट्रक्चर देंगे, बिजली देंगे और 57 हजार करोड़ रुपये लेंगे। जब आप 57 हजार रुपये कर्ज रहित लेंगे 15 साल के लिये तो यह 37 हजार करोड़ रुपये भी कैपिटल इन्वैस्टमेंट है। यह तो कर देते आप, आपके बजट में क्या है? आपका तो प्लान बहुत बड़ा है, कर्जा ही तो लेना था। पहले ही हम तो बहुत जोरदार कर्जा ले रहे हैं। आपका प्लान फंडिंग हम कर रहे हैं। फाइव-ईयर प्लान बनाया है एक लाख 94 हजार 283 करोड़ का। इसमें 37 हजार करोड़ ज्यादा लगते, कर्जा लेते, हम समर्थन करते। ऐसे कर्जे का हम समर्थन करते। वैसे भी एक लाख 94 हजार 283 करोड़ के इस फाइव-ईयर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

प्लान में एक लाख 54 हजार 260 करोड़ रुपये कर्ज ही है, हुजूर। एक लाख 54 हजार 260 करोड़ का कर्जदार बनाएगा यह प्लान राजस्थान की जनता को। इसमें 37 हजार करोड़ रुपये जोड़ते तो हमारे यह शांति होती कि 37 हजार करोड़ रुपये कैपिटल इन्वैस्टमेंट किया। यह राजस्थान की अपनी रिफाइनरी है, हमारी रिफाइनरी है, हमने कर्जा लिया। लेकिन आम जनता की रिफाइनरी है, हम कर्जा लेंगे। यह 57 हजार करोड़ का भी कर्जा है, इतना पैसा कहां है हमारे पास में? इतना रेवेन्यू सरप्लस कहां है हमारा? यह कर्जा लेंगे। रिफाइनरी के नाम पर वोटों की सौदेबाजी की, रिफाइनरी जिन शर्तों पर लाई गई है। हम रिफाइनरी का स्वागत करते, हम रिफाइनरी की लगातार कोशिशें करते, लेकिन राजस्थान की जनता के हितों की कीमत पर नहीं। राजस्थान की जनता की शर्तों पर रिफाइनरी लानी चाहिए थी। राजस्थान की जनता के हित के साथ समझौता करके, एच.पी.सी.एल. के सामने घुटने टेक कर, मोइली के सामने घुटने टेक कर नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सुल्तानपुर में एक रिफाइनरी लगी थी, स्टोन-लेइंग सेरेमनी हो गई थी, यू.पी. में सुल्तानपुर, रायबरेली कांस्टीट्युएंसी के पास। नरसिंहरावजी पधारे, कैप्टन सतीश पधारे, फाउण्डेशन लेइंग सेरेमनी हो गई, रिफाइनरी आज तक नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? वाएबल नहीं थी। अगर इतना बड़ा वाएबिलिटी गैप है तो फिर रिफाइनरी लगेगी नहीं। 37 हजार करोड़ के कैपिटल इन्वैस्टमेंट पर 53 हजार करोड़ का वाएबिलिटी गैप है तो रिफाइनरी लग ही नहीं सकती। और यह वाएबिलिटी गैप अगर नहीं है तो वाएबिलिटी गैप के नाम पर राजस्थान की जनता के हितों के साथ सौदा हम नहीं होने देंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस तरह से 5 साल की विनाशकारी सरकार रही है, मौतों की चर्चा तो मैं करूंगा नहीं, बहुत लोगों ने चर्चा की है, 5 साल के अन्दर कभी तो स्वाइन-फ्लू से मर गये, कभी गलत ग्लूकोज चढ़ा दिया, प्रसूताओं की मौत हो गई, कभी आई.सी.यू. में चूहा कुतर गया, सैकड़ों मर गये। राजस्थान के इतिहास में गये 5 साल में साढे चार सौ से ज्यादा नैग्लिजेंस मौतें हुई हैं। यह राजस्थान की सरकार, राजस्थान की सरकार नहीं, मोंस्टरस गवर्नमेंट है। यह राजस्थान की जनता के लिये मोंस्टरस गवर्नमेंट थी। इस मोंस्टरस गवर्नमेंट का पेश किया हुआ ऐसा बजट जिसमें मुख्य मंत्रीजी को यह भी पता नहीं कि तैर रहे हैं या डूब रहे हैं। सिंकिंग और स्वीमिंग में अन्तर जिस मुख्य मंत्री को पता नहीं हो, वह पानी में जाने को ही

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

अपने को तैरना मानते हैं। पानी में हूं, मतलब तैर रहा हूं। पानी में होने का मतलब डूबना भी हो सकता है। सिंकिंग चीफ मिनिस्टर अपने आपको स्वीमिंग चीफ मिनिस्टर मानता रहा। पूरी की पूरी यह वोकल गवर्नमेंट, वर्किंग गवर्नमेंट से डीविएट होकर जो वोकल गवर्नमेंट हुई, इसका यह थोथा ढपोरशंख बजट जिसकी घोषणाएं यहां पूरी हो ही नहीं सकतीं, आज तक आपने नहीं किया, अब भी नहीं कर सकते, ऐसे ढपोरशंख बजट का राजस्थान की जनता और राजस्थान की जनता में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो समर्थन करता हो, इसलिये मुझे भी समर्थन करने की हिम्मत नहीं है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री प्रतापसिंह जी खाचरियावास।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आदरणीय उपाध्यक्षजी, हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट के समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्षजी, हर वर्ष बजट पेश होता है और बजट को लेकर जनता में भी चर्चा होती है, जन प्रतिनिधियों में भी चर्चा होती है, विद्वानों में भी चर्चा होती है। हर कोई बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देता है। सबको प्रतिक्रिया देने का अधिकार है। हर आदमी अपने-अपने नजरिये से बजट की व्याख्या करता है। जो जनता है, जो राजस्थान के लोग हैं, जो सात करोड़ की आबादी है, जिस दिन बजट जारी होता है और अखबारों में साया होता है उसके बाद थड़ी पर बैठ कर, दुकान पर बैठ कर हर जगह गरीब से गरीब आदमी भी यदि वह अनपढ़ है तो बात जरूर करता है कि आज बजट में नया क्या आया है। कोई नई बात आई है क्या। अपने भी मतलब की बात है या फिर बड़े आदमियों का ही बजट है। इस तरह चर्चा जब आम आदमी करता है, गांव और ढाणी में बैठकर करता है, तब हम लागों को एक बात जरूर तय करनी चाहिए। जब बजट अच्छा आ जाए तो हम उसको कह दें, चुनावी बजट है। उससे पहले बजट अच्छा आ जाए तो, इसमें नई बात क्या कर दी। कहीं तो हमें बैठकर इस बात को तय करना पड़ेगा कि पूरा देश जिस मुद्दे पर बात कर रहा है, पूरा देश जिस मुद्दे पर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहा है, और वह मुद्दा है मंहगाई, उस मंहगाई को रोकने के लिये यदि काम किसी ने किया है तो राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने किया है। मंहगाई रोकने की शुरूआत इस बजट में उसी दिन से लागू हो गयी।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

(14.00 बजे)

आप मुझे एक बात बता दीजिए कि बजट किस का होना चाहिए? बजट आम आदमी का होना चाहिए। गरीब का होना चाहिए। गांव का होना चाहिए। ढाणी का होना चाहिए। मोहल्ले का होना चाहिए। विद्यार्थी का होना चाहिए। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर और किसान का होना चाहिए। बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें सर्व समाज की आवाज आती हो। जिसमें सर्व समाज यह कहता हो कि इस बजट में सबको मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है जब बजट में राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने 40139 करोड़ की योजना में समाज के किसी भी व्यक्ति को अलग नहीं रखा। समाज के हर तबके को देने की कोशिश की। शुरूआत की बिलो पावर्टी लाइन से और खतम किया एबव पावर्टी लाइन पर। ऐसा नहीं है कि व्यापारी को नहीं मिला। उसको भी मिला। ऐसा नहीं है मजदूर को नहीं मिला। उसको भी मिला। एक ऐसा बजट जिसमें यह भी फैसला हो गया कि अब 100 दिन के ही रोजगार की गारंटी नहीं होगी, अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। गांव छोड़कर आने की जरूरत नहीं है, गांव में बैठो, आपको रोजगार मिलेगा।

बार-बार कर्जे की बात हो रही है। कौन मना कर रहा है? हम खुद जानते हैं कि 52 परसेंट पैसा इनके जमाने में भी और हमारे जमाने में भी कर्मचारियों की तनख्वाह में और गैर योजना मद में खर्च हो रहा है। आप और हम मिलकर, चाहे राज इधर चला जाए या इधर चला जाए, लेकिन हम इन खर्चों को नहीं रोक पाये। जो आम आदमी के लिए हम खर्च कर रहे हैं वह 48 परसेंट ही है। अब पैसा कहां से आ रहा है और कहां पर जा रहा है, कर्जा कितना लेकर आये हैं और कर्जा कितना चुकाना है? जो कर्जा लेने की तैयारी की गई है, आज मैं गुजरात के मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदीजी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं तीन मुद्दों पर गुजरात को माडल स्टेट बना रहा हूं। तीन मुद्दे उन्होने बताये कि मैं आई.ए.एस. के आधार पर गुजरात को माडल स्टेट बना रहा हूं- आई.ए.एस., आई-इंवैस्टमेंट, ए-एग्रीकल्चर, और एस से उन्होंने कहा- सर्विस टैक्स। पर राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत वे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने डबल काम कर दिया। आप तो इंवैस्टमेंट, एग्रीकल्चर और सर्विस सैक्टर की ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया कि आइए, डबल है। उन्होंने इन्वैस्टमेंट, एग्रीकल्चर, सर्विस सैक्टर और साथ ही में सोशल सिक्योरिटी की भी गारंटी दे दी।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन, यह अकेले सिर्फ कांग्रेस की ही डिमांड नहीं थी। यह बी.जे.पी. की भी डिमांड थी। राजस्थान का हर जन-प्रतिनिधि यह चाहता था कि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन पर से राइडर हटा दिये जाएं। ये राइडर आप नहीं हटा पाये। आप जब भी चाहते थे आपकी हिम्मत नहीं हुई। आपने सोचा कि हम राइडर हटा देंगे तो हम करेंगे कैसे। हिम्मत के लिए नीयत अच्छी चाहिए। जब नीयत अच्छी होती है तो बरकत भी अच्छी होती है। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। आपकी नीयत ऐसी होनी चाहिए कि मैं आम आदमी तक फायदा पहुंचाना चाहता हूं। इस बजट में चीफ मिनिस्टर अशोक जी गहलोत की नीयत अच्छी है। सरकार की सोच अच्छी है। पिछले जो तीन बजट आये उनके मुकाबले यह बजट अच्छा लाना बहुत जरूरी था। हम यह उम्मीद कर रहे थे कि क्या यह बजट उनसे अच्छा आएगा? यह बजट उनसे बहुत अच्छा बजट आया, इसके लिए मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देता हूं।

जिस बात को लेकर कोर्ट चिंतित है, सारे लोग चिंतित हैं, इस बजट में एक बहुत बड़ा जो काम हुआ है बजट में उन्होंने यह कह दिया कि मेज नदी से पानी लेकर आएंगे लेकिन रामगढ़ बांध को जिंदा करेंगे। बहुत बड़ी सोच। और यह कोई घोषणा ही नहीं है, इसकी पूरी तैयारी हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी अपनी योजना बनाकर लोगों ने बताई कि बूंदी जिले से यहां तक हम पानी कैसे लेकर आएंगे। इतनी बड़ी सोच कि रामगढ़ बांध में पानी लेकर आएंगे, उसका पूरा प्लान तैयार हो जाए, प्लान तैयार होकर पानी पहुंच जाए। इस तरह की सोच, यह सिर्फ वोट के लिए सोच नहीं है। यह बात तय है कि जब भी बजट आता है तो अपोजीशन के लोग हर बार एक बात का प्रचार करते हैं कि यह सारा बजट है यह तो वोट के लिए है। तो आप भी क्या वोट के लिए, नोट के लिए बजट लाते थे? यह तो तय करना पड़ेगा। हर आदमी जो पोलिटिक्स में है, वह वोट की तो हमेशा ध्यान में रखता ही है। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? और चुनाव आ रहे हैं तो चुनावी बजट है, तो क्या हो गया? चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव का भी ध्यान रखेंगे। आपके जब चुनाव आते थे तो क्या आप चुनाव का ध्यान नहीं रखते थे? वोटर आपको वोट देकर, चुनकर विधान सभा में भेज रहा है। आप चैलेंज कर रहे हैं कि यह तो वोटर को लुभाने के लिए है। वोटर को तो लुभाना ही पड़ेगा। यह थोड़े ही न चलेगी।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

घर की दुकान है कि वोटर से वोट लेकर आ गये। यहां विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वोटर को लुभाने के लिए, इसका मतलब राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत राजस्थान के करोड़ों वोटर का सम्मान करते हैं, उनकी सोच का सम्मान करते हैं। उसके मन में सरकार के प्रति क्या सोच है, वह क्या सोचना चाहता है, उसका सम्मान करते हैं।

साढ़े 38 लाख बी.पी.एल. परिवार, 2 रुपये किलो में गेहूं, अब वह गेहूं एक रुपये किलो में। उसकी आंख में चमक है। आप जाकर उससे पूछो कैसा बजट है, वह कहेगा भगवान भला करे। 8 रुपये, 10 पैसे किलो में जो आटा मिलता था, वह 5 रुपये किलो में आटा हो जाएगा तो महंगाई नियंत्रित नहीं होगी? महंगाई पर कंट्रोल होगा। जो 81 रुपये का आटा आ रहा था वह 50 रुपये में आएगा।

मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहां पर मंत्रीजी नहीं हैं लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने तो घोषणा कर दी। पहले दो कट्टे मिलते थे। मैं कहूंगा, यह सरकार की मारल ड्यूटी बनती है। यही सरकार पहले दो कट्टे देती थी, आज वह एक कट्टा दे रही है। यह भी जांच होनी चाहिए उन अधिकारियों की कि पहले दो, अब एक क्यों? दो की व्यवस्था करें। मुख्य मंत्री ने साफ-साफ कह दिया कि हमारी पालिसी, हमारा बजट जो घोषित किया, उसको लागू करना मंत्रियों की ड्यूटी है। उनकी मारल ड्यूटी है। उनको मानिटरिंग मीटिंग करनी चाहिए। विपक्ष के और पक्ष के एम.एल.एज. को भी साथ में बैठाना चाहिए। उन अधिकारियों का भी पता चलना चाहिए कि कौन अधिकारी है जो इतने बढ़िया बजट को कम समय में लागू नहीं करना चाहता। उनका भी इलाज होना चाहिए। बजट बहुत अच्छा है, बजट में कोई कमी नहीं है। लेकिन बजट को लागू करना हमारी भी ड्यूटी है तो विपक्ष की भी ड्यूटी है। यह बजट केवल कांग्रेस का बजट नहीं है, यह राजस्थान की सरकार का बजट है। इस बजट के प्रति गम्भीरता दिखाना आपकी और हमारी मारल ड्यूटी है। यदि आज विपक्ष के लोग यह कह दें कि इस बजट से हमारा कोई लेना-देना नहीं है तो खड़े होकर घोषणा कर दें। क्या आज ये जितने भी सीनियर सदस्य बैठे हैं, इनकी मारल ड्यूटी नहीं बनती? बजट में जनता के लिए पैसे का प्रावधान किया गया है, कोई रिलैक्सेशन दिये गये हैं और जनता तक वह बजट का पैसा नहीं पहुंचे तो पक्ष और विपक्ष के लोगों की यह मारल ड्यूटी है कि उस बजट को लागू करवाएं। हाथ पकड़कर कहें कि यह जो बजट में प्रावधान हुआ है आप उसके

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

विपरीत जा रहे हैं। तब लोग कहेंगे कि राजस्थान की विधान सभा में बैठा हुआ हर सदस्य जनता की आवाज बनकर जनता के साथ खड़ा है। तब आपके प्रति और हमारे प्रति लोगों का विश्वास ज्यादा कायम होगा।

अभी सब जगह पर 400 दवाइयां फ्री में मिल रही हैं। अब 400 की जगह 600 कर दीं। जो दवाइयां शामिल नहीं थीं, वे दवाइयां शामिल हो गईं। अब मुफ्त में जांच होगी। मेरे से लोगों ने कहा, जो अपोजीशन के लोग हैं उन्होंने कहा कि आप दवाइयां 400 दे रहे हैं पहले वे ही पूरी नहीं मिल रही हैं। मैंने कहा, थोड़ी तो मिल रही थीं, यह तो मान लो। बोले, यह तो मान लिया। मैंने कहा कि राजस्थान में एक कहावत है, नहीं बीच तो 'काना मामा ही अच्छा।' दोनों आंखें तो खराब नहीं हैं। कोशिश तो कर रहे हैं। जो आदमी 8 दवाइयां लिखवाकर आ रहा है, उसको 6 मिल जाएं तो आप उसकी आंख में देखो। 6 जब इंजेक्शन हाथ में लेता है गरीब आदमी तो उसकी आंख में चमक होती है। उसको आप कहो कि दो बाहर से ले आओ तो वह कहता है कि मैं दो दिन बाद ले आऊंगा। मेरे को वह दुकानदार कह रहा है कि दो दिन बाद आएगी। वह उन दो दिनों को देख रहा है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं हैं। इसमें कोई गुनाह कर दिया? वह यह कहता है कि मैं 6 में ही ठीक हो जाऊंगा। उसकी मजबूरी को हम नहीं समझ रहे हैं। योजना अच्छी है। यदि खराब है तो मेरा चैलेंज है, अपोजिशन के लोग खड़े होकर कह दें कि हम इस योजना को बंद कर देंगे। कह दें खड़े होकर। कहीं नहीं कहेंगे। योजना अच्छी है। फिर भी योजना में कमी निकालेंगे। कमी निकालना आपकी मारल ड्यूटी है। 400 की जगह 600 दवाइयां। बड़ा काम हो गया कि अब जांच फ्री में हो गई। दवाई मिल जाती है लेकिन जांच के लिए पैसे नहीं होते तो गरीब आदमी तड़पता था कि पैसे कहां से आएंगे। सोनोग्राफी नहीं करवा सकता। ई.सी.जी. नहीं करवा सकता। ब्लड टैस्ट नहीं करवा सकता। कहा कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से खड़ा होगा? जब यह शुरू होगा तो धीरे-धीरे वह भी खड़ा हो जाएगा। कहीं से शुरूआत तो हुई अच्छी सोच की। जब सोच अच्छी होती है तो रास्ते बन जाते हैं। बड़ा चैलेंज का काम हुआ है। मैं अभी देख रहा था कि आपने जो रिलैक्सेशन दिए हैं पेंशन नियमों में, उससे 1500 करोड़ का भार राजस्थान की सरकार पर पड़ेगा। पड़ेगा न? भार तो पड़ेगा ही। पैसा आएगा कहां से, जाएगा कहां पर, यह काम तो सरकार का मैनेजमेंट है। यही तो सरकार का मैनेजमेंट है। यह सरकार तय करेगी कि कैसे आएगा और कैसे जाएगा।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

बीच-बीच में बात उठी, मैंने अखबारों में पढ़ा, सब जगह पर देखा, अभी घोषणा कर दी मुख्य मंत्रीजी ने। पहले इन्होंने पशुओं की दवाइयां फ्री कर दीं, अब इन्होंने कहा कि 25 हजार बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ-यात्रा पर भेजेंगे। यह बात हम कर रहे हैं, यह बात आपने नहीं की। जो काम आपने कुछ भी नहीं किये, एक डायरेक्ट काम, मैं आज कह रहा हूं आजादी के 65 वर्षों में जितने भी बजट आये, सारे बजट उठाकर देख लो और इन चार वर्षों में जितने बजट आये हैं, उन बजटों को उठा लो और इस बजट को उठा लो, मैं गारण्टी से कह रहा हूं दोनों तरफ की कमेटी बना दो, लोग इस बजट को नम्बर वन देंगे। लोग कहेंगे, 65 वर्षों का आज तक का सबसे बढ़िया बजट है। बजट में कोई कमी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आपके बजट में कोई कमी नहीं है। आप मन से बजट लेकर आये हो, पूरी तैयारी से बजट लेकर आये हो। मैं सही कह रहा हूं।

मुझे इस बात की खुशी हुई, इसमें अब की बार एक बहुत बड़ा फैसला हुआ कि आठवीं में दो से लेकर ग्यारहवीं रैंक लाने वालों को टैबलेट पी.सी. देंगे। लैपटाप की घोषणा पहले कर दी, सवा लाख लैपटाप- पहले 60 हजार, फिर 60 हजार। कोई गुनाह कर रहे हैं जो फर्स्ट टैन आ रहे हैं, उनको लैपटाप यदि सरकार दे रही है, टैबलेट पी सी दे रही है? जिस बच्चे के हाथ में लैपटाप आता है, उसकी आंख में चमक होती है। वह खरीद नहीं सकता। वह छाती पर चिपकाकर घर लेकर जाता है। सीखा नहीं तो मास्टरजी से कहता है कि मुझे सिखा दो, मेरे हाथ में लैपटाप है। उसको क्या मालूम इस बात का पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि कांग्रेस सरकार ने लैपटाप दिया है। किसने दिया? कि सरकार ने लैपटाप दिया है। हम उसको वोट से जोड़ रहे हैं, हम इसको सोच से नहीं जोड़ रहे हैं। उस आदमी की सोच पर तो कायम होने की कोशिश करो जो अकेला खड़ा है।

जब यह सोच की बात आई, बीच में मेरी बात आ गयी, बजट में बहस हो रही है, मैं दोनों तरफ के सदस्यों से एक बात कहूंगा। अभी अखबारों में एक खबर आई और सुबह मेरे घर पर कुछ लोग आये। कुछ लोग आये और मेरे से मिलकर गये बच्चे, मुझे बड़ा दु:ख हुआ। मैं रवाना हो रहा था, मैंने रुककर उन बच्चों से बात की। अखबारों में एक खबर आई, पांच हजार में बच्चे बिक रहे हैं। मंत्रीजी, आप बैठो हो, इसलिये कह रहा हूं। पांच हजार में बच्चे बिक रहे हैं यह अखबारों में खबर आई। एक खबर आई कि 150 बच्चे

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

बरामद किये। बाल कल्याण समिति ने बरामद कर लिये। बच्चे बरामद करके अलग-अलग एन जी ओ संस्थाओं में भेज दिये और उनसे कहा कि इन बच्चों को रखना पड़ेगा। मंत्रीजी, बाल मजदूरी के मैं भी खिलाफ हूं, आप भी खिलाफ हो, कागजों में हम सब खिलाफ हैं। हमारी मारल ड्यूटी बनती है। बच्चों को बरामद तो कर लिया, अख़बार में कुछ एन जी ओ ने झूठी-अच्छी खबरें भी छपवा लीं कि कैम्प में बरामद कर लिया। वे बच्चे अपने घर पर जाना चाहते हैं। वे घर पर जा रहे थे, परन्तु उनके पास किराया नहीं है। मैंने कहा, मेरी तनख्वाह ले जाओ, 15 को तो मैं भेज दूंगा। लेकिन चैक करा लो, वे जाना चाहते हैं। यह पक्ष और विपक्ष के झगड़े की बात नहीं है। वहां कुछ एन जी ओ ने यह कर लिया वह बच्चा भूखा है, उसके मां-बाप भूखे हैं। बिहार में भुखमरी है, भुखमरी के कारण वे बच्चे यहां भेजे जाते हैं। उनके लोग यहां आते हैं। मैंने उनसे सबसे बात की। मुझे आश्चर्य हुआ, एक नया चेहरा देखने में आया समाज का। उन्होंने कहा, हम तो भूखे मर रहे थे, हमें तो सुबह-शाम रोटी मिलती है। हमें तनख्वाह दे रहे हैं और हम हमारे घर पर जा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, एन जी ओ वालों से, वहां हसनपुरा में एक एन जी ओ चलता है। मिस्टर अनीस उनके साथ आये थे, मैंने कहा, इनको भेज दो वहां। उसने कहा, भेजें कैसे? हमारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं। छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैंने उनसे पूछा, आपको कोई मारता है? वे बोले, नहीं। मैं मान रहा हूं, बाल मजदूरी गलत है। लेकिन हमको यह तय करना चाहिये। अख़बार ने तो अपनी ड्यूटी निभा दी। हम चैक करें, हमारा जन प्रतिनिधि, मंत्री, तो हकीकत सामने आए कि उन बच्चों की सोच क्या है। वे कहां जा रहे थे? वे कह रहे थे कि घर जा रहे थे। यदि वे घर जा रहे थे तो हमने रोक लिया, अब वे घर कैसे पहुंचेंगे? हम उनकी एण्ड तक की व्यवस्था करें। यदि हमें बाल मजदूरी रोकनी पड़ेगी, बाल मजदूरी रोकी है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि उन बच्चों को आपने एन जी ओ में भेज दिया, कल वह वहां से डरकर भाग जाएगा, क्योंकि उसके घर छोड़ने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आप चैक कराओ, यह मानवता से जुड़ा हुआ मामला है और चैक कराकर पूरा मामला चैक करो जिससे सच्चाई सामने आए कि इस तरह से जो बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, उनकी मजबूरी क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण हैं। वास्तविकता सामने आए तो उनको भेजने की व्यवस्था सरकार करे और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप सबसे बात कर ले। 10-10 प्रतिशत हमारी तनख्वाह का ले लो, उनको घर तो

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

भिजवाओ। उसमें कोई नुकसान नहीं है। वे बहुत परेशान हैं, मैंने बच्चों से बात की है।

सोशल सिक्योरिटी का हमने जो काम शुरू किया है, उसमें यह काम भी बहुत जरूरी है। यह जो सारा बजट आया है, उस बजट में मैं यह मानता हूं कि हमने तम्बाकू पर 65 प्रतिशत टैक्स लगाया, गुटखा बंद कर दिया। उसका असर भी हुआ। बहुत लोगों में आदत होती है जब गुटखा बंद होता है, उसको आसानी से नहीं मिलता तो वह फिर नहीं लेता। इसी तरह से शराब की दुकान का मैंने देखा रात को 8 बजे। मैं आपको गारण्टी से कह रहा हूं, या तो गोविन्द देवजी के मंदिर में लोग इस तरह से हाथ निकालते हैं, या आप रोड पर देख लो दारू की दुकान पर, बढ़िया से बढ़िया आदमी 8 बजे जैसे ही दुकान बंद होने वाली होती है, आपको हाथ ऐसे किये हुए मिल जाएंगे 20-20, 25-25 आदमी। इतनी भीड़ है। 8 बजे दुकान बंद होती है उसमें दहशत है, वह 8 बजे दारू लेता है। लेकिन 9 बजे जब वह पहुंचता है, मुझे किसी ने कहा कि साहब 9 बजे दुकान पर नहीं मिलती है, पर साइड में मिल जाती है। पर वह साइड में नहीं लेता है, क्योंकि वह ज्यादा पैसे मांगता है। ज्यादा पैसे मांगते हैं तो वह कम पीकर चला जाता है। यदि कोई एडिक्ट आदमी है, यह बड़ा काम उस वक्त हुआ, यह मैं मानता हूं कि आबकारी में जो आपकी पालिसी थी, वही हमारी पालिसी है और आबकारी से बहुत बड़ा पैसा हमारे पास आ रहा है, लेकिन यह सोच, पहले 8 बजे तो कुछ नियम ही नहीं था। पहले तो 5 बजे दुकान खुलती और वह 6 बजे वहां पड़ जाता, क्योंकि वह एक साथ खींच लेता है। देसी पीने वाला एक साथ खींच लेता है। एक साथ खींचते ही नीचे पड़ जाता है। और शाम को कोई पता नहीं था कि 12 बजे बंद होगी या 8 बजे बंद होगी। (व्यवधान) कोई बात नहीं, उपाध्यक्षजी, हमारा टाइम होगा तो मुख्य सचेतक ही एडजस्ट कर लेंगे।

आज 8 बजे दुकान बंद होगी सोच, सोच बहुत बड़ी है। इस बजट में जयपुर समेत 16 जिलों में मेडिकल कालेजों की घोषणा की। यह एस एम एस राजा के टाइम का है और यह एस एम एस सेवा का केन्द्र है। अब की बार जब डाक्टर्स ने हड़ताल की, तब लोगों को पता चला कि सरकारी सैक्टर का कितना बड़ा लाभ आम आदमी को मिलता है। पूरे राजस्थान में हंगामा हो गया। डाक्टर्स ने स्ट्राइक कर दी। दवाइयां फ्री हुईं, डाक्टर्स की स्ट्राइक हो गयी। आज तक आजादी के बाद दूसरा मेडिकल कालेज जयपुर में कोई भी

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। आज न्यू एस एम एस की जरूरत है जयपुर में। एक और मेडिकल कालेज हो तो दूसरा बड़ा अस्पताल बने। नया मेडिकल कालेज जयपुर में खोल दिया इससे पूरे देश के लोगों को फायदा मिलेगा। पूरे देश के लोग जयपुर में इलाज कराने के लिये आते हैं। एस एम एस में आप लोगों से मिलो तो आपको पता चलेगा कि हर स्टेट का आदमी एस एम एस में आ रहा है। एस एम एस बहुत बड़ा सेवा का केन्द्र है। जयपुर में मेडिकल कालेज और उसके साथ 16 जिलों में मेडिकल कालेज, इतना बड़ा डिसीजन, इससे मेडिकल सुविधाएं कहां पहुंचेंगी! आज आबादी बढ़ गयी लेकिन मेडिकल सुविधाएं नहीं बढ़ीं। मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने का फैसला, जब फैसले होते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन भी होता है।

मुझे कहा गया कि इस सरकार ने अब की बार बहुत सारे फैसले किये। आज बताइये, स्टाम्प ड्यूटी 5 से घटाकर 1 प्रतिशत, क्या इससे मंहगाई कम नहीं होगी? इससे मंहगाई कम होगी। इससे जो फ्लैट खरीदने जाएगा, उसको सस्ता फ्लैट मिलेगा। यह डायरेक्ट रिलीफ मिलेगी आम आदमी को। यह बहुत बड़ा फैसला राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया। जब बजट पर चर्चा हो रही थी, मैंने अखबारों में सब जगह पढ़ा, लोगों ने कहा, सब काम आपने बढ़िया कर दिया, पर पैट्रोल-डीजल पर वैट नहीं घटाया। अब एक ही मुद्दा रह गया पैट्रोल-डीजल का, तो मुझे आप यह बता दो, पैट्रोल-डीजल पर वैट घटा दिया उसके बाद तो आप अशोक गहलोत जिन्दाबाद का नारा लगा दोगे क्या? आप लगा दो तो हम वैट घटा दें, हम करवा देते हैं। आप लगा दो, मान लोगे तो यह भी हो जाएगा। फिर क्या रहेगा? आप-हम कहीं न कहीं गली ढूंढते हैं। पैट्रोल-डीजल पर वैट अशोक गहलोत पहले भी हटा चुके हैं। पैट्रोल-डीजल पर आप बताइये यह 50 पैसे सैस किसने लगाया? आपने लगाया है। आपको जनता से पैसे लेने थे, आपने 50 पैसे सैस लगाया। आज तक राजस्थान की किसी भी सरकार ने पैट्रोल-डीजल पर सेस नहीं लगाया, वह काम भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सरकार ने किया। अशोक गहलोत जी ने अभी थोड़े दिन पहले रसोई गैस पर 25 रुपये कम किये, पैट्रोल पर वैट कम किया, डीजल पर वैट कम किया। मंहगाई से लड़ने के लिये आप जो इतने बढ़िया–बढ़िया सुझाव दे रहे हो, और अशोक गहलोत दोनों हाथों से जनता को दे ही रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा मुख्य मंत्रीजी, विपक्ष यह चाहता है, और बार-बार आपकी तारीफ भी करता है

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

कि इसमें हो जाए, राजस्थान की जनता यदि चाहती है, बाकी सब आपने दे दिया तो आपको दो-तीन काम के लिये मेरा निवेदन है। एक तो आपको जयपुर और जोधपुर से पूरी तरह से यूजर चार्ज हटाना चाहिए। यह यूजर चार्ज आपको इसलिए हटाना चाहिए क्योंकि यूजर चार्ज का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। यूजर चार्ज का कोई यूज नहीं है। यूजर चार्ज के नाम पर यदि हम बिल में वसूली कर रहे हैं, वैसे भी गैर कानूनी है। हम बिल में वसूली नहीं कर सकते। हमें यूजर चार्ज हटाना चाहिए। यदि यूजर चार्ज किसी को लगाना था तो नगर निगम लगाता। नगर निगम को पूरे पावर दे रखे हैं, रूल्स-रैगुलेशन तय हैं। नगर निगम के एक्ट में प्रावधान है। नगर निगम के एक्ट के अनुसार अरबन डवलपमेंट टैक्स नगर निगम वसूल कर रहा है। अरबन डवलपमेंट टैक्स पूरा नगर निगम वसूल नहीं कर पा रहा है। हालत यह है कि राम बाग पैलेस होटल में लाखों रुपया, बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों का लाखों रुपया आज भी अरबन डवलपमेंट टैक्स का बकाया है। वे हमारे कोई रिश्तेदार थोड़े ही लगते हैं। मैं कहूंगा कि हमारी सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। मैं खुद तैयार हूं ढोल-नगाड़े बजाने चाहिए उन बड़े प्रतिष्ठानों के खिलाफ। उन्होंने जयपुर और जोधपुर नगर निगम का लगभग 50 करोड़ रुपया खा रखा है, हम उनसे वसूली करें।

इस देश के हालात क्या हैं? उपाध्यक्षजी, पचास हजार बड़े आदमी ऐसे हैं इस देश में जिन्होंने बैंकों का करोड़ रुपये से ज्यादा खा रखा है। 50 हजार करोड़ रुपया बैंक मांगती है लोगों में, लेकिन उसकी वसूली के लिए हमारे पास कोई नियम नहीं हैं। हम छोटे आदमी पर अटैक कर सकते हैं लेकिन बड़े आदमी पर अटैक नहीं कर सकते। ऐसे में हमारी मारल ड्यूटी बनती है कि हम आगे बढ़कर इस यूजर चार्ज को समाप्त करें। जो बड़े धन्ना सेठ हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो बड़े-बड़े बिजनैस ग्रुप हैं, उनसे अरबन डवलपमेंट टैक्स की वसूली करें। उससे नगर निगम की भरपाई करें और जयपुर और जोधपुर में सफाई की व्यवस्था करें। यदि वह मिल जाएगा तो मैं आपको कह सकता हूं कि जोधपुर और जयपुर में जबरदस्त सुधार हो जाएगा।

उपाध्यक्षजी, जब यह योजना लागू की गई और बजट लागू किया गया, बजट लागू करने के साथ-साथ राजस्थान के कर्मचारियों को ढाई हजार करोड़ रुपये प्रावधान करके छठा वेतनमान लागू किया गया था। वेतनमान को लेकर, यह डिसकस आ रहा है, यह विसंगति आ रही है। वे कह रहे हैं कि हमें

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

यही पता नहीं है कि कृष्णा भटनागर कमेटी की रिपोर्ट क्या है। अलग हटकर मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि कृष्णा भटनागर कमेटी ने जो प्रावधान लागू नहीं किये छठे वेतनमान के, वे भी मैं लागू कर रहा हूं और छठा वेतनमान पूरा हम देंगे। ढाई हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया। ढाई हजार करोड़ रुपये इसीलिए दिये गये हैं कि छठा वेतनमान देंगे। यदि कहीं कोई कमी रह गयी तो...

श्री उपाध्यक्ष: आपको 25 मिनट हो गये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): कोई बात नहीं, उपाध्यक्षजी, हमारी पार्टी का जो समय है वह कम हो जाएगा। ज्यादा बोलने वाले हैं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: पार्टी कह दे कि आपको और देना है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): तो आप ही बुलाओ, उपाध्यक्षजी, आप ही बाउण्ड कर सकते हो उनको, मैं कैसे बाउण्ड करूं? आप चेयर पर बैठे हो।

उपाध्यक्षजी, ढाई हजार करोड़ रुपये का प्रावधान मुख्य मंत्री ने किया और मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि इसमें ढाई हजार करोड़ रुपया खर्च होगा। उपाध्यक्षजी, मैं आज आपके जरिये अभी बाहर गया था, मैं यहां पर राहुल गांधीजी की एक बात का समर्थन करता हूं। बाहर नींदड़ से किसान आये हुए थे, उन्होंने आकर कहा कि हम जमीन नहीं देना चाहते। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में उपाध्यक्ष हैं, लोक सभा में बिल आने वाला है, किसानों की जमीन बचाने के लिए उनकी तैयारी है। राजस्थान में भी हमें यह तय कर लेना चाहिए। जब तक केन्द्र का किसानों का जमीन अधिग्रहण का बिल क्लीयर नहीं हो तब तक हमें राजस्थान के किसानों की कोई भी जमीन अधिग्रहीत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह बिल किसानों के पक्ष में आ रहा है। आज किसान जमीन देना नहीं चाहता। हम उसकी जमीन लेना चाहते हैं। यदि किसान जमीन नहीं देना चाहता तो उसकी जमीन नहीं लें। आज नींदड़ का किसान अपने बीवी-बच्चों के साथ आया हुआ है। वह कह रहा है कि मेरा मकान बना हुआ है, मेरे परिवार में 55-60 लोग हो गये। किसी की जमीन चार बीघा है, किसी की दो बीघा है, किसी की पन्द्रह बीघा है, मुश्किल से पांच-पांच सौ गज की जमीन उनको मिलेगी। आज जेडीए उनकी जमीन लेना चाहता है, जमीन लेकर खुद कमाई करना चाहता है तो किसान क्यों नहीं कमाई करना

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

चाहेगा? किसान भी चाहता है कि मुझे कमाई मिले इसलिए मैं आज पूरे सदन का ध्यान उनकी तरफ कर रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा कि किसानों को लेकर दोनों पक्षों को फैसला करना चाहिए और तय करना चाहिए कि किसान की जमीन हम जबरदस्ती नहीं लें। किसान को उसका पूरा अधिकार मिले।

जब बजट पर पूरी चर्चा हुई, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अन्तरजातीय विवाह के बारे में मुख्य मंत्रीजी की सोच बहुत अच्छी है। बहुत बड़ी सोच है उनकी। उन्होंने कहा कि मैं पांच लाख रुपये दूंगा। इसमें हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि इस बात को लेकर अननैसेसरी डिस्प्यूट खड़ा हो जाए। कहीं लोगों में इस तरह से होड़ लग जाए कि पांच लाख रुपये तो मिल ही रहे हैं, उनकी खातिर थोड़ा बहुत कुछ ही लें तो माथा फोड़ी मिटे। इस मामले पर कोई नहीं बोलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। हमें स्ट्रिक्टनैस रखनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, इस बात को लेकर नया झंझट खड़ा नहीं हो जाए पांच लाख रुपये की बात पर कि भाई, ठीक है, पैसे हैं नहीं, इस वास्ते कुछ कर लें। तो यह बड़ी बात है। डर लगता है क्योंकि नई सोच का जमाना है, विकास की बात हम कर रहे हैं, प्रताप सिंह क्या कह रहा है? मैं यही कह रहा हूं। यह सोच अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है। आप समाज में बहुत कुछ सुधार लाना चाहते हैं। लेकिन हम जो अखबारों में और टीवी पर देख रहे हैं, ऐसे हालात पैदा हो गये हैं। कई बार टेंशंस हो जाते हैं, उनका भी हम खयाल करें और खयाल करके हम यह ध्यान रखें कि हम जो सुविधा दे रहे हैं वह वास्तव में सही आदमी के पास पहुंचे। कहीं ऐसा नहीं हो कि गांवों में फ्रैक्शंस पैदा हो जाएं, अननैसेसरी के डिस्प्यूट खड़े हो जाएं।

मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने घोषणाओं में कोई कमी नहीं रखी। आपने सबको दिया। सब लोगों के लिए व्यवस्था की है। आपने 22 शहरों में पेयजल की व्यवस्था भी कर दी, मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा। हिन्दुस्तान में राजस्थान एक मात्र ऐसा स्टेट है जहां पर पीने का पानी सबसे सस्ता। गुजरात में पानी राजस्थान से तीन गुना महंगा है। तीन गुना से भी ज्यादा है। मैं यह शपथपूर्वक कह रहा हूं। मेरी इस बात का कोई भी खण्डन कर दे। तीन गुना से भी ज्यादा में पानी गुजरात की सरकार बेच रही है। राजस्थान में सबसे सस्ता पानी उपलब्ध हो रहा है। बार-बार हम महंगाई की बात करते हैं, सरकार को चैलेंज करते हैं।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

अब की बार पत्रकार भाइयों को लैपटाप की बात हुई। 600 पी एच सी की घोषणा हुई। मतलब एक भी तबका, एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसको कुछ नहीं मिला हो। हर वर्ग के लोगों के लिए कोई कमी नहीं रखी। जब हर वर्ग को मिल गया तो मैंने सब तरफ देखा। अखबारों में किसी ने उनको जादूगर बताया, किसी ने कहा कि ये चुनाव के खिलाड़ी हैं। किसी ने कहा कि पूरे राजस्थान को मिल गया। घूम फिर कर जब बात वापस आयी तो सिर्फ इतनी-सी आयी कि इस बजट में कमी क्या रह गई। केन्द्र सरकार में सिस्टम अलग हो गया, पैट्रोल और डीजल को लेकर जैसे ही अन्तरराष्ट्रीय मार्केट में भाव कम ज्यादा होते हैं, पैट्रोल और डीजल की दरें बढ़ जाती हैं।

अभी रिफाइनरी को लेकर बात हुई। दो तरह की बात। रिफाइनरी आयी है, 37 हजार करोड़ रुपये की रिफाइनरी लगेगी। 54 हजार करोड़ रुपये का खर्चा होगा। इतना खर्चा राजस्थान के माथे आ जाएगा। तो फिर रिफाइनरी का स्वागत करने की जरूरत क्या है? पार्टी की तरफ से आपको घोषणा कर देनी चाहिए कि हम तो रिफाइनरी का विरोध कर रहे हैं। रिफाइनरी राजस्थान में नहीं लगनी चाहिए, ऐसा विपक्ष को कहना चाहिए अखबारों के माध्यम से। डबल बात नहीं हो सकती। बात तो सिंगल ही होगी। रिफाइनरी को लेकर पूरे राजस्थान की जनता वर्षों से इन्तजार कर रही है। जैसे ही रिफाइनरी की घोषणा हुई, राजस्थान की जनता ने स्वागत किया कि यह राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। आप आश्चर्य करेंगे। आप दो-तीन महीने रुक जाओ, राजस्थान का विकास देखना। मैंने पहले भी कहा था, इस सदन में जितने लोग हैं, आप घाट की घूणी टनल देखोगे, रात के वक्त देखोगे तो आपको वर्ल्ड क्लास जयपुर लगेगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): एक मिनट। कैपिटल इन्वैस्टमेंट और वाएबिलिटी गैप, मैं तो केवल एक चीज पूछ रहा हूं, मैं रिफाइनरी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि रिफाइनरी किन शर्तों पर लगेगी? क्या एक करोड़ रुपये की दुकान खोलने के अन्दर छह करोड़ रुपये का घाटा लगेगा? उस छह करोड़ रुपये के घाटे की भरपाई मैं करूंगा? सवाल यह है कि कैपिटल इन्वैस्टमेंट कहां हो। हम वैलकम करते हैं उसका। हम तो यह कह रहे हैं कि 37 हजार करोड़ रुपये तो हम ही लगा देते। प्लान में शामिल कर लेते उसको। हम तो केवल यह कह रहे हैं कि 37 हजार करोड़

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

के इन्वैस्टमेंट पर 53 हजार करोड़ का वाएबिलिटी गैप राजस्थान की जनता भरे, अगर यह कहीं हुआ हो तो हमारे यहां भी करें।

हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हुआ इसलिए मैं कह रहा हूं। रिफाइनरी का विरोध या समर्थन की बात नहीं है, किन शर्तों पर रिफाइनरी आए? राजस्थान के हित की बात है, मैं भी खिलाफ नहीं हूं, आप भी खिलाफ नहीं हैं। रिफाइनरी लगे लेकिन उन टर्म्स एण्ड कंडीशंस पर लगे जो राजस्थान के अलावा हिन्दुस्तान में लगीं। इस तरह की इकोनोमिक्स नयी इकोनोमिक्स है, इस इकोनोमिक्स को जरा मुख्य मंत्रीजी ढंग से देखें, राजस्थान की जनता को, विधान सभा को इसके लिए विश्वास में ले और फिर समझाएं।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, विराजें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्ष जी, राजपाल जी ने जो सुझाव दिया, उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन, राजपाल जी, एक बात आप समझ लीजिए, उपाध्यक्ष जी...

श्री उपाध्यक्ष: यह आंकड़ों पर ...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं आंकड़ों पर ही बोल रहा हूं, उस पर ही बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष जी, इन्होंने अपनी जगह जो स्टडी की है वो ठीक हो सकती है लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। अभी रिफाइनरी आने का फैसला हुआ है, अब कितना खर्च होगा, कितना जाएगा और कितना आएगा, कोई भी सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि वो यह गलती कर लेगी कि स्टेट को घाटे में रखकर रिफाइनरी लेकर आये। स्टेट को घाटा कहीं नहीं होगा।

अभी भी आंकड़ों का मायाजाल हम निकाल रहे हैं, उस मायाजाल में पहले से तैयारी है सरकार की और यह तय है कि रिफाइनरी पर स्टेट को बहुत बड़ा फायदा होगा। और फायदा तो शुरू हो गया। आप खुद जानते हो, जब से डीजल निकलने लगा है, जब से तेल बाड़मेर में निकलने लगा है तब से पैसा भी बढ़ा है। पैसा बढ़ा है तो स्टेट को फायदा हुआ। आज जनता तक बड़ी-बड़ी डाइरेक्ट घोषणाएं पहुंच रही हैं। रिफाइनरी में कहीं आपके अच्छे सुझाव हैं, विपक्ष यह सोचता है कि रिफाइनरी हमारी है, राजस्थान की जनता की है, जनता को फायदा होगा, आपके अच्छे सुझाव हैं तो चीफ मिनिस्टर कब मना कर रहे हैं, आपको जाकर अच्छा सुझाव देना चाहिए। बताना चाहिए कि, साहब,

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

इसको ऐसे नहीं ऐसे करो तो राजस्थान को ज्यादा फायदा होगा। इस मामले में इतना कह सकता हूं कि ये चीफ मिनिस्टर अशोक जी गहलोत डेमोक्रेटिक आदमी हैं, भले आदमी हैं, कोई जाकर सुझाव दे तो उस सुझाव को मानने की ताकत रखते हैं। प्रेस्टीज इश्यू ये बनाते नहीं। मैंने कभी नहीं देखा कि अशोक गहलोत जी ने कभी प्रेस्टीज इश्यू बनाया हो।

जब बात निकल गयी तो आज मैं आपको कहूंगा, पहला चीफ मिनिस्टर है राजस्थान की राजनीति में मैंने जो देखा, जिसने बड़प्पन से खड़े होकर यह कहा कि, विपक्ष के नेता, आप खुद जांच कर लें। बहुत बड़ी बात है। कोई तो कहे, कोई तो आगे आए। घबराये नहीं। खुद ने कह दिया। नहीं तो लोग नाराज हो जाते हैं, नाराज होकर आवेश में आ जाते हैं। आकर कहेंगे, कुछ नहीं, आपने ऐसा कैसे कह दिया। हंगामा हो जाता है। कोई हंगामा नहीं हुआ। यह बहुत बड़ी सोच दर्शाती है।

मैं आपको आज कह सकता हूं, एक लाख 50 हजार रुपया किसान को बिना ब्याज के ऋण, बिना ब्याज के ऋण की बात है। अशोक जी गहलोत ने जो कहा है वो करके दिखाया। आप लोगों ने बार-बार चार्ज किया, मुझे इस बजट में आप पुराने बजट की घोषणाएं बता दो, कोई बहुत बड़ी आम आदमी को डाइरेक्ट रिलीफ की घोषणा हो और उस घोषणा को सरकार पूरा नहीं कर पायी हो। आपके पास कोई बात नहीं है। मुझे तब आश्चर्य हुआ जब पिछली सरकार ने तो ए.पी.एल. का गेहूं उठाया ही नहीं और जब ए.पी.एल. का गेहूं नहीं उठाया तो आप जनता तक कोई स्कीम नहीं पहुंचा पाये।

उपाध्यक्ष जी, मैं आज इतना कह सकता हूं कि इस बजट की चर्चा चारों तरफ है, हर आदमी बजट की तारीफ कर रहा है, हर आदमी इस बात को मानता है कि इस बजट ने लोगों को रिलीफ देने का काम किया है। यह बजट महंगाई से लड़ने वाला है, महंगाई को खतम करने वाला है। आम आदमी को राहत पहुंचाने वाला बजट है, हर वर्ग की सहायता करने वाला बजट है और राजस्थान को आगे ले जाने वाला है। यह बजट गांव, गरीब, शहर, मजदूर, किसान, व्यापारी, विद्यार्थी सब के पक्ष का है। यह बजट बिलो पावर लाइन से लेकर एबव पावर लाइन सब के हित का है। यह बजट ऐसा है जिसमें कमियां निकालना बहुत मुश्किल है लेकिन इस बजट की तारीफ करना बहुत आसान है। इसके लिए मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को बधाई देता

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

हूं। बधाई इस बात की भी देता हूं कि आप जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, इस बजट में बड़ी बात यह है, उपाध्यक्ष जी, चार वर्षों में जितनी भी बहस इस विधान सभा में हुई, जो-जो मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये वो सब मुद्दे इस बजट में नजर आते हैं और वो सारी रिलीफ इस बजट में नजर आती है। यह बहुत बड़ी बात है।

चाहे पक्ष चाहे विपक्ष के लोग जिन्होंने अच्छी बातें उठायीं, उन अच्छी बातों को चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने इस बजट में शामिल किया। सब का मन का पिटारा इकट्ठा कर ऐसे पिटारे का निर्माण किया जो राजस्थान की जनता को सहायता पहुंचाने वाला साबित हुआ।

इस बजट में बुराई करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आप यह जरूर कह रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, आप कैसे लेकर आओगे, इतना बड़ा कर्जा हो जाएगा। आज मुझे यह बता दो कि आपने बिना कर्जे के कौनसी योजना लागू की? बिना कर्जे के कौनसी योजना लागू करके विकास कर दिया?

इसलिए, उपाध्यक्ष जी, इस बजट की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इस बजट के लिए मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं। इसके साथ ही मैं पक्ष और विपक्ष के दोनों सदस्यों से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के इस बजट के लिए हर आम-अवाम उम्मीद कर रहा है कि बजट में जो योजना मेरे लिए लागू हुई है वो योजना मेरे तक पहुंचेगी। यदि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी यह बजट लागू होने के बाद आम जनता को रिलीफ नहीं देता है तो आपकी मारल ड्यूटी बनती है, आप भी उतरिये, जाइये आफिस में, आफिस में जाकर बात कीजिए, उसको मजबूर कीजिए कि बजट को वो लागू करे। आम आदमी को उसका अधिकार मिले, आम आदमी को लगे कि विधान सभा में पक्ष और विपक्ष के लोग एक-दूसरे पर रोज आरोप लगाते हैं, लड़ते हैं लेकिन पक्ष और विपक्ष के लोग बजट को पूरा लागू कराने के लिए आम- अवाम के साथ खड़े हैं, राजस्थान की जनता के साथ खड़े हैं।

मुझे भरोसा है, उपाध्यक्ष जी, यह बजट जैसे ही हम लोग आम आदमी में लेकर जाएंगे, जिनको रिलीफ मिलना है उनको मिलना शुरू हो गया तो उसका हमें भी फायदा होगा। विधान सभा के प्रति लोगों का सम्मान भी बढ़ेगा

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

और लोगों को लगेगा कि हमने जिनको चुन कर भेजा है वो हमारे वास्तव में देवदूत हैं।

इसके लिए मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने जो तुरुप के पत्ते इस बजट में काम में लिए हैं उसके लिए बधाई देता हूं और भरोसा करता हूं कि यह बजट राजस्थान को आगे ले जाने वाला होगा, यह गरीब का और पूरे समाज का भला करेगा, इससे महंगाई कम होगी और राजस्थान विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री फतेह सिंह जी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपने दे दी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं नहीं, वो नहीं है, साहब। यह हमारा अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं। (व्यवधान) आप लिखकर दें। केवल फतेह सिंह जी का।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: फतेह सिंह जी, आप बोलिये। केवल फतेह सिंह जी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय फतेह सिंह जी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपको मौका पार्टी देगी जब बोलिये, खूब बोलिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपको मौका मिलेगा आपकी पार्टी की तरफ से।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित ही नहीं हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है न। वो आप पार्टी से बात करिये। फतेह सिंह जी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, वो अंकित नहीं हो रहा है। अब आप विराजिये। माननीय सदस्य, कृपा कर विराजिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें, कोई नहीं सुन रहा है बात को।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा का 14वां बजट मुख्य मंत्री महोदय द्वारा पेश हुआ। इस बजट के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी राय पेश की है, मैं भी अपनी बात कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जनतंत्र में सरकारों का गठन होता है और बहुमत के आधार पर जो सरकारें बनकर आती हैं उन सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि देश की सुरक्षा, देश का विकास, देश की समस्याओं के बारे में बजट पेश करें, पालिसी तय करे। उसी रूप में राजस्थान में मुख्य मंत्रीजी द्वारा यह बजट पेश हुआ है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि सभी वर्गों सभी समाज के लोगों के लिए इसमें प्रावधान जरूर बताया गया है लेकिन मैं आखिरी समाज की ओर जाना चाहूंगा। राजस्थान में ऐसा भी समाज कोई है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है। हमारे प्रदेश में दूर-दराज के इलाके में आदिवासी समाज के लोग भी रहते हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग भी रहते हैं, ओ बी सी के लोग भी रहते हैं। जो भी बजट पेश होता है, जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, बड़े-बड़े लोगों के लिए, बड़े-बड़े शहरों के लिए और बड़े समाज के लिए ये योजनाएं बनाई जाती हैं, उन पर लागू होती हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि हमारा उदयपुर सम्भाग आदिवासी बहुल सम्भाग कहलाता है। नब्बे परसेंट आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और अनुसूचित जाति-जनजाति के नाम से हम माने जाते हैं। लेकिन हमारा समाज दो भागों में बंटा हुआ है- एक समाज मीणा समाज के नाम से पुकारा जाता है, दूसरा समाज जो आदिम जमाने से जंगलों में बसा हुआ है, खेती करता है, मजदूरी करता है, वह भील समाज के नाम से माना जाता है। उस इलाके में आपने भी देखा होगा, जो सरकारें बनीं हैं उन्होंने भी देखा होगा, हमारे जन प्रतिनिधियों ने भी देखा होगा कि उदयपुर संभाग के अन्दर आदिवासी समाज के लोग अपने अपने खेतों में मकान बनाकर रहते हैं। अपने खेत में रहते हुए छोटी जो जोत होती है, उसके ऊपर वे खेती करते हैं। खेती से भी पूरा नहीं होता है तो गुजरात, महाराष्ट्र या अन्य क्षेत्रों में जाकर मजदूरी करके अपने परिवार को जिन्दा रखने की कोशिश करते हैं। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि आजादी

(श्री फतेह सिंह)

के इतने वर्ष के बाद भी आज दिन तक उस गरीब की झोंपड़ी में बल्ब नहीं लगा, वह समाज अंधेरे में है। कहने के लिए इसी सरकार ने राजीव गांधी विद्युतीकरण नाम से योजना चलाई थी। उस इलाके में सामान डालने के बाद ठेकेदार चले गये और उन लोगों को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत जो लाभ मिलना था, कनेक्शन मिलना था, वह नहीं मिल पाया। मैं इस मौके पर राजस्थान की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आदिवासियों की हालत है उसके बारे में आप सोचें। हम बड़े-बड़े शहरों के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाते हैं लेकिन आदिवासी समाज के लोग दूरदराज के इलाके में रहते हैं, हम उनके लिए कोई योजना तैयार नहीं करते। हम कह देते हैं कि बी पी एल में चयनित कर दो, एक रुपया किलो उनको अनाज दे दो, खाद्यान्न दे दो। इसके अलावा क्या किया?

अभी बीच में मुख्य मंत्री आवास योजना में उनको मकान दिये गये, बी पी एल के मकान दिये गये। पचास हजार में उस व्यक्ति का मकान नहीं बन पाया। उनके ऊपर दबाव बनाया गया और वह मकान बनाया। लेकिन उसके ऊपर कर्जा हो गया। कहीं जमीन गिरवी रखी, कोई मवेशी बेचा या कोई दागिना बेचा। उनके पास में था उसको बेचकर उस मकान को पूरा किया। मैं इस बारे में भी कहना चाहूंगा कि वास्तव में उस गरीब को मकान देना है तो एक लाख रुपया उसको दिया जाए ताकि वो अपना एक कमरा तो बना सके पर वो भी स्थिति हमारे सामने नहीं है। अभी इस बजट में मुख्य मंत्री जी ने रखा है 75 हजार रुपया 75 हजार रुपये से कुछ होना-जाना नहीं है। इससे अच्छा होता कि मकान नहीं दिये जाते। जो इन्दिरा आवास के मकान मिल रहे थे, जिस आदमी को यह पता है कि मकान मिलेगा, वह आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक वह मकान बना सकता था। लेकिन यह नहीं हो पाया। वह मकान देकर भी हमने उस आदमी को और गरीब माना है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जितना भी हमारा ट्राइबल एरिया है उदयपुर संभाग के अन्दर, उस एरिया के लिए सरकार योजना तैयार करे। उस इलाके में सिंचाई का कोई साधन तैयार करे, लोगों के मकान बनाने के लिए उनको पूरी तरह से सहयोग देवे। मैं तो कहता हूं, सभी आदिवासियों को चयनित में मान लेना चाहिए। दस परसेंट चयनित लोग हैं आदिवासी समाज के, उन लोगों के लिए योजना बनाकर वहां बिजली उनको मिले। खेत छोटे-छोटे हैं वहां सिंचाई के

(श्री फतेह सिंह)

उनको साधन हों और जहां सड़क नहीं बनी है वहां सड़कों का भी निर्माण हो। हालांकि पी एम जी एस वाई में हर गांव को सड़क से जोड़ा गया है लेकिन कोई ऐसी ढाणी बाकी है वहां पर भी सड़क की जरूरत है।

दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि उस आदिवासी इलाके में स्कूलें हमने खोल दीं। राजीव गांधी पाठशालाएं भी खोली थीं जो उसके बाद प्राइमरी में कन्वर्ट की गयीं। जितनी स्कूलें वहां पर खोली गयीं- प्राइमरी हों, मिडिल हों, सीनियर हों, सैकण्डरी हों या कालेज हों, मैं कहना चाहूंगा कि आदिवासी इलाके में हमने सुविधा तो दी है लेकिन वहां पर प्राइमरी स्कूलें बिना अध्यापक के खाली पड़ी हैं। शिक्षाकर्मी वहां पर काम करता है। मिडिल स्कूलों में मास्टर नहीं है, सीनियर में, सैकण्डरी में मास्टर नहीं है, ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वास्तव में उस इलाके के लोगों को राहत देनी है तो स्कूलों में जो अध्यापकों की कमी है, उस कमी को पूरा किया जाए।

मैं कहना चाहूंगा कि उस इलाके में छोटे-छोटे किसान रहते हैं, छोटे खेतिहर मजदूर, उनको कृषि कनेक्शन में टी ए डी मद से अनुदान दिया जाता था। चार साल से जो उनको अनुदान मिल रहा था, राज्य सरकार ने बंद कर दिया टी ए डी मद से। दस हजार की जो डिमांड निकलती है उसके अन्दर पांच हजार जनजाति मद से पैसा जमा होगा और पांच हजार उस काश्तकार को खुद को भरना पड़ेगा। वो भी पैसा लोगों ने पांच-पांच हजार रुपया जमा कर दिया। लेकिन आधी सब्सिडी मिलनी चाहिए थी वो बंद कर दी। आज भी कई लोगों के कनेक्शन करना बाकी है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि वह सब्सिडी किन कारणों से रोकी गयी है। जब हम आदिवासी इलाके की बात करते हैं, गरीब तबके की बात करते हैं, गरीब का विकास हम चाहते हैं तो यह सब्सिडी हमारे इलाके में सरकार ने रोकी, उसके बारे में भी मैं सरकार से कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षेप में करें।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): मैं तो अभी बोला भी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: आपको दस मिनट हो गये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): ज्यादा बोलता नहीं मैं।

श्री उपाध्यक्ष: जितना पार्टी का समय था ...

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): विरोध करने के लिए तो काफी समय आप देते हो। विरोध किसी का करना हो, पक्ष-विपक्ष का, उसके लिए तो काफी समय देते हो।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं। आपके दल को जो समय मिला है, उससे आपका दुगना हो गया।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): दूसरा मैं निवेदन करना चाहता था कि हमारे इलाके में जितने भी आदिवासी हास्पिटल हैं, वहां डाक्टर नहीं। सरकार कह रही है कि हमने इतनी दवाइयां इलाके में भेज दीं, हर जगह गरीब को मुफ्त दवाई मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं, दवाई आपने फ्री कर दी लेकिन मरीज को दवाई लिखने वाला डाक्टर नहीं होगा तो वह दवाई किस काम की होगी?

आपके पी एच सी, सी एच सी भी क्रमोन्नत हुए हैं, वहां पर डाक्टरों की कमी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि डाक्टरों की कमी की पूर्ति की जाए। जहां-जहां हास्पिटल हैं वहां पर एक्स-रे मशीन नहीं है। हम जयपुर के आस-पास, जोधपुर के आस-पास या बड़े-बड़े कस्बों की बात तो कर लेते हैं। जब चुनाव होता है तो उस इलाके में किसी भी पार्टी के नेता जाते हैं वहां पर लोगों को लुभाने की बात करते हैं, लेकिन उस इलाके की हालत हम देखें तो वहां हर तरह की कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए सरकार को कोई न कोई योजना बनानी चाहिए। उस योजना के तहत एरिया हमारा अगर सुधर सकता है, वहां के आदिवासी ठीक तरह से सक्षम हो सकते हैं, तो उचित है। बाकी हम वोट लेकर ही उनको छोड़ देते हैं, उसके बाद में हम उनकी तरफ देखते ही नहीं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उस इलाके में मास्टरों की कमी है, उस कमी को दूर किया जाए। डाक्टरों की कमी है उसको भी दूर किया जाए।

उसके बाद यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले साल बरसात खूब हुई, उस बरसात के अन्दर सरकारी सम्पत्ति खतम हुई- मकान भी गिरे, रोड भी खतम हुए, पुलिया भी बह गये व्यक्तिगत लोगों के मकान भी गिर गये। उसके बाद भी आज दिन तक सरकार ने उन सड़कों को ठीक करने के लिये कोई पैकेज नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया। हम डिपार्टमेंट वालों से पूछते हैं, कलक्टर से पूछते हैं, वे कहते हैं कि सरकार पैसा नहीं दे रही, हम किस रूप में सड़कों का काम करें।

(श्री फतेह सिंह)

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में उस इलाके की रिपोर्ट आपके पास आयी है कि वहां नुकसान हुआ है अधिक बारिश से, तो उस जिले में पैसा देकर उन रोड्स को ठीक करें। आवागमन का रास्ता ठीक करें, लोगों को राहत दें, यह मेरा निवेदन करना था।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा, जो मैंने बातें कही हैं डाक्टर्स के बारे में, अध्यापकों के बारे में, जो रोड हमारी खतम हुई उनके बारे में, जो रिक्त पद हैं उनको भरने के बारे में सरकार सोचे और उसके ऊपर विचार करके पूर्ति करे। इतना ही कहते हुए मैं इस बजट का विरोध करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता जी व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री ने 2013-14 का जो बजट पेश किया है, मैं समझती हूं, आगामी चुनाव में जाने के लिये आम आदमी के साथ धोखा और छलावा किया है। इस एक मात्र उद्देश्य से वर्ष 2013-14 का बजट पेश किया गया। इस बजट में दूरदर्शी वित्तीय प्रबन्धन या कोई ऐसी बात नहीं सोची गयी जिससे जनता को राहत मिल सके। इसमें सिर्फ एक बात आयी है, सवा तेरह हजार करोड़ का घाटा इसके अन्दर जरूर दिखाया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने चार बजट चार साल में पहले भी पेश किये और यह आपका अंतिम बजट है, इस बजट में आपने इतनी घोषणाएं तो कर दीं मगर पहले वाले बजट की घोषणाएं भी पूरी नहीं हुईं, फिर इस बजट में भी आपने इतनी घोषणाएं की हैं। यह सिर्फ एक चुनावी बजट है, इस बजट पर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं।

स्थानीय स्तर पर जोधपुर नगर निगम की मैं बात करती हूं। जोधपुर नगर निगम में भी बजट पेश किया, खर्च कुछ नहीं किया, सिर्फ 15 परसेण्ट खर्च किया। जोधपुर जे डी ए की बात करती हूं तो सिर्फ 25 परसेण्ट खर्च किया और कुछ नहीं किया। राजस्थान के वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, इनका भी सिर्फ 40 परसेंट बजट काम आया है, बाकी ऐसे के ऐसे पड़ा रह गया। तो ये तो सारी घोषणाएं ही घोषणाएं होती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घोषणाओं से कुछ नहीं होता। कभी भी इन्होंने मानिटरिंग नहीं की कि बजट के अन्दर कितना काम होना चाहिये, क्या होना चाहिये। इस बात को कभी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

देखा ही नहीं, मेरा यह पूरा दावा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर की कोई भी समस्या हो, जोधपुर शहर का कोई भी कार्य हो, जब कहीं भी स्कूल, हास्पिटल देखने जाती हूं तो राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी या सम्बन्धित मंत्रीजी से पत्र व्यवहार करती रहती हूं। मगर उस पत्र व्यवहार का भी मुझे कभी जवाब नहीं मिला। जवाब मिला तो यह मिला कि सम्बन्धित अधिकारी को भेज दिया गया है। अब सम्बन्धित अधिकारी ने क्या किया, क्या नहीं किया, वह कागज तो खड्डे के अन्दर गया। इस तरीके से यह बजट है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, औषधि निरीक्षण प्रयोगशाला की इन्होंने घोषणा की थी, अब तक नहीं हुई। खेजड़ली जोधपुर के रेस्क्यू सेण्टर की स्थापना की बात कही, अब तक नहीं हुई। कालेज छात्राओं के लिये छात्रावास अब तक नहीं बना। जोधपुर व कोटा में 73 बसें मिलनी थीं, अब तक नहीं मिलीं। नागौरी गेट के अन्दर इन्होंने खुद कहा कि मैं पुलिस थाना बनाऊंगा, अभी तक नहीं बना। वह घोषणा ही रह गयी। कमिश्नर प्रणाली लागू तो कर दी, दस्तों का गठन कर दिया, अब तक नहीं हुआ। जोधपुर में 150 संवेदनशील स्थानों पर सी सी टी वी कैमरे लगाने का इन्होंने कहा था, वह भी अभी तक नहीं हुआ। कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना अब तक नहीं हुई। डी एम आई सी के तहत जोधपुर, पाली, मारवाड़ क्षेत्र में वृहत् नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग व इन्वैस्टमेंट जोन की स्थापना अब तक नहीं हुई। बासनी बेंदा में 40 एम एल डी का एस टी पी बनना था, अब तक नहीं बना। कार्यादेश हुए, मतलब अब तक केवल कागजों में ही प्लान बनाने के हैं। वर्क आर्डर हुए, धरातल पर पड़े रह गये। वर्क आर्डर भी हो गये, मगर काम अभी तक नहीं हुआ। सरदार पटेल पुलिस व सुरक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना का तो शिलान्यास आपने अभी जाकर किया ही है। गौशाला में सिन्थेटिक ट्रैक निर्माण के लिये तो एस्टीमेट का काम ही अब पूरा हुआ है। पशुपालन परीक्षण केन्द्र की कार्यादेश की पत्रावली ही चल रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को रोकना मत, मैं फिर भूल जाऊंगी ऐसे ही। मान्यवर, ये तो केवल कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बड़े होने से दिख रहे हैं। अब, बजट घोषणाओं का काम कैसे धीमी गति से होता है। इस सरकार ने लगभग दो साल पहले सूरसागर क्षेत्र में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में सैटेलाइट हास्पिटल की घोषणा की थी। करीब ढाई करोड़ का इन्होंने प्लान बनाकर दिया कि यह हास्पिटल बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मगर आज तक उस पर एक

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

पैसा भी नहीं लगा। तो आप समझ लो, बजट के अन्दर इन्होंने बातें तो खूब की हैं। खाचरियावास जी ने बहुत लम्बी-लम्बी बातें कीं। यह बात सही है कि बजट में घोषणा करो। मगर घोषणा करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन तो हो। उसका काम तो हो। कोई काम ही नहीं हो रहा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलता। केवल घोषणाओं की सरकार है, धरातल पर कोई काम नहीं करती। जब दो साल में सैटेलाइट हास्पिटल में ढाई करोड़ में से एक धेले का काम नहीं करवाया तो बजट की घोषणाओं को छह महीने में कैसे पूरा करेंगे? बहुत लम्बा-चौड़ा बजट दिया है, बहुत सारी बातें कह दीं आपने बजट के अन्दर, लेकिन जब 4 साल में भी आपने काम नहीं किया तो 4 महीने में कैसे कर लेंगे? मारवाड़ी में एक कहावत है, 'सेठजी की लड़की पूठरी है, वह कहे कि म्हनै देओ।' आपने घोषणाएं तो खूब कर दीं, पर काम हुआ ही नहीं तो क्या मतलब है? मेरा आपसे कहना है कि जितनी आप घोषणाएं करें, बजट पेश करें, उसको इम्प्लीमेंट भी करें, उसकी मानिटरिंग भी करें। इसके लिये मैं आज की तारीख में वसुन्धरा जी और भैरोंसिंह जी की सरकार को धन्यवाद दूंगी कि बजट पेश करते तो ये हर एम एल ए को बुलाकर पूछते और पता लगाकर अधिकारियों के साथ मीटिंग करते कि इस काम का क्या हुआ, इस काम का क्या हुआ और फिर हमें बुलाकर पूछते, यह काम हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से अगर करें तो बजट का कोई औचित्य होगा। अभी तो चार-छह महीने में जितना हो पाएगा, उतना होगा।

मान्यवर, इस सरकार ने पहले तीन साल तक लगातार हजारों नौकरियों की घोषणाएं अपने बजट में कीं, परन्तु एक भी नौकरी नहीं दी। नौकरियों की घोषणा की, मैं सरकार से यह निवेदन करूं कि आप तो जो रिटायर हुए हैं उनकी जगह पर नौकरी लगा दोगे तो भी हम बहुत खुश हैं कि जितने रिटायर हुए उनकी जगह पर नौकरी लगा दी। रिटायरमेंट से खाली जगह को भी नहीं भर रहे हैं तो फिर इन नौकरियों के लिये कैसे सोच सकते हैं? युवाओं के रोजगार को चार साल तक दबाये रखा। युवाओं को कहा कि रोजगार देंगे, मगर आज तक कोई रोजगार नहीं दिया। अब पांचवें वर्ष में आप कह रहे हैं कि डेढ़ लाख नौकरियां देंगे। कैसे देंगे डेढ़ लाख नौकरियां, मेरी समझ से बाहर है। कैसे ये डेढ़ लाख नौकरियां देंगे, भगवान जाने कैसे करेंगे?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। आपकी सरकार ने जो थोड़ी-बहुत नौकरियां दी भी हैं, दी हैं थोड़ी-बहुत

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

नौकरियां, उनमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी जीता जागता प्रमाण है, मैंने 295 में भी बोला है, जयनारायण जी का नाम भी खराब कर रहे हैं। जयनारायण विश्वविद्यालय के अन्दर आपने नौकरियां दीं, ऐसे लोगों को दीं जिनको कि प्राथमिकता नहीं, उनकी क्वालिफिकेशन नहीं और फिर भी नौकरियां दी हैं। उसके अन्दर लाखों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। मैं दावे के साथ कह रही हूं। आप चाहेंगे तो एक-एक कागज टेबल कर दूंगी और मैं प्रूव कर दूंगी कि इसमें इतने लिये और इन्होंने इतने लिये। इतने लिये। तो यह नौकरी दी, न दी, बराबर है। यहां विधान सभा में बोलने के बाद भी अधिकारियों के सिर पर जूं तक नहीं रेंग रही है। लोग भूख हड़ताल पर 20 दिन से बैठे हैं, उनकी भी सरकार कोई देखभाल नहीं कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यहां पर कहना चाहूंगी, मुझे सन् तो याद है नहीं, मेरे पति का भी स्वर्गवास हो गया, एक दफा अमृत लाल जी गहलोत यहां एम एल ए थे, एक नये पैसे का घासलेट के अन्दर सवाल उठा था। पूरे जोधपुर ही नहीं, सारी जगह शोर मच गया, एक नया पैसा। एक नये पैसे के लिये विधान सभा में सवाल उठना कोई मामूली बात नहीं होती है।

श्री उपाध्यक्ष: कब उठा था? कौन से वर्ष में?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सन् तो मुझे याद नहीं है। अमृत लाल जी गहलोत एम एल ए थे। मुझे याद तो है नहीं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 1967 की बात है।

(15.00 बजे)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हां, 1967 की बात है। विधान सभा में अगर भ्रष्टाचार का सवाल उठ जाए और उसकी इन्क्वायरी नहीं हो तो यह बहुत भारी शर्म की बात होनी चाहिए। विधान सभा सर्वोच्च है, यहां पर भी कुछ नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आपके तो बिना कहे ही काम हो जाते हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या कहा?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आपके तो बिना कहे ही काम हो जाते हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, नहीं, आपके कहने से ही काम थोड़े होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: वह आपके डिपार्टमेंट की तो शिकायत कर ही नहीं रही हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): पैरा नम्बर 216, स्थानीय निकाय विभाग में एक बार फिर आपने नौकरियों की बात की, मगर पहले की घोषणाओं का क्या हुआ है? नगर निगम जोधपुर में 700 पदों पर भर्ती 2 साल से अटकी हुई है। जोधपुर में मोनो मैट्रो के सर्वे के नाम पर आपने झूठी वाहवाही लूटी। मुख्य मंत्रीजी ने खुद कहा था कि मैट्रो होगी, रिंग रोड बनेगी, मगर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। यह जोधपुर का तो नाम लेते हैं लेकिन जोधपुर को देते कुछ नहीं हैं। दिया है तो जोधपुर ने दिया है, 2-2, 3-3 यहां मुख्य मंत्री दिये हैं। 2 दफे अशोक जी को खुद मुख्य मंत्री को बनाया है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, आप मुझे रोकना मत। नहीं, मेरे को मेरी बात करनी है। नहीं, नहीं, मैं तो बोली भी नहीं हूं। आप यूं क्या कर रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष: आपके पास तो बहुत पाइंट हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, पाइंट नहीं, मैं मेरी बात तो रखूंगी। नहीं रखूंगी तो कैसे नहीं रखूंगी?

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा ध्यान रखो, औरों को भी बात करनी है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं बोलूंगी मेरी बात। आपने जयपुर और जोधपुर में यूजर चार्ज के नाम पर जनता से राशि वसूल की, वह भी बिना काम किये। कम्पनियों को बिना बात का फायदा देने के लिए यूजर चार्ज लगा दिया। कहीं भी आप चाहें तो टीवी कवरेज करवा दें, आप चाहें तो फोटो लाकर रख दें। क्या यूजर चार्ज लगाकर किया है कि एक जगह भी कहीं तगारी नहीं उठी है। जोधपुर शहर सड़ रहा है, जिस जोधपुर को लोग सोने की चिड़िया कहते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, पैरा नम्बर 216 में आर यू आई डी पी के तृतीय फेज में 250 करोड़ रुपये के जोधपुर सहित राज्य के अनेक शहरों में सीवरेज और ड्रेनेज विकास के काम होने की घोषणा की। लेकिन आप आज जनता से यह पूछें कि यह सीधा-सीधा कर्जा है जिस पर लागत सिर्फ जनता पर यूजर चार्ज लगाकर वसूल होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जनजाति क्षेत्र में खराब स्थिति की पोल तो महामहिम राज्यपाल महोदय ने खुद खोली है। आपने अनेक छात्रवृत्तियों को

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

बढ़ावा देने की और अनेक नयी चीजों की बात की है लेकिन आप ओ बी सी वर्ग को भूल गये हैं। ओ बी सी छात्रवृति में बजट नहीं आए और साल खत्म हो जाए तो छात्रवृत्ति खारिज हो जाती है। यह प्रदेश के लाखों ओ बी सी छात्रों के साथ धोखाधड़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वाइन फ्लू फैल रहा है, आम जनता मर रही है। जब दिल्ली की टीम ने आकर जगाया, तब जागे। तब तक बीमारी इतनी फैल चुकी थी कि लोग अब तक मर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, स्वाइन फ्लू की दवाइयां इतनी घटिया क्वालिटी और घटिया कम्पनी की आती हैं कि उन दवाइयों का कोई असर ही नहीं हो रहा है। ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मुफ्त दवाइयां दे रहे हैं, वह कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह दूं, आप मेरे साथ चलो, जोधपुर के गांधी हास्पिटल और एम.डी. हास्पिटल में जाकर खड़े हो जाओ, वहां लोगों को कितनी तकलीफें हैं और दवाइयां किस तरीके से मिलती हैं, वह देखो। लोग कहते हैं कि दवाइयों का कुछ असर भी नहीं हो रहा है? आप दवाइयां दे रहे हैं तो अच्छी कम्पनी की दवाइयां दो। आप फ्री दे रहे हो तो लोगों को ऐसे क्यों मार रहे हो? आप अच्छी कम्पनियों की दवाइयां दो। आप वे दवाइयां लेकर देख लो। मैं आपको दावे के साथ कह रही हूं, इतनी हल्की क्वालिटी और हल्की कम्पनियों की दवाइयां हैं कि क्या मालूम कहां से ला रहे है। डुप्लीकेट हैं कि क्या हैं, भगवान जाने।

उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा क्षेत्र के अन्दर आपकी उपलब्धियां ये हैं, आपकी कंपनियां इतनी ज्यादा घाटे में हैं कि उनकी बैंक गारंटी जब्त होने की तैयारी चल रही है। ये घाटे में चल रही हैं। राज्य में खनिज की उपलब्धता से आपको 4 हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपने इस बड़ी राशि का उपयोग केवल घोटाले में ही किया। आपकी केन्द्र सरकार लगातार असत्य बोलकर और तेल कम्पनियों में घाटे का राग अलाप कर पैट्रोल, डीजल के भाव बढ़ा रही है। तब आप 4 हजार करोड़ के राजस्व की थोड़ी राशि जनता में बांट देते तो आज की तारीख में गैस, डीजल, पैट्रोल सब रियायती दर से मिल जाते, जनता के साथ अच्छा न्याय होता।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में सौर ऊर्जा की अपार सम्भावनाएं हैं। राज्य में सौर ऊर्जा के लिए रियायती जमीनें अपने चहेतों को बांटी गयी हैं लेकिन उत्पादन के मामले में कोई ठोस उपलब्धि प्राप्त नहीं की है। उत्पादन कितना हो रहा है यह आपने बताया ही नहीं। इसका जवाब दीजिये। जोधपुर नगर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

निगम पिछले 3 साल से केन्द्र सरकार से सौर ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं में 10 करोड़ रुपये नहीं ले पाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के सहित देश भर में किसान विभिन्न रासायनिक खादों के खर्चों के कारण ऋणग्रस्त होकर आत्महत्या कर रहा है। दूसरों का पेट पालने वाला खुद खेती से मुंह मोड़ रहा है। आपने रासायनिक खाद कम्पनियों से सांठ-गांठ के चलते बजट के पैरा संख्या 133 में लाखों मैट्रिक टन रासायनिक खाद के भण्डारण का प्रावधान कर दिया है। यह आपने प्रदेश के किसानों को आत्महत्या की ओर धकेलने का काम किया है। रासायनिक खाद के उपयोग से जो खेती होगी, उसके सेवन से प्रदेश का आम आदमी गम्भीर बीमारियों से ग्रसित होगा। सबसे बड़ी बात प्रदेश की मिट्‌टी में है जो पहले से ही 4 गुना ज्यादा उपयोग हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष: 20 मिनट हो गये, माननीय सदस्य।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): यह और बढ़ जाएगा। यह प्रावधान प्रदेश की मिट्‌टी, प्रदेश के किसान और प्रदेश के आम आदमी के लिए स्लो पायजन का कार्य करेगा। आज जोधपुर के अन्दर भी ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें, समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जोधपुर के अन्दर कोई सब्जी मिलती है तो वह गंदे पानी की सब्जी मिल रही है। उसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। केवल मात्र 2 करोड़ का प्रावधान जैविक खाद के लिये किया है। अगर हजारों, लाखों टन का प्रावधान करते तो प्रदेश का किसान ऋण से बचता। प्रदेश के पशु धन का संरक्षण होता।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के नाम पर जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार में आपके दल के लोगों ने कैसे लोकतंत्र का गला घोंटा, वह आपसे छुपा नहीं है। लेकिन आप मौन रहे। जोधपुर में सहकारिता के नाम पर आम जन के साथ लगातार धोखाधड़ी और लूट की जा रही है। कैसे भी करके आपके दल के लोग संचालन मण्डल में रहें, इसलिए आपने स्पष्ट घोटाले किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): 5 मिनट में समाप्त करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: औरों को भी बोलना है, माननीय सदस्य।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रदेश में खान विभाग को तो आपने अपने हितबद्ध लोगों को ही देने का हथियार बना लिया है। पहले रोहिल्ला कलां में आपने नियमों के विरूद्ध अपने लोगों को फायदा देने के लिए भ्रष्टाचार किया। मैंने आपको कई बार लिखा, लेकिन आप मौन रहे। हुआ क्या? माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। एक बार फिर गजब का भ्रष्टाचार हुआ। आरोप पहले से संगीन और गम्भीर हैं। सदन के नेता ने यह कहा था कि 7 पीढ़ी भी नहीं कर सकतीं। लेकिन जो खान विभाग में घोटाला हुआ है, उसमें जोधपुर तक तो कोई एप्लीकेशन भी नहीं पहुंची है। यह तो सारा का सारा ऊपर की ऊपर और जयपुर में ही हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार की उपलब्धि यह है कि कभी कानून व्यवस्था तो कभी महिला अत्याचार, तो कभी सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव, बच्चों के अपहरण, गुमशुदाओं के मामले में माननीय उच्च न्यायालय टिप्पणी करता है कि इस प्रदेश में सरकार है भी या नहीं। आपके नगर में हालात यह है कि सफाई भी माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार होती है। उपाध्यक्ष महोदय, सफाई कराने के लिए हाई कोर्ट, एनक्रोचमेंट हटाए तो हाई कोर्ट।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करो। माननीय श्री सुरेन्द्र जी जाड़ावत।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सब बात हाई कोर्ट ही हाई कोर्ट करेगी।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, नहीं, उपाध्यक्ष महोदय। मुझे मेरी 2 बात और कहनी हैं। यह सरकार अपने कार्यों के लिए खुद की तारीफ करती है। जबकि हकीकत यह है, विधान सभा सदस्य होने के नाते, मैंने पहले भी बताया कि मैंने इतने पत्र लिखे, मगर एक भी पत्र का जवाब नहीं देते हैं। मान्यवर, यह बजट केवल चुनावी झुनझुना है। मेरी मांग है कि जब मुख्य मंत्रीजी जवाब दें तो मेरे इस प्रस्ताव के लिए बजट प्रावधान रखें। सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाए। सूरसागर विधान

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सभा क्षेत्र में देवनगर में प्रस्तावित नये पुलिस थाने की स्वीकृति दी जाए। सुन्दरहीर बालाजी और संलग्न पहाड़ी क्षेत्र को संरक्षित पर्यटन क्षेत्र घोषित कर विकसित किया जाए। सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय प्रबोधानन्द चिकित्सालय, प्रतापनगर को सैटेलाइट अस्पताल का दर्जा दिया जाए। बंगला तालाब के जीर्णोद्धार और सौन्दर्यीकरण के लिए बजट में कुछ प्रावधान रखे जाएं। जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अधीन होम्योपैथी महाविद्यालय खोला जाए। जोधपुर में नगरीय परिवहन सेवा में सुधार के लिये वर्तमान में उपलब्ध मण्डोर, सालावास, बरनाड़, सालावास और भगत की कोठी फितूसर चौपड़, रेलवे ट्रैक तक फास्ट राकर लेकर्स आरम्भ किया जाए। सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में संचालित पश्चिमी राजस्थान के एकमात्र पीजी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया जाए। मेरी मांग है कि नि:शुल्क दवा वितरण योजना आरम्भ करते समय सभी फार्मासिस्टों को नियमित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद देती हूं मगर इस बजट की मैं भर्त्सना करती हूं। यह बजट चुनावी बजट है और इस बजट के अन्दर जोधपुर को कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ हौव्वा फैलाया है। आप जोधपुर में जाये-जन्मे हो, जोधपुर आपका गृह क्षेत्र होते हुए भी आपने जोधपुर को न के बराबर रखा है। मैं इस बजट की भर्त्सना करती हूं।

(15.10 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, जो बजट हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत ने पेश किया, मैं उसके समर्थन में बोलूंगा। 6 तारीख को जो बजट पेश किया गया, वह राजस्थान के आम जन के लिए, राजस्थान के विकास के लिये, राजस्थान की गरीब जनता के लिये, राजस्थान के सभी लोगों को लाभ देने वाला बजट पेश किया गया है। लेकिन विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति के तहत इस बजट की शुरूआत में ही इसको कैसे धूमिल किया जाए, जब सदन के नेता बोलने के लिए खड़े हुए बजट के ऊपर, तो कभी परम्परा नहीं रही

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

सदन के अन्दर, लेकिन माहौल बनाया गया कि बजट किसी तरह से मुख्य मंत्रीजी नहीं पढ़ पाएं। ऐसे अनर्गल आरोप जिनका कोई सिर पैर नहीं। हम लोग जो राजनीति में आते हैं, हमारा कोई रिश्तेदार कोई काम करे, सरकार के नियमों के तहत कानून के तहत, उस पर उंगली उठाकर हमको कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करें, यह राजनीति के लिये, स्वच्छ राजनीति के लिए उचित नहीं है। उस दिन उनको बार-बार टोका गया, रोका गया। उनकी समझ में नहीं आई बात कि मामला क्या है। जब उन्होंने सुना तो उन्होंने बजट के बारे में बोलने से रुक कर पहले सारी बात प्रतिपक्ष के नेता के ऊपर ही डाल दी कि स्वयं जांच कर लें, उसके बाद उन्होंने अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अशोक गहलोत ईमानदार नहीं हैं तो इस देश के अन्दर ईमानदारी का नाम ही खतम हो जाएगा। उन्होंने आज तक कभी भी नापाक समझौता नहीं किया। वह जितने ईमानदार और साफ सुथरे अपने जीवन में हैं, व्यक्तिगत जीवन में हैं, उतने ही वह प्रशासनिक जीवन में भी हैं। राजनीति में उन्होंने हमेशा गांधीजी के आदर्शों को अपना आदर्श माना है गांधीजी के हर बताये रास्ते पर चलकर, उनके मार्ग का अनुसरण करके। व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, जब वह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, केन्द्र में मंत्री थे, लोक सभा के सदस्य थे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह बजट में लिखा है क्या?

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): यह जेडीए, नगर निगम पर बोलीं, मैं क्यों नहीं बोलूंगा?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बजट पर बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह अब कह रहे हो, तब बोलते।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): मैं क्यों नहीं बोलूंगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह कह रही थीं तो जांच करवा लेना। जांच करवा लो। (व्यवधान) कहां दिक्कत है?

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): मैंने आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया। मैं मेरे नेता के लिए बोलूंगा। आपने बजट भाषण में जिस तरह से आरोप लगाकर इस बजट को धूमिल करने की कोशिश की है, उसके बारे में मैं अवश्य बोलूंगा। रिश्तेदारों के बारे में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य राठौड़ साहब, कृपया बैठिये। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सारे घोटाले ही घोटाले हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): घोटाले हुए हैं तो आप आ जाओ। पांच साल का जो पांचवां बजट किया है मुख्य मंत्रीजी ने पेश, आपके बजट ले लो और हमारे बजट को ले लो, तीन दिन इसी पर डिबेट करा लो आप कि आपकी सरकार ने कैसा बजट पेश किया और हमारी सरकार ने कैसा बजट पेश किया। (व्यवधान) बहस हो जाए तीन दिन की।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): घोषणा ही घोषणा है, किया कहां है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपकी यह चुनौती मंजूर है, करवा लो बहस। यह चुनौती मंजूर है। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आपने घोषणा ही घोषणा की है, किया कुछ नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): करवा लो आप बहस।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): तैयारी कर लो आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): यह अपनी नेता के बारे में बोलें। मैंने तो नहीं कहा इनको। स्वर्गीय राजस्थान के हमारे पूर्व मुख्य मंत्री थे, बहुत ईमानदार और बहुत कर्मठ नेता रहे मुख्य मंत्री रहे, उप राष्ट्रपति रहे, भैरोसिंह जी शेखावत, कोई आरोप लगाए, मैंने तो यह नहीं कहा। मैंने तो यह नहीं कहा कि इनके लोग, इनकी पार्टी के उपाध्यक्ष ने क्या आरोप लगाये। मैंने तो यह नहीं कहा। मैं अपने नेता की तारीफ कर रहा हूं, उनकी ईमानदारी की तारीफ कर रहा हूं, ...(व्यवधान) मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माथुर आयोग बनाया था न? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): जो भी मिलता है उनकी ईमानदारी की तारीफ करता है। उनके जो चिंतक हैं वे भी कहते हैं कि आपका मुख्य मंत्री बहुत ईमानदार है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बजट पर आइये। राठौड़ साहब, आप अपने पाइण्ट पर आइये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, फिर जब बजट पेश हो रहा था, न जाने कैसे-कैसे, एक आंदोलन न मालूम किन के द्वारा खड़ा किया गया, वकील आंदोलन। वकील आंदोलन से माहौल पैदा करके इस बजट को धूमिल करने की पहले सदन में कोशिश हुई फिर सदन के बाहर कोशिश हुई। किस तरह से राजस्थान के अन्दर आज हालात हैं, इन हालात को इसको समझना पड़ेगा। जो कानून सिखाते हैं, जिनका चोली-दामन का साथ है, पुलिस और वकीलों का, उन दोनों का आमने-सामने हो जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बुद्धिजीवी तबका कहलाता है, वकील बुद्धिजीवी तबका है, जो कानून बताता है और जो कानून बनाया जाता है उसकी रक्षा करने वाली पुलिस किस तरह से आमने-सामने हो गये! राजस्थान में किस तरह के हालात हो गये? मैस का बहिष्कार हो रहा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा इसको भयावह रूप में पूरे राजस्थान में पेश किया गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, केवल आप बजट पर विवेचना करें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): बजट मैं कह रहा हूं आपको कि पिछले वर्ष भी बहुत अच्छा था और इस बार भी। इनको मालूम था कि पिछले बजट में भी हम नहीं बोल पाये थे, इस बजट पर क्या बोलेंगे। आज इन्हीं लोगों ने ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, एक शब्द बजट पर बोला हो तो बता दें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): मैं बजट पर बोल दूंगा। (व्यवधान) राठौड़ साहब, मैं आ रहा हूं बजट पर। (व्यवधान) आप सुनने का माद्दा रखो। जब आपकी ऐसी हालत देखी तब आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता देव दर्शन पर रवाना हो गये। यह हालत देखकर वह खुश नहीं हुए। तो बहुत गलत तरीके से सदन के अन्दर प्रतिपक्ष कर रहा है। इन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य जो कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, प्रतिपक्ष के सम्मानित नेता हैं, पहले भी सरकार में बहुत अच्छे पदों पर रहे हुए हैं, वह दु:खी-पीड़ित होकर पहले तो एस एम एस अस्पताल में

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

भर्ती हो गये और वहां से निकलकर सीधे गणेशजी को धोक लगाकर देव दर्शन पर निकल गये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इनसे पूछा जाए, प्रतिपक्ष के नेता तो अभी हाल ही में मनोनीत हुए हैं इनकी पार्टी के द्वारा, कटारिया साहब, हमारे संभाग के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत ईमानदार आदमी हैं, इसके पहले प्रतिपक्ष की नेता थीं कहां पर, यह बताओ आप? यह आम बजट है, वह हैं कहां? क्यों नहीं बजट पर बोलतीं? वह कह रही हैं कि मैं मुख्य मंत्री की अगली दावेदार हूं, मुख्य मंत्री बनूंगी। मुख्य मंत्री जनता बनाएगी, आज कहां है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपकी कब्र खोदने के लिए मैदान में हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): हमारी कब्र नहीं खुदेगी। (व्यवधान).

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जिस वक्त आप यहां बोल रहे हो, 50 हजार आदमियों के बीच में भाषण दे रही हैं, 50 हजार लोगों के बीच में।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): हमारी कब्र नहीं खुदेगी। (व्यवधान) अब आप सुनो।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): आपका मंत्रिमण्डल तो पूरा खाली पड़ा है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): मालूम पड़ जाएगा। आप तो विराजो ...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): इसके अलावा कुछ कहने के लिए नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): आपको कुछ मालूम ही नहीं है, आप तो बुला लो मुख्य मंत्रीजी को। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): गलत क्या बोल रहा हूं, यह बताओ आप। (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी को तो बुला लो ...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है, उसके लिए तो समय नहीं है और इस तरह की चर्चाओं के लिए पूरा सदन का समय वेस्ट किया जा रहा है। (व्यवधान) इनसे कहें, यह बजट पर बोलें। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): अब सदन के नेता कहां हैं? (व्यवधान) बजट पर बोल रहे हैं, बड़ी गम्भीर चर्चा चल रही है, वह कहां हैं? (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): नहीं, यह बजट पर कहां बोल रहे हैं? हम लोगों को एक-एक शब्द बोलने का समय नहीं मिलता और इस तरह समय को वेस्ट किया जा रहा है, यह क्या तरीका है? (व्यवधान) क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हमारी पार्टी का समय वेस्ट हो रहा है, हम हमारे हिसाब से बोल रहे हैं, सुनिए न। (व्यवधान) इनको कौन-सी तकलीफ हो रही है? आपको तो कोई मंत्री नहीं बनाएंगे। (व्यवधान) आप बोल लेंगे तो आपकी टिकट पक्की हो जाएगी? जनता के बीच में जाना पड़ेगा। (व्यवधान) कौन सी तकलीफ हो रही है? (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): आप बैठो, पूरा शोषण किया है ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): हां, बजट पर आ रहा हूं।

श्री सुखराम (बसेड़ी): हां, बजट पर आइए।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): हां, बजट पर ही आ रहा हूं। आप लोग ये सपने देखने बंद कर दो, 2018 की तैयारी करना ...(व्यवधान) आप लोग जीत नहीं सकते, कहीं जीत नजर नहीं आ रही है। यही मुख्य मंत्री अशोक गहलोत वापस बजट पेश करेंगे, वापस कांग्रेस की सरकार धड़ल्ले से आएगी, यह और सुन लो आप। अब आप सुनते रहो कि सरकार कैसे आएगी, वह भी सुन लो। (व्यवधान) रिफाइनरी लगाई गई, सभापति महोदय, ... (व्यवधान) ये कहते हैं कि रिफाइनरी के आने से क्या होगा। जब मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि रिफाइनरी आई है, तब इन्होंने कहा कि हमने भी बहुत प्रयास किये और अभी कह रहे थे कि रिफाइनरी के आने से क्या फायदा होगा। रिफाइनरी आने से डेढ़ लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा, 128 तरह के छोटे-मोटे उद्योग धंधे लगेंगे वहां पर। बाड़मेर में जिस दिन रिफाइनरी आई, उस दिन जश्न का माहौल था, जिस तरह से दीवावली हो या बहुत बड़ी कोई सौगात मिली हो। इससे बड़ी सौगात पूरे राजस्थान के लिए नहीं हो सकती। बाड़मेर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

जिला तो अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली है। यह मुख्य मंत्री की इच्छा शक्ति थी इसलिए रिफाइनरी राजस्थान के अन्दर अपने पूरे प्रभाव का उपयोग करते हुए उन्होंने स्वीकृत कराई। उसको भी धूमिल करने की कोशिश की गयी। (व्यवधान) अब आप विकास पर आ जाओ ...(व्यवधान) अरे, बैठ तो जाओ, हुजूर, सुनने का माद्द रखो। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप कृपया बीच-बीच में व्यवधान न करें, बोलने दें। वह आपके साथी बोल रहे हैं, बैठिए आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, यह कहते हैं विकास, विकास के लिए मुख्य-मुख्य पांच-सात बातें होती हैं। उसमें मैं निवेदन करूंगा आपसे, सड़क हर राज्य के विकास के लिए एक बहुत बड़ा आधार होती है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्रीजी की सोच को और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री भरत सिंह जी को, जिन्होंने पिछले वर्ष 250 से 499 तक की आबादी के पूरे राजस्थान के हर गांव को जोड़ने का फैसला किया। उस पर काम शुरू हो गया है। ये कहते हैं, बजट की घोषणाएं कब पूरी होंगी। अभी 10 सड़कें एक ही दिन में, भरत सिंह जी सार्वजनिक निर्माण मंत्री यहां विराजे हुए हैं, एक ही दिन में 10 सड़कों का शिलान्यास करके पधारे हैं, 7 सड़कों का शिलान्यास मैं करके आया हूं, जो काम शुरू हो गया। मार्च के आखिर तक 250 से 500 तक की आबादी की लगभग सड़कें जुड़ जाएंगी, मिसिंग लिंक के 5 गांव जुड़ जाएंगे। हमारी धार्मिक सड़कें जुड़ चुकी हैं। उससे आगे बढ़कर चित्तौड़ जिले के लगभग 250 गांव जुड़ेंगे, चित्तौड़ विधान सभा के लगभग 50 गांव 250 से 500 तक की आबादी के जुड़ेंगे। अभी एक और फैसला किया कि सौ से लेकर ढाई सौ तक की आबादी के गांव जुड़ेंगे। इस सोच के लिए हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा और यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा। आने वाले समय के अन्दर राजस्थान के अन्दर कोई ऐसा गांव नहीं रहेगा, राजस्व गांव, जो कि सड़क के बिना हो। यह आधारभूत ढांचे के लिए सबसे बड़ा काम किया। 6 हजार करोड़ रुपये इसके लिए उन्होंने रखे। झालावाड़ के अन्दर पांच साल में क्या हुआ, सभापति महोदय, हवाई पट्टी बनाई गई वहां पर। हमारी सरकार ने ये आंकड़े मैं निवेदन कर रहा हूं, 49 गांव तो 250 से 500 तक की आबादी

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

के, जो पूर्व मुख्य मंत्री हैं, उनके झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र में जोड़ने का फैसला सरकार ने करके टेंडर लगा दिये हैं, नाबार्ड से और वर्ल्ड बैंक से। 38 गांव 100 से 250 तक के जुड़ जाएंगे, 87 गांव उस विधान सभा क्षेत्र से जुड़ेंगे। यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो आज भाजपा की अध्यक्ष हैं, जो पूर्व मुख्य मंत्री रही हैं, उनके विधान सभा क्षेत्र का निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान) और पूरे जिले में ...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): 8 हजार गांव थे, आपने 8 सौ नहीं जोड़े।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, 564 गांव झालावाड़ जिले के जुड़ेंगे जहां से मुख्य मंत्री रही हैं। 8 सौ गांव कोटा संभाग के जुड़ेंगे ...(व्यवधान) ये सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

आर यू बी राजस्थान के मुख्य मंत्री की योजना है, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना नहीं है। सभापति महोदय, इसे मुख्य मंत्रीजी ने संसाधन जुटा कर, वर्ल्ड बैंक से ऋण लेकर शुरू किया है। (व्यवधान). अब मैं आगे चलता हूं। (व्यवधान) 6 हजार किलोमीटर का सुदृढ़ीकरण होगा।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापति जी, इस तरह डिस्टर्ब करेंगे तो इधर से भी करेंगे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): इसलिए पहले भी हुआ और अभी भी होगा ...(व्यवधान) आप धर्म की बात करते हो, हमारे मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट में भी और इस बजट में भी सड़कों से धार्मिक स्थानों को जोड़ने का निर्णय किया। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, इधर से बोल गये, उधर से बोल गये, निर्दलियों का सवा घंटा है और मैं अकेला ही हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। देखिए, एक बात के लिए मैं माननीय सदस्यों को अपील करने की ही बात कहूंगा, कि जो बोल रहे हैं आपके साथी, उनका हक है बोलने का, कृपया उनको सुनें। आपका जो आलोचना करने का हक है, वह आप अपने टर्न पर करें, लेकिन आप उनको बोलने दें। इसलिए मेरा आपसे यह है कि जब आपका नम्बर आए तो वे आपको व्यवधान नहीं करते हैं, जब उनका नम्बर आए तो आप व्यवधान मत करें। चलिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): आप सुनते रहो। सड़क हो गई, अब मैं ऊर्जा के क्षेत्र में आता हूं। सभापति महोदय, ऊर्जा किसी भी राज्य का आधारभूत उस ढांचे को मजबूत करने वाला तंत्र है, अगर वह नहीं चले आज की व्यवस्था में, तो पूरा राज्य पंगु हो जाता है। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने, हमारे ऊर्जा मंत्रीजी जितेन्द्र सिंह जी ने फैसला करके 4600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। इस वर्ष को शामिल करते हुए लगभग सवा तीन लाख कृषि कनेक्शन दे देंगे और 16 लाख उन लोगों को जो आज तक घरों के कनेक्शन के लिए बाट जोह रहे हैं, कनेक्शन दे देंगे। 100 से कम आबादी के गांवों के अन्दर कनेक्शन हो जाएंगे। 765 के वी ए के ग्रिड बन रहे हैं, प्रसारण तंत्र मजबूत हो रहा है। 400 के वी ए के ग्रिड बन रहे हैं, 220, 132, 33 के वी ए के ग्रिड सब-स्टेशन बन रहे हैं, ताकि पूरा का पूरा प्रसारण तंत्र मजबूत हो और आम आदमी को अच्छी बिजली मिल सके। आज एक मोटर जल जाती है, सभापति महोदय, तो किसान के ऊपर 10 हजार रुपये का कर्जा आता है, सीधा वह 10 हजार रुपये जेब से भरता है, तब जाकर वह मोटर ठीक होकर आती है। आज प्रसारण तंत्र मजबूत होने से मैं अपनी विधान सभा की ही कह रहा हूं आपको, हम लोगों ने लगभग 17 ग्रिड हमारे विधान सभा क्षेत्र में चालू कर दिये। आज एक भी किसान नहीं कहता कि मेरी मोटर जल गई है ट्रिपिंग की वजह से। यह प्रसारण तंत्र की मजबूती का उदाहरण मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। ऊर्जा के क्षेत्र के अन्दर काम हुआ। इसके आगे ...(व्यवधान) अरे भाई, बोलने तो दो, गलत बोल रहा हूं? (व्यवधान) 400 का ग्रिड मेरे यहां बन रहा है माण्डलदा में, 132 के ग्रिड मेरे यहां बन रहे बस्सी में, विजयपुर में, 220 का सावा में बन रहा, ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बिजली नहीं, रोएंगे किसान, मारेंगे आपको। अब 1450 रुपये यूजर चार्ज लगा दिये, कूटेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं फिर आपको एक बार अपील करता हूं कि आप ...(व्यवधान) कृपया व्यवधान न करें, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, हाउस को हाउस की सीमा के अन्दर चलने दें। चलिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): 20 ग्रिड चित्तौड़ विधान सभा क्षेत्र में बन रहे ...(व्यवधान) नि:शुल्क दवा योजना है इनके लिए। खास तौर से प्रतिपक्ष के लिए बहुत तुषारापात वाली योजना है । पूरे राजस्थान के लिए तो यह बहुत ही जीवनदायी योजना साबित हो रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपसे मैं कई बार कह चुका हूं कि कृपया व्यवधान मत करिये। आपसे मैं बार-बार व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि आप कृपया व्यवधान मत करिये, पर आप बार-बार व्यवधान कर रहे हैं। आसन यह देख रहा है कि आप बार-बार व्यवधान कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, मेरे अपने चित्तौड़ जिले की ओ.पी.डी. 16 लाख 40 हजार 500 आज से 10 दिन पहले हो चुकी है और लगभग 5 करोड़ 37 लाख रुपये दवाइयों पर खर्च हुए हैं। इसके अलावा चित्तौड़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर साढ़े सात लाख मरीजों ने इस दवाई का फायदा उठाया है। इस दवाई का फायदा यह हुआ कि मुख्य मंत्री जी ने दायरा और बढ़ा दिया और 400 की जगह 600 दवाई कर दीं। निःशुल्क जांच की व्यवस्था कर दी। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय सदस्या यहां से चली गई हैं, वो कह रही थीं कि दवाइयां बहुत घटिया किस्म की दे रहे हैं और मरीज ठीक नहीं हो रहा है। यह राजस्थान पत्रिका में आया है, यह पुष्पा मीणा गांव पचूण्डल और अभयपुर पंचायत की है, 13 वर्षीय बालिका थी, सभापति महोदय, सांप खा गया। उसको उसके परिवारजन सांवरिया चिकित्सालय में लेकर आये और वहां पर सांप के जहर को खत्म करने वाले इंजेक्शन लगाये गये। लगभग 30 वाइल लगाई गईं। सभापति महोदय, एक इंजेक्शन की कीमत 300 रुपये है और जो सांप का काटा हुआ आता है उसको 30 भी लग सकते, 60 भी लग सकते हैं, 70 इंजेक्शन भी लग सकते हैं। उस पुष्पा मीणा की जान बच गई। अगर वो इंजेक्शन गलत होता तो वो बचती नहीं। वो भाई को राखी बांधने आई थी। क्योंकि बचपन में शादी हो गई, ससुराल चली गई और फिर भाई को राखी बांधकर वो वहां से गई है। ये जहां जोधपुर की बात करते हैं तो मैं जोधपुर की बात ही निवेदन करता हूं। जोधपुर के अन्दर एक निर्मला देवी, खारी गांव की रहने वाली थी जिसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। मथुरादास अस्पताल के अन्दर वो 4 या 5 फरवरी के लगभग भर्ती हुई। ब्रेन स्ट्रोक को ठीक करने का एक इंजेक्शन आता है जिसकी कीमत 30 हजार रुपये है। उस इंजेक्शन का नाम है टेनेक्टा सेलेस, कोई डाक्टर है तो वो मुझे करैक्ट कर दे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। उसको जब बताया गया कि 30 हजार रुपये का इंजेक्शन आएगा तो साथ वाले के हाथ-पांव फूल गये क्योंकि वह गरीब परिवार की थी। जैसे ही वो दवाई लेने गया तो कम्पाउंडर दौड़कर आया और पूछा कि कहां जा रहे हो। तो उसने कहा कि मैं दवाई लेने जा रहा हूं, मेरे पास 30 हजार की व्यवस्था नहीं है। तो उसने बताया कि मुख्य

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

मंत्रीजी ने नि:शुल्क दवा योजना की व्यवस्था कर रखी है, वहां जाकर दवाई ले लो। 30 हजार रुपये का इंजेक्शन उस महिला को फ्री मिला और वो तीन घंटे में ठीक होकर अपने घर चली गई। दिल में जब स्ट्रोक आ जाता है तो उस वक्त स्पैक्टाकायेज इंजेक्शन लगता है और वो इंजेक्शन 1200 रुपये का आता है, सभापति महोदय। जब हार्ट अटैक आता है, बड़े लोगों की बात छोड़ दो, गरीब के पास तो 12 रुपये ही नहीं होते। वो जाता है तो इंजेक्शन एक भी लग सकता है, दो भी लग सकते हैं और उसके बाद में 400-400 रुपये के दो इंजेक्शन रोज 5-7 दिन तक लगते हैं, तब जाकर वो मरीज ठीक हो पाता है। यह मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं कि इस दवा से 7 करोड़ 43 लाख राजस्थान के लोग फायदा उठा चुके हैं। मुख्य मंत्रीजी ने अभी हास्पिटल के अन्दर महिला चिकित्सालय दिया।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सात करोड़ तो पूरे राजस्थान की पापुलेशन है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): दुबारा नहीं लेगा क्या? दवाई दुबारा नहीं लेता क्या? (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सारे के सारे अस्पतालों में ही खड़े हैं क्या? ऐसे गलत बोलने से कुछ तो डरो, कुछ तो शर्म करो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, समझाओ इनको। (व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापति जी, प्रतिपक्ष के माननीय सचेतक भी बैठे हैं, मैं निवेदन करूं कि इसमें आप खड़े होकर कह दो कि सात करोड़ आबादी नहीं है राजस्थान की, तो दवाई आदमी दो या चार बार लेता है। उसमें भी आपको डिस्टर्ब करना है। और फिर अपन कहें कि समय बढ़ाओ, सब लोग बोलें। आपने 20-22 की लिस्ट दे दी, 10-12 इधर के हैं.....

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सचेतक जी, 7 करोड़ 43 लाख लोग बता रहे हैं जबकि टोटल पापुलेशन ही सात करोड़ है। टोटल पापुलेशन नहीं बोला है, उसको उठाकर देख लो, कहा है कि दवाइयां ले चुके हैं। क्या पता, सबको दो-दो बार दे दी होगी इन्होंने सारे राजस्थान को। कम से कम असत्य बोलने में शर्म तो करो।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): मैं बात कर रहा हूं न। मेरी बात तो सुनें एक बार। बैठो तो सही। आप मेरी बात सुनो। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): इस तथ्य की जांच करा ली जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, कृपया विराजिये। देखिये, मैं बहुत गम्भीरता के साथ आपसे कह रहा हूं कि आप हाउस की गरिमा बनाकर नहीं रख रहे हैं। आप में से कई लोग वरिष्ठ सदस्य भी हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप गरिमा बनाये रखें और सदन की कार्यवाही चलने दें। अगर आप लोग सदन को चलाना नहीं चाहते तो फिर दूसरी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग बोलने तो दे नहीं रहे हैं और हर दो मिनट के बाद में व्यवधान कर रहे हैं। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोगों का गरिमा को नहीं रखने का तरीका यह है कि जब भी सभापति यहां होता है तो आप लोग कुछ ज्यादा व्यवधान करते हैं। ये व्यवधान आप तब नहीं करते जब अध्यक्ष यहां होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, आपको यह भी मालूम नहीं है कि आसन की ताकत वो ही है जहां तक यहां के अनुशासन की बात है। आप यह बात ध्यान से सुन लें कि अगर आपने व्यवधान करने की कोशिश की तो आप समझो कि जो अनुशासन के लिए इस आसन के पास ताकत है वो इतनी ज्यादा है कि हाउस की गरिमा आपको मेनटेन करनी ही पड़ेगी। आप बोलिये और जल्दी खतम करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): अभी तो मुझे इन्होंने बोलने ही कहां दिया है, आधा गला तो इन्होंने वैसे ही सुखा दिया।

श्री सभापति: आपने ज्यादातर टाइम तो यूज कर लिया।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, हास्पिटल के अन्दर गरीबों के लिए एक करोड़ की धर्मशाला जिला चिकित्सालय के ऊपर बना रहे हैं। 15 मेडिकल कालेज की किसी ने कल्पना की थी क्या कि एक साथ 15 मेडिकल कालेज आ जाएंगे? मैं मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन जरूर करूंगा कि जो पी.पी.पी. मोड पर कर रहे हैं उसको पी.पी.पी. मोड पर नहीं करके जिस तरह से इन्होंने सात विश्वविद्यालय खोले, आई आई टी, आई आई एम दिये हैं उसी तरह से ये सारे मेडिकल कालेज राजकीय स्तर पर खोलें

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

क्योंकि पी.पी.पी. मोड पर व्यवस्था चरमरा जाती है, बहुत मुश्किल से वह हो पाता है। उसके साथ-साथ साढ़े सोलह करोड़ का हर जिला चिकित्सालय के ऊपर, राजस्थान के अन्दर जहां 300 बैडेड हास्पिटल हैं वहां पर नया महिला चिकित्सालय बन सके....

श्री सभापति: ऐसा है, माननीय सदस्य, आसन का सहयोग करेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उसके लिए पैसा दिया है और इसमें चित्तौड़ भी शामिल है। हमारे यहां पर बर्न यूनिट भी दी है, हमारे यहां पर सी टी स्कैन भी दिया है, जन सहभागिता में दिया है लेकिन यहां से व्यवस्था कराकर दिया है। अभी हमारे चित्तौड़ के अन्दर डायलिसिस मशीन बहुत सुचारु रूप से चल रही है। प्राइवेट सैक्टर में मुख्य मंत्रीजी की प्रेरणा से बिरला सीमेंट हमारे यहां पर 40 करोड़ रुपये का अत्याधुनिक हास्पिटल बनाने जा रहा है और वो भी मेडिकल कालेज के साथ में चित्तौड़ के लिए बहुत सुविधाजनक चीज होगी। कहने का अर्थ यह है कि नि:शुल्क दवा योजना, नि:शुल्क जांच योजना जिसमें 200 दवाइयां और बढ़ा दीं, यह राजस्थान की जनता के लिए उन्होंने किया है और इसके लिए उनके हम बहुत-बहुत आभारी हैं। हमारी सरकारें भी रहीं, प्रतिपक्ष की भी रहीं, लेकिन आम आदमी के लिए उन्होंने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। इतना बड़ा कदम उठाना हर किसी के बूते की बात नहीं होती है। सभापति महोदय, जब तक इच्छा शक्ति मजबूत नहीं हो तब तक ये चीजें नहीं होतीं।

पशुओं के लिए उन्होंने नि:शुल्क दवा योजना शुरू कर दी। मेरे अपने जिले में 64 हजार पशुओं को आज से दस दिन पूर्व तक लाभान्वित किया जा चुका है। अब उन्होंने दवाइयां जो 90-95 थीं, उनमें 20-25 तरह की दवाइयां और बढ़ा दीं। सभापति महोदय, जी एन आर एस, ये हारमोंस बढ़ाने का इंजेक्शन है, लगभग 500 रुपये का एक आता है, एक एक्ससीजी, यह भी हारमोंस बढ़ाने वाला इंजेक्शन है और 350 रुपये का एक आता है, आज किसान जब जाता है तो सबसे महंगी दवाई भी राजस्थान की सरकार नि:शुल्क दे रही है। इसके साथ-साथ एंटी बायोटिक इंजेक्शन सवा सौ रुपये से कम का नहीं है, और वो 10 भी लग सकते हैं, 20 भी लग सकते हैं, वो इंजेक्शन सारे के सारे नि:शुल्क सरकार ने देने का फैसला किया। एम्बुलेंस का किया कि अब डाक्टर जाकर इलाज करेगा। पशुधन अगर बीमार होगा तो उसकी व्यवस्था राजस्थान की सरकार कर रही है। 108 की व्यवस्था आम

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

आदमी के लिए की, जननी सुरक्षा योजना महिलाओं के लिए की और अब यह एम्बुलेंस देने का भी मुख्य मंत्रीजी ने फैसला किया है। पशु चिकित्सालय के अन्दर पशु उप केन्द्र देने जा रहे हैं, नये-नये 'ए' श्रेणी के चिकित्सालय खोले जा रहे हैं। पशुधन राजस्थान के विकास का सबसे आधारभूत ढांचा है। राजस्थान कृषि के क्षेत्र से ही जाना जाता है और उसमें पशुधन भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साढ़े पांच करोड़ पशुओं का इलाज नि:शुल्क करना, साढ़े छह करोड़ आदमियों के लिए नि:शुल्क दवा योजना देना,

यह कम बात नहीं है। यह मील का पत्थर साबित हो रही है। राजस्थान की इन योजनाओं से बाहर के राज्य भी आ-आकर प्रेरणा लेकर जा रहे हैं, सभापति महोदय, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ 30 लाख किसानों को 10,000 करोड़ रुपये के ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंक के द्वारा, 152 करोड़ रुपये भूमि विकास बैंक के द्वारा। मैं सहकारिता मंत्रीजी को भी धन्यवाद दूंगा कि उनकी मानिटरिंग उन्होंने फील्ड में जा-जाकर की। आज, सभापति महोदय, अगर एक किसान एक लाख रुपया लेता है, छह महीने का 24,000 रुपये का ब्याज लगता है। आज 24,000 रुपये मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत उस किसान के खाते में ब्याज पेटे जमा करा रहे हैं, यह कोई कम बात नहीं हुई।

इसके आगे चलकर, सभापति महोदय, किसानों को बोनस आज तक के इतिहास में नहीं दिया गया, 100 रुपये पिछले वर्ष शुरू किया, 20 लाख टन गेहूं। इस बार उन्होंने बोनस 150 रुपये कर दिया। पशुपालक जो अधिकांश किसान ही होते हैं, उनके प्रति लीटर दूध के ऊपर दो रुपये लीटर बोनस अलग देने का फैसला किया। किसानों को राहत देने के लिए राजस्व से सम्बन्धित एस डी ओ कार्यालय, तहसील, उप तहसील, पटवार सर्किल, आर आई सर्किल, आई टी सेंटर, ये सारे के सारे कार्यालय आज राजस्थान के अन्दर मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने दिये हैं। हमारी सरकार ने तो जो उप तहसीलें खोलीं, इनकी सरकार ने बंद कर दीं, लेकिन इस सरकार ने आते ही उन उप तहसीलों को चालू किया, तहसीलों को चालू किया, एस डी ओ हैडक्वार्टर को चालू किया। तो आज इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत राजस्व के मामले में हुई है। आई टी सेंटर बन जाएंगे, किसान सेवा केन्द्र बन जाएंगे, आप उसके बाद देखना कि राजस्थान का हर पंचायत मुख्यालय मिनी सचिवालय के रूप में काम करेगा। सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी की यह सोच है।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

ड्रिप इर्रिगेशन बूंद-बूंद इर्रिगेशन है, उसके अन्दर स्प्रिंकलर सैट के माध्यम से उन्होंने सब्सिडी और बढ़ा दी। कर्ज की सीमा भी एक लाख से डेढ़ लाख रुपये बढ़ा दी। मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन भी करूंगा, सहकारिता मंत्रीजी विराजमान हैं, कि किसानों के बोनस की राशि अगर और बढ़ जाती है और जो लक्ष्य 20 लाख टन गेहूं का है, वह कम है, वैसे 26 लाख टन कर दिया है, उसको भी और थोड़ा बढ़ाएंगे तो किसानों को और अधिक राहत मिलेगी क्योंकि 150 रुपया होने के बाद में किसानों में अपार खुशी है।

सभापति महोदय, मैं ईमानदारी से इस पवित्र सदन में निवेदन कर रहा हूं कि बजट के बाद में बधाइयां, बधाई के एस एम एस, बधाई के फोन आ रहे हैं। आम आदमी, सड़क पर चलता हुआ आम आदमी यह कह रहा है कि मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ही शानदार बजट दिया है। राजस्थान की गरीब जनता को तो उन्होंने निहाल कर दिया है। अब आप सोचो, 38.63 लाख बी पी एल परिवार को दो रुपये किलो गेहूं था, उसको एक रुपया किलो कर दिया। यह कोई कम काम है? गरीब महिलाओं के लिए दो साड़ी, एक कम्बल, यह कोई कम काम है? 10 लाख लोगों को मकान, 50,000 रुपया, 10,000 रुपया उसके शौचालय के लिए, यह कोई कम काम है? अब 75 कर दिया, 70 कर दिया। मैं पुरानी बात कर रहा हूं, पिछले बजट की बात कर रहा हूं। अब इस बजट की बात तो मैं करता ही। उसके साथ-साथ, सभापति महोदय, आम आदमी के लिए गेहूं पांच रुपये किलो कर दिया। तेल, दाल, साबुन, बिस्किट, ये राशन की दुकान से सस्ता उपलब्ध कैसे हो, उसकी व्यवस्था सरकार ने करनी शुरु कर दी। गरीब बी पी एल को शक्कर 14 रुपये किलो मिलती थी, 13.70 रुपये किलो मिलती थी, उसको मुख्य मंत्रीजी ने 10 रुपये किलो कर दिया। यह कोई कम काम हुआ है?

सामाजिक क्षेत्र में आप देख लो। पेंशन- विधवा, वृद्ध, विकलांग और पालनहार, पहले 18 साल था, इनके शासन में ये नहीं कर सके, हमने 25 साल की मांग रखी, इस मुख्य मंत्री ने, इन अशोक जी गहलोत ने 25 साल कर दिया। और जब हमने यह कहा कि यह विसंगति राजस्थान में बहुत अधिक आ रही है, गांव की आम महिलाएं, बुजुर्ग, विधवा महिलाएं, आज सब यह कह रही हैं कि हमारे लड़के हमको कमाकर नहीं खिलाते हैं, इसलिए इस राइडर को आप हटाओ। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा, 1,500 करोड़

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

रुपया उन्होंने इस पेटे रखा है। यह कोई कम काम हुआ है? और टाइम बाउंड कर दिया है कि शीघ्र से शीघ्र उन सभी को लाभान्वित किया जाएगा जिनके लिए उन्होंने घोषणाएं की हैं। पालनहार के अन्तर्गत गरीब बच्चे के लिए पहले 675 रुपये था, उसको 1,000 रुपये कर दिया, यह कोई कम काम हुआ है?

अब मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां राजस्थान के अन्दर नाता प्रथा है जिसके अन्दर कोर्ट से बहुत मुश्किल से तलाक होता है, उन परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन नहीं मिल पाती। सामाजिक न्याय मंत्री महोदय विराजे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस चीज को देखें। गांवों के अन्दर यह समस्या बड़ी विकट है। किस तरह से कानूनी अमलीजामा पहनाकर हम उनको पेंशन दे सकें, वह रास्ता सरकार अवश्य निकाले। हमारे संवेदनशील मुख्य मंत्री हैं, हमको पूरी आशा है कि उन्होंने जिस तरह से हर चीज का रास्ता निकाला है, इसका भी निकालेंगे ताकि उनकी भी आशा को हम पूरा कर सकें। आज गांव के बुजुर्ग, विधवा इतने ज्यादा प्रसन्नचित्त हैं कि राजस्थान की सरकार ने हमको निहाल कर दिया। मुझे आ-आकर शनिवार-रविवार को खूब सारे लोग मिले हैं और उन्होंने इस योजना के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है।

इसके साथ-साथ अब आप पेयजल पर आ जाओ। 10,000 गांवों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। 6,000 तो बांधों से, 3,000 एससी, एसटी, अल्पसंख्यक ढाणियां, गांव और बस्तियां हैं, उनको लाभान्वित किया जाएगा। 20,000 हैण्डपम्प देने की बात हो रही है कि 20,000 हैण्डपम्प लगाये जाएंगे। पी एच ई डी मंत्री यहां पर हैं नहीं, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि 20,000 हैण्डपम्प जो दिये जा रहे हैं, क्योंकि भूजल स्तर बहुत नीचे जा रहा है, फिर इनको सिंगल फेस ट्यूबवैल मोटर बोर के अन्दर परिवर्तित किया जाए ताकि 500 मीटर तक बोर हो सके। 250 फीट से ज्यादा हैण्डपम्प का बोर होता नहीं है, इसलिए इसको बढ़ाकर सिंगल फेस ट्यूबवैल मोटर बोर के अन्दर परिवर्तित किया जाएगा तो इसका बहुत अधिक फायदा मिलेगा और गर्मियों में भी इसका फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, जिला मुख्यालय पर किसी ने नहीं सोचा कि आम आदमी आकर कहां ठहरेगा। 25-25 लाख रुपये के भवन बनाने का फैसला किया। जिला मुख्यालय पर आम आदमी आएगा, गर्मी में वह कहां बैठेगा?

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

सर्दी में कहां बैठेगा? अब 50 लाख रुपया हो गया, वही कह रहा हूं। वह कहां बैठेगा, कहां पानी पीएगा, कहां शौचालय के लिए जाएगा, कहां महिलाएं जाएंगी, कहां वृद्ध आदमी बैठेगा? यह मुख्य मंत्रीजी की सोच है कि आज उन्होंने हर जगह, हर जिला मुख्यालय पर बनाने का काम शुरु कर दिया।

आज आई टी आई के केन्द्र खोले गये हैं। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्दर भदेसर में खोले गये हैं, जो प्रकाश जी चौधरी, भाई शंकरसिंह जी और हमारे तीनों का उपखण्ड मुख्यालय है। वहां तीनों जगह आई टी आई के केन्द्र खोले गये ताकि लड़का शिक्षित हो और ट्रेंड होकर कहीं न कहीं वह या तो खुद का रोजगार कर ले या किसी उद्योग में उसे रोजगार मिल जाए। यह मुख्य मंत्रीजी की सोच है।

नौकरियां खूब दी हैं। डेढ़ लाख नौकरियां दे दीं। किसी एक विभाग में नहीं दीं। शिक्षा विभाग में लगभग 59,000 नौकरियां दी गई हैं। पुलिस विभाग में दी गई हैं, ऊर्जा क्षेत्र में दी गई हैं। (व्यवधान) हां, पूरा बजट तो बोलूंगा, बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पहले जब नहीं बोल रहा था तो कहा कि बजट पर बोलो और अब जब बजट पर बोल रहा हूं तो कह रहे हैं कि सारा बजट पर ही बोलोगे क्या। बजट पर बोलने के लिए ही खड़ा हुआ हूं, बजट पर बोलूंगा।

पटवारी, नरेगाकर्मी, एन आर एच एम हर विभाग के अन्दर नौकरियों के रास्ते उन्होंने खोल दिये। आज राजस्थान का युवा बेरोजगार आदमी बहुत ज्यादा खुश है कि नौकरियों के द्वार खुल गये हैं। चाहे नौकरियां किसी की भी लगें लेकिन सरकार ने नौकरियों का जितना भी बैकलाग था, सारा का सारा पूरा कर दिया। अभी मुख्य मंत्रीजी ने और घोषणा कर दी कि डेढ़ लाख और रोजगार मिलेंगे। रिफाइनरी आ जाएगी, डेढ़ लाख लोगों को और रोजगार मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर आई ए एस तक, सब पदोन्नति की आस छोड़ बैठे थे, उन सबको मुख्य मंत्रीजी ने पदोन्नति दी है। टाइमबाउंड प्रोग्राम करके उनको पदोन्नति दी है और आज भी वह व्यवस्था चल रही है। हर दिन अखबारों में पढ़ना पड़ता है कि आज डीपीसी हुई, आज पदोन्नतियां उनको मिलीं। मुख्य मंत्रीजी यह क्रम बराबर जारी रख रहे हैं इसलिए उनके भी असंतोष को कम किया गया।

अब मैं यह निवेदन कर रहा हूं, सभापति महोदय, सरकारें बनती ही

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

इसलिए हैं कि वे लोक कल्याणकारी हों, विकास हो और वापस जनता सरकार को आशीर्वाद भी दे। जनता हमको पूरा आशीर्वाद देगी। राजस्थान की साढ़े छह करोड...(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) बस मैं सम-अप ही कर रहा हूं। साढ़े छह करोड लोग, आम आदमी के लिए दवाइयां दीं, उनका जन समर्थन। वह पशु जो बोल नहीं सकता। शिशु-जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से 98 लाख महिलाएं और शिशु लाभान्वित हुए हैं। आज पशु भी बोल रहा है कि अशोक गहलोत जिंदाबाद। आज शिशु भी बोल रहा है, अशोक गहलोत जिंदाबाद। आज साढ़े छह करोड़ जनता भी बोल रही है, अशोक गहलोत जिंदाबाद। आज 10 लाख गरीब भी बोल रहे हैं, मकान जिनका बन रहा है, कि अशोक गहलोत जिंदाबाद। आज 38.63 लाख लोग भी बोल रहे हैं, जिनको एक रुपया किलो गेहूं मिलेगा, कि अशोक गहलोत जिंदाबाद। आज जिनके पेंशन के द्वार खोल दिये पच्चीस साल हटा कर, वे भी कह रहे हैं, कि अशोक गहलोत जिंदाबाद। आज 48 हजार कर्मचारी मन ही मन, सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते, कह रह हैं, अशोक गहलोत धन्यवाद, जिंदाबाद। आज वे लोग भी जिंदाबाद कर रहे हैं जिनकी नौकरियां लग रही हैं, सभापति महोदय। तो आज इनको दिवा स्वप्न देखना भूल जाना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार...(व्यवधान) दो तिहाई बहुमत से आ रही है इस मुख्य मंत्री के नेतृत्व के अन्दर। यही बात कहते हुए इस बजट की और आप लोग बिलकुल...(व्यवधान) बिलकुल, बिलकुल, बिलकुल सोचो ही मत। सोचो ही मत आप। राजस्थान की जनता राजस्थान के जाये को पसंद करेगी, बाहर के जाये को पसंद नहीं करेगी, कि वह राजस्थान की बागडोर संभाले। यह मैं ही नहीं कह रहा हूं, यह प्रतिपक्ष के नेता भी कह रहे हैं, इनके लोग भी कह रहे हैं...(व्यवधान) कि हमारा फैसला मध्य प्रदेश के लोग नहीं करेंगे। राजस्थान के भाग्य का फैसला राजस्थान की सूर्यनगरी में जो पैदा हुआ है...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): देश की जनता भी देश का फैसला करेगी, उसको भी विदेशी नहीं चाहिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ये कपड़े बदल-बदल कर आने वाले...(व्यवधान) अब कपड़े बदल-बदल करके राज नहीं आने वाला। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): राजस्थान में सबसे बड़ी जाति की बहू है। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): इटेलियन नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सारे काम समय पर होते जा रहे हैं, इनके लिए कोई बोलने का नहीं ....(व्यवधान) यह बात कह दो कि क्या व्यवस्था हमारे गांव के अन्दर...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हिन्दुस्तान में...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, वह तो राजस्थान की सबसे बड़ी जाति की बहू है। सबसे ज्यादा बड़ी जाति की बहू है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप समाप्त करें। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। (व्यवधान) अब आप कृपया समाप्त करें। (व्यवधान) अब समाप्त करें आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): वसुंधरा का तो मुख्य मंत्री बनना अब तय है। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): वह राजस्थान की बहू है। और अब महारानी है राजस्थान की, बहू है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): यह बहुत परेशान हो रहे हैं... (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): +++ (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप कृपया विराजें। समाप्त करें। अब आप कृपया समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापतिजी, मेरा निवेदन है...

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): सभापतिजी क्या करेंगे इसके अन्दर? (व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापतिजी, मेरा निवेदन है, माननीय सदस्य द्वारा जो व्यक्ति इस सदन का मैम्बर नहीं है उसको लेकर, उनके नाम से जो संबोधन किया गया, उनके नाम से जो बात की है, एक तो उसको व्यवस्था में से डिलीट किया जाए और मैं आपको...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): और दूसरा इटली से...(व्यवधान) हम इटली बोल रहे...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हम नाम नहीं ले रहे हैं, हम इटली से आयातित बहू बोल रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: देश में साठ करोड़ महिलाएं हैं, उनका सम्मान करो। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सबसे ज्यादा बड़ी आबादी है राजस्थान की, उसकी बहू है, बाहर का कैसे बता रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया अब आप विराजिये। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): वह इटली से आयातित है, यह तो...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांति बनाएं। (व्यवधान) माननीय सदस्य जाड़ावत साहब, अब आप कृपा करके समाप्त करें। माननीय सदस्य। (व्यवधान) अब आप समाप्त करें, आपका समाप्त हो गया। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): राजस्थान की बहू है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें। मैं अब नाम बोल रहा हूं दूसरा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): क्या कमी रखी इस सरकार ने, मैं यह पूछना चाहता हूं? (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद कर दो...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री रोहिताश शर्मा। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करो।

श्री सभापति: ठीक है, अब आप कृपया विराजिये। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): और इटली से आयातित लोगों का बहिष्कार करो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): अब, माननीय सभापति

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

महोदय, यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जो पेश किया बजट, इसमें दो बातें निवेदन करके समाप्त, बस दो बातें, पूरे सदन के लिए जरूरी हैं...

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सभापति महोदय, +++ के बारे में जो कहा है, आप कड़े अनुशासन का पालन कराओ, कड़े अनुशासन का। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): एक तो दसवीं से बारहवीं तक की स्कूलों का शिक्षा मंत्रीजी, सुन रहे हो? दसवीं से बारहवीं तक की स्कूलों की संख्या हमको बढ़ानी होगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आसन पैरों पर है और यह बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, फोर्टी फाइव मिनट हो गये आपको। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापतिजी, मेरे को दो मिनट। अब दो मिनट, लास्ट सम-अप कर रहा हूं मैं।

श्री सभापति: यह बार-बार कह रहा हूं मैं, फोर्टी फाइव मिनट हो गये आपको।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): बस दो मिनट, सीएचसी की थोड़ी संख्या और बढ़ाई जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): शर्म आनी चाहिए, आसन पैरों पर है और बोले जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सीएचसी की संख्या बढ़ाई जाए। सीनियर सैकण्डरी स्कूल की संख्या भी बढ़ाने की बहुत ज्यादा महती आवश्यकता है। (व्यवधान) यह मैं निवेदन करते हुए मुख्य मंत्रीजी के प्रति बहुत-बहुत आभार, पूरे राजस्थान की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए चित्तौड़ को मेडिकल कालेज की बहुत बड़ी सौगात देने के लिए, यूआईटी देने के लिए, एनडीपीएस कोर्ट देने के लिए, सड़कें देने के लिए और न जाने जो आम आदमी को फायदा देने के लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं और पूरे राजस्थान की जनता के प्रति हम....

श्री सभापति: समाप्त। समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री रोहिताश शर्मा। (व्यवधान) बैठिये, बैठिये।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट जो सरकार ने वर्ष 2013-14...

श्री सभापति: आपस में बातचीत नहीं करें, माननीय सदस्य। कृपया आपके साथी बोल रहे हैं उनको सुनें, मौका दें। आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे। बंद कर दिया। सुनो। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): वर्ष 2013-14 का जो वार्षिक बजट पेश किया, यह बजट 40139 करोड़ का प्रस्तावित है। माननीय सभापति महोदय, ऐसा लगता है जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के बारे में आम जनता में एक धारणा है, कि यह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। पिछले चार सालों से लगातार बजट पेश करते आ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सुशासन, सुशासन की बात करते-करते एक तरह से ऐसा हव्वा खड़ा कर रहे हैं सत्ता पक्ष के लोगों में, जैसे मुख्य मंत्रीजी खुश होकर इनको लाल बत्तियां दे देंगे, लेकिन धरातल पर इस बजट का जीरो असर है, जीरो असर। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रदेश का इन्फ्रास्ट्रक्चर जब तक धरातल पर नहीं आएगा, लोगों को नजर नहीं आएगा, विकास कैसे करोगे, मेरी समझ में नहीं बैठ रहा। मजदूर सड़क पर है, हमारी महिलाएं इज्जत बचाने के लिए सड़क पर है, आज वकील सड़क पर हैं। आज किसान न तो बिजली मिल रही है, न पानी मिल रहा, सड़क पर जगह-जगह चक्का जाम हो रहा है बिजली के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए। (व्यवधान) यह तुमको ज्ञान आ जाएगा नवम्बर में, मैं आपसे कहना चाहता हूं। (व्यवधान) अभी, आ जाने दो, आ जाएगा, हम भी देख लेंगे। माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है कि हमने बिजली

(15.57 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

के क्षेत्र में चार सालों में 4628 मेगावाट बिजली पैदा की है। यह सफेद झूठ का पुलिंदा है। एक यूनिट भी इस सरकार ने चार सालों में पैदा नहीं की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कोटा थर्मल की सातवीं इकाई, छबड़ा की दूसरी इकाई, सूरतगढ़ की छठी इकाई और गिराल की दो इकाई, 1070 मेगावाट बिजली पैदा हुई है इनसे। दो प्राइवेट सैक्टर है। विंड पावर में 2351 मेगावाट और एक प्राइवेट फर्म है राजवेस्ट, 540 मेगावाट। यह प्राइवेट सैक्टर हैं। इसमें

(श्री रोहिताश कुमार)

आपका क्या लगा? ये जो ऊपर तीनों-चारों मैंने बताईं यूनिट, ये बीजेपी के राज में शुरू हो गई थीं। बीजेपी के राज में शुरू हो गई थीं, आपने कहीं इसमें कुछ भी नहीं किया। आपको तो मुफ्त में, हमारे द्वारा पैदा की गई, हमारे द्वारा योजना बनाई गई, प्रोजैक्ट लगाया गया, उसका लाभ मिला। दूसरे में निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अपने टेन्योर में छबड़ा यूनिट पांच-छह, सूरतगढ़ यूनिट सात-आठ, धौलपुर गैस, सूरतगढ़ यूनिट नौ-दस, काली सिंध यूनिट तीन-चार, बांसवाड़ा यूनिट एक-दो, रामगढ़ चार, कोटा गैस, छबड़ा गैस, ये आपने कागजों में चढ़ा रखी हैं, कागजों में। कागजों से आगे ये कहीं नहीं बढ़ पाई।

(16.00 बजे)

आप कह रहे हैं कि हमने बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। बिजली को जो टोटल बजट है आपने लम्बी डींग हांकी कि चूंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर बिजली से डवलप होता है, पचास परसेंट से भी ज्यादा हिस्सा बिजली में खर्च किया है। माननीय सभापति महोदय, इनकी जो मानिटरिंग रही है वह जीरो मानिटरिंग रही है। इनके कुप्रबंधन के कारण आज बिजली बोर्ड 60 हजार करोड़ से भी ज्यादा घाटे में चल रहा है। इसका कौन जिम्मेवार है? आपने किस बात की वाहवाही लूटी? इतना पैसा किस बात के लिए खर्च किया? दूसरा, सोलर ऊर्जा नीति में 2013 तक 200 मेगावाट का लक्ष्य था। कितनी पैदा की? शून्य। फिर किस बात की +++ उसमें है।

श्री ओम जोशी (फलौदी): जहां बिजली पैदा हो रही है वहां से मैं आता हूं, वहां 150 मेगावाट तो बिजली चालू हो गई, लोगों को सप्लाई हो रही है। आप कहां +++ बोल रहे हो?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आप बैठिये, अगर इसमें +++ हो तो उसका बाद में निर्णय करेंगे।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अभी तो शिलान्यास किया है, पैदा कहां हो रही है? पैदा नहीं हो रही है।

श्री ओम जोशी (फलौदी): पैदा हो रही है, आप आ जाना और उधर रह जाना।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो। आप तो विराजो, आप क्यों बोल रहे हो?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): कांग्रेस के घोषणा पत्र में आपने कहा, आठ घंटा बिजली हम किसान को देंगे। जैसे यह नई बात चलाई है वोट नवम्बर में लेने के लिए, ऐसे पहले भी आपने यह काम किया है, आप कोई नये नहीं हो- आठ घंटा बिजली देंगे, घरेलू बिजली चौबीस घंटे देंगे। और तो और हम अपने पड़ोसी राज्यों को जो सरप्लस हो गयी, हम तो ज्यादा बिजली करेंगे और वो बेचेंगे। खाक में गया। साठ हजार करोड़ घाटे में, बिजली बोर्ड को तनख्वाह देने का रुपया नहीं है, हम सब के लिए यह डूब कर मरने की बात है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 75 हजार नये कनेक्शन आपने किसान को देने का वादा किया है अपने बजट में, यह भी +++ का पुलिंदा। बिजली कम्पनियों ने आपके विद्युत नियामक बोर्ड को मात्र 40 हजार कनेक्शन की बात की है। यह आपने बढ़ा दिया तो 25 हजार कहां से देंगे? यह +++ क्यों बोल रहे हो? इसका जवाब दो कि आप क्यों +++ बोल रहे हैं?

श्री सभापति: यह +++ असंसदीय शब्द है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीजेपी के राज में हमने अनुसूचित जाति को प्रायोरिटी पर कनेक्शन देने की कही थी। आपका राज आया, आप बड़े दलित वर्ग के हिमायती हो, लेकिन आपने उसको बंद कर दिया। अब जब वोट आ गया, चुनाव का टाइम नजदीक आया तो आपने फिर उसको वापस खोल दिया। यह शर्म की बात है। पैरा नम्बर-34 में 22 जिलों में 100 से 300 तक की आबादी वाली 15 हजार 149 ढाणियों के विद्युतीकरण की योजना सेंट्रल गवर्नमेंट को मंजूरी के लिए हमारे टाइम पर हमने भेजी हुई थी, आपने उसी को कह दिया कि हम भी कर रहे हैं। यह हमने भेजा हुआ था, आपने उसकी भी जिम्मेदारी ले ली।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जब एक बुद्धिमान विधायक बोल रहा हो तो सब चुप रहो।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): 100 से कम आबादी वाली ढाणियों के विद्युतीकरण का हमने वादा किया था, हमने वह योजना चलाई थी, आपने आते ही उसको बंद कर दिया। जब चुनाव नजदीक आ गये तो फिर चालू कर दी आपने। ये क्या आपकी नीतियां हैं, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं?

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, कोई भी राज्य, उसका जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं होगा तब तक विकास नहीं कर सकता। मैं एक ऐसे सैक्टर को टच करने की कोशिश कर रहा हूं जो आमजन के लिए बहुत जरूरी

(श्री रोहिताश कुमार)

है वह ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कि आपने पांच हजार करोड़ रुपया यह जो जयपुर में मैट्रो चलाई है, पांच हजार करोड़ रुपये राजस्थान के फण्ड से लगाये मात्र 12 किलोमीटर के लिए। सिर्फ 12 किलोमीटर के लिए आपने पांच हजार करोड़ रुपये लगाये और यह कहकर लगाये कि हम जयपुर को इन्टरनेशनल सिटी बनाएंगे। आप जरा सोचो, राजस्थान सारी दुनिया में हैरिटेज के नाम से मशहूर है, जयपुर को हैरिटेज सिटी नाम से देखने के लिए आते हैं। आपने उस हैरिटेज सिटी का डब्बा गोल करके रख दिया, यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इस प्रदेश की 80 परसेंट जनता गांवों में रहती है, आपने उनको किसके भरोसे छोड़ा हुआ है? आपके पास मात्र 4500 रोडवेज़ बसें हैं जो मेरे टाइम में भी उतनी ही थीं और आज भी वही हैं। एक भी नहीं बढ़ी है। सात करोड़ के लगभग राजस्थान की जनता में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग आवागमन का साधन ढूंढते हैं। दस लाख पैसेंजर की आवागमन की राजस्थान रोडवेज की क्षमता है, आप क्या कर रहे हो? 12 किलोमीटर के लिए तो पांच हजार करोड़ और आपने राजस्थान की गरीब जनता को 4500 बसों के भरोसे छोड़ दिया। अगर प्राइवेट सैक्टर में भी जाना चाहे तो 28 हजार बसें हैं, तो भी लगा लीजिए, तीस लाख पैसेंजर हैं, सत्तर लाख पैसेंजर का क्या होगा, आपने कभी सपने में सोचा था? ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक नहीं होगा तो इण्डस्ट्री, आपका सारा काम सफर करेगा।

दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, हैरिटेज के नाम पर जो टूरिस्ट आता था जयपुर में, वह टूरिस्ट ब्लाक हो गया। वह आज सूर्यनगरी में जा रहा है। यह क्या तरीका हुआ? आपने अट्रेक्ट कर लिया जोधपुर, टूरिस्ट जाएगा जोधपुर। क्योंकि यहां तो उतरते हुए धुआं, रिक्शा, तांगा, बसें, मिनी बसें, साइकिलें मिक्स ट्रैफिक है। There is no system at all here. पिंक सिटी का जो कंसैप्ट था, आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बना दीं, यह बना दिया, वह बना दिया। इससे कोई इन्टरनेशनल सिटी बन सकती है क्या? इन्टरनेशनल सिटी कभी आपने देखी होगी, कागजों में पढ़ी होगी और आप तो बहुत बड़े अनुभवी लोग हो, कांग्रेस से आये हुए लोग हो, आपने तो विदेश यात्राएं भी बहुत की हैं, इन्टरनेशनल सिटी में क्या होता है? वह आप यहां डवलप करेंगे क्या? यहां जो हमारी संस्कृति है, जिस संस्कृति में राजस्थान पल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसमें गांधीवादी मुख्य मंत्री ने इन्टरनेशनल सिटी का नाम तो ले लिया परन्तु इन्टरनेशनल सिटी बना कैसे पाओगे?

(श्री रोहिताश कुमार)

अभी हमारे जयपुर के सिविल लाइंस से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आठ बजे बाद, यह आपकी पार्टी के सत्तारूढ़ माननीय सदस्य ने कहा है, मैंने नहीं कहा, कि आठ बजे बाद लोग-बाग़ ताका-झांकी करते हैं। ताका-झांकी नहीं करते हैं, इसका असली स्वरूप यह है, कोड वर्ड बना हुआ है। +++, आठ बजे बाद लोग टेलीफोन से करते हैं। आठ बजे बाद फोन आएगा, **+++** यह कोड बना हुआ है, घर पर डिलीवरी हो जाती है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आपको कैसे पता चला यह?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप कांग्रेस से आये हुए पहले ही कह चुके हैं और जब आप इनके घर आये थे तो आपके लिए ही तो मंगाई थी।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): यह आपको कैसे पता? (व्यवधान) आपके पास में आये थे?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): चलो, एक ही बात है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, हमारे जिले में...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट विराजें आप। मेरा निवेदन है आपसे कि आप मेहरबानी करके खूब अच्छा बोलें, सदन के आप पुराने सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन सदन के नेता का शब्द आप उसके साथ जो जोड़ रहे हैं, वो उचित नहीं है, उसको मैं एक्पंज करता हूं।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सदन के नेता का नाम नहीं बोला है, कोड बोला है। ठीक है, ठीक है, एग्रीड। इसमें किसी को मैंने ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, जो कोड जनता में चल रहा है उसके लिए कहा है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, हमारे अलवर में एक नया पैसा भी, परिसम्पत्तियां डवलप हों, कोई काम हो, उसके लिए इतनी दुभांत रखी गई अलवर में कि सारा का सारा पैसा जो आपकी पार्टी के प्रभावशाली लोग हैं वहां, सब ले गये और अलवर को कुछ नहीं दिया। अब इसमें कहा है, हमारे मत्स्य विश्वविद्यालय की जो बात थी, जो आदरणीय वसुन्धरा जी ने खोला था, आपने उसको तीन साल तो लटकाये रखा और चौथे साल आपने कहा कि हम मत्स्य विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा करते हैं। माननीय सभापति महोदय, बड़े शर्म की बात है। और उसके लिए एक नया

(श्री रोहिताश कुमार)

पैसा नहीं दिया। घोषणा करते हैं, और फिर उसके लिए जगह कहां ढूंढी है? एक गढ़ीकर जगह है। कथनी और करनी में इतना अन्तर है कि मुख्य मंत्रीजी को पता था इस बात का कि गढ़ीकर में ये जमीन देख लेंगे तो मत्स्य विश्वविद्यालय कभी खुल ही नहीं सकता क्योंकि वह तो फोरेस्ट में है। वह रिजर्व क्षेत्र फोरेस्ट में है, ये मेरे पास डाकूमेंट हैं गढ़ीकर के। इतना धोखा किया अलवर की जनता के साथ कि गढ़ीकर जो फोरेस्ट में रिजर्व है जगह, उसमें जमीन एक्वायर करने का एक सपना दिखाया। जो आखिरी बजट है, दो करोड़ समथिंग का और इंतजाम किया है, अब दो करोड़ में तो डंडा भी नहीं, डंडा कहां खींचेंगे? जब रिजर्व फोरेस्ट में आप कोई जमीन एक्वायर करोगे तो कौन बनने देगा? अलवर के साथ इससे बड़े असत्य, फरेब की बात कोई हो नहीं सकती और अलवर जिले की जनता माफ नहीं कर सकती।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर के साथ ठगी ही ठगी हुई है। दिल्ली से भी बड़ी वाहवाही लूटी गई कि ईएसआई का एक हजार करोड़ की लागत से होगा। वो चार वर्ष तो हो गये ईएसआई करते-करते। मुख्य मंत्रीजी पत्थर तो लगा आये, वो पत्थर भी वैसे के वैसे पड़ा है। और अब आगे क्या बात करूं। उस जगह पर क्या-क्या हो रहा है, वो वर्णन तो मैं विधान सभा में कर नहीं सकता। हमारे साथ अन्याय पर अन्याय हुआ है। हमारे साथ कोई कम अन्याय नहीं हुआ है। सब जगह जो सड़कों की तारीफ हुई, मैं मंत्री महोदय की तो तारीफ करता हूं क्योंकि जो भी कमप्लेंट होती है तो तुरन्त भरत सिंहजी पहुंचने की कोशिश करते हैं। परन्तु मुख्य मंत्रीजी के हाथ में क्या है, हम सब जानते हैं। मंत्रीजी के हाथ में कितना है? सब काम सेन्ट्रलाइज किया हुआ है, मुख्य मंत्रीजी के हाथ में है। सारी सड़कें जो अलवर में दी हैं वो बी.ओ.टी. बेस पर दी हैं, डंडा लगेगा। डंडा वो झुका कर गुंडागर्दी का अड्डा बनेगा। गरीब जनता से पैसा वसूल होगा। अभी एक घोषणा की कि किशनगढ़, बानसूर, कोटपूतली ये गरीब क्षेत्र हैं किसानों का क्षेत्र है, अब इस पर बी.ओ.टी. बेस सड़क बनेगी। अब बी.ओ.टी. बेस सड़क बनेगी तो क्या होगा? बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य भी यहां बैठे हैं उनको भी पता है बहरोड़ का क्या होगा? अलवर से बहरोड़- अलवर-नारनौल बी.ओ.टी. बेस, और जितनी भी सड़कें हैं बी.ओ.टी. बेस, तो राजस्थान में अलवर का नामोनिशान नहीं है क्या? सबसे ज्यादा अगर कोई

(श्री रोहिताश कुमार)

रेवेन्यू देता है तो अलवर जिला देता है और इसके साथ भेदभाव। एनसीआर तो नाम ही नाम हमने सुना है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अलवर के नुमाइंदे दिल्ली की सरकार में भी बैठे हैं पर एनसीआर का तो अभी तक प्लान ही नहीं बना पाये। अलवर को एक पैसे का लाभ नहीं हुआ है। एनसीआर का लाभ एक नये पैसे नहीं हुआ है और हमारी जमीन सबसे ज्यादा गई है। डार्क जोन बना दिया गया, हमारे किसानों का शोषण वैसे हो गया। मतलब अलवर जिले को कोई सौगात नहीं मिली, तो इसकी मैं घोर निन्दा करता हूं।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, अभी आप भी अपने दिल की पीड़ा को बता रहे थे। आप तो राज़ी हो रहे थे क्योंकि आपके यहां तो आपके हिसाब से खोल दी। हमारे यहां एक उप तहसील बनी हुई थी नारायणपुर में मेरे विधान सभा क्षेत्र में, 2003 में गहलोत साहब जब मुख्य मंत्री थे, इन्होंने उस उप तहसील को खोला। उन्होंने उसको बंद भी कर दिया। और अब जब चुनाव के दिन नजदीक आ गये तो वाहवाही लेने के लिए फिर उप तहसील घोषित कर दिया। जरा सोचो, 10 साल हो गये, वैसे तो नारायणपुर डाइरेक्ट तहसील बनानी चाहिए, पर आपकी कलम से खोली हुई तहसील की 10 वर्ष की सीनियरिटी हो गई। आप में से बहुत से कह रहे थे कि हमारे मुख्य मंत्री तो डैमोक्रेट हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वो डैमोक्रेट हैं और प्रतिपक्ष की वाजिब बात को मानते हैं जैसा कि सुखाड़ियाजी करते थे, जैसा हरिदेवजी जोशी करते थे, जैसे भैरोंसिंहजी शेखावत करते थे, वसुन्धरा राजे सिन्धिया करती थीं, अगर आपके मुख्य मंत्री ने नारायणपुर को तहसील बनाया तो हम भी आपकी बात को समझेंगे कि आप भी बोलते तो कभी-कभी सच्चा ही हो, कभी-कभी। हालांकि हमको उम्मीद कम है पर आप कहते हो, हमारे साथी हो, तो हम आपकी बात मानेंगे। तो मैं चाहता हूं कि नारायणपुर को तहसील का दर्जा दिया जाए।

दूसरा, माननीय सभापति जी, अब आप चेयर पर विराजमान हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं, कि हमारे सत्ता पक्ष के बहुत सारे माननीय सदस्यों ने, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा हूं, किसी को छेड़खानी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, अपने भाषण में मुख्य मंत्रीजी की जितनी तारीफ की, वो तो करनी

(श्री रोहिताश कुमार)

चाहिए क्योंकि नवम्बर आ गया टिकट का सवाल है, ये तो करोगे ही करोगे परन्तु धरातल पर, बिजली आपको मारेगी। स्कूल आप इतने खोलने की बात कर रहे हो, स्कूलों में टीचर नहीं हैं उनके ताले बंद हैं। अस्पतालों में डाक्टर और जो मुफ्त दवाइयों की बात कर रहे हो, 'जिसके लागे वो ही जाणे औरां न के बेरा', एक हरियाणा की कहावत है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में साठ से ज्यादा मौतें हुईं आपकी मुफ्त की दवाइयों के चक्कर में। मरीज वहां अटक गये और बहुत गर्क हो गया। सुन लो, स्वास्थ्य मंत्री भी गये थे और आपके स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी गये थे, हमारे यहां डबल काम हो गया। वहां से मरीज जयपुर आ गये और दो-तीन लाख रुपये साथ लेकर आये, और भगवान की कृपा हो तो मरीज वापस चला जाए, नहीं तो मरीज रामपुर चला जाता है और तीन लाख रुपये भी चले जाते हैं ऐसा बुरा हाल कर दिया। चीप पापुलरिटी की बात मत करो, आप अच्छे मुख्य मंत्री हो, प्रशासक हो। चाइना की बात को सोचो आप, चाइना ने क्या किया। चाइना ने अपनी गरीब जनता को पंगु बनाने की कोशिश नहीं की। रोज दो रुपये का चावल, एक रुपये का चावल, पांच रुपये का आटा, क्या इन बातों से वोट मिलता है? चाइना, कोरिया की तरह देखो।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): आप इसके खिलाफ हो क्या? आप एक रुपये किलो चावल, एक रुपये गेहूं के खिलाफ हो क्या?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सवाल खिलाफ का नहीं है। बात खिलाफ की नहीं है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं आप एक रुपये और दस रुपये के विरोध में हो तो हां भर लो न आप तो।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आप विराजिये। एक रुपये और दस रुपये की बात नहीं है, आप हमको कमाने के लिए तैयार करो। आपने क्या योजना बनाई कि वह आदमी स्वाभिमानी बने और स्वाभिमान से कह सके कि मे बीपीएल नहीं हूं? चाइना ने क्या किया? हमसे भी ज्यादा जनसंख्या थी चाइना की, हमसे भी ज्यादा गरीबी थी, लेकिन आज चाइना वर्ल्ड के मैप पर नंबर-1 हो गया। क्या कर रहे हो आप, यह किस बात का बीपीएल बांट रहे हो? कांग्रेस पार्टी ने, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं साबित करके कह रहा हूं, कि राजस्थान की जनता का बंटाधार कर दिया। सभापति महोदय, यह कहते

(श्री रोहिताश कुमार)

हुए मैं इस बजट का विरोध करता हूं कि यह जन विरोधी है किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और नवयुवकों के भी खिलाफ है, देश विरोधी है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): डाक्टर साहब, आपका आधे से ज्यादा समय तो कांग्रेस में गुजरा, इसका मतलब आप भी बंटाढार के लिए जिम्मेदार हो?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): एक रुपए किलो गेहूं की बात कही, आप किसानों के विरोध में हो क्या ?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): एक लाइन और बोलूंगा, यह जो रिफाइनरी की बात आपने की है, रिफाइनरी की आप बड़ी वाहवाही लूट रहे हैं, आपसे एक बात पूछूं, घर में छोरा-छोरी हो जाता है तो ब्याह अपन को ही करना होता है या और को करना होता है? यहां कच्चा तेल निकल आया तो रिफाइनरी हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? इसमें किस बात की वाहवाही? खेतड़ी में तांबा निकला तो शोधन का कारखाना बना कि नहीं बना? तो इसमें कौनसी नई बात हो गई? यह तो बनानी ही पड़ती। फिर किस शर्त पर बनाई है? आपने इसको 53767 करोड़ रुपए दिये हैं। भले लोगों, इसमें तीन-चार कम्पनियां पार्टनर हैं और हमारा हिस्सा तो 26 परसेंट है। 26 परसेंट के मुकाबले में आपने उन कम्पनियों से पैसा क्यों नहीं लिया? आपकी गलत नीति है, असत्य वाहवाही लूटने के लिए करते हो। जैसे जयपुर का मैट्रो है यह प्राइवेट सैक्टर में देना चाहिए था, पीपीपी पर करना चाहिए था। इसमें भी आप ओएनजीसी से पैसा लेते, दूसरी तेल कम्पनियों से पैसा लेते। आपने अपनी जेब से पैसा भर दिया। हमारे पास सरप्लस रुपया है क्या? यह तो धन्य हो वसुंधराजी को कि उन्होंने एक्स्पर्ट बुलाकर इस रिफाइनरी की खोज की। इसको चालू करने की स्टेज में आ गये जब आप असत्य वाहवाही लूट रहे हो। तीन हजार करोड़ रुपया आपको इसका मिलने लग गया, तब बातें आती हैं। (व्यवधान) साढ़े पांच अभी नहीं हुआ है, साढ़े पांच तो हम लेंगे नवम्बर में। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, डाक्टर साहब का

(डा. रघु शर्मा)

उत्साही भाषण सुनकर मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सात बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय सात बजे तक बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय सात बजे तक के लिए बढ़ाया गया। श्री मेवाराम जैन।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, बजट 2013-14 हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने जो प्रस्तुत किया है, यह बजट गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए इस बजट में प्रावधान नहीं किया गया हो। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं मुख्य मंत्रीजी को विशेष तौर पर इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बाड़मेर में रिफाइनरी की घोषणा 5 तारीख को की है। अभी मेरे साथी रिफाइनरी के बारे में खूब चर्चा कर रहे थे कि पहले वसुंधराजी के समय में लग रही थी। क्या-क्या बातें कर रहे थे- कोई कह रहा था कि इसमें नुकसान है, नफा नहीं है, सरकार क्यों कर रही है। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि बाड़मेर में जो तेल की खोज हुई हमारी सरकार जो पहले अशोकजी के नेतृत्व में थी उस समय तेल निकला था, आपके आने के बाद उन तेल कुओं का केवल नामकरण हुआ, आपने रिफाइनरी के लिए कोई प्रयास नहीं किये। पूरे पांच साल निकाल दिये परन्तु उस रिफाइनरी के लिए आपने कुछ काम नहीं किया। मैं हमारी नेता सोनियाजी, राहुलजी, प्रधानमंत्रीजी और हमारे नेता अशोकजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बाड़मेर और राजस्थान की जनता के मन में रिफाइनरी के प्रति जो भाव था कि रिफाइनरी बाड़मेर में खुले, उन्होंने यह कर दिखाया।

बजट के बारे में खूब चर्चा हुई। इस बजट में क्या-क्या प्रावधान किये, उसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको इसकी आलोचना ही करनी है, प्रशंसा तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि यह आपका धर्म है। इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट में जो प्रावधान किये गये हैं, एक-एक चीज

(श्री मेवाराम जैन)

पर आप जाओगे तो आपको यह कहना ही पड़ेगा। इस बजट में जयपुर में मैट्रो, बाड़मेर में रिफाइनरी, डूंगरपुर-बांसवाड़ा-रतलाम के लिए रेलवे लाइन, जोधपुर में एम्स, भीलवाडा में रेलवे फैक्ट्री, कहां-कहां आईआईएम, आईआईटी, जिस तरह का विकास का जाल राजस्थान में फैलाया है, आने वाली सदियां इसको याद रखेंगी कि राजस्थान में अशोकजी के नेतृत्व में किस तरह का विकास हुआ है। आप बातें कुछ भी करो। आप तो इस बात को कह ही नहीं सकते कि यह अच्छा काम हुआ। अभी मैट्रो के लिए बात कर रहे थे, जिस समय अशोकजी ने इसकी घोषणा की उस समय आपको सपना ही लग रहा था कि ये बातें ही कर रहे हैं, हकीकत में काम नहीं होगा। वास्तव में काम करके दिखाया और हमारे समय में ही इस मैट्रो का उद्घाटन भी होगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में पीने के पानी के लिए ऐसी परियोजनाएं शुरू की हैं जो कोई सोच नहीं सकता। पीने के पानी के लिए जो करोडों रुपए स्वीकृत किये हैं इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी आप बात कर रहे थे कि बजट में घोषणाएं खूब होती हैं, मैं कहना चाहूंगा कि घोषणाएं आपके समय में हुईं। बाडमेर मोहनगढ़ लिफ्ट कैनाल का शिलान्यास अशोकजी की पहली सरकार के समय किया गया। हमारी सरकार चली गई, पांच साल बीत गये आपकी सरकार ने जाते समय 6 महीने पहले सिर्फ शिलान्यास ही किया और एक पैसा खर्च नहीं किया। अगर आप कुछ करते तो लोगों को वहां पानी मिल जाता। आप सिर्फ असत्य वाहवाही लेना चाहते हैं। काम पर तो आपका विश्वास ही नहीं था, करना तो दूर की बात रही। आज बाड़मेर में पीने के पानी के लिए पांच बड़ी परियोजनाएं सैंक्शन की गईं। करीबन 40 हजार करोड़ रुपए पीने के पानी के लिए बाड़मेर को मिले। मोहनगढ़-बाड़मेर लिफ्ट कैनाल, पोकरण-फलसूंड लिफ्ट कैनाल, नर्मदा में पीने के पानी की योजना, नर्मदा से गडरा रोड तक पीने के पानी के लिए इसी बजट में प्रावधान करना, ये जितनी योजनाएं पानी के लिए की हैं, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

इनको यह भी तकलीफ है कि गरीब को एक रुपए किलो गेहूं क्यों मिले। किसी ने सोचा था कि रुपए किलो में गेहूं मिलेगा? बीपीएल जो किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके लिए एक रुपए किलो गेहूं। आज एपीएल के लिए पांच रुपये किलो में आटा, यह कोई मामूली बात नहीं है। यही तकलीफ तो आपको हो रही है कि यह क्यों हो रहा है। इसके साथ-साथ दस

(श्री मेवाराम जैन)

रुपये किलो शक्कर की बात करें। दवाइयों के लिए तो अभी खूब चर्चा हो रही थी। दीदी कह रह थीं, अन्य लोग भी कह रहे थे कि इस दवाई योजना में लोग मर रहे हैं। आप कभी अस्पतालों में जाते ही नहीं हैं, गांवों में आप जाते ही नहीं हैं, आपको पता ही नहीं है कि हकीकत क्या है। आप गांवों में अस्पतालों में जाएं और मरीज को पूछें कि आपको इसमें फायदा हो रहा है या नहीं। आप बाजार से पैसा लाकर इलाज करा रहे हो या सरकार मुफ्त में कर रही है, यह पता करो, तब हकीकत आपको पता चलेगी। और आने वाले इलेक्शन आपको बता देंगे। ये जो हम बातें कर रहे हैं वह कहां गई, यह आपको समय बताएगा। अभी ठीक कह रहे थे कि दो-दो लाख रुपये में इलाज कराने के लिए अस्पतालों में लाते हैं, पर ये दो-दो लाख आपके समय में लाते थे, अब मुख्य मंत्रीजी एक पैसा खर्च नहीं करने दे रहे हैं, सरकार अपनी ओर से सारा खर्च कर रही है और इससे सबको राहत मिली है। आप देख रहे हैं, सब बीपीएल के लिए तो मुफ्त दवाई थी ही इसके साथ-साथ एपीएल, अन्य लोग जिनकी एक लाख वार्षिक आय हो, उनके लिए भी एक लाख तक का इलाज कराने की सरकार ने इस बजट में घोषणा की है। इसके साथ-साथ सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर, डाक्टरों की भर्ती, एएनएम भर्ती, यह कोई कम चीज है क्या? इसका रिजल्ट आप चुनाव में देखेंगे कि यह क्या हुआ। आप देखते जाओ। मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में यह घोषणा की, 60 साल का जो राइडर था पेंशन का, उसका लाभ जनता को अब मिलना शुरू होगा तब आपको पता पड़ेगा कि विधवा, विकलांग, वृद्ध कितनी दुआएं देंगे। उनका कोई करने वाला नहीं था, उनके परिवार वाले उनको राम भरोसे छोड़ रहे थे, उनको लाभ होगा। आने वाला समय आपको बताएगा कि लोगों को कितनी राहत मिल रही है, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री गरीब के लिए कितनी-कितनी योजनाएं ला रहे हैं। ये बीपीएल आवास की बात कर रहे हैं, पहले कह रहे थे 50 हजार ही है, अब 70 हजार कर दिये। अब 10 लाख मकान बनेंगे। जिसके घर में झोंपड़ी नहीं थी उसके लिए अगर पक्का मकान बना है तो उसकी आत्मा कितनी राज़ी होगी, वे हमारे मुख्य मंत्रीजी को कितनी दुआएं देंगे, यह समय आएगा जब आपको बताएंगे। इसमें लोग कितने राज़ी हैं और आपके मन में किस बात की तकलीफ है, यह भी आपको पता लग जाएगा। आज प्रशासन शहरों के अन्दर और गांवों के अन्दर जो काम हुए, जो शिविर लग रहे हैं, वर्षों से लोग पट्टों के लिए तरस रहे थे उनको घर बैठे कैम्प में पट्टे मिल रहे हैं। 90 बी का क्या

(श्री मेवाराम जैन)

खेल हुआ था? 90 बी के लिए आपके कार्यकाल में क्या-क्या नहीं हुआ? राजस्थान के लोग जानते हैं कि आपके पांच साल में क्या हुआ। अब सरलीकरण कर आम जनता को किस तरह से उसका लाभ मिले, यह हमारी सरकार ने किया, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किया, यह आपके सामने है। आज प्रशासन गांवों की ओर कैम्प में कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा। हजारों पेंशन, हजारों लिटिगेशन पैंडिग, राजस्व रिकार्ड अधूरा जो कई सालों से पड़ा था, उनका काम हुआ। अगर काम नहीं होता तो उस शिविर में हजारों की भीड़ क्यों होती? कम से कम ढाई हजार, तीन हजार लोग वहां होते। आसानी के साथ वहां काम हो रहा है। जनता धन्यवाद देना चाह रही है। आज राजीव गांधी विद्युतीकरण, यह योजना अपने आप में कम है क्या? ऐसी ग्राम पंचायतें, मैं बताना चाहूंगा, बेरीवाला तला हो चाहे मूण्डवा की ढाणी हो, एक विद्युत कनेक्शन नहीं था। इस चार साल के अन्दर उन पंचायतों में दो-दो हजार कनेक्शन फ्री हुए हैं बीपीएल योजना के तहत, मुख्य मंत्री विद्युतीकरण, राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत। आज वह जनता याद नहीं करेगी? अकेले बाड़मेर में 65 हजार कनेक्शन और मेरी विधान सभा में 12 हजार परिवारों को राजीव गांधी विद्युतीकरण के मुफ्त कनेक्शन किये गये, क्या जनता वह भूलेगी?

शिक्षा में हकीकत बोल रहे हैं, आप जाकर वहां देख सकते हैं। शिक्षा के बारे में बात करूंगा कि कितनी स्कूलें खुलीं, कितने अध्यापकों की भर्ती हुई। मिडिल, प्राइमरी, सीनियर सैकण्डरी, सैकण्डरी स्कूलें खुलेंगी। आप कह रहे हैं, अध्यापक नहीं हैं। अध्यापक आपके समय में नहीं थे। आपने स्कूलें खोल दीं, एक अध्यापक लगाया नहीं। हमने तो खूब अध्यापक लगाये और आने वाले समय में खूब लगाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि स्कूल खोलने से आपको क्या लाभ है और हानि है। यह अन्दर आपकी आत्मा जान रही है कि यह हो क्या रहा है। आपको दर्द इस बात का हो रहा है। यह नहीं हो रहा है कि क्यों हो रहा है, यह होने में ही तो आपका इलाज होगा।

तहसीलों की बात करें, कितनी तहसीलें खुलीं, कितनी उप तहसीलें खुलीं, कितने हैडक्वार्टर खुले, कितने पुलिस थाने, सी.ओ. सर्किल, कितनी चौकियां। यह जनता के सामने कार्य हो रहा है। जनता को कितनी परेशानी हो रही थी, वह परेशानी हमारी सरकार ने दूर की। हमारे मंत्रीजी ने, हमारे सीएम साहब ने देखा कि वास्तव में लोगों को राहत मिल सके, लोगों को आगे ज्यादा दूर जाना नहीं पड़े इसके लिए यह सरलीकरण किया गया।

(श्री मेवाराम जैन)

सड़कों की बात करें, आपके समय में भी खूब बात हुई कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना है प्रधानमंत्री सड़क योजना। बिलकुल थी, आपने क्या किया? आपने 250 तक के रेवेन्यू विलेज लिये, जबकि उसमें था कि 250 तक के हैबीटेशन को सड़कों से जोड़ेंगे। वह आपने छोड़ा उसकी वजह से हजारों गांव हैबिटेशन में रह गये। हमारी सरकार ने आते ही उन गांवों को जोड़ने के लिए प्रयास किये और अब जुड़ भी रहे हैं। सारे 250 से ऊपर की आबादी के। इसके साथ साथ (व्यवधान) मेरी विधान सभा में कम से कम...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह क्या सवाल जवाब कर रहे हैं? (व्यवधान) आपको यह पता ही नहीं है कि हाउस में क्या है। यह टाइम लेकर बोल रहे हैं और पीछे से बैठे-बैठे बोल रहे हो आप ।

श्री सभापति: श्री वासुदेवजी देवनानी। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आपको पता नहीं है, आपके हो नहीं रहा है। हमारे यहां जाकर देखिये, कितना हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इधर देखकर।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आपको तकलीफ हो रही है इस बात की। नहीं होने वाले के तकलीफ ही हो कि आप करा नहीं पा रहे हो, हमारे यहां तो किसी काम की कोई कमी नहीं है।

सड़कों की आप बात कर रहे हो, जाकर सड़कें देख लो। नेशनल हाइवे सड़कें बनी हैं, स्टेट हाइवे नई बनी हैं। इस बजट के अन्दर सड़कों के लिए जो बजट दिया है, पहली बार धार्मिक सड़कें हमारी सरकार के समय हुई हैं। आपने किया हो तो बता सकते हैं। अन्य सड़कों, मिसिंग लिंक की बात करें तो आपको यह समय बताएगा कि ये काम किस तरह से हो रहे हैं। बजट खर्च नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही बात। यह मात्रा की कमी, सिर्फ यही निकालिए, बाकी आपके पास कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं। कर्मचारी वर्ग काफी समय से अपने आपको उपेक्षित मान रहा था, आप देखिये, आर.ए.एस., आई.ए.एस., आर.पी.एस., अन्य जितने भी विभाग हैं, कितनी पदोन्नतियां की है, आप पता कर लेना। रही सही जो छठे वेतन आयोग की बात थी, उनको दे दिया। तो अब आप देखेंगे कि आपके मन में जो सपने थे, वे सारे के सारे चूर होंगे। कर्मचारी भी राज़ी। नई भर्तियां हो रही हैं, जनता तो वैसे ही राज़ी है। ये जो योजनाएं हैं तो इन योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिलेगा।

(श्री मेवाराम जैन)

अब आप कह रहे हो कि यह तो अंतिम वर्ष है, बजट लागू नहीं होगा, अब एक रुपये किलो गेहूं, पहले दो रुपये किलो वाले गेहूं नहीं मिल रहे। कोई इसमें हाथ खड़ा करके कह दे कि जनता को नहीं मिलता तो मुझे बताइये। यह एक रुपये किलों क्यों नहीं मिलेगा, कल ही शुरू कर देंगे। यह पांच किलो आटे वाली क्यों नहीं बात होगी, यह कभी करा देंगे। जो बातें आप कर रहे हो, जनता को भ्रमित भले ही कर सकते हो, जनता के पास पहुंचीं तो अपने आप ये सारी बातें रह जाएंगी और आप सिर्फ सपने देखोगे, हम वापस आ रहे हैं। गत बजट के समय आप उत्साहित थे, रात-दिन का अंतर है उस चेहरे में और आज के चेहरे में। जरूर आपके दिमाग में है, अब नहीं कहो तो आपकी मजबूरी है। हकीकत आपके अन्दर है, हकीकत आपकी आत्मा जान रही है कि हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा। आप देखना इस इलेक्शन के अन्दर वापस कांग्रेस की सरकार आएगी और अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में आएगी। मैं डंके की चोट के साथ कह रहा हूं, आप इस बात को ध्यान रखना।

मैं बाड़मेर की बात करना चाहूंगा। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बाड़मेर के अन्दर रिफाइनरी के साथ-साथ यूआईटी दी, बाड़मेर में मेडिकल कालेज की घोषणा की। बाड़मेर में पशु चिकित्सालय खोलने की इस बजट में घोषणा की। वृद्धाश्रम के लिए कई घोषणाएं कीं। बाड़मेर के अन्दर मैं ओवरब्रिज की बात करना चाहूंगा, एक की जगह दो ओवरब्रिज और 90 परसेंट काम हो चुका है, इस जून में उसका उद्‌घाटन और कराऊंगा। 25-25 करोड़ के दो ओवरब्रिज, सीमेण्ट सड़कें, पांच करोड़ का बस स्टैण्ड, पांच करोड़ का पार्क, आज बाड़मेर जाकर देखें कि विकास वहां हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको वहां जाने से पता पड़ेगा कि किस तरह से विकास हो रहा है। विकास होगा तो आप भी समझ रहे हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। यह सब आपके सामने है, आज मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा।

विद्युत के क्षेत्र में बातें कर रहे हैं। बात चली सवेरे कि कांग्रेस की सरकार में विद्युत का उत्पादन क्या हुआ। मेरे क्षेत्र में एक तो गिरल का और दूसरा राजवेस्ट का पावर प्लाण्ट है। यह बात सही है कि आपने शिलान्यास भी किया। लेकिन आपने जहां प्लाण्ट बनना था, सिर्फ उस जगह ही 22 हजार रुपये किसानों को उसका मुआवजा देकर सिर्फ 550 बीघा जमीन लेकर वह काम शुरू कराया। न कि वहां जहां लिग्नाइट था, जो भूमि अवाप्त करके

(श्री मेवाराम जैन)

कोयला निकालना था। वह आपके समय एक बीघा भी नहीं ली गई। यह आप जाकर वहां पूछ सकते हैं। हमारे समय में 40 हजार बीघा किसानों की जमीन, एशिया का सबसे बड़ा भूमि अवाप्ति का मामला था, हमने वह किया और आज वहां कोयला निकल रहा है। पावर प्लाण्ट चालू है, राजस्थान को बिजली मिल रही है। इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी और विद्युत मंत्रीजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं 5-7 बातें जरूर इसमें निवेदन करना चाहूंगा कि बजट में तो खूब दिया है लेकिन कुछ कमियां हैं। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): आपको सबसे ज्यादा मिला है राजस्थान में।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): यहां हमारे जलदाय मंत्रीजी बैठे हैं, इनसे मैं कहना चाहूंगा कि यह जनता जल योजना है, इस जनता जल योजना को आप वापस अपने पास ले लो। पंचायती राज इसको नहीं सम्भाल पा रहा है इस कारण योजनाएं ठप पड़ी हैं। इसलिये आप इसको वापस लो। दूसरा जो पी.एच.ई.डी. के अन्दर हैल्पर हैं उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग के यहां जयपुर में जो अधिकार हैं, उसको खतम करके वहां के एक्स.ईएन. और एस.ई. को दें ताकि उनके अण्डर में वे लोग काम कर सकें। नहीं तो उनको तो कोई भय नहीं है, तो वे काम क्यों करेंगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह करिये। तीसरा, इस बजट के अन्दर हैल्पर और इंजीनियर्स, जिस स्टाफ की कमी है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा लें। जितनी स्कीम्स बननी हैं, उनमें स्टाफ की कमी है, आप उसमें स्टाफ ज्यादा से ज्यादा लो। चौथा मैं पंचायती राज में नरेगा के मामले में बात करना चाहूंगा कि नरेगा के अन्दर जो ठेका प्रथा है, जो कार्य ठेके पर हो रहे हैं, उसको खतम करके आप पी.डब्ल्यू.डी. में जो बी.एस.आर. है, आप हर साल बी.एस.आर. बना लो, साल में दो बार बनाना चाहो मार्केट रेट से, तो वह बना लो। लेकिन वह ठेका प्रथा खतम करो और बी.एस.आर. पर काम देना शुरू करो। सरपंचों के काम में कठिनाइयां आ रही हैं। सरपंच के सामने जो सरंपच खड़ा हुआ, वह टेण्डर कापी लेकर, काम लेकर अड़ंगा डाल देता है और काम होता नहीं है। उस पंचायत का विकास रुका ही रहता है। तो सरपंचों की यह एक बड़ी प्राब्लम है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको साल्व करने की बात करें।

एक विद्युत कनेक्शन- हमारे बाड़मेर जिले में तो सारे खेतों में बैठे हैं और ढाणियों में बैठे हैं, लेकिन किसी खातेदारी भूमि में आप कनेक्शन अलाउ

(श्री मेवाराम जैन)

नहीं कर रहे हैं। आप पहले की भांति इनको छूट दिलाओ। लोगों की फाइलें जमा हैं, 5-5 के ग्रुप में मुख्य मंत्री विद्युतीकरण में जमा हैं। तो वह एक छूट दिलवाओ ताकि उनको लाभ मिले।

मैं एक और निवेदन भी करना चाहूंगा कि बाड़मेर विधान सभा में तेल के लिये भूमि अवाप्त हुई, पावर प्लाण्ट के लिये भूमि अवाप्त हुई। अब शिवपुर कला स्कीम के नाम से बाड़मेर शहर के बिलकुल पास में, आबादी के एक किलोमीटर पास में जो भूमि अवाप्त की जा रही है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको रोका जाए क्योंकि बाड़मेर शहर के मास्टर प्लान के अन्दर वह आई हुई है। जब रिफाइनरी आ रही है, वहां बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, और जगह नहीं है। जनता में बड़ा भारी रोष है। इसको रोका जाए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

बाकी, जिस तरह से हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने यह बजट प्रस्तुत किया है, मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आम गरीब, आम किसान, आम मजदूर, महिला, अल्पसंख्यक, इन सबको हितैषी यह बजट पेश किया है। अल्पसंख्यक विभाग में चाहे मदरसे खोलना, क्रमोन्नत करना, भर्तियां करना, सब्सिडी देना और जो कल्याणकारी योजनाएं चालू की हैं, मैं उसके लिये धन्यवाद देना चाहूंगा। अंत में हमारे मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए विपक्ष में बैठे भाइयों को कहना चाहूंगा कि आप इसका स्वागत करें। आप और हम सब मिलकर जनता को लाभ पहुंचा सकें, इसमें आप भागीदार बनें। न कि आप यह कहें कि झूठी पर्ची है, दवाइयां काम नहीं आ रही हैं, इससे मर रहे हैं। ऐसी खोटी बात करने से जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। यह जनता कतई भ्रमित नहीं होगी। जनता को लाभ मिल रहा है और मिलेगा। उनकी आत्मा हमारे मुख्य मंत्रीजी को और हमारी सरकार को दुआएं दे रही है। आप निश्चित रहें। आप तो यहीं बैठेंगे, यह समय बता देगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, सुबह से बैठे हैं, निर्दलीयों में से हमारा नम्बर भी लें।

श्री सभापति: अब आपको बुलवा लूंगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): एक घण्टा है हमारा, उसमें थोड़ा-सा टाइम तो करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से राज्य सरकार द्वारा रखे गये वर्ष 2013-14 के बजट पर अपने विचार रख रहा हूं। लोकतंत्र में सरकारें बनती हैं, कभी किसी एक दल की बनेगी, कभी दूसरे दल की बनेगी। प्रत्येक सरकार अपना संवैधानिक दायित्व निभाने के लिये बजट प्रस्तुत करती है। उस बजट में योजनाएं भी बनाती है, घोषणाएं भी करती है। लेकिन वास्तव में उसका मूल्यांकन धरातल पर पहला व्यक्ति है, आमजन है। उसको उस योजना का, उस बजट का कितना लाभ मिला, उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यहां मैं देख रहा हूं, सत्ताधारी पक्ष सराहना करता जाएगा, मुख्य मंत्रीजी के गुणगान गाएगा क्योंकि इनको दूसरी बार टिकट चाहिए। विपक्ष में कई बार हम उसकी आलोचना करेंगे। लेकिन वास्तव में उस बजट के क्या सुझाव हो सकते हैं, उन सुझावों को मुख्य मंत्रीजी स्वीकार भी करें, महत्व दें और साथ ही पिछले वर्ष जो बजट पेश किया गया उसकी क्रियान्विति का सही ढंग से मूल्यांकन भी किया जाए। इस अन्तिम बजट में घोषणाएं की हैं, खूब घोषणाएं की हैं। घोषणाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन उनको धरातल पर उतारने की दिशा में कुछ भी नहीं सोचा गया है। घोषणाएं वाहवाही लूटने के लिये जरूर की हैं। लेकिन उसके क्रियान्वयन का, यदि पिछले चार वर्षों के बजट को आधार मान लें तो मुझे लगता है कि यह बजट जान-बूझकर सोते हुए स्वप्न देखने के समान है। मैं एक बात कहूं, 'इस बजट के आधार पर बातें हुईं बड़ी-बड़ी, जनता अब सुबक रही। वाह रे! नारों के जादूगर, जनता तुझे ढूंढ रही'। इस प्रकार नारे खूब हुए। सरकार ने चार वर्षों में 487 घोषणाएं की हैं। अब मेरे विपक्षी सारे लोग कह रहे थे, हम तीन दिन तक इसमें आपस में बहस करते हैं। मैं चुनौती देता हूं, मैं तैयार हूं। किसी भी मंच पर खड़े होकर कि 487 घोषणाएं हुई हैं उनमें से केवल 263 ही पूरी की गईं। अर्थात् आपने केवल 53 प्रतिशत घोषणाएं पूरी कीं। अभी भी 47 प्रतिशत आपकी अधूरी पड़ी हैं- या तो शुरू ही नहीं हुईं, या अधूरी हैं। इस कारण से आपके कार्यकाल के अन्दर न तो गरीबी हटी, न चिकित्सा व्यवस्थाएं सुधरीं और न शिक्षा का कोई स्तर सुधरा और आर्थिक प्रबन्धन तो इतना गड़बड़ रहा कि जी.डी.पी. ग्रोथ केवल 3.5 प्रतिशत रही। इतनी न्यूनतम जो आज तक नहीं रही। बड़ी-बड़ी घोषणाएं एग्रीकल्चर के बारे में हुईं, एग्रीकल्चर ग्रोथ केवल 1.1 प्रतिशत है। इण्डस्ट्री की बात करते हुए उद्योग मंत्री उस दिन बहुत कह रहे थे, लेकिन

(श्री वासुदेव देवनानी)

इण्डस्ट्रियल ग्रोथ 0.6 प्रतिशत हुई है। माननीय मुख्य मंत्रीजी का मुझे पहला बजट भाषण ध्यान है, उसमें कहा था, फिस्कल डेफिसिट केवल 0.87 होगा। लेकिन आज चार वर्षों के चार बजटों के बाद बताया गया है कि फिस्कल डेफिसिट 2.35 प्रतिशत होगा। वास्तव में 2.89 प्रतिशत हुआ है। जबकि वित्तीय नियमों के तहत तीन प्रतिशत से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं हो सकता। 3 प्रतिशत के हम नजदीक आ गये। यदि फिस्कल डेफिसिट रहा तो हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। घाटे की बात करते हैं, घाटा 7800 करोड़ का सोचा गया, हुआ कितना? 11300 करोड़। और यह भी कब हुआ? जबकि आपको तेल से 5500 करोड़ मिल गये।

पैट्रोल और डीजल के भाव केन्द्र सरकार ने बढ़ाये। उसके आधार पर जो वैट बढ़ा उससे भी आपको 550 करोड़ रुपए ज्यादा मिले। तो आपको 750 करोड़ रुपए के आस-पास ज्यादा मिला, फिर भी आपका घाटा 7800 करोड़ की जगह 11300 करोड़ रहा, यह है आपका आर्थिक प्रबंधन।

हम एक दूसरे की खूब वाहवाही कर सकते हैं। हम यहां पर आलोचना भी कर सकते हैं और सराहना भी कर सकते हैं लेकिन धरातल के आंकड़े आपने बजट में ये जो किताबें दी हैं, उनमें लिखे हुए हैं। इनमें से एक भी आंकड़ा मेरा नहीं है। इस आधार पर यह सरकार कर्जा लेकर चल रही है, कितना कर्जा है? आज एक बच्चा जो जन्म लेता है मां के पेट से, उस पर कर्जा है 15500 रुपए। यह 2003-04 में था केवल 6000 रुपए। 6000 रुपए से बढ़कर मेरे गरीब बच्चे पर जो नया पैदा हुआ है, जिसको पता ही नहीं है, उसने जीवन देखा ही नहीं, उसके ऊपर 15500 रुपए का कर्जा कर रहे हो। उस आधार पर आपने 1 लाख 17 हजार करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। यदि इसको आपके हिसाब से सोचें तो 2 लाख करोड़ रुपए का भार हो जाता है। यह हाल है आपकी आर्थिक स्थिति का।

अब यदि एक-एक बात करेंगे तो, चिकित्सा सुविधाओं की बहुत सराहना हुई कि दवाइयां बहुत मिल रही हैं। मेडिकल कालेज के लिए भी अभी मेरे सारे मित्र कह रहे थे कि 15 मेडिकल कालेज खोल रहे हैं। आप खोलो, उसकी मनाही नहीं है लेकिन वास्तव में अभी जो मेडिकल कालेज हैं, उनकी स्थिति आपने पता की क्या? एक मेडिकल कालेज के प्रोफेसर को आपने ट्रांसफर करके दूसरी जगह पर भेजा, एन.एम.सी.आई. का इंस्पेक्शन है, उन

(श्री वासुदेव देवनानी)

प्रोफेसर से आपने इंस्पेक्शन करवा दिया और महीने भर बाद आपने वापस कर दिया। आज एन.एम.सी.आई. के कारण कई लोगों की तो सम्बद्धता है वह भी खतरे में पड़ गई है। पुराने मेडिकल कालेजों को तो सम्भालो। 15 मेडिकल कालेज खोल रहे हैं। आपने घोषणा कब की? मार्च में। एक अप्रैल के बाद आप उसके लिए जमीन लाएंगे, उसके लिए आदेश जारी करेंगे और 31 अगस्त को आपकी आचार-संहिता लागू हो जाएगी। एक भी मेडिकल कालेज धरती पर या आपके शहर में या आपकी कांस्टीट्युएंसी में कहीं भी खुलने वाला नहीं है। यह है जीवन की वास्तविकता।

इसके अलावा आपने चार साल के अन्दर क्या किया? मैं केवल अपने अजमेर का ही एग्जाम्पल दूं, वहां पर एक कार्डियोथोरेसिक सेंटर है। चार साल से पैसा पडा है यू.आई.टी. के द्वारा दिया, वह खर्च नहीं हुआ। आज बाई पास के लिए या तो जयपुर जाना पड़ता है या अहमदाबाद जाना पड़ता है। कार्डियोथोरेसिक पर आप एक भी डाक्टर को लगा नहीं पाये। वहां पर ट्रोमा सेंटर बना हुआ है, ट्रोमा सेंटर के 37 पद आपने कागजों पर तो स्वीकृत कर दिये लेकिन एक भी आज तक नहीं लगा। इधर से डैपुटेशन पर करके केवल एक आर्थोपैडिक सेंटर चला रहे हो। ट्रोमा सेंटर तो वहां पर नहीं चल रहा है। यह है आपकी वास्तविक स्थिति। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम दवाइयां दे रहे हैं। दवाइयां तो आपने देनी शुरू कीं, 400 में से भले ही 200 मिल रही हों, लेकिन डाक्टर्स की हालत क्या है? डाक्टर्स आपके पास हैं ही नहीं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अन्दर आज डाक्टर्स नहीं हैं।

राजस्थान के अन्दर आपके पास आपने अपने उत्तर में दिया है कि 30358 डाक्टर्स पंजीकृत हैं जिनमें से 10451 तो स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन आपकी सरकारी नौकरी में कोई आना नहीं चाहता। सरकार के सारे 8496 पदों में से केवल 5000 के आस-पास पद भरे हुए हैं। आप कहते हैं कि हम एडवरटाइज करते हैं, डाक्टर आते नहीं हैं। क्यों नहीं आते? क्या इस बजट में आपने डाक्टर्स की सेवा-शर्तों के बारे में कुछ प्रावधान सोचा क्या कि नये डाक्टर्स कैसे आएंगे? क्या आपने उनके वेतनमान के लिए सोचा क्या? आज मेडिकल कालेज के डाक्टर्स के साथ आप दोहरा चरित्र अपना रहे हैं। जब मेरे यहां पर डाक्टर्स ने हड़ताल की थी तो आपने उनका प्रोबेशन पीरियड एक वर्ष कर दिया, लेकिन मेडिकल कालेज के डाक्टर्स का आज भी प्रोबेशन पीरियड दो वर्ष है। इस प्रकार

(श्री वासुदेव देवनानी)

से कौन आएगा आपके मेडिकल कालेज में डाक्टर्स बनने के लिए? प्राइवेट में उसको एक लाख रुपए का, डेढ़ लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है, आपके यहां 18 हजार रुपए पर, 22 हजार रुपए पर, 25 हजार रुपए पर कौन आएगा? क्या आपने डाक्टर्स की रिटायरमेंट की एज बढ़ायी? क्या डाक्टर्स की सेवा-शर्तें बढ़ाईं जिससे वे एट्रेक्ट होकर आपके पास आएं? उसके लिए बजट में आपने एक पैसे का भी प्रोविजन नहीं रखा है। डाक्टर्स की कमी के कारण से मरीजों की हालत क्या हो रही है? अभी बड़ी सराहना हो रही थी, एक डाक्टर साधारणतया छह घंटे ड्यूटी देता है। जिसमें से एक घंटा तो इंडोर में जाता है पेशेंट को देखने के लिए और बाकी पांच घंटे में उसके पास ढाई सौ से तीन सौ पेशेंट आते हैं। एक मिनट में एक पेशेंट। उसमें वह देख भी लेता है और उसकी दवाई भी लिख देता है। आखिर उस पेशेंट के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस पर भी जरा आप विचार करिए। इन सारी व्यवस्थाओं को सुधारें।

आपने घोषणाएं जैसे कीं, मैं अजमेर की बात करता हूं कि वहां पर जनाना हास्पिटल के अन्दर जननी सुरक्षा में प्रसूताओं को कलेवा देने की आपने घोषणा की। तीन साल के अन्दर एक भी प्रसूता को कलेवा नहीं मिला है, यह आपके उत्तर में लिखा हुआ है। क्या किसी ने उसकी सुध ली कि क्यों नहीं मिल रहा है? क्या किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की? वह पैसा कहां पर गया, उसकी कोई चिंता हुई? लेकिन मानिटरिंग के नाम पर यह सरकार शून्य है।

शिक्षा की बात पर आएं, उच्च शिक्षा में आपकी आज तक डी.पी.सी. तक नहीं हुई। मेरा अजमेर का पी.जी. कालेज जो कि सम्भाग का सबसे बड़ा शिक्षा का केन्द्र है, दो वर्ष से वह प्रिंसिपल के लिए भी तरस रहा है, वाइस प्रिंसिपल भी पूरे नहीं हैं। आखिर क्या आपकी स्थिति है? आपके पद खाली पड़े हैं। इस बजट में आपने हायर एजुकेशन में एक भी लैक्चरर का पद घोषणा नहीं की भर्ती करने की, आखिर वहां पर 600-700 पद खाली पड़े हैं। नए-नए कालेज खोल रहे हैं उनके लिए आपने कोई नया पद नहीं बनाया। क्या कालेज में जो विद्यार्थी आएंगे, वे बिल्डिंग्स में पढ़ेंगे? उसके लिए आप कम से कम लैक्चरार तो नियुक्त करो, लैक्चरर की बात तो करो। जो लेक्चरर भरे गये आर.पी.एस.सी. के द्वारा, ये भी हमारी सरकार के समय। हमने 956 प्राध्यापकों

(श्री वासुदेव देवनानी)

के पद सैंक्शन किए थे। 456 हमने भरे थे, 457 आर.पी.एस.सी. को देकर गये थे जिसको आपने भरा। लेकिन आपने एक भी पद नहीं भरा।

यही हाल तकनीकी शिक्षा का है। पोलीटैक्निक में आज भी सैकड़ों पद खाली पड़े हुए हैं। पोलीटैक्निक का विद्यार्थी आप कैसा निकालना चाह रहे हो? बिना पढ़े ही? उसके लिए एक भी पद अभी तक नहीं इसमें, मैंने बजट पूरा दो बार पढ़ा है। हायर एजुकेशन के लिए, टैक्निकल एजुकेशन के लिए आपने एक भी पद का प्रावधान इस बजट में नहीं रखा है।

स्कूल एजुकेशन पर आ जाएं। घनश्यामजी तिवाड़ी की अध्यक्षता में एक माध्यमिक शिक्षा परिषद् बनी थी उसने देशभर के लिए कुछ प्रपोज किया था। उसमें राजस्थान को 2010-11 के अन्दर 250 करोड़ रुपए मिले, आपने खर्चा कितना किया? केवल 50 करोड़। उसके बाद 2011-12 के अन्दर आपको 700 करोड़ रुपए मिले, आपने खर्चा किया शून्य। इसीलिए 2012-13 के अन्दर आपको केन्द्र सरकार ने भी जीरो कर दिया, एक पैसा भी नहीं दिया। आपको केन्द्र सरकार पैसा दे रही है। आज माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों के लिए सारी व्यवस्थाएं चाहिए, लेकिन मशीनरी कुछ नहीं कर रही है। वह करने के लिए आपकी जो कुछ व्यवस्थाएं चाहिए, आज डी.ई.ओ. के पद कितने हैं? आपने स्कूलों में उनके काम बढ़ा दिये। उनको कह दिया कि प्राइवेट स्कूलों का भी आपको निरीक्षण करना है। आज एक डी.ई.ओ. के पास ढाई हजार स्कूल हैं, जबकि वह डेढ़ सौ से दो सौ स्कूलों से ज्यादा नहीं कर सकता। क्या डी.ई.ओ. के पदों के बारे में आपने इसमें कोई प्रावधान रखा कि हम डी.ई.ओ. के पद बढ़ाएंगे? शिक्षा के प्रति आपका कहीं भी कोई रुझान नहीं है, आपकी कोई सोच नहीं है। शिक्षा का बंटाधार हो रहा है। आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा कि बच्चियों के लिए स्कूलों में टायलेट नहीं हैं। 46 हजार बच्चियों ने टायलेट की कमी के कारण स्कूल छोड़ा है। 2936 स्कूलों में टायलेट तक बच्चियों के लिए नहीं हैं। 69420 स्कूलों में केवल एक टायलेट है। पहले टायलेट तो बच्चियों के लिए करो। आप बच्चियों की पढ़ाई को बढ़ाना चाह रहे हो लेकिन बच्चियों की पढ़ाई तब होगी जब आपके...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप सदन में थोड़ी शांति रखें ताकि माननीय सदस्य जो बोलें उसको सुनें आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): राजस्थान के अन्दर महिला और पुरुषों की साक्षरता में 28 परसेंट का गैप है जबकि राष्ट्रीय गैप केवल 16 परसेंट है। हम महिला शिक्षा को बढ़ाना चाह रहे हैं- आप भी बढ़ाना चाह रहे हो और हम भी बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमने टायलेट तक की व्यवस्था नहीं की और पीने के पानी की व्यवस्था भी कई स्कूलों में नहीं है। इसकी चिंता कौन करेगा?

हम 2015 में शत-प्रतिशत लोगों को साक्षर बनाना चाह रहे हैं, क्या इसी हालत से साक्षरता होगी? इसलिए बजट को वाह वाह कहें? क्या इस बजट में इसका प्रावधान नहीं हो सकता था? केन्द्र सरकार से जो पैसा आ रहा है, उसको भी आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, अपने बजट में तो आप रख ही नहीं रहे हो। तो जरा प्रायोरिटी बदलो। राजस्थान को नया राजस्थान बनाने की जो बात आप कहते हो, उसके लिए स्कूलों में सबसे पहले आप अध्यापकों की नियुक्ति करो। डाक्टर्स एवं नर्सों की नियुक्ति करो। पुलिस में नफरी की नियुक्ति करो तो जाकर कुछ व्यवस्थाएं ठीक होंगी। लेकिन तीनों में लगभग शून्य है।

जब मैं अध्यापकों की बात करता हूं, अभी एक प्रश्न में बताया कि, साहब, बहुत अध्यापकों की नियुक्ति कर दी। आपके द्वारा ही इस विधान सभा में बताया गया है कि 1,17,321 अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे। आपने कितने नियुक्त किये? 34 हजार, और कहते हैं कि आपकी सरकार में नहीं थे। हमारी सरकार ने नहीं, आपने ही आंकड़े दिये हैं कि 87 हजार अध्यापक तो हमने नियुक्त किये। आपने केवल 34 हजार इन साढ़े चार सालों के अन्दर। अब घोषणा कर रहे हैं कि हम एक लाख 30 हजार युवकों को रोजगार देंगे। तीन महीनों के अन्दर एक लाख 30 हजार में से किसको नौकरी दे दोगे? तीन महीने में तो आप एडवरटाइजमेंट भी नहीं कर पाओगे। एडवरटाइजमेंट करने के बाद आवेदन भी नहीं आ पाएंगे। यह केवल युवकों को भ्रमित करने का है।

आपने कहा कि हम बच्चियों को स्कूटी देंगे। मेरे पास एक अभिभावक आये, उन्होंने कहा कि स्कूटी तो मिलेगी लेकिन स्कूटी में पैट्रोल कहां से भरवाऊंगा। पैट्रोल के भाव जो आप बढाते जा रहे हो, उस पैट्रोल के बिना स्कूटी चलेगी कैसे? यह मेरे उसके लिए कहा। आप जरा वैट कम करो। आपने घोषणा तो की चुनाव घोषणा पत्र में लेकिन अपने वैट की कहीं पर कमी नहीं की। जो आपका बढ़ता जा रहा है, उतना तो कम से कम कम करते, लेकिन नहीं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

फिर आपने कहा कि आर.टी.ई. को लागू करेंगे राजस्थान में। आपका संवैधानिक दायित्व है कि आप आर.टी.ई. को लागू करो। लेकिन आर.टी.ई. को लागू करने के लिए कहा कि 25 परसेंट गरीब बच्चों के स्कूल के अन्दर एडमिशन होने चाहिए। आपने कुछ स्कूलों में एडमिट करवा दिये। उन्होंने पुनर्भरण के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट भेजी। पिछले दो साल से एक को भी पुनर्भरण नहीं हुआ है और तीसरे साल अपेक्षा कर रहे हैं कि वे भरें। तो आखिर वह भरेगा कैसे? यह स्थिति जो बनी है, मुझे लगता है कि आपकी

(17.00 बजे)

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

इसमें कोई रूचि नहीं है। रूक्टा वालों ने वहां पर प्रदर्शन किया एरियर के लिये। आपका तीन साल पहले का कमिटमेंट था कि 60 प्रतिशत अभी देंगे, 40 प्रतिशत बाद में देंगे। वे तीन साल से बेचारे तरस रहे हैं। यह है शिक्षा में आपके वादे का नाम।

विश्वविद्यालय की यदि बात करूं तो विश्वविद्यालयों की हालत तो यह है, विश्वविद्यालयों की नियुक्तियां इत्यादि कई बातें सदन में आ गयीं, जोधपुर विश्वविद्यालय में तो खुलेआम उसकी धज्जियां उड़ी हैं। कोटा में धज्जियां उड़ी हैं। यदि आप अपनी सरकार के तीन मंत्रियों की कोई समिति बनाकर उसकी जांच करवाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह सारी स्थिति वहां पर बनी है। केवल शिक्षा को बनाया तो लूट का केन्द्र बनाया है। आपने बी एस टी सी की परीक्षा अजमेर के कालेज को दी। चार साल के अन्दर उन गरीब बच्चों से आपने 37 करोड़ रुपये कमाये और उन परीक्षाओं की व्यवस्थाओं पर खर्चा हुआ केवल 16 करोड़। क्या 21 करोड़ केवल कमाने के लिये है। क्या उनकी फीस आधी नहीं की जा सकती थी? लेकिन 21 करोड़ उस कालेज को लूटने के लिये आपने दे दिये। उसके पहले सारे मानदेय जितने देने थे, उसके बाद यह आंकड़ा है। फिर आपने टैट की परीक्षा ली। टैट की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दी, टैट की एक परीक्षा के अन्दर आपने 34 करोड़ कमाये। आपका व्यय 17 करोड़ ही हुआ, 17 करोड़ फिर जेब में गये। आपने यह सारी व्यवस्था प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये की है क्या? मैं कहता हूं, जरा इस पर पुनर्विचार करो। आप गरीब जनता को मत लूटो। दूसरा आपने इस बजट में ...(व्यवधान) आपने जितना समय औरों को दिया है, मैं उनसे कम समय लूंगा।

(श्री वासुदेव देवनानी)

आपने सड़कों की बात की, आपने कहा कि 20,743 करोड़ की योजना प्रस्तावित है। ये सड़कें तो बी ओ टी से बन रही हैं, इसका जनता पर भार पड़ेगा क्योंकि उन्हीं को गाड़ी का सारा टोल टैक्स देना है। आप काहे के लिये वाहवाही लूट रहे हो? इसमें आपका क्या हिस्सा है? मेरी मांग है कि जिस जिले में जो वाहन पंजीकृत है, कम से कम उस जिले में तो आप टोल की उसको छूट दोगे, तब जाकर जनता को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी।

कानून-व्यवस्था, कल-परसों से अख़बार में हम पढ़ रहे हैं कि पुलिस और वकीलों का जगह-जगह संघर्ष चल रहा है। पुलिस की नफरी के लिये आपने कहा कि इतने पुलिस वाले भर्ती होंगे, लेकिन उनकी कोई चिन्ता नहीं। कानून-व्यवस्था आपसे सम्भल नहीं रही है। कानून–व्यवस्था के बारे में आपकी कोई सोच तक नहीं है। और जो है, वह तो जब पुलिस की डिमाण्ड होगी, तब उसके बारे में चर्चा करूंगा।

अब पानी की व्यवस्थाओं में बात करें, उसकी हालत भी बुरी है। आपने एम पी गवर्नमेंट की नकल करके वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा का प्रावधान रखा है। इसके लिये निश्चित रूप से आपने प्रावधान शुरू किया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, लेकिन साथ में मेरी मांग है कि जिस प्रकार हज के यात्रियों को अनुदान मिलता है, सिन्धु दर्शन के लिये, सिन्धु नदी पर दर्शन करने के लिये लोग जाते हैं, उनको भी अनुदान मिलना चाहिये। सिन्धु नदी हमारी पवित्र नदी है, उसके किनारे पर बैठकर वेद लिखे गये थे। आज वहां पर देश भर से लोग जाते हैं। वहां राजस्थान से जाने वाले लोगों को यदि हज की तरह अनुदान मिलेगा तो वे आपकी वाहवाही करेंगे। इसका बजट में प्रावधान कोई बहुत अधिक नहीं चाहिये, लेकिन जो लोग अपना सिन्ध देश छोड़कर आये, सिन्धी लोग, उनको कम से कम इतना तो लाभ होगा कि वे अपने वहां पर जा सकें।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

विकास की बात होती है कि जे एन आर यू एम के साथ शहरों का विकास हो रहा है। मैं केवल एक बात बताऊंगा, विकास के नाम पर आप प्रावधान तो रखते हो, लेकिन हालत क्या है? आपने झील संरक्षण में अजमेर की झीलों के लिये 18.62 करोड़ रुपये रखे, जो योजनाएं अभी मार्च में खतम

(श्री वासुदेव देवनानी)

होने वाली हैं, लेकिन उसमें खर्चा कितना हुआ है? मात्र 6 करोड़ रुपये। यानी 12 करोड़ रुपये अभी तक पड़े हुए हैं। क्या लास्ट के पांच दिनों में हेराफेरी करके आप खर्च करोगे? या खर्च नहीं होगा? क्या होगा विकास का, जरा इस पर कोई विचार करे।

अजमेर में वेदांता ग्रुप को आपने जिंक निकालने के लिये अनुमति दी है। उसने जिंक निकालना शुरू भी किया है। वे यू आई टी से अरबों रुपये की जमीन भी ले रहे हैं। तो अजमेर के अन्दर एक जिंक स्मैल्टर यदि आप बनाएंगे तो अजमेर में औद्योगिक विकास के लिये एक कदम आगे बढ़ेगा। लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वहां से लाखों टन जो जिंक जाता है, वह वहीं स्मैलटर में काम आकर आगे बढ़ेगा। इसकी आवश्यकता है।

दूसरा अजमेर की ट्रैफिक व्यवस्था से बहुत परेशान हैं। उसके लिये एलीवेटेड रोड का सर्वे भी हुआ है, लेकिन एलीवेटेड रोड के लिये इसमें कोई प्रावधान नहीं रखा है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): हमारी सरकार ने, वसुन्धराजी की सरकार ने मेडिसिटी की बात की थी, उसके लिये भी एक पैसे का भी प्रावधान नहीं रखा है। इसके लिये अजमेर विश्वविद्यालय को कुछ भी नहीं मिल रहा है। पी एस वी की जो टंकियां बनी हुई हैं, चार साल से तरस रही हैं कि जरा पाइप तो लाओ। उसके पाइप की आप व्यवस्था करें। मैं समझता हूं कि इन तीन-चार बातों का बजट में प्रावधान करेंगे।

श्री सभापति: आप सम-अप करें, माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अपने बजट का मूल्यांकन करें, बजट का मूल्यांकन करके विकास में केवल जोधपुर को न देखें। जोधपुर में मेडिकल कालेज को 42 करोड़ रुपये दे दिये, अजमेर 10-12 करोड़ रुपये के लिये तरस रहा है। बाकी भी पूरा प्रान्त है। मुख्य मंत्रीजी, आप राजस्थान के मुख्य मंत्री हो, आप केवल जोधपुर के ही नहीं हो। अब अन्त में केवल एक बात कहता हुआ अपनी बात पूरी करूंगा।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री वासुदेव देवनानी)

अब मुझे केवल एक बात कहनी है। आज जो स्थिति है वह है –

'अबला की आबरू लूटे, मंदिर भी टूट रहे,
जनता के आंसू सूखे, पर ये तो उपलब्धियों के ढोल पीट रहे।
विकास क्या होता है, ये क्या जानें,
ये तो बस लूट रहे हैं।
जनता त्रस्त होकर कहती
बस करो, हम बहुत सह चुके।।' धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ओ.पी. यादव।

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2013-14 के बजट भाषण पर बहस में मुझे दिये गये समय के लिये आपका आभार। I will try my level best to restrict myself within the orbit of the Budget. But I certainly like to touch those salient features which have somehow not been touched by the Members. मैंने इस बजट भाषण के पैरा नं. 13 पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा उद्धृत की गयी कविता के अंशों का सहृदय विश्लेषण करने का प्रयास किया है। साथ ही पार्टी के घोषणा पत्र एवं विभिन्न कार्यक्रमों का विश्लेषण भी किया है। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों, नीतियों में जनप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा सब के कुशलक्षेम की इच्छा शक्ति परिलक्षित होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्य मंत्रीजी की निष्ठा समाज के किसी वर्ग में नहीं है, बल्कि बच्चे के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, उनको कुशल एवं सक्षम बनाने के प्रयास दृष्टिगोचर होते हैं। यह बिलकुल सही है कि मुख्य मंत्री का ध्येय सबकी सेवा करना है, सबकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना है। यह भी सही है कि बच्चा हो, बूढा हो, नि:शक्तजन हो, रोगी हो, या अन्य कोई जन, सबके लिये इस बजट में रिलीफ देने का प्रयास किया गया है, जो हम सबको विदित है। इतना ही नहीं, माननीय द्वारा समाज के बीपीएल परिवारों को दी गयी सुविधाओं को अंत्योदय परिवार को भी उपलब्ध कराना एक सराहनीय प्रयास है। मुख्य मंत्रीजी द्वारा राजस्थान राज्य विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्ध घुमन्तू कल्याण बोर्ड के लिये आवास, शिक्षा एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिये बजट में 50 करोड़ रुपये की विशेष योजना लागू किये जाने की घोषणा हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री नेहरूजी द्वारा गाड़िया लुहारों के लिये एक जगह बनाने का प्रयास किया गया था, इसी कड़ी में एक अभूतपूर्व कदम है।

(मेजर ओ.पी. यादव)

मुझे लगता है इसकी ओर पहले किसी की दृष्टि नहीं गयी है। जैसा मैंने कहा, सेलिंट फीचर्स की तरफ मैं ध्यान ले जाऊंगा, I will try to get you back to the history हालांकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूं। आपको याद हो, आजादी के बाद स्व. जवाहरलाल नेहरू राजस्थान के अन्दर जब आये थे, तो गाड़िया लुहारों को देखने के बाद उन्होंने कहा था कि आजादी अब आपको मिल गयी है। महाराणा प्रताप के टाइम में आपने जो कसम खाई थी, वह अब आप खतम करो और अपना काम शुरू करो, अपने घर लेओ। उसके बाद में कुछ उदासीनता रही। लेकिन इस मुख्य मंत्री ने उस बात को याद करते हुए, जवाहरलाल नेहरूजी की इच्छा को याद करते हुए यह काम दुबारा शुरू किया, जहां किसी की सोच नहीं गयी थी। राजस्थान में वृद्धाश्रम की योजना से वृद्धों के प्रति, अल्पसंख्यकों के लिये विभिन्न योजनाओं से अल्पसंख्यकों के प्रति और टी एस पी क्षेत्र के निवासियों के लिये विशेष पैकेज लागू करने की घोषणा से माननीय मुख्य मंत्री की इन लोगों के प्रति चिन्ता एवं सद्‌भावना परिलक्षित होती है। माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार बच्चों के अधिकार एवं संरक्षण के लिये ... (व्यवधान)

श्री सभापति: सदन में थोड़ी शांति रखो आप।

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): अलग से घोषणा, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले बच्चों को यूनिफार्म उपलब्ध कराने की घोषणा एवं शुभलक्ष्मी योजना एक युगदृष्टा मुख्य मंत्री की ही सोच हो सकती है। माननीय सदस्यों द्वारा बजट के बारे में अपने अपने मत व्यक्त किये गये हैं, जो उनका अधिकार क्षेत्र है। पर मैं आपका ध्यान पुन: पैरा 13 में अंकित कविता की पंक्तियों की ओर ले जाना चाहूंगा, जिसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उद्धृत किया है-

''सभी मेरे सखा बंधु हैं, मैं सबकी परछाई हूं,
मेरा है सम्बन्ध सभी से, सबसे मेरी स्नेह सगाई।''

इस बजट की घोषणाओं एवं इनकी नीतियों से इस कविता के अंशों के प्रति मुख्य मंत्रीजी की भावना शत-प्रतिशत परिलक्षित होती है। वचन से ही नहीं, अपितु कर्म से भी सब के सखा हैं, सबके बंधु हैं और सभी से इनका सम्बन्ध है।

(मेजर ओ.पी. यादव)

सभापति महोदय, बजट को देखने के पश्चात् शायद ही आलोचना के लिए कुछ कहने को कुछ बचता हो। हां, इसकी आलोचना करना विपक्ष धर्म का पालन करने का प्रयास हो सकता है।

वित्तीय प्रबन्धन के बारे में मैं यदि बात करूं तो वर्ष 2011-12 का रेवेन्यू सरप्लस 3357 करोड़ का रहना कुशल वित्तीय प्रबन्धन का ही परिणाम है एवं रेवेन्यू सरप्लस होना राज्य की प्रगति का द्योतक है। अभी मेरे से पहले मेरे साथी बोल रहे थे कि शराब की कमाई से सरप्लस बजट है। वह यह भी बोल रहे थे कि इसके घाटे की तरफ भी जाना चाहिए, और कि कर्जा कितना है। लेकिन देखना आपको यह है कि बजट के अन्दर असेट्स क्या हैं, एक्सपेंडीचर क्या हैं। सकारात्मक रुख से टीम का कुशल नेतृत्व किया, उसी का रिजल्ट है।

अधिकार का युग- हमारे मुख्य मंत्रीजी की नीति और बजट भाषण से लगता है, राज्य में अधिकार के युग का सूत्रपात हो चुका है। राजस्थान लोक सेवा प्रदान करने की गारन्टी और राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 इस सन्दर्भ में की गई प्रशंसनीय पहल है।

मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना, मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना, जननी सुरक्षा योजना, मुख्य मंत्री ग्रामीण एवं शहरी बीपीएल आवास योजनाओं से दृष्टिगत होता है कि प्रदेश की जनता को खाद्य सुरक्षा का अधिकार, आवास का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार दिये जाने की राज्य सरकार की अद्वितीय पहल है। इन कार्यक्रमों को राजस्थान में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है और आप भी यह महसूस करते हैं कि काश हम भी यह सब कर पाते। पर समय निकल गया और आने वाले समय में कोई आशा आपको ऐसी नहीं करनी चाहिए कि आप ऐसा कुछ कर पाएंगे।

समस्त बीपीएल परिवारों को एक रुपया प्रति किलो गेहूं देना दूरगामी सोच का परिणाम है। इसी प्रकार मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के साथ मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना, राइट टू हैल्थ, I repeat राइट टू हैल्थ प्रदान करने की अवधारणा को मूर्त रूप देने का प्रयास है जिसकी हर स्तर पर सब लोगों ने प्रशंसा की है।

सभापित महोदय, मैं अक्सर अस्पतालों में जाकर पीएमओ से मिलता हूं तब पता चलता है। पीएमओ की जुबान से योजनाओं की तारीफ तो होती ही

(मेजर ओ.पी. यादव)

है तथा योजनाओं के प्रति संतोष भी प्रकट किया जाता है, हम सबको भी संतुष्टि मिलती है। और सच्चाई यह है कि आप लोग भी अस्पतालों में जहां-जहां भी जाते हैं अपने साथियों को मिलने के लिए, आपको भी यही संतुष्टि मिलती है। पर आपको यहां 'ना' कहने से संतुष्टि मिलती है। यह एक धर्म है। जिन पीड़ित परिवारों को नि:शुल्क दवा योजना, मुख्य मंत्री सहायता कोष, जननी सुरक्षा योजना जैसे प्रोग्राम्स से लाभ होता है, वे मुख्य मंत्रीजी की योजनाओं एवं उनसे प्राप्त लाभ की बात तो करते ही हैं, उनसे मिलने के बाद तो ऐसा लगने लगा है कि वे अपने जन हितकारी प्रोग्राम्स से गरीबों के मसीहा के रूप में उनके दिलों में भी स्थापित हुए हैं। मुख्य मंत्री सहायता कोष से सहायता राशि एक लाख रुपया किया जाना इस सन्दर्भ में मुख्य मंत्रीजी की महती पहल है। इससे उन पीड़ितों को और भी लाभ मिलेगा। यदि मैं यह कहूं, बहुत ही विश्वास के साथ में, कि सरकार की ये योजनाएं मुख्य मंत्रीजी का यह सोच अब प्रात: स्मरणीय एवं संध्या वंदनीय कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

बजट में राज्य की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किये गये हैं। राज्य में सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण, चौड़ा करने के कार्य, मिसिंग लिंक के कार्य, धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ने के कार्य किया जाकर सड़क तंत्र को मजबूत किया गया है। आगे भी इस कार्य को सतत् करते हुए राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना एक प्रशंसनीय कदम है जो राज्य के विकास के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा। इसी कड़ी में विशेष सड़क निर्माण निधि बनाने की घोषणा, वित्तीय प्रबन्ध एवं आधारभूत संरचना बनाने का एक अभिनव प्रयास है।

सभापति महोदय, अगर मैं ऊर्जा की बात करूं, राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए सतत् प्रयास किये गये हैं। उसी का परिणाम है कि राज्य की ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में 4628 मेगावाट की वृद्धि हुई है और आगामी वर्षों में इसको बढ़ाने का प्रयास जारी है। ऊर्जा के क्षेत्र में पवन ऊर्जा उत्पादन, सौर ऊर्जा उत्पादन की ओर भी ध्यान दिया गया है जो अपने आप में अच्छी पहल और कंस्ट्रक्टिव सोच है क्योंकि इसमें न तो कोई एक्सपेंडीचर है और न कोई फ्यूल है।

(मेजर ओ.पी. यादव)

बजट घोषणा में राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण, इनके अल्पकालीन ऋणों को रि-स्ट्रक्चर करने और किसानों को छह घंटे बिजली उपलब्ध कराने के पेटे अतिरिक्त विद्युत खरीद का भार राज्य सरकार के द्वारा वहन करने का कार्य प्रशंसनीय है। मैं समझता हूं, यह बात सभी लोग मानते हैं कि हम लोगों ने जो यह काम किया है, इससे किसानों को बहुत राहत मिल रही है और मिलेगी। ऊर्जा की बचत के साथ-साथ समाज के 50 लाख बीपीएल परिवारों को 2-2 सीएफएल मुफ्त उपलब्ध कराना स्वागत योग्य कदम है।

सभापति महोदय, मैं पेयजल एवं जल संसाधन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये कार्यों एवं प्रबन्धन की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। नदी बेसिनों में वर्षा के समय अतिरिक्त पानी बहकर राज्य से बाहर चला जाता है। इस बहकर जाने वाले पानी का राज्य में ही उपयोग करने की दृष्टि से चम्बल से अलवर के जयसमंद बांध में, मेजा नदी से जयपुर के रामबढ़ बांध में, माही से जयसमंद, राजसमंद एवं मेजा में पानी लाने की घोषणा और अन्य इसी तरह की जल संसाधन की घोषणाएं हमारे मुख्य मंत्रीजी की दूरदर्शी सोच की तरफ इशारा करती हैं। इससे प्रदेश की जनता को वास्तविक लाभ मिलेगा, ऐसा हम सबका विश्वास है। जल संसाधन की संरचना को सुदृढ़ करने के लिए शायद ही ऐसा जिला बचा होगा जिसको कि जल संसाधन के आधारभूत ढांचे से जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया हो।

सभापति महोदय, मैं चाहे किसानों की बात करूं या पशुपालकों की, बजट में इन सब का ध्यान रखा गया है। सार्वजनिक पुस्तकालयों का निर्माण, यह सोच देखिए आप, पुस्तकालयों को कार्यशील बनाने की घोषणा को मैं एक ऐसी घोषणा के रूप में देखता हूं जो समाज की संरचना और युवाओं को निरन्तर गति प्रदान करेगी। आवश्यकता है तो सिर्फ इनके सुचारु संचालन की। पिछले कई दशकों से लाइब्रेरियन रिटायर तो हो गये मगर शायद ही उनकी कभी नियुक्ति हुई हो। यह सच में देखने की बात है। इस क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा एक अभिनव प्रयास है, आवश्यकता इसको गति प्रदान करने की है।

सभापति महोदय, उद्योग की बात मैं करना चाहता हूं। राज्य के दस औद्योगिक क्षेत्रों में से एक औद्योगिक क्षेत्र कोलीला जोगा अलवर में है जो मेरे

(मेजर ओ.पी. यादव)

विधान सभा क्षेत्र में आता है। इलेक्ट्रोनिक एसोसिएशन आफ इण्डिया द्वारा टपूकड़ा के नजदीक सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रोनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने से यहां के युवाओं को लगभग 20 हजार रोजगार उपलब्ध होंगे जिससे यहां के युवाओं में उत्साह का संचार होगा एवं युवा शक्ति को सही दिशा मिल सकेगी, ऐसा मैं मानता हूं।

साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराना में उप खण्ड बनाने की घोषणा करने से मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता को सस्ता एवं सुलभ लाभ मिल सकेगा। किसानों को दो स्टैप पर रेवेन्यू सम्बन्धी मामलों का समाधान किया जा सकेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को साधुवाद देता हूं। विशेष तौर से यह कि पिछले साल नीमराना को तहसील घोषित किया गया था और इस साल नीमराना को उप खण्ड घोषित किया गया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र की जनता उनके प्रति आभार व्यक्त करती है।

मैंने पहले भी सदन में चर्चा के दौरान युवाओं के रोजगार के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता व्यक्त की थी। इसी प्रकार मैंने सदन में दिल्ली-मुम्बई कोरिडोर से मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराना व जिले के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोडऩे के काम को शीघ्र ही क्रियान्वित करने की बात की थी। मैं समझता हूं कि स्पेशल इन्वैस्टमेंट रीजन एक्ट बनाये जाने की घोषणा की क्रियान्विति के समय मेरा निवेदन जो कि मैंने पूर्व सदन में रखा था, क्रियान्वित कर मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराना के युवाओं के रोजगार के सम्बन्ध में ध्यान रखा गया है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद देता हूं।

सभापति महोदय, इसी प्रकार राजस्थान वित निगम के सुदृढ़ीकरण की बात है, ये वे साइलेन्ट फीचर्स हैं जो समय पर टच नहीं हो पाये। राजस्थान वित्त निगम के वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु निगम की अधिकृत पूंजी को 200 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये किया गया जिसमें राज्य सरकार द्वारा 25 करोड रुपये की अंश पूंजी का सहयोग प्रदान किया जाएगा। इससे उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन योजना चलायी जाएगी जिसमें 25 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक लागत की परियोजनाओं हेतु युवाओं को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

(मेजर ओ.पी. यादव)

यह सबसे हटकर हमारे मुख्य मंत्रीजी की दरदर्शी सोच है। मैं यह भी कहना चाहूंगा, पिछले बजट की डिबेट में भाग लेते हुए मैंने यह अवगत करवाया था कि राजस्थान के औद्योगिकीकरण में राजस्थान वित्त निगम की महती भूमिका रही है एवं राजस्थान के उद्योगों के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान भी रहा है। इस प्रकार की संस्थाओं को सुदृढ़ करने का माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा किया गया प्रयास मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी मेरी दृढ़ मान्यता है।

सभापति महोदय, बजट में किस सम्भाग को किस क्षेत्र में क्या दिया गया, इस बारे में मेरे साथी सभी पूर्व वक्ताओं ने जिक्र किया है। मैं इसको दुबारा बोलकर सदन का समय जाया नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह बजट बिना किसी भेदभाव, पक्षपात, क्षेत्रवाद के राजस्थान की प्रगति, जनता के हर तबके के हित का बजट है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय व उनकी टीम की जितनी प्रशंसा की जाए, कम है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की जनता की तरफ से यह अपेक्षा करता हूं, निवेदन करता हूं कि देवनारायण योजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए पैकेज को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये करने की जो घोषणा की गयी है, जो कि हमारे भाई गूजरों की प्रगति का रास्ता प्रशस्त करती है, इस घोषणा को स्पेशल बैकवर्ड क्लासेज एस.बी.सी. में सराहा जा रहा है। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के गूजर वर्ग को जहां से मैं चुन कर आता हूं, इस महत्वाकांक्षी योजना में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। मेरे क्षेत्र में लगभग 14 हजार गूजर भाइयों की आबादी है, मैंने इनके जीवन को देखा है। आपको बताते हुए मुझे जरा भी कोई हिचकिचाहट नहीं है, ऐसे-ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गूजर भाई पहाड़ों को काट कर अपनी खेतीबाड़ी करते हैं। अब तो जब जमीनें कहीं नहीं मिलती हैं तो अपने विधान सभा क्षेत्र में वो बटालियंस अगर आती हैं, जो हमारे मंत्री महोदय लेकर आये, तो उसमें भी वो लोग अपना सहयोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे होंगे कि उनको देवनारायण योजना के अन्दर यह लाभ नहीं मिला। इनके शिक्षा का भाव और इनकी आशा की दृष्टि को देखते हुए मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के गूजरों को भी देवनारायण योजना की पात्रता में शामिल कर उन्हें लाभ दिया जाए।

(मेजर ओ.पी. यादव)

मेरे मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में कोई भी महाविद्यालय नहीं है, दूर-दूर तक नहीं है अत: राजकीय महाविद्यालय, आई वुड रिपीट, अत: राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा की जाए। जैसा कि मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है, मुण्डावर एक बहुत ही बैकवर्ड विधान सभा क्षेत्र है, वहां पर कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं होना एक चिंता का विषय है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को कोर्ट केसेज के सम्बन्ध में किशनगढ़बास जाना पड़ता है, इस न्यायालय में मुण्डावर क्षेत्र के 70 प्रतिशत से भी अधिक केसेज हैं अत: मुण्डावर में ए.डी.जे. न्यायालय की स्थापना का भी मैं निवेदन करता हूं कि इसी सत्र में न्यायालय खोलने की घोषणा की जाए।

महोदय, मुण्डावर में जो कस्बा है वो बहुत पुराना है, पिछड़ा हुआ है। छोटा-सा कस्बा था लेकिन अब वो काफी बढ़ गया है। ट्रैफिक का दबाव होने की वजह से वहां जो और लोग अपना व्यापार करने के लिए आना चाहते हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं इसलिए मेरी यह बहुत ही विनम्र शब्दों में गुजारिश है कि यहां पर बाई-पास की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां पर काफी कुछ जमीन नाले की है, सरकारी जमीन और कुछ वहां पर ली जा सकती है। मरीजों व प्रसूताओं को अस्पताल तक ले जाने में कई बार भारी असुविधा होती है। कई बार कुछ गम्भीर ऐसे भी केसेज आये हैं कि एक-एक घंटे तक जच्चा-बच्चा को वहां रहना पड़ा है। इसलिए मुण्डावर में बाई-पास का निर्माण किया जाना बहुत जरूरी है, ऐसी मेरी विनती है।

महोदय, अध्यापकों को अध्यापन के अतिरिक्त अन्य ड्यूटियों में कम से कम लगाना चाहिए, इससे शिक्षा के क्षेत्र में इनका ज्यादा योगदान होगा और विद्यार्थी सफर नहीं करेंगे। आमजन प्राइवेट क्षेत्र के स्कूलों की तरफ उतने आकर्षित नहीं होंगे जितना हो रहे हैं।

एरिया वाइज स्थापित उद्योगों में उनकी योग्यता अनुसार वहां के लोकल युवाओं को रोजगार निर्धारित किया जाए। मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी लोग, जितने भी हम नेता हैं, जितने भी हम माननीय सदस्य हैं, अपने-अपने क्षेत्रों में हम खूब जोर देकर यह बात कहते हैं कि जो हमारे उद्योग हैं, उद्योगपति और उनकी मैनेजमेंट हमारे लोकल लोगों को रोजगार दें लेकिन कहीं भी, किसी भी रूप में उनको बाध्य नहीं किया जाता। वो बाध्य किया जाना

(मेजर ओ.पी. यादव)

चाहिए ताकि युवाओं को योग्यता अनुसार रोजगार मिल सके और उनके पलायन को रोका जा सके।

मेरा विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर पशुधन में बहुत रिच है, यहां पशुधन द्वारा रोजगार उपलब्ध होने की विपुल संभावना है, अत: मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी बजट में विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में वेटरिनरी कालेज की स्थापना की जाए।

नीमराना में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार कार्यालय एवं प्लेसमेंट ब्यूरो की ब्रांच भी स्थापित की जानी चाहिए क्योंकि आज नीमराना औद्योगिक क्षेत्र है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि सारे राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश और राष्ट्रीय सीन पर उभर कर आया है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है, किसान अपनी फसल में पानी नहीं दे पाता है इससे कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिन किसानों ने बिजली कनेक्शन के लिए वर्ष 2009-10 में प्रार्थना पत्र बिजली वितरण कम्पनी में प्रस्तुत किये थे, उनको कनेक्शन नहीं मिले हैं। ऐसे सभी पुराने प्रार्थियों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराये जाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं।

राज्य में कितने ही मरीजों को दिल्ली, गुजरात एवं अन्य राज्यों में जाकर इलाज करवाना पड़ता है जो कि बहुत ही श्रम-साध्य एवं खर्चीला होता है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में पृथक से किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए उच्चस्तरीय सुविधाओं से युक्त चिकित्सालय की स्थापना की जाए। राज्य कर्मचारी जो बाहर जाकर किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, उनके बिलों की पुनर्भरण की सुविधा प्रदान की जाए एवं ऐसे अस्पतालों को पुनर्भरण की सूची में शामिल किया जाए।

अंत में मैं इस अभूतपूर्व बजट की प्रशंसा करते हुए माननीय श्री अशोकजी गहलोत को राजस्थान के विकास के लिए प्रस्तुत किये गये इस बजट के लिए धन्यवाद देता हूं। I would like to say that this has been a brilliant one by the Hon'ble Chief Minister of Rajasthan-cum-Finance Minister and this has been appreciated by everyone. जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रणवीर पहलवान।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, यह पुस्तक बजट की है, पांचवीं पुस्तक है और इसका हक, अधिकार राजस्थान की जनता ने आपको दिया था। इस पुस्तक के वैसे तीन पार्ट होने चाहिए थे, एक तो आपने जो बजट में घोषणाएं की थीं कि हम ऐसा करेंगे, वो पार्ट होना चाहिए था। दूसरा इसमें होना चाहिए था कि आज तक हमने चार वर्ष में क्या कर दिया। तो जनता आपके पांचवें बजट पर भरोसा करती।

मैं आपकी चुनाव की घोषणाओं से शुरू करता हूं। छोटी-सी जगह टोंक जिला, हमारा जिला है, वहां के सदस्य यहां बैठे हुए हैं। हमारे दो तो पुलिया ऐसी थीं जिसका आपने अपनी चुनावी गीता, रामायण जो भी आपने प्रचारित की थी कि हम ऐसा करेंगे, उन दो पुलियाओं की वजह से करीब 150 किलोमीटर तक, 70 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। इस पांचवें बजट भाषण में भी यह कहा गया है कि उन पुलियाओं का निर्माण विचाराधीन है, उन पुलियाओं का निर्माण करेंगे।

पहली बात तो जब यह बजट मुख्य मंत्रीजी ने पढ़ दिया तो सत्ता पक्ष के व्यक्ति को इस पर बहस करने का कोई हक, अधिकार नहीं बच जाता क्योंकि ये तो वो ही बात दोहरा रहे हैं जो मुख्य मंत्रीजी ने तीन घंटे में पढ़ कर सुना दी। इनको शांति से सुनना चाहिए, इनकी कमियां कहां रह गयीं वो हम इनको बताएंगे। बाकी तो गुणों की खान हैं ये। घोषणा इन्होंने कर दी, दोबारा सरकार आएगी। और इनकी घोषणाएं सच्ची हैं। भविष्य में जानते हैं तो इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी को नहीं मरने देते। यह बता देते न, कहां बम फटेगा और कहां गोली चलेगी। जब आपको एक साल आगे का पता ही है तो कम से कम उनको तो बचा लेते कि कल सुबह आफिस मत जाना, इन्दिराजी, गोली चलेगी या राजीवजी, वहां बम फटेगा। एक साल आगे की ये घोषणाएं।

सभापति महोदय, आपके चित्तौड़ के सदस्य को कह रहा हूं मैं। आप भी यही कह रहे थे, पर अब सभापति हो गये तो मैं बोल नहीं सकता आपके बारे में।

आपने घोषणा की थी कि बीसलपुर बांध से पूरे टोंक जिले को पीने का पानी दिया जाएगा। आपके उस चुनाव के एजेंडा के अन्दर शामिल था। हमारे निवाई के सदस्य यहां हैं, इनसे पूछें कि निवाई तहसील के एक गांव में भी बीसलपुर का पानी गया है चार वर्ष में? देवली में, उनियारा में या टोंक में? (व्यवधान)

श्री कमल बैरवा (निवाई): मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीपलू में प्रत्येक गांव को बीसलपुर का पानी पिलाया जा रहा है, जनाब। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सुनो आप। आपको भी मौका दूंगा बीच-बीच में बोलने का। पीपलू की प्रत्येक पंचायत में बी.जे.पी. के कार्यकाल में पानी चला गया था, उसकी वाहवाही लूटने की जरूरत है नहीं। (व्यवधान)

सच्ची बात बताता हूं, उस पर यकीन किया जाए, झूठ बोलने से क्या फायदा? पाइप भी पड़ी हो न निवाई में, देवली में और उनियारा में। घोषणाएं तो हो रही हैं चारों के चारों बजट भाषण में कि दिया जाएगा, विचाराधीन है, सरकार भी विचाराधीन है, सारी चीज है, पर सच्चाई में एक भी पाइप किसी गांव में पड़ी हो तो। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूरी टंकियां बन गयीं, मेरे विधान सभा क्षेत्र के पूरे गांव जुड़ गये, चार एम.एल.ए. में से तीन कांग्रेस के हैं और मैं निर्दलीय हूं, मेरे तो क्यों आ गया और इनके क्यों नहीं आया?

यह तो भला हो भंवरी का और उन फिल्मों का जो मुख्य मंत्रीजी ... (व्यवधान) फिर वही बात। मैं सच्ची बात कहता हूं, 2010 में मुख्य मंत्रीजी ने मेरे को जन्म दिन की मुबारकबाद दी थी। मैंने कहा था, मुख्य मंत्रीजी, पानी मैं प्याऊंगा अबकी बार, टोंक जिला ने तो नहीं पीया। सारी फिल्में दिखाऊंगा-इन नेताओं की भी और यह भंवरी वाली भी। सारी ताजी-ताजी रखी थीं। तो मेरे को सी एम ओ बुलाया गया। कल मुख्य मंत्रीजी आएंगे, उनके आगे यही बात पुछवा लेना और वह फिल्म यहां रख दूंगा, देख भी लेना। मेरी सी एम ओ में तलाशी ली, मेरा फोन रखवा लिया। फिर अन्दर ले जाकर, भई, ऐसा है, रणवीर, क्या तकलीफ है तुझे? मैंने कहा कि पानी के नाम पर पानी की तकलीफ है। हमारा बीसलपुर का पानी चला गया बाहर, वहां नागौर तक मांग हो रही है और हमारे पानी है ही नहीं। मेरी आंखों के आगे फाइल पर साइन करवाकर लाया था। झूठ हो तो कल मुख्य मंत्रीजी यहीं आएंगे।

भंवरी को क्या कहूं, देवी कहूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही। और कुछ वो नेताओं की फिल्म थी, जिन फिल्मों को दिखा कर तो मैं मुश्किल से पानी लेकर आया, इनको पानी देंगे। मार दी जनता इन्होंने, पच्चीस वर्ष हो गये वहां पर।

अभी घोषणा की है कि 500 करोड़ का बांध ईसरदा में बनाया जाएगा। सभापति महोदय, बीसलपुर डैम का जो कैचमेंट एरिया है वह आबू रोड से शुरू होता है, उस पर चौरासी हजार एनीकट बन गये। उसका पानी वहीं पर

(श्री रणवीर पहलवान)

रुक जाता है। बीसलपुर डैम खाली होने के बाद दो साल में भरने की भी, बारिश कितनी ही ज्यादा आ जाए, ऐसे तो राजस्थान कोई चेरापूंजी तो है नहीं कि रोज बारिश आएगी, वो कैचमेंट एरिया के जितने भी एनिकट, डैम बनाये हैं, इस बांध को नहीं भरने देते हैं। इस बांध से तीस-चालीस किलोमीटर आगे पांच सौ करोड़ की लागत से ईसरदा डैम बनाना, मैं समझता हूं, इस 500 करोड़ की बंदरबाट होगी, इसे जीमा जाएगा, वहां कुछ होना जाना है नहीं। अगर यह किसी तरह बना दिया तो यह भरने की तरकीब बता दें मेरे को कि उस बांध से कैसे भर देंगे। वह सिर्फ एक लूट का तरीका है। पहले रिश्वत आदमियों से ली जाती थी, आजकल बड़े बड़े प्लान बनाकर उन प्लान का दस बीस परसेंट लगाकर बाकी को खा-पीकर अफसरों के दस्तखत करवा लेंगे, और कोई लेना-देना है नहीं।

मैं टोंक जिले का जिक्र करूं, हरित राजस्थान के अन्दर टोंक जिले के अन्दर, यह मेरे विधान सभा के प्रश्न में उत्तर आया है, प्रत्येक पेड़ की कीमत 326 रुपये बताई गई है। टोंक जिले के अन्दर इतने पेड़ बताये गये हैं कि पहाड़ और एनीकट उसमें से निकाल दें तो हर दो मीटर पर एक पेड़ होना चाहिए। बाकी अन्य जिलों में 28, 30 और 35 रुपए तक एक पेड़ की कीमत आयी है। इसकी जांच विधान सभा में पहले भी मैंने कहा था, लेकिन आज तक कोई जांच नाम की चीज इसकी हुई नहीं। यह इतनी बड़ी लूट हुई है अन्दाजा लगाया जाए, एक जिले के अन्दर दो मीटर पर पेड़। दस किलोमीटर पर ही एक दिखाई नहीं दे रहा। पेड़ों की संख्या इतनी है, प्रत्येक पेड़ को 326 रुपए का बताया गया है। विधान सभा के प्रश्न में उत्तर दिया है। यह हरित राजस्थान नहीं मेरे ख्याल में इतना सूख जाएगा कि आदमी भी सूख जाएंगे।

1982 में रामगढ़ बांध में एशियाड हुआ था तो नौका दौड़ इसी के अन्दर हुई थी। एक गांव में एक पंडित रहता था। कोई बीमार होता तो उसको गोली दे दिया करता। पांच रुपये लिया करता था फिक्स। अकाल पड़ गया तो पांच रुपये भी नहीं बचे जनता के पास। तो उसने सोचा कि पर्ची बनाकर दे देता हूं। वायरल वगैरह होता है गांव में, तीन दिन में ठीक हो जाएगा। एक लड़का आया, उसने कहा, पंडितजी मेरे पिताजी के नाक से पानी टपकता है। तो उसने पर्ची बनाकर दे दी, गले में बांध देना, बेटा, तीन दिन में ठीक हो जाएंगे। लड़का पढ़ा-लिखा था, थोड़ी दूर जाकर उसने देखा तो उस पर्ची पर लिखा था

(श्री रणवीर पहलवान)

+++ वापस आकर बोला कि यह क्या लिख रखा है। बोला, क्या तकलीफ है तेरे बाप के? बोला, नाक से पानी टपकता है। बोला, इसके नाम से बड़े-बड़े बांध सूख गये, तीन बूंद पानी तो गले की तरफ करते ही सूख जाएगा। जैसे ही गले की तरफ करेगा, पानी फट से सूख जाएगा, चिन्ता ही मत कर।

इस बांध को बूंदी से जोड़ा जाएगा। तीन महीने सरकार के रह गये, यह बांध जोड़ना था तो चार वर्ष आपके ही पास थे, हमने कब मना किया था? गंगा जी से, हरिद्वार से कहीं से जोड़ते, इस बांध को जोड़ देते। (व्यवधान) अगले पांच साल आए तो इन्दिरा राजीव क्यों मरे थे, आपकी साजिश थी क्या? उनको क्यों नहीं बचाया गया? जब भविष्यवाणी ही करते हो तो उनको क्यों नहीं बचाया? यह मैने पहले कही थी न कि भविष्य के बारे में जानकारी है तो इतने बड़े-बड़े नेता मरवा दिए, उनको क्यों नहीं बताया कि कल की सभा में मत जाना, आफिस मत जाना, वे बच जाते न!

पांच सौ करोड़ रुपए मिसिंग सड़क लिंक में देना अभी प्रस्तावित किया है। ये सड़कें कौन से जिले की हैं, यह कुछ नहीं बताया गया। समस्त विधायकगण से मांगी जाएगी कि नहीं? मैं तारीफ भी करता हूं। पहले 8-8 किलोमीटर की सड़क दी थी, क्या समस्त विधायकों को उसी तरह से दी जाएगी? या मनमर्जी से लगाई जाएगी तो मान्य नहीं होगा। समस्त विधायकों को कल गहलोत साहब कहते हैं तो हम उसकी तारीफ भी करेंगे। ऐसी बात नहीं है। आपने कोई भला काम किया और हम कहें कि नहीं किया तो यह गन्दी बात होती है। मैं आशा करता हूं, समस्त विधायकों को इस 500 करोड़ में बीस-बीस किलोमीटर की या तीस किलोमीटर या पांच सौ किलोमीटर की कितनी सड़कें आपने बताई हैं, ये बन जाएं तो अच्छी बात होगी।

अभी इतनी भारी घोषणाएं की गई हैं- प्रत्येक गांव में विद्यालय, महाविद्यालय और मेडिकल कालेज, कल परसों ही विद्यार्थी बढ़े हैं क्या राजस्थान में? एकदम विद्यार्थियों की इतनी बाढ़ आ गयी? राजस्थान में आपकी चार साल से सरकार थी, उस सरकार में आपको पता था कि राजस्थान के गरीबों के बच्चे अनपढ़ बैठे हैं, उनके लिए स्कूल नहीं हैं। आते ही आप इस चीज को लागू करते तो शायद अब तक पूर्ण भी हो जाती। अभी आपने घोषणा की है कि नब्बे हजार मास्टर भर्ती किये जाएंगे, पूरे राजस्थान को महाविद्यालय बना देंगे। एकदम इतनी एजुकेशन की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए थी। अगर यह

(श्री रणवीर पहलवान)

पड़नी भी चाहिए थी तो आपकी सरकार आते ही इन चीजों को परिपूर्ण करके इनमें विद्यार्थी पढ़ता दिखा देती। हम अगर आपकी बुराई करते तो पापी होते।

(17.36 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

राजस्थान की जनता पूरी की पूरी यह कह रही है कि इन बजट भाषणों पर यकीन करें तो करें कैसे, जो चुनाव घोषणा पत्र पहले के थे वो घोषणा पत्र ही पूरे नहीं हुए। एक लाख नौजवान प्रत्येक वर्ष भर्ती करेंगे, यह भी कर देंगे, वो कर देंगे, वो जोड़ देंगे और ये जोड़ देंगे, बांध बना देंगे और यह कर देंगे। कोई एक भी चीज बनी हो तो हमें बतायी जाए।

मेरे खयाल में मुख्य मंत्रीजी ने यहीं पर सबसे पहले बजट भाषण में कहा था कि झुन्झुनूं के अन्दर एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। वह आज तक कोई पत्थर रखा हो तो हमें बता दो। इन विद्यालयों पर कब तक यकीन करेगी जनता? जो आज घोषणा कर रहे हो, तीन महीने बाद मैं नहीं मानता। समस्त भारत में जिस तरह साफ होते जा रहे हो, यहां सरकार लाने की नहीं। 15-20 एम एल ए की सोचो कि दुबारा कौनसा आ जाए, विचार करना। सरकार ले आओगे। सरकार ले आते तो बिहार में चार सीट आयीं, उत्तर प्रदेश में कुछ लेना-देना नहीं, पंजाब में नहीं, गुजरात में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, कहीं आयी क्या दुबारा? साफ होते आ रहे हो पूरे भारत के अन्दर। समस्त भारत समझ गया है कि +++ ।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): एक तो ममता आयी।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): रिफाइनरी का इतना बड़ा चक्कर है, हमारे बीसलपुर बांध है उसका पानी जयपुर में आ रहा है। उसका फिल्टर प्लाण्ट उसके पास में लगाया गया है। यह रिफाइनरी उसका फिल्टर प्लाण्ट वहां नहीं लगाकर गुडगांव लगाकर फिर जयपुर में पानी लाते। सिलीगुढी में लगा दो इस रिफाइनरी को और फिर वहां से तेल लाना। रिफाइनरी बना दी हमने! फिर सरकार कहती है, ऊपर भी इनकी सरकार और नीचे भी इनकी सरकार। वह कहती है, नहीं, एक बार सिलीगुढी लगाएंगे, वैस्ट बंगाल में नहीं फिर दूसरी जगह लगाएंगे। +++ कहीं भी लगा लो, उसमें तेल खरीदोगे क्या? कुछ फायदा करोगे, वह समझा दो हमें। जहां पर तेल निकलता है उसकी रिफाइनरी वहीं लगती है, दुनिया जानती है। आप फिल्टर प्लांट दिल्ली में

(श्री रणवीर पहलवान)

लगाकर फिर जयपुर में पानी लेकर आओगे? वह बांध के पास ही लगा दिया, बीसलपुर डैम के पास ही लगा हुआ है फिल्टर प्लांट और उसका पानी फिल्टर करके जयपुर को दे रहे हो।

रिफाइनरी लगा देंगे, अशोक गहलोत साहब पसीना-पसीना हो रहे हैं, रिफाइनरी के लिए दण्ड बैठक मार रहे हैं, कभी कसरत कर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं। यह लगनी ही है, और लग ही नहीं सकती कहीं। राजस्थान में इसका तेल आएगा और रिफाइनरी आप वैस्ट बंगाल में लगाओगे तो फिर एक पाइप दबाकर वापस भी तो लानी पड़ेगी न यहां तेल देने के लिए। यहां से पहले ले जाओगे कच्चे तेल को, फिर वहां से इसको फिल्टर करके वापस लाओगे, यूं? इतना दिमाग है तो कमाल की जनता थी जिससे आप चुने हो। फिर तो आप दुबारा आने ही चाहिए। (व्यवधान) बता दी, ममता तो आएगी, कोई रोक थोड़े ही रहा है।

हमारे रघु शर्मा से बात करो, कोई भी बोलेगा, तुम्हारी पार्टी में वो कौनसी पार्टी से आकर मिल गये हैं, जनता दल से। तुम भी क्या बोलते हो, इनका हर दल जनता दल से आया है। डेढ़ बार एम एल ए रहा +++, ढाई साल तो जनता दल से....

श्री सभापति: जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उनका नाम अंकित नहीं होगा, मैं आदरणीय समस्त सदस्यों को यह निवेदन कर रहा हूं। आपने अगर इस प्रकार की अभिव्यक्ति सदन में की तो आसन को सख्ती से कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सारी, सर। बहुत अच्छी बात है। मैं आसन की पूरी मर्यादाओं को ध्यान में रखता हूं। लेकिन आसन पर ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आप भी कुछ खा रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: अगर किसी भी सदस्य की शारीरिक अभिव्यक्ति भी ऐसी लगेगी कि इस प्रकार के कथन को बोलने में समर्थन प्रदान कर रहे हैं तो उनको भी प्रताड़ित किया जा सकता है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): क्षमा करें, सर। कई बार ऐसा होता है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आप भी आसन पर विराज कर कुछ खा रहे हैं, यह भी नियमों के प्रतिकूल है।

श्री सभापति: मैं आसन पर बैठकर सिर्फ विचारों का मंथन कर रहा हूं। वही खा रहा हूं और वही अभिव्यक्त कर रहा हूं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): कई बार इसी आसन से खूब बोलने का समय दिया जाता है और ऐसे-ऐसे शब्द बोले जाते हैं जिन शब्दों को बाहर भी नहीं बोलना चाहिये, अन्दर तो बोलने की जरूरत ही नहीं है और उनको टाइम दिया जाता है। सर, मैं तो सारी बोलता हूं। सर, मैं नहीं बोलूंगा।

आपने लिखा कि किसानों की भलाई के लिये हमने बड़े-बड़े वह खोल दिये और यह खोल दिये। ध्यान से सुनो, बड़े गौर से, 70 से 80 प्रतिशत ग्रामीण लोग हैं और वे किसान हैं, सन् 1970 में खाद का कट्टा 15 रुपये का मिलता था, 40 वर्ष में बढ़कर 2010 में खाद के कट्टे की कीमत 500 रुपये हो गयी थी। किसान को केवल खाद, डीजल और पैट्रोल ही काम में आता है, बाकी तीसरी, चौथी चीज कोई काम में आती नहीं। 40 वर्ष में खाद का कट्टा बढ़ता-बढ़ता 500 रुपये का हुआ। और 2010 में कौनसा आदेश लाये थे? साढ़े बारह सौ रुपये का एक। एकदम साढ़े सात सौ रुपये एक खाद के कट्टे पर बढ़ा देना, मेरे खयाल में इससे बुरा तो किसान का किसी राज में हुआ भी नहीं होगा और आगे होने की उम्मीद भी नहीं है। दस परसेंट महंगाई बढ़ती है, बीस परसेंट बढ़ती है, तीस परसेंट बढ़ती है, पर एक ही दम दो सौ, ढाई सौ गुणा। जिस किसान के खाद बीस हजार रुपये की आती थी, मजबूर हो गया पचास हजार रुपये की खाद खरीदने को।

डीजल, पैट्रोल की बात करें तो डर लगता है सुबह का अख़बार उठाने से पहले। यह खबर जरूर छपेगी कि डीजल आज फिर बढ़ गया है। कितनी मिलीभगत की कुश्ती है, सभापति महोदय! भारत सरकार कहती है कि 8 रुपये डीजल, पैट्रोल बढ़ाया जाता है और हमारे मुख्य मंत्रीजी कितने विनम्र हैं। नहीं, मैं इस महंगाई को सहन नहीं करूंगा, 25 पैसे कम करता हूं इसमें से। यह न्याय करते हैं राजस्थान की जनता के साथ। 8-8, 9-9 रुपये की बढ़त और 25 पैसे कम करके वाहवाही लूटना। ऊपर भी आपकी सरकार है और नीचे भी आपकी सरकार है। धन्य हैं वो मुख्य मंत्री जिनकी कड़ी से कड़ी नहीं जुडी और आप उनको तोड़ ही नहीं पा रहे हो। चार-चार बार सरकार रिपीट कर रहे हैं। आपका तो ऊपर का खजाना भी आपका और नीचे का खजाना भी आपका और बांटने के लिये जनता बैठी है। दवाई फ्री, कच्छा फ्री, बनियान फ्री, साड़ी फ्री, +++

(श्री रणवीर पहलवान)

मेरे खयाल में, दी आज तक किसी को नहीं है। +++ मैं गिनवा सकता हूं। +++ और उन आदमियों के द्वारा जो रहबर बने बैठे थे राज्य के और राष्ट्र के। कह रहे हैं, हम साड़ी भी बांटेंगे, कच्छा भी देंगे, अंडरवियर भी देंगे, मूली भी देंगे, गाजर भी देंगे। चुनाव आ गया, मेरे खयाल में, जान भी दोगे थोड़े दिन में। यह भी देनी पड़ेगी।

मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलकर, सभापति महोदय, इतना कहना चाहता हूं, ये चीजें मेरी अपनी नहीं हैं। इस बात पर राजस्थान हाई कोर्ट कह चुका है कि सदी की इतनी निकम्मी, बेइमान और भ्रष्ट सरकार सदी में नहीं देखी कहीं। मैं हाई कोर्ट में थोड़े ही बैठा था ? वह तो हाई कोर्ट के फ्रंट पेज पर छपी है।

आज लोकतन्त्र का स्तम्भ सरपंच के कंधों पर टिका होता है। तीन ही पद होते हैं राज्य और राष्ट्र में- पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, राज्य का मुखिया मुख्य मंत्री होता है, राष्ट्र का प्रधानमंत्री होता है। करीब सवा नौ हजार सरपंच जयपुर में बुलाकर उनको जिस ढंग से लट्ठों से और जूतों से मारा, वे सरपंच क्या आपको याद नहीं करेंगे? उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बी जे पी को वोट डालने वाले ही सरपंच थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र के हावड़ा का भंवर लाल सरपंच कांग्रेस का ऐसा मठाधीश है जैसे ह्यूम कोई पैदा करके छोड़ गया था कांग्रेस खड़ी करते ही। वह कांग्रेस का लगाये रहता है बड़ा-सा गेट। वह सुबह-सुबह मेरे घर आया। कच्छा पट्टे का था, धोती फट गयी, कमर पर कामड़ी लगी हुई थी। चप्पल मैंने लाकर दी उसको। मैंने पूछा, सरपंच साहब, ये का ये कांग्रेस का निशान छपवा कर लाये हो। यह बच गया। इनके भी थे।

वकीलों की यह हालत है। पुलिस वालों की यह हालत है। दोनों लट्ठों में आपस में खड़े कर दिये। क्या गुनाहगार मैं हूं? राज्य सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है? दो पढ़े-लिखे वर्ग जब रोड पर खड़े हैं तो उनका मीडियेटर बनना, उनका समझौता करना किसका काम है? विपक्ष का और हमारा काम है कि आपका काम है?

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

कोई बात नहीं, सभापतिजी, ये बोलें उतना समय, हमारा तो डेढ़ घण्टा है निर्दलीयों का और निर्दलीय मैं अकेला हूं। इनकी भी मैंने ले ली पावर आफ अटार्नी। तो हमारे डेढ़ घण्टा तो बोलने दोगे, माननीय सभापति जी।

सभापति महोदय, कौनसा वर्ग है- पुलिस है, वकील हैं, सरपंच हैं, नर्स हैं, पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, अध्यापक हैं, सब जो इनका लट्ठ नहीं खाकर गये

(श्री रणवीर पहलवान)

हों। और ये कह रहे हैं, दुबारा सरकार आएगी। ये गांव में नहीं गये मेरे खयाल में। लेनिन को जब दरबार में बुलाया था तो जार ने कहा था, मिस्टर जार, मेरे खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। क्लिंटन ने ताली बजायी थी कि वह गांव, ढाणी की बात, मिस्टर जार, आपके सिंहासन तक आ गयी है तो रशिया के अन्दर बहुत कुछ हो चुका है। और हुआ यह अगले दिन वह सिंहासन से नीचे उतर गया था।

गांव-गांव तड़प चुका है, मेरी गारण्टी है इस बात की। आप गांव जानते हो। आपकी यहां तक बात आयी है। निकालने में डर लगता है कि अपनी ही सरकार की बुराई कैसे करें। आप इस किताब से बाहर बोल भी क्या सकते हो? और इस किताब के अन्दर ही कुछ बोलोगे तो यहां तो मुख्य मंत्रीजी बोलकर सुना गये थे सबको, इसमें फिर दोहराना। मुख्य मंत्रीजी ने यह भी बहुत अच्छा काम किया। 2003 में भी किया था बहुत अच्छा काम, कर दी थी न रिपीट आपने? 2003 में अगर अच्छा काम किया होता तो आपकी सरकार चलती। हम मना कहां करते हैं। हां भरते इस जनता के सामने। आपको सपोर्ट करने के लिये कितनी बड़ी भारत सरकार बैठी है। फट से एक मिनट में कह देते हैं कि यह मुख्य मंत्री तो बाहर से आयी है। हमें पता ही नहीं, इटली से कौनसी जगह से +++ आयीं ? आज कौनसा रोग उसका होता है, वहां डाक्टर मिलते हैं कि राष्ट्र के दलाल मिलते हैं?

श्री सभापति: मैं फिर, सम्माननीय सदस्य, आपसे....

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अच्छा, क्षमा करें, साहब। थोड़ी जुड़ी हुई कड़ी थी इसलिये कह गया मैं। माफ करो...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): यह तो हर बार लेते हैं नाम। यह तो बार-बार उन्हीं का नाम लेते हैं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): इसको निकाल, मैं तो क्या देश की जनता बराबर निकाल देगी...

श्री सभापति: आसन की बगैर अनुमति से जिसने भी कोई बात अभिव्यक्त की है वह अंकित नहीं होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अंकित मत करो। इसको निकाल दो। पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिये। वह स्वीकार कर लीं इन भाइयों ने तो हमें कहां आपत्ति है, करे रखो। कभी कहते हैं, कांग्रेस राष्ट्र को आजाद

(श्री रणवीर पहलवान)

करवाने वाली पार्टी है। कांग्रेस की नींव का पत्थर मिस्टर ह्यूम इस देश का था ही नहीं। उन्हें लोकतन्त्र दिखाना था एक बार यू एन ओ के अन्दर तो यहां पर अरजी-फरजी मोहरे इकट्ठे करने थे। जिस पार्टी की नींव ऐसी जगह रखी हुई है, जिसका कोई सोच नहीं, विचार नहीं, जिसका कोई भी लेना-देना नहीं हो उस पार्टी! फिर भी चलो। और कौन से इनके मां-बाप कांग्रेस के अन्दर नहीं थे? हमारे बुजुर्ग कांग्रेस में नहीं थे? क्या कांग्रेस में ये ही थे? क्योंकि जब दूसरी पार्टी कोई थी ही नहीं, पूरा राष्ट्र कांग्रेस के सान्निध्य में ही काम कर रहा था। उस कांग्रेस में महान नेता हुआ करते थे, हम तारीफ भी करते हैं। गांधीजी थे, 65 वर्ष में कपड़े नहीं पहना पाये, आज भी नंगा ही बिठा रखा है। कोट तो पहनाते न, भाई? यह नेता आपका ही हो गया, हमारा नहीं है क्या? हम भी इनके सान्निध्य में, हमारे बुजुर्ग काम करते होंगे। सरदार पटेल थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। सुभाष चन्द्र बोस 1939 में अध्यक्ष थे आपकी पार्टी के। वे कोई नेता थे? आज सुरेश कलमाड़ी, कनिमोझी, ए राजा, भंवरी देवी, ये आपकी सरकार में हैं...

श्री सभापति: मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं और अगली बार, सम्माननीय सदस्य, मैं निवेदन नहीं करूंगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सर, मैं तो आपकी सज़ा भी प्रेम से ही लूंगा।

श्री सभापति: आप अपनी अभिव्यक्ति को...

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): राज्य की जनता...

श्री सभापति: सदन के नेता द्वारा प्रस्तुत बजट तक सीमित रखें। राजस्थान के विकास और राजस्थान की जनता की जो अपेक्षाएं आपसे हैं, उन तक सीमित रखें। और अभिव्यक्ति को एक निश्चित समय अवधि में आप कनक्लूड भी कर दें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ऐसा है, मैं आपकी सज़ा को भी इनाम समझूंगा। ऐसी बात नहीं है। आप सज़ा भी मेरे को पोलाइटली दोगे, ऐसी कठोर नहीं दोगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

आज सुबह ही यहां पर प्रश्नकाल के दौरान चर्चा चली। बड़ी कमाल की चर्चा थी। उसमें कहा गया कि तीन सौ से ज्यादा आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये हैं। उसमें इतने कलक्टर लिप्त पाये गये हैं। उन पर कोई

(श्री रणवीर पहलवान)

कार्यवाही नहीं होना। परन्तु मैं पंचायती राज मंत्री का तहे दिल से आभार करता हूं वह नेक आदमी हैं। सच्ची बात कहता हूं, या तो इनके ध्यान में नहीं आयी होगी यह बात, या ऊपर का दवाब इनके ऊपर आ गया होगा तो उनको सज़ा नहीं दे पाये होंगे। मेरी गारण्टी है इस बात की। तो फिर अजमेर का एस पी और यह महिपाल मदेरणा इनको निकालो न, ये अन्दर क्यों पड़े हैं? फिर जब भ्रष्टाचारियों को इस तरह इनाम ही देना है तो वह एस पी अन्दर क्यों डाल रखा है, उसको बाहर करो। और एक एवार्ड बनवा लो, भ्रष्ट जो बड़ा होगा, उसको बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। छोटा होगा, छोटा दिया जाएगा। जब इस तरह लुटेरे खुले आम यह काम करेंगे। फिर आप कहते हो, बड़ी पारदर्शी, नेक, चरित्रवान, ईमानदार सरकार है हमारी।

अपनी चम्बल घाटी तो राजस्थान से लगती हुई है, सभापति महोदय। मेरी गारण्टी है, चम्बल घाटी में बहन-बेटियां, यहां भी विधान सभा में सदस्य हैं, औरों पर एक्सपेरिमेंट मत करो, इन पर ही कर लो। इनको दो-दो किलो सोना-चांदी पहना करके चम्बल घाटी में भेज दो, अगर एक भी लुट जाए तो मैं गारण्टी लेता हूं। दिल्ली भेज दो, इज्जत और गहना दोनों ही बच जाएं तो मेरी गारण्टी है। यह हाल तो राष्ट्र की राजधानी का कर दिया। यह मैंने किया है क्या? यह कोई कम है? बड़ा काम किया था, सारे चम्बल घाटी के डाकू पार्टी में शामिल कर लिये और इस देश को लूटने का काम उनको दे दिया। पहले शस्त्र से लूटते थे, अब कलम से लूटने लगे। और लूट बदस्तूर जारी है। पता चल गया उनको। इसकी बानगी तो गयी थी, वह बन गयी थी नेता, क्या नाम फूलन देवी। फिर उसके बाद चम्बल घाटी खाली। उनको पता चला, दिल्ली में बैठकर ज्यादा लूटा जाता है। इतने-इतने बड़े घोटाले इस राष्ट्र में हुए कि अंग्रेज भी इस बात को कहने को मजबूर हो गये कि 250 वर्ष के राज्य में हम इतना भारत से नहीं लूटकर लाये जितना भारत में इन्होंने लूटा। राजस्थान के पांचों बजटों से ज्यादा तो अकेला कलमाड़ी ने ही लूट लिया। फिर दूसरा भाई और था, उसने 1 लाख 76 हजार करोड़ लूट लिये। ये किसके लूटे? खजाना खाली हो गया।

सभापति महोदय, पता था कि किसान फसल बीजेगा, उसको खाद की जरूरत पड़ेगी, 500 का कट्टा साढ़े 1200 का कर दिया। यह किसान और मजदूर की जेब की लूट है। उसकी जेब से पैसे निकले हैं। फिर भर लो उस

(श्री रणवीर पहलवान)

खजाने को और फिर लूट लो। 18 हजार करोड़ लीटर डीजल-पैट्रोल, 19 हजार 76 सौ लीटर डीजल-पैट्रोल एक दिन के अन्दर बिकी है। उस पर 5 रुपये बढ़ाने का मतलब कितने होते हैं? 18 हजार गुणा 5 यानि 80 हजार करोड़ के आसपास प्रत्येक दिन इनके पास जाता है। और चुनाव से पहले कहते हैं कि 60 हजार करोड़ रुपये किसानों के माफ किये जाते हैं। 60 हजार करोड़ में भारत को खरीदना चाहते हैं। किस किसान के माफ होते हैं, यह हमें आज तक पता नहीं चला। मालपुरा का किसान समझता है कि निवाई वालों के हो गये होंगे। निवाई का समझता है कि अजमेर वालों के हो गये होंगे। वह सोचता है कि झुंझुनूं वालों के हो गये होंगे। आज तक किसी का पैसा माफ हुआ नहीं। कोई लेन-देन है नहीं। लेकिन इस तरह की असत्य बात जनता के सामने बोल रहे हैं।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): सूची दिखा दो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सूची भी है मेरे पास।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): दिखा दो।

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, कनक्लूड करें। पिछले 40 मिनट से आप बोल रहे हैं। 5.25 से आपने शुरू किया था।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, हमारा डेढ़ घंटा है निर्दलीयों का, बीजेपी का और कांग्रेस का अलग टाइम है।

श्री सभापति: प्रतिपक्ष से 22 व्यक्ति हैं जिसमें से 4 बोल पाये हैं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, मैं इसके बाद बैठ जाऊंगा। मैं इस पवित्र सदन में दुबारा आ पाऊं या नहीं आ पाऊं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सत्ता पक्ष से 3 व्यक्ति बोल पाये हैं। अगर इन सभी को बोलना है तो मुख्य सचेतक से मैं निवेदन करुंगा कि वह यह बात सुनिश्चित कर लें कि कल सवेरे तक इस सदन की कार्यवाही को चलाएं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): आप मुझे केवल पांच मिनट दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: जो बाकी बोलने वाले व्यक्ति हैं, वह अपना-अपना समय कटौती करके अगर माननीय सदस्य को प्रदान करना चाहते हैं तो प्रदान कर दें। अन्यथा आप बाध्य करेंगे आसन को कि मैं दूसरे का नाम पुकारूं।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): मेरा समय मैं इनको प्रदान करता हूं।

श्री सभापति: वह तो आपका ले चुके हैं वह।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): प्रदान तो आप करेंगे, सभापति महोदय। यह भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, आपका समय तो यह ले चुके हैं। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, एक मिनट रुकें, वह तो मुझे भी मरवाएगा। (व्यवधान) मेरी एक प्रार्थना है, वह कौन प्रदान करने वाला है। हमारा निर्दलीयों का जैसे डेढ़ घंटा है, जैसे बीजेपी का अलग बांट दिया था, कांग्रेस का अलग, उसमें तो हमें रो लेने दो हमारा दु:ख। दुबारा मैं शायद सदन में आऊं कि नहीं, यह मेरे को तो पता नहीं, कांग्रेसियों को तो पता है।

सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है, 2003 में मैंने इनकी सारी सरकार की फिल्म बनाई थी रुपये लेते हुए की, वह एक मैटर था फाइल का, वह फाइल मुख्य मंत्रीजी के कार्यालय में थी। मुख्य मंत्री के ये चेले-चपटे- गृह मंत्री, यूडीएच मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री, ये सब पैसे मांग रहे थे। उनकी मैंने वीडियो फिल्म बना ली थी। क्योंकि अजमेर के एसपी को तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन मुख्य मंत्री को और गृह मंत्री को पुलिस कैसे पकड़ेगी। पुलिस तो उनके नीचे है। उनकी बदली ही वह करते हैं, तो उनको पकड़ नहीं सकती है। मैंने अपने प्राणों की बाजी लगा डाली। कल सदन में मेरी वह फिल्म पूरे सदन को दिखाई जाए, ऐसी मेरी प्रेयर है, राज्य की जनता भी देख सके। न्याय ये नहीं तो जनता देगी।

सभापति महोदय, अगर फिल्म असत्य हो तो साइनाइड मैं कहीं से मंगवा लूंगा, नहीं तो गहलोत साहब खुद मंगवा लेंगे, सरकार है, मैं खा लूंगा इधर, नहीं तो वह खा लेंगे उधर। मेरी गारंटी है, अगर वह फिल्म एक भी गलत हो तो। अगर फिल्म सही है तो फिर ये किसलिए सत्ता में बैठने योग्य हैं? +++ और उनकी डाक्यूमेंट्री फिल्म, उनके खुद के मुंह से बोली हुई फिल्म मैं पूरे भारत के टेलीविजन चैनलों पर दिखा चुका हूं।

सभापति महोदय, उसके उपरांत मेरे को कहा गया कि यह बीजेपी का स्टंट है। आप बीजेपी वालों की बना लो न, मैंने कब मना किया था? बीजेपी उन नेताओं की गर्दन पकड़कर लायी थी क्या कि आप फिल्म बनवा लो? वह

(श्री रणवीर पहलवान)

रिपोर्ट लिखवा देते कि हमें पकड़कर ले जा रहे हैं। अगर मैं बीजेपी का इतना ही हितैषी होता और बीजेपी मेरी इतनी संरक्षक थी तो मैं निर्दलीय ही क्यों लड़कर आता? मैं टिकट ले लेता उनसे अगर मैंने समझौता करके ही फिल्म दिखाई थी तो। लेकिन मैं निर्दलीय लड़कर आया हूं। यह क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले मुख्य मंत्री हैं, वह अपने आपको कह चुके हैं कि 7 पीढ़ी तक मुझ पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। तो मैं घोषणा करता हूं कि +++ मैं फिल्म दिखाऊंगा और अगर फिल्म गलत हो तो मैं यही जहर सदन में खाने को तैयार हूं। दस्तखत करके दे दूंगा। यह बच्चों का खेल नहीं है, मेले में खेल लेना। यह फिल्म है नेताओं की रिश्वत लेते हुओं की। यह कोई मैं मेलों की बात कर रहा हूं क्या? भंवरी नाचने गयी थी और आपने देख ली और महिपाल ने। यह तो सच्ची डाक्यूमेंट्री फिल्म है। मैं इस सदन का सदस्य हूं और जब मैं, इस सदन का सदस्य न्याय की बात नहीं कर सकता हूं तो मेरी 2 लाख जनता कहां बात करेगी? उसने भेजा हूं यहां मैं। कल मैं टेलीविजन का इंतजाम कर दूंगा, मुझे परमिशन दी जाए और इस सदन की लाइट बंद करके उन फिल्मों को प्रेमपूर्वक 200 सदस्य यहां देखें और न्याय करें कि वास्तव में कौन गुनाहगार है। वह क्या चीज थी? +++ मैं भी जानता था कि पैसे देने नहीं हैं। काम कुछ नहीं था। जमीन एक्वायर की, उसका मुआवजा था 15 प्रतिशत किसानों का, वह देना था। उन किसानों को मुआवजा देने की एवज में यह रिश्वत मांगी जा रही थी।

सभापति महोदय, मैं भी एक किसान बन गया, कहा, कि मेरी भी इसमें जमीन है। किसानों की तरफ से हमने एक टीम बना ली है। और इतनी बढ़िया तरीके से मांगते, वहां बैठा है मैम्बर, उसका पिताजी ही था। टिकट दे दी इसको। इतनी बढ़िया तरीके से खुद रिश्वत मांग रहे हैं कि +++ उसके उपरांत आपका काम हो जाएगा। उस फिल्म में मैं और मेरा पिताजी नहीं बोल रहे हैं, +++ वह फिल्म देखकर अगर वह खुद निर्णय कर दें कि रणवीर गलत है तो मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा और राज्य को भी त्याग करके चला जाऊंगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): नाम तो यह बताएं सदन में, हम सब लोग लाभान्वित होंगे। नाम बताओ जिस मंत्री ने यह कहा है।

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, अब आप अपनी बात को कनक्लूड कर लें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, यह व्यवस्था तो आसन देगा मुझे। मेरे घर वाले थोड़े ही देंगे! अभी तो आप कह रहे थे कि सज़ा दे दूंगा तो फल भी तो आप ही दोगे न।

श्री सभापति: अब आप अपनी बात को कनक्लूड कर दें। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): फिर इस सदन का क्या महत्व है? अगर सारी ही बातें कैंसिल कर दें और सारी ही निकल जाएं तो फिर इसका मतलब क्या है? हमें परमिशन प्रदान करें, मैं बाकायदा टीवी इन गांधीजी के नीचे लगाकर एलसीडी और तार लगाकर...

श्री सभापति: आसन आपको यह निर्देशित करता है, आपको यह प्रार्थना करता है। नियमों के आधार पर जो कुछ भी सम्भव होगा, आसन उससे बंधा हुआ है। नियमानुसार आसन कार्यवाही करने के लिए बाध्य है। आपने जो भी अपना कथन कहा है, जो नियम तक सीमित है, वह तो स्वीकार किया जाता है और जो नियमों के परे है, वह अस्वीकार किया जाता है। कृपा करके अब विराज जाएं। आदरणीय महेन्द्र सिंहजी गुर्जर। आदरणीय महेन्द्र सिंहजी गुर्जर। धन्यवाद।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, मैं एक ही सैकण्ड लेता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय महेन्द्र सिंहजी गुर्जर। (व्यवधान) अब अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री सभापति: अब अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): इधर से तो बोल चुके ओ.पी. यादव साहब। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री सभापति: कृपा करके आप विराज जाएं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री सभापति: आप 2 मिनट विराज जाएं, मैं आपसे कुछ निवेदन

(श्री सभापति)

करना चाहता हूं। 5 बजकर 25 मिनट पर आपने अपनी बात अभिव्यक्त करना शुरू की थी, 6 बजने वाले हैं। अगर इसी प्रकार से हरेक सदस्य समय का विभाजन करने लगा तो संसदीय मंत्रीजी भी यहां विराजे हुए हैं, प्रतिपक्ष के वरिष्ठ नेतागण भी यहां हैं, आप बैठकर तय कर लें ...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री सभापति: आपसे किसने पूछा? आप विराज जाओ।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री सभापति: यह दोनों सचेतकों को बैठकर तय करना है कि आज के सदन की कार्यवाही को मध्य रात्रि के उपरांत भी चलाना चाहते हैं और तथ्यों के अलावा जो कुछ भी हमारे पास में समस्त राजस्थान के सम्बन्ध में जानकारी है, और राष्ट्रीय स्तर की, अंतरराष्ट्रीय स्तर की, सभी का विवेचन यहां करना चाहते हैं। तब तो आप यह तय कर लें। वरना अपनी अभिव्यक्ति को बजट की सीमाओं तक रखते हुए, जहां से आप आते हो, जिस जनता का आप प्रतिनिधित्व करते हो, वहां तक सीमित रहते हुए अपनी बात को अभिव्यक्त करें। मैंने दूसरा नाम पुकार लिया है। आसन अब इजाजत किसी को नहीं देता। श्री महेन्द्र सिंहजी गुर्जर। इनके अलावा किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद): सभापति महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री, जन-जन के मसीहा, बजट पर बहस चल रही है और मालपुरा से आने वाले सदस्य ...(व्यवधान) रिकार्ड क्यों बनाया इन्होंने? कैसेट किस मतलब से बनाई इन्होंने? (व्यवधान) इनकी भी कुछ गर्ज होगी कैसेट बनाने में। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद): इनका भी कुछ हिस्सा होगा उसमें ...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद): जमीनों का कारोबार करते थे जयपुर में ...(व्यवधान) जमीनों का कारोबार करते थे माननीय मालपुरा से आने वाले सदस्य, इसलिए कैसेट बनाई है ...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

(18.00 बजे)

श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद): आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट दिया है, प्रतिपक्ष वालों ने कहा है, क्या बजट दिया है।

श्री सभापति: अंकित महेन्द्र सिंहजी के अलावा किसी का नहीं होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): **×××**

श्री सभापति: आसन पांवों पर है। विराज जाओ। आसन पांवों पर है, विराजिये।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): **×××**

श्री सभापति: जहां जो बात कहनी है वहां वह बात कहिये। यह स्पष्ट है कि महेन्द्र सिंहजी को आसन ने इजाजत दी है, आप अपनी बात अभिव्यक्त करिये। कोई व्यवधान डालेगा तो उसके साथ कठोरता से हम कार्यवाही करने को बाध्य होंगे। अब, महेन्द्र सिंहजी, आप अपनी बात अभिव्यक्त करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): **×××**

श्री सभापति: आप नहीं थे, सचेतक महोदय, आपको यहां विराजना चाहिए था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): **×××**

श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने जो बजट दिया है, उस बजट की चर्चा सदन में चल रही है।

श्री सभापति: एक मिनट और विराजें आप। आदरणीय राधेश्यामजी गंगानगर, आपका आपके बाद है क्योंकि आसन पर जब मैं आया था तो आसन की तरफ से एक निर्देश था, उसी निर्देश की पालना कर रहा हूं। कहा गया था कि इधर से आप एक हैं तो नैक्स्ट वाले में आपका है।

श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय, गांधीवादी मुख्य मंत्री ने जो बजट दिया है, उस बजट की चर्चा चल रही है। बजट इतना अच्छा और इतना बढ़िया है कि जो सदस्य हैं विपक्ष से आने वाले, उन्होंने भी इसकी तारीफ की है। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं कि मैंने कैसेट बनाई है, उसमें +++ पैसे मांगे

(श्री महेन्द्र सिंह)

गये हैं। मैं आज कुछ बनाऊंगा तो मुझे लाभ होगा, इस बात से, इस उद्देश्य से उन्होंने कैसेट बनाई है। राजस्थान के पूरे दो सौ विधान सभा क्षेत्रों में जो काम हुए हैं, आज यह इस बात को बोलना नहीं चाह रहे हैं इसलिए ...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद): बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य, आपने भाषण दिया यहां पर, मैं कुछ बोला? और वह बोल रहे थे। चुनावी साल है, आपने भी टिकट मांगा है। आपने भी दो बार टिकट मांगा, टिकट से आपका क्या हाल हुआ है वह आपको मालूम है।

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, आपसे भी निवेदन है कि बजट के सम्बन्ध में आप बोलें। अब यहां का वातावरण सौहार्दपूर्ण बने तो कम से कम आसन ऐसा निवेदन करता है कि आप बजट तक इसको सीमित रखें।

श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद): जो बजट आया है, सार्वजनिक निर्माण विभाग में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राज्य में सड़कों के विकास कार्य करवाये हैं। माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, 500 करोड़ रुपये लागत की निर्माण योजनाएं हैं, ये जीरो पाइण्ट से लेकर 250 तक की जनसंख्या को, पूरे राजस्थान में सड़कों से जोड़ेंगी।

ऊर्जा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शासन सम्भालने के तुरन्त बाद यह घोषणा की थी कि किसानों के लिए विद्युत दरें पांच साल तक नहीं बढ़ाएंगे। वह बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में जो काम हो रहे हैं, वह आप सबको मालूम है।

पेयजल के लिए अभी मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पांच सौ करोड़ ईसरदा बांध पर खर्च करेंगे, उसको भरेंगे कैसे। चार साल से राज्य में इतनी बारिश हो रही है, कोई बांध ऐसा नहीं है जो खाली हो, ईसरदा बांध भी भरेगा और इसमें 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह किसानों के लिए बहुत बढ़िया बात है। आप कह रहे हैं कि 500 रुपये का कट्टा 1200 रुपये में मिल रहा है। खाद की लागत बढ़ी है तो किसानों की आय भी बढ़ी है आज। आज 5000 रुपये क्विंटल कपास बिक रहा है, कभी जिन्दगी में सुना नहीं था कि 15000 रुपये क्विंटल ग्वार बिकेगा।

शिक्षा के क्षेत्र में जो बढोतरी हुई है, उसमें कहा गया कि इसकी घोषणा कर दी, उसकी घोषणा कर दी। आज ही बच्चे बड़े हुए हैं क्या? बच्चे

(श्री महेन्द्र सिंह)

तो धीरे-धीरे बड़े होते आ रहे हैं और बड़े होते रहेंगे। शिक्षा में स्कूल खोले हैं और कालेज खोले हैं, और भी खोलेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट दिया है शिक्षा के ऊपर, करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, वह पैसा खर्च होता रहेगा।

आप बोलते हैं कि चुनावी साल है, चुनावी साल है, कोई अच्छा कार्य होगा तो थोड़ी जलन तो होती ही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में जननी सुरक्षा के अन्दर दवाएं जानवरों के लिए, इंसानों के लिए और अब 7 अप्रैल से टैस्टिंग फ्री की है पूरे राजस्थान में। आज तक कोई ऐसा समाचार हमने नहीं पढ़ा न सुना कि इस दवा से कोई व्यक्ति मारा गया हो। अभी पहले सदन में बात उठी थी कि इतने व्यक्ति जयपुर आये और जयपुर में 3 लाख रुपये खर्च किये और मर गये, वापस चले गये। ये सारी बातें असत्य हैं, सबको मालूम है। यहां इतने माननीय सदस्य आते हैं, अपने-अपने क्षेत्रों में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, यहां आकर बोलने की बात ढूंढते हैं कि कैसे हम पक्ष वालों की खिलाफत करें, कैसे हम वाहवाही लूटें। यह सबको मालूम है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने देवनारायण योजना के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये बजट किया है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय मंत्रीजी को। एसबीसी वर्ग और विशेष वर्ग का ध्यान रखा गया, इसके लिए यह सम्पूर्ण वर्ग आपका हृदय से स्वागत करता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता में 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र का सदस्य नहीं होने की शर्त हटाने की जो हमारी मांग थी, पूरे सदन के सदस्यों की, उसको आपने हटाया। गांवों और शहरों में इसका लाभ मिलेगा बूढे व्यक्तियों को, यह एक लाभकारी योजना है।

महिला और बाल विकास के अन्दर आंगनबाड़ी केन्द्रों में जो महिलाएं काम करती हैं, उनका मानदेय बढ़ाया और जो बच्चे वहां आते हैं उनको दो ड्रैस देने की घोषणा की, यह एक सराहनीय कदम है।

जो काम राजस्थान में हुए हैं, अब थोड़ी तकलीफ तो इनको होगी ही। यह तो मालूम था कि मध्य प्रदेश में यह हुआ, हिमाचल प्रदेश में यह हुआ। हिमाचल में भी हम आये हैं, त्रिपुरा में भी हम आये हैं, गुजरात में बराबर की

(श्री महेन्द्र सिंह)

टक्कर ली, पहले से एक सदस्य ज्यादा जिता कर लाये हैं। राजस्थान में फिर मैदान के घोड़े हैं, टक्कर लेंगे और वापस सरकार बनाकर लाएंगे। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वर्ष 2013-14 के बजट के ऊपर बोलने की मुझे परमिशन दी। आज एक बड़ा गम्भीर विषय इसमें निकलकर आया है कि बिजली के ऊपर हम बजट का 48 प्रतिशत व्यय करते हैं लेकिन बिजली की हालत यह है कि एक यूनिट भी आपने पैदा नहीं की। बिजली 8 घण्टे देने का कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा, बजट में घोषणा की थी कि किसान को 8 घण्टे बिजली देंगे। तो वह आपको मालूम है। 6 घण्टे बिजली देते जरूर हैं, लेकिन वह किस तरह आती है, इस बात से प्रदेश के सारे किसान परिचित हैं। बजट का इतना पैसा लगाकर भी कम्पनियां घाटे में हैं, बड़ी विडम्बना है कि वह पैसा गया कहां? आपने इतना ज्यादा बजट का हिस्सा बिजली पर खर्च किया तो यहां बिजली के तो अम्बार लग जाने चाहिये थे और बिजली कम्पनियों को प्रोफिट होना चाहिए था। परन्तु बिजली कम्पनियां आज घाटे में हैं।

माननीय सभापति महोदय, हरियाणा में, गुजरात में इण्डस्ट्री कितनी आगे जा रही हैं और हमारे राजस्थान में इण्डस्ट्री की क्या हालत है, यह हमारे सोचने का विषय है। लेकिन पता नहीं सरकार ने इस बात पर पूरी तरह मनन क्यों नहीं किया, देखा क्यों नहीं। अब हर साल यह कह देते हैं कि हमारे यहां बाहर से एनआरआई आ रहे हैं, बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्री लगेंगी। लेकिन इण्डस्ट्री का कहीं नाम ही नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट भाषण के बिन्दु संख्या 5 में मुख्य मंत्रीजी ने नि:शुल्क जांच की योजना प्रारम्भ करने की योजना की घोषणा की है। हालत यह है कि राजकीय अस्पतालों में करोड़ों रुपयों की लागत से स्थापित जांच की मशीनें एमआरआई, सीटी स्कैन व अन्य उपकरण नाकारा पड़े हैं। इनके संचालन हेतु बजट में व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है। सम्माननीय सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 7 में उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना में राजीव गांधी डिजिटल

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

विद्यार्थी योजना में बजट प्रावधान के साथ-साथ रोजगारोन्मुखी उपक्रमों में आईटीआई आदि के लिए बजट एवं प्रोत्साहन योजना के लिए कोई स्थान नहीं है।

सम्माननीय सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 11-सेवानिवृत्ति व अन्य कारणों से रिक्त होने वाले पदों को भरने के लिए सम्बन्धित विभागों को अधिकृत करने की घोषणा झूठ का पुलिंदा है। हकीकत है कि रिक्त हो रहे पदों को समाप्त किया जा रहा है। इसके अलावा, कम्प्यूटरीकरण के नाम पर भी मंत्रालयिक वर्ग के पदों पर कैंची चलाई जा रही है।

सम्माननीय सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 14- सड़क तंत्र को मजबूत करने के नाम पर टोल रूपी बोझ को लादा जा रहा है और हर तीसरी बड़ी सड़क को बीओटी आधार पर बना रहे हैं। तो माननीय मुख्य मंत्री कौन से तंत्र पर पैसा लगाने की बात कर रहे हैं? अभी भी राज्य के हजारों गांव सम्पर्क सड़क से वंचित हैं।

सम्माननीय सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 30- मुख्य मंत्री ने विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में बढ़ोतरी नहीं करने की घोषणा कर लुभाने का प्रयास किया था, जब कि आपके 4 साल के शासन काल में विद्युत दरों में तीन-चार बार बढ़ोतरी कर दी गई है। महंगाई से त्रस्त विद्युत उपभोक्ताओं पर विभिन्न विद्युत उपकरणों के माध्यम से भी अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है।

सम्माननीय सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 52- सिंचाई परियोजनाओं में नहरों की डीसिल्टिंग और पक्का करने के लिए बजट में कहीं कोई प्रावधान नहीं किया गया है। नहरों की बंदी कर या डाइवर्शन लेकर मरम्मत करने की किसानों की मुख्य मांग को भी नजरअंदाज किया गया है।

सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 121- श्रीगंगानगर के घग्घर के आसपास बड़ोपल पक्षी अभयारण्य घोषित करने की घोषणा मात्र की गई है, इसके सम्बन्ध में कोई भी बजट प्रावधान नहीं किया गया है। घग्घर बैल्ट को विकसित करने और राइस बैल्ट विकसित करने की किसानों की मांग पर बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

बिन्दु संख्या 132- किसानों को कृषि उत्पादों के उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है जब कि उन्नत किस्म के बीज उत्पादन के लिए स्थापित प्रयोगशालाएं बंद पड़ी हैं। उनके सुदृढ़ीकरण और

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

विकास के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं रखा गया है। कृषि प्रयोगशालाओं में लैब टैक्नीशियन के पद भी समाप्त किये गये हैं।

बिन्दु संख्या 135- श्रीगंगानगर कृषि प्रधान जिला है और अन्न के कटोरे के नाम से विख्यात है। महोदय, मेरी अधिकृत जानकारी में गंगानगर सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला है, लेकिन गंगानगर में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की बजाय गैर कृषि जिलों में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की बजट में घोषणा की गई है।

बिन्दु संख्या 145- किसानों को फसल पर ब्याज मुक्त ऋण के प्रावधानों के अलावा, श्रीगंगानगर सहित अन्य जिलों में ट्रैक्टर ऋण के बोझ तले दबे किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, राहत की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

बिन्दु संख्या 145- स्पिन फैड के सशक्तीकरण के साथ-साथ उनके श्रमिकों, कर्मचारियों के कल्याण के कोई प्रावधान नहीं रखे। वर्षों पुराने श्रमिकों की वेतन वृद्धि नहीं की जा रही है। स्पिन फैड सहायता उपक्रम होने की वजह से श्रमिकों को श्रम कल्याण के लाभ नहीं मिल रहे हैं।

बिन्दु संख्या 150-156- पशु चिकित्सालय कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। पशुपालन विभाग में नयी चल-अचल पशु चिकित्सा इकाइयां व नये पशु चिकित्सालय खोलने के साथ-साथ पशु चिकित्सालयों में भर्ती का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना होनी चाहिए। वर्तमान में मौजूदा पशु चिकित्सालय जांच उपकरणों व पशुओं के इलाज में काम आने वाले अन्य उपकरणों के अभाव में जूझ रहे हैं। उनके लिए कोई घोषणा नहीं की गई है।

बिन्दु संख्या 174- नये पुस्तकालय स्थापित करने हेतु घोषणा की गई है जब कि श्रीगंगानगर सहित अन्य सभी जिलों में पूर्व में ही पुस्तकालय सहायक और अधीक्षकों के काफी पद वर्षों से रिक्त चल रहे हैं। इन रिक्त पदों को भरने की कोई घोषणा नहीं की गई है।

बिन्दु संख्या 195- आधार योजना में जिला मुख्यालय के अलावा अन्य केन्द्रों पर कोई व्यवस्था नहीं है, न इसके प्रचार-प्रसार के लिए सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गई है। आम जन को अभी तक यह भी नहीं पता है कि आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य है या स्वैच्छिक। आधार कार्ड भी बीपीएल कार्ड के समय तक बन जाएगा।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

बिन्दु संख्या 199- श्रीगंगानगर के रीको औद्योगिक क्षेत्र में वस्त्र उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं लेकिन बजट में इस तरह की कोई भी घोषणा नहीं की गई है। पूर्व में लम्बित गंगानगर टैक्सटाइल पार्क खोलने की मांग को भी बजट में कहीं स्थान नहीं दिया गया है। साथ-साथ, गंगानगर के अन्दर जेसीटी मिल और काटन काम्प्लैक्स, शुगर फैक्टरी और तमाम जो बड़े-बड़े कारखाने थे, उनको बंद कर दिया गया है। यह भी बड़ी अजीब-सी बात है। खोले जाएं तो कोई बात हो, बंद कर दिया है। शुगर फैक्ट्री जिसका आज से साढ़े चार साल पहले श्रीमती वसुंधराजी ने शिलान्यास किया था, वहीं की वहीं खड़ी है। 14 लाख हैक्टेयर में लोग गन्ना बीजते हैं और वे हरियाणा-पंजाब में ले जाते हैं। किसान इससे बड़ा भारी दुःखी है।

बिन्दु संख्या 203- मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवाओं को ऋण देने की प्रक्रिया में सरलीकरण नहीं है, हजारों लोग वंचित रह जाते हैं। बैंकों द्वारा मनमानी की जाती है। कई प्रकरणों में तो बैंकों द्वारा निजी स्वार्थों की पूर्ति किये बिना बेरोजगारों से दुर्व्यवहार किया जाता है। जब एक बार उक्त योजना में लाभान्वित को पात्र मान लिया जाता है तो बैंक द्वारा पुन: पात्रता की परीक्षा करवाना गलत है। इसके लिए भी प्रभावी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

बिन्दु संख्या 204- खादी कातिनों व बुनकरों की बिक्री बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई भी प्रचार-प्रसार नहीं किया जाता, न ही कोई सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। कातिनों व बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके कल्याण के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। खादी कातिनों व बुनकर से खादी उत्पादों को सीधे सरकार द्वारा खादी बोर्ड के माध्यम से खरीद किये जाने से उनका अस्तित्व बना रह सकता है।

बिन्दु संख्या 211- सभी जिला परिवहन कार्यालयों में एजेंटों एवं सलाहकारों की भरमार रहती है। इसे उचित प्रक्रिया में शामिल कर लाइसेंस प्रदान कर सभी कार्यों के लिए कमीशन अथवा मानदेय तय किये जाने से न केवल परिवहन कार्यालयों के कार्यों में सहायता प्रदान होगी, एजेंटों और सलाहकारों को बेरोजगारी से भी बचाया जा सकता है और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जा सकता है।

ये मेरे कुछ सुझाव हैं। बिन्दु संख्या 216- बजट में सिविल निर्माण कार्य किन-किन शहरों में प्रगति पर है, इसका उल्लेख न कर 32 शहरों में

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

सीवरेज निर्माण कार्य प्रगति पर बताया गया है जबकि हकीकत यह है कि श्रीगंगानगर समेत कई शहरों में स्वीकृत सीवरेज योजना में पिछले चार सालों में घोषणाओं के अलावा कोई कार्य नहीं हो रहा है। गंगानगर में बार-बार सीवरेज कार्य को टाला जा रहा है। अन्तिम वर्ष में टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। महोदय, यदि चार वर्ष पूर्व स्वीकृत सीवरेज योजना का यह हाल है तो आगामी वर्षों के लिए प्रस्तावित सीवरेज योजनाओं का क्या हश्र होने वाला है, यह राजस्थान की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु संख्या 220- नगरीय निकाय और न्यासों में रिक्त पदों को भरने की प्रत्येक बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा केवल घोषणाएं की जाती रही हैं लेकिन इसके लिए कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाये गये हैं। सफाई कर्मचारियों की स्थिति यह है कि नगर निकायों के लिए इनकी महत्त आवश्यकता है लेकिन बजट में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है।

बिन्दु संख्या 221– गंगानगर में आरओबी के निर्माण की स्वीकृति के पश्चात् कछुआ गति से कार्य हो रहा है। पूर्व में की गई ओवरब्रिज की घोषणा पर इस बार कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया। गंगानगर की वर्षों पुरानी मांग और आवश्यक ओवरब्रिज को टाला गया। सामरिक महत्व के लिए गंगानगर में मिलिटरी, बीएसएफ का आवागमन आजाद टाकीज रेलवे फाटक के पास होता है। इसके अलावा पड़ौसी राज्य पंजाब, हरियाणा का आवागमन भी आजाद टाकीज के रेलवे फाटक से होता है जो कि अक्सर बन्द रहता है। ओवरब्रिज से इस समस्या का हल किया जा सकता है लेकिन घोषणाएं करने के बावजूद ओवरब्रिज अभी तक नहीं बना। इस बजट में भी ओवरब्रिज के लिए कोई राशि नहीं रखी गई जबकि दो साल पहले घोषणा हो गई थी, राशि रखी गई थी। पिछले साल भी घोषणा हुई थी, राशि रखी गई थी लेकिन इस बार कोई भी राशि नहीं रखी गई।

बिन्दु संख्या 230 में ग्रामीण पर्यटन...

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, मैं व्यवधान नहीं डालना चाहता लेकिन बजट के ऊपर या गवर्नर के अभिभाषण पर वाद-विवाद में आप कागज से अंकित की गई कोई चीज रेफरेंस में तो यूज कर सकते हैं....

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ठीक है। बिलकुल ठीक है।

श्री सभापति: मैं इसलिए निवेदन कर रहा था। हालांकि याददाश्त की वजह से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप वैसे अभिव्यक्त करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। समय का भी थोड़ा आप ध्यान रखें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि बजट में राजस्थान कैनाल से आप सिंचित क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, एक लाख 35 हजार और सिंचित क्षेत्र कर रहे हैं। फर्स्ट फेज को पानी पूरा नहीं हो रहा, सैकिण्ड फेज तरस रहा है और थर्ड फेज आप और बना रहे हैं। पिछले वर्ष आपने एक लाख 25 हजार एकड़ भूमि को सिंचित करने का बजट में प्रोविजन रखा था लेकिन उसमें से केवल 30 हजार को आप पिछले साल कर पाये और अब फिर उसी बात को दोहराते हुए एक लाख 35 हजार इसमें दर्शाया है। होने वाली बात कुछ मुझे लगती नहीं है।

पीने का पानी- मेरे खयाल में पूरे राजस्थान में इस तरह की हालत नहीं है कि जहां भांखड़ा कैनाल हो, गंग कैनाल हो, इंदिरा गांधी कैनाल हो। घग्घर फ्लड से पानी आता हो और उस पानी में 14 हजार क्यूसेक पानी सीवरेज का, फैक्टरियों का और सेम का पानी आता हो। मैं पहले भी हाउस में कई बार कह चुका हूं कि उसको पीने से कैंसर, लीवर डैमेज, हार्ट अटैक, हजार तरह की बीमारियां होती हैं। भटिण्डा से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम कैंसर ट्रेन है जो गंगानगर, हनुमानगढ़ होकर जाती है। इस पर भी कोई घोषणा नहीं की गई कि कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगाते जिससे लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिलता। 65 साल की आजादी के बाद भी लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल सका तो फिर सरकार अपनी थोथी घोषणाएं करके क्या लूटना चाहती है, क्या कहना चाहती है, यह हमें तो इस बजट से समझ में नहीं आया। दो साड़ियां दे दीं, कम्बल दे दिया अच्छी बात है, पर आज डीजल में कम करते न। हरियाणा जो दो किलोमीटर है वहां से और पंजाब में हमारे से डीजल में पांच रुपये कम है। अब आप बताओ कि वहां का किसान, वहां का मजदूर, वहां का व्यापारी जब पांच रुपये ज्यादा भरेगा तो महंगाई तो उसका सिर तोड़ देगी। अगर आपको कम करना था तो उसमें कम करते। आज मैट्रो की उतनी जरूरत नहीं थी, आप 500-500 करोड़ रुपये हर कांस्टीट्युएंसी को दे देते। मैट्रो पांच साल बाद बन जाती। मैट्रो को चाटना है क्या, जबकि गरीब

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

तरस रहे हैं! आपने दो साड़ियां और एक कम्बल देकर बहुत बड़ा उपकार कर दिया जबकि उसके ऊपर सीधा टैक्स लग रहा है। आप 18 प्रतिशत वैट ले रहे हो, आप वैट को खतम कर देते। आपके पास रिफाइनरी से इतनी इनकम आएगी। उसमें भी अभी अंदेशा है, जैसा राजपाल जी अभी कह रहे थे, कि 600 और कुछ करोड़ रुपये का घाटा होने वाला है। रिफाइनरी लगी है, इसमें तो सारे हाउस को खुशी है, प्रतापसिंह खाचरियावास ने भी इसकी तारीफ की थी। लेकिन उसके बाद राजपाल सिंह जी ने उनको शुद्ध किया कि 600 और कुछ करोड़ रुपये का घाटा होने वाला है। वह घाटा क्यों हो रहा है, कहां गलती है, दुबारा जब बजट की रिप्लाई देंगे तो वह चीज भी आनी चाहिए।

हमारे जिले में हास्पिटल की ऐसी हालत है जैसे बूचड़खाना होता है। आज वहां डाक्टर नहीं हैं। वहां पर सारी मशीनें हैं पर मशीनें बन्द पड़ी हैं क्योंकि मशीनों को आपरेट करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सी.एम. साहब से प्रार्थना करूंगा कि जब आप बजट की रिप्लाई दें तब इसका ध्यान रखें। आप कहते हैं, गांवों में डाक्टर। गांवों में डाक्टर जाए कैसे, आप उनको पैसे ही नहीं देते। कितने पैसे देते हो? कैसे रहेगा गांवों में डाक्टर? शहरों में डाक्टर की भर्ती नहीं करते, सारे हास्पिटल खाली पड़े हैं। सारे स्कूल खाली पड़े हैं। स्कूलों की घोषणा कर रहे हो पर टीचर्स का नाम नहीं। पिछली बार भी कहा था कि हम डेढ़ लाख व्यक्तियों की भर्ती करेंगे। वो कहा गया? एक भी कोई आदमी हुआ? अब फिर आप घोषणा कर रहे हैं जबकि मात्र चार महीने बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो कैसे करेंगे आप इसकी योजना? सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए, जनता के वोट बटोरने के लिए आप झूठे वायदे करो, यह बात मेरे खयाल में उचित नहीं है। कम से कम सी.एम. साहब के लिए यह बात उचित नहीं है। वो कहते हैं कि मैं तो गांधीवादी हूं, गांधीवादी व्यक्ति के लिए इस तरह की थोथी घोषणाएं करना अपने आप में मेरे खयाल में उचित नहीं है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी कार्य हो रहे हैं, जितनी घोषणाएं हुई हैं, घोषणाएं तो बहुत अच्छी हैं पर वो सिर कैसे चढ़ेंगी, पैसा कहां से आएगा, बजट तो आपका घाटे का है? चार महीने में इसकी कैसे पूर्ति करोगे, यह मुझे तो समझ में आया नहीं। हो सकता है कि मेरे पढ़ने में गलती रह गई हो। बजट घाटे का और दुनियाभर की घोषणाएं कर दीं। घोषणाएं पूरी

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

तब होंगी जब हम मन बनाकर बजट को भी सही हिसाब से रखेंगे, संतुलन रखेंगे। वो संतुलन तो है नहीं और केवल घोषणा कर देनी है। घोषणा का 50 प्रतिशत भी बजट खर्च नहीं होता। जब घोषणा का 50 प्रतिशत बजट खर्च नहीं होता तो चार साल से आप घोषणा कर रहे हैं। जो आप तीन साल पहले कह रहे थे वो ही बात आपने दो साल पहले कही थी, वो ही आपने एक साल पहले कही थी और वो ही आप चार साल बाद कह रहे हैं और वो ही इस बजट में कह रहे हैं। फर्क क्या रहा? वो ही बजट, वो ही चीजें, सेम की सेम, कुछ थोड़ी-बहुत बदल कर सदन में प्रस्तुत हो जाती हैं। मुख्य मंत्री यहां पर विराज नहीं रहे, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि जब बजट की रिप्लाई देंगे तो सारी बातें जो मैंने प्रार्थना की हैं, उनको पूरी तरह से एग्जामिन करके जो श्रीगंगानगर के साथ अन्याय हो रहा है उसका जवाब देंगे।

मेडिकल कालेज खोल दिया, मैंने सुबह भी कहा था कि जहां 300 बैड का हास्पिटल होगा वहां मेडिकल कालेज खुल जाएगा। न नौ मण तेल होगा और न राधा नाचेगी। कहां से खोल देंगे? एक मेडिकल कालेज तो खुलता नहीं।

गंगानगर में घोषणा की, उसका बजट में कहीं जिक्र नहीं। अखबारों में यह कह दिया कि 30 मार्च को राजस्थान डे पर हम उसका शिलान्यास करेंगे। यहां घोषणा करो न, लोगों को पता लगेगा। मेडिकल कालेज यहां जयपुर को दिया है, उसके लिए बाकायदा बजट रखा है, उसकी जमीन के लिए भी रखा है। मान लो, दानदाता उनको 100 करोड़ रुपये का चैक दे गया तो वह बताएं कि हमारे पास 100 करोड़ रुपये का चैक आया है और हम इसको बनाना चाहते हैं। उस तरह की कोई बात है नहीं। तो ये अकेली घोषणाएं कर देने से कभी पूर्ति नहीं होती और आने वाला टाइम कांग्रेस के लिए बड़ा खतरनाक है। आप भाइयों, कितना ही हंसो, कितनी ही तालियां लगाओ, ऐसा खतरनाक टाइम आने वाला है। उधर से हमारे मंत्रीजी की तारीफ कर रहे थे, वास्तव में वह तारीफ के काबिल हैं। नरेगा जैसी चीज में, उसकी कोस्ट क्या आ रही है 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। नरेगा में काम कहां हो रहा है और भ्रष्टाचार के अलावा नरेगा में चीज क्या है? 6-6 कलक्टर्स के ऊपर इस तरह की टिप्पणी हो जाए और उधर से कोई जवाब नहीं आए, कमाल की बात है। जब मंत्रीजी का लिखा हुआ है, या तो मुख्य मंत्री उसके ऊपर बैठे या केबिनेट बैठे या विधान सभा को अधिकार है। एक बनाई हुई कमेटी केवल इस तरह का आदेश कर दे और उसको मान लिया जाए कि इनको वार्निंग दे दो और छोड़

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

दो। इस तरह से कैसे चलेगा? अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं, नरेगा में हालत क्या है? नरेगा को किसान के साथ जोड़ना चाहिए था। किसान 50 प्रतिशत पैसा देता है, 50 प्रतिशत भारत सरकार देती तो मेरे खयाल से उस नरेगा का कोई और ही परिणाम निकलता। आज जो हश्र हो रहा है, वह हश्र नहीं होता। आप इशारा कर रहे हैं, धन्यवाद। मैं कुछ थोड़ी बातें और करना चाहता था, पर समय का अभाव है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपने मुझे टोका नहीं।

श्री सभापति: श्री पदमा रामजी मेघवाल।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा, यानी सात बजे के बाद में एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आठ बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आठ बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

श्री पदमा रामजी मेघवाल।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट की बहस पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्य मंत्री द्वारा 6 मार्च को आने वाले साल के लिए जो अनुमानित बजट पेश किया गया, उस बजट के पक्ष में मैं बोलना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, 6 तारीख को राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया, उसके अन्दर जो घोषणा की गयी है, पूरे राजस्थान के अन्दर उसकी गली-गली में प्रशंसा हो रही है, गांव-गांव में प्रशंसा हो रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गांव के गरीब, गांव के किसान, गांव के व्यापारी, उद्योगपति, सभी का ध्यान रखते हुए इस बजट के अन्दर घोषणा की है, वह सराहनीय है।

(श्री पदमाराम)

माननीय सभापति महोदय, अभी बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य यह फरमा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार ने आते ही अनुसूचित जाति के किसान थे, उनके कनेक्शन बंद कर दिये। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत वरिष्ठ सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा, आपका हमेशा विचार रहा है कि आप कभी किसानों के नाम पर, कभी अनुसूचित जाति के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी गौ-माता के नाम पर हल्ला करके यह जो अच्छा बजट पेश किया है, जनता का ध्यान उससे हटाना चाहते हो। परन्तु आज मीडिया के मार्फत, इस संचार क्रांति में मोबाइल के मार्फत, टीवी चैनल के मार्फत आम गरीब, किसान, ढाणी में बैठे हुए आदमी को भी यह मालूम हो गया है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री कल्याणकारी हैं, गरीबों के हितैषी हैं, किसानों के हितैषी हैं, आम वर्ग के हितैषी हैं। 36 कौमों को साथ में लेकर चलने वाले मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, आने वाले समय के अन्दर राजस्थान का विकास होगा, आम गरीब का विकास होगा, किसान का विकास होगा, राजस्थान खुशहाल बनेगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अब बात चली बिजली की। राजस्थान की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया, राजस्थान के अन्दर कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार बनते ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि किसानों का हम बिजली का एक पैसा भी पांच साल तक नहीं बढ़ाएंगे। बात किसानों की चल रही है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बिजली के पैसे बढ़ा दिये। किसानों के बढ़ाये हों तो बताओ। और तो बिजली के पैसे बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे। मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के लिए घोषणा की। पिछले चार साल में 4,600 मेगावाट अधिक बिजली पैदा की। पवन ऊर्जा के रूप में पैदा की। सौर ऊर्जा के रूप में पैदा की। पिछले चार साल के अन्दर 2.46 लाख किसान कनेक्शन दिये। एक गरीब आदमी जिसके घर के अन्दर विद्युत कनेक्शन मिल गया, उसने अपनी खेती की। उस खेती से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए उसका सहारा बन गया, इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और विद्युत मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसके साथ-साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी और विद्युत मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 132 के दो

(श्री पदमाराम)

जीएसएस बनाये और 18, 33 के ग्रिड स्टेशन बनाकर साबित कर दिया। मेरा विधान सभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है जो यहां से 710 किलोमीटर दूर है, वहां भी इस तरह की व्यवस्था की है। इससे यह साबित हो रहा है कि मुख्य मंत्रीजी की यह मंशा है, हमारे मंत्रिमण्डल की यह मंशा है कि आम जन का विकास कैसे हो, गांव का विकास कैसे हो, गांव का गरीब आगे कैसे बढ़े। उसको मद्देनजर रखते हुए यह योजना बनाई है, जो सराहनीय है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने पिछले चार सालों के अन्दर हमारे जो एससी के हास्टल हैं, जो वृद्धावस्था आश्रम हैं, जो महिला आश्रम हैं, उनके अन्दर जो बढोतरी की है, वह धन्यवाद के पात्र हैं। उनको मालूम है कि इस महंगाई के युग के अन्दर एक गरीब का बच्चा अच्छी तरह से पढ़े, उसको पौष्टिक भोजन मिले, वह आगे बढ़े और आगे बढ़कर अपने क्षेत्र का और अपने परिवार का नाम रोशन करे। उसके आधार पर 2008 में 675 रुपये मिल रहे थे, उसके बाद में उसको 1,000 रुपये किया, गत बजट के अन्दर 1,250 रुपये किया और इस बजट के अन्दर 1,750 रुपये करके यह साबित कर दिया कि राजस्थान का मुख्य मंत्री गरीब के बच्चे को बढ़ाना चाहता है, एक गरीब को ऊपर उठाना चाहता है, एक गरीब की आवाज सुनना चाहता है कि गरीब आगे बढ़े, अपनी समानता का जीवन जीए और हमेशा प्रगति की ओर अग्रसर रहे।

(18.39 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, पालनहार योजना वरिष्ठ के लिए/वृद्ध के लिए, योजना है। समय ऐसा आ गया, कलयुग है। कलयुग के अन्दर भी गरीब ढाणियों वाले तो जरूर जो हमारी परम्परा है, जो हमारी मर्यादा है, जो हमारी मान्यता है, हम अपने मां-बाप की सेवा अच्छी तरह से करते हैं। परन्तु समय ऐसा चेंज हो गया कि उनके पास आज कमाने का साधन नहीं है। वे वरिष्ठ हो गये हैं, असहाय हो गये हैं। उनकी सेवा करने के लिए 750 रुपये की पेंशन की योजना लागू की। उसके साथ-साथ, आज उसका 25 साल का बेटा है, वह शर्त समाप्त करके माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह साबित कर दिया कि मुख्य मंत्रीजी ने विधवाओं के हित के लिए, वृद्धों के हित के लिए बहुत शानदार कदम उठाया है।

(श्री पदमाराम)

उसके साथ-साथ मुख्य मंत्रीजी ने 25 साल के उनके बेटे या परिवार के और सदस्य हैं, वे उनको तीर्थयात्रा नहीं करा सकते हैं, तीर्थयात्रा के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया।

सभापति महोदय, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाले माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1100 किलोमीटर जो सड़कें दी हैं, सब को दी हैं, पक्षपात नहीं किया है, किसी पक्ष की पार्टी के लिए नहीं दी हैं। सभी के लिए 1100-1500 किलोमीटर सड़कें बनाकर यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सभी को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने मिसिंग लिंक की सड़कों की व्यवस्था की, वह सभी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर की। इसके साथ-साथ अभी पांच सौ की आबादी की सड़कें पूर्ण की हैं। इसके बाद 399 से 250 की आबादी के गांवों को जोड़ने की व्यवस्था की, 250 से कम, 100 से 250 की आबादी को सड़कों से जोड़ने की व्यवस्था की। इसके साथ-साथ मिसिंग लिंक हैं, धार्मिक सड़कें हैं, सड़कों का सुदृढ़ीकरण करना है, नवीनीकरण करना है, उसके अन्दर भी व्यवस्था करके मुख्य मंत्रीजी ने साबित कर दिया कि बिना सड़क कोई विकास नहीं हो सकता। आगे बढ़कर राजस्थान के विकास को ध्यान में रखकर यह प्रावधान किया है इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा के क्षेत्र में अथक प्रयास करके साबित कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जहां स्कूलें नहीं हैं, 2010 की बजट घोषणा के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने बिना भेदभाव जितने भी पंचायत मुख्यालय थे, जिस पंचायत के अन्दर, माध्यमिक विद्यालय नहीं थे, सब जगह खोले। आपके समय में आपने जातिवाद किया, आपने भाई-भतीजावाद किया। आपके नेताओं ने अपने क्षेत्र के अन्दर अपनी ढाणियों के अन्दर जो स्कूलें खुलवाईं, उस कारण से हमारे क्षेत्र में आठ पंचायत मुख्यालय स्कूलों से रहित रह गये। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक हजार माध्यमिक स्कूलों की जो घोषणा की है, वह धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ-साथ जो ग्राम पंचायतें माध्यमिक विद्यालयों से रहित हैं, उनको भी इसमें साथ जोड़ने की आप मेहरबानी करें। आपने घोषणा जरूर की है परन्तु इसके अतिरिक्त करें तो आप धन्यवाद के पात्र होंगे। इसके साथ एक हजार प्राइमरी स्कूलें खोलीं, एक हजार प्राइमरी से

(श्री पदमाराम)

उच्च प्राइमरी के अन्दर क्रमोन्नत करने का प्रावधान किया, छह सौ उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने का प्रावधान किया, धन्यवाद के पात्र हैं। अभी माननीय सदस्य देवनानी साहब यहां से पधार गये, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के स्तर की ग्रामीण क्षेत्र में जो दयनीय स्थिति बनी है, वह आपके समय में बनी है, आपकी मेहरबानी से हुई है। आपने पिछले चुनाव से एक महीना, दो महीना पहले भयंकर ट्रांसफर किये वोट का समय नजदीक आ रहा था, चुनाव नजदीक आ रहा था, नजदीक आते-आते ग्रामीण क्षेत्र की पूरी स्कूलें आपने खाली कर दीं। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने अध्यापकों की भर्ती की उसमें से अड़तालीस हजार की नियुक्तियां अब दे दी हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर चार सौ नये मास्टर आये। आज हर स्कूल के अन्दर चार से पांच टीचर हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। दसवीं के अन्दर भी आपने वरिष्ठ अध्यापकों की लमसम अठारह हजार नियुक्तियां की हैं। आपने दसवीं स्कूलों की घोषणा कर दी, पर स्कूल में आपने सबजैक्ट टीचर लगाने की घोषणा नहीं की थी। स्कूलें खोल दी थीं, स्कूलों की कंडीशन क्या थी? प्राइमरी की दो टीचर, बच्चे स्कूल आ नहीं रहे थे। पांच साल तक अध्यापकों ने मौज की। उस मौज करने की भावना से आज स्कूलों की जो हालत हुई है उसमें सुधार करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी मुख्य मंत्री महोदय ने बीस हजार टीचर, दस हजार वरिष्ठ अध्यापक और उच्च माध्यमिक के अन्दर लैक्चरर की भर्ती की घोषणा करके यह साबित कर दिया कि राजस्थान शिक्षा के अन्दर आगे बढ़े, शिक्षा के अन्दर क्रांति करे। जो अभी समस्या आ रही है कि मास्टर नहीं हैं, कहीं डाक्टर नहीं हैं, कहीं पशु चिकित्सक नहीं हैं, इसका मेन कारण है कि शिक्षा की कमजोरी है। जो यह आगे बढ़ेगा और आने वाले समय के अन्दर इसमें कोई कमी नहीं आएगी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विपक्ष का धर्म है, जब भी बजट आया है, उन्होंने एक ही भावना जाग्रत की है। पहले तो उनका उद्देश्य था कि बजट की चर्चा नहीं हो, लोगों को यह मालूम नहीं हो कि इस बजट के अन्दर क्या प्रावधान रखा है और उसका लोगों को क्या फायदा हो रहा है। वह दो-चार दिन आपने कोशिश की, एक-दूसरे को डाइवर्ट करने की कोशिश करी, परन्तु अभी यह बहस चालू हुई है। वरिष्ठ सदस्य फर्मा रहे थे कि दो रुपये किलो गेहूं से कुछ नहीं होगा, साड़ी से कुछ नहीं होगा, कम्बल से कुछ नहीं होगा। पैसे

(श्री पदमाराम)

वालों को मालूम नहीं, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपने गरीबी देखी नहीं है, आपको मालूम नहीं है गरीबी क्या है। आपको मालूम नहीं है कि किसान क्या है। आपको इस चीज की तकलीफ नहीं है, पैसे वालों को इस चीज का कोई एहसास नहीं है, सभापति महोदय। गरीब के घर पच्चीस किलो जो दो रुपये किलो मिल रहा था, आज एक रुपये किलो मिलेगा। एक रुपये किलो गेहूं पच्चीस किलो मिलेगा। डेढ़ रुपये किलो तो पिसाई लगती है, एक रुपये किलो गेहूं कोई नहीं देता है। बाजार के अन्दर अच्छा खेत है जिसके अन्दर उपजाऊ मिट्टी है वह भी एक तगारी मिट्टी हजार रुपये में भी नहीं देगा। मुख्य मंत्रीजी ने गरीब आगे कैसे बढ़े, वह बचत करके अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, अपना जीवन कैसे संवारे, अपने सामाजिक अस्तित्व के अन्दर ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचे, उसको मद्देनजर रखते हुए यह घोषणा की है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक प्रावधान और किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को जो फंड मिल रहा था उसका पहले प्रावधान डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को, कि उन्होंने ग्रामीण और पंचायत समिति लेवल को इसमें बनाया। मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन को उसमें चयनित किया इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को और अल्पसंख्यक मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ-साथ उन्होंने डेढ़ सौ करोड़ का प्रावधान रखा है कि अल्पसंख्यक क्षेत्रों के अन्दर स्कूलें खुलेंगी, वहां पानी की व्यवस्था होगी, वहां शिक्षा की व्यवस्था होगी। शिक्षा के अन्दर सीनियर में साठ प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली बच्ची को भी ओबीसी के समान स्कूटी दिये जाने की बात की है, धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ-साथ मदरसों के सुदृढ़ीकरण का कानून बनाया है, नये कम्प्यूटर पैरा टीचर लगाने की व्यवस्था की, और कई टाइप की योजना कीं। माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, वह शिक्षा में जुड़े, शिक्षा में आगे बढ़े, हर क्षेत्र में वह आगे प्रगति करे। इसके साथ-साथ उन्होंने बीस उच्च आवासीय विद्यालयों की जो घोषणा की है, सराहनीय कदम है। आज दिन तक किसी ने नहीं घोषणा की। वाहवाही कोई भी ले सकता है, प्रशंसा कोई भी कर सकता है, वोट कोई भी ले सकता है, परन्तु अल्पसंख्यकों के लिए कोई सोच करने वाला मुख्य मंत्री है तो माननीय अशोकजी गहलोत साहब हैं। उन्होंने पन्द्रह आईटीआई पहले चालू की हैं, बीस आईटीआई और खोलने की व्यवस्था की है, मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत माननीय मुख्य

(श्री पदमाराम)

मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है जहां भारी तादाद में अल्पसंख्यक लोग निवास कर रहे हैं, उनके आवास की घोषणा भी आप यदि इस बजट में साथ-साथ कर देते तो उन गरीबों को अपने बच्चों का सिर ढकने के लिए छत मिल जाती और वे मजदूरी करके, व्यायाम करके अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करते। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्रीजी को, माननीय कृषि मंत्रीजी को और सहकारिता मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, कि एक लाख रुपये तक का ऋण जो किसान समय पर चुका देगा उसका पूरा ब्याज राजस्थान सरकार देगी, ये धन्यवाद के पात्र हैं। वर्ष 2008 के अन्दर किसानों को 2500 करोड़ रुपये ही ऋण वितरण हो रहा था जो आज दस हजार करोड़ हो गया है। मैं कोआपरेटिव में नौकरी करके आया हूं, छब्बीस साल नौकरी की है, ऋण वितरण करने के लिए हम एक किसान को तीन टाइम में पैसे देते थे। तब उनकी भावना थी कि आप एक साथ हमको पैसा दो, हमारी खेती इसके अन्दर होगी, हम बीज इससे लाएंगे, हम खाद इससे लाएंगे और जुताई के पैसे भी हम इससे देंगे।

आज मैं सहकारिता मंत्री, मुख्य मंत्री महोदय और कृषि मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 50 हजार की साख सीमा को 1 लाख रुपये किया और यह भी कि समय पर पैसे चुकाएंगे उनका ब्याज पूरा राजस्थान सरकार वहन करेगी। अभी मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के अन्दर घोषणा की है कि जो किसान डेढ़ लाख रुपया तक का कर्जा लेगा और समय पर चुका देगा, उसका पूरा ब्याज राजस्थान सरकार वहन करेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा, कृषि मंत्रीजी विराजे हैं, यह जो मौसम आधारित बीमा लागू किया है, जहां ज्यादा सर्दी पड़ती है, नमी वाले क्षेत्र हैं उनके लिए तो यह उपयोगी है। परन्तु हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र के अन्दर इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के अन्दर किसानों के लिए क्राप कटिंग आधारित बीमा लागू करें। इसके साथ-साथ माननीय पंचायतीराज मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर अभी नरेगा के अन्दर चार हजार बेरियां बनीं और उन चार हजार बेरियों के अन्दर किसानों ने मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री की मेहरबानी से कृषि कनेक्शन ले लिया। आज उनके खेतों में लाखों रुपए की फसल लहरा रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान है। इसके

(श्री पदमाराम)

साथ-साथ पक्के कामों के लिए भी इन्होंने राज्य कोष से पैसे देने की घोषणा की है, इसके लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले चार साल में देवनारायण छात्रावास की घोषणा की गयी थी, उसका काम चालू हो गया है। अनुसूचित जाति की बच्चियों के पढ़ने के लिए जो 97 लाख के छात्रावास की घोषणा की है, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ-साथ माडल स्कूल चौहटन के अन्दर, एसीजेएम कोर्ट चौहटन के अन्दर, फास्ट ट्रैक कोर्ट चौहटन के अन्दर, शेडियो को तहसील बनाया, शेडियो को उपखण्ड कार्यालय बनाया। नर्बदा से जल लाने के लिए 540 करोड़ रुपए की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): 322 गांवों को पानी पिलाने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा करके यह साबित कर दिया कि गांव के गरीब के क्षेत्र का विकास करना, शहर का विकास करना और राजस्थान को आगे बढ़ाने का किसी ने काम किया है तो वह हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी अशोक जी गहलोत साहब ने किया है। इन्होंने पूंजीपतियों का काम किया, इन्होंने उद्योगपतियों का काम किया। अपने सगे सम्बन्धियों से पैसे बटोरने का, जो काम किया है यह बीजेपी वालों ने किया है।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री पदमाराम (चौहटन): राजस्थान के अन्दर वापस कांग्रेस की सरकार आएगी। राजस्थान यह साबित कर देगा कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने चार साल के अन्दर राजस्थान के विकास के लिए जो योजनाएं लागू की हैं, वे सब सराहनीय योजनाएं हैं। 90 परसेंट योजनाएं गांवों के अन्दर लागू हो गई हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान के इस बजट के पक्ष में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, राजस्थान के विकास के लिए, गरीब के विकास के लिए, किसान के विकास के लिए जो बजट बनाया है उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बनवारी लाल सिंघल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, बजट 2013-14, पूर्व वक्ताओं ने जैसा कहा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब सदन के नेता के रूप में बजट का भाषाण पढ़ दिया तो कांग्रेस को इसमें सुर में सुर मिलाने की बात तो स्वाभाविक ही है। आप हां पक्ष हैं तो आपसे बुलवाकर इसको वाद-विवाद प्रतियोगिता जैसा बनाने का कोई अर्थ नजर नहीं आता। किन्तु फिर भी यह व्यवस्था है, मैं अपनी बात इस बजट में और वर्तमान परिस्थितियां जो राजस्थान की हैं इस परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रख रहा हूं। आपके माध्यम से मैं राजस्थान की सरकार को अपनी बात कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र जहां से आता हूं यह अलवर जिला है, अलवर शहर मुख्यालय है। वैसे तो मेरा मन है कि इस पूरी फाइल को इस बातचीत के बाद टेबल किया जाए ताकि राजस्थान सरकार की आंखें खुलें। अलवर में अपराध ऐसा लग रहा है जैसे नेशनलाइज हो गया हो, अपराधियों को लाइसेंस दे दिया गया हो। अलवर से भिवाड़ी के बीच में, भिवाड़ी से अलवर या अलवर से भिवाड़ी कोई भी व्यक्ति रात को दस बजे बाद आने और जाने की स्थिति में नहीं है। इस बात का प्रमाण है कि अभी आपकी ही पार्टी कांग्रेस के नेता को सपत्नीक 26 फरवरी, 2013 को लूटा गया। उनकी कार लूट ली, उनको मारा पीटा गया, उनका एटीएम छीन लिया। जब उन्होंने हैण्ड्सअप कर दिये कि हमारी जान बख्श दो, तो उनको सड़क पर खड़ा छोड़ गये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य बजट पर बोलो न आप, यह सब डिमाण्ड पर बोल लेना। डिमाण्ड आएगी तब बोल लेना।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह लोक कल्याणकारी सरकार है, मैं लोक कल्याणकारी सरकार और बजट पर ही बोल रहा हूं। यह डिमाण्ड है मेरी कि अलवर में आप शांति व्यवस्था कायम कराएं। अलवर से केन्द्र में मंत्री भी हैं, अलवर से राजस्थान की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन हमारा जिला अपराध की आगोश में आ गया है। कांग्रेस के नेता लुट रहे हैं, साढ़े आठ करोड़ की बाइक्स एक साल में पार हो रही हैं। 2163 बाइक्स की एक साल के अन्दर एफआईआर लॉज हो गई, 2163 बाइक एक साल के अन्दर पार हुई हैं। आजकल चोरों ने अलवर में जोरदार तरीका अपना लिया है, आजकल ताला नहीं तोड़ते हैं, गेटों को उखाड़ते हैं साइड में रख देते हैं और दो पहिया हो या चौपहिया हो, आराम से ठाठ से उठाकर ले जाते हैं। पुलिस पर राजस्थान की सरकार का इतना इकबाल बुलंद है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह आप डिमाण्ड पर बोल लेना, यह बजट के लिए है तो बजट पर बोलें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। डिमांड पर अवसर मिल जाएगा तो बोल लेंगे लेकिन मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। चूंकि राज्य सरकार की बहुत भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है तो मैं वास्तविकता सामने रख रहा हूं आप मुझे समय दें।

श्री सभापति: डिमाण्ड पर बोल जाना, अभी तो बजट है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अलवर में पुलिस पर रोजाना हमले हो रहे हैं। आप बात करते हैं कि हम इस प्रकार की कानून व्यवस्था दे रहे हैं। कहीं ढाबे पर एसएचओ पिट रहा है, कहीं बदमाश सिपाही को गोली मार रहे हैं। जो बार्डर होमगार्ड आप लगाते हैं। खानों पर अवैध खनन को रोकने के लिए, रात को 12 बजे एडिशनल एसपी छापा मारते हैं तो पता लगता है कि 4 लाख 35 हजार तो रात के 12 बजे तक ही इकट्ठे कर लिये गये। इस प्रकार का हमारी राजस्थान की सरकार का इकबाल है। अलवर में छह वर्षीय बच्ची से बलात्कार होता है, इस तरह की व्यवस्था आप कर रहे हैं।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मेरा विशेष निवेदन है कि कम से कम बजट पर बात आ जाए। अभी तो पूरी की पूरी डिमाण्ड आएगी, पुलिस की डिमाण्ड पर आप बोल लें। सदन चलाना चाहते हो, अभी आठ बजे तक किया है, आप बोलें। आठ बजे तक चलाओ, साढ़े आठ बजे तक चलाओ, काफी माननीय सदस्य बाकी हैं। फिर वापस वही बात हो जाएगी।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अभी आपने सारी बातें बजट पर ही सुनी हैं, मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। आप सारी बात या तो यह कह दें कि बजट में से लिखा पढ़ दें, अपने विचार कोई नहीं रखेगा। यह क्या बात हुई? इधर से कोई कुछ भी बोले? ऐसा नहीं चलता।

बजट 2013-14 में गो-वंश संरक्षण हेतु राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान गो सेवा आयोग को एक करोड़ रुपए की राशि दी, इस 2013-14 के बजट के अन्दर अलाट की है। अभी दूदू में एक +++ भी मंजूर किया है, आप गायों को बचाने की राजस्थान में बात करते हो। पचपदरा से आने वाले भाई बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे कि एक-एक गाय को या तो पाल लो और नहीं तो गाय को गोद ले लो। राजस्थान से कितनी बड़ी गो तस्करी हो रही है?

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, अगर कोई ऐसा तथ्य हो तो अलग बात है, आपने कहा कि बजट में +++ कहीं मंजूर कर दिया, आप इसको एक्सपंज करा दें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं बजट में +++ मंजूर करने की बात नहीं कर रहा हूं। आप मेरी बात में अवरोध खड़ा करना चाहते हैं। दूदू में +++ की मंजूरी सरकार ने दी है, मैं बजट में घोषणा की बात नहीं कर रहा हूं। आप मेरी बात को अवरोध में खतम करना चाहते हैं, आपको पता है कि कुछ न कुछ ऐसा...

श्री सभापति: आपके पास है क्या कुछ ऐसा?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): राजस्थान गो सेवा आयोग को एक करोड़ रुपए देने की घोषणा हुई है कि नहीं हुई?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपके पास है क्या कुछ ऐसा? दूदू का कोई है क्या आपके पास में?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं प्रमाण दूंगा आपको, उसका आज नहीं तो कल दूंगा।

श्री सभापति: कल देंगे जब तक इसको एक्सपंज कर दें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): गो-वंश की तस्करी राजस्थान से हो रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं, आप बैठिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मेरे बोलते ही पता नहीं क्या तकलीफ हो जाती है, मेरे समझ में ही नहीं आता है। सभापति महोदय, आप हमारा संरक्षण करें, हम अपनी बात कह रहे हैं। जो गलत हो, आप हमको बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सदन ठीक चल रहा है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): गो-वंश संरक्षण हेतु राजस्थान गो सेवा आयोग को एक करोड़ रुपए की राशि दी गई है। मेरा यह कहना है कि अलवर में पूरे ज़िले में गायों की तस्करी की रोज ख़बरें छपती हैं। आजकल तो ऊंटों की तस्करी और ले जाकर उनको खाने की परम्परा शुरू हो गई है। गायों की तस्करी, ऊंटों की तस्करी रोकी जाए। अभी भिवाड़ी में, मैं

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

कानून-व्यवस्था की फिर बात कर रहा हूं, इतना बड़ा विस्फोटकों का जखीरा पकड़ा गया। अगर विस्फोट हो जाता तो 45 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र उससे बिलकुल तबाह हो जाने की स्थिति थी। ऐसी स्थितियों पर विस्फोटक की खेप पकड़ी, अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से किसी भी दिन यह अलवर जिला हमारा ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि पता लगेगा, अलवर जिला नक्शे पर ही था, और कहीं भी स्थिति नहीं है दूसरी देखने की।

(19.00 बजे)

जैसे जोधपुर में और दूसरे जिलों में ग्रामीण और शहर के एस.पी. दो लगा रखे हैं, अलवर में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, तस्करी बढ़ रही है, सोने की नकली ईंटों का काम हो रहा है, अलवर में भी दो एस.पी. लगाये जाने की मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय से इस बजट की अपनी बातचीत के माध्यम से मांग करता हूं सभापति महोदय, आपके माध्यम से। बजट 2013 में घोषणा की गई जिस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बड़ी जोर से मेजें थपथपाईं। डवलपर एग्रीमेंट पर राज्य सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी पांच प्रतिशत से घटा कर एक प्रतिशत कर दी, मकान सस्ते होंगे। बढ़ाई किसने? एक साल पहले आपने। यह क्या तमाशा कर रहे हो, 2012 में बढ़ा दो 2013 में घटा दो? तो जनता ऐसी बावली पागल थोड़ी हो गई कि इसको पढ़ नहीं सकती, जनता इसको देख नहीं सकती? 2012 में आपने ही बढ़ायी, एक प्रतिशत की पांच प्रतिशत की और उसके बाद आपने ही इसको वापस एक प्रतिशत कर दिया और जोर-जोर से मेज थपथपा रहे हैं। राजस्थान में सत्ता में आने के बाद इस तेरहवीं विधान सभा में आपने डीएलसी कितनी बार बढ़ायी? आप यह कह रहे हैं कि आम आदमी के घर का सपना हम पूरा करेंगे। राजस्थान के इतिहास में डीएलसी बढ़ाने का काम मुख्य मंत्री के द्वारा नहीं हुआ था लेकिन 2009 में सबसे पहले आपने आते ही डीएलसी पच्चीस प्रतिशत जयपुर में और दस प्रतिशत पूरे राजस्थान में बढ़ाने का काम किया है। सबसे पहले आपने मकान, दुकान, जमीन-जायदाद की कीमत बढ़ाने का काम किया। इसके बाद लगातार आपने हर वर्ष डीएलसी में बहुत भारी बढ़ोतरी करने का काम किया।

सभापति महोदय, 2010-11 के बजट में माननीय मुख्य मंत्री ने एक घोषणा की थी, वह घोषणा कब तक पूरी होगी? सरकार का तो विदाई समारोह होने वाला है और घोषणाएं अभी तक सारी अधूरी। मैंने जो कहा अभी, डवलपर

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

एग्रीमेंट पर आपने बढ़ाया था पैसा और अब आपने घटाया। सबसे बड़ी बात तो यह है, ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार के पास विशेषज्ञों की कमी है। राजस्थान सरकार ने पावर आफ अटार्नी को दो टुकड़ों में बांटा रिवोकेबल और इर्रिवोकेबल। इर्रिवोकेबल तो पावर आफ अटार्नी होती ही नहीं है। बिना वेतन के किसी व्यक्ति को सहमति के आधार पर ही नियुक्त किया जाता है अपना काम करने के लिए। निष्ठा संदेहप्रद हो जाए तो उसको रिवोक करने का चौबीस घंटे अधिकार होता है। किसी को पावर आफ अटार्नी के रूप में इर्रिवोकेबल अधिकार कभी नहीं दिया जा सकता। लेकिन राजस्थान की सरकार ने इस राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए 2010-11 के बजट में बिन्दु संख्या-279 में घोषणा की कि हम रिवोकेबल पावर आफ अटार्नी पर दो प्रतिशत के स्थान पर स्टाम्प ड्यूटी को 0.2 प्रतिशत करते हैं। 2010-11 के बजट की घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई। मैंने जब प्रश्न लगा कर पूछा तो अलवर में मार्च, 2010 से जनवरी, 2012 तक राशि प्राप्त की 10 लाख 17 हजार 37 रुपये। अगर आपने वास्तव में इसको घटा दिया होता तो आपके पास चंद रुपये की राशि रह जाती, हजारों में रह जाती।

सभापति महोदय, 2013-14 के बजट में आरयूआईडीपी की बात की गई। अलवर में आरयूआईडीपी के काम से जो टंकियां बनीं, मेरे पास प्रश्नों के जवाब के सारे दस्तावेज मौजूद हैं, अधिकतम काम वो हैं जो 2003 से 2008 के बीच राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकृत किये थे- चाहे वो ओएचएसआर के हों, जीडब्ल्यूआर के हों, या पाइपलाइन का काम हो। अब जो नया काम इस सरकार के समय में हुआ है, उस काम ने अलवर शहर की सारी व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया। सड़कों को तोड़-तोड़ कर लाइन डालने का जो काम हुआ है, रोजाना ट्रक की, किसी बस के फंसने की खबरें समाचार पत्रों के प्रमुख पृष्ठ पर प्रमुख रूप से होती हैं। अभी मेरे कांग्रेस के साथियों ने इधर जो बात की थी, पानी की जो स्थिति है, अलवर शहर में बहुत सारी ऐसी कृषि भूमि बसी हुई हैं जो शहर के परकोटे से लगती हुई हैं राजस्थान की सरकार ने, जलदाय विभाग ने, राजस्व विभाग ने और अन्य विभागों ने मिलकर तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि कृषि भूमि पर पानी के कनेक्शन नहीं दिये जाएंगे। भूमि पर बस गये, मकान बस गये, लोगों ने मकान बना लिये, आप पानी और बिजली के कनेक्शन नहीं देंगे तो उनका जीवन तो आपने ग्रामीण स्तर से भी नीचा कर दिया। लोग गांवों से अपने

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

बच्चों को पढ़ाने-लिखाने के लिए शहरों में आ रहे हैं, रोजगार की तलाश में शहरों में आ रहे हैं लेकिन आपने उनको बिजली और पानी के कनेक्शन से महरूम कर दिया। अब स्थिति यह हो गई है, आप अपने प्रश्न के उत्तर में भी कहते हैं कि इनको कनेक्शन देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। राजस्थान सरकार यह कहती है कि हम सबको पानी पिलाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि आप तो पानी पिलाओगे या नहीं पिलाओगे लेकिन जिन लोगों को आपने बिजली और पानी के कनेक्शनों से महरूम किया है, ये नौ महीने बाद आपको पानी पिलाएंगे, शत-प्रतिशत पिलाएंगे।

अफोर्डेबल हाउसिंग का राजस्थान की सरकार ने जिक्र किया, बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुईं। पूरे राजस्थान में बोर्ड लग रहे हैं, आप कहें तो मैं टेबल कर दूं। बड़े-बड़े वादे और छोटे-छोटे इरादे। आपने कहा कि हमने राजस्थान में शहरों के गरीबों के उन्नयन के लिए, उत्थान के लिए पांच लाख आवासों का निर्माण करने की योजना बनाई है। आपने बजट में भी घोषणा की, आपने चुनाव घोषणा पत्र में भी कहा। अभी एक धोखा देने का काम किया है राजस्थान की सरकार ने, सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में सभी शहर मुख्यालयों पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाये गये, उनमें पांच लाख लिखा गया है आदमकद साइज में और उसमें नीचे लिखा है बड़े छोटे-छोटे अक्षरों में-92,751 आवासों का निर्माण जारी/पूर्ण/भूखण्ड आबंटन एवं 41,000 मकानों की स्वीकृतियां जारी। तो इसमें से वास्तविकता क्या है, कितने बन गये, कितने अपूर्ण हैं, कितनों का काम जारी है, कितनों की आपने स्वीकृति जारी कर दी? 41,000 की कि 92,000 की? अगर पांच लाख में 92,000 को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी उपलब्धि 18 प्रतिशत है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो, साहब, मैंने बोलना शुरू किया है। आधा-आधा, पौन-पौन घंटे लोग बोल रहे हैं, आप मेरे साथ ही ऐसी गड़बड़ क्यों करना चाहते हो?

वृद्धावस्था, विधवा अवस्था पेंशन, विशेष योग्यजन पेंशन की घोषणा इस बजट में की गई। मैं इस बात के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का स्वागत करता हूं कि आपने इसमें पच्चीस साल की उम्र की सीमा हटा दी। लेकिन आपने इसके साथ एक नया अड़ंगा फिट कर दिया। एक उपखंड स्तरीय अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी जिसमें जन प्रतिनिधि भी होंगे।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्पष्ट घोषणा क्यों नहीं की कि स्थानीय जन प्रतिनिधि होगा। आज तक जैसे राजस्थान की सरकार जन प्रतिनिधियों के साथ में मनमानीपूर्वक दुर्व्यवहार कर रही है, दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है, इसी प्रकार का इसमें करेंगे। जो जन प्रतिनिधि जहां का होगा उसके अलावा दूसरे जन प्रतिनिधि को बैठाएंगे। अपने क्षेत्र की जनता की चिन्ता तो स्थानीय जन प्रतिनिधि ही करेगा। सभापति महोदय, इसमें कहीं भी यह लिखा हुआ नहीं है कि स्थानीय जन प्रतिनिधि को इस कमेटी का सदस्य बनाया जाएगा।

सभापति महोदय, एक घोषणा की गई है विशेष सड़क निर्माण निधि बनाने की। अब चूंकि चुनावी वर्ष है, हमारे सारे कांग्रेस के भाई, सत्तासीन भाई कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। इसका मतलब राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने इनको चुपके से अण्डर-द-टेबल यह बता दिया है कि विशेष सड़क निधि बना रहे हैं जिसमें आप-आपको सड़कें देंगे। जहां से भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों के लोग जीते हैं, वहां कोई सड़कें नहीं मिलेंगी। माननीय सड़क निर्माण मंत्रीजी, पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी बैठे हैं आपसे मेरा निवेदन है, आप भी कृपया इस बात को ध्यान रखें, मंत्रीजी, कि इस तरह का व्यवहार किसी भी जन प्रतिनिधि, ...(व्यवधान) पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब बैठे हैं न।

राजस्थान सरकार बार-बार अनुसूचित जाति/जनजाति, ओबीसी, सभी छात्रों को बड़ी-बड़ी छात्रवृत्ति की घोषणाएं करती है। हजारों की तादाद में छात्र सड़कों पर घूमते हैं। आपने जिन निजी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता दे रखी है वो निजी शिक्षण संस्थान आप लोगों के, सरकारी अधिकारियों और बाकी के प्रशासनिक अमले की मिलीभगत के चलते उन लोगों को घुमा रहे हैं। ऐसे छात्र जिनकी पढ़ाई केवल छात्रवृत्ति पर निर्भर करती है, उन छात्रों को आज तक छात्रवृत्ति के पैसे दो-दो, तीन-तीन साल से नहीं दिये गये, सभापति महोदय।

मुख्यमंत्री दवा वितरण योजना, इसमें बड़ी जोरदार बातें सारे लोगों ने कही हैं। चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य सुरेन्द्र सिंह जी जाड़ावत ने भी कहा है, सभापति महोदय। उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही है कि, साहब, 5 करोड़ 37 लाख रुपये की दवा 16 लाख लोगों को बांट दी। मैंने इसका जोड़-बाकी लगा लिया, बनिये का बेटा हूं। हिसाब लगा लिया, 33.30 रुपये की दवाई आपने राजस्थान में एक आदमी को कुल दी, 33.30 रुपये की। हिसाब लगा लो, अन्तर आ जाए तो बता देना। 33.30 रुपये की दवाई से आपने

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

लोगों का इलाज किया। मैं आपको एक प्रमाण सहित बात बताता हूं, एक दवा आती है बायोसिप टैबलेट। बड़ी-बड़ी बातें कीं आपने-वो इंजेक्शन दिया हमने, वो सुई दी, वो टैबलेट दी, वो गोली दी, वो सिरप दिया। आपने दी बिलकुल ऐसी कि एक बार मेरे पास एक एसएमएस आया था कि आप बताइये, हवा फ्री की है कि कीमत की है। तो किसी दूसरे बच्चे ने कहा कि अंकल चिप्स का पैकेट खरीद लो, पता लग जाएगा, हवा फ्री की है कि पैसे की है। तो यही स्थिति राजस्थान की सरकार कर रही है, हवा में चल रही है। बायोसिप टैबलेट का मार्केट में से सैम्पल उठाया गया, सैम्पल चेक कराया गया-500 एम.जी. की टैबलेट आती है, एंटीबायोटिक टैबलेट होती है। बड़े विश्वास के साथ मरीज अस्पताल में आता है, बायोसिप टैबलेट डाक्टर लिखता है, तीन दिन में ठीक हो जाएगा। 14 एम.जी. दवाई निकली है। राजस्थान सरकार की रिपोर्ट सदन की टेबल पर रख सकता हूं। 500 एम.जी. टैबलेट दिन में तीन बार खाएगा 1500 एम.जी., इसके बदले में आप उसको 14 एम.जी. के हिसाब से 42 एम.जी. में ठीक करना चाहते हो। कम से कम सरकार अपने आइने में झांक कर तो देखे।

चुनाव घोषणा पत्र में डीजल और पैट्रोल की स्थानीय दरों में कमी की आपने बात की थी, आपको लग रहा है कि मुझको कम समय में कनक्लूड करना चाहिए। राजस्थान की सरकार आम आदमी की बात करती है, राजस्थान की सरकार बड़े-बड़े बजट प्रस्तुत कर रही है। राजस्थान की सरकार ने जब आम आदमी को पैट्रोल और डीजल की दरों में कमी करके राहत पहुंचाने की बात की थी तो पिछले चार साल में जितनी बार भी पैट्रोल और डीजल की दरों में बढोतरी हुई है, उन समस्त पर से कम से कम वैट को वापस लेने की घोषणा राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय करें अगर सरकारी तौर पर दरों में कमी की घोषणा नहीं करते हैं तो। मैं मेरे साथी प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी की बात को ही आगे बढ़ाता हूं, सभापति महोदय, किसानों से धोखा करके 2008 में राजस्थान की सरकार ने वोट ले लिये। किसानों को कहा गया कि आपकी जमीनों की अवाप्ति होगी, हरियाणा की तर्ज पर अवाप्ति कानून बनाएंगे। कहां है वह अवाप्ति कानून? कौनसी हवा में है? आज भी किसानों को डंडा दिखाया जाता है। किसानों की जमीनों को जबरन छीनने का काम किया जा रहा है। अगर वे जमीन नहीं देंगे तो उनकी जमीनों पर जबरन इन्तकाल दर्ज करवाये जा रहे हैं। उन पर गार्ड लगाये जा रहे हैं, उन पर

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

फैंसिंग करवाई जा रही है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार का चाल, चरित्र और चेहरा दोहरा क्यों प्रतीत हो रहा है?

राजस्थान की सरकार ने किस प्रकार से जन प्रतिनिधियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया है कि राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी से स्थानीय जन प्रतिनिधि बाहर, यूआईटी की सभी समितियों से, स्थानीय निकायों की समितियों से स्थानीय जन प्रतिनिधि बाहर। कौन रखेगा अपने क्षेत्र की जनता की बात? इसके अलावा कृषि उपज मण्डी की समितियों से बाहर।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): समाप्त कर रहा हूं, साहब। मेरे अलवर विधान सभा क्षेत्र में जहां 90-95 प्रतिशत मकान फौजियों के, पुलिस वालों के या ऐसे किसानों के हैं जिन्होंने अपनी जमीन-जायदाद बेचकर भूखण्ड खरीदे, उनके मकानों को स्थानीय नगर विकास न्यास ने ऐसे तोड़ दिया जैसे रात को तूफान आता है और लोगों के छप्पर गिरे मिलते हैं। 200 लोगों के मकान तोड़े गये। एक बस अड्डा बनाने के लिए योजना पास कर दी, 600 मकानों को तोड़कर बस अड्डा बनाएंगे। यह तो ऐसे लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस का शासन नहीं होकर अकबर और बाबर शासन करने आ गये। तुगलकी फरमान, ले जाओ बुलडोजर, तोड़ दो यहां से यहां तक। अकबर और बीरबल का किस्सा हम कई बार सुनते हैं, अकबर ने बीरबल से कहा कि यह सूत की कूकड़ी ले जा और हजार रुपए इकट्ठे कर के ला। बीरबल ने ले जाकर लोगों के मकान पर लगा दिया। मकान वालों ने पूछा कि क्या होगा? तो उसने कहा कि आपके मकान टूटेंगे। सब लोगों ने चुपचाप पैसे पकड़ा दिये। ऐसा काम राजस्थान की सरकार कर रही है। चित्तौड़गढ़ से आने वाले आदरणीय विधायक महोदय, अभी आपने मांग की है, राजस्थान में 20 हजार हैंड पम्पों की घोषणा मुख्य मंत्रीजी के द्वारा इस बजट भाषण में की गई है, 100 हैंड पम्प प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आएंगे। जियोलोजिक सर्वे रिपोर्ट आ रही है कि डार्क जोन हो गया, पानी 500 फीट गया, 400 फीट गया। यह तो ऐसे लगता है कि +++ होने वाला है। इसलिए होने वाला है, जब आपकी सारी की सारी सर्वे रिपोर्ट कह रही हैं ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अभी खुदे नहीं, किये नहीं और +++ यह क्या है? समाप्त करो आप।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): योजना एडवांस में बन गई न, साहब। घोटाले की योजना ही तो बनी है।

श्री सभापति: बजट पर बात करो न आप सीधी-सीधी।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): जब आपको भी पता है, आसन को भी पता है...

श्री सभापति: आप जो बात कहना चाह रहे हो वह कहो। अभी कुछ हुआ नहीं, बजट पास हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं और आप। सीधी-सीधी बात कहो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं वही कहूंगा जो आपने अभी कही है। मैं भी यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जनता को वास्तव में पानी पिलाना चाहती है तो इन 20 हजार हैंड पम्पों के स्थान पर 20 हजार सिंगल फेज ...

श्री सभापति: कोई सकारात्मक सुझाव दो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आपने भी तो यही बात कही है, साहब।

श्री सभापति: कोई सकारात्मक सुझाव दो। यह क्या कह रहे हो कि +++ यह क्या हो गया?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सकारात्मक ही तो बोल रहा हूं। यह घोटाला ही है, साहब। आपको पता है कि बोर में पानी निकलेगा नहीं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं ऐसी बातों को एक्सपंज करता हूं। अब आप विराज जाओ। श्री शंकर लाल जी बैरवा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सभापति महोदय, अभी अलवर में मत्स्य यूनिवर्सिटी की जो घोषणा की गई ....

श्री सभापति: श्री शंकर लाल बैरवा। अब आप विराजो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सिर्फ एक मिनट। अलवर में मत्स्य यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई, इस मत्स्य यूनिवर्सिटी का पहले नाम था महाराजा भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी। किन कारणों से, किस षड्यंत्र के तहत महाराजा भर्तृहरि जो अलवर की तपो भूमि के संत हैं और दुनियाभर में पूज्य हैं, उनका नाम हटाकर केवल मत्स्य यूनिवर्सिटी किया गया? मैं आपसे मांग

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

करता हूं कि इसको बजट में पुन: संशोधित करके इसका नाम महाराजा भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी किया जाए। इसमें साथ में मेरी मांग है कि इस यूनिवर्सिटी को फोरेस्ट के एरिया में एक व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं पहुंचा कर राजऋषि कालेज में स्थापित किया जाए। मात्र एक कांग्रेस के नेता को लाभ पहुंचाने के इरादे से ...(व्यवधान) जो कि राजऋषि कालेज में पास हो चुकी थी उस यूनिवर्सिटी को जबरन ....

श्री सभापति: हो गई बात, अब अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अब विराज जाओ आप। श्री शंकर लाल बैरवा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): सभापति महोदय, वर्ष 2013-14 के बजट भाषण पर बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। साथ ही माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि वर्ष 2013-14 के इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गरीब, किसान, व्यापारी और मजदूर सबको ध्यान में रखते हुए राजस्थान में इतना अच्छा बजट पेश किया जिसकी प्रशंसा पूरे राजस्थान की जनता कर रही है और कह रही है कि ऐसा बजट न तो पहले कभी किसी सरकार ने पेश किया था और आगे भी अगर कोई इतना अच्छा बजट पेश करेगा तो माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ही कर पाएंगे। 2013-14 के इस बजट में देखा जाए तो माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत ने एक बहुत ही बड़ी मिसाल कायम की है। गरीब वर्षों से सोचता था कि मेरे भी कभी पक्का मकान बनेगा। गरीब की आशा के बारे में कहना चाहूंगा कि द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था उस समय सुदामा जी की आस थी कि अगर मेरा दोस्त, मेरा साथी भगवान कृष्ण है तो एक न एक दिन मेरी गरीबी को मिटाएगा। द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण ने जिस तरह सुदामा का पक्का मकान बनवाया था उसी तरह इस कलयुग में एक नजर से देखा जाए तो माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत हैं जिन्होंने गरीब को याद रखा और 2012-13 के बजट में 50 हजार का मकान बनाने की घोषणा की।

हमारे विपक्ष के सभी नेतागण, सदस्यगण इस बात को उठाते थे कि 50 हजार में मकान नहीं बनता है तो इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 50 हजार के बजाय 70 हजार की घोषणा की कि गरीब के लिए 70 हजार का

(श्री शंकर लाल बैरवा)

मकान बनाया जाएगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी को वह गरीब परिवार, बीपीएल परिवार सपने में भी नहीं भूल सकता है कि आज जो हमारा मकान बनाया है वह अशोक जी गहलोत ने बनवाया है।

अभी बातें आ रही हैं, कह रहे हैं कि क्या कर दिया। दवाइयों के बारे में बोल रहे हैं, मकानों के बारे में बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आपकी ऐसी ही मंशा होती तो पूर्व में आपकी सरकार थी, उस समय आप भी एक आवास योजना चालू करके गरीबों के मकान बनवा देते।

माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने जननी शिशु सुरक्षा योजना लागू की। जननी शिशु सुरक्षा योजना के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि गांव, ढाणी और मजरे में निवास करने वाले जो गरीब परिवार हैं, उनके घर तक डाक्टर नहीं जा सकता था। इतनी गरीबी थी कि उनके पास नायन के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। मैं आपकी सरकार के समय की ही बात बता रहा हूं, पांच साल पूर्व अगर किसी के डिलीवरी होती, बहन के होती, पुत्रवधु के होती, उस समय उस गरीब आदमी को विचार करना पड़ता था कि हमारे घर में डिलीवरी है, 10 हजार, 50 हजार एडवांस में रखे हैं, न जाने अपने को किसी पीएचसी में डिलीवरी नहीं होगी तो सीएचसी में जाना पड़ेगा, उदयपुर जाना पड़ेगा या चित्तौड़गढ़ जाना पड़ेगा, ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए 25-30 हजार रुपये रखने पड़ते थे। माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, आत्मा पर हाथ रखकर बताएं कि पांच साल पहले अगर डिलीवरी घर में होती थी तो यही बात सोचनी पड़ती थी कि हमारे घर के अन्दर पैसे रखे हैं, किस समय कौनसा टाइम आ जाए। लेकिन इस बात का माननीय अशोक जी गहलोत ने पूरा ध्यान रखा। हमारी माताओं-बहनों का ध्यान रखा और जननी शिशु योजना लागू की। साथ ही 108 एम्बुलेंस लागू की, 104 एम्बुलेंस लागू की। 108 नम्बर लगाते ही, 104 नम्बर लगाते ही गाड़ी सीधे उनके घर पर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद डिलीवरी वाली माता-बहन को गाड़ी में ले जाती है। गाड़ी में पूरा स्टाफ लगा हुआ है और उसमें एक ऐसा उपकरण लगा हुआ है जिसका सीधा सम्पर्क एसएमएस जयपुर से होता है, 108 नम्बर लगाते ही जयपुर बात हो जाती है। माता-बहन को गाड़ी में लेने के बाद भी किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो सम्पर्क करने से जयपुर में बैठा हुआ डाक्टर उनको बता देगा कि फलां इंजेक्शन लगा दो, फलां ड्रिप चढ़ा दो, फलां गोली दे दो ताकि वह सुरक्षित सीएचसी तक पहुंच सके। ऐसी-ऐसी माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने

(श्री शंकर लाल बैरवा)

योजना लागू की। उसके बाद भी अगर अस्तपाल में सीधी डिलीवरी हो जाती तो कोई तकलीफ नहीं, अगर सर्जरी करने की जरूरत पड़ जाती तो सारा खर्चा सरकार वहन कर रही थी। इसके अलावा अगर परिवार का साथ में कोई नहीं है, अकेली महिला है, साथ में कोई आने वाला नहीं था, उस समय ब्लड की जरूरत पड़ जाती तो भी हमारी सरकार ने ब्लड देने की व्यवस्था की है। मुख्य मंत्रीजी ने पूरे राजस्थान के मृत्यु दर के आंकड़े मंगवाये थे, उनको देखा तो उन आंकड़ों के अन्दर या तो बच्चे-बच्ची की मां मर जाती थी या वह बच्चा बच्ची मर जाता था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसकी भी व्यवस्था कर दी। डिलीवरी वाली माता-बहन को डिलीवरी से छुटकारा पाने के बाद नई जिंदगी मिलती है। नई जिंदगी मिलने के उपरान्त सात दिन तक उसको तान चलने की सम्भावना रहती है, तान की बीमारी चल जाती है। मैं खुद लेकर गया हूं, उदयपुर लेकर गया हूं। डिलीवरी होने के 6 दिन बाद तान चल गई थी उस महिला को मैं उदयपुर लेकर गया। अस्पताल में जाकर इलाज करवाया। इस बात को भी मुख्य मंत्रीजी ने ध्यान में रखते हुए सात दिन तक उस महिला को अस्पताल में रोकने की व्यवस्था कर दी। उसका सारा खर्चा सरकार वहन कर रही है। कितनी बड़ी सरकार की घोषणा है, इसको अगर आप नजरअंदाज करते हैं, इसकी आप तौहीन करते हैं, यह सम्भव नहीं है। आप जिस तरह से तौहीन कर रहे हो, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं लेकिन मैं इस बात को कहूंगा कि सत्य को सत्य बताना चाहिए। सोने को सोना बताना चाहिए और कतिर को कतिर बताना चाहिए। आप सोने को कतिर बता दोगे यह सम्भव नहीं है। दिल में नहीं भाती यह बात कि हम सोने को कतिर कैसे बता रहे हैं।

इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और भी कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिनके बारे में पूरा सदन चर्चा कर रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 250 की आबादी के गांव जोड़ने की बात की। 500 से 250 की आबादी के गांव जोड़ने के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि कपासन विधान सभा क्षेत्र में सड़सठ गांवों के अन्दर डामर रोड जाएगी, यह कोई बुरी बात है? हमारे रोड़ का काम चल गया, देवस्थान जोड़ने का, पहले मुख्य मंत्रीजी अशोक जी गहलोत हैं जिन्होंने देवस्थान जोड़ने का निर्णय लिया, देवस्थान तक डामर रोड पहुंचाई। और वे काम पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा मिसिंग लिंक का काम भी लगभग पूरा हो गया है। कुछ अगर बाकी रह गया है तो वह भी

(श्री शंकर लाल बैरवा)

हो जाएगा। यह भी मुख्य मंत्रीजी ने बहुत अच्छी योजना लागू की। गरीब और गांव तक सड़क का काम किया तो हमारे मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने किया।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नि:शुल्क दवा योजना लागू की, आप बता रहे हो, खराब दवा है, गलत दवा है। गलत दवा आप भी अपनी सरकार के अन्दर चलाते तो मैं मान लेता कि वास्तव में आपकी सरकार ने भी गरीबों का ध्यान रखा है। नि:शुल्क दवा अगर मान लो माननीय वसुन्धराजी लागू कर सकती थीं तो इस बात पर मैं यह कहना चाहूंगा कि सत्य को सत्य कहें। राजस्थान सरकार चाहे कोई-सी भी हो, लेकिन विधान सभा राजस्थान का भविष्य बनाने वाली विधाता है, यहां बैठकर अपन राजस्थान का भविष्य बनाते हैं। असत्य बोलना, इसमें अगर अपन यह बोलेंगे तो आदमी की वैसी ही मंशा हो जाएगी कि वास्तव में दवाई खराब है, तो वह बंगाली के यहां जाएगा, बंगाली हाई डोज यूज करेगा। बंगाली हाई डोज यूज करने के बाद अगर वापस वह बीमार हो गया तो चाहे आप उदयपुर ले जाओ, चाहे चित्तौड़ ले जाओ, चाहे एसएमएस जयपुर लाओ, उसको मरना ही मरना है। यह एक बहुत बुरा संदेश जा रहा है, गरीब दवाई लेने में हिचक रहा है कि वास्तव में लोग बता रहे हैं कि गलत दवाई है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, हम सारे विधान सभा के सदस्य हैं, हमारे सन्तों ने भी एक बात कही थी कि सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा है। कोई डिलीवरी वाली माता-बहन है, आप खुद उनको अस्पताल लेकर जाओ, उनकी सेवा कराओ, बीमार को अस्पताल लेकर जाओ, इलाज कराओ, मुफ्त दवा और नि:शुल्क दवा का प्रयोग कर आदमी की जान बच जाए, बहन की जान बच जाए तो यह मान लो कि खूब बड़ा पुण्य कर दिया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं पेंशन के बारे में। पहले काफी गरीब लोग जो पेंशन के पात्र थे, वे वंचित रह गये। बीपीएल के अन्दर भी ऐसा ही हुआ। आपकी सरकार थी उस समय बीपीएल सर्वे हुआ था। आपके कार्यकर्ताओं ने ऐसी सर्वे कराई कि भगवान उनका कैसे भला करेगा, कि जो उनके मिलने वाला था, जिसके घर में ट्रैक्टर था, जिसके बीस बीघा जमीन थी, उसको तो बीपीएल बना दिया और जो गरीब आदमी है, जिसके झोंपड़ी नहीं थी, एक बिस्वा भी जमीन नहीं थी, वह वंचित रह गया। इन लोगों के लिए माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष हम सभी ने निवेदन किया था कि यह सर्वे वापस कराया जाए। बीपीएल सर्वे हो जाएगा तो बीपीएल पात्रता रखने वाला इंसान है वह

(श्री शंकर लाल बैरवा)

बीपीएल सर्वे में जुड जाएगा। मुख्य मंत्रीजी ने प्रशासन गांवों के संग अभियान चालू किया और प्रशासन गांवों के संग अभियान चालू करने के बाद कितने ही लोगों को बीपीएल में जोड़ा गया। पेंशन के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही थीं, आफिस में चक्कर लगा रही थीं- विधवा मां-बहनें, वृद्ध माता, इस बात को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ध्यान में रखकर प्रशासन गांव के संग अभियान चालू किया। एक भी अभियान मैंने नहीं छोड़ा है, सब अभियान में मैं गया हूं। मैंने बैठकर जो भी विधवा माता-बहनें थीं, उनके पेंशन के लिए फार्म भरवाये, पीपीओ जारी कर दिया। जो वृद्धावस्था में थे उनके भी जारी हो गया। कई तरह से जो वंचित रह रहे थे, 50-50 साल से जो गांव में बसे हुए थे, मकान बने हुए थे चरागाह भूमि में बने हुए थे, बेनाम भूमि में बने हुए थे और कई वर्षों से गांव आबादी में बना हुआ था, लेकिन पट्टा नहीं मिल पा रहा था। उस पट्टे की व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्रीजी ने करवायी। वह परेशान हो रहा था कि बगैर पट्टे मकान का लोन नहीं मिलता है, बिना पट्टे नल का कनेक्शन नहीं होता है, लाइट कनेक्शन नहीं मिलता है। कई दिनों से वह परेशान था तो यह भी व्यवस्था हमारे मुख्य मंत्रीजी ने प्रशासन गांवों के संग अभियान में की। कितने ही भाइयों को पट्टा दिया गया, उनकी समस्या खतम की। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को तो बहुत धन्यवाद देता हूं कि गरीबों को बहुत ज्यादा उन्होंने ध्यान में रखा। सदन में बैठकर अपन असत्य बोलें तो यह बहुत बुरी बात है। जैन धर्म के 25 बोल लिखे हैं, 25 बोल के अन्दर गुरु और शिष्य की बात होती है। शिष्य पूछता है, गति कितने प्रकार की है? कहे, हे शिष्य, गति चार प्रकार की है। गुरुदेव, कौन-कौन सी? कहे त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति और नर्क गति। तो शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या करने से कौनसी गति प्राप्त होती है? तो गुरुजी ने कहा, हे शिष्य, जो जीव झूठ बोलता है, छल कपट करता है और जीव हिंसा करता है वह फिर मर करके नर्क गति को प्राप्त होता है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: यह गति के लिये है।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): बैठें आप, सदस्य महोदय, आप विराजो। मैं बीच में बोलता नहीं। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मेरे समय में ...(व्यवधान) ऐसी तकलीफ हो रही थी। यह तो सारे बजट में नहीं है। (व्यवधान) कमाल करते हो आप लोग वास्तव में।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): मैं झूठ बोलने की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अब आपके कान में रुई डली हुई है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अच्छी गति बता रहे हैं कि क्या करने से अच्छी गति मिलती है।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): मैं सारी चीजें नहीं बता रहा हूं, वह लेख की बता रहा हूं। कोई बगैर लेख की बात नहीं बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह बजट में लिखा हुआ है क्या? इधर से कुछ भी बोलो, छूट है। (व्यवधान)

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): आपको गर्मी कैसे हो रही है, भाई साहब? इसका मतलब असत्य आप ही ज्यादा बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): यह बिलकुल स्पष्ट हो गया है इसका मतलब आप असत्य बोल रहे हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): अगर असत्य नहीं बोलते तो मेरे से बैर किस बात का होता? दर्द होना नहीं चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आपको भी आनन्द आ रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): मैं निवेदन करना चाहता हूं, शिष्य पूछता है कि, गुरुदेव, क्या करने से मनुष्य गति प्राप्त होती है? हे शिष्य, जो सदा सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, छल-कपट नहीं करता है, जीव-हिंसा नहीं करने वाले जीव मर करके वापस मनुष्य गति को प्राप्त होते हैं। हे गुरुदेव, नर्क गति किसे कहते हैं? हे शिष्य, नर्क गति उसे कहते हैं जो गंदी

(श्री शंकर लाल बैरवा)

नाली और कीड़ा, जो कीड़े जन्मते हैं, गंदी नालियों के अन्दर, मल-मूत्र के अन्दर, वह एक नर्क है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधान सभा एक विधाता है और इस विधाता के अन्दर बैठ करके कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना हमेशा के लिये अच्छा रहेगा आपके लिये।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भूपाल सागर उप-खण्ड कार्यालय खुलवा दिया, भूपाल सागर थाना भी खुलवा दिया, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। पांच बार एम.एल.ए. चुनकर आये हैं कपासन विधान सभा क्षेत्र से, कपासन विधान सभा में एक ही मांग है कालेज की। महाविद्यालय नहीं है। महाविद्यालय नहीं है तो कपासन के गरीब, सबसे ज्यादा गरीब परिवार निवास करते हैं, सबसे बड़ा धर्म शिक्षा का है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मेरा थोड़ा-सा निवेदन सुनो, साहब, मेरे बहुत पीड़ा है। कपासन में कालेज नहीं खुला तो मैं वहां मुंह बताने लायक भी नहीं हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी समस्या कपासन विधान सभा की है, कपासन की एक ही मांग है, कालेज। कालेज के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां सबसे ज्यादा एस.सी; एस.टी; गरीब परिवार निवास करते हैं, प्राइवेट कालेज में बच्चे और बच्चियों को उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करा सकते, इसलिये कालेज अगर खुलवा देंगे तो वे लोग दुआ देंगे । सबसे बड़ा दान विद्या दान है। अगर एक-एक छात्र-छात्रा को करोड़-करोड़ रुपये दे देंगे तो भी उनकी जिन्दगी नहीं निकल पाएगी।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मेरा थोड़ा निवेदन है, मेरी पीड़ा को सुनना पड़ेगा। मान लो, एक-एक करोड़ रुपया भी अपन एक-एक छात्र-छात्रा को दे देंगे तो उनकी जिन्दगी नहीं निकल पाएगी। लेकिन एक कालेज खोल कर विद्या दान कर दोगे तो बच्चों की जिन्दगी ही नहीं बल्कि उनकी सात पीढ़ियां पनपेंगी, वे सातों पीढ़ियां आपको दुआएं देंगी कि गरीब के बच्चे पढ़ गये, उच्च शिक्षा प्राप्त कर गये, उनकी जिन्दगी बनाई और उनका परिवार चलेगा। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटिया नीर। धर्म करते धन न घटे, कह गये दास कबीर। तो मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि हमारे महाविद्यालय खोलने की कृपा करें।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द भंसाली। आप जल्दी करें।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): साथ ही पाहुना उप तहसील की मांग कर लूं कि उप तहसील पाहुना खुल जाए। उप तहसील बासाड़ो को क्रमोन्नत करके तहसील बनवा देंगे तो हमारे वहां बासाड़ो में सांवरिया सेठ का मंदिर है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): सांवरिया का बड़ा मंदिर है, वहां आये दिन तहसील की जरूरत पड़े, अगर वहां उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत कर देंगे तो सांवरिया सेठ भी आप लोगों का भला करेंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों से माफी चाहूंगा कि कुछ भी कह दिया हो तो छोटा भाई समझ कर आप मुझे माफ करना। सभापति महोदय, मुझ को बोलने के लिये समय दिया उसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय नौ बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय नौ बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 9 बजे तक बढ़ाया गया।

अब मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अभी कई माननीय सदस्यों को बोलना है, डिमाण्ड के ऊपर भी आप बोलेंगे, मेहरबानी करके जो अपने-अपने आवश्यक सुझाव हैं, वे अगर आप देंगे तो यह समय जो बढ़ाया है उसके अन्दर काफी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिल जाएगा। घण्टी बजाने के बावजूद भी अगर आप लोग बराबर बोलते रहेंगे तो माननीय सदस्य बहुत कम संख्या में बोल पाएंगे। मैं चाहूंगा, मेरा निवेदन आपसे है कि 5-5 मिनट से ज्यादा आप नहीं लें तो बेहतर होगा। इससे बहुत माननीय सदस्य बोल पाएंगे। यह पूरे सदन की भावना है। श्री कैलाश चन्द भंसाली।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापतिजी, मैं आज सदन में सर्वप्रथम पूरे पश्चिमी राजस्थान की ओर से, मरुधरा की ओर से माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत साहब का बहुत-बहुत हार्दिक अभिनन्दन करता हूं। भैरोंसिंह शेखावत और पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा बाड़मेर में रिफाइनरी लगाने का जो प्रयास किया गया था, उसका फल इनको मिला है, यह सबके लिये खुशी की बात है। पूरा देश विशेषकर हमारा प्रदेश इससे बहुत लाभान्वित होगा। अभी कपासन वाले सदस्य कह रहे थे, सोना, चांदी और रुपये की बात कर रहे थे, मुझे वही बात याद आ गयी। 1972 की बात है, पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जोधपुर पधारे थे उस समय स्टेडियम में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। उस सभा में पूर्व प्रधान मंत्रीजी को जो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष भी थे, रूपादान से तौला गया, चांदी से तौला गया। तो किसी अख़बार वालों ने, अभी साढ़े चार वर्ष पूर्ण होने पर फिर लिखा था कि इनको हमेशा फल मिलता ही है क्योंकि इनके जस लिखा हुआ है, जस। यही लिखा हुआ था, जस लिखा हुआ है। किसी ने चुटकुला दिया, इन्होंने वह काम कर दिया और राजीव गांधी साहब के बड़े गहरे मित्र हो गये। आज तक वह फैमिली फ्रैण्ड हैं। इसलिये वह जो भी काम कराना चाहते हैं, वे काम हो जाते हैं। तो मैं इस बात के लिये उनका अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने यह प्रयास किया। पश्चिमी राजस्थान के अन्दर बाड़मेर में ही नहीं, मेरे जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र के पांच इंडस्ट्रियल एरिया भी उसमें सम्मिलित हैं, सबमें पांच हजार इकाइयां लगेंगी जो पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उत्पादन करेंगी और सारे जोधपुर का आर्थिक विकास हो जाएगा, राजस्थान का आर्थिक विकास हो जाएगा। तो उसके लिये उनको धन्यवाद।

परन्तु साथ-साथ मुझे दु:ख भी है, जितनी बातें बजट में कही गयी हैं उनमें जोधपुर की घोर उपेक्षा हुई है। कोई विकास का नया काम पिछले साढ़े चार साल में हुआ नहीं। सब काम हुए हैं सेंटर की मदद से, क्योंकि इन पर सेंटर मेहरबान है, दयावान है। राज्य सरकार का एक भी बड़ा प्रोजैक्ट, हजार करोड़ या दो हजार करोड़ लगा हुआ, ऐसा एक भी प्रोजैक्ट नहीं लगा। सबसे बड़ी दुविधा जोधपुर की है कि जोधपुर में कनैक्टिविटी नहीं है। एयर कनैक्टिविटी होने से हमारे एक्सपोर्ट का अभी जो धंधा है वह 16 हजार करोड़ का है, वह दो साल में 30 हजार करोड़ का हो सकता है। मतलब बढ़ सकता है, अगर जल्दी से जल्दी जोधपुर की कनैक्टिविटी हो जाए। 3 कार्गो फ्लाइट्स के

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

लिए और 9 सवारी फ्लाइट्स के लिए हो जाए तो सारे जोधपुर की विश्व से कनैक्टिविटी हो जाएगी।

इसी के साथ-साथ आज सबसे बड़ी समस्या है कि एक भी इंडस्ट्रियल एरिया रीको ने डवलप नहीं किया है। जोधपुर के कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, शिल्पकार तथा हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों की मांग रहती है कि हमको सस्ती जमीन दें, चाहे आप एक हजार गज ही दे दें, जिससे हम हमारा अच्छा-सा काम चलाकर देश के उत्पादन के साथ-साथ एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं और हमारा स्वयं का आर्थिक विकास भी हो सकता है। उसमें ज्यादातर लोग दस्तकारी, हस्तकारी, चुंदड़ी, लाख का काम करने वाले हैं, ऐसे सब लोगों का भला हो जाएगा जो मंशा अशोक गहलोत साहब की है।

इसके साथ में मेरी मांग है कि हस्तशिल्प को 50 परसेंट में, एस.एम.ई., कुटीर उद्योग और छोटे, बहुत छोटे उद्योगों को 25 परसेंट रिजर्व प्राइस पर तथा मीडियम साइज के जो बड़े उद्योग हैं उनको 25 परसेंट रिजर्व प्राइस पर तथा बड़ा विशेष उद्योग लगाने वाले को 50 से 75 परसेंट पर भूमि उपलब्ध करवाई जाए।

मैंने मद्य निषेध के लिए पहले भी निवेदन किया था। गुजरात से लोग आकर राजस्थान में दारू-खोरी करते हैं, तस्करी होती है। रात को आठ बजे बाद वहां मंडियां लगती हैं और उसके साथ में शारीरिक शोषण का काम भी चलता है। आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं। तम्बाकू और गुटका बंद करने का संकल्प दिया जाए। अभी हमारे अलवर के भाई ने कहा था कि गायों के बछड़ों की बड़ी तस्करी होती है। मैं आंखों देखी आपको कह रहा हूं। परसों एक ट्रक भरकर आया था, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको रोका और पुलिस में दिया। मालूम पड़ा कि वे आगे जाकर बाड़मेर-चौहटन में बूचड़खाने को सौंप दी गई। तो इसको रोका जाना चाहिए।

सबसे बड़ी जो जोधपुर की दर्द भरी कहानी है, वह मैंने आपको पहले भी बताने की कोशिश की परन्तु नहीं बता पाया क्योंकि मुझे समय नहीं मिला, स्वाइन फ्लू की। अभी राजस्थान में तो है पर जोधपुर में 445 पाजिटिव आये हैं उसमें से करीब 112 लोग मृत्यु लोक में पधार चुके हैं क्योंकि यहां बच्चों के लिए जो टानिक आता है, जो लिक्विड आता है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

इलाहाबाद कुम्भ में जो शहीद हुए हैं उन 16 लोगों को 25 लाख प्रति व्यक्ति मुआवजा दिया जाए तथा जो घायल हुए हैं उनको एक लाख दिया जाए। इसी तरह से मेहरानगढ़ की हमारी पुरानी मांग है कि जो लोग शहीद हुए 93 लोग, उनके बच्चों के लिए एफ.डी.आर. दी जाए कम से कम पांच लाख की, जिससे उनका भविष्य अच्छा बन सके। इसी तरह से प्रसूताओं की जो 39 डैथ हुई हैं, उनको भी मुआवजा दिया जाए।

सार्वजनिक निर्माण के लिए आप सबने कहा कि हमने सब दर्शनीय स्थानों को, सार्वजनिक स्थानों को जोड़ दिया है। मेरी मांग है, मैं ऐसे धार्मिक स्थानों के नाम बता रहा हूं कि आप कहेंगे कि वहां की लिंक रोड खराब कैसे है? मैं दस दिन पहले चार जगह पर जाकर आया हूं- नाकोड़ा- जोधपुर-बाड़मेर-खैड से मांजी-सा के मंदिर तक, ओसियां से रामदेव पोकरण तक, जोधपुर से पाली तक चार लाइन आधा पड़ा है और वहां पर जो माताजी का मंदिर है, वहां तक। फिर बिलाड़ा आई माता, दांताराम, पिपाड़, निम्बाय, इन सारी रोड्स पर हमारा रोज आना-जाना है, ये सब खुदी हुई पड़ी हैं। कहीं पर सीवर लाइन बन रही है कहीं पर और तरह का ब्रिज बनाने में सब सड़कें खुदी पड़ी हैं, लोग चल ही नहीं सकते।

जोधपुर की एक बड़ी समस्या यह भी है कि जोधपुर पानी पर तैर रहा है। इतना पानी है वह केवल नाले में बहाया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि उसको खेती में दिया जाए। जैविक खाद बनाई जाए और फल-फूल की खेती की जाए।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

ऐसा है, सर, मेरा एक विनम्र निवेदन है, मैं सुबह से बैठा हूं, पांच मिनट के लिए विनम्र निवेदन कर रहा हूं। जब भी मेरा नम्बर आता है तो मुझे समय कम दिया जाता है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आप मेहरबानी करें।

श्री सभापति: बोलिए।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): धन्यवाद।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): माननीय सभापति महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): मैं एक छोटा -सा निवेदन करना चाहूंगा। उन्होंने दूदू में +++ खोलने की बात अभी कही थी माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री सभापति: वह एक्सपंज कर दिया गया है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): माननीय सभापति महोदय, दूदू में कोई +++ नहीं खोला गया है।

श्री सभापति: वह एक्सपंज कर दी, अब आप क्यों कुरेद रहे हो? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): इसके अलावा एक और निवेदन करना चाहूंगा कि मीट प्रोसेसिंग यूनिट की बी.जे.पी. गवर्नमेंट के समय में जिला उद्योग केन्द्र और प्रदूषण बोर्ड ने स्वीकृति दी थी। हमारी सरकार के आने के बाद जो हमारी जानकारी में आया, उसको हमने प्रदूषण बोर्ड से निरस्त करवा दिया है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आपने प्रदूषण बोर्ड से निरस्त नहीं करवाया, निरस्त प्रदूषण बोर्ड ने किया है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): प्रदूषण बोर्ड में हम लोग गये हैं, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिये हैं और हमने उसको निरस्त करवाया है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): चारदीवारी हो गई, मंत्रीजी, मशीनें लग गई हैं उसमें। आपसे निवेदन यही है, कोई वाद-विवाद नहीं है, वह +++ नहीं खुले, बस इतनी-सी बात है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं होगा। विराजिए।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): आप निश्चित रहो, दूदू में कोई भी +++ खुल नहीं सकता।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): क्योंकि बी.जे.पी. गवर्नमेंट में ऐसा हुआ था, वह हमारी जानकारी में आया और हमने रुकवा दिया।

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं श्रीमान को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने यहां सदन में घोषणा की है कि बूचड़खाना दूदू में नहीं लगेगा। मैं उनकी बहुत-बहुत सराहना करता हूं। साधु-संतों ने दस दिन पूर्व ही मुझे नाकोड़ा में कहा कि यह काम करवाओ, बूचड़खाना नहीं खुलना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। सरकार को इसके लिए धन्यवाद।

आम आदमी की सरकार की बात कहते हैं कि आम आदमी की सरकार है। पांच रुपये आपने डीजल पर बढ़ाया, तीन रुपये पैट्रोल पर बढ़ाया और साढ़े आठ रुपए रसोई गैस पर बढ़ाया। सारी गृहिणियों के बजट को खलबला दिया है। आम आदमी महंगाई से त्रस्त हो गया है। केन्द्र सरकार ने तो किया सो किया, राज्य सरकार में मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है। वे इतने दयालु हैं, इतना काम करना चाहते हैं, आम आदमी की हमदर्दी में रहना चाहते हैं, उनको कम से कम पांच प्रतिशत का फायदा देना चाहिए। वैट का जो 26 परसेंट है उसको 20 परसेंट करें, सबको 20 परसेंट करके आम आदमी को राहत दें तो उससे सारा प्रदेश और 200 लोग प्रसन्न होंगे। ऐसा काम करें ताकि हमारी माताएं-बहिनें तथा हम स्वयं महंगाई के त्रास कुछ कमी महसूस कर सकें।

मेरा माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन है, ट्रांसफार्मर्स की इन्होंने बहुत व्यवस्था की परन्तु जोधपुर के लिए मैंने बार-बार कहा है, सी.एम.डी. साहब को भी कहा है, दस स्थान हैं जहां पर वायर लटक रहे हैं। आपने जो ट्रांसफार्मर लगाया वह या तो खम्भे पर लगा दिया या घर के पास में लगा दिया। बच्चों का हाथ जाए और बरसात में कई गाएं भी मरती हैं। मैंने आपको दस स्थान बताये हैं परन्तु यदि मैं पूरी जांच करूंगा तो करीबन 25 स्थान होंगे जहां पर उन ट्रांसफार्मर्स को दूसरी जगह पर लगाएं या उन ट्रांसफार्मर्स को पूरा पैक करें।

चिकित्सा मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं, मैं उनको कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा। मथुरादास माथुर अस्पताल में चाइल्ड वार्ड तैयार है, आप जल्दी से जल्दी उसे करें। धर्मशाला में आम पैसेंजर के लिए एक करोड़ की योजना के लिए दानदाता तैयार हैं, वह शिलान्यास करवाना चाहते हैं। ढाई करोड़ रुपए की धर्मशाला महावीर इंटरनेशनल के प्रीमिसेज में ही लगाएंगे। उसके विस्तार के अन्तर्गत सरकार ने मंजूरी दे दी है इसलिए यह काम शीघ्र करवाया जाए।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

उम्मेद अस्पताल में कचरा हटाने का/संग्रह करने का अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है, सारा हास्पिटल बदबू मार रहा है। मरीज पहले भी संक्रमण से बहुत बीमार हुए तथा जो 39 मौतें हुईं, उसका कारण भी संक्रमण था। उम्मेद अस्पताल में पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। ए.सी. आधे काम करते हैं, कूलर्स भी आधे काम करते हैं जबकि आज कल मरीजों की संख्या और डिलीवरी की संख्या भी बढ़ गई है। 2500 डिलीवरीज हर माह हो रही हैं जो कि एशिया का रिकार्ड है। इसलिए वहां पर यह सारी व्यवस्थाएं की जाए। एडिशनल वार्ड और बनाए जाए।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमान, निवेदन है। नव-चौकियां में, महिला वार्ड में, ... (व्यवधान) 30-30 बैड का बने और मधुवन में 60 बैड का जच्चा-बच्चा वार्ड भी बने तो इससे उम्मेद अस्पताल में कुछ भार कम हो जाएगा। एक बड़ा चिकित्सालय मधुबन डिस्पेंसरी में खोलें जहां पर जगह बहुत है। इसी तरह से एम.जी.एच. में बर्न यूनिट को जल्दी प्रारम्भ किया जाए। उसमें कुछ इक्विपमेंट्स आने हैं, वे जल्दी से मंगाये जाएं। स्टाम्प ड्यूटी में जो आपने कमी की है, उसके लिये धन्यवाद। परन्तु माताओं को 100 प्रतिशत ड्यूटी नहीं लगनी चाहिये। सामाजिक न्याय की बात जब आप कर रहे हैं श्याम सैकण्डरी विद्यालय में बाथरूम एवं लेट्रिन नहीं है। उद्योग भवन में जो छात्रावास है, उसमें लेट्रिन एवं बाथरूम नहीं है, छत नहीं है। मधुबन में नये रूम्स बनाने और ठंडे पानी की व्यवस्था करनी है। उद्योगों में जगह-जगह प्याऊ और बैंचें लगाई जाएं ताकि लोग आराम से बैठ सकें। एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए, शायद केन्द्र सरकार ने कुछ ऐसी मंजूरी दी है, ऐसा अखबारों में पढ़ने को मिला है। वह झालामण्ड में ही बनाया जाए, क्योंकि झालामण्ड तीनों अस्पतालों से पांच से सात किलोमीटर दूर है, बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही मैं कहूंगा कि सहकारी विभागों के चुनाव नहीं होते हैं। दवाइयों के सलेक्शन में जन प्रतिनिधियों को नहीं बैठाया जाता है। घटिया दवाइयां बिक रही हैं और लूट मची हुई है। सारी पर्चियां जो आती हैं, सब डाक्टर्स कहते हैं कि दवाइयां बिलकुल बेकार दवाइयां हैं, इनको लेने से आप ठीक नहीं हो पाएंगे। मुफ्त दवाई योजना की भी सरकार मानिटरिंग करे और बच्चों को जल्दी ठीक होने वाली दवाइयां दी जाएं।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्रीजी से निवेदन है कि कुत्ते एवं गाय रोटी नहीं खा रहे हैं, ऐसा आपका आटा है। मेरा यह निवेदन है आप अच्छा गेहूं ही दें। ए पी एल को पांच किलो गेहूं ही दे दें, आटा नहीं दें। आटा उसको कम्पलशन में लेना पड़ता है, उसको चावल लेना पड़ता है और शक्कर तो हर आदमी लेना चाहता है। शक्कर तो लेने को तैयार है। युवाओं के खेलने के लिये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी आपको कुछ बता रहे हैं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सदस्य, राज फोर्टिफाइड आटा है, उसके लिये तो लाइनें लगती हैं। अगर आपको कोई शिकायत है क्वालिटी में, तो आप मुझे बताएं। उस मिल के खिलाफ उसी दिन कार्यवाही करेंगे, एक भी जगह की शिकायत आएगी तो।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): सर, एक मिनट मेरा निवेदन सुनिये।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उसी दिन मिल का लाइसेंस सस्पैण्ड कर देंगे, एक भी जगह की शिकायत आएगी तो। लोग खा रहे हैं, बहुत पापुलर है, लाइनें लगती हैं। मैं व्यक्तिगत निवेदन कर रहा हूं, अगर आपको एक भी जगह की शिकायत आए, मैं सभी माननीय सदस्यों को कह रहा हूं, एक भी जगह की शिकायत आएगी, उस मिल का लाइसेंस उसी दिन सस्पैण्ड कर देंगे।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): मेरा आप निवेदन सुनें। एक जगह की शिकायत की है, डी एस ओ सिंह साहब को दी है, उसके बाद में भी आप चाहते हैं, मेरा निवेदन है...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सरकार का इरादा है, पहले गेहूं जो देते थे ए पी एल का, उसका ब्लैक होता था, वह ए पी एल परिवारों तक गेहूं नहीं पहुंचता था। आटे की कोई मंडी नहीं है। आटे की क्वलिटी में कोई शिकायत हो, मैं तो सभी माननीय सदस्यों को निवेदन करता हूं, कहीं भी हो सकती है, हम उसी दिन उस मिल का लाइसेंस का सस्पैण्ड कर देंगे।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): मेरा निवेदन सुनिये। मैंने दस जगह का इंस्पेक्शन किया है, मेरे रजिस्टर में दस्तखत हैं, परन्तु कुछ कार्यवाही नहीं हुई।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आपको उस मीटिंग में बुलाया था, पर, श्रीमान, आप आये नहीं। आपकी शिकायत सुनने गया था पर आप पधारे ही नहीं थे।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): आप मेरा निवेदन सुनिये, मैं प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे बम्बई काम से जाना था, नहीं तो मैं निश्चित आता। मैंने मैसेज भी किया था आपको कि मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल वर्क से जा रहा हूं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): जिस दिन आप कहोगे मैं फिर आ जाऊंगा और आपकी सुनूंगा। शिकायत हुई तो वहीं पर कार्यवाही करूंगा। आप तारीख दे दो, उसी दिन आ जाऊंगा।

श्री सभापति: माननीय भंसाली साहब, जरा जल्दी करो। थोड़ा जल्दी करो।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): झालामण्ड में एक स्टेडियम बनाया जाए। शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में तीन ग्राउण्ड बनाये जाएं जिसमें एशियाड के टूर्नामेंट होते हैं उसके लिये पूरी तैयारी की जाए। सरकार उसमें सहयोग दे और मैंने भी कह दिया, मैं भी 20 लाख रुपये विधायक फण्ड से उसमें दूंगा। एक विकलांग का केस मैंने पहले भी बताया था, मुख्य मंत्रीजी ने तब एक लाख रुपया दिया था। अभी तक उसका साढ़े 8 लाख रुपये पारितोषिक का बकाया है, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से, सदन से प्रार्थना करूंगा कि उस विकलांग बच्ची के साढ़े 8 लाख रुपये दिलवाएं, उसने बड़ी मेहनत से मैडल जीता है विकलांगों के एशियाड में। (व्यवधान)

श्री सभापति: जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य बुजुर्ग आदमी हैं, थोड़ा सम-अप करो जल्दी। जल्दी-जल्दी सम-अप करो।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): मैं जल्दी ही निवेदन कर रहा हूं। पांच मिनट में मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरा निवेदन है कि वह बच्ची विकलांग है, उसके माता-पिता मुख्य मंत्रीजी से मिले थे सर्किट हाउस में। उन्होंने कहा, मैं देखूंगा, पर उसमें अभी कुछ हुआ नहीं। मैंने भी मुख्य मंत्रीजी को निवेदन किया कि उसके आज भी साढ़े 8 लाख रुपये बाकी हैं। उन्होंने कहा, मैं इसकी बात करूंगा।

इसी तरह से अभी बात कर रहे थे पेंशन की। एक डाक्टर साहब की

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

2002 में डैथ हुई है, आज तक उनकी पेंशन नहीं बनी। मुख्य मंत्रीजी ने मेरे सामने निर्देश दिये थे। कहा सर्विस डायरी बन रही है, वह सर्विस डायरी कल तारीख तक नहीं आई है। तो इससे ज्यादा मैं क्या प्रूफ दे सकता हूं कि ऐसी व्यथा है मेरी और उस विडो की, जो बार-बार आकर मुझे कहती है कि आप एम एल ए कैसे बन गये। आप हमारे एम एल ए हो और इतना-सा काम नहीं करवा सकते। मैंने कहा कि मैंने मुख्य मंत्रीजी से आपको मिलवा दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी डायरी कम्प्लीट करवाकर तुरन्त पेमेंट करवा दूंगा, दूसरे दिन ही पेमेंट हो जाएगा। परन्तु न तो डायरी बनती है और न ही पेमेंट होता है। मैं यहां मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट में बार-बार चक्कर काट रहा हूं, सब यही कहते हैं कि, साहब, वहां बालेश्वर गयी हुई है, बालेश्वर से नहीं आ रही है। वह गुम गयी है। उस फाइल को रखने का किसका जिम्मा है? जो मर गया क्या उसका जिम्मा था? किस तरह की बात करते हैं। और फिर कहते हैं पारदर्शी, भ्रष्टाचार रहित सरकार है। यह खोखली बात करना छोड़ो और धरातल पर आओ, मेरा यही निवेदन है।

श्री सभापति: माननीय श्री रामलाल जी मेघवाल।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत धन्यवाद। जिन बातों का मैंने आपसे निवेदन किया है, उन पर आप कुछ गौर फरमाएंगे और जोधपुर की जनता को राहत दिलाएंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल जी मेघवाल।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर): माननीय सभापति महोदय, आपने आज मुझे बजट की चर्चा में भाग लेने के लिये समय दिया उसके लिये मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने जो बजट पेश किया है, वह बजट सभी समाज, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी को मद्देनजर रखते हुए आमजन के लिये प्रस्तुत किया, उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं और बजट के लिये भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। बजट में आप देखो तो शिक्षा के लिये नवीन स्कूल खोलने का, माध्यमिक में क्रमोन्नत करने का, सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने का प्रावधान किया, उससे शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा। विद्युत के बारे में

(श्री रामलाल मेघवाल)

विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य अभी फरमा रहे थे कि आपने विद्युत का उत्पादन किया नहीं। विद्युत के बारे में बहुत ही ज्यादा हल्ला कर रहे थे। माननीय सदस्यों को यह पता होना चाहिये कि गत सरकार में भारतीय किसान संघ जो आपकी पार्टी का है, आपकी सरकार में कितने धरने दिये जाते थे और कितने आन्दोलन होते थे। अगर अभी किसानों को बिजली नहीं मिलती होती तो आप साढ़े चार साल में राजस्थान में एक धरना तो बताओ कि उस जगह धरना दिया। आपकी पार्टी का भारतीय किसान संघ है, उन्होंने भी धरना नहीं दिया, क्योंकि वे भी विद्युत विभाग और इस सरकार की विद्युत प्रणाली से खुश हैं। इसलिये उन्होंने धरना नहीं दिया। इसके साथ मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय विद्युत मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जालौर विधान सभा क्षेत्र में 33 केवीए के 23 जी एस एस ग्रिड स्वीकृत किये। स्वीकृत ही नहीं बल्कि बनकर तैयार होकर उनसे बिजली सप्लाई चालू हो गयी।

(20.00 बजे)

मेरे विधान सभा क्षेत्र में 220 केवी का एक जीएसएस बन रहा है। नींव भर गई है, काम प्रगति पर है, शिलान्यास के इन्तजार में महीने, दो महीने रुका हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और विद्युत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उसका जल्दी से जल्दी शिलान्यास कराएं। साथ ही, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, आप जालौर 33 केवी के उद्घाटन समारोह में पधारे थे और उसमें आपने सुराना के 132 केवी के जीएसएस की घोषणा की थी। पहले सिराना में 132 केवी के जीएसएस की भाजपा की सरकार में घोषणा हुई थी लेकिन वह आज दिन तक भी नहीं बना। वह दूसरी जगह दे दिया। तो जनता को याद दिलाने के लिए सुराना का जीएसएस और सिराना का जीएसएस चालू करवाने की कृपा करें। भाजपा सरकार में घोषणा हुई, उस जीएसएस को वापस दिया जाए, जनता आपको आशीष और दुआ देगी।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य सिंघल साहब यहां से पधार गये हैं, वह फर्मा रहे थे कि अलवर में कानून की व्यवस्था क्या है। माननीय सदस्य, आप यह बताएं कि अलवर में सोने की ईंटों का धंधा अभी चालू हुआ? यह आपकी सरकार में भी चल रहा था। इसी तरह कपासन से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि असत्य बोलने वाले को नरक मिलता है। तो

(श्री रामलाल मेघवाल)

किसी भी माननीय सदस्य को एतराज नहीं हुआ, आपको एतराज हुआ। इससे साबित होता है कि आप असत्य बोल रहे थे क्योंकि आपको नाराजगी हुई।

सभापति महोदय, मैं सदन को इस बात से अवगत करवाता हूं, आप लोगों ने कहा कि ये घोषणाएं कब लागू होंगी, ढेर सारी घोषणाएं कर दीं। क्या पहले कभी दो रुपये किलो गेहूं देने की घोषणा की गई? क्या बीपीएल को दो रुपये किलो गेहूं नहीं मिला? अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बीपीएल परिवार के लिए जो एक रुपये किलो गेहूं की घोषणा की है, विधान सभा सत्र खतम होते ही गजट नोटिफिकेशन निकलते ही अप्रैल में उनको मिलना चालू हो जाएगा। इस बात का आप और हम सबको विश्वास रखना चाहिए। मुख्य मंत्रीजी बजट भाषण में जो घोषणा करते हैं, वह घोषणा अवश्य पूरी होती है। वह बजट की घोषणा होती है। हर अधिकारी, इंसान इस बात को समझता है कि यह बजट की घोषणा है। बजट की घोषणा में अवहेलना नहीं होती। ऐसे रास्ते चलते कोई घोषणा कर दे, जैसे बीजेपी सरकार में मेरे विधान सभा क्षेत्र के बाकरा गांव में नरपत सिंह राजवी साहब पधारे थे, उन्होंने एक पीएचसी की घोषणा की थी। पांच साल निकल गये, चार साल पहले निकल गये, अभी लास्ट 2012-13 की घोषणा में मुझे बाकरा में पीएचसी मिली है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और स्वास्थ्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने टेंट लगाया, मेला लगाया और वहां पर बड़े-बड़े भाषण दिये लेकिन उनकी वह घोषणा पूरी नहीं हुई क्योंकि बजट में नहीं थी। उन्होंने रास्ते चलते घोषणा की थी, ऐसी घोषणा पूरी नहीं होती है।

ये तो सारी बजट की घोषणाएं हैं और सदन के सामने घोषणा की है, सभी घोषणाएं पूरी होंगी। इस बजट घोषणा में सभी समाज को, जैसे कि बीपीएल के लिए कहा, यह कोई कम ऐतिहासिक घोषणा है? एपीएल वर्ग या विधवा पेंशन में 25 साल के बच्चे वाली रुकावट थी, विपक्ष और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने गत बजट सत्र के दौरान इस बात का जिक्र किया था, उसको मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस शर्त को हटाकर सभी को इस बात का पैगाम दिया कि वृद्ध और विधवा, उसके दो बच्चे हों, तीन बच्चे हों, 25 साल का हो, 30 साल का हो, उनको पेंशन मिलेगी, वे पेंशन के हकदार हैं।

इसके साथ ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गत बजट में बीपीएल

(श्री रामलाल मेघवाल)

परिवारों को मकान देने की घोषणा की, वह लागू नहीं हुई? अगर वह लागू नहीं हुई होती तो आप इस बात की शंका भी करते कि लागू होगी या नहीं। पहले जो-जो भी घोषणाएं की गई हैं, वे आप सबके ध्यान में हैं। बीपीएल परिवारों को राजस्थान मुख्य मंत्री आवास योजना के तहत, वह इसलिए कि इन्दिरा आवास योजना में दो या तीन साल में मिलते थे और बीपीएल लोग ज्यादा थे, उनको पर्याप्त मकान देने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने सोच कर सभी बीपीएल को आवास देने की यह घोषणा की। सभी बीपीएल को मकान मिल रहे हैं और राशि 50 हजार कम पड़ती थी, उसके लिए इस बजट में 70 हजार रुपये की घोषणा की है। यह अत्यन्त ऐतिहासिक कदम है। यह कदम जन-जन और गरीब के हित में है।

आटा जो एपीएल को मिलता था, वह आठ रुपये चालीस पैसे मिलता था। उसको पर किलो पांच रुपये किया है। यह भी ऐतिहासिक कदम है। राशन पर उपभोक्ताओं को शक्कर 13 रुपये किलो में मिलती थी, उसको 10 रुपये किलो करके ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह आप और हम सभी के लिए सराहनीय होना चाहिए। ऐसी बातों के लिए आपको भी उनको धन्यवाद देना चाहिए।

पहले हज जाने के लिए अनुदान दिया जाता था तो बहुत से माननीय सदस्यगण यह कहते थे कि ये अल्पसंख्यकों को ही देते हैं और हज जाने के लिए ही देते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने अमरनाथ यात्रा के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया है। यह भी ऐतिहासिक कदम है। किसी का बेटा या अन्य कोई यात्रा नहीं करवा सकता, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की, उस राशि से वे यात्रा करेंगे, दर्शन करेंगे। उसकी दुआ भी सरकार को मिलेगी।

सरकारी कर्मचारियों की मांग लम्बे समय से चल रही थी कि छठे वेतनमान का हमें केन्द्र के बराबर लाभ मिलना चाहिए। इस मांग की तरफ किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आयोग गठित किये गये। भटनागर आयोग गठित किया गया, उसने कर्मचारियों के विरुद्ध रिपोर्ट दी। फिर भी उस रिपोर्ट को नजरअन्दाज कर माननीय अशोक गहलोत जी ने कर्मचारियों के हित में फैसला किया है और 2006 से छठे वेतनमान को लागू किया है। उससे पूरे राजस्थान के कर्मचारी मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करते हैं। हर

(श्री रामलाल मेघवाल)

अखबार में बधाई, धन्यवाद देते हैं। अभी हर गली, ढाणी, मोहल्ले में मुख्य मंत्रीजी का आभार है। पहले मैं भी यह समझता था, लेकिन इस बजट के बाद अभी दो दिन शनिवार और रविवार को मैं क्षेत्र में गया और क्षेत्र में लोगों से मिला तो हर इन्सान के मुंह से यह निकलता है कि बहुत अच्छा बजट दिया। अभी-अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य भंसाली साहब फर्मा रहे थे, रसोई का भाव बढ़ा दिया, लेकिन भंसाली साहब इस बात को भूल गये कि मसाले, आटा और रसोई में काम आने वाले सभी सामान से वैट हटा दिया। वो उनको याद नहीं रहा और एक गैस सिलेण्डर के पैसे उनको याद रहे।

माननीय सभापति महोदय, डीजल के बारे में सभी फर्मा रहे हैं कि डीजल, पैट्रोल के भाव कम नहीं कर रहे। आप इस बात को देखें कि पहले आपके घर में इतने साधन थे, किसके पास गाड़ी थी? आज उन गाड़ियों का आकलन भी आप करें कि एक घर में कितनी गाड़ियां हो गयीं, कितने स्कूटर हो गये, कितनी मोटर साइकिल हो गयीं। उसके अनुपात में यह पैट्रोल, डीजल का तो अन्तरराष्ट्रीय भाव है, यह कोई राजस्थान तय नहीं करता है। यह तो अन्तरराष्ट्रीय भाव है, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। आप सभी माननीय सदस्य जानते हुए इस बात का जिक्र करते हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। लेकिन एक बात जरूर है, गांवों में भी यह बात चलती है कि कांग्रेस को विरोध करना नहीं आता और भा.ज.पा. को सरकार चलाना नहीं आता। ये बातें गांवों में होती हैं और किसान लोग ये बातें करते हैं।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

तो यह बात जरूर है कि आपको तो सिर्फ विरोध करना ही है, लेकिन आपको यह भी सोचना चाहिए कि विरोध करना हो उसी बात पर करें, जो अच्छा काम है उसके लिए तो धन्यवाद दें।

माननीय सभापति महोदय ने घंटी बजा दी है, और माननीय सदस्यों को बोलना है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन एक बात मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरा सायला सब-डिवीजन एस.डी.एम. कोर्ट है, तहसील है, थाना है और पहले एस.डी.एम. हैडक्वार्टर पर कालेज की घोषणा की हुई है, मेरे वहां कालेज नहीं है। एक मेरे केथूना में किसान केन्द्र है, वहां स्टाफ है, बिल्डिंग है, जमीन है और एरिया बहुत लम्बा-चौड़ा इर्रिगेटेड है, किसान का

(श्री रामलाल मेघवाल)

क्षेत्र है, गंगानगर के बाद सैकिण्ड नम्बर सायला क्षेत्र का आता है, उस किसान केन्द्र में अगर कृषि महाविद्यालय खोला जाए तो बजट भी कम देना पड़ेगा। जमीन वहां है, खेती बहुत है, उसके अन्दर बिल्डिंग बनी हुई है।

तो इसका मैं धन्यवाद करता हूं और बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री विजय बंसल।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि मैं काफी समय के पश्चात् बोल रहा हूं, अगर दो-चार मिनट ज्यादा हो जाएं तो समय देने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2013-14 का यह बजट इस सरकार का पांचवां और आखिरी बजट है और बजट की घोषणाओं से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि चुनाव की घबरायी हुई पार्टी किस तरह से थोथी घोषणा कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा, 2008 के चुनावी घोषणा पत्र में आपने लिखा था कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो हरियाणा और दिल्ली की तरह पैट्रोल और डीजल पर वैट कम कर किसानों को राहत दी जाएगी। 2011-12 के बजट में भी यह बात उठी थी, कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि चुनावी घोषणा पत्र पांच वर्ष के लिए होता है, हम करेंगे। लेकिन आखिरी बजट में भी इस पर कोई रियायत देने की बात नहीं कही गयी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप वास्तव में ही किसानों के प्रति कोई सहानुभूति रखते हैं तो जब जवाब दें, इस वैट को कम करने की अवश्य घोषणा करें।

माननीय सभापति महोदय, आज से पांच वर्ष पूर्व भरतपुर में मेडिकल कालेज और यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा हुई, यूनिवर्सिटी की घोषणा के समय उसका नाम रखा गया था महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय। लेकिन बड़े दुःख के साथ कह सकते हैं कि भरतपुर रियासत, लोहागढ़ कहलाने वाली भरतपुर रियासत से, पूरे संसार पर राज करने वाले अंग्रेजों ने भरतपुर रियासत को विजयी नहीं किया, उसके संस्थापक का नाम वहां से हटाकर ब्रज विश्वविद्यालय

(श्री विजय बंसल)

किया गया है। मैं मांग करता हूं कि इसका नाम पुन: महाराजा सूरजमल के नाम पर रखा जाए।

साथ-साथ अभी एक प्रश्न के जवाब में यह जवाब दिया गया था कि यूनिवर्सिटी जहां खोली जाएगी, उसकी जमीन के अधिग्रहण करने की प्रक्रिया जारी है। पांच साल पूर्ण होने के पश्चात् अभी तक जमीन अधिग्रहित नहीं की गयी है। माननीय सभापति महोदय, मैं अवगत कराना चाहूंगा कि सावलदास के नाम से एक ट्रस्ट है जिसके पास 456 बीघा जमीन है, उन्होंने दान पत्र लिखकर जिला कलक्टर को दिया है कि जितनी जमीन यूनिवर्सिटी को चाहिए, मुफ्त में देने को तैयार हैं। फिर जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही क्यों कर रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, मेडिकल कालेज की बात करें, घोषणा थी सरकारी मेडिकल कालेज की, इस पांचवें बजट में जयपुर में मेडिकल कालेज की घोषणा, पैसे सहित जमीन और निर्माण के लिए, उसके साथ भरतपुर के नाम पर बताया गया है कि पी.पी.पी. पर चरणबद्ध तरीके से, यानी बीस साल बाद शायद नम्बर आए। इन थोथी घोषणाओं से क्या फायदा है?

माननीय सभापति महोदय, हम सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात करें तो यह तो सही बात है कि आठ-आठ किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कें और पांच किलोमीटर धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें दी हुई हैं, लेकिन अगर मेरे विधान सभा क्षेत्र की हालत देखें तो लगता है कि यह कोई सम्भाग मुख्यालय या जिला मुख्यालय नहीं बल्कि एक गांव है। एम.एस.सी. कालेज से चिकसाना होती हुई यू.पी. बार्डर तक सड़क जो तीन वर्ष पूर्व बनी थी और गारंटी पीरियड में थी, आज कोई वाहन वहां से नहीं निकल सकता। चाहे भरतपुर से डीग जाएं, भरतपुर से बयाना जाएं, चारों तरफ सड़कों का हाल खराब है। हालांकि माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर शिकायत मिलने पर निरीक्षण करते हैं लेकिन बयाना और भरतपुर की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं।

माननीय सभापति महोदय, अभी इस बजट में पहले की तरह मिसिंग लिंक देने की कोई घोषणा नहीं की गयी। अभी किसी सदस्य ने कहा था कि हमारी सरकार ने सभी विधायकों को बगैर भेदभाव के सड़कें दीं। यह कोई नयी बात नहीं थी, पिछली सरकार में भी पूरे 200 विधायकों को इतनी मिसिंग

(श्री विजय बंसल)

लिंक सड़कें दीं गयी थीं, सब को बराबर ही दी गयी थीं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो पांच सौ करोड़ रुपये विशेष सड़क निर्माण निधि में रखे गये हैं, इसका बंटवारा भी प्रत्येक सदस्य के लिए होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हम ऊर्जा के विषय में बात करें, ऊर्जा के विषय में भी चुनावी घोषणा पत्र में यह था कि किसानों को हम थ्री-फेज बिजली आठ घंटे और सिंगल फेज 24 घंटे देंगे। दो सौ में से कोई माननीय सदस्य बता दे कि किसानों को आठ घंटे लगातार थ्री-फेज बिजली किसी भी दिन दी गयी हो।

चार घण्टे बिजली मिलती है वह भी ट्रिपिंग करके। किसान आज परेशान है। किसानों की हालत यह है कि डीजल, पैट्रोल के दाम निरन्तर बढ़ रहे हैं, खाद के दाम ढाई-तीन गुना हो गये, लेकिन किसान का लागत मूल्य वही की वही है। सभापति महोदय, सरकार ने घोषणा की थी, अगर ट्रांसफार्मर चोरी जाता है या फुंक जाता है तो हम बहत्तर घंटे में बदलकर देंगे। हमारे यहां के हालात तो ये हैं, रिकार्ड है मेरे पास, मैं टेबल कर सकता हूं, दो-दो महीने के पश्चात् भी ट्रांसफार्मरों को नहीं बदला जाता है। पढ़ाई के दिनों में बच्चे परेशान होते हैं।

सभापति महोदय, सिंचाई के साधनों की बात करें, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक चिकसाना बांध पड़ता है जो काफी समय से बाढ़ के कारण टूट गया था। मेरे बार-बार कहने के पश्चात भी आज तक उस बांध की मरम्मत, नव निर्माण नहीं हो पाया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर चिकसाना बांध की मरम्मत करा दी जाए तो वहां के आसपास के किसानों के लिए जल स्तर भी बढ़ेगा और सिंचाई का साधन भी बढ़ सकता है।

सभापति महोदय, भरतपुर में पूरे हिन्दुस्तान में पक्षियों के लिए एक सैंक्चुरी है। वह भरतपुर में स्थित है जहां पानी की कमी की वजह से यूनेस्को तक ने यह कह दिया था कि इसको वर्ल्ड हैरिटेज की श्रेणी में से हम हटाने जा रहे हैं। इस पानी का मेन स्रोत गम्भीरी नदी थी, गम्भीरी नदी पर पांचना बांध बनने के पश्चात वह पानी रोक दिया गया जबकि उस गम्भीरी नदी में रियासतकालीन संधि के अनुसार तेरह परसेंट पानी भरतपुर का था। अगर वह पानी वहां से दे दिया जाए तो इस घना को संरक्षण प्राप्त हो सकता है।

सभापति महोदय, जहां तक पेयजल की बात है, मैं धन्यवाद देना

(श्री विजय बंसल)

चाहता हूं मुख्य मंत्री महोदय को जिन्होंने चम्बल परियोजना जो काफी वर्षों से अटकी हुई थी, उसको पूर्ण कराकर भरतपुर के लिए पेयजल की व्यवस्था की। आर यू आई डी पी की लापरवाही की वजह से, पानी तो भरतपुर आ गया लेकिन अभी तक इन्फ्रास्ट्रक्चर न शहरों में और न गांवों में डवलप हो पाया है। कम से कम दो वर्ष लगेंगे। इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पेयजल के बारे में मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि जहां इस तरह की व्यवस्था नहीं है, बीस हजार हैण्डपम्प लगवाए जाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं इस बात का। लेकिन विधायकों की राय से, जहां कम हैं वहीं उनके कहने के अनुसार अगर लगाये जाएं तो उसका सार्थक प्रयोग हो सकेगा।

सभापति महोदय, जहां तक चिकित्सा-स्वास्थ्य की बात है, मेडिकल कालेज की तो बात हो गयी लेकिन सरकारी अस्पताल भरतपुर में जो आर बी एम है, उसकी भयंकर दुर्दशा है। सम्भाग मुख्यालय का हास्पिटल, वहां सी टी स्कैन मशीन खराब पड़ी है, सोनोग्राफी मशीन खराब, चार एक्स-रे मशीन में से तीन खराब पड़ी हैं, एक चालू है। सम्भाग मुख्यालय का अस्पताल है, चारों तरफ से वहां आदमी आते हैं, लेकिन डाक्टरों की भयंकर कमी है । मुफ्त दवाई की आप व्यवस्था करें तो किसी भी गांव की पी एच सी और सी एच सी में आपको दवाई लिखने वाला नहीं मिलेगा, तो इस योजना का फायदा क्या होने वाला है?

सभापति महोदय, भरतपुर के लिए इस बजट सत्र में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, मैं इसके लिए मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद तो देना चाहता हूं लेकिन यह भी कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी और मेडिकल कालेज की तरह यह भी कहीं पंचवर्षीय योजना न बन जाए। इसी साल इसके अधिग्रहण की कार्यवाही कर इसकी कार्यवाही करेंगे तो भरतपुर की जनता निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देगी।

सभापति महोदय, अभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत घोषणाएं हुई हैं कि इतने प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, इतने मिडिल स्कूल खोले जाएंगे, इतने सैकण्डरी और इतने सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले जाएंगे लेकिन आज जितने खुले हुए हैं वहां भी अध्यापकों की संख्या पूरी नहीं है तो इन स्कूलों को खोलने से क्या फायदा होने वाला है? पहले अध्यापकों की पूर्ति करो, उसके बाद स्कूल खोलो तो स्वागत योग्य कदम होगा। मेरा पंचायत मुख्यालय

(श्री विजय बंसल)

बिलोटी, पंचायत मुख्यालयों पर हर जगह सैकण्डरी स्कूल खोल दिये गये लेकिन वहां आज भी उच्च प्राथमिक स्कूल है। शिक्षा मंत्री महोदय विराजे हुए हैं, पंचायत मुख्यालय बिलोटी में सैकण्डरी स्कूल खोलकर अपने इस वादे को अवश्य पूरा करें।

माननीय सभापति महोदय, बात युवा मामले एवं खेलकूद की आती है तो कुश्ती, कबड्डी और अन्य खेलों में आज भरतपुर का स्थान सर्वोपरि है। पिछले तीस वर्षों से राजस्थान केसरी का खिताब भरतपुर को ही आता रहा है। लेकिन वहां जो स्टेडियम बना हुआ है, उसकी बद से बदतर हालत है। सम्भाग मुख्यालय पर इस तरह की घोषणा होती है कि वहां हम कुश्ती संकुल खोलने जा रहे हैं, फलाना खोलने जा रहे हैं लेकिन कोई क्रियान्विति नहीं होती। मेरा अनुरोध इसमें यह है कि अगर कालेज ग्राउण्ड में वह स्टेडियम बनाएं तो शहर के खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा।

अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक घोषणा की थी कि झील संरक्षण योजना में इन-इन जगहों को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। झील संरक्षण योजना केन्द्र सरकार की एक योजना है। मेरे विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में लोहागढ़ के, किसी शहर के चारों ओर बहने वाली सुजानगंगा पूरे हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध थी लेकिन वह गंदगी से त्रस्त हो चुकी है। यू आई टी द्वारा करोड़ों रुपए उसकी सफाई करने पर लगाये जा चुके। आज हालत यह है कि अनेकों दुघर्टनाएं होकर जन हानि हो चुकी है, उसकी मोटवाल टूट चुकी है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, मुख्य मंत्री महोदय, कृपया झील संरक्षण योजना में इस सुजानगंगा को भी शामिल करने की मेहरबानी करें।

सभापति महोदय, भरतपुर जिला पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसके चारों ओर डीग है, गोवर्द्धन है, फतेहपुर सीकरी है, मथुरा है, वृन्दावन है, भरतपुर का पक्षी विहार है, मैं यह मांग करता हूं, और बहुत समय से यह मांग उठी चली आ रही है कि भरतपुर को पर्यटन जिला घोषित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, स्थानीय निकाय की बात करें, मैं भी नगर परिषद का सभापति 1994 से 1999 और 1999 से 2003 रह चुका हूं। निरन्तर रूप से हर कालोनी में कार्य कराये जाते थे। पिछले चार वर्ष पूर्व एक आदेश जारी हुआ कि जिन-जिन कालोनियों का नियमन नहीं है या जो एग्रीकल्चर पर बसी हुई कालोनियां हैं, वहां कोई भी डवलपमेंट के कार्य नहीं

(श्री विजय बंसल)

कराये जाएं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रशासन शहरों के साथ पट्टे वितरित भी हो चुके हैं, इस आदेश को वापस कर वहां भी कार्य शुरू कराए जाएं।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं पहले भी अनुरोध कर चुका हूं, सिर्फ दो मिनट लूंगा।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करो, माननीय सदस्य।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, हम कानून व्यवस्था की बात करें, भरतपुर में कानून-व्यवस्था चौपट हो चुकी है। डेढ़ वर्ष पूर्व एक आई.पी.एस. विकास कुमार को वहां का एस.पी. लगाया गया था, उसने कानून-व्यवस्था की हालत यह की थी कि अपराधी भरतपुर छोड़कर अन्य प्रदेशों में भाग गये थे। जो टकलू गिरोह थे वो वहां से छोड़ चुके थे, औरतें आराम से सड़क पर निकल सकती थीं। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि ऐसे योग्य अफसर को पांच महीने में हटाकर कानून व्यवस्था फिर चौपट करने का काम किया गया है, यह सबसे शर्म की बात है।

मैं एक मांग भी करना चाहूंगा, अनेक थाने खोले गये हैं, चिकसाना थाना मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है, उसका काफी बड़ा एरिया है, उसके अन्डर में एक ऊंचा नगरा पुलिस चौकी आती है, उस चौकी को थाने में क्रमोन्नत किया जाए एवं पीपला में जो चौकी है उसको परमानेंट चौकी बनाया जाए।

अंत में, माननीय सभापति महोदय, एक और मांग करना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं अगर उचित हो तो मेरा समर्थन करें, कि हमारा जो एम.एल.ए. लैड है, इसमें अनेक व्यवस्थाएं हैं कि 20 परसेंट एस.सी., एस.टी. के लिए दिया जाएगा, इतना उसके लिए दिया जाएगा, मेरा अनुरोध है कि राज्य या नेशनल लेवल की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उसमें राइडर लगाया जाए कि पांच परसेंट राशि खेलों के लिए होगी। साथ-साथ पांच परसेंट राशि सामाजिक कार्य हेतु, यानी किसी गरीब का घर जल गया, भैंस मर गयी, दाने-दाने को मोहताज हो गया, हमारी अनुशंसा पर कलक्टर से उसका सर्वे करवाकर उस राशि में से उसकी सहायता हो सके तो यह गरीबों के लिये बहुत ही अच्छा काम होगा।

(श्री विजय बंसल)

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसलिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2013-14 के लिये बजट प्रस्ताव में वार्षिक योजना का आकार 40,139 करोड़ निर्धारित किया। यह बजट राजस्थान के हर वर्ग के लिये, हर आम आदमी के लिये राहत देने वाला है। चाहे बी पी एल हो, गरीब हो, किसान हो, अल्पसंख्यक हो, एस टी, एस सी हो, युवा वर्ग हो, छात्र वर्ग हो, महिला वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, अधिकारी-कर्मचारी वर्ग हो, पत्रकार हो, स्वतन्त्रता सेनानी हो, बुजुर्ग हो, हर आदमी को राहत दी गयी है। यही नहीं, राजस्थान के हर जिले में, हर तहसील में, यहां तक कि हर पंचायत और राजस्व ग्राम तक इसमें कार्य योजना इस तरह की घोषित की गयी है कि राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट राजस्थान के इतिहास में पहला बजट है जो आम आदमी को फायदा पहुंचाएगा। बी पी एल को एक रुपये किलो गेहूं, इंदिरा आवास के लिये 75 हजार रुपये दिये जाएंगे। आम आदमी को रोटी-कपड़ा और मकान चाहिये। रोटी और मकान की व्यवस्था तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहले बजट में ही कर दी थी। इस बजट में गरीब महिला को दो साड़ी और गरीब व्यक्ति को एक कम्बल देकर जो कपड़े की भी व्यवस्था की है, वह बहुत ही लाभदायक है। आज भी गांवों में स्थिति यह है, कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कम्बल नहीं ओढ़ा। जब सर्दी में वह व्यक्ति कम्बल ओढ़ेगा तो सर्दी में गर्मी का एहसास होगा, मैं यह बताना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अल्पसंख्यकों के लिये इस बार अनेक प्रावधान रखे गये हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की छात्रा यदि 60 प्रतिशत से पास करके प्रथम वर्ष में एडमिशन लेती है कालेज में, तो उसको स्कूटी दी जाएगी। यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है।

किसानों के लिये इस बार बजट में घोषणा की गयी है कि दो रुपये लीटर दूध पर अनुदान दिया जाएगा। दूध पर अनुदान देने से किसान को तो फायदा है ही, इससे उपभोक्ता पर असर नहीं होगा। दो रुपये सीधा किसान

(श्री भगवान सहाय सैनी)

को मिलेगा जो डेयरी में दूध देगा और उसका उपभोक्ता पर भी फर्क नहीं पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, किसान को गेहूं के समर्थन मूल्य के बाद डेढ़ सौ रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। डेढ़ लाख रुपये प्रति किसान बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा। यह किसानों के लिये अच्छी योजना दी गयी है।

माननीय सभापति महोदय, युवा वर्ग, छात्रों का भी बहुत ध्यान रखा गया है। अधिकारी-कर्मचारी वर्ग के लिये छठा वेतन आयोग लागू करना, 51 हजार से अधिक कर्मचारी-अधिकारियों की डी पी सी करना, यहां तक कि 47 आर ए एस को आई ए एस बनाना जो 17 वर्षों से लम्बित था, यह कार्य इस साल किया गया है।

(20.33 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पत्रकार बन्धुओं के भी 62 वर्ष की जगह 60 वर्ष किये गये हैं। अधिस्वीकृत पत्रकारों को 5 हजार रुपये दिये गये हैं। साथ में सभी पत्रकारों को जो अधिस्वीकृत हैं, लैपटाप दिया जाएगा।

स्वतन्त्रता सेनानियों के भी 17 हजार से 20 हजार रुपये किये गये हैं। बुजुर्गों के लिये तीर्थयात्रा की व्यवस्था की गयी है।

वृद्धावस्था और विधवा पेंशन में जो पुत्र की शर्त हटायी गयी है यह ऐतिहासिक फैसला है। पूरा सदन इस बात की मांग बहुत समय से करता आ रहा है कि यह शर्त हटायी जाए। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह शर्त हटायी है, बुजुर्गों को बहुत बड़ी राहत दी गयी है। आज के कलियुग में बेटा मां-बाप को रोटी नहीं देता, उनकी सेवा नहीं करता तो 500 रुपये प्रति, पति-पत्नी दोनों की 1000 रुपये पेंशन से उनका काम चल जाएगा।

महंगाई पर रोक लगाने के लिये साबुत मसालों पर वैट समाप्त किया गया है इससे भी काफी फर्क पड़ेगा।

नि:शुल्क दवा की व्यवस्था की गयी है और नि:शुल्क जांच भी अब 1 अप्रैल से चालू हो रही है। यह भी एक ऐतिहासिक फैसला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सामने से माननीय सदस्यगण चर्चा कर रहे थे ऊर्जा की। विद्युत उत्पादन में राजस्थान ने 1998 से 2003 तक

(श्री भगवान सहाय सैनी)

1750 मेगावाट का उत्पादन करके जो रिकार्ड कायम किया था, उस 1750 मेगावाट के भरोसे ही भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल चलाये थे। 5 साल ही नहीं चलाये थे, महारानी साहिबा तो तैयारी कर रही थीं मध्य प्रदेश बिजली भेजने की, लेकिन कांग्रेस के विरोध के कारण उनको फैसला वापस लेना पड़ा।

4 वर्ष में 4628 मेगावाट बिजली उत्पादन की वृद्धि हुई है। जल्द ही राज्य क्षेत्र में 960 मेगावाट और निजी क्षेत्र में 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने वाला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दरों में 5 वर्ष तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी। अभी सामने से कह रहे थे कि दो-तीन बार वृद्धि की गयी। अन्य क्षेत्रों में की गयी होगी, कृषि क्षेत्र में कोई विद्युत दर बढ़ोतरी नहीं की गयी। जो फ्लैट रेट थी वह उतनी ही है, जो 90 पैसे विद्युत रेट थी वह 90 पैसे ही रखी गयी है। 5 साल तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी। 4 वर्षों में लगभग 2 लाख 46 हजार 757 कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं और 75 हजार कृषि कनेक्शन अब देने का प्रावधान रखा गया है।

चिकित्सा क्षेत्र की बात करें तो जब से देश आजाद हुआ तब से राजस्थान में 1649 पी एच सी कार्यरत हैं और इस बार 600 पी एच सी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खोलने की घोषणा की है, वह बहुत अहम फैसला है। 50 पी एच सी से 50 सी एच सी, 50 सी एच सी खोलने का प्रावधान इसमें रखा गया है। 7 अप्रैल से नि:शुल्क जांच की जा रही है और 1 जुलाई से तीसरे चरण में सभी पी एच सी में सभी जांचें नि:शुल्क की जाएंगी। सी एच सी पर धर्मशालाओं के लिये 50-50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। बाहर से जो मरीजों के साथ अटेंडेंट आते हैं, उनको रहने में बड़ी असुविधा होती है, उनके लिये यह व्यवस्था की गयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 64 दंत चिकित्सकों को नियुक्ति दी गयी है। 258 दंत चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रत्येक सी एच सी में दंत चिकित्सक और आंखों का डाक्टर होना चाहिये क्योंकि ये बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। हर पी एच सी में स्त्री रोग विशेषज्ञ होना चाहिये जिससे महिलाओं को परेशानी नहीं हो।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन के अन्तर्गत शर्त थी 25 वर्ष का बेटा होने की, उस शर्त को हटाकर राजस्थान के आम बुजुर्ग को राहत दी गयी है।

पालनहार योजना में 675 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है।

सामूहिक विवाह आयोजनों में जो साढ़े चार हजार रुपये वधु और एक हजार रुपये आयोजक को देते थे, अब 10 हजार रुपये वधु के नाम एफ डी होगी एवं ढाई हजार रुपये आयोजक को दिये जाएंगे। इससे सामूहिक विवाह की प्रक्रिया बढ़ेगी।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 7 सौ रुपये और आंगनबाड़ी सहायिका, साथिन, आशा सहयोगिन का 5 सौ रुपये मानदेय बढ़ाकर एक अच्छा कदम उठाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा कर रहे थे कि 4 साल में बजटों की क्रियान्विति नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले बजट में जिला परिवहन कार्यालय, कालाडेरा में बी एड कालेज और मेगा हाइवे सैंक्शन हुआ था। जिला परिवहन कार्यालय विद्युत चालू हो चुका है, मेगा हाइवे का काम चालू है, बी एड कालेज की बिल्डिंग बन रही है और कालाडेरा में सी एच सी का कार्य चालू हो गया है। चौमूं बाइपास जो 22 साल से काम अटका हुआ था, वह बनकर तैयार हो गया है और फोर लेन का काम भी बनकर तैयार हो गया है।

इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चौमूं विधान सभा क्षेत्र के गोविन्दगढ़ में उप तहसील, चौमूं में ए डी जे और ए सी एम न्यायालय, कस्बा चौमूं व जाटावाली में पुलिस चौकी, जिला परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग टैस्ट हेतु ट्रैक्स के निर्माण की घोषणा की है, मैं इसके लिये बहुत-बहुत आभारी हूं।

पंचायती राज की बात कर रहे हैं, पंचायती राज में 38 हजार थर्ड ग्रेड के अध्यापकों की भर्ती हो गयी है इससे साबित होता है कि पंचायती राज को सुदृढ़ किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब भी ओलावृष्टि, शीतलहर, पाले से फसल नष्ट होती है तो किसानों को मुआवजा भी दिया जाता है। लेकिन जब किसानों की सब्जियां, बेर, आंवला ये जिंस नष्ट हो जाते हैं, उनका कोई मुआवजा नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इसको भी आपदा में शामिल करने के लिए एक कानून बनाएं।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

जिससे सब्जियां, बेर, आंवला भी ओलावृष्टि, शीतलहर या पाले से खराब हो जाएं तो उनको मुआवजा मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों का डीएपी, यूरिया खाद निश्चित रुप से बहुत महंगा हो गया है, डीजल भी बहुत महंगा हो गया है। इसको कोई नहीं रोक सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी से कि किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन 10 एचपी पावर की मोटर तक नि:शुल्क की जाए। जिससे किसानों को राहत मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, गैर आबादी में घरेलू कनेक्शन की जो योजना है, 1 लाख कनेक्शन उसमें दे रहे हैं, लेकिन उससे पार नहीं पड़ेगी। आम बच्चा पढ़ना चाहता है उसमें बिजली के बिना बड़ी दिक्कत होती है। गैर आबादी में हर व्यक्ति जो भी घरेलू कनेक्शन मांगे, उसको कनेक्शन दिये जाएं। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी बैठे हैं, विद्युत कनेक्शन में एस.टी. को कोई प्रायोरिटी नहीं है। एस.टी. को एस.सी. की भांति कनेक्शन देने की प्रायोरिटी की जाए जिससे कि उनको भी फायदा मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैट्रो रेल परियोजना जिसका काम जयपुर में चल रहा है, इसको चौमूं, गोविन्दगढ़ तक ले जाने की माननीय मुख्य मंत्रीजी घोषणा करें तो इसमें काफी फायदा होगा। इससे एक्सीडेंटों में राहत मिलेगी और आम जनता इसका फायदा उठाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करें थोड़ा।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): उपाध्यक्ष महोदय, चौमूं कस्बे में पानी की बड़ी समस्या आ गयी है इसलिए मेरा निवेदन है, पहले भी मैंने मांग की है, कि चौमूं को बीसलपुर जल योजना से जोड़ा जाए। चौमूं में सीवर लाइन स्वीकृत की जाए। चौमूं में जो कि राजधानी का उप नगर है, महिलाओं का 200 बैड का हास्पिटल स्थापित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, चौमूं विधान सभा क्षेत्र में राजौला बांध है जो टूट चुका है और मोरीजा बांध भी टूट चुका है, इनका निर्माण करवाया जाए। ताकि जल स्तर बना रहे। कालाडेरा में एक कोका कोला प्लांट है, उसको पिछले 5 साल से सभी सामाजिक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के लोग बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, इस कोका कोला प्लांट को बंद किया जाए क्योंकि जल स्तर काफी नीचे जाता जा रहा है।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बच्चियों के लिए सरकारी कालेज बासा में और गोविन्दगढ़ में नहीं हैं, वहां सरकारी कालेज खोला जाए। जयपुर-चौमूं के बीच टाटियावास में प्रस्तावित टोल बूथ बनाना जन हित में नहीं है। यह जेडीए सीमा में है। सामोद से जयपुर आने वाले को सामोद में और चौमूं में दो जगह टोल टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए इस स्थान को बदलकर आगे किसी ग्रामीण स्थान में करवाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, धार्मिक स्थानों को जोड़ने हेतु नांगल बलधा से वीर हनुमान जी मंदिर तक और ढोढसर से खाटू श्याम जी तक सड़क निर्माण की स्वीकृति दिलवायी जाए। जयपुर-रींगस रेल लाइन ब्राड गेज स्वीकृत है, लेकिन इसके काम की गति धीमी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि इंटरफियर करके इस ब्राड गेज का काम अविलंब करवाने का प्रयास करें।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा कर रहे थे हमारे सामने वाले और आज एक अख़बार में भी आया है कि चौमूं विधायक ने 4 साल के कार्यकाल में कृषि कार्य में खपत होने वाले डीजल पर किसानों को सब्सिडी व मोटरें, केबल, स्टार्टर आदि नि:शुल्क देने की योजनाओं का लाभ नहीं दिलवाया। विदेशी सहायता योजना का लाभ भी चौमूं तहसील की जनता को नहीं दिलाया। हमारे वरिष्ठ नेता हैं राव राजेन्द्र सिंहजी, उन्होंने यह बात कही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह कल जब बोलें तो ज्ञानवर्धन कराएं कि यह योजना कब स्वीकृत हुई।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप संक्षिप्त करें।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): चौमूं विधायक ने 4 साल के कार्यकाल में कृषि कार्य में खपत होने वाले डीजल पर किसानों को सब्सिडी देने...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आपका नाम नहीं लिया था।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): इसमें लिखा है साफ।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मिनट मैं बोल दूं, आप विराज जाएं।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): एक मिनट, एक मिनट। कालाडेरा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राव राजेन्द्र सिंह ने...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): यह तो अखबार वाले ने लिखा है, मैंने थोड़े ही लिखा है।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): नहीं तो आप खंडन करो इसका।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): हां, तो मैं एक बात बता रहा हूं। इसकी जो वास्तविकता है वह बता दूं कि 2009 तक ...

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): आप कल बता देना।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): नहीं, नहीं, एक मिनट।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): अभी मेरा टाइम है। कल बता देना।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): 2009-10 में सब्सिडाइज्ड डीजल की योजना आयी थी...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, वह पहले अपनी बात तो कह लें। वह एक बार अपनी पूरी बात तो करें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): वह अख़बार की कटिंग पढ़ रहे हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): वह अपनी बात तो कह लें, फिर आप फर्मा लेना।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अच्छा ठीक है। आप फरमा लें।

श्री उपाध्यक्ष: राव साहब, अब समय कम है। माननीय सदस्य भगवान सहायजी, अब आप समाप्त करें।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने वहां कहा है कि चौमूं विधायक ने 4 साल के कार्यकाल में कृषि कार्य में खपत होने वाले डीजल पर किसानों को सब्सिडी देने, काश्तकारों को मोटरें, केबल, स्टार्टर आदि नि:शुल्क देने की योजनाओं का लाभ नहीं दिलवाया।

श्री उपाध्यक्ष: आपके पक्ष की बात है, इसको क्यों रिपीट कर रहे हो?

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): विदेशी सहायता योजना का लाभ भी चौमूं तहसील की जनता को नहीं दिला पाये। कल माननीय राव साहब बोलें तो ज्ञानवर्धन करें, पूरे सदन को ही अवगत कराएं। वैसे चौमूं तहसील की 7 पंचायतें आपके भी आती हैं, आपको भी करवाना चाहिए था। मैंने नहीं करवाया तो आपको करवाना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट कल्याणकारी बजट है, आम व्यक्ति तक पहुंचने वाला बजट है। इस बजट के लागू होने की चिंता कर रहे थे सामने वाले साथीगण, समय पर लागू होगा। हमारे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह सरकार की विदाई की तैयारी है। मैं यह बता दूं कि

(श्री भगवान सहाय सैनी)

यह सरकार दुबारा आने की तैयारी हो रही है, जाने की कोई तैयारी नहीं है। नवम्बर, 2013 में चुनाव होंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती संजना आगरी। आप तो विराजो, माननीय सदस्य।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सारे ही पंडित हो रहे हैं कांग्रेस के लोग तो। भविष्यवाणियां करने में लगे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बैठे-बैठे कोई नहीं बोले। यह अच्छा तरीका नहीं है।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): उपाध्यक्ष महोदय, बजट 2013 की चर्चा पिछले 2 दिन से सदन में हो रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया, वह बहुत ही मीठा है, लुभावना है। लेकिन जब तक मैनेजमेंट नहीं होता है, तब तक सारी बातें अधूरी रह जाती हैं। मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ही अच्छी-अच्छी योजनाएं चलायीं लेकिन योजनाएं क्रियान्वित करने वाले कोई नहीं थे और वे योजनाएं आज दिन तक जनता के बीच में नहीं पहुंच पायीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोजत विधान सभा क्षेत्र के लिए पेयजल के बारे में अवगत कराना चाहूंगी कि वहां की जनता 2700 से 2800 टीडीएस फ्लोराइडयुक्त पानी काम में ले रही है। विगत 4 वर्षों में मुझे जब-जब भी विधान सभा में मौका मिला, मैंने सदन को यह अवगत कराया कि हमारे यहां खारे पानी की समस्या से निजात दिलाया जाए। बजट 2009 से लेकर आज तक। हमारी पूर्व यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने जवाई पाइप लाइन परियोजना को 5 पैकेज में बनाया। उसके थर्ड पैकेज का कार्य पूर्ण हो चुका है। थर्ड पैकेज के दूसरे चरण के अन्दर पाली से रोहिट और रोहिट से सोजत तक कार्य पूर्ण होना था। लेकिन बजट 2010-11 के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सोजत के लिए तीसरे बजट की वित्तीय स्वीकृति जारी की। जो सोजत से लगाकर रोहिट और रायपुर तक पानी उपलब्ध होना था। उपाध्यक्ष महोदय, 3 वर्ष पूर्ण हो गये, मात्र 40 किलोमीटर पाइप लाइन है जो आज भी जारडन और पाली के बीच में अधूरी पड़ी है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को अवगत कराना चाहूंगी कि जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बना रहे हैं, जयपुर की मैट्रो का कार्य पूरे शहर के अन्दर से निकल रहा है, क्या उसमें रास्ते के अन्दर परेशानियां नहीं आयी होंगी। आज

(श्रीमती संजना आगरी)

पाइप लाइन नेशनल हाइवे-14 के ऊपर से जा रही है, बीच में कह रहे हैं कि स्कूल आ रही है, मकान आ रहे हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी है या जनता की? मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि पाली जिले के अन्दर सोजत पानी के मामले में बहुत ही क्रिटिकल एरिया है। आगे मई, जून की गर्मी को देखते हुए अभी यह काम अधूरा पड़ा है। एनएचआई वाले हैं या एनसीसी या जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत जवाई पाइप लाइन परियोजना के एक्स.ईएन हैं, एसई हैं, एईएन हैं या जिला कलक्टर, किसकी लापरवाही रही कि यह काम आज दिन तक बंद पड़ा है? इससे सम्बन्धित कंपनियों को और प्रशासन को सरकार पाबंद क्यों नहीं करती? इसके खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। जगह-जगह पर गड्ढे खोदकर रख दिये। जेसीबी पड़ी हैं, ट्रक पड़े हैं। पाइप लाकर रख दिये। आये दिन कई तरह की दुर्घटनाएं इससे हो रही हैं। लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि यह कार्य अतिशीघ्र शुरू कराया जाए।

इसके साथ ही बजट 2011-12 में जवाई पाइप लाइन का पानी गांवों और ढाणियों को मिले, इसके लिए क्लस्टर योजना की घोषणा की गई है। इससे सोजत और रायपुर के 35 से 40 गांवों को जोड़ा जाएगा जिसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पूर्ण रूप से जारी हो चुकी है। मेरा निवेदन है कि यह योजना अतिशीघ्र शुरू की जाए ताकि जवाई का पानी सोजत विधान सभा क्षेत्र के रायपुर और जैतारण को मिले। इसके साथ ही मई-जून की गर्मी को देखते हुए सोजत विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ट्यूबवैल खुदाये जाएं और हैण्ड पम्पों की स्वीकृति दिलाई जाए ताकि हमारा पश्चिमी बैल्ट जो पानी की समस्या से ग्रस्त है, वहां के नागरिकों को पानी की परेशानी न हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा विभाग के बारे में पिछले चार वर्षों में मुख्य मंत्रीजी को और माननीय मंत्रीजी को बहुत बार अवगत कराया, सोजत सिटी के अन्दर रायपुर और मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र का यह सबसे बड़ा अस्पताल है, यहां 40 से 50 पद स्वीकृत हैं लेकिन 16 या 17 डाक्टर लगे हुए हैं। आज की वास्तविक स्थिति तो यह है कि 7 से 8 डाक्टर लगे हुए हैं। उसमें भी वे गांवों में कैम्प लगाते हैं उसमें चले जाते हैं। एनेस्थीसिया के डाक्टर का मुख्य पद भी हमारे यहां खाली पड़ा है। इससे महिलाओं को बहुत परेशानी होती है।

(श्रीमती संजना आगरी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसी महिला या बालिका के साथ जब किसी तरह का दुष्कर्म या अपहरण का मामला सामने आता है तो इससे सम्बन्धित पुलिस और चिकित्सा डिपार्टमेंट वाले पीड़िता की पहचान को सार्वजनिक कर देते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट वालों द्वारा वायरलैस पर कण्ट्रोल रूम को यह बताया जाता है और उस मां और बेटी की इज्जत को जलील किया जाता है, जबकि आईपीसी की धारा 228-ए के अन्दर ऐसा करने वाले के खिलाफ मुकदमे का प्रावधान है। पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में डाक्टर जांच करने से मुंह छिपाते हैं क्योंकि उनको कोर्ट के अन्दर चक्कर लगाने पड़ते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): सार्वजनिक जगहों पर उस मां और बेटी की इज्जत को तार-तार किया जाता है, उनकी जांच खुले में, सार्वजनिक की जाती है, जबकि कानून में ऐसे मुकदमों की जांच गुप्त तरीके से काले कांच के अन्दर बंद कमरे में या चैम्बर के अन्दर की जानी चाहिए ताकि मां और बेटी की इज्जत को बचाया जा सके। आज दुर्भाग्य की बात है कि गृह विभाग, सीएमएचओ, पुलिस वालों की वैबसाइट पर पीड़िता का नाम आता है। सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार को पाबन्द करना चाहिए ताकि बहन और बेटी की इज्जत को बचाया जा सके।

मैं आपको बताउंगी कि नर्सिंग कर्मचारियों ने अभी इसी विधान सभा सत्र के दौरान 27.2.2013 को उद्योग मैदान जयपुर में विशाल रैली के माध्यम से केन्द्र के समान वेतन की जायज मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इनको केन्द्र के समान जस का तस वेतनमान दिया जाए एवं मैस भत्ता जिस प्रकार से पुलिस विभाग में कर्मचारियों को दिया जाता है, उसके बराबर ही वादे के अनुसार नर्सिंग कर्मचारियों के वेतन बढ़ाये जाएं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोजत विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मास्टर प्लान का सैटेलाइट से जो नक्शा बनाया गया है, नागरिकों के द्वारा जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इसको पुनः संशोधित किया जाए और नये सिरे से इसको बनाया

(श्रीमती संजना आगरी)

जाए। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि गृह सुरक्षा का सिपाही...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह सुरक्षा का सिपाही, होम गार्ड जो पुलिस वालों की तरह ही पूर्ण जिम्मेदारी से अपना काम करता है, उनका वेतन और दैनिक भत्तों में बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है बजट संशोधन में उनके दैनिक भत्ते बढ़ाये जाएं और नियमित भत्ते दिलाये जाएं, इन दोनों को संशोधित आप जरूर करें और इनके वेतन बढ़ाएं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। अब आप विराजिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): इसके साथ ही रोजगार सहायकों का भी मानदेय बढ़ाया जाए। आपने विद्यार्थी मित्रों को मात्र 900 रुपये बढ़ाया, इनको राज़ी किया जबकि...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री कमलजी बैरवा। विराजिये, अब आप विराजिये, माननीय सदस्या, आपको 10 मिनट हो गये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): जबकि हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री ने छठा वेतन आयोग लागू करके राजस्थान की जनता को इसका लाभ दिया, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है...

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): आपने विद्यार्थी मित्रों के 500 रुपये, 700 रुपये, 900 रुपये बढ़ाये हैं, इनको आपको कुछ और नहीं बढ़ाकर, जस्ट डबल करना था, इस महंगाई को देखते हुए।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये, धन्यवाद। माननीय कमलजी बैरवा। अब आप विराजिये, आपको 10 मिनट हो गये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): इनको आपको ध्यान में रखना था। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप विराज जाएं। माननीय सदस्य खड़े हो गये हैं।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्लीज।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या, अब आपका अंकित नहीं होगा। माननीय कमलजी बैरवा।

श्री कमल बैरवा (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने 6 मार्च, 2013 को वर्ष 2014 का जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही साढ़े नौ बजे तक के लिये बढ़ा दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की कार्यवाही साढ़े नौ बजे तक बढ़ाये जाने की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही नौ बजकर तीस मिनट तक बढ़ाई जाती है।

माननीय कमलजी।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री कमल बैरवा (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत द्वारा 6 मार्च को वर्ष 2013-14 का जो अनुमानित बजट पेश किया गया है, मैं उस कल्याणकारी बजट के समर्थन में अपने विचार रखना चाहता हूं। इसमें कोई संशय नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब से सरकार सम्भाली, इन चार सालों में उन्होंने नई-नई योजनाएं लाकर राजस्थान की जनता का विकास करने का प्रयास किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जन कल्याण और राजस्थान के चहुंमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया है। उन्होंने गत चार सालों में नई फ्लैगशिप योजनाएं लाकर राजस्थान की जनता का विकास करने का प्रयास किया, उनमें हैं- मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, मुख्य मंत्री शहरी आवास योजना, मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, मुख्य मंत्री पशु धन नि:शुल्क दवा योजना, मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की

(श्री कमल बैरवा)

गारण्टी अधिनियम। जो योजनाएं उन्होंने चालू कीं, उनके परिणाम अच्छे आये, राजस्थान में अच्छे विकास की गंगा बही, इसे देखते हुए इस बजट में भी हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने कई नई योजनाएं लागू की हैं कई पूर्व में संचालित योजनाओं के विस्तार की घोषणा की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान का आम आदमी गांवों में रहता है, 80 प्रतिशत गांवों में रहता है, गरीब आदमी है, इस सबको ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण राजस्थान के लोगों के लिए मुफ्त दवा योजना लागू की। निश्चित तौर पर इससे पूरे राजस्थान के लोगों को बहुत लाभ मिला है। इसकी यहां राजस्थान के लोग ही नहीं तारीफ कर रहे हैं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं और अन्य स्टेटों में भी इस योजना को लागू करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस योजना में 400 दवाएं दी जा रही हैं उनको बढ़ाकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 600 प्रकार की दवाएं देने की घोषणा करने का निर्णय लिया है। इस योजना से आउटडोर में 46 प्रतिशत तथा इन्डोर में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और आम आदमी को इसका लाभ मिल रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नि:शुल्क जांच की योजना भी अभी 7 अप्रैल से चालू करने की घोषणा की है, इसमें ईसीजी, एक्स-रे, सोनोग्राफी आदि की जांच भी नि:शुल्क की जाएगी जिससे आम आदमी को लाभ होगा और वह अपना मुफ्त में इलाज करवा सकेगा।

प्रदेश में जिला चिकित्सालयों में 1 करोड़ रुपये की लागत से तथा सीएचसी में 50-50 लाख की लागत से धर्मशालाओं का निर्माण करने की घोषणा की गयी है। गांवों से आने वाले लोग जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर अपना इलाज करवाने आते हैं, उनके साथ जो लोग रहते हैं उनको ठहरने के लिए सुविधा दी जा सकेगी जिससे निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता को लाभ मिल सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस साल 50 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की गयी है। 50 पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गयी है, 600 नये पीएचसी खोलने की घोषणा की गयी है। 1000 शैयाओं की वृद्धि राज्य के सीएचसी में की है। 108 एम्बुलेंस की

(श्री कमल बैरवा)

संख्या बढ़ाई है। 200 जननी एक्सप्रेस उपलब्ध करवाने की घोषणा की गयी है। निश्चित तौर पर इससे आम आदमी को लाभ मिल सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष: 10 मिनट हो गये आपको।

श्री कमल बैरवा (निवाई): 2 मिनट में कर दूंगा, 5 मिनट तो दो।

श्री उपाध्यक्ष: दस मिनट दे दिये आपको।

श्री कमल बैरवा (निवाई): सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी 4 वर्षों में करीब 9500 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर सड़क तंत्र को मजबूत करने, 7900 किलोमीटर लम्बाई की जिला सड़कों के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण और चौड़ा करने के कार्य किये गये हैं। 250 से 500 की आबादी में 2442 किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य किये जा रहे हैं और 1337 गांवों को सड़कों से जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि 250 से 500 की आबादी के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीपलू और निवाई में करीब 70 सड़कों का निर्माण हो रहा है, निश्चित तौर पर उन गांवों के लोगों को लाभ होगा। वे बहुत खुश हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी जिस प्रकार विकास करवा रहे हैं।

(21.00 बजे)

ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूर्व में, किसानों के लिए बिजली में एक रुपया भी नहीं बढ़ाया जाए, यह घोषणा की थी। निश्चित तौर से उसका पालन किया गया है और किसान की बिजली पर कोई पैसा नहीं बढ़ाया गया है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि 2 लाख 46 हजार 657 कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं और इस बजट में भी करीब 75 हजार नये कनेक्शन जारी करने की घोषणा की गई है, किसानों को निश्चित तौर पर इसका लाभ होगा।

मुख्य मंत्रीजी ने तीन हजार गांवों और ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 600 अनुसूचित जाति, 400 अनुसूचित जनजाति व डेढ़ सौ अल्पसंख्यक बहुल ग्राम ढाणियों को शामिल किया गया है, निश्चित तौर से इसका लाभ इन ग्राम-ढाणियों को मिलेगा व इन्हें शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। करीब 20 हजार हैण्डपम्प देने की घोषणा की गई है। यहां मैं कहना चाहूंगा कि बनास नदी पर बीसलपुर की डाउन स्ट्रीम में स्थित ईसरदा बांध का 5 सौ करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य आगामी वर्ष में प्रारम्भ

(श्री कमल बैरवा)

किया जाएगा जिससे निश्चित तौर से टोंक जिले के किसानों को फायदा हो सकेगा।

इस बजट में राज्य की वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन की पात्रता हेतु जो 25 वर्ष का राइडर लगा हुआ था, उसको हटाया गया है और सभी को उससे मुक्त किया गया है, निश्चित वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन पाने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा और गरीब लोग हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री को दुआएं देंगे।

पालनहार योजना में भी 675 रुपये को बढ़ाकर एक हजार रुपये किया गया है, निश्चित तौर पर उन बच्चियों को जो स्कूल में जा रही हैं, इसका लाभ मिल पाएगा।

देवनारायण योजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों में दो सौ करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई थी, उसको बढ़ाकर तीन सौ करोड़ रुपये की घोषणा की गई है, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत अच्छा कदम है, मैं इसके लिए उनको साधुवाद देना चाहूंगा।

सामूहिक विवाह सम्मेलनों को प्रोत्साहित करने के लिए जो वधु को 4,500 रुपये दिये जाते थे, उसको बढ़ाकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 10 हजार रुपये किया है और संस्था के लोगों को जो 1500 रुपये दिये जाते थे, उनको ढाई हजार रुपये दिये गये हैं, निश्चित तौर से जो सामूहिक विवाह होते हैं, उनमें इसका लाभ मिलेगा।

प्रशासन गांव के संग में 10 जनवरी से 20 फरवरी, 2013 तक विभिन्न समस्याओं के समाधान के साथ 3 लाख 4 हजार 215 प्रकरणों में आबादी के पट्टे जारी किये गये, 54246 प्रकरणों में आवासीय भूखण्डों के नि:शुल्क पट्टे बांटे गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर बताना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें अब।

श्री कमल बैरवा (निवाई): दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट तो बहुत होते हैं, साढ़े 9 का ही तो टाइम है, कितने सदस्य बोलने वाले हैं!

श्री कमल बैरवा (निवाई): थोड़ा टाइम बढ़वा लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल गया। बोलने वाले को पता ही नहीं चलता है। बस आखिरी लाइन है आपकी, समाप्त करें।

श्री कमल बैरवा (निवाई): एक मिनट। शहरों के संग प्रशासन में जो पट्टे बांटे गये हैं, मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि मेरी एक कालोनीशिवाजी कालोनी, 50 साल से बिना नियमन के पड़ी थी, वहां सारी सुविधाएं थीं, मगर उनको पट्टे नहीं मिलने की वजह से वे सब परेशान थे। प्रशासन शहरों के संग में पट्टे दिये गये, नि:शुल्क पट्टे दिये गये, उसका लाभ उनको मिला।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री बंशीधर जी खण्डेला।

श्री कमल बैरवा (निवाई): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में मैं अपनी बात कह दूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत घोषणाएं शिक्षा के क्षेत्र में की हैं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मैं विशेष तौर से अपनी बात जो यहां कहना चाह रहा हूं, वह यह है कि विश्वविद्यालय साथ में खोले गये, उनका सौ करोड़ रुपये का प्रावधान है, मेरे सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र निवाई में कालेज नहीं है, मैंने चार साल में हर बार मुख्य मंत्रीजी से बजट घोषणा में निवेदन किया है कि मेरे यहां भी राजकीय कालेज खोला जाए जिससे कि मेरे यहां के बच्चे सरकारी कालेज में पढ़ सकें और उनको लाभ मिल सके। एक मेरे दतवास ग्राम पंचायत निवाई से करीब 33 किलोमीटर दूर है, मैंने निवेदन किया है कि वहां एक उप तहसील खोली जाए जिससे कि मेरे वहां के लोगों को आराम मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें, धन्यवाद।

श्री कमल बैरवा (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह शानदार बजट पेश किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय बंशीधर जी खण्डेला।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी में 30-40 किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण का पैकेज दिया था पिछले साल, मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 30-40 किलोमीटर छोड़कर 15 किलोमीटर भी पूरी नहीं हुई है। यह पिछले बजट की थोथी घोषणा है। अभी भी इतनी सड़कें जो बनाई जा रही हैं, बीओटी के हिसाब

(श्री बंशीधर खण्डेला)

से बनाई जा रही हैं, सारी की सारी बीओटी के आधार पर बनाये जाने के बाद सरकार का क्या इसमें इन्वाल्वमेंट है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में काश्तकारों के लिए कुठाराघात है, आम उपभोक्ता के लिए कुठाराघाती कदम सरकार ने उठाया है। अपनी मनमर्जी के हिसाब से, काश्तकार या दूसरा उपभोक्ता यदि चोरी में पकड़ा जाता है या झूठी चोरी का इल्जाम लगाया जाता है कि उसको 11 हजार रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से पैनल्टी देनी पड़ेगी। यदि किसी काश्तकार के साथ झूठा अन्याय भी हो गया 10 एचपी के लिए तो एक लाख रुपया वह काश्तकार अपना घर बेचकर भी नहीं दे सकता। ऐसा काला कानून विद्युत बोर्ड ने बनाया है। यह बिलकुल काला कानून है काश्तकार के लिए और उपभोक्ता के लिए। एक चीज और है, काश्तकारों के लिए 75 हजार नये कनेक्शन देने की घोषणा की गई है, पहले जो बजट में घोषणा की गई थी, वह भी अभी तक पूरी नहीं हुई तो यह केवल थोथी घोषणा ही बनकर रह गई है। जो घरेलू कनेक्शन की बात है मुख्य मंत्री योजना के अन्दर, घरेलू कनेक्शन में पहले जो टारगेट दिये थे पांच-पांच का समूह है या दस-दस का समूह है, वह भी आज तक लागू नहीं हुआ। घोषणा की तारीख तय की थी कि फलां तारीख तक आप जमा करा सकते हैं, उसके पहले ही योजना बंद कर दी गई और आज एक भी कनेक्शन लागू नहीं हुआ उसके अन्दर। उन काश्तकारों के लिए, ढाणियों के बाशिंदों के लिए यह कुठाराघात है। पहले घोषणा की, वह भी नहीं हुई तो अब ये 60 हजार घरेलू कनेक्शन कहां से दे देंगे?

जल संसाधन मंत्री बैठे हुए हैं, इसके अन्दर पैरा नम्बर 40 में बता रखा है कि राज्य में कुछ नदियों को, बेसिनों को जोड़ा जाएगा। इस पैरा नम्बर 40 में नदियों को जोड़ने का काम तो कह रखा है लेकिन बजट का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसी असत्य घोषणा करने में क्या फायदा है? इसी हिसाब से पैरा नम्बर 45 में भी दौसा में बीसलपुर बांध के पानी के लिए कह रखा है लेकिन इसमें भी बजट का कोई प्रावधान नहीं है। यही हाल बारां के अन्दर अन्धेरी नदी पर एनिकट बनाने का है, और कहीं एनिकट बनाने का कह रखा है, कहीं पर भी बजट का कोई भी प्रावधान नहीं है। बिना बजट कैसे कर सकेंगे, मेरी तो समझ से बाहर है।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के बारे में अपन बात करें तो चिकित्सा के अन्दर हर जिले में धर्मशाला बनाने की बात कही गई थी। मैं कहना चाह रहा हूं कि डाक्टर और कर्मचारी कम होने के कारण सारे के सारे हास्पिटल वैसे ही धर्मशाला बने हुए हैं, नई धर्मशाला बनाकर क्या करेंगे? सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, आपका सीएचसी है, अन्दर आज किसी भी हास्पिटल के अन्दर सारा स्टाफ और डाक्टर्स नहीं हैं- कहीं प्रसूति का नहीं है, कहीं एमओ नहीं है, कहीं सर्जन नहीं है, तो कई जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दो-दो डाक्टर बैठे हुए हैं। तो ये तो आलरैडी धर्मशाला बनी हुई हैं आप क्या धर्मशाला बनाओगे?

आयुर्वेद के बारे में जरूर यह कहना चाहूंगा कि जो पुराने आयुर्वेद की पद्धति थी, वह धीरे-धीरे खतम होती जा रही है। मैं मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इस हिसाब से आयुर्वेद के अन्दर बजट में कोई प्रावधान करें। पहले के जमाने में नाड़ी देखकर एमआरआई कर लेते थे, एमआरआई ही नहीं, माइक्रो एमआरआई कर लेते थे नाड़ी देखकर हाथ से। लेकिन आज एक भी वैद्य नाड़ी का कोई प्रशिक्षण नहीं ले रहा है। प्रशिक्षण ले कहां से? यहां नाड़ी वैद्य का प्रशिक्षण है भी नहीं जो उसमें कोई पीजी करे या आगे बढ़े। तो ऐसा करना चाहिए जिससे गरीब लोगों के लिए गांव में नाड़ी वैद्य के हिसाब से अच्छी सुविधा मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बंशीधर जी, नाड़ी के ऊपर घड़ी भी होती है, थोड़ा ध्यान रखें।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): नहीं, नाड़ी की बोल रहा हूं मैं घड़ी की नहीं। आप बोल रहे हैं घड़ी की।

अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी घोषणाएं कर रखी हैं, जो घोषणाएं पहले के बजट में की थीं, वे ही नहीं हुईं तो अब कहां से होंगी? कांग्रेस सरकार तो हमेशा यह चाहती है कि अल्पसंख्यक कम से कम पढ़ें जिससे वोट बैंक बना रहे। पढ़ा-लिखा अल्पसंख्यक है मुसलमान भाई, वह कांग्रेस के साथ कभी नहीं रहता, वह बीजेपी के साथ बैठता है। तो ऐसी घोषणा मत करो, जिससे आपका नुकसान हो जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 20 करोड़ रुपये की घोषणा की है कि

(श्री बंशीधर खण्डेला)

उन्नत बीज लाएंगे। क्या ऐसा ही उन्नत बीज लाएंगे जो पिछले टाइम खरीफ के टाइम पर बाजरे का मुफ्त में बांटा गया था? उसके अन्दर हमारे काश्तकार भाई बर्बाद हो गये और इतने बर्बाद हुए कि 2-3 साल तक भी उबर नहीं सकते। बाजरे का बीज ले लिया, बीज का पैसा नहीं लगा लेकिन बुवाई के अन्दर जो पैसा लगा वो मिलना तो दूर रहा, पशुओं के लिए चारा भी नहीं बचा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के क्षेत्र में मैं इस बात के लिए मुख्य मंत्रीजी को जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा कि गैर पारम्परिक स्रोत के हिसाब से पहले बजट में सौर ऊर्जा के लिए काश्तकार को 5 एचपी की मोटर लगाने के लिए कहा था, लेकिन उसके अन्दर कमी रखी कि पांच की जगह अभी भी तीन एचपी का सौर ऊर्जा का सब्सिडीयुक्त प्लांट लगाने के लिए स्वीकृति है। जब पहले वाली स्वीकृति पूरी नहीं हुई तो इस स्वीकृति के लिए हम कैसे आशा करें?

श्री उपाध्यक्ष: बिलकुल संक्षेप में करें।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): संक्षेप में ही कर रहा हूं। अभी तीन पाइंट ही बोले हैं, साहब, अभी दो मिनट ही हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, सात मिनट हो गये आपके।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): तो इस हिसाब से हम कैसे आशा करें? मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट में पांच एचपी की घोषणा की वह अभी तीन एचपी पर ही चली हुई है। माननीय मुख्य मंत्रीजी शायद भूल जाते हैं अपने कहे हुए को।

सहकारिता मंत्रीजी बैठे हुए हैं, सहकारिता के अन्दर घोषणा की थी आपने पिछले बजट में कि प्रत्येक पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समिति बना दी जाएगी। लेकिन आज भी आधी से ज्यादा पंचायत ऐसी हैं उनमें ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं बनी है। उसमें कुछ ढील दी जाए, नियमों में कुछ सुधार किया जाए जिससे प्रत्येक पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति बन सके। किसान नोशनल शेयर के हिसाब से पहले लोन लेता था, पर अब नियमों में ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि नोशनल शेयर से उसको कोई लोन नहीं मिलेगा। एक बाप के पांच बेटे है, जमीन है बाप के नाम से, पांचों बेटे अलग-अलग हो रहे हैं, तो पहले नोशनल शेयर से उसको क्रेडिट कार्ड के हिसाब से भी मिलता था और सहकारिता से भी लोन मिलता था। अब वो प्रावधान खतम

(श्री बंशीधर खण्डेला)

कर दिया। इससे एक नुकसान और होगा को-आपरेटिव सैक्टर में और वो, मंत्री महोदय, आपको बताना चाहूंगा कि जिस क्रेडिट कार्ड...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद कृपया।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): मैं सुझाव ही दे रहा हूं, प्लीज। जिस काश्तकार ने को-आपरेटिव बैंक से नहीं लेकर कामर्शियल बैंक से ले लिया तो को-आपरेटिव बैंक के, जीएसएस के उसके द्वार बंद हो गये। वहां से एनओसी मिलेगी नहीं और आप जो ब्याज का बता रहे हैं कि हम ब्याजमुक्त ऋण दे रहे हैं उससे वे वंचित रह जाएंगे। इसलिए ऐसी दोहरी नीति नहीं करें। ऐसी व्यवस्था करें, उसकी जमीन केवल क्रेडिट कार्ड जितनी ही तो नहीं है, उससे तो ज्यादा जमीन है, तो उसे दोनों फायदे मिलने चाहिए। आप वहां क्रेडिट कार्ड के कम देते हैं और कामर्शियल बैंक ज्यादा देते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पशुपालन के बारे में बात करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय लालशंकरजी घाटिया।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): पशुपालन चिकित्सा के अन्दर पशु चलकर हास्पिटल नहीं जा सकता इसलिए डाक्टर को पशु के पास जाना पड़ता है। पशु को अगर हास्पिटल लेकर जाएंगे तो काश्तकार के बहुत बड़ा खर्चा होगा। इसके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। पशु चल चिकित्सा बनाई गई है लेकिन हर जिले में बनी हुई नहीं है। और जिले में भी वह क्या काम आएगी? अपने तो हर दो-दो, तीन-तीन पंचायतों में हास्पिटल खोल रखे हैं, उसमें डाक्टर और कम्पाउण्डर को वाहन के फ्यूल के लिए पैसा देना चाहिए, काश्तकार को उसका फायदा मिलेगा क्योंकि डाक्टर वहां जा सकता है। यह काश्तकार के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है और बजट में इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। दूध के बारे में अपन बात करें....

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें कृपया।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट और दीजिये हमें।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, दो मिनट नहीं। आप समाप्त करें, आखिरी लाइन है बस। माननीय मदनलालजी वर्मा।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, ओनली वन मिनट। शिक्षा के बारे में और बताना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट में आखिरी लाइन।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): आखिर में शिक्षा के बारे में बोल रहा हूं एक मिनट में। शिक्षा के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार में आदरणीय वसुंधरा राजेजी ने हमारे शेखावाटी में शेखावाटी यूनिवर्सिटी खोली थी, मत्स्य अलवर में खोली थी और ब्रज भरतपुर में खोली थी, आज पांच साल का दिन वापस आ गया है, उन तीनों विश्वविद्यालयों के अन्दर अभी भी कुछ नहीं हुआ है। इसलिए मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं, यह निराशाजनक बजट है। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मदनलालजी वर्मा।

श्री मदनलाल वर्मा (डग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट के पक्ष में बोलने के लिए समय दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्रीजी, इस सदन के नेता ने सदन में अपना पांचवां बजट पेश किया। पहली बार यह देखने को मिला इस बजट को लेकर....

श्री उपाध्यक्ष: मदनजी, आप पाइंटेड बात करना, अपने क्षेत्र की बात को पहले ले लेना।

श्री मदनलाल वर्मा (डग): कर रहा हूं, साहब। बड़ी मुश्किल से आखिर में तो टाइम दिया है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: वो भी तीन के बाद का दिया है आपको, इसलिए कि आप विराज रहे थे।

श्री मदनलाल वर्मा (डग): इस बजट को लेकर गांवों में उत्सुकता थी और बजट के बाद आतिशबाजी के द्वारा गांव के लोगों ने इस बजट का स्वागत किया है। पहली बार ऐसा है कि गांव के गरीब और किसान के दिल में इस बजट को लेकर खुशी है। यह बजट हमारे मुख्य मंत्रीजी ने महात्मा गांधी की कल्पना को साकार करने के लिए पेश किया है। राष्ट्रपिता यह चाहते थे कि हमारा गांव मजबूत हो, गरीब मजबूत हो, किसान मजबूत हो, इस बजट में जो प्रावधान किया यह निश्चित रूप से उसी परिकल्पना को साकार करता है। वो छोटे-छोटे गांव जो विकास से वंचित थे और विकास की बाट राह देख रहे थे, उनके लिए मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। 250 की आबादी वाले गांव जो पिछले साल सड़कों से जुड़ने से वंचित रह गये थे, उनके लिए सड़क योजना की मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में घोषणा की। 100 से कम आबादी वाली

(श्री मदनलाल वर्मा)

ढाणियां जो बिजली से वंचित थीं, उनके लिए बिजली की योजना के लिए बजट में प्रावधान किया और वहां बिजली दी। शिक्षा के क्षेत्र में ढाणियों में प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रावधान किया ताकि उन छोटे-छोटे गांवों का विकास हो, गरीब का विकास हो। राजस्थान के लाखों गरीब इस बजट की आस लगाये बैठे थे, इस बजट में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो उनको दिया वो निश्चित ही एक ऐतिहासिक कदम है। बी पी एल परिवार का व्यक्ति जो पिछले वर्ष तक दो रुपये किलो गेहूं प्राप्त कर रहा था, उसको आज एक रुपये किलो के हिसाब से गेहूं दिया, गरीब के घर में उसके बच्चे भूखे नहीं सोएं, उसके चूल्हे पर रोटी बने, यह मुख्य मंत्रीजी ने प्रावधान किया है। बी पी एल परिवार को पक्की छत देने की धारणा थी उसके तहत पिछले वर्ष 10 लाख बी पी एल परिवार को मकान देने की घोषणा की। उसमें लगातार पैसा कम पड़ रहा था तो उनको अब 70 हजार रुपये देकर पक्की छत देने का निर्णय लिया है। यह निश्चित ही गरीब परिवार को मजबूती देने का मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास किया है। बी पी एल परिवार जो नरेगा में 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर रहा था, उसको 150 दिन का रोजगार देकर, 50 दिन अतिरिक्त राज्य सरकार के कोटे से देकर उस गरीब को आर्थिक सम्बल प्रदान किया, उसको मजबूती दी इसलिए वो गरीब आज राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का आभार मानता है। किसान को राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, वो ही योजना हमारे मुख्य मंत्रीजी ने उस किसान को दी- चाहे बिजली के पाँच साल के बिलों में छूट दी और बिजली का उनका बिल नहीं बढ़ाया। इस बजट के माध्यम से किसान को मजबूती देने का प्रयास किया गया है। गेहूं खरीद में 150 रुपये उसको अतिरिक्त बोनस देकर, उसकी उपज का अच्छा मूल्य मिले यह इस बजट में प्रावधान किया। गत वर्ष एक लाख रुपये तक का ऋण ब्याज मुक्त था, इस वर्ष डेढ़ लाख रुपये के ऋण को ब्याज मुक्त कर गरीब परिवार को सहायता देने का हमारे मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास किया है। गांव, गरीब और किसान की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का इस बजट में पूरा प्रयास किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक परिवारों को भी मजबूती देने का इस बजट के माध्यम से प्रयास किया गया है।

(21.18 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

अनुसूचित जाति परिवार के वो बालक जो छात्रावासों में अध्ययन कर

(श्री मदनलाल वर्मा)

रहे थे, उनका मासिक भत्ता कम था, उसको बढ़ाकर 1750 रुपये प्रति माह करके उन बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। अनुसूचित जाति की जिन बस्तियों में पेयजल की किल्लत थी, उन बस्तियों को चिह्नित कर पेयजल उपलब्ध कराने का मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में प्रावधान किया है और उसके लिए हम सब उनके बहुत-बहुत आभारी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीब परिवारों के बच्चे इस कम्पीटिशन के युग में महंगी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, मैरिट में आने के बाद हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए राजकोष से अनुदान देकर उन बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया ताकि गरीब परिवार का बच्चा पढकर अपने घर को ताकत दे, अपने घर को सम्बल दे। यह हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में प्रावधान किया है।

मैं इस अवसर पर हमारे मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 325 करोड़ रुपये की एक गागरीन पेयजल परियोजना स्वीकृत कर मेरे विधान सभा क्षेत्र के वंचित सभी गांवों को पीने का पानी मिलने का प्रावधान किया है। भवानीमण्डी में एक उप परिवहन कार्यालय खोलकर इस क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास किया है, मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। यहां पर राजस्व मंत्रीजी मौजूद हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे डग की उप तहसील को जहां 19 पटवार मण्डल आते हैं, तहसील में क्रमोन्नत करने की कृपा करें। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती कमला कस्वां।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, 6.3.2013 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री की हैसियत से जो बजट पेश किया, उसके विषय में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजट में पैरा एक से लेकर 277 तक हर पैरा में कोई न कोई योजना की घोषणा की है, उन पर मैं चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि उन घोषणाओं की क्या इतिश्री होगी, यह सत्ता पक्ष भी जानता है, खुद मुख्य मंत्रीजी भी जानते हैं और हम सब भी जानते हैं। समय बहुत कम रह गया, घोषणाओं की क्रियान्विति में टाइम लगेगा और उनमें क्या होगा, यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन, सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान उन बातों की ओर दिलाना चाहती हूं जिनके ऊपर मुख्य मंत्रीजी को अपने बजट में

(श्रीमती कमला कस्वां)

प्रावधान रखना चाहिए था, उसका वर्णन होना चाहिए था। उन पर नहीं करके जो कमी रह गई है, मैं अपनी तरफ से सुझाव देना चाह रही हूं कि यह कमी बजट में रही है।

28 फरवरी को जब लोक सभा में आम बजट पेश हुआ तो उस बजट में राजस्थान का नाम नहीं था। न राजस्थान को रिफाइनरी की घोषणा हुई, न राजस्थान को पेयजल का विशेष पैकेज मिला, न राजस्थान को विशेष दर्जा मिला। इन तीनों की ही कमी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया, उसमें रही। रिफाइनरी के लिए आनन-फानन में मुख्य मंत्रीजी ने एच पी सी एल के साथ पांच तारीख को मीटिंग की और प्रस्ताव केन्द्र को भेजने की तैयारी की और छह तारीख को बजट पेश किया। 14 तारीख को एमओयू पर साइन होने हैं और केन्द्र को यह फाइल जानी है। कितने दिन में स्वीकृति होगी, कितने दिन में काम होगा, यह निकट भविष्य में है। चुनाव नजदीक है।

जहां तक पेयजल की बात है तो हमें आज तक पीने को शुद्ध जल की तो बात छोड़िये, पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं है। प्रदेश में पानी का भयंकर संकट है, इतने प्रयासों के बाद भी हम केन्द्र से पेयजल का विशेष पैकेज नहीं दिला पाये और मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के अन्दर एक लाइन भी यह नहीं लिखी है, न उसका वर्णन किया है कि हमारी क्या कार्य योजना है। भाखड़ा का पानी 0.6 एम.ए.एफ. जो हमारे राजस्थान का हक था, वह 1983 से आज तक पैंडिंग है, उसके विषय में भी मुख्य मंत्रीजी ने एक लाइन नहीं लिखी है कि हम इसके लिए क्या प्रयास करेंगे। रावी-ब्यास बोर्ड के अन्दर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इन तीनों राज्यों के प्रतिनिधि बैठने चाहिए, हमारा प्रतिनिधि आज तक नहीं बैठ पाया। मुख्य मंत्रीजी ने इस विषय में भी क्या प्रयास किया, वह इस बजट के अन्दर दिखाई नहीं देता।

एक बात मैं और भी कहना चाहूंगी, कि आज जब हिन्दुस्तान नई दिल्ली की दामिनी की दमक से दहक रहा है, तब मुख्य मंत्रीजी महिलाओं को दो साड़ी, एक कम्बल, एक स्कूटी देकर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर और शुभलक्ष्मी योजना में 1,000 रुपये अलग देकर क्या दिखाना चाहते हैं, महिलाओं की स्मिता की रक्षा क्या स्कूटी और साड़ियों से होगी? एक लाइन भी इस बजट के अन्दर नहीं है कि महिलाओं की स्मिता की रक्षा किस तरह से यह सरकार करेगी, क्या प्रबन्ध किये हैं। शिक्षा प्राप्त करके महिला का

(श्रीमती कमला कस्वां)

हर क्षेत्र के अन्दर दखल है। ईवन नरेगा की योजना भी आज महिलाओं के दम पर पूरे हिन्दुस्तान में चल रही है। न केवल राजस्थान में, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में नरेगा में कहीं भी जाकर देख लीजिये, महिलाओं की संख्या ज्यादा पायी जाएगी। हर स्कूल में, दफ्तर में, अदालतों में, पुलिस में, नर्सिंग स्टाफ में जहां भी देखो, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। उन महिलाओं की स्मिता की रक्षा जो सरकार नहीं कर सके, बजट में उसका प्रावधान नहीं कर सके, मैं उस बजट को कंडैम करती हूं, उसका विरोध करती हूं। जब तक आप महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, उनको इतना सक्षम नहीं बनाएंगे कि वे विरोध कर सकें, उनमें इतनी ताकत पैदा नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए नारी कल्याण की बात करना शोभा नहीं देता।

मैं मुख्य मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहती हूं कि नारी की सुरक्षा का ध्यान अपने बजट भाषण में जरूर रखें। आज राजस्थान में जिस तरह से भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, विशेषकर शहरों में...

श्री सभापति: आपको सिर्फ पांच या छह मिनट ही बोलना है, मैडम, क्योंकि बाकी लोग भी बोलेंगे। आप एक मिनट और बोल लीजिये। और बोल लीजिये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): आपने टाइम दिया है तो दो मिनट बोलने दीजिये, नहीं तो मैं बैठ जाती हूं। ऐसा तो है नहीं। आपने अभी 10 मिनट दिये हैं, मैं बोल रही हूं।

उस भ्रूण हत्या को रोकने के लिए क्या कार्य-योजना है, उसका भी इस बजट में प्रावधान नहीं है। मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में नरेगा में दिवस 100 से 150 किये, फिर उसका संशोधन करके 125 दिवस की घोषणा की है। मैं कहती हूं कि पिछले चार सालों के अन्दर चार लाख कार्य दिवस से घटते-घटते 77,000 पर हमारा प्रदेश आ गया है, इन कार्य दिवसों को बढ़ाने का क्या औचित्य है? लोक सभा के अन्दर खुद ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने एक निजी विधेयक के जवाब में यह कहा कि हिन्दुस्तान में सिर्फ आठ प्रतिशत लोग काम मांगते हैं, 92 प्रतिशत लोगों की कोई रुचि नहीं है। जितने लोग काम मांग रहे हैं, उनको ही काम नहीं दे रहे हैं तो यह दिवस बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, मेरा यह मानना है।

(श्रीमती कमला कस्वां)

दूसरा मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहूंगी। विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर, यह पांचवां बजट है, हमेशा इस क्षेत्र की अवहेलना हुई है। पिछले बजट में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि सिद्धमुख नहर से जो वंचित गांव हैं, उनका साहवा लिफ्ट योजना से सर्वे कराने का हम काम करेंगे। आज दिन तक सर्वे नहीं हुआ। मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट में, 2012-13 के बजट में घोषणा की कि बूंगी-राजगढ़ जल प्रदाय योजना को 248 करोड़ रुपये सैंक्शन करके उसका कार्य कराएंगे। पूरा एक साल बीत गया, वहां एक पाइप नहीं लगा, कोई काम नहीं हुआ। वह योजना जो 2008 में स्वीकृत होकर आज दिन तक पूरी होनी थी, वह अधर में लटक गई है। मेरा क्षेत्र प्यासा मर रहा है, पानी पीने को नहीं है। वहां अगर पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो आने वाले समय में, गर्मी में लोग किस तरह से अपना टाइम निकालेंगे, मैं कह नहीं सकती।

दूसरी बात मैं कहना चाह रही हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट में 32 आरओबी सैंक्शन किये, जिनमें से छह पर काम हुआ। मेरे क्षेत्र में सादुलपुर-पिलानी मार्ग पर रेलवे फाटक है जो दिन-रात बंद रहता है। रेलवे ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि यहां आवागमन बहुत है, आरओबी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसकी स्वीकृति नहीं हुई। इस बजट में भी मेरे उस आरओबी का कोई वर्णन नहीं है। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद जरूर दूंगी कि उन्होंने चूरू जिले में 14 आरयूबी मंजूर किये लेकिन उनमें से मेरे क्षेत्र में सिर्फ तीन हैं, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मेरे क्षेत्र में विभिन्न फाटकों की मांग को लेकर, विभिन्न आरयूबी की मांग को लेकर गांव के लोग धरने पर बैठे...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, कृपया समाप्त करें अब आप।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): ...दो महीने से वहां आवागमन बंद है, खेतों में जाना बंद है, फसल लाना बंद है। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन है कि बचे हुए आरयूबी लसेड़ी, लुब्दी, गुलपुरा, पहाड़सर, भगेला, ख्याली, चैनपुरा छोटा...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): ...ये सारे हैं जिनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी रेलवे से आ चुकी है और उनका औचित्य भी है, आप आने वाले जवाब में इन आरयूबी की भी घोषणा करें ताकि मेरे क्षेत्र को राहत मिल सके।

अंतिम बात मैं कहना चाहूंगी कि मेरा विधान सभा क्षेत्र हरियाणा से

(श्रीमती कमला कस्वां)

लगा हुआ है, वहां शराब की तस्करी इतनी भयंकर मात्रा में होती है कि मेरा क्षेत्र अपराध का हब बन गया है। वहां बुरी हालत है। आये दिन चोरी, डकैतियां, लूटपाट होती है। चोरी की कोई भी बरामदगी आज दिन तक नहीं हुई। लोग परेशान हैं। आपने एडिशनल एस.पी. का कार्यालय खोलने की घोषणा करके मेरे क्षेत्र को राहत दी है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं। लेकिन एक निवेदन जरूर करना चाहती हूं कि केवल कार्यालय खोल देना ही काफी नहीं है, जब तक पुलिस का इकबाल नहीं होगा, वह सशक्त नहीं होगी, उसको आधुनिक संसाधनो से सुसज्जित नहीं किया जाएगा...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): तब तक कोई भी काम नहीं होगा। आपने मुझे अंत में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 9.45 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय 9.45 बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 9.45 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

श्री जाकिर हुसैन। श्री जाकिर हुसैन नहीं बोल रहे हैं? श्री मंगलाराम।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं जो बजट पेश किया है, उसके लिए मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं। पूरे राजस्थान की जनता को इस बजट में दिया है, गरीब से लेकर अमीर तक को सब कुछ दिया है इस बजट में, इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं। मैं इस बजट के बारे में धन्यवाद देता हूं मुख्य मंत्रीजी को। मैं विशेषकर मेरे क्षेत्र की जो योजना है, उसके बारे में ही कहना चाहूंगा। बजट तो मुख्य मंत्रीजी ने बढ़िया दिया है, जो भी बजट में लिया है। जैसे किसानों के

(श्री मंगलाराम गोदारा)

लिए, किसानों के लिए यह बजट बड़ा राहत का बजट है। बिजली के 75 हजार कनेक्शन, कृषि कनेक्शन, बहुत बड़ी बात है। पीछे भी कनेक्शन खूब दिये हैं, और अभी भी कनेक्शन खूब दिये। मेरे यहां पूर्ववर्ती सरकार के समय 33 केवी के जीएसएस मात्र पांच साल में तीन बने थे और अभी चार-साढ़े चार साल में 33 केवी के 37 जीएसएस बनकर तैयार हो गये और 24 जीएसएस स्वीकृति के लिए भेजे हुए हैं, मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह जल्दी स्वीकृत करवाकर काम चालू करवाएं। 1/32 के तीन जीएसएस मेरे यहां चालू हो गये, पूर्ववर्ती सरकार में एक जीएसएस 1/32 का बना, दो जीएसएस और स्वीकृति के लिए भेजे हुए हैं- जाखासर और कीतासर, मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह भी जल्दी से जल्दी चालू करवाएं।

बिजली की बात, विपक्ष कह रहा था कि आठ घंटे की घोषणा थी, बिजली मात्र छह घंटे मिल रही है। सही बात है, बिजली छह घंटे मिल रही है, बाकी जो बिजली मिल रही है छह घंटे, वह बढ़िया वोल्टेज की मिल रही है। पिछली बार तीन जीएसएस मेरे क्षेत्र में बने थे 33 केवी के, अब की बार 37 जीएसएस 33 केवी के, तो आप अनुमान लगा लें कि किस वोल्टेज के हिसाब से बिजली मिल रही थी। आज जो छह घंटे बिजली मिल रही है किसान को, वह किसान एकदम खुश है, कहीं कोई कमी नहीं है किसान के। मैं मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं, किसानों को जो दिया है। जैसे अनाज का भाव, गेहूं का समर्थन मूल्य सरकार ने बढ़ाया। फिर सौ रुपये बोनस दिया पिछली बार, अब की बार एक सौ पचास रुपये बोनस कर दिया। चने का समर्थन मूल्य बढ़ाया, मूंगफली का समर्थन मूल्य पिछली बार एक हजार रुपये बढ़ाया, उसके पिछली बार एक हजार रुपये और बढ़ाया। दो हजार रुपये मूंगफली का समर्थन मूल्य बढ़ाने के बाद में पांच हजार रुपये मूंगफली बिकी है खलों में। आज तक का रिकार्ड है पचास साल में मेरे हिसाब से। जिस टाइम किसान मूंगफली निकालता है या चना निकालता है या गेहूं निकालता है, किसान को भाव नहीं मिलता है। भाव तीन महीने, चार महीने बाद में मिलता है। तीन-चार महीने बाद भाव मिलता है वह असली किसान को नहीं मिलता है। गांव में एक-दो कोई बड़ा किसान है उसको मिलता है या व्यापारी को मिलता है। यह जो फायदा मिला, इस सरकार में फायदा मिला इस तीन साल के अन्दर। समर्थन मूल्य की तुलाई चालू हो गई, डूंगरगढ़, बीकानेर, लूणकरणसर। पिछली बार चालू की, और भी राजस्थान में कई जगह की, टाइम पर चालू होने से किसान को

(श्री मंगलाराम गोदारा)

असली भाव मिल गये। खलों में गेहूं निकाला और समर्थन मूल्य के हिसाब से 1385 रुपये जो गेहूं बिक रहा था, वह उस किसान को सीधा भाव मिल गया। 1385 रुपये सरकार खरीद रही थी। बाजार के अन्दर कोई लेना चाहता था तो पन्द्रह सौ रुपये गेहूं बिका, उससे नीचा नहीं बिका। चने का भाव है, पिछले टाइम में अठारह सौ, दो हजार से चना कभी ऊपर नहीं गया। और जैसे ही किसान के फसल बिक गई, बिकने के बाद चना चार हजार, पांच हजार रुपये बिकता था। अब की बार खलों के अन्दर जैसे किसान चना निकालता है, उसी टाइम चने का भाव है वह साढ़े चार और पांच हजार के बीच में रहता है। उसके बाद में कम जरूर हुआ है, बाकी जिस टाइम किसान निकालता है उस टाइम किसान को भाव मिला है। मूंगफली का जैसे मैंने बताया, पांच हजार रुपये भाव मिला है। तो किसानों के सम्पन्नता आई है तीन सालों में। तीन साल में जिस तरह किसान सम्पन्न हुआ है पूरे राजस्थान में वैसे ही मेरे यहां भी किसान सम्पन्न हुआ है। सभापति महोदयजी, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जो सम्पन्नता आई है, पचास साल में आज तक इतनी सम्पन्नता नहीं आई। भाव से आई है सम्पन्नता। क्या है कि जैसे पांच हजार मूंगफली बिकी, साढ़े चार, पांच हजार चना बिका, पन्द्रह सौ रुपये गेहूं बिका, सरसों बिकी, वह भाव मिलने से मजदूर को भी मजदूरी मिली है। जैसे आज अपन नरेगा की बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि नरेगा में मजदूर नहीं है, नरेगा का ग्राफ गिरा है, नरेगा में कम लगे हैं मजदूर। तो नरेगा में कौन लगेगा? पांच सौ रुपये मजदूर को मिलता है। खेत वाला पांच सौ रुपये देता है मजदूर को और साथ में खाना देता है, चाय देता है। बहुत बड़ी बात है। मजदूर को मिले, साथ ही जैसे मूंगफली बिकी दो हजार रुपये, तो एक व्यापारी के आढ़त हुई बीस रुपये, और पांच हजार बिकते ही व्यापारी के आढ़त हो गई सौ रुपये। तो व्यापारी को भी फायदा है, किसान को भी फायदा है और मजदूर को भी फायदा है। जब तक राजस्थान के किसान को फायदा नहीं होगा तब तक न तो मजदूर को फायदा होगा, न व्यापारी को फायदा होगा, न और किसी को फायदा होगा। आज हर दुकानदार को, हर आदमी को फायदा है। यह कृषि प्रधान देश है, किसान के पास जितने पैसे आएंगे, जितना किसान सम्पन्न होगा उतना ही अपना स्टेट सम्पन्न होगा। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। किसानों के लिए चाहे गेहूं की बात करो, चाहे अपने बिजली की बात करो, चाहे मूंगफली की बात करो, चाहे चने की बात करो, चाहे सरसों की बात करो, जो भी भाव मिले हैं

(श्री मंगलाराम गोदारा)

किसान को। चाहे दूध की बात करो, दूध का बोनस दे दिया दो रुपये, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दवाई फ्री, पशुओं की दवाई फ्री, आदमियों की दवाई फ्री। बी पी एल को मकान मिल रहे हैं, ए पी एल को दवाई फ्री मिल रही है, हर आदमी इस सरकार से खुश है। गांव में अगर कोई आदमी जाकर बात करे, हो सकता है, एक-दो कोई विरोधी कोई बात कह सकता है, बाकी कोई आदमी के मुंह में यह जबान नहीं है कि साहब इस सरकार ने बुरा काम किया है कोई। सरकार जो दे रही है, मैं समझता हूं कि इतना ज्यादा आज तक कभी नहीं मिला। तो मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि मेरे जो बाकी जी एस एस हैं, ये जल्दी से जल्दी स्वीकृत करवाएं।

बाकी एक कन्या महाविद्यालय मेरे डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नहीं है और साठ-साठ, सत्तर-सत्तर किलोमीटर की दूरी में कन्या विद्यालय नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से, मंत्रीजी से मांग करता हूं कि मेरे यहां कन्या विद्यालय जरूर आप खुलाने की चेष्टा करें। दूसरा, पीएचईडी मंत्रीजी बैठे हैं, मेरी छोटी-छोटी मांग हैं एक-दो- उदरासर पाइप लाइन और बीआई पाइप लाइन। उदरासर जो सुरजनसर से पानी जाता है, वह पाइप लाइन बार-बार टूट जाती है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हूं, छोटा ही काम है, कोई दो -ढाई करोड़ का हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो आप जरूर इसमें घोषणा करें और काम करवाएं। तीसरा मेरे तीस से पैंतीस गांव फ्लोराइड पानी से युक्त हैं, फ्लोराइड है पानी में और जल स्तर भी नीचा गया है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कंवरसेन लिफ्ट से उन गांवों को पानी देने की योजना भी आप इस बजट में लें और घोषणा करें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। तीसरा, मेरी सड़क, डूंगरगढ़-सरदारशहर सड़क खराब है, पहले बीओटी में ली थी। बीओटी में उसमें, एक टेण्डर आया इसलिए वह पास नहीं हुआ। डूंगरगढ़-लूणकरणसर, वह भी बीओटी में ली हुई थी और उसमें भी टेण्डर आये नहीं, इसलिए वह काम बीच में पड़ा है। दोनों सड़कों की स्थिति खराब है इसलिए मैं मंत्रीजी से, मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि ये दोनों सड़कें किसी योजना में लेकर सड़कों का काम करवाएं जिससे कि जनता को राहत मिल सके, क्योंकि सरदारशहर-डूंगरगढ़ एक ऐसा मार्ग है जिससे दिल्ली डाइरेक्ट जुड़ता है डूंगरगढ़ -बीकानेर से। पूरा जो बैल्ट है वह जुड़ता है। सरदारशहर-डूंगरगढ़ सड़क ठीक होते ही। सार्दुलशहर-राजगढ़ और राजगढ़ से झूंपा और हरियाणा को क्रास करती है यह रोड। जयपुर का ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, जो ट्रैफिक बढ़ा है

(श्री मंगलाराम गोदारा)

सीकर साइड में। ज्यादा से ज्यादा व्हीकल झुंझुनूं होकर जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरदारशहर-डूंगरगढ़ सड़क को किसी योजना में लेकर इसका काम करवाएं और लूणकरणसर का भी काम करवाएं। लूणकरणसर का काम होते ही क्या हैं कि नागौर, जोधपुर जाने वाली गाड़ियां जो गंगानगर साइड से आती हैं, उन गाड़ियों को सौ किलोमीटर बचेगा और इस मेगा हाइवे से सीधा बीदासर से यह जुड़ जाएगा। मेरा निवेदन है कि इन सड़कों का काम कराएं। आपने समय दिया इसके लिए आपका मैं आभारी हूं, मुख्य मंत्रीजी का। मैं इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं कि ऐसा बजट आज तक किसी को नहीं मिला है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो उन्होंने छुई नहीं है। पूरा का पूरा एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक टच किया है, कोई भी योजना हो उसको टच किया है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री छोटूसिंह भाटी।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): सभापति महोदय, मुख्य मंत्री द्वारा पेश इस बजट के ऊपर मैं मेरा वक्तव्य देना चाहता हूं। माननीय, 1500 दिन पूरे कर लिये और चार बार यह बजट भाषण हमने सुना और हमारा वक्तव्य दिया। चार साल के पीरियड के अन्दर ज़िला लेवल की आशाएं यहां लेकर आये और इस पवित्र सदन में हमने बताई। जनता ने भी विश्वास किया था और सोचा था कि हमारे विधायक हमारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। माननीय सभापति महोदय, जिस हिसाब से जनता ने हमें खजाना दिया है, अस्थायी हम ट्रस्टी हैं, हम यही चाहते हैं कि सत्ता पक्ष और ना-पक्ष दोनों ही मिलकर जितना लाभ जनता को दे पाएं, निष्पक्ष न्याय दे पाएं, दें, ताकि जनता हम पर विश्वास करे। जिस हिसाब से जो सोच थी, चार साल का कार्यकाल पूरा हुआ, हर सोच, हर योजना में, मैं मेरी बात करता हूं, कि जैसलमेर में मैं उन विश्वासों पर खरा नहीं उतरा। मैंने मेरे क्षेत्र में हर बात ली और यहां तक पहुंचाई मगर उस हर योजना की बात पर जिस हिसाब से सोच था, उसमें सरकार खरी नहीं उतरी है। माननीय सभापति महोदय, पूरी बात करने के लिए तो समय नहीं है, लेकिन प्रशासन गांव की ओर इस कार्यकाल में दो बार हुआ। जनता यह चाहती थी। गांव में वही काम होंगे जो कई सालों से अटके हुए हैं। सरकार ने बहुत बड़े पैराग्राफ बनाकर तैयार किये थे कि नियमन होगा, कृषि अलाटमेंट होगा, किसी का फैसला होगा, स्कूल होगी, स्कूल के अन्दर पूर्णत: अध्यापक होंगे और जो अधूरी सड़कें पड़ी हैं वे भी पूरी होंगी। 2010 का जो प्रशासन हुआ, उसमें भी

(श्री छोटू सिंह भाटी)

लोगों ने खूब सारे आवेदन किये। हमारे जैसलमेर की बात मैं करता हूं, न तो किसी प्रकार का कृषि अलाटमेंट हुआ, न ही किसी प्रकार का नियमन हुआ। हुआ तो केवल मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र। या कोई अपने पूर्वजों की अपनी ही जमीन, अपनी ही औलाद को तो मिलनी है, उसमें किसी बात का कोई एहसान नहीं है। मेरे जैसलमेर क्षेत्र की मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम कई सालों से खेती कर रहे हैं लेकिन पूर्व भू-अभिलेखों ने सही नामांकन नहीं किया और लोगों का इन्द्राज सही नहीं हुआ। चाहते यह थे कि किसी भी प्रकार से जो हम अनआथोराइज्ड खेती कई सालों से कर रहे हैं, वह हमारी नियमन हो जाए। लेकिन इस चार साल के पीरियड में किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ। मेरे खयाल में जैसलमेर में ही नहीं पूरे प्रदेश के क्षेत्र में कहीं ऐसा काम नहीं हुआ है। यदि हो गया है किसी जगह, तो हमारे साथ भेदभाव हुआ होगा- चाहे पेयजल का मामला हो, सड़क निधि का मामला, चाहे बिजली का मामला हो। हमारा जैसलमेर एक ऐसा क्षेत्र है जो हर प्रकार के खनिज इस प्रदेश को देता है। लेकिन जिस पंचायत हैडक्वार्टर के अन्दर प्रशासन शिविर लगता था उस गांव में पीने को पानी नहीं है। उस गांव के लोगों ने विरोध किया कि बाकी चीजों को छोड़ पहले पानी पिलाओ। इससे ज्यादा सरकार के लिए क्या अफसोसजनक हो सकता है? उस दिन स्कूल बंद रही, उस दिन ये काम हुए।

सभापति महोदय, मुझे पता है कि समय कम मिलेगा, लेकिन हमारी भी ख्वाहिश है कि इस पांच साल के अस्थायी ट्रस्ट को कुछ सुनाएं ताकि हमारी बात पहुंचे कि वकील ने बोलने में कमी नहीं रखी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप विराजें। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 12 मार्च, 2013 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.45 बजे मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 2013 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

अलवर जिले में संचालित छात्रावास

167. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले में कितने राजकीय छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं व इन छात्रावासों में कितने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं? छात्रावासों में रह रहे बच्चों का छात्रावास वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में क्या-क्या सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान है? इसके लिये कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? छात्रावासवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावासों में लम्बे समय से छात्रावास अधीक्षक तथा अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में 30 में से 29 राजकीय छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, इन छात्रावासों में 1118 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। छात्रावास में रह रहे बच्चों की संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) उक्त छात्रावासों में रह रहे छात्र-छात्राओं को विभागीय आदेश क्रमांक 41746 दिनांक 26.05.2011 में उल्लिखित प्रावधान अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 (जनवरी, 2013 तक) में कुल 93 लाख 47 हजार 280 रुपये की राशि व्यय की गई है। व्यय राशि का मदवार व छात्रावासवार विवरण परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के सेवानिवृत होने व त्याग पत्र देने तथा अन्य पदों में चयन होने के कारण पद रिक्त हैं।

(4) जी हां। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर को विश्वविद्यालय का दर्जा

168. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या तकनीकी शिक्षा [कृषि] राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने कृषि विश्वविद्यालय कहां-कहां पर कब से संचालित हैं और इनके अधीन कितने-कितने कृषि महाविद्यालय कहां-कहां पर कब से संचालित हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग विभिन्न संगठनों द्वारा की जाती रही है? यदि हां, तो कब-कब तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर को विश्वविद्यालय का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में दो कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनमें एक स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में 1 अगस्त, 1987 से एवं दूसरा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में वर्ष 1999 से संचालित है।

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अधीन निम्न संघटक कृषि महाविद्यालय संचालित है:-

1. गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर - 1988 से संचालित।
2. कृषि महाविद्यालय, बीकानेर—1988 से संचालित।
3. श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) - 1947 से संचालित।
4. कृषि महाविद्यालय, लालसोट (दौसा) - 2007 से संचालित।
5. कृषि महाविद्यालय, मंडोर (जोधपुर) - 2012 से संचालित।
6. कृषि महाविद्यालय, सुमेरपुर (पाली) - 2012 से संचालित।

इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त निम्न छह कृषि महविद्यालय भी संचालित हैं :-

(तकनीकी शिक्षा (कृषि) राज्य मंत्री)

1. राजकीय पी जी महाविद्यालय, सवाई माधोपुर।
2. बाबा भगवानदास राजकीय पी जी महाविद्यालय, चिमनपुरा।
3. स्वामी केशवानन्द महाविद्यालय, संगरिया।
4. दयानन्द कृषि महाविद्यालय, अजमेर।
5. परमानन्द डिग्री कालेज, गजसिंहपुर।
6. चौधरी परमाराम गोदारा कृषि महाविद्यालय, भादरा, तहसील पदमपुर।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के अधीन निम्न संघटक कृषि महविद्यालय संचालित हैं:-

1. राजस्थान कृषि महाविद्यालय वर्ष 1955 से उदयपुर में संचालित है।
2. प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महविद्यालय वर्ष 1964 से उदयपुर में संचालित है।
3. गृह विज्ञान महाविद्यालय वर्ष 1966 से उदयपुर में संचालित है।
4. डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय वर्ष 1978 से उदयपुर में संचालित है।
5. उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय वर्ष 2004 से उदयपुर में संचालित है।
6. मात्स्यिकि महाविद्यालय वर्ष 2010 से उदयपुर में संचालित है।

(2) जी हां। यह सही है कि जयपुर ज़िले में जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग विभिन्न संगठनों द्वारा की जाती रही है। श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर को विश्वविद्यालय का दर्जा देने की निम्न संगठनों द्वारा मांग की गयी है :-

1. डा. बी.एल. जाट, यूनिट सचिव. राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन

   एस.के.एन. कालेज आफ एग्रीकल्चर जोबनेर जिला जयपुर द्वारा दिनांक 15.02.2010
2. श्री सुरेन्द्र सिंह राव, प्रधान, शैक्षणिक कर्मचारी संघ कृषि महाविद्यालय जोबनेर द्वारा दिनांक 15.2.2010

(तकनीकी शिक्षा (कृषि) राज्य मंत्री)

3. श्री कालूराम धायल, अध्यक्ष व्यापार मण्डल, जोबनेर द्वारा दिनांक 15.2.2010
4. श्री बाबूलाल फगोडिया अध्यक्ष, सेन्टल स्टूडेन्ट यूनियन एस.के.आर.ए.यू; बीकानेर द्वारा दिनांक 18.9.2012 एवं 11.2.2013
5. समस्त कर्मचारी संघ, एस.के.एन. कालेज आफ एग्रीकल्चर जोबनेर जिला जयपुर द्वारा दिनांक 11.2.2010
6. श्री बाबूलाल नागर, मा. राज्य मंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग एवं डेयरी विकास द्वारा दिनांक 9.2.2013
7. श्री लाल चन्द कटारिया मा. सांसद लोकसभा द्वारा दिनांक 11.2.2013
8. श्री गोविन्द कुमार बागडी, 36 एसकेएन स्टाफ कोलोनी, जोबनेर द्वारा 9.2.2013 से ईमेल से
9. विधान सभा के विगत सत्रों में भी माननीय विधायक श्री निर्मल कुमावत द्वारा जोबनेर में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की मांग की गयी थी ।

उक्त मांग पत्रों पर विभाग द्वारा स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर से प्रस्ताव का परीक्षण हेतु पत्र कुलसचिव, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर को भिजवाये गये।

(3) वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट भाषण में जोबनेर में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की जा चुकी है।

जमवारामगढ़ में टीएफसी योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कें

169. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में टीएफसी योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में कितनी-कितनी सड़कें कहां-कहां स्वीकृत की गयी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों का कार्य प्रारम्भ करने की तिथि तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि क्या रखी गयी तथा कौन-कौनसी सड़कों के कार्य की निविदा जारी कर दी गई एवं कौन-कौनसी सड़कों के कार्य की निविदा

(श्री गोपाल मीणा)

अभी तक जारी नहीं की गई? निविदा जारी नहीं करने के कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त स्वीकृत सड़कों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार उक्त स्वीकृत सड़कों की शीघ्र निविदा जारी कर कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में टी.एफ.सी. योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में निम्न तीन सड़कें स्वीकृत की गई:-

क्र. सं.	**सड़क का नाम**	**लम्बाई (कि.मी.)**	**राशि (रु. लाख)**
1	आंधी से साईपुर कि.मी. 0/0 से 3/0	3.00	32.00
2	सम्पर्क सड़क केला का बास 0/0 से 1/0	1.00	10.00
3	बूज चावंडिया दूधली रोड 3/0 से 6/900	3.90	39.00
	योग	**7.90**	**81.00**

(2) उक्त सभी सड़कों की निविदायें दिनांक 22.02.2013 को प्राप्त कर ली गई हैं तथा निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित अवधि चार माह में कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(4) उपरोक्त भाग 2 एवं 3 अनुसार।

प्रदेश के कृषकों को रासायनिक खाद की उपलब्धता

170. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

प्रदेश में वर्ष 2008 से 2012 तक किस-किस वर्ष में किन-किन जिलों में कहां-कहां पर कितनी-कितनी डीएपी, यूरिया व अन्य रासायनिक खाद

(श्री नन्दलाल मीणा)

किसानों को उपलब्ध करवाया गया तथा किन-किन जिलों में कहां-कहां पर खाद का वितरण नहीं हो पाया और इसके क्या कारण रहे? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में वर्ष 2008 खरीफ से रबी 2012-13 तक उपलब्ध कराये गये डीएपी, यूरिया व अन्य रासायनिक खाद का वर्षवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जिन जिलों में खाद का वितरण नही हो पाया उसका कारण सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षण हेतु कार्य योजना

171. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में 1 जनवरी, 2008 से जनवरी, 2013 तक वर्षवार मदरसों में कितने-कितने शिक्षक, शिक्षा सहायक (पैरा-टीचर) एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षक कार्यरत रहे हैं? उक्त में से कितने मदरसे मदरसा बोर्ड से सम्बद्ध हैं?

(2) उक्तावधि में कौन-कौन से वर्षों में उच्च पदों पर कितनी नई नियुक्तियां हुई एवं कितने सेवानिवृत्त हुए?

(3) वर्तमान में मदरसों में कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने-कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सरकार की क्या योजना है?

(4) मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या सुविधाएं सृजित की गईं? कितने मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है एवं कितने मदरसों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है?

उत्तर

(1) मदरसा बोर्ड के अधीन पंजीकृत मदरसों में अध्यापन कार्य करवा रहे शिक्षा सहयोगियों का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	कार्यरत उर्दू शिक्षा सहयोगी	कार्यरत कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी
1.	2007-08	501	-

(अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री)

2.	2008-09	1793	-
3.	2009-10	1793	-
4.	2010-11	1793	500
5.	2011-12	3605	500
6.	2012-13	5293	500

वर्तमान में 5293 उर्दू शिक्षा सहयोगी एवं 500 कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी पंजीकृत मदरसों में कार्यरत हैं।

उपरोक्त सभी शिक्षा सहयोगी मदरसा बोर्ड से सम्बद्ध है।

(2) राजस्थान मदरसा बोर्ड के अधीन पंजीकृत मदरसों में शिक्षा सहयोगियों को संविदा पर रखा जाता है। बोर्ड कार्यालय में सभी पद प्रतिनियुक्ति के हैं। जिन पर राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों आदि से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लिए जाते हैं एवं इनकी सेवानिवृति इनके मूल विभाग से ही की जाती है।

(3) मदरसावार शिक्षा सहयोगियों के पद स्वीकृत नहीं है। बोर्ड को पंजीकृत मदरसों हेतु समग्र रूप से शिक्षा सहयोगियों के पद उपलब्ध करवाए जाते हैं। मदरसों की आवश्यकता एवं बोर्ड के पास उपलब्धता के आधार पर शिक्षा सहयोगी मदरसों को अध्यापन कार्य हेतु उपलब्ध करवाए जाते हैं। वर्तमान में 826 पद रिक्त हैं। जिन पर शिक्षा सहयोगी लेने हेतु भर्ती की कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी तथा कम्प्यूटर सिस्टम आबंटित किए जाते हैं। वर्तमान में 881 मदरसों में कम्प्यूटर सिस्टम के साथ कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है एवं 2807 मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा पुस्तक के माध्यम से दी जा रही है।

राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन द्वारा प्रशिक्षण पर व्यय राशि

172. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन कितना दुग्ध

(श्री अमराराम)

संकलन करती है तथा कितना दुग्ध एवं अन्य उत्पाद बिक्री करती है? वर्ष 2008 से 2013 तक की माहवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में दुग्ध खरीद की दर क्या है तथा विक्रय मूल्य क्या है तथा कौन-कौन से जिला दुग्ध उत्पाद संघ घाटे में या मुनाफे में हैं?

(3) सरकार द्वारा गत चार वर्षों में प्रशिक्षण के लिये जमा की गई राशि का उपयोग कहां-कहां प्रशिक्षण शिविर लगाकर कितनी राशि का उपयोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण प्रदर्श-क पर संलग्न है।

विवरण प्रदर्श-ख 1 से ख-5 पर वर्ष 2008 09 से 2012 13 तक संलग्न है।

(2) राज्य में दूध की वर्तमान खरीद दर (के.जी. फैट के अनुसार) संघवार विवरण प्रदर्श-ग पर संलग्न है। विवरण प्रदर्श-घ पर संलग्न है।

वर्ष 2011-12 में घाटे एवं मुनाफे के संघों का विवरण प्रदर्श-य पर संलग्न है।

(3) विवरण प्रदर्श-र पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नदबई के ग्रामों हेतु पेयजल योजनाएं

173. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा' (नदबई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई के अन्तर्गत पंचायत समिति नदबई, रूपवास एवं सेवर में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में क्षेत्र की पेयजल समस्या से सम्बन्धित गांवों की डी.पी.आर. स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो इनमें से कितने कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है एवं कितने कार्य पूर्ण होने शेष हैं? सूची वर्षवार एवं गांव के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई, रूपवास एवं सेवर में वर्ष 2012-13 में जिन गांवों में पेयजल समस्या थी उनके लक्ष्य प्रस्तावित किये गये हैं? यदि हां, तो इन गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा')

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के गांव श्यौराना में पेयजल आपूर्ति हेतु कोई पेयजल स्कीम नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों के लिये पेयजल स्कीम स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) की पंचायत समिति, नदबई एवं सेवर में वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम अन्तर्गत क्रमश: 15 गांवों एवं 2 गावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) स्वीकृत की जाकर क्रमश: 13 एवं 2 गांवों की योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। पंचायत समिति, नदबई के शेष 2 ग्रामों की प्रगतिरत योजनाओं के कार्य मार्च, 2013 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में पंचायत समिति, नदबई के 10 गांवों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) स्वीकृत की गई एवं इन समस्त योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जाकर गांवों को स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। वर्षवार वांछित पूर्ण विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ व ब पर संलग्न है।

पंचायत समिति, सेवर के 95 ग्राम (विधान सभा क्षेत्र नदबई के 53 एवं विधान सभा क्षेत्र, भरतपुर के 42 ग्राम) एवं पंचायत समिति, कुम्हेर के 2 ग्राम सहित कुल 97 ग्राम चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना के प्रथम चरण के द्वितीय भाग में सम्मिलित होने के कारण विधान सभा क्षेत्र नदबई की पंचायत समिति, सेवर के ग्रामों की उक्त दो वित्तीय वर्षों में डी.पी.आर. स्वीकृत नहीं की गई।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) की पंचायत समिति, नदबई एवं रूपवास में वित्तीय वर्ष 2012-13 में पेयजल समस्या से प्रभावित एवं लक्षित क्रमश: 3 गांव एवं 1 गांव, कुल 4 गांवों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करने हेतु स्वीकृत की गई योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) की पंचायत समिति, सेवर के हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित ग्राम श्यौराना (वर्ष 2001 की जनगणनानुसार जनसंख्या = 647) में विभागीय नीति अनुरूप 3 क्रियाशील हैण्डपम्पों से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना के प्रथम चरण के द्वितीय भाग के अन्तर्गत, मलाह हैडवर्क्स भरतपुर आफटेक से स्वीकृत 97 ग्रामों की क्षेत्रीय जल योजनाओं में सम्मिलित ग्राम श्यौराना को कूम्हां ग्राम में प्रस्तावित उच्च जलाशय से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है । उक्त योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 13 सितम्बर, 2012 को कार्यादेश जारी किया जा चुका है तथा योजना को कार्यादेश तिथि से आगामी 30 माह में पूर्ण किया जाकर श्यौराना ग्राम सहित उक्त समस्त 97 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाटाडू (बाड़मेर) में सहकारी बैंक की स्थापना

174. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा सहकारिता के माध्यम से कौन-कौनसी जन उपयोगी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जनता एवं किसानों को सुविधा मुहैया करवाये जाने हेतु सहकारी बैंकों का संचालन किया जा रहा है?

(3) बाड़मेर जिले में कितने सहकारी बैंकों का संचालन किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि बायतू पंचायत समिति के बाटाडू कस्बे में को-आपरेटिव बैंक की महती आवश्यकता है और प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन है?

(5) क्या सरकार उक्त बैंक के संचालन के आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सहकारिता विभाग के माध्यम से संचालित जन उपयोगी योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 से 3 पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) बाड़मेर जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक लि; बाड़मेर, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि., बालोतरा और बालोतरा अरबन को-आपरेटिव बैंक लि., संचालित है।

(सहकारिता मंत्री)

(4) बायतू पंचायत समिति के बाटाडू कस्बे में सहकारी बैंक की शाखा खोलने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(5) बाड़मेर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक से बाटाडू में बैंक शाखा खोले जाने का प्रस्ताव का परीक्षण प्रकियाधीन है। परीक्षण उपरांत उचित कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समितियों में कार्यरत विकास अधिकारी

175. श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समितियों में जो विकास अधिकारी का पद है क्या वह राजपत्रित (गजेटेड) अधिकारी का पद है?

(2) एक राजपत्रित अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद एवं दूसरे राजपत्रित अधिकारी के आने तक विकास अधिकारी का चार्ज किस स्तर के अधिकारी को दिया जाता है? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि इस वरिष्ठता क्रम की अवहेलना की जा रही है, तो इसमें उत्तरदायित्व किस का है?

(4) क्या वरिष्ठ कर्मचारी के रहते किसी कनिष्ठ कर्मचारी को राजनैतिक आधार पर विकास अधिकारी बनाया जा सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विकास अधिकारियों का चार्ज देने के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाये गये हैं। चार्ज देने के सम्बन्ध में विभागीय आदेश क्रमांक 2321 दिनांक 5.9.2007 में विकास अधिकारियों का पद रिक्त होने की स्थिति में विकास अधिकारी के पद का अतिरिक्त कार्यभार पंचायत समिति में पदस्थापित वरियताक्रम में से एक को दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को प्रसारित किये हुए हैं (परिशिष्ट "अ"), इसके साथ ही विभागीय आदेश क्रमांक 2168 दिनांक 2.6.2010 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना एवं अन्य विकास

(पंचायती राज मंत्री)

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकास अधिकारी के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को देने हेतु निर्देशित किया गया है (परिशिष्ट "ब") । इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन या राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के मध्यनजर किसी अन्य अधिकारी को विकास अधिकारी के पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है।

(3) विभाग द्वारा विकास अधिकारी के रिक्त पद का कार्यभार देने हेतु वरिष्ठता क्रम में से किसी भी एक अधिकारी को कार्यभार देने के आदेश प्रसारित किये हुए हैं। जिला स्तर सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किसी भी एक अधिकारी को कार्यभार दिया जा सकता है।

(4) जी नहीं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

विशेष बाल गृहों को विभिन्न कार्यों हेतु आबंटित राशि

176. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सम्प्रेषण गृह, विशेष गृह, किशोर गृह तथा अपचारी बालिका गृहों में बच्चों को मनोचिकित्सक, अध्यापन कार्य, भ्रमण कार्य, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि के लिए क्या प्रावधान है? प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रावधानों के तहत विगत पांच वर्षो में कितनी राशि आबंटित की गई तथा उसके विरुद्ध कितनी राशि अब तक व्यय की गई? वर्षवार व जिलेवार आबंटित राशि व व्यय राशि की सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त गृहों में काम करने वाले विभिन्न कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विगत पांच वर्षो में इन कर्मचारियों के कब-कब प्रशिक्षण आयोजित किये गये तथा कितने लोगों को इसमें प्रशिक्षित किया गया? वर्षवार प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की सूची तथा इन प्रशिक्षण पर आबंटित राशि के विरुद्ध व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा संचालित सम्प्रेक्षण गृह, किशोर गृह एवं अपचारी बालिका गृह में बच्चों को मनोचिकित्सक, अध्यापन कार्य, भ्रमण कार्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण नियम) 2011 के नियम 46(7), 47(1)(2)(3), 48(अ)(ब), 49(1)(2) के अन्तर्गत प्रावधान उपलब्ध है। नियम की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। व्यावसायिक प्रशिक्षण की सेवायें लेने तथा भ्रमण के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट- 2 व परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध हैं।

(2) उक्त प्रावधानों के तहत राज्य में संचालित सम्प्रेक्षण गृह, अपचारी बालिका गृह एवं किशोर गृहों में विगत 5 वर्षों में आबंटित तथा व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2011 के नियम 90 में गृहों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। राजस्थान किशोर न्याय नियम, 2011 की प्रति परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

(4) विगत पांच वर्षों में आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों (सम्भाग स्तर पर/राज्य स्तर) में प्रशिक्षित किये गये कार्मिकों की सूची एवं प्रशिक्षण पर आबंटित राशि एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-6 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बयाना (भरतपुर) में कृषि महाविद्यालय की स्थापना

177. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या तकनीकी शिक्षा [कृषि] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बयाना तहसील में स्थित बंध बारैठा बांध के पास जो सरकारी भूमि है, में कृषि महाविद्यालय का खोला जाना भरतपुर एवं पड़ौसी जिलों के लिये वरदान सिद्व होगा?

(2) क्या सरकार बयाना स्थित बंध बारैठा के पास स्थित भूमि पर कृषि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट भाषण में भरतपुर में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा किये जाने से अब एक ही जिले में दो कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता नही है।

(2) जी नहीं। बयाना स्थित बंध बारैठा बांध के पास स्थित भूमि पर कृषि महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कें

178. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में कौन-कौनसी सड़कों के पेचवर्क/मरम्मत पर राशि व्यय की गयी? सड़कवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण अथवा मरम्मत करने हेतु कौन-कौन से प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण अथवा मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक सड़कों के पेचवर्क एवं नवीनीकरण पर व्यय राशि का सड़कवार विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में कुल 543.27 कि.मी. लम्बाई की 158 सड़कों में से 5 सड़कों की 21.35 कि.मी. लम्बाई आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण के प्रस्तावों पर विचार राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) जी हां। उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हरा चारा बीज क्रय हेतु निर्धारित शर्तों में छूट

179. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा रंजका, जई और बरसिंग चारे का बीज वर्ष 2011 व 2012 में क्रय किया गया? यदि हां, तो किस-किस फर्म से किन नियमों एवं शर्तों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त वर्षों में बीज क्रय हेतु बीज निगम ने कम्पनियों पर शर्तें रखी गई थीं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बीज निगम द्वारा रखी गई शर्तों के तहत बीज क्रय किया गया? यदि नहीं, तो क्यों एवं क्या बीज निगम की शर्तों में किसी प्रकार की छूट दी गई है? यदि हां, तो किस के द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा वर्ष 2011 व 2012 में चारे का बीज क्रय किया गया उसका विवरण नियम एवं शर्तों सहित परिशिष्ट-1 व 2 पर है।

(2) हां। नियम व शर्तें परिशिष्ट-2 पर है।

(3) हां। बीज निगम द्वारा रखी गई शर्तों के तहत ही चारा बीज क्रय किया गया है।

जी नहीं, बीज निगम की शर्तों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फर्जी मदरसा शिक्षकों का नियुक्ति प्रकरण

180. श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर) : क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने मदरसा शिक्षा उन्नयन के लिए मदरसा शिक्षकों की भर्ती की है? यदि हां, तो 2008 से जनवरी, 2013 तक भर्ती किए मदरसा शिक्षक एवं कम्प्यूटर शिक्षकों की सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मई, 2012 में मदरसा उर्दू शिक्षा सहयोगी एवं कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगियों को नियुक्ति दी थी? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सूची में 104 मदरसा शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति दे दी गई थी और उन्होंने 5 माह तक वेतन भी उठा लिया था?

(4) क्या यह सही है कि उक्त फर्जी 104 मदरसा शिक्षा सहयोगियों को हटा दिया गया था व जांच रिपोर्ट बिठाई गई थी?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान मदरसा बोर्ड ने मदरसा शिक्षा उन्नयन के लिए पंजीकृत मदरसों में अध्यापन कार्य करवाने हेतु उर्दू शिक्षा सहयोगी एवं कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगियों को पूर्वत: अस्थाई तौर पर संविदा पर लिया है। वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 तक संविदा पर लिये गये मदरसा शिक्षा सहयोगियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वर्ष	परिशिष्ट संख्या
1.	2008-09	1
2.	2011-12	2, 3 एवं 4
3.	2011-12	5

उपरोक्त सूची जारी आबंटन पत्रों के आधार पर तैयार की गयी है।

(2) जी हां। सूची परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(3) मदरसा बोर्ड द्वारा गठित जांच समिति ने भर्ती प्रक्रिया में 128 मदरसा शिक्षा सहयोगियों को अनियमित माना है। इनमें से केवल 12 शिक्षा सहयोगियों को कुछ माह का मानदेय दिया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट 6 पर संलग्न है।

(अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री)

(4) मदरसा बोर्ड द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर 128 शिक्षा सहयोगियों के नाम बोर्ड की कार्यरत शिक्षा सहयोगियों की सूची से हटा दिए गए हैं। प्रकरण की प्राथमिक जांच मदरसा बोर्ड स्तर पर करवाई गई थी। अब विस्तृत जांच के लिए निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

(5) उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने हेतु निदेशक, उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने हेतु निदेशक, उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने हेतु निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदत्त सहायता

181. श्रीमती अन्जु खन्गवाल (बस्सी): क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग/बोर्ड द्वारा किस-किस प्रकार की सहायता स्वीकृत की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कितने व्यक्तियों को कितनी राशि की सहायता/अनुदान दिया गया? नामवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी राशि सहायता/अनुदान हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं/इकाइयों को कितनी -कितनी राशि की सहायता/अनुदान का भुगतान किया गया? नामवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त में से वर्तमान में कितने प्रस्ताव लम्बित हैं? सरकार द्वारा लम्बित प्रस्तावों पर कब तक सहायता/अनुदान स्वीकृत कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग/बोर्ड द्वारा जिन योजनाओं में सहायता स्वीकृत की जाती है उनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री)

(2) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के अन्तर्गत एजेन्सीवार लाभान्वितों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	एजेन्सी	लाभान्वितों की संख्या	मार्जिन मनी/अनुदान
1	खादी बोर्ड	11	16.15 लाख रु.
2	खादी आयोग	10	74.03 लाख रु.
3	उद्योग विभाग	13	45.67 लाख रु.

वर्षवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। उक्त के अलावा सघन क्षेत्र विकास समिति बस्सी को स्फूर्ति योजनान्तर्गत जनवरी, 2009 से आज तक रु. 8.60 लाख अनुदान के रूप में दिये गये हैं। इसी समिति को प्रोडिप योजनान्तर्गत रु. 1.00 लाख का अनुदान दिया गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक एजेन्सीवार प्राप्त आवेदन पत्र निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	एजेन्सी	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	मार्जिन मनी/अनुदान राशि
1	खादी बोर्ड	63	100.99 लाख रु.
2	खादी आयोग	34	184.12 लाख रु.
3	उद्योग विभाग	88	219.71 लाख रु.

जिनकी नामवार, वर्षवार सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। लाभान्वित व्यक्तियों की सूची प्रश्न संख्या 2 अनुसार परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) उक्त में से एजेन्सीवार लम्बित आवेदन पत्र बैंक शाखाओं में वास्ते स्वीकृति हेतु तथा जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु लम्बित है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	एजेन्सी	बैंकों में लम्बित आवेदन पत्र	टास्क फोर्स समिति में रखे जाने वाले लम्बित आवेदन पत्र
1	खादी बोर्ड	7	1
2	खादी आयोग	-	-
3	उद्योग विभाग	8	-

(खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री)

उक्तानुसार लम्बित आवेदन पत्रों का 31 मार्च, 2013 से पूर्व तक सम्बन्धित वित्तीयन बैंक शाखाओं तथा जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। सूची परिशिष्ट-4 एवं 5 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना उपखण्ड मुख्यालय पर 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना

182. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डेगाना विधान सभा क्षेत्र के डेगाना कस्बे की समान आबादी वाले सभी कस्बों व उपखण्ड मुख्यालयों पर 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन बने हुए हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर?

(2) क्या सरकार डेगाना कस्बा जो उपखण्ड मुख्यालय एवं महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, उसमें 132 केवीए ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन विधान सभा क्षेत्रवार/जिलेवार/उपखण्ड मुख्यालय अनुसार स्वीकृत नहीं किये जाते हैं। नये 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन विद्युत वितरण निगमों द्वारा क्षेत्र की विद्युत मांग के आधार पर प्रस्तावित किये जाते हैं, जिन पर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप पाये जाने पर तथा संसाधनों की उपलब्धता एवं विभिन्न योजनाओं की प्राथमिकता के मद्देनजर स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(2) डेगाना कस्बे में 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बनाये जाने की योजना को राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा दिनांक 28.2.2013 को स्वीकृति जारी कर दी है तथा इसके क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

बीपीएल व अन्त्योदय परिवारों को लेवी चीनी का वितरण प्रकरण

183. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ओम बिरला)

(1) क्या यह सही है कि राज्य के बीपीएल व अन्त्योदय परिवारों को 500 ग्राम प्रति यूनिट लेवी चीनी का वितरण किया जाता है? यदि हां, तो सम्बन्धित आदेशों की प्रति सहित जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक राज्य को आबंटित लेवी चीनी की मात्रा की माहवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त लेवी चीनी को जिलेवार आबंटित किया जाता है? यदि हां, तो राज्य में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक आबंटित की गई लेवी चीनी व आबंटन के विरुद्ध जिलों द्वारा किये गये उठाव व बीपीएल परिवार को वितरित की गई चीनी मात्रा का जिलेवार माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कई जिलों द्वारा आबंटित लेवी चीनी का पूर्ण उठाव नहीं करने के कारण कई माह तक बीपीएल उपभोक्ताओं को चीनी वितरण से वंचित रहना पड़ा है? यदि हां, तो बीपीएल उपभोक्ताओं हेतु आबंटित कितनी लेवी चीनी की मात्रा उठाव नहीं करने के कारण लैप्स हुई? जिलेवार माहवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बीपीएल/अन्त्योदय उपभोक्ताओं को लेप्स की गयी चीनी की मात्रा का उठाव करवाकर पुन: वितरित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के बीपीएल व अन्त्योदय परिवारों को 500 ग्राम प्रति यूनिट लेवी चीनी का वितरण किया जाता है। सम्बन्धित आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर एवं भारत सरकार से जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक राज्य को आबंटित लेवी चीनी की माहवार सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक लेवी चीनी के जिलेवार आबंटन, उठाव/वितरण का माहवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। आबंटित लेवी चीनी का उठाव नहीं करने के कारण लैप्स हुई मात्रा का जिलेवार एवं माहवार विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) जी हां। माह अप्रैल, 2012 से अक्टूबर, 2012 तक लैप्स हुई लेवी चीनी की छोटी-छोटी मात्रा को अलग-अलग चीनी मिलों के स्थान पर परिवहन

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

की व्यावहारिक दृष्टि को ध्यान में रखकर एक ही चीनी मिल से सामूहिक आबंटन हेतु चीनी निदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अनुरोध कर अवशेष रही लेवी चीनी प्राप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास में आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवार

184. श्री नवलकिशोर (बामनवास) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2012 तक विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कितने परिवारों को इंदिरा आवास योजना एवं मुख्य मंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया? तहसीलवार परिवार के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वर्ष 2008 से दिसम्बर, 2012 तक इन्दिरा आवास योजना में 2488 परिवारों को एवं मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना में 3726 परिवारों को आवासीय अनुदान सहायता की स्वीकृतियां जारी कर लाभान्वित किया गया। तहसीलवार परिवारों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धानका जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र प्रकरण

185. श्री रोहिताश कुमार (बानूसर) व **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2012 में राज्य के मुख्य सचिव ने धानका जाति को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र जारी करने के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु कोई पत्र केन्द्र सरकार को लिखा है? यदि हां, तो केन्द्र सरकार को लिखे पत्र की छाया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मुख्य सचिव द्वारा सीधे केन्द्र सरकार को लिखे पत्र पर तत्कालीन विभागीय मंत्री द्वारा मुख्य मंत्रीजी को विरोध दर्ज करवाया गया है? यदि हां, तो क्या? इस संदर्भ में हुए पत्राचार की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। धानका जाति को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने के स्पष्टीकरण के संदर्भ में मुख्य सचिव द्वारा सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अ.शा. पत्रांक 59404 दिनांक 16 अगस्त, 2012 द्वारा लिखा था। जिसकी प्रति परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

ब्यावर-पिंडवाड़ा सड़क मार्ग का मुआवजा प्रकरण

186. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सोजत के ब्यावर के पिण्डवाड़ा सड़क मार्ग को चार लाइन की सड़क करने हेतु एन.एच.आई. के द्वारा टेण्डर एल. एण्ड टी. कम्पनी को दिया गया है? यदि हां, तो कार्य कब तक पूर्ण होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार का गजट नोटिफिकेशन के बाद जो खसरा भूमि गजट में नहीं होती है उसे एन.एच.आई. अवाप्त कर सकती है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एल. एण्ड टी. कम्पनी व एन.एच.आई. द्वारा किसानों तथा सरकारी व गैर सरकारी मकानों का मुआवजा नहीं दिया है? यदि हां, तो किन-किन को मुआवजा दिया व कितने किस कारण से बकाया हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि एन.एच.आई. व एल. एण्ड टी. द्वारा चल रहे चार लाइन सड़क निर्माण कार्य से गांव व शहर में आने-जाने के रास्ते अवरूद्ध हुए हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा आने-जाने हेतु रास्ते कब तक बनाये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) जयपुर से प्राप्त जबाव के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-14 के ब्यावर-पाली-पिण्डवाड़ा सड़क खण्ड को चार लेनीकरण का कार्य डी.बी.एफ.ओ.टी. आधार पर मैसर्स एल. एण्ड टी. बी.पी.पी. टोलवे प्रा.लि. को रियायतग्राही के रूप में

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

आबंटित किया है। रियायतग्राही के साथ सम्पादित अनुबन्ध के अनुसार प्रस्तावित चारलेन निर्माण कार्य माह जून, 2014 तक पूर्ण किया जाना है।

(2) भा.रा.रा.प्रा. से प्राप्त जबाव के अनुसार परियोजना क्रियान्वयन हेतु वांछित अतिरिक्त भूमि अवाप्ति का कार्य राज्य सरकार की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा रहा है, जिसमें धारा 3(क) एवं 3(घ) के अनुसार गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रियानुसार वांछित अतिरिक्त भूमि अवाप्ति हेतु की जाती है। इसके अन्तर्गत भौतिक सत्यापन में पाई गई अतिरिक्त भूमि अवाप्ति, राजस्व नक्शों के अपूर्ण एवं त्रुटियों के समाधान हेतु अतिरिक्त भूमि अवाप्ति, मानवीय भूलों के निराकरण हेतु अतिरिक्त भूमि अवाप्ति छूटे हुए खसरा नम्बरों की भूमि अवाप्ति हेतु पुन: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत वांछित गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया का पालन कर ही भूमि अवाप्ति की कार्यवाही सम्पादित की जाती है, जो कि पूर्णतया वैध कार्यवाही है।

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत फोरलेन परियोजना हेतु भूमि को अधिग्रहित की जाकर, मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। अधिग्रहित भूमि में स्थित सरकारी, गैर सरकारी निर्माण/संरचना की सर्वे वेल्यूअर द्वारा करायी जाकर बाद वेटिंग मूल्यांकन राशि का निर्धारण किया गया है। मुआवजा राशि एवं मूल्यांकन राशि का भुगतान हितबद्ध व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा किया जा रहा है। जिसमें अधिग्रहित निजी भूमि के मुआवजा निर्धारण एवं भुगतान का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है तथा संरचना/निर्माण मूल्यांकन राशि का निर्धारण एवं भुगतान का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। इसके अनुसार किसानों को देय मुआवजा राशि रुपये 89.85 करोड़ है। इसके अलावा सरकारी एवं गैर सरकारी मकानों की देय मुआवजा राशि रुपये 10.06 करोड़ है।

किसानों को देय राशि मुआवजा राशि रुपये 89.85 करोड़ में से 7222 चैकों के माध्यम से रुपये 42.39 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, शेष रही राशि रुपये 47.46 करोड़ का भुगतान नहीं किये जाने का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) भा.रा.रा.प्रा. के अनुसार वर्तमान में चारलेन सड़क निर्माण का कार्य प्रगतिरत होने से कुछ गांवों/शहरों की अप्रोच/लिंक सड़कों के मिलान प्रभावित होना स्वाभाविक है किन्तु इस सड़कों के मिलान बिन्दुओं का यथोचित अभियांत्रिकी निवारण राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क सीमा में कार्य सम्पादन के दौरान ही रियायतग्राही द्वारा किया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में गैर आबादी क्षेत्र में घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु कार्य योजना

187. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा गैर आबादी क्षेत्र में घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी करना बन्द कर रखा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार गैर आबादी क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन देने के लिए 2 एच.पी. की डी.पी. उपलब्ध करवाकर विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) डिस्काम समन्वय मंच द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं अन्य योजनाओं में गोचर भूमि, सिवाय चक भूमि, चरागाह, कृषि भूमि तथा राजकीय कार्यो के लिये आरक्षित भूमि, गैर आबादी भूमि तथा नाला, नदी, पहाड़ों पर आवासों में घरेलू कनेक्शन जारी नहीं करने का निर्णय लिया था। जबकि विद्युतिकृत गांव/ढाणियों एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत चयनित बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क एवं सामान्य परिवारों को नियमानुसार शुल्क लेकर कनेक्शन दिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्व-वित्त पोषित योजना में (अधिकतम पांच आवेदकों के समूह में भी) सम्पूर्ण राशि वहन करने पर या एम.पी./एम.एल.ए. राशि से विस्तार किये गये विद्युत तंत्र से कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है तथा स्थापित सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से 500 मीटर की परिधि में एवं अधिकतम कुल 5 घरेलू कनेक्शन तक दिये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं।

नीमराणा (अलवर) की मस्जिद भूमि पर अतिक्रमण

188. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर के नीमराणा कस्बे में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने मस्जिद पर अतिक्रमण कर लिया है? इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार बहरोड़ के सर्वे में मस्जिद व खसरा नम्बर-224 की रकबा 112 बीघा भूमि को वक्फ सम्पत्ति माना है?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1962 में उक्त सर्वे के आधार पर ही इसे वक्फ सम्पत्ति होने की अधिसूचना प्रकाशित की गई?

(4) क्या सरकार उक्त मस्जिद को अतिक्रमियों से मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला अलवर के नीमराणा कस्बे में स्थित मस्जिद पर अतिक्रमण नहीं है। जिला कलक्टर अलवर को इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर यथा स्थिति रखी हुई है।

(2) जी हां। तहसीलदार बहरोड की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 'मस्जिद 224 रकबा 112 बीघा 6 बिस्वा पूर्व 23 पश्चिम 23 उत्तर 22 दक्षिण 22 कुल 506 वर्गफुट' अंकित है। सर्वे रिपोर्ट परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) उक्त सर्वे के आधार पर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित सूचना परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(4) मस्जिद पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

(रिपोर्ट पुस्तकालय में रखी गयी)

खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं को अनुदान

189. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में खादी व ग्रामोद्योग से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार प्रदेश में खादी से रोजगार बढ़ाने के क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री सुखराम)

(3) प्रदेश में खादी बुनकरों की औसत प्रतिदिन आय कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में खादी का उत्पादन 2008 से 2012 तक किस-किस संस्था का कितना-कितना उत्पादन हुआ व कितनी-कितनी बिक्री हुई? संस्थावार वर्षवार उत्पादन व बिक्री का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त बिक्री पर सरकार द्वारा किस-किस संस्था को कितना-कितना अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2011-12 तक खादी बोर्ड व खादी आयोग द्वारा राज्य में खादी उद्योग के अन्तर्गत 26,978 व्यक्ति एवं ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत 4,88,004 व्यक्तियों को पूर्णकालीन एवं अंशकालीन रोजगार प्राप्त हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) **खादी बोर्ड**

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य सरकार की 12 वीं पंचवर्षीय योजना में खादी बोर्ड के माध्यम से खादी विकास फण्ड योजना, वर्कशैड निर्माण योजना, लघु खादी परियोजना को क्रियान्वित कराया जा रहा है, जिससे खादी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। योजनाओं का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट- 2)

खादी आयोग

संस्थाओं में नए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर नई-नई योजनाएं प्रायोजित की गई हैं, जैसे कि स्फूर्ति कार्यक्रम के तहत संस्थाओं को पुराने सरंजाम के बदले नई तकनीक के चर्खे व कर्घे उपलब्ध कराना, इसी प्रकार तथा रेडी टू वार्प योजना के तहत कामगारों को बुनाई हेतु ताना/बाना तैयार कर उपलब्ध कराना तथा कामगारों को वर्कशैड योजना के तहत उनके रहने के लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराना। योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) खादी क्षेत्र में कताई-बुनाई का कार्य पूर्णकालीन नहीं होता है, क्योंकि कत्तिन-बुनकरों द्वारा अपने घरेलू व कृषि कार्य के उपरान्त शेष समय में खादी का कार्य किया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर खादी बोर्ड व खादी आयोग के अन्तर्गत राज्य में कार्यरत खादी संस्थाओं में वर्ष

(खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री)

2011-12 में कार्यरत खादी बुनकरों की औसत वार्षिक आय रु 17891/- है। खादी बुनकर ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, जो औसतन छह माह कृषि एवं अन्य कार्य में व्यस्त रहते हैं। अनुमानत: छह माह खादी बुनाई कार्य से जुडे होते हैं। इस प्रकार सामान्यत: खादी बुनकरों की औसत प्रतिदिन आय लगभग रु. 100/- होती है।

(4) वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर खादी बोर्ड व खादी आयोग की राज्य में कार्यरत खादी संस्थाओं/समितियों के उत्पादन एवं बिक्री की जानकारी संस्थावार वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(5) सरकार द्वारा बिक्री पर संस्थाओं को कोई अनुदान देय नही होता है, अपितु संस्थाओं द्वारा ग्राहकों (उपभोक्ता) को बिक्री में दी गई छूट (रिबेट) राशि के पुनर्भरण स्वरूप राशि संस्थाओं को दी जाती है। संस्थावार वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक की रिबेट भुगतान की सूची परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले में वर्षा जल संग्रहण हेतु कार्य योजना

190. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भू-जल में यूरेनियम होना स्वास्थ्य के लिये घातक है? यदि हां, तो इसके क्या-क्या दुष्प्रभाव हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के कई जिलों में भू-जल में खतरनाक यूरेनियम पाया गया है? यदि हां, तो किस-किस जिले में? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि सीकर जिले में परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय एएमडी की ओर से किये गये अध्ययन में भू-जल में यूरेनियम की मात्रा तय मानक से सौ गुना अधिक पाई गई है? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में तय मानक से कितनी अधिक मात्रा में यूरेनियम पाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(4) क्या सरकार भू-जल में यूरेनियम से होने वाले ब्लड बोन और पेट के कैन्सर से मुक्ति दिलाने हेतु ठोस उपाय लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार जिला सीकर में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये कारगर नीति लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। चिकित्सा शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचनानुसार यदि भूजल में यूरेनियम पाया जावे एवं उस जल का लगातार उपयोग किया जावे तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चूंकि यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है। अत: भूजल में तय मानक से अधिक यूरेनियम होने पर इसके दुष्प्रभाव से ब्लड, बोन एवं पेट के कैंसर होने की संभावना रहती है।

(2) भूजल विभाग तथा जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की रसायनशाला द्वारा भूजल में यूरेनियम की मात्रा हेतु किसी प्रकार की जांच नहीं की जाती है।

(3) यूरेनियम की जांच परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसन्धान निदेशालय (एएमडी) द्वारा की जाती है जो भारत सरकार का उपक्रम है। अत: राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है।

(4) वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से राज्य के भीलवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, गंगानगर जिले में नेशनल प्रोग्राम फार प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल आफ केन्सर, डायबिटिज, कार्डियोवास्कुलर डिजिज एवं स्ट्रोक राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप चलाया जा रहा है।

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय में स्थापित एनसीडी क्लिनिक के तहत डे केयर कैंसर फेसिलिटी सेन्टर प्रारम्भ करने की प्रक्रिया की जा चुकी है। जिसके अन्तर्गत उक्त चयनित जिलों में ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर एवं सरवाइकल कैंसर के मरीजों को मेमोग्राफी जांच की सुविधा सहित आवश्यक दवाइयां, उपकरण आदि की व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं।

(5) सीकर जिले की पिपराली पंचायत समिति क्षेत्र में विश्व बैंक की

(भू-जल मंत्री)

सहायता से राजस्थान जल क्षेत्र पुन:संरचना परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इस क्षेत्र में जन सहभागिता आधारित योजना में वर्षा जल संरक्षण एवं कृत्रिम भूजल पुनर्भरण का कार्य जारी है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छत के वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहित करना राजस्थान जल नीति 2010 में शामिल किया गया है।

भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त अनाज की भण्डारण व्यवस्था

191. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 व 2011-12 में भारतीय खाद्य निगम से किस-किस किस्म का, कितना-कितना अनाज प्राप्त हुआ? प्राप्त अनाज में से कितना-कितना, किन-किन जिलों में वितरित किया गया? जिलेवार वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त अनाज में से कितने प्रतिशत की जांच करवाई गई व जांच में कितना अनाज खराब पाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वितरित अनाज का जिलों में उचित भण्डारण व्यवस्था अभाव के कारण से खराब होने के प्रकरण प्रकाश में आये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें

(4) क्या सरकार प्रदेश में खाद्य सामग्री का उचित भण्डारण व्यवस्था करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 व 2011-12 में भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त अनाज का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर एवं प्राप्त अनाज में से जिलों में वितरित की गई मात्रा का जिलेवार एवं वर्षवार परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त अनाज के प्रत्येक स्टाक से क्वालिटी निरीक्षक द्वारा गेहूं की गुणवत्ता की जांच हेतु नमूना लिया जाकर गेहूं की गुणवत्ता की जांच उपरान्त ही 'फेयर एवरेज क्वालिटी' के गेहूं का उठाव करवाया जाता है। 'फेयर एवरेज क्वालिटी' नहीं पाये जाने पर अनाज का उठाव नहीं किया जाता है। राज्य में खराब अनाज पाये जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से थोक विक्रेताओं के माध्यम से अनाज का उठाव कर जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पहुंचाया जाता है। उचित मूल्य की दुकानों पर भण्डारण व्यवस्था के अभाव के कारण अनाज खराब होने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

(4) राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खाद्यान्न के उचित भण्डारण की व्यवस्था करने हेतु 8.00 लाख मै.टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत वर्तमान पंचवर्षीय योजना में करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में इस भण्डारण क्षमता का विकास राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम एवं सहकारिता विभाग के माध्यम से करवाये जाने की योजना है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा जिले में हरित राजस्थान योजनान्तर्गत रोपित पौधे

192. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास [नरेगा] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा जिले से वर्ष 2008 से किन-किन ग्राम पंचायतों के किन-किन गांवों की सड़कों के साइड में कितने-कितने पौधे किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि खर्च कर लगाये गये, उनमें से कितने पौधे जीवित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा इन जीवित पौधों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2008 से अब तक भीलवाड़ा जिले में सड़कों के साइड पर कुल 119738 पौधे रोपित किये गये, जिन पर कुल 292.19 लाख रु. व्यय हुए। उनमें से कुल 41371 पौधे जीवित हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। इन जीवित पौधों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था की गयी थी। व्यवस्था हेतु कार्यकारी संस्था एवं विभागों द्वारा थोर फैंसिंग, झाड़ियों एवं कांटों की बाड़ लगाई गयी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हनुमानगढ़ जिले में सरकारी व निजी विशेष बाल गृहों पर व्यय राशि

193. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) हनुमानगढ़ जिले में कितने सम्प्रेक्षण गृह, अपचारी बालिका गृह एवं किशोर गृह सरकार व निजी संस्थानों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं? सम्प्रेक्षण गृह, अपचारी बालिका गृह एवं किशोर गृह के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संचालित सम्प्रेक्षण गृह, अपचारी बालिका गृह एवं किशोर गृह में कितने बच्चे रह रहे हैं? पिछले पांच वर्षों में इन गृहों में कितने बच्चे आये/लाये गये तथा कितने बच्चों को उनके माता-पिता को सुपुर्द किया गया? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त गृहों में बच्चों को कब से कब तक रखा जाता है? इन बालक-बालिकाओं पर प्रतिदिन के अनुसार कितना पैसा व किस-किस मद में व्यय किया गया? विगत पांच वर्षों में सरकारी व निजी संस्थानों के आय-व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हनुमानगढ़ जिले में एक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह संचालित हैं, जिसे विधि से संघर्षरत एवं देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को रखे जाने हेतु योग्य घोषित किया गया है।

(2) जिले में संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह में वर्तमान में 6 विधि से संघर्षरत बालक आवासित हैं एवं विगत 5 वर्षों में कुल 76 बच्चे प्रवेशित हुए एवं कुल 67 बच्चों को उनके माता-पिता को सुपुर्द किया गया, विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह में 6-18 आयु वर्ग के विधि से संघर्षरत बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों में निर्धारित अवधि तक रखा जाता है। इन बालक-बालिकाओं पर प्रतिदिन दी जाने वाली सामग्री की मात्रा निर्धारित है। परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। विगत पांच वर्षों में राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह हनुमानगढ़ में आबंटित राशि एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झालावाड़ जिले के मिनी सचिवालय भवन की लिफ्ट का संचालन

194. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिला मुख्यालय स्थित मिनी सचिवालय भवन पर किस-किस तल पर कौन-कौन से विभाग के कार्यालय संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भवन में ऊपरी मंजिलों पर आवागमन हेतु लिफ्ट का निर्माण किया गया था? यदि हां, तो वर्तमान में कितनी लिफ्ट संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भवन के ऊपरी मंजिलों पर आवागमन हेतु लिफ्ट को संचालित नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त मिनी सचिवालय में निःशक्त, विशेष योग्यजन एवं वृद्ध व्यक्ति चौथी मंजिल तक आवागमन कर सकें इस हेतु क्या व्यवस्था की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार निःशक्त, विशेष योग्यजन, वृद्ध व्यक्तियों को उक्त कार्यालयों में आवागमन को सुविधाजनक बनाने हेतु मिनी सचिवालय में स्थापित लिफ्ट का नियमित संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिला मुख्यालय स्थित मिनी सचिवालय भवन में संचालित विभिन्न विभागों के कार्यालयों की सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। मिनी सचिवालय भवन झालावाड़ में ऊपरी मंजिलों पर आवागमन हेतु 3 लिफ्ट का निर्माण किया गया था, वर्तमान में 1 लिफ्ट संचालित की जा रही है।

(3) जी नहीं। मिनी सचिवालय भवन झालावाड़ में 3 लिफ्ट में से 1 लिफ्ट का संचालन 1 फरवरी, 2013 से शुरू कर दिया गया है।

(4) मिनी सचिवालय भवन झालावाड़ में नि:शक्त, विशेष योग्य जन एवं वृद्ध व्यक्ति को चौथी मंजिल तक आवागमन हेतु लिफ्ट की व्यवस्था है जो 1 फरवरी, 2013 से चालू कर दी गई है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(5) जी हां। नि:शक्त, विशेष योग्य जन एवं वृद्ध व्यक्तियों को उक्त कार्यालयों में आवागमन को सुविधाजनक बनाने हेतु मिनी सचिवालय में स्थापित लिफ्ट का नियमित संचालन 1 फरवरी, 2013 से किया जा रहा है।

परिशिष्ट-1

झालावाड़ जिला मुख्यालय स्थित मिनी सचिवालय भवन में संचालित विभिन्न विभागों के कार्यालयों की सूची

क्र.सं.	कार्यालय का नाम
	भू-तल
1	जिला रोजगार
2	जिला श्रम कल्याण
3	कोषाधिकारी
4	हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
5	सेन्ट्रल बैंक
6	अधिशासी अभियन्ता, सा.नि.वि., गुण नियंत्रण खण्ड
7	अधिशासी अभियन्ता, सा.नि.वि., खण्ड प्रथम झालावाड़
8	अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि., वृत्त झालावाड़
9	समाज कल्याण विभाग
10	सहायक अभियन्ता, माइन्स
11	जन सम्पर्क विभाग
12	बाल श्रमिक परियोजना
13	वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र
14	एस.बी.बी.जे.
	प्रथम तल
1	जिला कलक्टर
2	डीआईओ, एनआईसी
3	उपखण्ड अधिकारी झालावाड़
4	स्वच्छता टीएससी
5	लोक मित्र
6	पुलिस अधीक्षक, अति. पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक
7	उप पुलिस अधीक्षक, वायर लेस

क्र.सं.	कार्यालय का नाम
8	होमगार्ड
9	सहायक निदेशक अभियोजना
	द्वितीय तल
1	भू-राजस्व विभाग
2	आयोजना
3	सांख्यिकी
4	आईसीडीएस व सीडीपीओ
5	रसद विभाग
6	सीआईडी पुलिस
7	सेल्स टैक्स
8	पीएचईडी प्रोजेक्ट
9	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
	तृतीय तल
1	जीपीएफ
2	उपनिदेशक कृषि विस्तार
3	उद्यान
4	आयुर्वेद
5	साक्षरता
6	कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक
7	डिस्ट्रीक्ट टाउन प्लानर
8	पशुपालन
9	मतस्य
10	परियोजना प्रबन्धक एससी/एसटी
11	अल्प संख्यक विभाग
12	जिला परियोजना प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण, आजीविका परियोजना-इकाई (डीपीएमयू)

अलवर जिले में सौर ऊर्जा पम्प योजनान्तर्गत लाभान्वित किसान

195. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(1) उच्च तकनीक उद्यानिकी सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना में कौन से किसान लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं तथा उन्हें क्या लाभ देय है व किसानों द्वारा इसमें कितना अंशदान दिया जाता है?

(2) जिला अलवर में कितने किसानों ने इस योजना में सौर पम्प हेतु आवेदन किया? कितने किसानों के आवेदन निरस्त किये गये एवं कितने किसानों के आवेदन अनुमोदित किये गये? किसानों से कितनी राशि आवेदन के साथ प्रतिभूति के रूप में अथवा अन्यथा ली गई? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना की पात्रता हेतु कृषक के पास न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर जमीन, जल स्त्रोत, ड्रिप सिंचाई संयंत्र, ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस हो या न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर में ड्रिप पर सब्जी/फूल/फलोद्यान लिया जा रहा हो एवं भू-जल स्तर अधिकतम 75 मी. हो। सौर उर्जा आधारित पम्प पर आधार दर का 86 प्रतिशत अनुदान का लाभ देय है तथा कृषक अंशदान 14 प्रतिशत है।

(2) अलवर जिले में वर्ष 2012-13 में 235 कृषकों ने इस योजना में आवेदन किया । इनमें से 14 किसानों के आवेदन निरस्त किये तथा 221 पात्र किसानों के आवेदन अनुमोदित किये गये। प्रत्येक आवेदन के साथ राशि 10,000 रुपये के कृषक अंशदान राशि के रूप में डी.डी. लिये गये। विधान सभा क्षेत्रवार आवेदन विवरण परिशिष्ट-1 पर है।

परिशिष्ट-1

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्रवार सौर पम्प हेतु अनुमोदित कृषक विवरण										
	बहरोड़	बानसूर	कठूमर	मुण्डावर	किशनगढ़बास	थानागाजी	तिजारा	रामगढ़	राजगढ़ लक्ष्मणगढ	अलवर ग्रामीण	अलवर
अनुमोदित आवेदन	9	10	22	31	38	32	14	20	21	24	0
अपात्र कृषक सं.	-	-	3	9	1	1	-	-	-	-	-

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग/आयुक्त अल्पसंख्यक निदेशालय द्वारा पंजीकृत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं

196. डा. [श्रीमती] परम नवदीप सिंह (संगरिया) : क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यकों हेतु संचालित ऐसे कितने विद्यालय पंजीकृत हैं जिन्हें शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत छूट प्राप्त है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त विद्यालयों में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु क्या प्रावधान है? प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) जयपुर शहर में ऐसे कितने और कौन-कौन से विद्यालय अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित हैं, जिन पर उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत 25 प्रतिशत कोटे में निःशुल्क प्रवेश देने का नियम लागू नहीं होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जयपुर शहर के उक्त विद्यालयों में अल्पसंख्यक समुदाय तथा सामान्य वर्ग के कितने-कितने छात्र-छात्रायें अध्ययनरत हैं? उक्त विद्यालयों में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को क्या-क्या अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यकों हेतु संचालित विद्यालयों का पंजीकरण अल्पसंख्यक मामलात विभाग नहीं करता है केवल अल्पसंख्यक संस्थाओं को संचालन हेतु एन.ओ.सी./स्टेटस प्रदान की जाती है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने 84 संस्थाओं को प्रमाण-पत्र जारी किये हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट -अ पर संलग्न है।

(2) अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान है। प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) इन विद्यालयों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की सूची शिक्षा विभाग से प्राप्त होने पर उपलब्ध करवा दी जायेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अनूपगढ़ की पेयजल आपूर्ति योजनाएं

206. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में कुल कितने भूमिगत जलाशय हैं तथा इनमें से विगत चार वर्षो के दौरान कितने भूमिगत जलाशय प्रारम्भ किये गये एवं शेष को सरकार कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में कुल कितनी पेयजल योजनायें हैं इनमें कितने फिल्टर कब से बन्द हैं? विगत दो वर्षों में पेयजल योजनाओं पर स्थापित फिल्टरों की सफाई कब-कब की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की तहसील अनूपगढ़ एवं घड़साना की कुल 166 ग्रामीण पेयजल योजनाओं (तहसील अनूपगढ़, 83 योजनाएं एवं तहसील घड़साना, 83 योजनाएं) अन्तर्गत क्रमश: 216 एवं 323, कुल 539 जी.एल.आर. (भू-तल जलाशय) निर्मित हैं । योजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

विगत चार वर्षों में विभिन्न कारणों से बंद/आंशिक बंद कुल 192 भू-तल जलाशयों में से 119 भू-तल जलाशयों से पूर्ण रूप से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है । 64 भू-तल जलाशयों को पाइप लाइन से जोड़ने एवं मरम्मत आदि का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा इन भू-तल जलाशयों से माह अप्रैल, 2013 तक पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करना प्रस्तावित है । योजनावार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है । शेष 9 भू-तल जलाशयों के क्षेत्रों की आबादी विस्थापित हो जाने के कारण वर्तमान परिपेक्ष्य में इन्हें चालू नहीं किया जाना है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की एक शहरी जल योजना, अनूपगढ़ अन्तर्गत निर्मित दो रेपिड ग्रेविटी फिल्टर संयंत्रों में से एक रेपिड ग्रेविटी फिल्टर (जल छनन क्षमता 4.46 एम.एल.डी.) द्वारा शहर की वर्तमान पेयजल मांग अनुरूप पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है । अन्य रेपिड ग्रेविट फिल्टर संयंत्र (जल छनन क्षमता 0.3 एम.एल.डी.) लगभग

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

एक वर्ष से बंद है तथा इस संयंत्र का सुधार कार्य वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्ण कर चालू करना प्रस्तावित है।

क्षेत्र में उक्तानुसार 166 ग्रामीण पेयजल योजनाओं अन्तर्गत कुल निर्मित 403 स्लो-सैण्ड फिल्टर संयंत्रों में से 40 संयंत्र पूर्ण क्षमता अनुरूप कार्य नहीं करने के फलस्वरूप इनके जीर्णोद्धार कार्यों हेतु आवश्यक स्वीकृति जारी की जा चुकी है । इन्हें पूर्ण क्षमता से उपयोग में लाने हेतु जीर्णोद्धार का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा यह कार्य माह, मई, 2013 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है । विगत दो वर्षों में ग्रामीण जल योजनाओं अन्तर्गत आवश्यकतानुसार 52 स्लो-सैण्ड फिल्टर संयंत्रों की सफाई (फिल्टर मीडिया बढ़ाना) का कार्य कराया गया है । पूर्ण विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कठूमर (अलवर) के ग्रामों हेतु स्वीकृत पेयजल योजनाएं

207. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर जिला अलवर में कितने व कौन-कौन से ग्रामों की पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई हैं? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत योजनाओं से सम्बन्धित ग्रामों में कार्य करने हेतु निविदा आमंत्रित कर ली गई है? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों के लिए? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरकार द्वारा उक्त ग्रामों की पेयजल योजना कब तक प्रारम्भ कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सामान्य एवं सुचारू बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 (माह फरवरी, 2013 तक) की अवधि में पेयजल सम्बन्धी कुल 618 योजनाओं/कार्यों हेतु राशि रुपये 1995.26 लाख की स्वीकृतियां आवश्यकतानुसार जारी की गई। नामवार वांछित सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(2) जी हां । वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है ।

(3) विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त अवधि में पेयजल सम्बन्धी कुल 618 योजनाओं/कार्यों हेतु जारी की गई स्वीकृतियों के विरुद्ध अब तक 317 योजनाएं/कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 11 योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं । इसके अतिरिक्त 23 विद्यालयों में 23 सिंगल फेस नलकूपों का निर्माण कार्य मार्च, 2013 तक पूर्ण करना लक्षित है। शेष 267 अपूर्ण योजनाओं/कार्यों को माह अप्रैल, 2013 से प्रारम्भ किया जाकर इन योजनाओं/कार्यों को संलग्न परिशिष्ट-अ में उल्लेखित अवधि तक पूर्ण करना प्रस्तावित है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सवाई माधोपुर जिले में फल उत्पादन में वृद्धि हेतु कार्य-योजना

208. श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सवाई माधोपुर में विगत तीन वर्षों में व्यवसायिक स्तर पर अमरूदों की बागवानी में वृद्धि का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इसके अतिरिक्त उक्त जिले में अन्य किन-किन फलों के पौधों की मांग होती रही है? गत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा वितरित पौधों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश के फलों के पौधों की मांग के क्या कारण हैं?

(4) विगत तीन वर्षों में वर्षा से फलों के पौधों को किस-किस प्रकार से कितना-कितना अलग-अलग किस्म का नुकसान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त जिले में फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विगत तीन वर्षों में किए गए सरकारी प्रयासों तथा प्राप्त परिणामों का विवरण एवं इस हेतु स्वीकृत अनुदान राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में विगत तीन वर्षों में अमरूदों के फल बगीचे स्थापना की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:-

(कृषि मंत्री)

(हैक्टेयर में)

वर्ष	लक्ष्य	प्रगति
2009-10	300	547
2010-11	200	242
2011-12	350	294.7

(2) अमरूद के अतिरिक्त जिले में नींबू, अनार, पपीता, आंवला, आदि फलदार पौधों की मांग होती रही है। पिछले तीन वर्षो में अमरूद के अतिरिक्त स्थापित अन्य फलों के बगीचों का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	नये बगीचों की स्थापना (है.)			
	नींबू	आम	बेर	ऑवला
2009-10	16.7	10.51	3.00	13.00
2010-11	10.34			
2011-12	14.8			

(3) उद्यान विभाग द्वारा राज्य के लिए अनुमोदित अमरूद की किस्मों के पौधे कृषकों को राजहंस के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाते हैं। जिलें के कुछ कृषक अपने स्वयं के स्तर पर उत्तर प्रदेश से अमरूद के पौधे लाकर पौधरोपण करते हैं। कृषकों द्वारा सीधे ही लिये जा रहे अमरूद के पौधे गोला, बर्फखाना के नाम से जाने जा रहे हैं। यह दोनों तरह के पौधे प्रमाणित नहीं है। जबकि विभाग से आपूर्ति ग्राफ्टेड पौधे एल-49 व इलाहबाद सफेदा किस्मों के हैं, जो उत्तम गुणवत्ता के साथ प्रमाणित है।

(4) वर्ष 2009-10 व 2010-11 में अमरूद उत्पादन में कमी नहीं आई है। वर्ष 2011-12 में अमरूद बगीचों में एन्थेक्नोज बीमारी का प्रकोप रहा जिसके कारण उत्पादन में आंशिक नुकसान रहा है।

(5) जिले में फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विगत तीन वर्षों में नये बगीचों की स्थापना व पुराने बगीचों के जीर्णोद्धार कार्यक्रम के तहत अर्जित प्रगति एवं स्वीकृत अनुदान राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(कृषि मंत्री)

वर्ष	नये बगीचों की स्थापना		पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार	
	भौतिक प्रगति (है. में)	अनुदान के रूप में वित्तीय प्रगति (लाख में)	भौतिक प्रगति (है. में)	अनुदान के रूप में वित्तीय प्रगति (लाख में)
2009-10	590.7	43.097	50	7.30
2010-11	252.45	21.19	53	7.50
2011-12	309.53	32.94	129.4	19.18

जैसलमेर जिले में कृषि कार्य हेतु देय अनुदान से लाभान्वित कृषक

209. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को किन-किन मदों एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है तथा अनुदान प्राप्त करने हेतु किसानों को कौन-कौनसी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी,2009 से जनवरी, 2013 तक जैसलमेर जिले की उक्त योजनाओं में कितने किसानों को लाभ प्राप्त हुआ? कृषकवार, ग्रामवार, योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों को कार्य योजना, आईसोपाम तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से अनुमोदित कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। योजनावार कृषि यंत्रों पर देय अनुदान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

उद्यान विभाग द्वारा होर्टिकल्चर मैकेनाइजेशन के अन्तर्गत अनुदानित दर पर पावर मशीनस मय उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं। पावर मशीनस का श्रेणीवार विवरण व देय अनुदान परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

कृषक पंजीकृत निर्माता/विक्रेता/क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति से मोल भाव कर कृषि यंत्र क्रय करने हेतु स्वतंत्र है। अनुदान आवेदन पत्र पर कृषक की स्व-प्रमाणित फोटो लगाया जाना अनिवार्य है। कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु किसानों को यंत्र क्रय तिथि से 30

(कृषि मंत्री)

दिवस में सम्बन्धित जिला कार्यालय में अनुदान क्लेम एवं स्व-हस्ताक्षरित मूल बिल प्रस्तुत करना पड़ता है।

(2) जैसलमेर जिले में उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा 1 जनवरी, 2009 से 31 मार्च, 2009 तक 01, वर्ष 2009-10 में 14, वर्ष 2010-11 में 58 तथा वर्ष 2011-12 में 61 किसानों को अनुदान से लाभान्वित किया गया। कृषकवार, ग्रामवार, योजनावार सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

वर्ष 2012-13 में 31 जनवरी, 2013 तक कृषि विभाग द्वारा किसानों को अनुदान नहीं दिया गया है।

उद्यान विभाग द्वारा उक्त अवधि में पावर मशीनस मय उपकरण आदि पर जैसलमेर जिले में कृषकों को कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले में कृषि अनुदान हेतु लम्बित प्रकरण

210. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वित्तीय वर्ष 2012-13 में पाली जिले की किस-किस तहसील में किस-किस कृषक द्वारा किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि अनुदान के रूप में मांगी गई?

(2) उक्त में से किस-किस कृषक को किस-किस कार्य हेतु कितना-कितना अनुदान दिया गया?

(3) उक्त अनुदान के कौन-कौन से प्रकरण किन-किन कारणों से अस्वीकृत किये गये एवं कौन-कौन से प्रकरण किन-किन कमियों के कारण लम्बित हैं?

(4) सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में कितने कृषकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था एवं लक्ष्य के विरुद्ध कितने कृषकों को लाभान्वित किया गया?

उत्तर

(1) कृषि विभाग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में पाली जिले में संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार कृषकों द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु राशि 304.10 लाख अनुदान के रूप में मांगी गयी। उद्यान विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में संलग्न परिशिष्ट-2 के अनुसार कृषकों द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु राशि 925.28 लाख अनुदान के रूप में मांगी गयी।

(कृषि मंत्री)

(2) कृषि विभाग अन्तर्गत पाली जिले में वित्तीय वर्ष 2012-13 में संलग्न परिशिष्ट-3 के अनुसार कृषकों को विभिन्न कार्यो हेतु राशि रुपये 98.59 लाख का अनुदान दिया गया। उद्यान विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में संलग्न परिशिष्ट-4 के अनुसार विभिन्न कार्यो हेतु राशि रु. 405.32 लाख का अनुदान दिया गया।

(3) कृषि विभाग अन्तर्गत अनुदान का कोई भी प्रकरण अस्वीकृत नहीं किया गया। सलंग्न परिशिष्ट-5 के अनुसार 400 प्रकरण अपूर्ण होने के कारण लम्बित है। उद्यान विभाग अन्तर्गत विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य नही पाये जाने के कारण 177 आवेदन लम्बित है एवं 11 अस्वीकृत किये गये हैं। सूची परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(4) कृषि विभाग अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में निर्धारित किये गये लक्ष्य एवं प्रगति का विवरण परिशिष्ट-7 पर संलग्न है। फरवरी, 2013 तक 974 कृषकों को लाभान्वित किया गया। उद्यान विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में निर्धारित किये गये लक्ष्य एवं प्रगति का विवरण परिशिष्ट-8 पर संलग्न है। फरवरी, 2013 तक 823 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रायसिंहनगर में राशन डीलरों की नियुक्ति

211. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को राशन डीलर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर (जिला श्रीगंगानगर) में कितने राशन डीलरों की कमी है? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार अब उक्त क्षेत्र में नये राशन डीलर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में उचित मूल्य दुकानों के आबंटन हेतु जारी दिशा-निर्देश दिनांक 27.04.2012 के द्वारा इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेश/परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों को अधिकृमित करते हुए पीयूसीएल

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

बनाम यूनियन आफ इण्डिया में न्यायाधिपति वाधवा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उचित मूल्य दुकानों को कम्प्यूटराइजेशन करने के सम्बन्ध में पारित आदेश, भारत सरकार के निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानों में महिला समूहों व सहकारी समितियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जारी दिशा-निर्देश दिनांक 27.04.2012, 18.06.2012, 12.07.2012, 13.08.2012, 07.09.2012, 11.12.2012 (तीन आदेश) एवं 06.03.2013 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में शहरी क्षेत्र में वार्ड नम्बर 14 एवं वार्ड नम्बर 19 (दो) रिक्त हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत थान्देवाला एवं ठण्डी (दो) रिक्त हैं।

(3) जी हां। 30 जून, 2013 तक नियुक्ति कर दी जायेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

भूख से मृत व्यक्ति के परिवार को आर्थिक सहायता

212. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विगत चार वर्षों में प्रदेश में भूख से मौत के मामले सामने आये हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितने-कितने व किस कारण से? मृतक के नाम व पते सहित जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि मृतक के परिवार वालों को स्थानीय प्रशासन व सरकार द्वारा कोई राहत/सहायता प्रदान की गई? यदि हां, तो दी गई सहायता/राहत का विवरण मृतक के नाम व पते सहित जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। विगत चार वर्षों में प्रदेश में भूख से मौत के मामले सामने नहीं आये हैं।

(2) बिन्दु संख्या-1 के अनुसार है।

प्रदेश में उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना

213. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि प्रदेश में उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना की गई है? यदि हां, तो उक्त कोष में दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक कितनी राशि जमा की गई व कितनी राशि किस-किस मद पर व्यय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी हां। राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष (पी.डी. खाता संख्या 160) के अन्तर्गत दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक जमा एवं व्यय राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

जमा राशि का विवरण-

क्र.सं.	अवधि	जमा राशि (रुपये)
1	दिसम्बर, 2008 से मार्च, 2009 तक	858251
2	अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010 तक	1693687
3	अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 तक	2255443
4	अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 तक	1586224
5	अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013 तक	3309508

व्यय राशि का विवरण-

क्र.सं.	अवधि	व्यय राशि (रुपये)	मद
1	दिसम्बर, 2008 से मार्च, 2009 तक	1540000	उपभोक्ता दिवस आयोजन
2	अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010 तक	0	
3	अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 तक	0	
4	अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 तक	0	
5	अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013 तक	1820000	उपभोक्ता दिवस आयोजन

नगर में गठित सतर्कता समितियां

214. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं प्रभावी निगरानी/नियंत्रण के लिए प्रत्येक स्तर पर एवं दुकानवार भी सतर्कता समितियों का गठन किया हुआ है तथा इसके लिए निर्देश/परिपत्र जारी किये हुए हैं? यदि हां, तो उनकी पालना के लिए अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है? निर्देश/परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र नगर की सभी ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी के लिए दुकानवार सतर्कता समिति का गठन किया हुआ है? यदि हां, तो पंचायतवार समिति के सदस्यों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उचित मूल्य की दुकानों पर वितरण व्यवस्था की निगरानी हेतु लगाये गये राज्य कर्मचारियों के नियमित उपस्थित रहकर वितरण व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित की जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश/आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या तथा अनुपस्थिति रहने वाले कितने कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? नगर विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी इस व्यवस्था में लगे हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 11.05.1999 द्वारा जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन किया हुआ है। आदेश दिनांक 29.10.2010 द्वारा जारी निर्देशानुसार वर्तमान में सभी जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि सतर्कता समितियों को उनके कर्तव्य/उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने हेतु अपने स्तर से निर्देश प्रदान करें तथा इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 23.12.2011 एवं 11.01.2012 को जारी कर निर्देशों में सरपंच, ग्राम पंचायत को प्रत्येक माह की 05 तारीख को आयोजित बैठक में उनके क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानों के सभी पीडीएस एवं गैर पीडीएस सामग्री के आबंटन, उठाव एवं वितरण का सत्यापन किये जाने के लिए अधिकृत किया गया है। सम्बन्धित आदेशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) जी हां। नगर विधान सभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी के लिए दुकानवार सतर्कता समिति का गठन किया हुआ है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिये सरपंच को एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद को पदेन रूप से नियुक्त किया हुआ है। नगर विधान सभा क्षेत्र की पंचायतवार समिति के सदस्यों की संख्या सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 11.03.2010 द्वारा माह मई, 2010 से उचित मूल्य दुकानों की वितरण व्यवस्था की निगरानी हेतु राज्य कर्मचारियों के नियमित उपस्थित रहकर वितरण व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित की जाने सम्बन्धी निर्देश जारी किये गये थे (आदेश की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है), जिसकी पालना में विधान सभा क्षेत्र नगर के क्षेत्राधिकार में उचित मूल्य दुकानों पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने सम्बन्धी कोई प्रकरण सामने नहीं आया है।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 10.07.2012 से यह व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सहाड़ा की नवीनीकरण योग्य सड़कें

215. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2008 से 31 जनवरी, 2013 तक कौन-कौनसी सड़कों का किस-किस वर्ष में नवीनीकरण का कार्य हुआ तथा वर्तमान में उक्त सड़कों की क्या स्थिति है?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में कितने किलोमीटर सड़कें नवीनीकरण करवाया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की सड़कों पर 1 जनवरी, 2008 से 31 जनवरी, 2013 तक किये गये नवीनीकरण कार्यों एवं उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में वर्ष 2013-14 में नवीनीकरण कार्यों का निर्धारण सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर जिले में सड़कों की मरम्मत पर व्यय राशि

216. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर शहर व जिले की कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण, मरम्मत व रखरखाव की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की है? सड़कों का नाम (प्रारम्भ व अन्तिम स्थल के नाम), लम्बाई सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2004 से वर्तमान तक उक्त सड़कों का निर्माण कब-कब करवाया गया तथा उस पर कितनी राशि व्यय की गयी एवं उक्त सड़कों की वर्तमान स्थिति क्या है? सड़कवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उक्त सड़कों का रख-रखाव, मरम्मत कब तक किया जाना था? सड़कवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गत चार वर्षों में अजमेर शहर की सड़कों की मरम्मत, पेचवर्क आदि पर कितनी राशि कब-कब व्यय की गयी? सड़कवार, तिथिवार राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर शहर व जिले की विभाग द्वारा नवनिर्मित एवं संधारित सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) अजमेर शहर एवं जिले में जनवरी, 2004 से फरवरी, 2013 तक विभाग द्वारा निर्मित सड़कों का व्यय सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त सड़कों का सम्बन्धित संवेदकों द्वारा रख-रखाव एवं मरम्म्त आदि का सड़कवार विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(4) गत चार वर्षों में विभाग द्वारा संधारित अजमेर शहर की सड़कों की नवीनीकरण, पेचवर्क आदि पर किये गये व्यय का सड़कवार, वर्षवार विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर सम्भाग में सड़क/भवन निर्माण हेतु जारी कार्यादेश

217. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर सम्भाग में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में सड़क एवं भवन निर्माण के कितने कार्यादेश जारी किये तथा इस हेतु कितनी राशि आबंटित की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त अवधि में कार्यादेश जारी होने के बाद वास्तविक कार्य कितने समय बाद प्रारम्भ हुआ? कितने कार्य निश्चित अवधि में पूर्ण हुये एवं कितने कार्य निश्चित अवधि के बाद पूर्ण हुए? कितने कार्य प्रगतिरत हैं एवं कितने कार्यादेशों में कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब एवं समयावधि में पूर्ण नहीं होने के क्या कारण रहे तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(4) क्या यह सही है कि अल्पावधि अनुज्ञा पत्र (एस.टी.पी.) प्राप्त करने में देरी एवं कठिनाइयों के कारण कार्यों में विलम्ब हो रहा है? यदि हां, तो सरकार इस हेतु क्या कार्य कर रही है?

उत्तर

(1) उदयपुर सम्भाग में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में सड़क एवं भवन निर्माण के जारी किये गये कार्यादेशों का मय राशि विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर प्रस्तुत है।

(2) कार्यादेश जारी होने के उपरान्त, कार्य शुरू होने की वास्तवित तिथि, निश्चित अवधि में कार्य पूर्ण, निश्चित अवधि बाद कार्य पूर्ण व कार्यों की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर प्रस्तुत है।

(3) कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं होने के कारण तथा विलम्ब से दूर करने हेतु किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट -1 व 2 पर प्रस्तुत है।

(4) जी नहीं। एस.टी.पी. प्राप्त करने में देरी एवं कठिनाइयों का खनिज विभाग से विचार विमर्श कर निराकरण किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बयाना में प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज

218. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ग्यारसाराम कोली)

(1) क्या यह सही है कि बयाना विधान सभा क्षेत्र में कुण्डा रेलवे फाटक व रूपवास रेलवे फाटक पर प्रतिदिन जाम की स्थिति बनी रहती है जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है?

(2) क्या सरकार उक्त रेलवे फाटकों पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) रूपवास रेलवे फाटक एल.सी. नं. 29-बी भरतपुर रूपवास सड़क पर रूपवास कस्बे में स्थित है। उक्त सड़क एन.एच.-123 है, जिसे नेशनल हाईवे आथोरिटी आफ इण्डिया को 19 फरवरी, 2013 को हस्तान्तरित की जा चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जयपुर के अनुसार रूपवास में स्थित वर्तमान रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने का कोई विचार नहीं है। वर्तमान में ऊंचा नंगला-धौलपुर मार्ग का सुदृढ़ीकरण करने से सम्बन्धित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने का कार्य चल रहा है, जिसके अन्तर्गत रूपवास में एक बाइपास का प्रस्ताव विचाराधीन है एवं इस बाइपास पर रेलवे लाइन पर एक आर.ओ.बी. का निर्माण प्रस्तावित है।

कुण्डा रेलवे फाटक एल.सी. नं. 219-बी बयाना रूदावल बोकोली मोड़ (एस.एच.-45) पर बयाना कस्बे के निकट स्थित है, जिसकी टी.वी.यू. अप्रैल, 2012 के अनुसार 461886 है, उक्त रेलवे फाटक पर आर.ओ.बी. बनाने हेतु रेलवे विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(रिपोर्ट पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में टोल टैक्स वसूली के निर्धारित मानदण्ड

219. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में टोल वसूली के क्या नियम/मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अनिल जैन)

(2) प्रदेश में किस-किस सड़क मार्ग पर टोल वसूली की जा रही है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त टोल वसूली नाकों में किस नाके की क्षेत्र सीमा कितनी है? टोलवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में कई टोल नाकों पर निर्धारित मानदण्डों से अधिक राशि की वसूली के प्रकरण भी सामने आये हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में राज्य सरकार की परियोजनाओं पर की जा रही टोल वसूली राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002 के अधीन जारी फीस नोटिफिकेशन के तहत की जा रही है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स राष्ट्रीय राजमार्ग फीस दर (दर का निर्धारण एवं सग्रहण) नियम, 2008 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2010 के अनुसार की जाती है। जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) प्रदेश में राज्य सरकार की परियोजनाओं पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, आर.एस.आर.डी.सी.सी. एवं रिडकोर एजेन्सी द्वारा विभिन्न सड़क मार्गों पर टोल वसूली की जा रही है जिसका विवरण परिशिष्ट-3, 4 एवं 5 पर प्रस्तुत है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदेश में की जा रही टोल वसूली का विवरण क्रमश: परिशष्ट-6 एवं 7 पर प्रस्तुत है।

(3) टोल वसूली नाकों में नाकों की क्षेत्र सीमा का विवरण परिशिष्ट-3, 4, 5, 6 एवं 7 पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। पूर्व में आर.एस.आर.डी.सी.सी. द्वारा संचालित बी.ओ.टी. परियोजना चला नीमकाथाना कोटपूतली सड़क पर दिनांक 07.12.2011 को अधिक वसूली की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस पर दिनांक 09.02.2012 को अधिक वसूली की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस पर दिनांक 09.02.2012 को संवेदक को नोटिस जारी कर रुपये 50000.00 की शास्ति आरोपित की गयी एवं संवेदक द्वारा 27.03.2012 को यह राशि आर.एस.आर.डी.सी.सी. में जमा

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

करवा दी गई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संचालित टोल बूथों पर प्राप्त शिकायतों एवं संवेदकों के विरुद्ध आरोपित शास्ति का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार उनके द्वारा संचालित टोल प्लाजा पर निर्धारित शुल्क से ज्यादा की वसूली की शिकायत कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डगडगा (अलवर)-बिवाई (दौसा) सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य

220. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील रैणी (अलवर) के ग्राम-डगडगा (कीलपुरखेड़ा) से बिवाई स्टेशन, जिला-दौसा के बीच 3.5 कि.मी. की दूरी से सड़क सीधा रेलवे स्टेशन बिवाई (आगरा-बांदीकुई-जयपुर) को जोड़ता है?

(2) क्या सरकार उक्त स्थानों के मध्य सम्पर्क सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील रैणी (अलवर) के ग्राम डगडगा (कीलपुरखेड़ा) से बिवाई रेलवे स्टेशन की दूरी 3.8 कि.मी. है एवं यह ग्रेवल सड़क है।

(2) उक्त दोनों स्थानों को जोड़ने हेतु सड़क का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 16 कि.मी. नई मिसिंग लिंक सड़कों की स्वीकृतियां क्षेत्रीय विधायकों की अनुशंषा पर की गई थीं, परन्तु उक्त सड़क माननीय विधायक द्वारा अभिशंषित सड़कों की सूची में शामिल नहीं थी।

करौली की क्षतिग्रस्त/मरम्मत योग्य सड़कें

221. श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष में निर्मित करौली विधान सभा क्षेत्र की सड़कें वर्तमान में क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी व क्षतिग्रस्त होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती रोहिणी कुमारी)

(2) क्या क्षतिग्रस्त सभी सड़कें गारण्टी अवधि में हैं? यदि हां, तो किस-किस ठेकेदार द्वारा बनाई गई? कौन-कौन सी सड़कें गारंटी अवधि में हैं और कब तक इनकी मरम्मत कर दी जायेगी?

(3) क्या यह सही है कि करौली विधान सभा क्षेत्र में गारंटी अवधि समाप्त हो चुकी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता है? यदि हां, तो कहां-कहां कौन-कौन सी सड़कें? क्या सरकार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) करौली विधान सभा क्षेत्र में गत एक वर्ष में निर्मित क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। गारण्टी अवधि की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत संवेदक द्वारा कर दी गई है।

(3) जी हां। गारण्टी अवधि के अलावा अन्य क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। उक्त सड़कों का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना की प्रस्तावित बाइपास सड़कें

222. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य सड़क मार्गों पर स्थित कितने शहरों/कस्बों में इस वित्तीय वर्ष में बाइपास निर्माण करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डेगाना के थांवला व रिया कस्बे में बाइपास बनाने का विचार रखती है? यदि हां,तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन बाइपासों की सूची परिशिष्ट-1 पर एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

प्राधिकरण द्वारा निर्माण किये जा रहे बाइपासों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

बी.ओ.टी. योजना में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सीकर जिले में पाटन-डाबला-बिहारीपुर-गांवली-निजामपुर सड़क (कि.मी. 0/0 से 21/593) परियोजना के तहत डाबला, चित्रवाल की ढाणी, बिहारीपुर एवं गांवली में बाइपास निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बी.ओ.टी. पी.पी.पी.-स्टेट हाइवे परियोजना जयपुर-भीलवाड़ा सड़क निर्माण के अन्तर्गत 5 नये बाइपास मालपुरा, शाहपुरा, कादेड़ा, फागी एवं रेनवाल में भी बाइपास निर्माण का कार्य कराने का निर्णय इस वित्तीय वर्ष में लिया गया है।

(2) जी हां। डेगाना विधान सभा क्षेत्र के थांवला कस्बे में बाइपास पी.पी.पी. योजना के अन्तर्गत अजमेर-नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-89 में प्रस्तावित है। रियां कस्बा इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है एवं बाइपास का निर्माण वर्तमान में स्वीकृत नहीं है, आगे निर्माण कराया राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जमवारामगढ़ की मिंसिग लिंक सड़कें

223. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्तमान में मिसिंग लिंक योजनान्तर्गत कौन-कौन से गांवों में कितनी-कितनी सड़कें स्वीकृत की गयी हैं? मय नाम सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत सडकों में से वर्तमान में कौन-कौन सी सड़कों का कार्य अपूर्ण है तथा कार्य पूर्ण नहीं होने के क्या कारण रहे? कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त अपूर्ण रही सड़कों को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्ष 2012-13 में मिसिंग लिंक योजनान्तर्गत निम्न तीन सड़कें स्वीकृत की गईं:-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

क्र. सं.	गांव का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	राशि (रु. लाख)
1	मंहगी	मंहगी से लोटवास (अलवर जिला सीमा तक)	3.750	93.75
2	हरीरामपुरा खरड़	एस.एच.-55 से हरीरामपुरा खरड़ वाया रायपुर घोरेट	1.750	43.75
3	पाल की ढाणी	आंधी से पाल की ढाणी	2.50	62.50
		योग	**8.00**	**200.00**

(2) उक्त स्वीकृत सभी सड़कों के कार्य प्रगतिरत हैं। उक्त कार्यों की निविदाओं में दो बार किसी भी निविदादाता ने भाग नहीं लिया। अत: तीसरी बार निविदायें आमंत्रित कर कार्यादेश माह फरवरी, 2013 में जारी किये गये हैं।

(3) उक्त प्रगतिरत सड़कों का कार्य अनुबन्धानुसार नियत तिथि 09.08.2013 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

बहरोड़ की क्षतिग्रस्त सड़कें

224. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत पांच वर्ष में कान्हावास से बहरोड़ तक कुल कितनी दुर्घटनायें हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं? यदि हां, तो उक्त सड़क की गत पांच वर्ष में कब-कब मरम्मत की गई?

(3) उक्त सड़क का निर्माण किस संवेदक द्वारा किया गया? क्या उक्त सड़क गारन्टी अवधि में है? यदि हां, तो इसकी ठीक प्रकार से मरम्मत नहीं होने के लिये संवेदक के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत पांच वर्षों में कानाबास से बहरोड़ में कुल 65 दुर्घटनायें हुई विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) बहरोड़ कान्हावास सड़क के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कि.मी. 0/0 से 17/0 तक अन्तर्राज्यीय सड़क योजनान्तर्गत एवं कि.मी. 16/400 से 31/0 तक केन्द्रीय सड़क निधि योजनान्तर्गत मैसर्स करण यादव संवेदक अलवर द्वारा किया गया था।

जी नहीं। वर्तमान में उक्त सड़क गारंटी अवधि में नहीं है।

इस सड़क के कि.मी. 0/0 से 16/400 की गारण्टी अवधि दिनांक 12.08.2011 एवं कि.मी. 16/400 से 31/0 की दिनांक 01.07.2012 तक थी। संवेदक द्वारा गारण्टी अवधि में मरम्मत कार्य नहीं करने पर अनुबन्धानुसार संवेदक के हर्जे-खर्चे पर उसकी जमा प्रतिभूति जब्त कर सड़क मरम्मत कार्य करवाया गया एवं संवेदक को निविदाओं में भाग लेने से दिनांक 19.04.2011 को वंचित (डीबार) किया गया। कोर्ट में चल रहे प्रकरण को वापस लेने के अध्यनधीन डीबार के आदेश को दिनांक 17.12.2012 को वापस लिया गया है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत पांच वर्ष में कान्हावास से बहरोड़ सड़क पर हुई दुर्घटनाओं का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	थाना मांढण से प्राप्त सूचनानुसार	थाना बहरोड़ से प्राप्त सूचनानुसार	योग
1.	2008	1	13	14
2.	2009	9	12	21
3.	2010	6	6	12
4.	2011	1	8	9
5.	2012	2	7	9
	योग	**19**	**46**	**65**

कृषि कनेक्शनों की विद्युत दरों में वृद्धि

225. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुरवाटी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(1) क्या सरकार ने यह घोषणा की थी कि आने वाले पांच वर्षों में किसानों पर विद्युत दर (टैरिफ) नहीं बढ़ाया जायेगा? यदि हां, तो कृषि कनेक्शन पर दिसम्बर, 2008 तक कौन-कौन सी राशियों को सम्मिलित कर किसानों को बिजली का बिल दिया जाता था तथा सितम्बर, 2012 में किसानों को जो बिल जारी किया गया है उसमें किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि जोड़कर बिल दिये गये हैं? दोनों का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दिसम्बर, 2008 से लेकर 15 जनवरी, 2013 तक सरकार ने घरेलू, अघरेलू, उपभोक्ता तथा कृषि कनेक्शन, उद्योग हेतु कितनी प्रति यूनिट दर (टैरिफ) बढ़ाई तथा इस राशि में किस-किस मद में कितनी राशि की बढ़ोतरी सम्मिलित की गई?

(3) क्या सितम्बर, 2012 के बाद 1000 रुपये के बिजली बिल में 100 रुपये सफाई शुल्क को भी जोड़कर बिजली का बिल देना प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां सफाई की व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित की जा रही है?

उत्तर

(1) संकल्प पत्र, 2008 में किसानों को सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराना था। जिसके तहत सरकार ने किसानों पर प्रभावी विद्युत दरें न बढ़ाकर बढ़ी हुई दरों का भार (अनुदान के रूप में) स्वयं द्वारा वहन किया जा रहा है। दिसम्बर, 2008 व सितम्बर, 2012 में सामान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को दिये गये बिलों का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) दिसम्बर, 2008 से लेकर 15 जनवरी, 2013 तक सरकार ने घरेलू, अघरेलू, उद्योगों एवं कृषि कनेक्शन हेतु दो बार विद्युत दरें (टैरिफ) बढ़ाई हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है, जो दिनांक 11 सितम्बर, 2011 एवं दिनांक 10 अगस्त, 2012 से क्रमश: प्रभावी हैं।

(3) जी हां। आदेश सं. जेपीआर-658 के तहत यूजर चार्जेज जयपुर व जोधपुर जिलों में घरेलू, अघरेलू, औद्योगिक मय मिश्रित भार श्रेणी के उपभोक्ताओं से द्विमासिक बिल के आधार पर बिलिंग माह सितम्बर, 2012 से लिया जाना वर्तमान में प्रभावी है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-'स' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

जयपुर व जोधपुर दोनों शहरों के लिए ही एकीकृत ठोस कचरा प्रबन्धन कार्य के अन्तर्गत निविदाएं आमंत्रित की गई तथा निविदाओं में सफल रहे न्यूनतम निविदादाता क्रमश: मैसर्स एटूजेड इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड, गुडगांव व मैसर्स रामकी एन्वायरों इंजिनियर्स प्रा. लि., हैदराबाद को कार्यादेश दिया गया। जयपुर में मैसर्स एटूजेड वेस्ट मैनेजमेन्ट (जयपुर) लिमिटेड द्वारा बीड डाक्यूमेन्ट के अनुसार प्रथम चरण में आंशिक सफाई कार्य के तहत 21 वार्डों में सफाई कार्य प्रारम्भ करना था, जो फर्म ने दिनांक 15.12.2012 से प्रारम्भ किया एवं तत्पश्चात् 25 वार्डों में सम्पूर्ण सफाई एवं शेष 31 वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य करना था। फर्म द्वारा टेण्डर डाक्यूमेट के अनुसार सफाई कार्य नहीं करने पर फर्म को समय-समय पर नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात् अचानक दिनांक 19.2.2013 से कार्य बन्द कर दिया गया। वर्तमान में नगर निगम द्वारा जयपुर शहर के सम्पूर्ण 77 वार्डों में नियमित सफाई कार्य करवाया जा रहा है।

जोधपुर नगर निगम क्षेत्र के 65 वार्डों में से 26 वार्डों में फर्म रामकी इन्वायरों द्वारा कार्य किया जा रहा है। साथ ही जोधपुर नगर निगम द्वारा भी नियमित रूप से सफाई कार्य सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में विद्युत ट्रांसफार्मर/विद्युत सामग्री की चोरी पर रोक हेतु कार्य योजना

226. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या अलवर जिले में गत चार वर्षों में विद्युत ट्रांसफार्मर/विद्युत सामग्री की चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं? यदि हां, तो उक्त चार वर्षों में अलवर जिले में कितने विद्युत ट्रांसफार्मर/विद्युत सामग्री की चोरियां हुई हैं? सहायक अभियन्ता कार्यालयवार व वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त चोरी हुए सामान का विद्युत विभाग द्वारा मूल्यांकन किया जाता है? यदि हां, तो अलवर जिले में गत चार वर्षों में चोरी हुए सामान का मूल्य कितना था? सहायक अभियन्ता कार्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त चोरी हुए सामान की सम्बन्धित पुलिस थानों में

(श्री रामहेत सिंह)

एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई? यदि हां, तो अलवर जिले में गत चार वर्षों में कितनी एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई? थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने उक्त चोरी हुए सामान की घटना पर गम्भीरता से विचार किया है? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु क्या उपाय किये गये?

उत्तर

(1) अलवर जिले में गत चार वर्षों में विद्युत ट्रांसफार्मर/विद्युत सामग्री की चोरी की घटनाओं का विवरण सहायक अभियन्ता कार्यालयवार एवं वर्षवार प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) अलवर जिले में गत चार वर्षों में चोरी हुए विद्युत ट्रांसफार्मर/विद्युत सामग्री का अनुमानित मूल्य 1680.39 लाख रुपए है। सहायक अभियन्ता कार्यालयवार एवं वर्षवार विवरण प्रपत्र- 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) उक्त चोरी हुए सामान की थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। गत चार वर्षों में कुल 3079 रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। थानेवार विवरण प्रपत्र-'स' पर उपलब्ध है।

(4) नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। समय-समय पर पुलिस के उच्च अधिकारियों से सम्पर्क कर व विभिन्न मीटिंगों में विद्युत सामग्री चोरों के खिलाफ कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाता है। कुछ चोरों को समय-समय पर पकड़ा भी गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर जिले के निर्माणाधीन ग्रिड सब-स्टेशन

227. श्री बहादुर सिंह (वैर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भरतपुर में वर्ष 2011 व 2012 में किस-किस तहसील में 135 केवी के कितने जी.एस.एस. स्वीकृत किये गये? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जी.एस.एस. स्वीकृत होने के पश्चात् एक वर्ष तक भी उनका निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया? यदि हां, तो क्यों? इस विलम्ब के लिए कौन दोषी है और क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या तथा शेष जी.एस.एस. का निर्माण अब कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 135 के.वी. का कोई भी ग्रिड सब-स्टेशन नहीं होता है।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन तहसीलवार/पंचायतवार स्वीकृत नहीं किए जाते हैं तथापि भरतपुर जिले मे वर्ष 2011 व 2012 में 132 केवी का कोई भी ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत नहीं किया गया है।

(2) भरतपुर जिले में वर्ष 2011 व 2012 में 132 के.वी. का कोई भी ग्रिड सब-स्टेशन. स्वीकृत नहीं किया गया है।

बाड़मेर जिले में कृषि भूमि पर निवासरत कृषकों को घरेलू विद्युत कनेक्शन में शिथिलता

228. श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्तमान में मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युतीकरण योजना लागू की गई है? यदि हां, तो कब से व इस योजना के तहत विद्युत कनेक्शन के लिए पात्रता के मानदण्ड क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के तहत सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है? यदि हां, तो कितने कनेक्शन जारी किये जायेंगे? यदि नहीं, तो सर्वे कार्य कब तक पूर्ण होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र सिवाना में विद्युतीकरण हेतु कितने विद्युत कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितनों के डिमाण्ड नोटिस जारी हुए व कितनों की राशि जमा हुई? इनको विद्युत कनेक्शन कब तक जारी किये जायेंगे? विवरण पंचायतवार, राजस्व ग्रामवार सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या उक्त योजना के तहत कृषि भूमि पर विद्युत कनेक्शन नहीं देने का नियम है? यदि हां, तो सरहदी जिले बाड़मेर के अधिकांश परिवार कृषि भूमि पर निवासरत होने के कारण क्या सरकार नियमों में शिथिलता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में ''मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युतीकरण योजना" (संशोधित) दिनांक 28.5.2012 से लागू की गई है। इस योजना के तहत घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए संशोधित मापदण्ड प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध हैं।

(2) उक्त योजना के तहत सर्वे का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के तहत राज्य में वर्ष 2012-13 व 2013-14 में 60 हजार घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये जाने हैं, प्रगति का विवरण प्रपत्र-'ब' पर उपलब्ध है।

(3) इस योजना के तहत पंचायत वार एवं राजस्व गांववार लक्ष्य आबंटित नहीं किये गये थे बल्कि पंचायत समितिवार लक्ष्य आबंटित किये गये थे। विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पंचायत समिति सिवाना में 11 समूह में 55 आवेदन एवं सिन्धरी पंचायत समिति (जिसमें सिवाना विधान सभा क्षेत्र भी सम्मिलित है) में 313 समूह में 1565 आवेदनों का लक्ष्य आबंटित किया गया। उक्त सभी आवेदकों का सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया है।

(4) कृषि भूमि पर स्थित आवासों पर निवास करने वाले परिवारों को विद्युत कनेक्शन राष्ट्रीय हैबिटेशन सर्वेक्षण, 2003 में चिन्हित 100 व उससे कम आबादी वाली कृषि भूमि (अरूपान्तरित भूमि) में स्थित ढाणियों में स्थायी रूप से निवास करने वाले परिवारों को इस योजना के अन्य मापदण्ड पूरा करने पर विद्युत कनेक्शन दिये जाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इस प्रावधान का लाभ उन परिवारों को प्राप्त नहीं होगा जो पहले से ही चिन्हित ढाणी/गांव में घरेलू कनेक्शन प्राप्त कर चुके हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले में कृषि कार्यों के लिये विद्युत आपूर्ति

229. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार कृषि कार्यों के लिये किसानों को आठ घंटे प्रतिदिन के हिसाब से सस्ती दरों पर निरन्तर एवं नियमित रूप से बिजली उपलब्ध करवा रही है? यदि हां, तो कोटा जिले में गत चार वर्षों में तहसीलवार कृषि कार्यों के लिये उपलब्ध करवाई गई बिजली का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(2) वर्ष 2009 से जनवरी, 2013 तक किसानों को उपलब्ध कराई गई बिजली दरों का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार राज्य के सभी गांवों में शहरों की भांति घरेलू बिजली 24 घंटे उपलब्ध करवा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार अब कब से सभी गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवा देगी?

(4) उक्त अवधि में राज्य के गांवों में घरेलू बिजली दरें क्या-क्या रही? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कृषि कार्य हेतु वर्तमान में रबी की सीजन में प्रतिदिन 6 से 7 घंटे के तीन ब्लाकों में साप्ताहिक रोटेशन में सस्ती दरों पर निरन्तर व नियमित रूप से विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है। कोटा जिले में गत चार वर्षो में किसानों को सभी तहसीलों में समान रूप से विद्युत उपलब्ध कराई गई है जिसका विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक किसानों को कृषि कार्य हेतु उपलब्ध कराई गई विद्युत दरों का वर्षवार विवरण प्रपत्र-'ब' पर उपलब्ध है।

(3) वर्तमान में सामान्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धतानुसार 20-22 घंटे घरेलू विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है।

(4) वर्ष 2009 से 2013 तक राज्य के गांवों में घरेलू कनेक्शन हेतु उपलब्ध कराई गई बिजली की दरों का विवरण प्रपत्र-'ब' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाली के खराब विद्युत मीटर

230. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली के विद्युत सब डिविजन, फालना के थ्री फेज विद्युत कनेक्शनधारी विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत मीटर जलकर/खराब होकर बन्द पड़े हैं, जिन्हें औसत उपभोग के आधार पर बिल दिया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसे थ्री फेज विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन विद्युत उपभोक्ताओं के कुएं/बेरों में

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

पानी ही नहीं है, जहां लेशमात्र भी विद्युत उपभोग नहीं किया जा रहा है, वहां भी मीटर को बन्द एवं जला हुआ बताकर उन उपभोक्ताओं से भी अनावश्यक बिल वसूला जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार फालना डिविजन में बन्द व खराब प्रत्येक थ्री फेज मीटर को बदलकर उपभोक्ता को वास्तविक विद्युत यूनिट उपभोग के अनुसार बिल भेजने का विचार रखती है? यदि हां, तो खराब मीटरों को कब तक बदल दिया जावेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली के विद्युत सब डिविजन फालना के थ्री फेज के 1205 कनेक्शनधारी विद्युत उपभोक्ताओं, जिनके विद्युत मीटर जलकर/खराब होकर बन्द पड़े हैं।

उपरोक्त मीटरों के उपभोक्ताओं को आर ई आर सी में वर्णित प्रावधान के आधार पर औसत राशि के बिल दिये जा रहे हैं एवं कृषि उपभोक्ताओं को फ्लैट रेट के आधार पर बिल दिये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं।

(3) थ्री फेज मीटर की उपलब्धता अनुसार बन्द व खराब मीटर बदलने का कार्य प्रगति पर है जिन्हें छह माह में पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

विद्युत प्रसारण निगम में नवनियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं का पदस्थापन प्रकरण

231. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम में वित्तीय वर्ष 2011-12 में कितने कनिष्ठ अभियंताओं को नयी नियुक्ति दी गई? नवनियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं में से जिला जयपुर में कितने कनिष्ठ अभियन्ताओं को उनके मूल निवास स्थान के पास पदस्थापित किया गया? नाम, स्थान व पदस्थापन की तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नवनियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं को उनके मूल निवास स्थान जिले में पदस्थापित करने के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो राजस्थान राज्य

(डा. दिगम्बर सिंह)

विद्युत प्रसारण निगम द्वारा जयपुर जिले में कतिपय नवनियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं को किस आधार पर उनके मूल निवास स्थान जिले में पदस्थापित किया गया?

(3) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम में वर्ष 2012-13 में जयपुर जिले में कार्यरत कितने कनिष्ठ अभियंताओं की जन शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? कनिष्ठ अभियंता का नाम, जन शिकायत प्राप्ति दिनांक व अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम में कनिष्ठ अभियंताओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई नीति बनी हुई है? यदि हां, तो नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम में वित्तीय वर्ष 2011-12 में 398 कनिष्ठ अभियंताओं को नयी नियुक्ति दी गई। नवनियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं में से जिला जयपुर में 15 कनिष्ठ अभियन्ताओं को उनके मूल निवास स्थान के पास पदस्थापित किया गया। विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। नवनियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं को उनके मूल निवास स्थान जिले में पदस्थापित करने के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं हैं। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा जयपुर जिले में कतिपय नवनियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं को रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार उनके मूल निवास स्थान जिले में पदस्थापित किया गया।

(3) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम में वर्ष 2012-13 में जयपुर जिले में 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन, मारखी में कार्यरत श्री सुरेश कुमार बागवान, कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध जन शिकायत अधीक्षण अभियन्ता (टीसीसी-प्रथम) के कार्यालय में दिनांक 22.02.2013 को प्राप्त हुई है। वस्तुस्थिति जानकारी हेतु अधीक्षण अभियन्ता (टीसीसी-प्रथम) के गोपनीय पत्र क्रमांक 84 दिनांक 26.02.2013 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता (220 केवी ग्रिड सब-स्टेशन) चौमूं से शिकायत की जांच कर तथ्यात्मक वस्तुस्थिति प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित किया गया था जिसकी जांच जारी है।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु स्थानान्तरण नीति बनी हुई है। जिसकी प्रति परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति

232. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा पाली जिले में कौन-कौनसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में पाली जिले के लिये किस-किस योजना में क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित था? किन-किन योजना में लक्ष्य प्राप्त हुए तथा किन-किन में नहीं? इसके क्या कारण रहे तथा लक्ष्य पूर्ति के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1. छात्रावास संचालन

2. उत्तर मैट्रिक छात्रावृत्ति

3. विधवाओं की पुत्री की शादी

4. गाड़िया लौहार मकान निर्माण

5. अनुप्रति योजना

6. अत्याचार पीड़ितों को सहायता

7. पालनहार योजना

8. विकलांग छात्रवृत्ति

9. आस्था कार्ड

10. सुखद योजना (विकलांग विवाह)

11. संयुक्त सहायता

12. विस्वास योजना

13. अन्तर्जातीय विवाह

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

14. विधवा पुनर्विवाह
15. विकलांग पेंशनधारियों को एक मुश्त भुगतान
16. सहयोग योजना
17. नवजीवन योजना
18. मुख्य मंत्री हुनर विकास योजना
19. एसबीसी प्रतिभावान छात्रा
20. एसबीसी प्रतिभावान छात्र

(2) उक्त जिले में पाली जिले को योजनावार जो बजट आबंटित किया गया है, वह इस जिले का प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्य है। प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध योजनावार उपलब्धियों का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने तथा जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिये योजनाओं का राज्य सरकार प्रचार-प्रसार करती है तथा जिलों को जो योजनावार बजट आबंटित किया जाता है उसके विरुद्ध प्रगति की राज्य स्तर पर बैठक आयोजित कर समीक्षा की जाती है तथा शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिलों को निर्देशित किया जाता है।

परिशिष्ट-अ

प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध योजनावार उपलब्धियों का विवरण जिला पाली (राज.)

क्र.सं.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2011-12 (राशि लाखों में)				वित्तीय वर्ष 2012-13 (31 जनवरी, 2013 तक) (राशि लाखों में)			विशेष विवरण
		आबंटित बजट	व्यय	लाभार्थियों की संख्या	कमी के कारण	आबंटित बजट	व्यय	लाभार्थियों की संख्या	
1.	छात्रावास संचालन	138.23	104.42	908	पात्र व्यक्ति के आवेदन कम प्राप्त हुए।	136.38	84.72	1122	
2.	उ.मै. छात्रवृत्ति	220.86	215.50	975	पात्र व्यक्ति के आवेदन कम प्राप्त हुए।	290.00	104.16	549	
3.	विधवाओं की पुत्री की शादी	11.20	11.20	112	-	7.00	5.10	51	
4.	गाड़िया लौहार मकान निर्माण	3.43	3.43	26		7.20	0	0	
5.	अनुप्रति योजना	4.00	1.25	4	पात्र व्यक्ति के आवेदन कम प्राप्त हुए।	2.75	0	0	
6.	अत्याचार पीड़ितों को सहायता	37.55	31.87	220	-	15.76	6.20	36	

क्र.सं.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2011-12 (राशि लाखों में)				वित्तीय वर्ष 2012-13 (31 जनवरी, 2013 तक) (राशि लाखों में)			विशेष विवरण
		आबंटित बजट	व्यय	लाभार्थियों की संख्या	कमी के कारण	आबंटित बजट	व्यय	लाभार्थियों की संख्या	
7.	पालनहार योजना	119.00	117.22	2226	-	256.00	205.87	2333	
8.	विकलांग छात्रवृत्ति	2.50	2.50	198	-	2.00	0.54	71	
9.	आस्था कार्ड	0.20	-	430	-	0.03	-	448	
10.	सुखद योजना (विकलांग विवाह)	4.00	4.00	16	-	4.25	1.50	9	
11.	संयुक्त सहायता	0.50	0.50	10	-	20.00	19.83	15	
12.	विश्वास योजना	4.00	3.33	23	पात्र व्यक्ति के आवेदन कम प्राप्त हुए।	6.00	0.23	6	
13.	अन्तर्जातीय विवाह	-	-	-	आवेदन अप्राप्त	2.00	-	0	
14.	विधवा पुर्नविवाह	-	-	-	आवेदन अप्राप्त	0.15	-	-	
15.	विकलांग पेंशनधारियों का एक मुश्त भुगतान	0.15	-	-	आवेदन अप्राप्त	0	0	0	
16.	सहयोग योजना	53.0	52.95	225	-	24.00	6.45	59	
17.	नवजीवन योजना	29.00	28.91	3278	-	58.00	34.85	992	

क्र.सं.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2011-12 (राशि लाखों में)				वित्तीय वर्ष 2012-13 (31 जनवरी, 2013 तक) (राशि लाखों में)			विशेष विवरण
		आबंटित बजट	व्यय	लाभार्थियों की संख्या	कमी के कारण	आबंटित बजट	व्यय	लाभार्थियों की संख्या	
18.	मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना	0.50	0.50	2	-	2.00	0	0	
19.	एसबीसी प्रतिभावान छात्रा	0.50	0.18	4	पात्र व्यक्ति के आवेदन कम प्राप्त हुए।	0.25	0	0	
20.	एसबीसी प्रतिभावन छात्र	0.50	0.03	1	पात्र व्यक्ति के आवेदन कम प्राप्त हुए।	0.20	0	0	

सूरसागर में नवीन छात्रावास निर्माण हेतु स्वीकृति

233. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत चार वर्ष में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के कुल कितने नागरिकों को लाभान्वित किया गया? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की 125 से अधिक कच्ची बस्तियों में रहने वाले समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के कल्याण के लिए नया छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में समस्त विभागीय योजनाओं में लाभान्वितों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जोधपुर नगर निगम परिक्षेत्र में विभाग द्वारा वर्तमान में 8 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं, जिनकी कुल स्वीकृत क्षमता 390 छात्र-छात्राओं की है। चूंकि एक विधान सभा क्षेत्र में स्थापित छात्रावास में अन्य विधान सभा क्षेत्र के छात्र-छात्राएं भी प्रवेश हेतु पात्रता रखते हैं। अत: राज्य सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में 125 से अधिक कच्ची बस्तियों के मद्देनजर नवीन छात्रावास खोले जाने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट–अ

सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में गत चार वर्षों में सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं में लाभान्वितों की संख्या

क्र.सं.	नाम योजना	वर्ष 09-10	वर्ष 10-11	वर्ष 11-12	वर्ष 12-13
1.	डे-केयर सेन्टर	25	25	25	25
2.	निराश्रित गृह	150	150	150	150
3.	विकलांग छात्रवृत्ति	383	146	104	80
4.	पालनहार योजना	140	150	157	159
5.	सहयोग योजना	33	49	90	80

क्र.सं.	नाम योजना	वर्ष 09-10	वर्ष 10-11	वर्ष 11-12	वर्ष 12-13
6.	अनु. जाति छात्रवृत्ति	291	639	374	227
7.	अनु. जनजाति छात्रवृत्ति	41	61	155	21
8.	विशेष पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति	0	9	17	1
9.	विश्वास योजना	5	3	2	4
10.	आस्था योजना	12	20	15	5
11.	अनुप्रति योजना (अनु. जाति)	5	4	6	5
12.	विधवा पुनर्विवाह	0	1	1	1
13.	विकलांगों को एक मुश्त अनुदान	0	0	0	0
14.	विकलांग विवाह पर अनुदान	1	2	3	0
15.	विकलांग संयुक्त सहायता (अंग उपकरण सहायता)	14	09	6	2
16.	नवजीवन योजना	47	47	200	200
17.	मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना	0	0	0	0
18.	अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति	49	134	72	0
19.	विधवा की पुत्री के विवाह पर अनुदान	5	26	6	8
20.	अन्तर्जातीय विवाह	8	3	3	3
21.	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	2754	2909	3293	2574
22.	राष्ट्रीय विकलांग पेंशन	0	116	153	113
23.	राष्ट्रीय विधवा पेंशन	0	803	1041	947
24.	राज्य वृद्धावस्था पेंशन	81	340	555	450
25.	राज्य विकलांग पेंशन	623	660	754	641
26.	राज्य विधवा पेंशन	4339	4457	4878	3969

नोट: पेंशन योजनाओं में विधान सभा वाइज तथा शहर-ग्रामीण वाइज रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है। रिकार्ड कोष/उपकोष वाइज ही संधारित किया जाता है। जोधपुर कोष से जोधपुर शहर, मंडोर पंचायत समिति तथा लूणी पंचायत समिति के 10 गांवों के लाभार्थियों को शामिल कर भुगतान किया जाता है। अत: वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक की सूचना में जोधपुर शहर, मंडोर पंचायत समिति तथा लूणी पंचायत समिति के 10 गांवों के लाभार्थी भी शामिल है।

कोटा शहर में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत लम्बित पेंशन प्रकरण

234. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन हेतु जनवरी, 2010 से जनवरी, 2013 तक कोटा जिले में कितने-कितने आवेदन कब-कब प्राप्त हुए तथा उनमें से किन-किन को पेंशन कब-कब प्रारम्भ कर दी गई व किन-किन की अब तक लम्बित है? लम्बित रहने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कोटा शहर में उक्त पेंशन हेतु आवेदन पत्र कहां जमा किये जाते हैं तथा क्या वहां से उक्त आवेदनों को अन्य कार्यालयों में भी भेजा जाता है? यदि हां, तो उक्त अवधि में प्राप्त आवेदनों को अन्य कार्यालयों में कब-कब भेजा गया? विगत दो वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विकलांग अथवा मंदबुद्धि व्यक्ति के परिवार में कोई व्यस्क सदस्य होने पर उसे पेंशन स्वीकृत नहीं की जाती? यदि हां, तो क्या सरकार विकलांगों को लाभान्वित करने हेतु इन नियमों में शिथिलता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या पेंशन हेतु आवेदक का राशन कार्ड होना आवश्यक है? यदि हां, तो जिस वृद्ध, विकलांग, मंदबुद्धि के पास राशन कार्ड नहीं है, तो उसके लिये क्या व्यवस्था की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अपनी नीतिगत घोषणानुसार 65 वर्ष से अधिक निराश्रित, विधवाओं, परित्यक्ताओं एवं नि:शक्त महिलाओं को बिना शर्त प्रतिमाह पेंशन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी तथा कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन पेंशन हेतु जनवरी, 2010 से जनवरी, 2013 तक कोटा जिले में किये गये आवेदन पत्रों/स्वीकृत किये गये एवं लम्बित प्रकरणों का उप खण्डवार एवं पंचायत समितिवार से सम्बन्धित पृथक-पृथक परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) कोटा शहर में पेंशन हेतु आवेदन पत्र नगर निगम कोटा में जमा

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

किये जाते हैं। उक्त आवेदन पत्र तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी कोटा कार्यालय में प्रेषित करने का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राजस्थान विशेष योग्य जन पेंशन नियम, 1965 के अन्तर्गत विशेष योग्यजन जो शारीरिक अक्षमता के कारण अपनी आजीविका के कमाने के लिए अयोग्य अथवा असमर्थ हैं तथा उनके पास जीवन निर्वाह के लिए स्वयं की एवं परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 14,000 से कम एवं शहरी क्षेत्र में रुपये 16,000 से कम है को पेंशन देय है। वर्तमान में नियमों में शिथिलता दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भविष्य में उचित प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

(4) राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 एवं राजस्थान विशेष योग्यजन पेंशन नियम 1965 के अन्तर्गत आवेदक का राशन कार्ड होना अनिवार्य नहीं है।

(5) 65 वर्ष व अधिक आयु की निराश्रित विधवाओं, परित्यक्ताओं एवं विशेष योग्यजन महिलाओं को पात्रता अनुसार पेंशन देय है। बी.पी.एल. परिवार की विधवा/परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन महिलाओं को पात्रता शर्तों में छूट प्रदान की गई है। वर्तमान में बिना शर्त पेंशन दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भविष्य में उचित प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रतापगढ़ जिले में निराश्रित सम्बल योजनान्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति

235. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला प्रतापगढ़ में वर्तमान में वृद्धावस्था/विधवा पेंशन से लाभान्वित होने वाले पुरुषों/महिलाओं की संख्या कितनी है? ग्राम-पंचायतवार तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2013 तक जिला प्रतापगढ़ में कितने आवेदन वृद्धावस्था/विधवा पेंशन के विचाराधीन हैं? ग्राम-पंचायतवार तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा संचालित निराश्रित सम्बल योजना में प्रतापगढ़

(श्री नन्दलाल मीणा)

जिले में वर्ष 2012-13 में कितने वृद्व लोगों को लाभान्वित किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला प्रतापगढ़ में जनवरी, 2013 तक वृद्वावस्था/विधवा पेंशन से लाभान्वित होने वाले पुरुषों/महिलाओं की संख्या 31299 है। ग्राम पंचायतवार/तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जनवरी, 2013 तक जिला प्रतापगढ में वृद्वावस्था/विधवा पेंशन का कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है।

(3) जिला प्रतापगढ़ में निराश्रित सम्बल योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में कुल 29 निराश्रितों को लाभान्वित किया गया है। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय छात्रावासों में प्रति छात्र पर व्यय राशि

236. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में छात्र व छात्राओं के कितने-कितने छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं? छात्रावासों में रह रहे छात्र-छात्राओं की संख्या, छात्रावासों की क्षमता सहित श्रेणीवार जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक प्रति छात्र विभिन्न मदों जैसे भोजन, वस्त्र एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री पर कितनी राशि आबंटित हुई व कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? माहवार, वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में किस-किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त में से कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं? श्रेणीवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने, कैडर रिव्यू करने व नये पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में छात्र व छात्राओं के कुल 766 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। छात्रावासों में रह रहे छात्र-छात्राओं की क्षमता एवं लाभान्वितों की संख्या का श्रेणीवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त छात्रावासों में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक विभिन्न मदों जैसे भोजन, वस्त्र व अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री पर कुल 109 करोड़ 84 लाख 82 हजार रुपये की राशि आबंटित की गई है। जिसके विरूद्ध 107 करोड़ 5 लाख 96 हजार की राशि व्यय की गई है। आबंटित राशि व व्यय राशि का छात्रावासवार, वर्षवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में स्वीकृत श्रेणीवार पदों का विवरण निम्नानुसार है-

श्रेणी का नाम	**कुल पद**	**भरे पद**	**रिक्त पद**
राज्य सेवा	96	40	56
अधीनस्थ सेवा	1690	650	1040
मंत्रालयिक सेवा	433	269	164
X केडर	137	40	97
च. श्रे. कर्म	1784	734	1050

श्रेणीवार व जिलेवार, स्वीकृत, भरे हुए तथा रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रकियाधीन है। जी नहीं। केडर रिव्यू व नये पद वित्तीय वर्ष 2012-13 में ही सृजित हुए हैं, अत: वर्तमान में केडर रिव्यू व नवीन पदों के सृजन का विचार नहीं है, विवरण परिशिष्ट 'द' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजनान्तर्गत आयोजित शिविर

237. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अभिषेक मटोरिया)

(1) क्या सरकार ने गत वर्ष पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजना प्रारम्भ की थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत जनवरी, 2013 तक कितने पशु चिकित्सा शिविर कहां-कहां आयोजित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत जनवरी, 2013 तक कितने पशु चिकित्सा शिविर पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? शिविरवार आबंटित व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त शिविर से कितने पशुपालक लाभान्वित हुए? जिलेवार लाभान्वितों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजना दिनांक 1 अगस्त, 2009 से प्रारम्भ है।

(2) पशुचिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजनान्तर्गत योजना प्रारम्भ होने के पश्चात माह जनवरी 2013 तक 2 लाख 12 हजार 704 शिविरों का आयोजन किया गया। आयोजित शिविरों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजना अन्तर्गत आयोजित होने वाले प्रत्येक शिविरों के आयोजन के लिए पृथक से बजट प्रावधान स्वीकृत नहीं किया जाता है।

(4) पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजनान्तर्गत योजना प्रारम्भ होने के पश्चात जनवरी 2013 तक 37 लाख 17 हजार 999 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है। जिलेवार लाभान्वितों की सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-अ

पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजना प्रगति

क्र.सं.	जिला	1 अगस्त, 2009 से जनवरी 2013 तक	
		आयोजित शिविरों की संख्या	लाभान्वित पशुपालकों की संख्या
1	अजमेर	4145	83501
2	भीलवाड़ा	8901	155334

क्र.सं.	जिला	1 अगस्त, 2009 से जनवरी 2013 तक	
		आयोजित शिविरों की संख्या	लाभान्वित पशुपालकों की संख्या
3	नागौर	4809	68803
4	टोंक	4614	108658
5	कुचामन सिटी	5548	134504
6	जयपुर	11652	112560
7	अलवर	15825	69568
8	दौसा	8592	126015
9	सीकर	10023	109622
10	झुन्झुनूं	11095	135482
11	बीकानेर	5094	267023
12	गंगानगर	6663	141885
13	हनुमानगढ़	4875	145459
14	चूरू	6764	125133
15	भरतपुर	8827	116429
16	धौलपुर	4423	85959
17	करौली	4645	70206
18	सवाई माधोपुर	4098	81522
19	जोधपुर	5574	82683
20	बाड़मेर	3915	122129
21	जैसलमेर	3415	56658
22	जालौर	6261	122262
23	पाली	7629	109084
24	सिरोही	3344	53956
25	कोटा	4903	96616
26	बारां	5280	101006
27	झालवाड़	4898	53982
28	बूंदी	**3451**	81781
29	डूंगरपुर	4558	90177
30	प्रतापगढ़	3130	58862

क्र.सं.	जिला	1 अगस्त, 2009 से जनवरी 2013 तक	
		आयोजित शिविरों की संख्या	लाभान्वित पशुपालकों की संख्या
31	उदयपुर	8644	139270
32	बांसवाड़ा	6765	187288
33	चित्तौड़गढ़	7292	155941
34	राजसमंद	3046	68641
	कुल योग	**212704**	**3717999**

पशुधन विकास बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की क्रियान्विति

238. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय अनुदानित पशुधन और पशुपालक बीमा योजना, पशुधन विकास बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि कई जिलों में यह योजना शुरू ही नहीं की जा सकी है? यदि हां, तो क्यों तथा उक्त जिलों में यह योजना अब कब तक प्रारम्भ कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत एक वर्ष में किन-किन जिलों में यह योजना क्रियान्वित की गई और कितनी राशि व्यय कर क्या लक्ष्य प्राप्त हुए?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नही ।

(3) वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रदेश के समस्त 33 जिलों में राजकीय अनुदानित बीमा योजनाओं की प्रगति निम्न अनुसार है :-

योजना का नाम	बीमा (पशुधन:पशुपालक)	अनुदान राशि पर व्यय
1. दुग्ध अक्षय योजना (22 जिलों में)	29737(गाय/भैंस)	122.54 लाख
2. कामधेनु/भैंस बीमा योजना (11 जिलों में)	369 (गाय/भैंस)	88768 रु.
3. गौरक्षक बीमा योजना (33 जिलों में)	1027 पशुपालक	20540 रु.
4. गौपालक बीमा योजना (33जिलों में)	1493 पशुपालक	37325 रु.
अनुदान पर कुल राशि व्यय		1,24,00,633 रु.

सिरोही जिले के पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत/रिक्त पद

239. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिरोही जिले में कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां और किस स्तर के संचालित हो रहे हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में संचालित पशु चिकित्सालयों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद भरे हुए व कितने किस तिथि व कारण से रिक्त हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सिरोही विधान सभा क्षेत्र में 15 राजकीय पशु चिकित्सालयों में से 10 चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों के पद रिक्त होने के कारण विगत समय में शिवगंज तहसील के आल्पा गांव में फैली अज्ञात बीमारी से सैकड़ों भेड़ों के एक साथ मरने की घटना घटित हुई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार पशु चिकित्सालयों में उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में संचालित पशु चिकित्सालयों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सिरोही जिले में संचालित पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) प्रदेश में रोग प्रकोप का मुख्य कारण रिक्त पद नहीं है। सिरोही जिलें में शिवगंज तहसील के आल्पा गांव में दिनांक 29 08 20012 को पशुओं में अज्ञात बीमारी की सूचना प्राप्त होते ही उसी दिन नजदीकी पशु चिकित्सालय जोगापुरा के प्रभारी मय चिकित्सा दल एवं स्वयं उप निदेशक पशुपालन विभाग, सिरोही मौके पर गये। मौके पर 200-250 भेड़ बकरियों के कंकाल/शव पड़े दिखे तथा मृत दो बकरियों का पशु चिकित्सक द्वारा तत्काल पोस्टमार्टम किया गया। जिसमें मृत्यु का कारण कोन्टेजियस केप्राइन प्लूरो न्यूमोनिया (सी सी पी पी) से होना पाया गया। स्थिति को देखते हुए आवश्यक चिकित्सा कार्य संपादित किया गया। वर्तमान में वहां रोग नियंत्रण में है।

(पशुपालन मंत्री)

(4) जी हां। रिक्त पदों को उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली जिला मुख्यालय पर दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना

240. श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र करौली में ग्रामीण लोगों की आय का मुख्य साधन दुग्ध उत्पादन है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में सरस डेयरी के कुल कितने, कहां-कहां पर दुग्ध संकलन केन्द्र संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरस डेयरी का दुग्ध अवशीतन केन्द्र हिण्डौन सिटी में बनाया गया है? यदि हां, तो उक्त केन्द्र निर्माण की स्वीकृति कब जारी हुई, यह कहां प्रस्तावित था तथा इसका कब निर्माण हुआ? उक्त अवशीतन केन्द्र पर कुल कितने लीटर दूध का, कहां-कहां से, कितने-कितने लीटर संकलन होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि करौली जिला मुख्यालय के आस-पास के गांवों विशेषकर रघुवंशी, कीरतपुरा, सायपुर, दहमोली, हजारीपुरा, हाथीपुरा, सेसरीपुरा आदि में बहुतायत में दुग्ध उत्पादन किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार करौली जिला मुख्यालय पर एक नवीन दुग्ध अवशीतन केन्द्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं । करौली में ग्रामीण लोगों की आय का मुख्य साधन कृषि है । दुग्ध उत्पादन अतिरिक्त आय का स्त्रोत है।

करौली में कुल 12 दुग्ध समितियां/संकलन केन्द्र 1. चैनपुर, 2 गादोली, 3 लेदोर, 4 छेनकापुरा, 5 मासलपुर, 6 भोजपुर, 7 गुडला, 8 बाधवा, 9 अतेवा, 10 करसाई, 11 शेरपुर एवं 12 चिनायत में स्थापित है, जिनमें से मात्र 4 दुग्ध संकलन केन्द्रों से दुग्ध संकलित हो रहा है ।

(2) जी हां। हिण्डौन सिटी, जिला करौली में डेयरी संयंत्र निर्माणाधीन है।

उक्त डेयरी संयंत्र निर्माण की स्वीकृति दिनांक 7 अगस्त, 2008 को जारी हुई, जिसकी प्रति प्रदर्श-क पर संलग्न है।

(डेयरी राज्य मंत्री)

उक्त डेयरी संयंत्र जिला करौली में प्रस्तावित था

तथा वर्तमान में उक्त डेयरी संयंत्र जिला करौली के हिण्डौन सिटी में निर्माणाधीन है, जिसका निर्माण कार्य माह दिसम्बर, 2009 में शुरू हुआ।

उक्त डेयरी संयंत्र पर दो बल्क मिल्क कूलर्स के माध्यम से औसतन लगभग 2,500 किलोग्राम प्रतिदिन संकलित होता है,

दुग्ध समिति दुग्ध संकलन केन्द्रवार दुग्ध संकलन का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	**समितियां/संकलन केन्द्र**	**मात्रा (किलो)**
1	शेरपुर	200
2	चिनायता	40
3	खीपकापुरा	20
4	सूरोठ	20
5	तारपुर	20
6	धुरसी	35
7	रीजबास	80
8	इरनिया	40
9	सिकरोदा जट	80
10	बिनेगा	400
11	गावडी	20
12	दानालपुर	40
13	सनेट का पुरा	80
14	शेखपुरा	100
15	अखाडा	40
16	निसूरा	40
17	गढी का पुरा	40
18	मोरडा	80
19	खोहरा	300
20	पदमपुरा	300
21	गांवडामीणा	400
22	बजेहडा	80

(डेयरी राज्य मंत्री)

क्र.सं.	**समितियां/संकलन केन्द्र**	**मात्रा (किलो)**
23	लीलोटी	10
24	भिवाडी	25
25	टोडूपुरा	10
		2500

(3) जी हां।

जी नहीं ।

करौली जिला मुख्यालय के आसपास के गांवों में विशेषकर रघुवंशी, कीरतपुरा, सायपुर, दहमोली, हजारीपुरा, हाथीपुरा, सेसरीपुरा आदि गांव गंगापुर सिटी के निकट स्थित हैं तथा इन गांवों से दुग्ध संकलित कर गंगापुर सिटी अवशीतन केन्द्र अथवा हिण्डौन सिटी डेयरी संयंत्र पर मंगवाया जा सकता है ।

(प्रदर्श पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले के रजिस्ट्रार सहकारी समिति कार्यालय के रिक्त पद

241. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समिति एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं अन्य विभागीय कार्यालयों में कौन-कौन से पद कितनी-कितनी संख्या में स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों में से कितने-कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सीकर के विभागीय कार्यालयों यथा उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सीकर, विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां सीकर एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की कार्यालयवार एवं पदवार सूचना निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(सहकारिता मंत्री)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	पद	स्वीकृत	रिक्त
1.	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सीकर	उप रजिस्ट्रार	1	-
		निरीक्षक (कार्यकारी)	9	2
		वरिष्ठ लिपिक	2	-
		कनिष्ठ लिपिक	3	1
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	-
		योग	17	3

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	पद	स्वीकृत	रिक्त
1.	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, सीकर	विशेष लेखा परीक्षक	1	-
		निरीक्षक (आडिट)	10	2
		वरिष्ठ लिपिक	2	1
		कनिष्ठ लिपिक	2	-
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	-
		योग	17	3

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	पद	स्वीकृत	रिक्त
1.	ग्राम सेवा सहकारी समितियां	मुख्य कार्यकारी (व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापक)	189	51

(2) जी हां। विभागीय कार्यालयों में रिक्त पदों को सीधी भर्ती (राजस्थान लोकसेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने पर) एवं विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न कर शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में स्क्रीनिंग/नियमितिकरण से रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही हेतु विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

बांसवाड़ा जिले में रासायनिक खाद की आपूर्ति

242. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा में इस वर्ष खरीफ की फसल हेतु किस-किस समिति को कितनी-कितनी खाद आबंटित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री फतेह सिंह)

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में मांग की तुलना में काफी कम मात्रा में खाद आबंटित की गई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) खाद का आबंटन समितिवार नहीं किया जाता है। क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के द्वारा लैम्पसों से सीजनवार मांग प्राप्त कर कृषि विभाग एवं आपूर्तिकर्ता कम्पनियों (इफ्को/कृभको) एवं राजफैड को भिजवाई जाती है। सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता कम्पनियों द्वारा उन्हें कृषि विभाग द्वारा सहकारिता क्षेत्र को जिलेवार व माहवार आबंटित खाद में से सम्बन्धित लैम्पसों की मांग के आधार पर आपूर्ति की जाती है। बांसवाड़ा जिले में वर्ष 2012-13 में खरीफ की फसल हेतु समितियों को सप्लाई की गई खाद की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में खरीफ की फसल हेतु उर्वरकों की कुल मांग एवं आपूर्ति का विवरण निम्नानुसार है-

(मात्रा- मै. टन)

क्र.सं.	नाम उर्वरक	उर्वरको की मांग	उर्वरको की आपूर्ति
1.	यूरिया	5000	4144
2.	डीएपी	750	513
3.	एसएसपी	1100	1053

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में मांग की तुलना में उर्वरकों की आपूर्ति कम रहने का मुख्य कारण राणाप्रतापनगर (उदयपुर) व चन्देरिया (चितौड़गढ़) रेल रैक पाइन्ट से विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की दूरी अत्यधिक होना है। विभाग द्वारा विभिन्न उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं से उर्वरकों की आपूर्ति सडक मार्ग से कराये जाने के प्रयास भी किये जाते हैं। मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से विभाग द्वारा रतलाम रेल रैक पाइन्ट से डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में उर्वरकों की आपूर्ति हेतु भारत सरकार से निवेदन किया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बायतू में विकास कार्यों पर व्यय राशि

243. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्तमान में ग्रामीणों के विकास हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? तत्सम्बन्धित जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(2) विधान सभा क्षेत्र बायतू में पंचायती राज विभाग के माध्यम से जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2012 तक कितने कार्य कितनी राशि व्यय कर किये गये? सूची योजनावार, मदवार एवं पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा वर्तमान में ग्रामीणों के विकास हेतु निम्नांकित महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

पंचायती राज विभाग की योजनाएं

1. एस.एफ.सी.
2. टी.एफ.सी.
3. निर्बन्ध राशि योजना
4. बी आर जी एफ

ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं

1. इन्दिरा आवास योजना
2. मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना

(2) विधान सभा क्षेत्र बायतू में पंचायती राज विभाग के माध्यम से जनवरी 2009 से दिसम्बर 2012 तक विभिन्न योजनाओं के तहत किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ए पर संलग्न है।

परिशिष्ट-ए

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	योजना का विवरण जिसमें फरवरी, 2009 से दिसम्बर, 2012 तक विधान सभा क्षेत्र बायतू में स्वीकृत कार्य एवं राशि का विवरण							
		एसएफसी		टीएफसी		निर्बन्ध राशि		बीआरजीएफ	
		कार्य	व्यय	कार्य	व्यय	कार्य	व्यय	कार्य	व्यय
1	बायतू	738	308.00	1332	540.00	133	175.00	408	13330.00
2	बालोतरा	87	94.35	216	121.30	64	27.69	134	379.25
3	सिणधरी	20	33.72	16	21.96	10	26.44	28	102.28
	योग	**845**	**436.07**	**1564**	**683.26**	**207**	**229.13**	**570**	**13811.53**

पंचायती राज संस्थाओं में कार्मिकों की सीधी भर्ती

244. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जिला परिषद के माध्यम से कनिष्ठ लिपिकों, कम्प्यूटर आपरेटर्स एवं अन्य पदों हेतु सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो यह भर्ती कब एवं किस प्रक्रिया से प्रारम्भ करवाई जा रही है?

(2) क्या सरकार उक्त सीधी भर्ती को राजस्थान लोक सेवा आयोग अथवा अन्य स्वतन्त्र एजेन्सी के माध्यम से करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कनिष्ठ लिपिक पदों की भर्ती हेतु नियम, 265 तथा 273 राज.पंचायती राज नियम, 1996 में दिनांक 17.12.2012 तथा 29.01.2013 को प्रभावशील संशोधन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भर्ती कार्यवाही अमल में लाई जानी है। अधिसूचना दिनांक 01.02.2013 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का वेटेज तथा अनुभव आधारित अनुग्रह अंकों का निर्धारण कर दिया गया है।

तीनों अधिसूचना की प्रतियां परिशिष्ट अ, ब, एवं स पर उपलब्ध हैं।

कनिष्ठ लिपिक पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, भर्ती प्रक्रियाधीन है।

अन्य पदों के बारे में नियमों में संशोधन प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं। उक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अंक

245. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की गई है? यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) क्या यह भी सही है कि इस भर्ती में राज्य के प्रत्येक जिले में अलग-अलग मेरिट बनाई गई है तथा क्या 40 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को पास किया गया है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2012-13 में जिला परिषदों द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 33,631 अध्यापकों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। जिलेवार संख्या परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 273 के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों की सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्राप्तांकों का 20 प्रतिशत जोड़कर वरीयता सूची बनाये जाने का प्रावधान है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायती राज संस्थाओं में कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती हेतु मानदण्ड/नियम

246. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 19,515 कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती बिना किसी लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर करने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो निर्णय किस स्तर पर लिया गया तथा अब तक कुल कितनी भर्तियां कहां-कहां हुईं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भर्ती में पूर्व में मनरेगा में कार्यरत संविदाकर्मियों को 10 से 30 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो कितने बोनस अंकों को प्रतिशत अथवा अंकों में दिये जाने का प्रावधान किया गया? भर्ती किये जाने वाले कर्मियों की मैरिट जिला स्तर पर बनेगी या राज्य स्तर पर? जारी निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायती राज संस्थाओं में होने वाली भर्तियों के लिए नियम कब बने? इन नियमों को कब-कब किस स्तर पर मंजूरी मिली तथा किस-किस भर्ती में यह नियम लागू होंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मंत्री मण्डल की आज्ञा संख्या 245/2012 द्वारा नव सृजित कनिष्ठ लिपिकों के पदों की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा के स्थान पर आवेदकों की शैक्षिणक योग्यता तथा अनुभव आधारित अनुग्रह अंकों के आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है। तदनुसार राज. पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया।

क.लि. पदों की भर्ती हेतु आवेदन आनलाइन लिये जा रहे हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 22.03.2013 है। इस कारण अभी तक भर्तियां नहीं हुई हैं।

(2) जी हां। पंचायती राज विभाग की अधिसूचना क्रमांक 114 दिनांक 01.02.2013 में चयन का आधार निर्धारित किया गया है। मनरेगा अथवा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं में निरन्तर कार्यरत संविदा कर्मियों को एक वर्ष से अधिक सेवा अवधि होने पर प्रतिवर्ष 10 अंक तथा अधिकतम तीन वर्ष तक 30 अंक बोनस के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 तथा राज. पंचायती राज नियम, 1996 के अध्याय 12 में प्रावधानों के अनुसार भर्ती किये जाने वाले कर्मियों की मैरिट जिला स्तर पर बनेगी।

अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) पंचायती राज विभाग में होने वाली क. लिपिक पद पर भर्तियों के बारे में राज. पंचायती राज नियम, 1996 वर्ष 1996 से प्रभावशील है। इन नियमों को समय-समय पर संशोधित किया गया है। कनिष्ठ लिपिक भर्ती हेतु विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2649 दिनांक 17.12.2012, 107 दिनांक 29.01.2013 एवं क्रमांक 114 दिनांक 01.02.2013 में चयन का आधार निर्धारित किया जाकर नियम बनाये गये हैं।

उक्त अधिसूचनाओं में संशोधित किये जाने वाले प्रावधानों को मंत्रीमण्डल/मंत्री स्तर से अनुमोदन प्राप्त है। क.लि. पदों की भर्ती पर उक्त प्रावधान लागू होंगे।

अधिसूचना दिनांक 17.12.2012 एवं 29.01.2013 की प्रति परिशिष्ट ब एवं स पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बस्सी की स्वीकृत/विचाराधीन योजनाएं

247. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक माडा/टाडा एवं सम्बल योजनान्तर्गत कौन-कौन से कार्य करवाये गये एवं कौन-कौन से कार्य स्वीकृत/विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत योजनाओं में किस-किस योजनाओं का कार्य कब-कब प्रारम्भ किया गया एवं कौन-कौनसी योजनाओं का कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में किस-किस गांव/पंचायत की कौन-कौनसी योजनाएं कितनी-कितनी राशि की विचाराधीन/स्वीकृताधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की माडा/टाडा एवं सम्बल योजनाओं के वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक के प्राप्त प्रस्ताव जो कि स्वीकृत/विचाराधीन है, का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बस्सी के अन्तर्गत पंचायत समिति बस्सी में जनवरी 2009 से जनवरी 2013 तक जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों का विवरण संलग्न अनुलग्नक 'अ' 'ब' एवं 'स' अनुसार है।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सम्बल योजनान्तर्गत पंचायत समिति चाकसू की ग्राम पंचायत हरी नारायणपुर के ग्राम चक चांदपुरा से ग्राम पंचायत की तरफ जाने वाले रास्ते में सी.सी. सड़क रु. 5.00 लाख का कार्य स्वीकृत किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी से सम्बन्धित निर्माण कार्यों के विचाराधीन प्रस्ताव अनुलग्नक "द" पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत योजनाओं में प्रारम्भ होने वाले कार्यों एवं अप्रारम्भ कार्यों की सूची संलग्न अनुलग्नक 'अ' 'ब' एवं 'स' अनुसार है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

अन्तर्गत कार्यों के 17 प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुए हैं जो परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। सम्बल योजनान्तर्गत वर्तमान में कोई भी कार्य विचाराधीन/स्वीकृतिधीन नही है।

(4) बिन्दु संख्या 3 के अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक जिले की बी.पी.एल. सूची के चयनित परिवार

248. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2002 में जिला टोंक में बी.पी.एल. सूची में कितने व्यक्तियों का चयन किया गया? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बी.पी.एल. सर्वे 2002 के अन्तिम चयन के पश्चात् उक्त सूची में कितने व्यक्तियों के नाम जोड़े गये तथा कितने हटाये गये? वर्षवार एवं तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 2002 की बी पी एल सूची में जिला टोंक में 20978 परिवारों का चयन किया गया था। सूची वर्ष 2006 में प्रभावी हुई है। तहसीलवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त सूची को अंतिम रूप देने के पश्चात् 17443 परिवारों के नाम स्वमोटो एवं अपील के द्वारा जोड़े गये एवं 746 परिवारों के नाम हटाये गये। वर्षवार एवं तहसीलवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

कार्यलय जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) टोंक

बी.पी.एल. सूची-2002 का वर्षवार एवं तहसीलवार विवरण

क्र. सं.	नाम तहसील	बी.पी.एल. सैंन्सस, 2002 के अनुसार वर्ष 2006 में चयनित बी.पी.एल. परिवारों की संख्या	स्वमोटो एवं अपील के द्वारा जोड़े गये बी.पी.एल. परिवारों का वर्षवार विवरण														कुल बी.पी.एल. चयनित परिवार
			2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (18.02.2013 तक)		योग		
			जोड़े गये नाम	हटाये गये नाम	जोड़े गये नाम	हटाये गये नाम	जोड़े गये नाम	हटाये गये नाम	जोड़े गये नाम	हटाये गये नाम	जोड़े गये नाम	हटाये गये नाम	जोड़े गये नाम	हटाये गये नाम	जोड़े गये नाम	हटाये गये नाम	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1	मालपुरा	2108	1919	0	61	0	34	0	67	0	48	0	39	0	2168	0	4276
2	उनियारा	481	3594	0	764	0	93	0	310	0	73	0	0	0	4834	0	5315
3	निवाई	6287	356	294	135	18	41	0	88	1	26	0	10	0	656	313	6630
4	टोंक	2448	1031	37	1238	14	281	0	33	0	252	0	1	0	2836	51	5233
5	पीपलू	2148	1477	0	118	91	72	0	19	0	101	0	37	0	1824	91	3881
6	टोडाराय सिंह	1155	491	0	62	0	16	0	203	0	87	0	1	0	860	0	2015
7	देवली	6351	3888	291	242	0	35	0	60	0	35	0	5	0	4265	291	10325
	योग	**20978**	**12756**	**622**	**6202**	**123**	**572**	**0**	**780**	**1**	**622**	**0**	**93**	**0**	**17443**	**746**	**37675**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद टोंक

नदबई के ग्रामीण श्मशान घाटों की चारदीवारी

249. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा' (नदबई) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नदबई के ग्राम बछामदी, श्यौराना, कुम्हा के श्मशान घाटों की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नदबई के ग्राम बछामदी में पोखर सुरक्षा दीवार का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र नदबई के ग्राम बछामदी, श्यौराना, कुम्हा में श्मशान घाट की बाउन्ड्रीवाल के कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नदबई के ग्राम बछामदी में पोखर सुरक्षा दीवार का निर्माण मनरेगा योजनान्तर्गत वार्षिक प्लान 2013-14 में प्रस्तावित है। आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृत होने पर करा दिया जावेगा।

मंत्रियों/संसदीय सचिवों को आबंटित वाहनों पर व्यय राशि

250. श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या राजस्थान स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2009 से 2012 के मध्य किस-किस माडल की कितनी-कितनी गाड़ियां क्रय की गई एवं उन पर कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में किस-किस माडल की कौन-कौन सी गाड़ियां कितनी-कितनी संख्या में स्टेट मोटर गैराज के अधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में राज्य के किस-किस मंत्री/संसदीय सचिव को कौन-कौन सी गाड़ी आबंटित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त आबंटित वाहनों की मेंटीनेंस एवं डीजल/पैट्रोल पर वर्ष 2009 से 2012 के मध्य कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वाहनवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्टेट मोटर गैराज द्वारा वर्ष 2009 से 2012 के मध्य क्रय की गई गाडियों का विवरण संलग्न है। अनुलग्नक "अ"

(2) स्टेट मोटर गैराज के अधीन वाहनों का विवरण संलग्न है। अनुलग्नक "ब"

(3) माननीय मंत्रीगण/संसदीय सचिवगण को आबंटित वाहनों का विवरण संलग्न है। अनुलग्नक "स"

(4) उक्त आबंटित वाहनों की मेंटीनेंस एवं डीजल/पैट्रोल पर वर्ष 2009 से 2012 के मध्य व्यय हुई राशि का विवरण संलग्न है। अनुलग्नक "द"

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली/सवाई माधोपुर जिले के मनरेगा मजदूरों का बकाया भुगतान

251. श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में मनरेगा योजना अन्तर्गत वर्ष 2008 से वर्ष 2012 तक वर्षवार कितना व्यय किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2008 से वर्ष 2012 तक जिला करौली एवं जिला सवाई माधोपुर में कितने मजदूरों को 100 दिवस एवं कितने मजदूरों को 100 दिवस से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया गया?

(3) उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2008 से वर्ष 2012 तक जिला करौली एवं जिला सवाई माधोपुर में कितने मजदूरों को समय पर भुगतान कर दिया गया एवं कितने मजदूरों का भुगतान अभी शेष है तथा शेष भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

(4) उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2008 से वर्ष 2012 तक उक्त जिलों में कितने मजदूरों को 100 दिन काम उपलब्ध नहीं करवाने पर भत्ते का भुगतान किया गया?

उत्तर

(1) प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक किए गए व्यय का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री)

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अधिनियम के प्रावधानानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मांग के आधार पर 1 परिवार को अधिकतम 100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है ना कि मजदूरों को। जिला करौली एवं सवाई माधोपुर में वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक 100 दिवस का रोजगार तथा 100 दिवस से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जिला करौली में वर्ष 2008 से 2012 तक सभी मजदूरों को यथा सम्भव समय पर भुगतान किया गया है तथा इस जिले में कोई भुगतान शेष नही है। जिला सवाई माधोपुर में ग्राम पंचायत अमरगढ़ की मस्टररोल गुम हो जाने के कारण 71 श्रमिकों के रु. 54708/- के भुगतान के सम्बन्ध में समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर 10 दिवस में भुगतान किये जाने के आदेश दिनांक 06.03.2013 को किये जा चुके हैं। ग्राम पंचायत बामनवास खुर्द में 5 व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों पर लाभार्थियों द्वारा समय पर मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण 44 मस्टररोल के भुगतान के आदेश दिनांक 06.03.2013 को दिये जाकर 10 दिवस में भुगतान किये जाने हेतु कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति बामनवास को निर्देशित किया गया है।

(4) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रोजगार की मांग किये जाने के उपरान्त नियत समय में रोजगार उपलब्ध नही कराए जाने की स्थिति में ही बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। उक्त दोनों जिलों में रोजगार की मांग करने वाले सभी परिवारों को नियत समय में रोजगार उपलब्ध कराए जाने के कारण किसी भी मजदूर को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा जिले में मनरेगा योजनान्तर्गत कराये गये विभागीय कार्य

252. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिनांक 1 जनवरी, 2010 से 15 जनवरी, 2013 तक भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर पंचायत समिति में महानरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायतों के अलावा किस-किस विभाग के कितनी-कितनी राशि के कार्य कब-कब स्वीकृत किये गये? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शिवजीराम मीणा)

(2) उक्त कार्यों के पेटे कार्यकारी संस्था द्वारा कब-कब राशि आबंटन की मांग की गई एवं पंचायत समिति द्वारा संस्था को कब-कब राशि का आबंटन किया गया? समय पर राशि आबंटन नहीं करने के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य विभाग द्वारा पूर्ण किये जाकर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है तथा पूर्ण किये गये कार्यों का भुगतान कब किया गया? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति जहाजपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त अन्य विभागों को स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) कार्यकारी संस्थाओं द्वारा राशि आबंटन की मांग एवं पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा राशि आबंटित किये जाने का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विभाग द्वारा पूर्ण किये गये कार्यों एवं भुगतान का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर में मनरेगा कार्यों की प्राप्त शिकायतें

253. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र नगर-डीग में नरेगा के तहत कितने, कहां-कहां और कितनी-कितनी राशि के कार्य करवाये गये? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में नरेगा कार्यों के तहत शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कितनी और कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र नगर-डीग में नरेगा के तहत कराये गये कार्यों का ग्राम पंचायत वार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

(2) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र में नरेगा कार्यों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय/निजी विद्यालयों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति

254. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) : क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र-छात्राओं में कितने निजी विद्यालय के एवं कितने राजकीय विद्यालयों से है? पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है की सूचना परिशिष्ट - "अ" पर संलग्न है।

पूर्व मैटिक छात्रवृति की सूचना शिक्षा विभाग से प्राप्त होने पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) छात्रवृत्ति आवेदन की समस्त प्रक्रिया आनलाइन है तथा आवेदन आमंत्रण से लेकर छात्रवृत्ति स्वीकृति तक भारत/राजस्थान सरकार द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु निजी/सरकारी संस्थान का कोई मापदंड नहीं होने के कारण छात्र/छात्राओं की निजी एवं सरकारी विद्यालयवार संख्या का संधारण नहीं किया जाता है इसलिए अभी सूचना उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हो पा रहा है। प्रयास कर सूचना अतिशीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज. जयपुर

नेहरू सहकार भवन, 219-220, द्वितीय तल, बाईस गोदाम पुलिया, जयपुर

भारत सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 से 2011-12 में निम्नानुसार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई :-

क्र. सं.	वर्ष	Post Matric Scholarship				Merit Cum Means Scholarship				State Merit Cum Means Scholarship			
		लक्ष्य	छात्र	छात्रा	योग	लक्ष्य	छात्र	छात्रा	योग	लक्ष्य	छात्र	छात्रा	योग
1	2009-10	9016	4277	3867	8144	579	784	172	956	यह योजना वर्ष 2011 से ही शुरू हुई है।			
2	2010-11	12022	6328	4448	10776	601	772	228	1000				
3	2011-12	15778	11154	8393	19547	601	807	380	1187	601	556	54	610

यह योजना CSS में भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है।

यह योजना CSS में भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है।

यह योजना पूरी तरह राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-164 का विवरण)

प्रपत्र 'अ'

राज्य में नई विद्युत उत्पादन (दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013) इकाइयों का विवरण

क्र.सं.	विद्युतगृह (इकाई) का नाम	क्षमता	विद्युत उत्पादन इकाई के निर्माण प्रारम्भ होने की तिथि	विद्युत उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि
1	गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन इकाई-2	125 मेगावाट	दिसम्बर, 2006	26.12.2008
2	सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन इकाई-6	250 मेगावाट	जून, 2006	31.3.2009
3	कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन इकाई-7	195 मेगावाट	जून, 2006	30.5.2009
4	छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन इकाई-1	250 मेगावाट	मार्च, 2006	29.4.2009
5	छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन इकाई-2	250 मेगावाट	मार्च, 2006	04.5.2010
6	राजवेस्ट पावर इकाई 1	135 मेगावाट	दि. 25 अप्रैल, 2007	26.11.2009
7	राजवेस्ट पावर इकाई 2	135 मेगावाट	दि. 25 अप्रैल, 2007	04.10.2010
8	राजवेस्ट पावर इकाई 3	135 मेगावाट	दि. 25 अप्रैल, 2007	07.11.2011
9	राजवेस्ट पॉवर इकाई 4	135 मेगावाट	दि. 25 अप्रैल, 2007	04.12.2011

क्र.सं.	विद्युतगृह (इकाई) का नाम	क्षमता	विद्युत उत्पादन इकाई के निर्माण प्रारम्भ होने की तिथि	विद्युत उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि
10	केन्द्रीय क्षेत्र में बरसिंहसर (जिला बीकानेर) इकाई 1	125 मेगावाट सम्पूर्ण ऊर्जा	दि. 14.09.2005	20.01.2011
11	केन्द्रीय क्षेत्र में बरसिंहसर (जिला बीकानेर) इकाई 2	125 मेगावाट सम्पूर्ण ऊर्जा	दि. 14.09.2005	29.12.2011
12	आर.ए.पी.पी. इकाई 5	220 मेगावाट (राज्य का हिस्सा 43.87 मेगा.)	दि. 18.09.2002	04.02.2010
13	आर.ए.पी.पी. इकाई 6	220 मेगावाट (राज्य का हिस्सा 43.87 मेगा.)	दि. 20.01.2003	31.03.2010

उपरोक्त के अतिरिक्त दिसम्बर, 08 से जनवरी, 2013 तक 1696 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनायें, 60 मेगावाट की बायोमास परियोजनायें तथा 276 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाकर विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया गया।

प्रपत्र 'ब'

राज्य में दिसम्बर 2008 से निर्माणाधीन तथा नवीन परियोजनाओं का विवरण

परियोजना का नाम	क्षमता	कार्य आदेश की तिथि	कार्य प्रारमभ करने की तिथि	वर्षवार बजट प्रावधान एवं व्यय (करोड़ रुपये)			उत्पादन शुरू होने की प्रस्तावित तिथि
				वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	
रामगढ़ गैस तापीय परियोजना चरण तृतीय	110 मेगावाट (गैस टरबाईन)	जुलाई 2009 (BHEL)	30.04.2010 (पर्यावरण स्वीकृति)	2009-10	180.00 करोड़	99.83 करोड़	15.03.2013
	50 मेगावाट (स्टीम टरबाईन)			2010-11	242.00 करोड़	248.82 करोड़	31.07.2013
				2011-12	233.00 करोड़	178.02 करोड़	
				2012-13	237.00 करोड़	127.08 करोड़	
छबड़ा इकाई-3	250 मेगावाट	दिसम्बर, 2008 (BOP)	दिसम्बर, 2008	2009-10	770.00 करोड़	624.07 करोड़	30.03.2013/ 31.07.2013
				2010-11	670.00 करोड़	762.06 करोड़	
छबड़ा इकाई-4	250 मेगावाट			2011-12	690.00 करोड़	485.13 करोड़	
				2012-13	568.00 करोड़	322.12 करोड़	
कालीसिंध इकाई-1	600 मेगावाट	जुलाई, 08	26.02.2009 (पर्यावरण स्वीकृति)	2009-10	1460.00 करोड़	1196.44 करोड़	26.03.2013/ 31.07.2013
				2010-11	1400.00 करोड़	1965.47 करोड़	
कालीसिंध इकाई-2	600 मेगावाट			2011-12	1700.00 करोड़	1482.17 करोड़	
				2012-13	1672.00 करोड़	1373.28 करोड़	

परियोजना का नाम	क्षमता	कार्य आदेश की तिथि	कार्य प्रारमभ करने की तिथि	वर्षवार बजट प्रावधान एवं व्यय (करोड़ रुपये)			उत्पादन शुरू होने की प्रस्तावित तिथि
रामगढ़ गैस तापीय परियोजना चरण चतुर्थ	110 मेगावाट (गैस टरबाईन)	नवमबर, 2012 (BOP)	नवम्बर, 2012	2012-13	75.00 करोड़	41.75 करोड़	अक्टूबर, 2014
	50 मेगावाट (स्टीम टरबाईन)						मार्च, 2015
निजी क्षेत्र में भारत सरकार के दिशा-निर्देश केस-1 के तहत अडानी पावर राजस्थान लि. कवई-12	1200 मेगावाट	-	जनवरी 2010	उक्त परियोजना निजी क्षेत्र की होने के कारण राज्य सरकार का बजट प्रावधान व व्यय शून्य है।			अगस्त, 2013
आर.ए.पी.पी. 7	700 मेगावाट (राज्य का हिस्सा 350 मेगावाट)	-	नवम्बर 2011	केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट			जनवरी, 2017
आर.ए.पी.पी. 8	700 मेगावाट (राज्य का हिस्सा 350 मेगावाट)	-	नवम्बर 2011	केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट			मार्च, 2017

नोट :- केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत इकाइयां भारत सरकार के उपक्रमों के अन्तर्गत आती हैं।